अनुक्रमणिका/Index

01. अनुक्रमणिका /Index 01
02. क्षेत्रीय सम्पादक मण्डल/सम्पादकीय सलाहकार मण्डल 06/07
03. निर्णायक मण्डल 08
04. प्रवक्ता साथी 10/11

(Science / विज्ञान)

05. Screening Of Coliforms From Drinking Water Supplied In Various Area Of Ahmedabad 12
(Dr. Dilip Zaveri, Anurag Zaveri, Avani Zaveri, Archana Patel)
06. Study Of Physico – Chemical Properties Of Narmada River , West Nimar, M.P. - 17
With Special Reference To Pollution Status (Dr. Darasingh Waskel)
07. Pteridophyta Of Mandugadh Dhar (M.P.) India 21
(Prof. Nirbhay Singh Solanki, Prof. S. C. Mehta)
08. Ethno-Medicinal Studies On Skin Diseases In Kol Tribes Of Jaisinghnagar 24
Tehsil District Shahdol Central India (Dr.Radheshyam Napit)
09. Industrial Effluent Affecting Hydrophytes In Tapti-River At Burhanpur, M.P. India 27
(Prof. I.A. Siddiqui)
10. Study on Traditional Knowledge Anti-Diabetic Plants Used By Local People of 30
Shahdol District (M.P.) India (Dr. Radheshyam Napit)
11. Digital Electronics (Dr. Neeraj Dubey) 34
12. Carbon-Sequestration, A way to management of global warming 36
(Kumud Dubey, Avinash Dubey)

(Home Science / गृह विज्ञान)

13. To Assess the Nutritional Status of the Adult Females (Madhu Kagat) 37
14. Pulses Intake Among Adolescent Girls And Boys Of HIG And MIG 40
(Dr. Madhubala Verma, Pranita Bahutra)
15. ग्रामीण क्षेत्रों में किशोर-किशोरियों में रोजगार के अवसर का अध्ययन (शारदा भिण्डे, डॉ. मंजू शर्मा) 42
16. इंटरनेट की लत का किशोर बालक एवं बालिकाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव (डॉ. आभा तिवारी, निरंजना धोटे) 47
17. हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम के किशोर बालक एवं बालिकाओं की आध्यात्मिक बुद्धि में लिंग भिन्नताओं का अध्ययन 51
(डॉ. आभा तिवारी, आहुति साहू)

(Commerce & Management / वाणिज्य एवं प्रबंध)

18. A Study Regarding The Brand Awareness Of News Channel IBC24 “Sawaal aapka hai” 54
- Chhattisgarh Region (Vikas Sharma)
19. Study of Agriculture Growth in Madhya Pradesh in Post Liberalization Period 58
(Rajesh Kumar Gautam,Dr. Pawan Kumar Jaiswal,Dr. Ajay Waghe)

20. A Comparative Study of Consumer Attitudes towards Pricing Strategy of Dabur & Himalaya (Prof. Vishwas Sharma,Dr. Pradeep Kumar Sharma) 62
21. The Transitional Phase Of Goods And Service Tax In India- With Special Refrence To Madyaprdesh (Prof. Pratap Rao Kadam) 65
22. Workers Participation In Management in India (Dr. Rakhi Saxena,Deepika Shrivastava) 68
23. Emerging Trends Of Hospitality Sector (Dr. L. N. Sharma) 70
24. M – कॉमर्स व इसकी भारत में संभावना (डॉ. पारितोष अवस्थी) 72
25. सिलाई, बुनाई दस्तकारी से संबंधित महिलाओं की आर्थिक दशाओ का अध्ययन (रीवा जिले के विशेष संदर्भ में) ..... 75 (डॉ. रूपेश द्विवेदी,राजेश कुमार विश्वकर्मा)
26. मुर्गी पालन फर्म की लागत लाभ विश्लेषण का अध्ययन (रीवा जिले के रतहरा फर्म के संदर्भ में) ..... 77 (राजेश कुमार विश्वकमा, डॉ. रूपेश द्विवेदी)
27. उद्योगों में कार्यशील पूँजी के प्रबंधन का महत्व (डॉ. सपना सोलंकी) 79
28. रीवा शहर में सिरमौर चौराहे में स्थिति फल विक्रेताओं की आर्थिक स्थिति अध्ययन (रूपेश द्विवेदी, क्रितिका सिंह) 81
29. मध्यप्रदेश में शक्कर उद्योग के विकास की संभावनाओं का अध्ययन (डॉ. प्रताप राव कदम) 83
30. कृषि उपज मण्डी करहिया (रीवा) की कार्यालयीन एवं समग्र प्रबन्ध प्रणाली का अध्ययन (क्रितिका सिंह, रूपेश द्विवेदी) 85
31. प्रबंध में कर्मचारी सहभागिता (डॉ. दिनेश कुमार चौधरी) 87

(Economics / अर्थशास्त्र)

32. Make In India - A Ray Of Hope For India Economy (Dr. R. P. Saharia) 89
33. Achieving Food Security Through Agricultural Growth: In Indian Context ..... 93 (Sunil Sharma, Dr. Rajeev Singh Chauhan,Dr. Kamlesh Kumar Shrivastava)
34. Economic Effects Of Drugs - An Analysis (Nisar Ahmad Wani,Pavan Kumar Shrivastava) 96
35. गरीबी – समस्या एवं समाधान (एस. एल. रजक, डॉ. सुनीता बाथरे) 99
36. भारतीय विदेशी व्यापार की दशा एवं दिशा (रावेन्द्र सिंह पटेल) 103
37. इन्दौर नगर के कुड़ा बीनने वाले श्रमिकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन (डॉ. अंजना जैन) 106

(Political Seience / राजनीति विज्ञान)

38. Decentralization And Women Empowerment -A Step Towards Development ..... 108 (Dr. Sushma Saini, Dr. Abha Saini)
39. भारत की संसदीय व्यवस्था में चुनाव आयोग की बहुमुखी और बहु-आयामी भूमिका (डॉ. जे.के. संत) 111
40. राजनैतिक दल, घोषणा-पत्र और मतदाता (भावना ठाकुर) 114
41. महात्मा गाँधी का आर्थिक चिन्तन (डॉ. अनिल कुमार जैन) 117
42. विकासशील भारत में भ्रष्टाचार का स्वरूप एवं निदान (डॉ. अलका भार्गव) 119
43. सौराष्ट्र विलय में सरदार बल्लभ भाई पटेल का योगदान (डॉ. पूर्णिमा शर्मा, अशोक कुररिया) 121
44. भारत – नेपाल सम्बंधों की एक झलक (डॉ. अनिल दीक्षित) 123

45. भारत में जन आन्दोलन एवं संवैधानिक मर्यादायें (डॉ. कविता चौकसे) 125
46. भारत-पाक सम्बंधों में कड़वाहट की मुख्य जड़ - कश्मीर समस्या (डॉ. अनिल दीक्षित) 127
47. नारी शक्ति (डॉ. टी. एम. खान, प्रो. वीणा बरड़े) 129
48. महात्मा गांधी के समाजवादी विचार एक अध्ययन (डॉ. पी.के. चतुर्वेदी, डॉ. पुष्पलता मिश्रा) 131

(History / इतिहास)

49. An Analysis Of The Success Of Magadhan Imperialism (Upto The Reign Of Ashoka) 132
(Dr. Preeti Prabhat)
50. प्राचीन भारतीय वैदिक शिक्षण पद्धति (डॉ. नितिन सहारिया) 134
51. आदिम जन जातियों की स्वातंत्र्य चेतना (डॉ. ऊषा मिश्रा) 138
52. सन्त कालूदास (डॉ. मधुसूदन चौबे) 141

(Geography / भूगोल)

53. मन्दसौर जिले में दालों की कृषि : स्थानिक तथा कालिक अध्ययन (डॉ. अख्तर बानो) 143
54. रायगढ़ जिले के भौतिक परिदृश्य का भौगोलिक विश्लेषण (डॉ. कपूरचंद गुप्ता) 145

(Sociology / समाजशास्त्र)

55. Global Warming, An Unfortunate Truth (Girish Makwana, Dr. Shraddha Malviya) 147
56. घरेलू एवं कामकाजी जनजातीय महिलाओं की सामाजिक - आर्थिक समस्याऐं- एक विश्लेषणात्मक अध्ययन 150
(अलीराजपुर जिले के कट्ठीवाड़ा विकासखण्ड के विशेष संदर्भ में) (आई. एस. सस्त्यां)
57. बाल श्रमिकों की समस्या - एक समाजशास्त्रीय अध्ययन (डॉ. कल्पना कोठारी) 152
58. जनजातीय महिलाओं की समस्याएं एवं महिला सशक्तिकरण- एक विश्लेषणात्मक अध्ययन (अलीराजपुर जिले के 155
सोण्डवा विकासखण्ड के विशेष संदर्भ में) (दिलीप सिंह चौंगड)
59. सामाजिक विकास की अवधारणा एवं उसकी मुख्य चुनौतियॉं (प्रो. आई. एस. सस्त्या, डॉ. आर. सी. पान्टेल) 157
60. नैतिक मूल्यों के गिरावट में परिवार एवं समाज की भूमिका (डॉ. आर.सी. पान्टेल, प्रो. आई.एस. सस्त्या) 159
61. छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति - एक ऐतिहासिक परम्परा (डॉ. मंजू गायकवाड़) 160
62. आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य की समस्या - एक समाज शास्त्रीय अध्ययन ,छत्तीसगढ़ राज्य के संदर्भ में (डॉ. मंजू गायकवाड़) 162

(Psychology / मनोविज्ञान)

63. To Study The Effect Of Social Networking Sites On Wellbeing Among Adolescents 163
(Dr. Rashmi Singh, Dr. Shipra Lavania)
64. Population Density And Its Effect On Human Behaviour (Prof. Smita Jain) 167
65. वन्य जीव संरक्षण एवं प्रबंधन (सुधा शाक्य) 169
67. विद्यार्थियों हेतु नैतिक शिक्षा की उपादेयता (ज्योत्स्ना झारिया) 171

(English Literature / अंग्रेजी साहित्य)

68. T.S. Eliot's Use of the Upanishad in the Waste Land (Aparna Ray) 172
69. गुरूचरण दास के नाटक 'Larins Sahib' में पंजाब का राजनैतिक व सामाजिक परिदृश्य एवं एक अंग्रेज की दुविधा..... 175
(डॉ. मनीषा जोशी)

(Hindi Literature / हिन्दी साहित्य)

70. हिन्दी बाल कविता का विकास (डॉ. वन्दना अग्निहोत्री) 177
71. कबीर का समाज दर्शन (डॉ.अंजली सिंह) 180
72. आदिवासी संघर्ष और हिन्दी उपन्यास (डॉ. उमा त्रिपाठी) 182
73. नाटक आदमी की तकलीफ देह यात्रा है (डॉ. रत्नेश विष्वक्सेन) 184
74. ऐतिहासिक उपन्यासों की परम्परा और प्रासांगिकता लोक चेतना के विशेष संदर्भ में (डॉ. अमित शुक्ल) 186
75. भूमण्डलीकरण के दौर में हिन्दी साहित्य पर संचार क्रांति का प्रभाव (प्रीति कुमारी) 188
76. स्वातंत्रयोत्तर हिन्दी पत्रकारिता के विविध आयाम (डॉ. गुरविन्दर सिंह गिल) 190
77. लोक संस्कृति एक चिंतन (डॉ. प्रेमलता तिवारी) 192
78. प्रसाद और उनकी बिम्ब योजना (डॉ. शबनम खान) 194
79. निराला – एक प्रगतिशील कवि (सुमन मरावी) 196
80. पं0 कामताप्रसाद 'गुरू'– एक विलक्षण व्यक्तित्व (डॉ. अर्चना देवी अहलावत) 198
81. जीवन मूल्य और साहित्य एक संदर्भ (डॉ. एस. एस. राठौर) 200
82. जनजातियों में पति पत्नी गीत (निमाड़ के संदर्भ में) (डॉ. गुलाब सोलंकी) 202

(Law/ विधि)

83. Music Piracy And Copyright Protection (Poorva Jadhav) 204
84. Role Of Government In Protection And PreservationOf The Environment 206
(Dr. Anand Sharma, Dr. R. Sudhir)
85. National Commission For Scheduled Caste - An Overview (Poorva Jadhav) 208

(Education / शिक्षा)

86. Relationship Between Teachers' Trust In PrincipalAnd Teacher Burnout (Luxmi Nagar) 210
87. Study Habits Of XI Standard Of Arts, Commerce And Science Students (Suman,Dr. Satish Gill) . 213
88. Ancient, Medieval and Modern Education : A Comparison (Sangeeta Vashisth) 215
89. Continuous And Comprehensive Evaluation (CCE)(Bimlesh Yadav) 218
90. विद्यार्थियों की उपलब्धि अभिप्रेरणा एवं अधिगम पर नवाचार उपागमों का प्रभाव (डॉ. सुगन शर्मा, इति व्यास) 220
91. माध्यमिक स्तर के विकलांग बालक व बालिकाओं की शिक्षा के लिए किए गए शासकीय प्रयासों का मूल्यांकन 223
(बुरहानपुर जिले के संदर्भ में) (राजेश कुमार मौर्य)

92. ग्रामीण एवं शहरी बालक एवं बालिकाओं के शैक्षिक मूल्यों का तुलनात्मक अध्ययन (ज़ूली शुक्ला,डॉ. सुधा रिछारिया) 226

93. डॉ. जाकिर हुसैन का शिक्षा दर्शन तथा उसका वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर प्रभाव (डॉ. पंकज पारीक, पुष्पा ढ़ोल्या)228

(Physical Education / शारीरिक शिक्षा)

94. The Effect Of Training On Ability To Play Square Cut & Pull Shot 231
(Dr. Gajender Singh Saroha, Vineet Masih)

(Others / अन्य)

95. Indian Tourism And Hospitality Sector - Potential, Challenges & Government Initiatives 233
(Munish Ahlawat)

96. Public Building Drainage System-An Architectural View 237
(Prof. S. A. Deshpande, Prof. Kiran P. Shinde)

97. माखनलाल चतुर्वेदी एक पुण्य स्मरण (प्रो. सीमा कदम) 240

98. स्त्री शिक्षा कल आज और कल (डॉ. आशा शुक्ला) 242

99. श्रृद्धा की साधना से रामायण के रचयिता तक (प्रो. जी.एस. वास्कले) 244

100. Coalition Government in India (D.C. Chauhan) 245

नवीन शोध संसार एवं दिव्य शोध समीक्षा की ओर से हार्दिक बधाई

भारत में नारी उत्पीड़न और उत्थान पुस्तक का विमोचन करते हुए माननीय श्रीमान् अंतरसिंह आर्य, श्रम मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल समारोह में उपस्थित भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीमान् वीरा स्वामी, श्रीमान् छोटू चौधरी सभापति नपा, सेंधवा पुस्तक के सम्पादक डॉ . कृष्णासिंह मोरे, श्रीमान् मंगल मोरे, सह–सम्पादक श्रीमती सुनीता बेले, मोहित मोरे

****

क्षेत्रीय सम्पादक मण्डल अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय (Regional Editor Board- International & National) मानद्

(01) डॉ. मनीषा ठाकुर ..... फुल्टन कॉलेज, एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी, अमेरिका
(02) श्री अशोककुमार ..... एम्प्लॉयब्लिटी ऑपरेशन्स मैनेजर, एक्शन ट्रेनिंग सेन्टर लि. लन्दन, यूनाईटेड किंगडम
(03) प्रो. डॉ. सिलव्यू बिस्यू ..... वाईस डीन (वाणिज्य एवं प्रबन्ध) कृषि एवं ग्रामीण विकास महाविद्यालय, बूचारेस्ट, रोमानिया
(04) श्री खगेन्द्रप्रसाद सुबेदी ..... सीनियर सॉयकोलॉजिस्ट, पब्लिक सर्विस कमीशन, सेन्ट्रल ऑफिस, अनामनगर, काठमौंडू, नेपाल
(05) प्रो. डॉ. ज्ञानचंद खिमेसरा ..... प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.) भारत
(06) प्रो. डॉ. प्रमोद कुमार राघव ..... शोध निदेशक, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्व विद्यालय, जयपुर (राज.) भारत
(07) प्रो. डॉ. एन.एस.राव. ..... संचालक, जनार्दनराय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत
(08) प्रो. डॉ. अनूप व्यास. ..... (पूर्व) संकायाध्यक्ष, वाणिज्य, देवी अहिल्या विश्व विद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत
(09) प्रो. डॉ. पी.पी. पाण्डे ..... संकायाध्यक्ष, वाणिज्य (डीन), अवधेश प्रतापसिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत
(10) प्रो. डॉ. संजय भयानी. ..... अध्यक्ष, व्यवसाय प्रबंध विभाग, सौराष्ट्र विश्व विद्यालय, राजकोट (गुजरात) भारत
(11) प्रो. डॉ. प्रताप राव कदम ..... अध्यक्ष, वाणिज्य, शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खण्डवा (म.प्र.) भारत
(12) प्रो. डॉ. बी.एस. झरे . ..... प्राध्यापक वाणिज्य विभाग, श्री शिवाजी महाविद्यालय, आकोला (महाराष्ट्र) भारत
(13) प्रो. डॉ. राकेश शर्मा ..... अध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गुड़गांव (हरियाणा) भारत
(14) प्रो. डॉ. संजय खरे ..... प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग, शास. स्वशासी कन्या स्नात. उत्कृष्टता महा., सागर (म.प्र.) भारत
(15) प्रो. डॉ. आर.पी. उपाध्याय ..... परीक्षा नियंत्रक, शासकीय कमलाराजे कन्या स्वशासी स्नातकोत्तर महा., ग्वालियर (म.प्र.) भारत
(16) प्रो. डॉ. प्रदीप कुमार शर्मा ..... प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग, शासकीय हमीदिया कला एवं वाणिज्य महा., भोपाल (म.प्र.) भारत
(17) प्रो. अखिलेश जाधव ..... प्राध्यापक, भौतिकी, शासकीय जे. योगानन्दम् छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़) भारत
(18) प्रो. डॉ. कमल जैन ..... प्राध्यापक, वाणिज्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खरगोन (म.प्र.) भारत
(19) प्रो. डॉ.डी.एन. खड़से ..... प्राध्यापक, वाणिज्य, धनवते नेशनल कॉलेज, नागपुर (महाराष्ट्र) भारत
(20) प्रो.डॉ. वन्दना जैन ..... प्राध्यापक, हिन्दी, शासकीय कालिदास कन्या महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत
(21) प्रो. डॉ. हरदयाल अहिरवार ..... प्राध्यापक, अर्थशास्त्र, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शहडोल (म.प्र.) भारत
(22) प्रो. डॉ. शारदा त्रिवेदी ..... सेवानिवृत्त प्राध्यापक, गृहविज्ञान, इंदौर (म.प्र.) भारत
(23) प्रो. डॉ. उषा श्रीवास्तव ..... अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, आचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रेच्यूट स्टडी. सोलदेवानली, बैंगलुरू (कर्ना.) भारत
(24) प्रो. डॉ. गणेशप्रसाद दावरे ..... प्राध्यापक, वाणिज्य, शासकीय महाविद्यालय, बड़वाह (म.प्र.) भारत
(25) प्रो. डॉ. एच.के. चौरसिया ..... प्राध्यापक, वनस्पति, टी.एन.वी. महाविद्यालय, भागलपुर (बिहार) भारत
(26) प्रो. डॉ. विवेक पटेल ..... प्राध्यापक, वाणिज्य, शासकीय महाविद्यालय, कोतमा, जिला अनूपपुर (म.प्र.) भारत
(27) प्रो. डॉ. दिनेशकुमार चौधरी ..... प्राध्यापक, वाणिज्य, राजमाता सिन्धिया शासकीय कन्या महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा (म.प्र.) भारत
(28) प्रो. डॉ. आर.के. गौतम ..... प्राध्यापक ,वाणिज्य, शासकीय मानकुंवर बाई कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) भारत
(29) प्रो. डॉ. जितेन्द्र के. शर्मा ..... प्राध्यापक, वाणिज्य एवं प्रबंध, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय केन्द्र, पालवाल (हरियाणा) भारत
(30) प्रो. डॉ. आर.पी. सहारिया ..... प्राध्यापक, अर्थशास्त्र, शासकीय जे.एम.पी. महाविद्यालय तख्तपुर जिला,बिलासपुर (छ.ग.) भारत
(31) प्रो. डॉ. गायत्री वाजपेयी ..... प्राध्यापक, हिन्दी, शासकीय महाराजा स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.) भारत
(32) प्रो. डॉ. अविनाश शेन्द्रे ..... विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र, प्रगति कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, डोम्बीवली, मुम्बई (महाराष्ट्र) भारत
(33) प्रो. डॉ. जी.सी. मेहता ..... अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल वाणिज्य, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत
(34) प्रो.डॉ. बी.एस. मक्कड़ ..... अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल वाणिज्य, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत
(35) प्रो.डॉ. पी.पी. मिश्रा ..... विभागाध्यक्ष, गणित, छत्रसाल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पन्ना, (म.प्र.) भारत
(36) प्रो.डॉ. सुनील कुमार सिकरवार.... प्राध्यापक, रसायन, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, झाबुआ (म.प्र.) भारत
(37) प्रो.डॉ. के.एल. साहू..... प्राध्यापक, इतिहास, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नरसिंहपुर (म.प्र.) भारत
(38) प्रो.डॉ. मालिनी जॉनसन ..... प्राध्यापक, वनस्पति, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महू (म.प्र.) भारत
(39) प्रो.डॉ. विशाल पुरोहित ..... एम.एल.बी. शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, किला मैदान, इन्दौर (म.प्र.) भारत

सम्पादकीय सलाहकार मण्डल (Editorial Advisory Board, INDIA) मानद्

(01) प्रो. डॉ. नरेन्द्र श्रीवास्तव .....प्रसिद्ध वैज्ञानिक 'इसरो' बैंगलुरू (कर्नाटक) भारत
(02) प्रो. डॉ. आदित्य लूनावत .....निदेशक, स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल (म.प्र.) भारत
(03) प्रो. डॉ. संजय जैन .....सहायक नियंत्रक, म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल (म.प्र.) भारत
(04) प्रो. डॉ.एस.के. जोशी .....प्राचार्य, शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.) भारत
(05) प्रो. डॉ. जे.पी.एन. पाण्डेय .....प्राचार्य, शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (म.प्र.) भारत
(06) प्रो. डॉ. सुमित्रा वास्केल .....प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खरगोन (म.प्र.) भारत
(07) प्रो. डॉ. पी.आर. चन्देलकर .....प्राचार्य, शासकीय कन्या महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा (म.प्र.) भारत
(08) प्रो. डॉ. मंगल मिश्र .....प्राचार्य, श्री क्लॉथ मार्केट, कन्या वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत
(09) प्रो. डॉ.आर.के. भट्ट .....प्राचार्य, शासकीय महिला महाविद्यालय, नरसिंहपुर (म.प्र.) भारत
(10) प्रो. डॉ. अशोक वर्मा .....संकायाध्यक्ष, वाणिज्य (डीन) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत
(11) प्रो. डॉ. टी.एम. खान .....प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, धामनोद, जिला-धार (म.प्र.) भारत
(12) प्रो. डॉ. राकेश ढण्ड .....संकायाध्यक्ष, विद्यार्थी कल्याण विभाग विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत
(13) प्रो. डॉ. अनिल शिवानी.....अध्यक्ष, वाणिज्य एवं प्रबंध विभाग श्री अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत
(14) प्रो. डॉ. पद्मसिंह पटेल .....अध्यक्ष, वाणिज्य विभाग शासकीय महाविद्यालय, महिदपुर (म.प्र.) भारत
(15) प्रो. डॉ. मंजु दुबे.....संकायाध्यक्ष (डीन), गृह विज्ञान संकाय, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत
(16) प्रो. डॉ.ए.के. चौधरी .....प्राध्यापक, मनोविज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत
(17) प्रो. डॉ. प्रदीप सिंह राव .....प्राध्यापक एवं अध्यक्ष, राजनीति विभाग शासकीय महाविद्यालय, सैलाना, जिला-रतलाम (म.प्र.) भारत
(18) प्रो. डॉ. पी.के. मिश्रा .....प्राध्यापक ,प्राणी शास्त्र, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बैतूल (म.प्र.) भारत
(19) प्रो. डॉ. के. के. श्रीवास्तव .....प्राध्यापक ,अर्थशास्त्र, विजया राजे शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत

****

निर्णायक मण्डल (Referee Board) मानद्

✻✻✻ विज्ञान संकाय ✻✻✻

गणित:- .... (1) **प्रो. डॉ.वी.के. गुप्ता,** संचालक वैदिक गणित एवं शोध संस्थान, उज्जैन (म.प्र.)

भौतिकी:- .... (1) **प्रो. डॉ. आर.सी. दीक्षित**, शासकीय होल्कर विज्ञान महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)
(2) **प्रो.डॉ. रवि कटारे,** शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

कम्प्यूटर विज्ञान:- .... (1) **प्रो. डॉ. उमेश कुमार सिंह** अध्यक्ष कम्प्यूटर अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)

रसायन:- .... (1) **प्रो. डॉ. मनमीत कौर मक्कड़,** शासकीय कालिदास कन्या महाविद्यालय, उज्ज्रैन (म.प्र.)

वनस्पति:- .... (1) **प्रो. डॉ. सुचिता जैन,** राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोटा (राज.)
(2) **प्रो.डॉ. अखिलेश आयाची,** शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

प्राणिकी:- .... (1) **प्रो.डॉ. मंजुलता शर्मा,** एम.एस.जे., राजकीय महाविद्यालय, भरतपुर (राज.)
(2) **प्रो. डॉ. अमृता खत्री,** माता जीजाबाई शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मोती तबेला, इन्दौर (म.प्र.)

सांख्यिकी:- .... (1) **प्रो. डॉ. रमेश पण्ड्या,** शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.)

सैन्य विज्ञान:- .... (1) **प्रो. डॉ. कैलाश त्यागी,** शासकीय मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)

जीव रसायन:- .... (1) **डॉ. कंचन डींगरा,** शासकीय एम.एच. गृह विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

भूगर्भ शास्त्र:- .... (1) **प्रो. डॉ. आर.एस. रघुवंशी,** शासकीय मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)
(2) **प्रो. डॉ. सुयश कुमार,** शासकीय आदर्श महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)

चिकित्सा विज्ञान:- .... (1) **डॉ. एच.जी. वरूधकर,** आर.डी. गारड़ी मेडिकल महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)

✻✻✻ वाणिज्य संकाय ✻✻✻

वाणिज्य :- .... (1) **प्रो. डॉ. पी.के. जैन,** शासकीय हमीदिया महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)
(2) **प्रो. डॉ. शैलेन्द्र भारल ,** शासकीय कालिदास कन्या महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)
(3) **प्रो. डॉ. लक्ष्मण परवाल,** शासकीय वाणिज्य महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.)

✻✻✻ प्रबंध एवं व्यवसाय प्रशासन संकाय ✻✻✻

प्रबंध :- .... (1) **प्रो. डॉ. रामेश्वर सोनी** , अध्यक्ष अध्ययन शाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)
(2) **प्रो. डॉ. आनन्द तिवारी ,** शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर कन्या उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)

मानव संसाधन:- .... (1) **प्रो. डॉ. हरविन्दर सोनी**, पैसेफिक बिजनेस स्कूल, उदयपुर (राज.)

व्यवसाय प्रशासन:- .... (1) **प्रो. डॉ. कपिलदेव शर्मा ,** राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोटा (राज.)

✻✻✻ विधि संकाय ✻✻✻

विधि:- .... (1) **प्रो. डॉ. एस.एन. शर्मा,** प्राचार्य, शासकीय माधव विधि महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)
(2) **प्रो. डॉ. नरेन्द्र कुमार जैन,** प्राचार्य श्री जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर विधि महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.)

✻✻✻ कला संकाय ✻✻✻

अर्थशास्त्र:- .... (1) **प्रो. डॉ. पी.सी. रांका,** श्री सीताराम जाजू शासकीय कन्या महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.)
(2) **प्रो. डॉ. जे.पी. मिश्रा,** शासकीय महाराजा स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)
(3) **प्रो. डॉ. अंजना जैन,** एम.एल.बी. शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, किला मैदान, इन्दौर (म.प्र.)

राजनीति:- .... (1) **प्रो. डॉ. रवींद्र सोहोनी,** शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.)
(2) **प्रो. डॉ. अनिल जैन,** शासकीय कन्या महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.)
(3) **प्रो. डॉ. सुलेखा मिश्रा,** मानकुंवर बाई शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

दर्शनशास्त्र:- .... (1) **प्रो. डॉ. हेमन्त नामदेव,** शासकीय माधव कला-वाणिज्य-विधि महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)

समाजशास्त्र:- ..... **(1) प्रो. डॉ. एच.एल. फुलवरे,** शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धार (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. इन्दिरा बर्मन , शासकीय गृह विज्ञान महाविद्यालय, होशंगाबाद (म.प्र.)
(3) प्रो. डॉ. उमा लवानिया , शासकीय कन्या महाविद्यालय, बीना, जिला-सागर (म.प्र.)

हिन्दी:- ..... **(1) प्रो. डॉ. चन्दा तलेरा जैन,** अध्यक्ष अध्ययन मण्डल, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र)
(2) प्रो. डॉ. जया प्रियदर्शनी शुक्ला, वनस्थली विद्यापीठ (राज.)
(3) प्रो. डॉ. कला जोशी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)

अंग्रेजी:- ..... **(1) प्रो. डॉ. अजय भार्गव,** शासकीय महाविद्यालय, बड़नगर (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. मंजरी अग्निहोत्री, शासकीय कन्या महाविद्यालय, सीहोर (म.प्र.)

संस्कृत:- ..... **(1) प्रो. डॉ. भावना श्रीवास्तव,** शासकीय स्वशासी महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. बालकृष्ण प्रजापति, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गंजबासौदा जिला विदिशा (म.प्र.)

इतिहास:- ..... **(1) प्रो. डॉ. नवीन गिडियन,** शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)

भूगोल:- ..... **(1) प्रो. डॉ. राजेन्द्र श्रीवास्तव** शासकीय महाविद्यालय, पिपलियामण्डी, जिला मंदसौर (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. अर्चना भार्गव, शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

मनोविज्ञान:- ..... **(1) प्रो. डॉ. कामना वर्मा,** प्राचार्य, शासकीय राजमाता सिंधिया कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. सरोज कोठारी, शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इंदौर (म.प्र.)

चित्रकला:- ..... **(1) प्रो. डॉ. अल्पना उपाध्याय,** शासकीय माधव कला-वाणिज्य-विधि महाविद्यालय उज्जैन (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. रेखा श्रीवास्तव, महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)

संगीत:- ..... **(1) प्रो. डॉ. भावना ग्रोवर (कथक),** सुभारती विश्व विद्यालय मेरठ (उ.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. श्रीपाद अरोणकर, राजमाता सिन्धिया शासकीय कन्या महाविद्यालय, छिन्दवाडा (म.प्र.)

**** गृह विज्ञान संकाय ****

आहार एवं पोषण विज्ञान:- .... **(1) प्रो.डॉ. प्रगति देसाई,** शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इंदौर (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. मधु गोयल, स्वामी केशवानन्द गृह विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर (राज.)
(3) प्रो. डॉ. संध्या वर्मा, शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

मानव विकास:- ..... **(1) प्रो. डॉ. मीनाक्षी माथुर,** अध्यक्ष, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर (राज.)
(2) प्रो. डॉ. आभा तिवारी, अध्यक्ष अध्ययन मण्डल रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

पारिवारिक संसाधन प्रबंध:- ... **(1) प्रो. डॉ. मंजु शर्मा,** माता जीजाबाई शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मोती तबेला, इंदौर (म.प्र.)
(2) प्रो. डॉ. नम्रता अरोरा, वनस्थली विद्यापीठ (राज.)

**** शिक्षा संकाय ****

शिक्षा ..... **(1) प्रो. डॉ. मनोरमा माथुर,** प्राचार्य, अरावली शिक्षा महाविद्यालय, फरीदाबाद (हरियाणा)
(2) प्रो. डॉ. एन.एम.जी. माथुर, प्राचार्य एवं डीन पेसेफिक शिक्षा महाविद्यालय, उदयपुर (राज.)
(3) प्रो. डॉ. अर्चना श्रीवास्तव, बी.सी.जी. शिक्षा महाविद्यालय, देवास (म.प्र.)
(4) प्रो. डॉ. नीना अनेजा, प्राचार्य, ए.एस. कॉलेज ऑफ एजुकेशन,खन्ना (पंजाब)

**** आर्किटेक्चर संकाय ****

शारीरिक शिक्षा ..... **(1) प्रो. किरण पी. शिंदे ,** प्राचार्य, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, आई.पी.एस. एकडेमी, इंदौर (म.प्र.)

**** शारीरिक शिक्षा संकाय ****

शारीरिक शिक्षा..... **(1) प्रो. डॉ. अक्षयकुमार शुक्ला,** अध्यक्ष शारीरिक शिक्षा पेसेफिक विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.)

**** ग्रन्थालय विज्ञान संकाय ****

ग्रन्थालय विज्ञान ..... **(1) डॉ. अनिल सिरौठिया,** शासकीय महाराजा महाविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)

प्रवक्ता साथी (मानद्)

(01) प्रो. डॉ. आर.के. गुजेटिया .....शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.)
(02) प्रो. श्रीमती विजया वधवा .....शासकीय कन्या महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.)
(03) डॉ. सुरेंद्र शक्तावत .....ज्ञानोदय इंस्टीट्यूट ऑफ मेनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, नीमच (म.प्र.)
(04) प्रो. डॉ. देवीलाल अहीर .....शासकीय महाविद्यालय, जावद, जिला नीमच (म.प्र.)
(05) श्री आशीष द्विवेदी .....शासकीय महाविद्यालय, मनासा, जिला नीमच (म.प्र.)
(06) प्रो. डॉ. मनोज महाजन .....शासकीय महाविद्यालय, सोनकच्छ, जिला देवास (म.प्र.)
(07) श्री उमेश शर्मा .....कृष्णा शिक्षा महाविद्यालय, जावी, जिला- नीमच (म.प्र.)
(08) प्रो. डॉ. एस.पी. पंवार .....शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.)
(09) प्रो. डॉ. पूरालाल पाटीदार .....शासकीय कन्या महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.)
(10) प्रो. डॉ. क्षितिज पुरोहित .....जैन कला-वाणिज्य-विज्ञान महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.)
(11) प्रो. डॉ.एन.के. पाटीदार .....शासकीय महाविद्यालय, पिपलियामंडी, जिला मन्दसौर (म.प्र.)
(12) प्रो. डॉ. वाय.के. मिश्रा .....शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.)
(13) प्रो. डॉ. सुरेश कटारिया .....शासकीय कन्या महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.)
(14) प्रो. डॉ. अभय पाठक .....शासकीय वाणिज्य महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.)
(15) प्रो. डॉ. मालसिंह चौहान .....शासकीय महाविद्यालय, सैलाना, जिला रतलाम (म.प्र.)
(16) प्रो. डॉ. गेंदालाल चौहान .....शासकीय विक्रम महाविद्यालय, खाचरौद, जिला उज्जैन (म.प्र.)
(17) प्रो. डॉ. प्रभाकर मिश्र .....शासकीय महाविद्यालय, महिदपुर, जिला उज्जैन (म.प्र.)
(18) प्रो. डॉ. प्रकाश कुमार जैन .....शासकीय माधव कला वाणिज्य विधि महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)
(19) प्रो. डॉ. कमला चौहान .....शासकीय कालिदास कन्या महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)
(20) प्रो. डॉ.आभा दीक्षित .....शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)
(21) प्रो. डॉ. पंकज माहेश्वरी .....शासकीय महाविद्यालय, तराना, जिला उज्जैन (म.प्र.)
(22) प्रो. डॉ. डी.सी. राठी .....स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, इंदौर
(23) प्रो. डॉ. अनिता गगराड़े .....शासकीय होलकर विज्ञान महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)
(24) प्रो. डॉ. संजय पंडित .....शासकीय एम.जे.बी. कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मोती तबेला, इन्दौर (म.प्र.)
(25) प्रो. डॉ. रामबाबू गुप्ता .....शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)
(26) प्रो. डॉ. अंजना सक्सैना .....शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इंदौर (म.प्र.)
(27) प्रो. डॉ. सोनाली नरगुन्दे .....पत्रकारिता एवं जनसंचार अध्ययनशाला देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर (म.प्र.)
(28) प्रो. डॉ. भारती जोशी .....आजीवन शिक्षण विभाग देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)
(29) प्रो. डॉ. एम.डी. सोमानी .....शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महू, जिला इन्दौर (म.प्र.)
(30) प्रो. डॉ. प्रीति भट्ट .....शासकीस एन.एस.पी. विज्ञान महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)
(31) प्रो. डॉ. संजय प्रसाद .....शासकीय महाविद्यालय, सांवेर, जिला इन्दौर (म.प्र.)
(32) प्रो. डॉ. मीना मटकर .....सुगनीदेवी कन्या महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)
(33) प्रो. मोहन वास्केल .....शासकीय महाविद्यालय, थांदला, जिला - झाबुआ (म.प्र.)
(34) प्रो. डॉ. नितिन सहारिया .....शासकीय महाविद्यालय, कोतमा, जिला अनूपपुर (म.प्र.)
(35) प्रो. डॉ. मंजु राजोरिया .....शासकीय कन्या महाविद्यालय, देवास (म.प्र.)
(36) प्रो. डॉ. शहजाद कुरैशी .....शासकीय नवीन कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, मूंदी, जिला खण्डवा (म.प्र.)
(37) प्रो. डॉ. शैल वाला गौंधी .....महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)
(38) प्रो. डॉ. प्रवीण ओझा .....श्री भगवत सहाय शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)
(39) प्रो. डॉ.ओमप्रकाश शर्मा .....शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, श्योपुर (म.प्र.)
(40) प्रो. डॉ. एस.के. श्रीवास्तव .....शासकीय विजया राजे कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)
(41) प्रो. डॉ. अनूप मोघे .....शासकीय कमलाराजे कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)
(42) प्रो. डॉ. हेमलता चौहान .....शासकीय महाविद्यालय, बड़नगर (म.प्र.)
(43) प्रो. डॉ. महेशचन्द्र गुप्ता .....शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खरगोन (म.प्र.)
(44) प्रो. डॉ. मंगला ठाकुर .....शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वाह, जिला खरगोन (म.प्र.)
(45) प्रो. डॉ. के.आर. कुम्हेकर .....शासकीय महाविद्यालय, सनावद, जिला खरगोन (म.प्र.)
(46) प्रो. डॉ. आर.के. यादव .....शासकीय कन्या महाविद्यालय, खरगोन (म.प्र.)
(47) प्रो. डॉ. आशा साखी गुप्ता .....शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.)

(48) प्रो. डॉ. हेमसिंह मण्डलोई .....शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धार (म.प्र.)
(49) प्रो. डॉ. प्रभा पाण्डेय .....शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मैहर, जिला- सतना (म.प्र.)
(50) डॉ. राजेश कुमार .....शासकीय महाविद्यालय अमरपाटन, जिला-सतना (म.प्र.)
(51) प्रो. डॉ. रावेन्द्रसिंह पटेल .....शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सतना (म.प्र.)
(52) प्रो. डॉ. मनोहरलाल गुप्ता .....शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजगढ़ ब्यावरा (म.प्र.)
(53) प्रो. डॉ. मधुसुदन प्रकाश .....शासकीय महाविद्यालय, गंजबासोदा, जिला-विदिशा (म.प्र.)
(54) प्रो. युवराज श्रीवास्तव .....सी.वी. रमन विश्वविद्यालय, कोटा-बिलासपुर (छ.ग.)
(55) प्रो. डॉ. सुनील वाजपेयी .....शासकीय तिलक स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कटनी (म.प्र.)
(56) प्रो. डॉ. ए.के. पाण्डे .....शासकीय कन्या महाविद्यालय, सतना (म.प्र.)
(57) प्रो. डॉ. यतीन्द्र महोबे.....शासकीय महिला महाविद्यालय, नरसिंहपुर (म.प्र.)
(58) प्रो. डॉ. शशि प्रभा जैन .....शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, आगर-मालवा (म.प्र.)
(59) प्रो. डॉ. नियाज अंसारी .....शासकीय महाविद्यालय,सिंहावल, जिला सीधी (म.प्र.)
(60) प्रो. डॉ. अर्जुनसिंह बघेल.....शासकीय महाविद्यालय, हरदा (म.प्र.)
(61) डॉ. सुरेश कुमार विमल.....शासकीय महाविद्यालय, भैंसादेही, जिला बैतूल (म.प्र.)
(62) प्रो. डॉ. अमरचन्द्र जैन .....शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)
(63) प्रो. डॉ. रश्मि दुबे .....शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)
(64) प्रो. डॉ. ए.के. जैन .....शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बीना, जिला- सागर (म.प्र.)
(65) प्रो. डॉ. संध्या टिकेकर .....शासकीय कन्या महाविद्यालय, बीना, जिला- सागर (म.प्र.)
(66) प्रो. डॉ. राजीव शर्मा.....शासकीय नर्मदा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, होशंगाबाद (म.प्र.)
(67) प्रो. डॉ. रश्मि श्रीवास्तव .....शासकीय गृह विज्ञान महाविद्यालय, होशंगाबाद (म.प्र.)
(68) प्रो. डॉ. लक्ष्मीकांत चंदेला .....शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, छिंदवाड़ा (म.प्र.)
(69) प्रो. डॉ. बलराम सिंगोतिया .....शासकीय महाविद्यालय सौंसर, जिला-छिन्दवाड़ा (म.प्र.)
(70) प्रो.डॉ. विम्मी बहल.....शासकीय महाविद्यालय, काला पीपल, जिला - शाजापुर (म.प्र.)
(71) प्रो. डॉ. अमित शुक्ल.....शासकीय ठाकुर रणमतसिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
(72) प्रो. डॉ. मीनू गजाला खान .....शासकीय महाविद्यालय, मक्सी, जिला-शाजापुर (म.प्र.)
(73) प्रो. डॉ. पल्लवी मिश्रा.....शासकीय महाविद्यालय, नई गढ़ी, जिला- रीवा (म.प्र.)
(74) प्रो. डॉ. एम.पी. शर्मा .....शासकीय महाविद्यालय, दतिया (म.प्र.)
(75) प्रो. डॉ. जया शर्मा .....शासकीय कन्या महाविद्यालय, सीहोर (म.प्र.)
(76) प्रो. डॉ. सुशील सोमवंशी .....शासकीय महाविद्यालय, नेपानगर, जिला बुरहानपुर (म.प्र.)
(77) प्रो. डॉ. इशरत खान .....शासकीय महाविद्यालय, रायसेन (म.प्र.)
(78) प्रो. डॉ. कमलेशसिंह नेगी .....शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सीहोर (म.प्र.)
(79) प्रो. डॉ. भावना ठाकुर .....शासकीय महाविद्यालय रेहटी, जिला सीहोर (म.प्र.)
(80) प्रो. डॉ. केशवमणि शर्मा .....पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शाजापुर (म.प्र.)
(81) प्रो. डॉ. रेणु राजेश .....शासकीय नेहरु अग्रणी महाविद्यालय, अशोक नगर (म.प्र.)
(82) प्रो. डॉ. अविनाश दुबे.....शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खण्डवा (म.प्र.)
(83) प्रो. डॉ. वी.के. दीक्षित.....छत्रसाल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पन्ना (म.प्र.)
(84) प्रो. डॉ. राम अवेधश शर्मा .....एम.जे.एस. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भिण्ड (म.प्र.)
(85) प्रो. डॉ. मनोज कुमार अग्निहोत्री .....सरोजिनी नायडू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)
(86) प्रो. डॉ. समीर कुमार शुक्ला .....शासकीय चन्द्र विजय महाविद्यालय, डिण्डोरी (म.प्र.)
(87) प्रो. डॉ. आर.सी. पान्टेल.....शासकीय महाविद्यालय, धामनोद, जिला-धार (म.प्र.)
(88) प्रो. डॉ. अनूप परसाई.....शासकीय जे. योगानन्दन छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)
(89) प्रो. डॉ. अनिलकुमार जैन.....वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा (राज.)
(90) प्रो. डॉ. अर्चना वशिष्ठ .....राजकीय राजऋषि महाविद्यालय अलवर (राज.)
(91) प्रो. डॉ. कल्पना पारीख .....एस.एस.जी. पारीख पी.जी. कॉलेज, जयपुर (राज.)
(92) प्रो. डॉ. गजेन्द्र सिरोहा.....पेसिफिक विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.)
(93) प्रो. डॉ. कृष्णा पैन्सिया.....हरिश आंजना महाविद्यालय, छोटीसादड़ी, जिला- प्रतापगढ़ (राज.)
(94) प्रो. डॉ. प्रदीप सिंह .....केंद्रीय विश्व विद्यालय हरियाणा, महेंद्रगढ़ (हरियाणा)
(95) प्रो. डॉ. स्मृति अग्रवाल .....शोध सलाहकार, नई दिल्ली

Screening Of Coliforms From Drinking Water Supplied In Various Area Of Ahmedabad

Dr. Dilip Zaveri * Anurag Zaveri ** Avani Zaveri * Archana Patel ****

Abstract - Water is a fundamental requirement for good health in any community is the availability of a safe domestic water supply. An adult human need at least 1.5 liters of water a day to replace fluid loss. Waterborne infections and outbreaks are usually associated with contaminated and poor quality of drinking water. Most intestinal (enteric) diseases are infectious and are transmitted through fecal waste. Among waterborne pathogens: Bacteria (e.g. cholera, typhoid, coliform organisms); Viruses (e.g. hepatitis A, poliomyelitis); Protozoa (e.g. cryptosporidiosum, amebae, giardia); Worms (e.g. schistosomia, guinea worm); and Toxins (e.g. arsenic, cadmium, numerous organic chemicals) are disease producing agents found in water. In the present study we collected 25 (83.30%) were samples from urban residential supplies and 5 (16.66%) were from slums. We found that the coliform count is very high in residential indicating the mixing of sewage like with drinking water line or a like chance.
Keywords- Drinking water, Water borne disorders, Ahmedabad, E. coli, Biocare.

Introduction - Worldwide, approximately 140 million people develop dysentery each year, and about 6,00,000 die. Most of these deaths occur in developing countries among children under age five. In the United States, only about 25000 to 30000 cases occur each year [1].Water is a fundamental requirement for good health in any community is the availability of a safe domestic water supply.An adult human need at least 1.5 liters of water a day to replace fluid lost by urine, sweat, and respired air and to perform essential biochemical functions. Almost 90% of body mass is water. Water is an important component of metabolic process and serves as a solvent for many bodily solutes. Water, however, may carry dangerous pathogens and toxic chemicals into the body. In most developed countries, quite safe water supplied to household, commercial areas, industries, food preparations. Waterborne infections and outbreaks are usually associated with contaminated and poor quality of drinking water.

Water also harbors the intermediate stages of many parasites, either as free living larvae or in some other form, and it is the vehicle for essential stages in the life cycle of many dangerous insects vectors, notably mosquitoes and black flies.Diarrhea is the major syndrome associated with such infection and out breaks among children, being most commonly affected particularly in developing countries. It is important to note that not only drinking water, but also water used for cleaning fruits, vegetables, and cooking utensils, and for washing can convey diseases. Indeed, salads that have been washed in polluted water are a frequently overlooked and rather are a common source of waterborne disease, responsible for an occasional outbreak of cholera or typhoid.Waterborne diseases are caused by pathogenic microorganism that most commonly are transmitted in contaminated fresh water. Infection commonly results during bathing, washing, drinking, in the preparation of food or consumption of food thus infected.

Most intestinal (enteric) diseases are infectious and are transmitted through fecal waste. Among waterborne pathogens: Bacteria (e.g. cholera, typhoid, coliform orgasims); Viruses (e.g. hepatitis A, poliomyelitis); Protozoa (e.g. cryptosporidiosum, amebae, giardia); Worms (e.g. schistosomia, guinea worm); and Toxins (e.g. arsenic, cadmium, numerous organic chemicals) are disease producing agents found in water. These diseases are more prevalent in areas were poor sanitary conditions, are prevailing. These pathogens travel through water sources and interfuses directly through persons handling food and water.Stagnant water and other untreated water provide a habitat for the mosquito and a host of other parasites and insects that cause a large number of diseases especially in the tropical regions.Coliforms are bacteria that are always present in the digestive tracts of animals, including human and are found in their excretory waste. They may also be found in plant and soil material. Condition under which drinking water may get contaminated is likely to be enriched into it, the types of disease they transmit.Total coliform, fecal coliform group is large collection of different kinds of generally harmless bacteria typically found in the environment.

* Director, Biocare Research (I) Pvt. Ltd, Ahmedabad (Gujarat) INDIA
** Research Assistant, Biocare Research (I) Pvt. Ltd, Ahmedabad (Gujarat) INDIA
*** Research Assistant, Biocare Research (I) Pvt. Ltd, Ahmedabad (Gujarat) INDIA
**** Research Assistant, Biocare Research (I) Pvt. Ltd, Ahmedabad (Gujarat) INDIA

Since these diseases are highly infectious, extreme care and hygiene should be maintained by people looking after an infected patient. Hepatitis, cholera, dysentery, and typhoid are the more common waterborne diseases that affect large populations in the tropical regions. Various salts present in soil makes the fresh water unusable for drinking and irrigation purposes.A four year epidemic in Central America, starting in 1968, resulted in more than 500000 cases and more than 20,000 deaths. Since 1991, dysentery epidemics have occurred in eight countries in Southern Africa.

In the present study we collected 25 (83.30%) were samples from urban residential supplies and 5 (16.66%) were from slums. We found that the coliform count is very high in residential indicating the mixing of sewage like with drinking water line or alike chance. Chatterjee, S.N. (2007), reported no coliform in municipal tap water, supplied to marked area of Burdwan. However, in the present study we have found out of 25 residential water samples 19 samples were positive the average coliform count of residential area 70 CFU / ml where in slum area 10 CFU / ml. as per the Central Pollution Control Board (CPCB) India total coliform organisms 100 ml shall be 10 ml of drinking water source. However in our water sample we found residential area water supply unfit for drinking purpose.

Materials and Methods -

Materials used -

Media used were - Brilliant green lactose broth, Hi Chrome agar, MacConkey Agar, MacConkey Broth (Double strength and single strength), MR broth, 1% peptone, Simon Citrate agar slant, Reagents used were: Acetic Acid, $FeCl_3$, Kovac's Reagent, Methyl Red, Instruments used were: Autoclave, Incubator, Laminar Air Flow, Micropipettes with Fixed and variable volume, Weighing balance, miscellaneous glass wares like test tubes, pipettes, flasks, Durham's vials along with miscellaneous consumables like gloves, micropipette tips etc…

All the reusablewas autoclaved using proper autoclaving method and was validated with the chemical as well as biological spore strips.

Method followed for sample collection: Samples were collected in pre sterilized 100 ml glass bottles.

Isolation of coliform - (See in the lasst page)

Presumptive Test - Principle: The presumptive test is specific for detection of Coliforms bacteria. Aliquots of the water to be tested are added to a lactose fermentation broth containing Durham's vial. The detection of bacteria capable of using lactose as a carbon source is facilitated by use of this medium. Additionally, this medium also contains bile salt that suppresses the growth of organisms other than coliforms. The coliforms present in the sample will ferment lactose and produce gas bubbles which can be observed in the Durham's vial.

Most Probable Number dilution series:

There are three sets of tubes and three tubes in each set.

- Each tube in the first set of double strength broth receives 10 ml of sample.
- Each tube in the second set of single strength receives 1 ml of sample.
- Each tube in the third set of single strength receives 0.1 ml sample.

Procedure -

- Make double strength and single strength Mac conkey broth.
- Inoculate 10 ml of sample in three double strength broth and 1 ml and 0.1 ml in six single strength broths.
- Incubate all tubes at 37°C for 24 to 48 hours.
- Record the positive tubes after 48 hours of incubation.
- Criteria for positive and negative tube calculation.

Positive - Acid and gas production in the tube

Negative - Only Acid production without gas production or No Acid and no gas production in the tubes considered as negative.

- Number of positive tubes compared with McCardy's table and probable number of coliforms were obtained.

Biochemical tests - Biochemical tests were carried out to identify the isolated organism viz:Indole production test, Methyl Red test, Vogusproskauer test, Citrate production test, Hi-Chrome test etc…

All the other tests were conventional biochemical test except for the Hi-Chrome test thus description of Hi-Chrome test is given:

Principle - The chromogen mix consists of artificial substrates (chromogens), which release differently colored compounds upon degradation by specific enzymes. This permits the differentiation of certain species, or the detection of certain groups of organisms, with only a minimum of confirmatory tests. Chloramphenicol inhibits most bacterial contaminants.

Colors produced by the organisms -

Green: Enterobacter spp.

Pink Magenta: E. coli

Procedure - A loopful suspension was inoculated from suspension made aseptically rom MacConkey agar plate, same was incubated at 37°C for 24 hours, results were noted down using colony pigment as discussed in the principle each and every organism gives different color after series of biochemical processes.

Results -

Table 1 Distribution of residential area and slum area from total number of sample

Total No. of Water Sample	No. of Residential Area	No. of Slum Area
30	25 (83.3%)	05 (16.66%)

Table 1 indicates that out of 30 water sample, 25 (83.3%) samples are of residential area and 5 (16.66%) samples are from slum area.

Table 2 (See in the last page) - Table 2 indicates that from the examination of 25 residential water, only 19 (76%) samples showed the presence of coliform, while 6 (24%) samples show the absence of coliform. 19 water samples were positive and the average coliform count of residential area was found to be 70 CFU / ml.

Table 3 (See in the last page) - Table 3 indicates that from the examination of 5 slum water sample, only 2 (40%) samples showed the presence of coliform, while 3 (60%) samples showed the absence of coliform. 2 water samples were positive, the average coliform count of slum area was found to be 10 CFU / ml.

Table 4 Distribution of isolated bacterial strain

Total No. of Bacterial Strain	Isolated bacterial Stain	No. of isolated bacterial strain
23	Enterobacter spp.	14 (60.86%)
	Pseudomonas sppp.	5 (21.73%)
	E. coli	4 (17.39%)

Table 4 indicates that the number of isolated bacterial strain were Enterobacter spp. 14 (60.86%), Pseudomonas spp. 5 (21. 73%) and E. coli 4 (17.39%).

Table 5 Distribution of positive water sample and negative water sample (By MPN method)

Total No. of Water Sample	No. of Positive MPN & Negative MPN	
30	Positive sample	Negative sample
	21 (70%)	09 (30%)

Table 5 indicates that from the examination of 30 municipal water sample, only 21 (70%) samples showed the presence of coliform, while 9 (30%) sample showed the absence of coliform.

Table 6 Distribution of positive confirmatory and negative confirmatory results in each MPN positive water sample

Total No. of Positive MPN Sample	No. of confirmatory positive and negative result of water sample	
21	Positive sample	Negative Sample
	17 (80.95%)	04 (19.05%)

Table 6 indicates that out of 21 MPN positive samples, only 17 (80.95%) samples showed growth of coliform, while 4 (19.05%) shows the absence of coliform.

Table 7 - (See in the last page) - Table 7 indicates that out of 17 positive samples Enterobacter spp. and Pseudomonas spp. were isolated as single organism in 10 samples (58.84 %) and 2 samples (11.76%) respectively. Where as two organisms were isolated in 4 samples consisting E. coli + Enterobacter spp. in 2 samples (11.76%), Pseudomonas spp. and Enterobacter in 1 sample (5.88%) and Pseudomonas spp. + E. coli in 1 sample (5.88%). All three organisms were isolated in single sample (5.88%).

Discussion and Conclusion - The four genera Escherichia spp., Klebsiella spp., Enterobacter spp. and Citrobacter spp. are generally accepted as comparing the total coliform population[2]enumeration of these total component of the microbial aquatic ecosystem has been universally applied to document the sanitary quality of water. In the present study we are reporting that out of 30 water sample tested for bacterial presence 17 (80.90%) water sample shows presence of different bacteria. Out of 17 positive water samples 23 different bacterial strains were isolated. Further to these 23 strains isolated 78% were coliform group of bacteria. 4 (17.34%) were E. coli and 14(60.86%) were Enterobacter spp. We did not find Citrobacter spp. and Klebsiella spp. in any of the samples tested. T. M. EVANS, et al (1981) has reported that 86% of isolates were identified as member of Enterobacteriace group. In their study they tested total 695 E. coli isolated. Out of these 695 E. coli was recovered at greater sequences.

In addition to the quantitative impact of suppression on coliform enumeration, other factors influence the qualitative recovery of the component coliform genera. It has been illustrated with polluted specimens that the kind of water examined (sewage, un chlorinated sewage effluent, surface water), as well as media and technique, will affect the isolated frequency of the four coliform genera[1,4]. Treatment of raw water may also influence the percentage distribution of component coliform genera found. Clark and Pagel reported that the percentage of Escherichia found in the component genera of contaminated drinking water sample was reduced compared to the un treated surface water source[2]. Chlorination has been reported by others to increase the percentage of Klebsiella spp. in the component coliform genera isolated from drinking water sample[5].

Water pollution causes a number of diseases like diarrhea, jaundice, typhoid, etc... according to rough estimates, more than 15 million deaths world wide result annually from water borne infection [6]. During the past two decades the quality of drinking water has undergone radical changes[7,8]. The surface water sources, in general, are not acceptable for drinking purpose as these are often loaded by various organic, inorganic and biological constituents [9,10]. The coliform group consist of several genera of bacteria in the family Enterobacteriaceae that include animal E. coli. E. coli is a normal inhabitant of the intestinal tract of humans and other warm blooded and is thus regarded as the fecal type of coliform[6]. E. coli is regarded as the most sensitive indicator of fecal pollution. The large numbers of E. coli present in the gut of humans and other warm blooded animals and the fact that they are not generally present in other environments support their continued use as the most sensitive indicator of fecal pollution available [11].

Chatterjee S. N. (2007), studied bacteriological examination of drinking water with reference to coliform. They perform MPN test in water sample collected from mobile vendor, sweet shops and tap water supplied from Burdwan Municipality. Study revealed there was more than 16000 CFU / ml coliform in water samples collected from mobile vendors. They identified E. coli as a major coliform group of water.

In the present study we collected 25 (83.30%) were samples from urban residential supplies and 5 (16.66%) were from slums. We found that the coliform count is very high in residential area (290 CFU / ml in water collected from Vejalpur area. Chatterjee, S.N. (2007), reported no coliform in municipal tap water, supplied to marked area of Burdwan. However, in the present study we have found out of 25 residential water samples 19 samples were positive the average coliform count of residential area 70 CFU / ml where

in slum area 10 CFU / ml. as per the Central Pollution Control Board India total coliform organisms 100 ml shall be 10 ml of drinking water source after disinfection. However in our water sample we found residential area water supply unfed for drinking purpose.

- Municipal drinking water supply in residential and slum areas of Ahmedabad shows inacceptable coliform count.
- MPN is very good tool to find out quality of drinking water.

References:-

1. W. Luckin, M. A. M.Sc., (1866), The final castrophe-cholera in London. History and Social Studies of Science, University of SUSSEX, Falmer, Brighton, Sussex.
2. Clark, J. A., and J. E. Pagel, (1977), Pollution Indicator bacteria associated with Municipal raw and drinking water supplies. Can. J. of Microbial. 23:465-470.
3. T. M. EVANS, M. W. LECHEVALLIER, C. E. WAARVICK and RAMON J. SEIDLER, Department of Microbiology.
4. Dutka B. J., and Tobin S. E. (1976). Study on the efficiency of four procedures for enumerating coliforms in water. Can. J. Microbial. 22:630-635.
5. Ptak, D. J. W. Ginsburg, and B. F. Willey, 1973. Identification an incidence of Klebsiella in chlorinated water supplies. J. Am. Works Assoc. 65:604-608.
6. Atlas R. M., and Bertha R., 1997. Microbial ecology-fundamentals and applications. Benjamin/commings science publishing. Pp. 01-694.
7. Katayal and Rajkumar, 1991. Environment pollution. Anmol Publication, New Delhi. Pp. 54-63.
8. Kudesia V. P., 1990. Water pollution, 3rd revised edn. PragatiPrakashan. Meeruy. Pp. 84-102.
9. KumarjiBagavathiraj, 1996. Physicochemical and Microbiology aspects Courtallam water. Poll. Res. 15(2):159-161.
10. Dahiya's, Kaur A., 1999. Assessment of physic – chemical characteristics of underground water in rural areas of Tasham subdivisions, Bhivani District, Haryana. Enviro. J. poll. 6(4):281-288.
11. Edberg S. C., Rice E. W., Karlin R. J., Allen M. J., 2000. Escherichia coli: the best biological drinking water indicator for public health protection. J. Appl. Microbiol. Symp. Suppliment. 88:116-281.
12. Chatterjee S. N. 2007. Find the reference as it is not written in the Thesis.

Isolation of coliform -

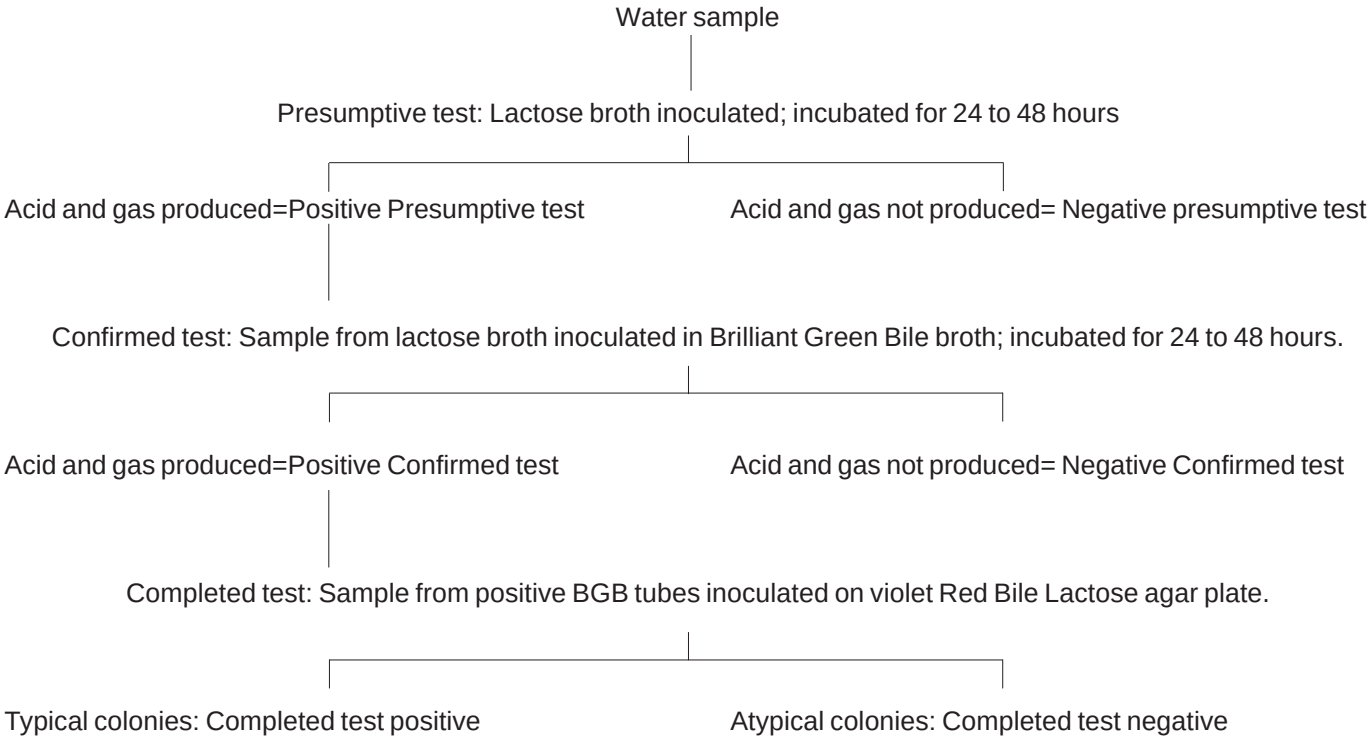

Table - 2 - Distribution of Negative water sample and positive water sample from 25 residential water sample and also find out the average of MPN test result (CFU/ml) from positive sample

Total No. of samples from residential Area	No. of Negative MPN sample	No. of Positive MPN Sample	Average of MPN Test Result (CFU/ml)
25	6(24%)	19 (76%)	70 CFU / ml

Table - 3 - Distribution of Negative water sample and positive water sample from 5 slum water sample and also find out the average of MPN test result (CFU/ml) from positive sample

Total No. of samples from slum Area	No. of Negative MPN sample	No. of Positive MPN Sample	Average of MPN Test Result (CFU/ml)
5	3 (60%)	2 (40%)	10 CFU / ml

Table 7 Distribution of Enterobacter spp. isolated from positive confirmatory municipal water sample

Total No. of Positive Confirmatory Sample	Organisms isolated					
	Enterobacter Spp.	Pseudomonas spp.	E. coli + Enterobacter spp.	Pseudomonas as spp. + Enterobacter spp.	Pseudomonas as spp. + E. coli	Pseudomonas spp. + Enterobacter spp. + E. coli
17	10 (58.84%)	2 (11.76%)	2 (11.76%)	1 (5.88%)	1 (5.88%)	1 (5.88%)

****

Study Of Physico Chemical Properties Of Narmada River , West Nimar, M.P. - With Special Reference To Pollution Status

Dr. Darasingh Waskel *

Abstract - The physico-chemical characteristics of Narmda River west Nimar (M.P.) have been studied. River Narmada is one of the 13 prominent rivers of India, which covers 98,797 sq km of total water shed. Narmada is considered to be the life line and west flowing river of the state of M.P.. The study of water quality of Narmada river was seasonally carried out for two years 2012 and 2013. Five sampling stations were selected at downstream of Mandleshwar city. The water samples collected were analyzed , as per standard methods of APHA (2005). obtained result were compared with standard values laid down by various agencies BIS(1991) and WHO (1992). The study was conducted based on their water source, phytoplankton community and origin of pollution such as utilization by human and animals. In this study the temperature Transparency Turbidity P^H , conductivity Dissolved oxygen, BOD and COD. The numerical relationship between species populations and communities of ten provide better and reliable indication of pollution than single species (Datta Munshi and Datta Munshi , 1995)
Key Word - Narmada River, Physico-chemical Properties , Pollution.

Introduction - Water is an important constituent of all living organisms and basic needs of human beings. Rivers have always been the most important fresh water resources and most development activities are still dependent upon them. Rivers play a major role in assimilating or carrying industrial and municipal waste water , manure discharge and runoff water form agriculture field , road ways and streets which are responsible for river pollution (Ward and Elliot , 1995). Pollution of surface and ground water is largely a problem due to rapid urbanization and industrialization. River pollution in India has now reached to a point of crisis due to unplanned urbanization and rapid growth of industrialization. The problem of water quality deterioration is mainly due to human activities such as disposal of dead bodies , discharge of industrial and sewage wastes and agriculture run off which are major causes of ecological damage and pose serious health hazards (Meitei et al. 2004).

The nature of rivers and their communities are determined by climate, vegetation and human activities (Johal, M.S, 2005). The degree of pollution generally assessed by studying physical and chemical characteristics of the water bodies (Duran and Suicnz, 2007). Studies related to water pollution of rivers like Betwa (Datar and Vashishtha , 1992, Ganga (Pandey , 1985 Singh et al . 1999, Sahu et al . 2000 and Khan, 2002), Godawari (Rao, 1993, Rafeeq and Khan , 2002) Yamuna (Meenakshi et al., 2002), Narmada (Sharma, et al. 2011).

Material And Methods - The river Narmada is the largest west flowing river of the country which originates from an elevation of 1051m. in Maikala highlands near Amarkantak under Shahadol district M.P. at 2240 N latitude and 8145 E longitude (Alvares and Billorey , 1988). The river ,after traversing 1312 km from its origin joins the "Gulf of combay " at 1312 km point. The stretch of river Narmada undertaken for present work is about 65 km downstream from Mandleshwar city. The water samples were collected from the river Narmada water from five selected stations I (Mandleshwar), II (Maheshwar), III (khalghat), IV (Dharmapuri) , V (Semalda). The seasonally (Rainy, winter and summer) during 2012 & 2013 at were collected each seasons early hours of the day i.e. between 7 am to 9 am. Same of the physico-chemical parameters of water including water temperature, transparency $P^{H,}$ dissolved oxygen, conductivity etc. were determined at the sampling stations, while other parameters including Turbidity BOD and COD were analyzed in the laboratory within 4 to 6 hours of collection. The physico-chemical characteristics of water were analyzed according to the methods of APHA (2005) and Trivedy and Goel (1984)- Obtained results were compared with standard values laid down by various agencies BIS (1991) and WHO (1992).

Results And Discussion - The obtained values of different selected pollution parameters have been tabulated in table 1 and table 2 with compared their respective limits. I representing the pollution load at Narmada river, west Nimar (MP)

Transparency - Transparency has direct bearing on the light penetration of water and depends upon suspended matter and dissolved coloured substances. The higher values were recorded during winter season , whereas lower values were

*Deptt. of Zoology, Maharaja Bhoj Govt. P.G. College, Dhar (M.P.) INDIA

found in Rainy season. Shrivastava and Patil (2002). reported a Transparency of 100-165 cm during winter and 80-125 cm during summer, while during post mansoon period it was 17-24 cm in Narmada river for the stretch Sandia to Mola. Transparency of a river water is also affected due to total solids partly of fully decomposed organic matters, silts and turbulence caused by the currents, waves, human and cattle activities (Singh el al 1999). The transparency values were less in rainy season due to high current which erodes the bank of the river and due to turbid flood water , suspended matter and dissolved particles.

Temperature - Temperature is basically important for its effects or certain chemical and biological reactions taking place in water and aquatic organisms (Shrivastava and Patil, 2002). The low water temperature was recorded in winter , while highest value was recorded in summer season. Similar seasonal variation in water temperature was recorded Nath and Shrivastava (2001) in river Narmada, Meitei et al. (2004) in river Purna.

Turbidity - Turbidity of water is an important parameter, which influences the light penetration. The turbidity minimum values was recorded in winter, 20.0 NTU while, highest 27.0 NTU was recorded in rainy season. Similar seasonal variation in Narmada river was recorded (Sharma et.al. 2011). In the present investigation, turbidity values of Narmada river water samples were found to be higher than that of the standard permissible limit BIS (1991) and WHO (1992). The maximum turbidity values was recorded in rainy season due to the mixing of runoff water and minimum in winter & summer due to the settlement of particals.

PH:

PH is an important parameters which is important in evaluating the acid-base balance of water. The PH of Narmada river water samples were found to be higher 8.3 mg/l in summer season while , lower values 7.0 in the rainy season. The BIS limits of PH for drinking water are 6.5 to 8.5. In the present investigation PH values of all water samples were found to be higher than that of the standard permissible limit BIS (1991) & WHO (1992). It may be due to the probable dissolution of CO_2 and decay of organic material in the Narmada river . Ellis (1937). has observed that a PH range of 6.7 to 8.4 is suitable for the growth of aquatic biota.

Conductivity - Conductivity is the measure of capacity of a substance or solution to conduct electrical current through the water. EC is an excellent indicator of TDS, which is a measure of salinity that effects the taste of potable water. The conductivity of river Narmada water samples were found to be lowest value 270 µ mhos/cm in rainy season and highest value 364 µ mhos/cm in summer seasonal all the stations. Saksena et al. (2008) studied the conductivity of river Chambal, lowest conductivity of 145.60 µ mhos/cm in the month of september and highest conductivity of 884 µ mho/cm in the month of may.

Dissolved Oxygen - Dissolved oxygen is one of the important parameter in water quality assessment. DO in natural and waste water depends on the physical, chemical and biological activities in the water body. The WHO (1992). suggested the standard permissible limit of DO is > 5.00 mg/l. In the present investigation the minimum values to DO was found to be 5.6 mg/l in rainy season while. the higher values of DO was recorded as 10.2 mg/l in winter season. Similar observed was recorded by Bhatt et.al.(2001), good amount of DO in Krishna river delta indicating good health and suitability for human purpose. Singh and Rai (1999). in river Ganga, Hiware and Jadhav (2001). in river Manjar, Rafeeq and Khan (2002). in river Godavari. The high value DO was found at minimum puring of discharge sewage effluent from city and low value found where the higher sewage discharge and human activity were taking station.

Biological Oxygen Demand -BOD is an important parameter which is widely used to determine the pollution load of waste water. The aim of BOD test is determine the amount of biochemically ox disable carbonaceous matter (Gupta et al., 2003). In the present investigation of water samples BOD, the minimum value was recorded 3.4 mg/l in winter season while, the maximum values recorded was 8.4 mg/l in summer season. The observed BOD value higher might be due to the biological activities at elevated temperature. Low BOD value in the winter season indicated poor biological activity of microorganisms at low temperature. Forkmare and Musaddiq (2002). recorded high value of BOD in Purna river and concluded that the river is highly polluted due to organic enrichment . Higher level of BOD was observed by Tiwari et al. , (2005), this may be due to sewage contamination in river Ganga at Bihar. Kulshreshtha and Sharma (2006), recorded BOD exceeded the permissible limit during the mass bathing in river Ganga at Haridwar. Saksena et al., (2008), observed BOD ranged between 0.60to 5.67 mg/l in Chambal river and suggested that this stretch of the river was free from organic pollution.

Chemical Oxygen Demand - COD test is measure of the oxygen required for chemical oxidation of organic matter and pollution of domestic waste and industrial waste. This gives valuable information about the pollution potential of industrial effluents and domestic sewage (Gupta et al., 2003). In the present investigation water samples, maximum value of COD, 37 mg/l during winter season while, the minimum value recorded was 22.0 mg/l during summer season. COD value of water samples were found to be higher than that of the limit of WHO (1992) and BIS (1991). It may be due to the higher COD values , indicated organic and inorganic pollution that the requires more oxygen to oxidize under increase thermal condition. Pillay, T.V.R. (2004), evident higher COD value due to organic matter discharged by Fish farms and other sources like sewage. Tiwari et al., (2005), observed high level of COD in river at various places of Bihar mainly due to raw sewage, municipal waste, industrial effluents and anthropogenic disturbances. Singh et al., (2007), In Gomati river at Sultanpur the COD is indicative of pollution in the river.

Conclusion - On the basis of physico-chemical

parameters studied, Narmada river in this stretch can be placed under oligosaprobic. Obtained results were compared with standards agencies BIS (1991) and WHO (1992). The major sources of pollution are local anthropogenic activities, agriculture runoff and by industrial effluents. In the present study it was found that few of the Narmada river water samples, maximum permisible limits BIS and WHO, due to heavy mixing of effluent waste and domestic sewage. It was found that the parameters indicates balances of the river Narmada was disturbed.

Table – 1 (See in the last page)

Seasonal Variation Of Physico-Chemical Parameters In Narmada River West Nimar M.P. **During – 2012**

Table – 2 (See in the last page)

Seasonal Variation Of Physico-Chemical Parameters Of Narmada River West Nimar M.P. **During – 2013**

References :-

1. Akuskar, S.K., Gaikwad, A.V. (2006). Physico-chemical analysis of Manjara dam back water of Manjara river Dhanegoan, Maharashtra. India. Ecol. Environ. and Conserv. 12(1):73-74
2. APHA (2005) : standard method for examination of water and waste water. 21st edn., Washington, D.C.
3. Begum, A. and Harikrishna (2008). Study of the quality of water in some treams of Cauvery river in J. Chem., Environ. 2(5):377-384
4. Begum, A., Ramaiah, M., Harikishana, Irfaanulla Khan and veena K. (2009). Heavy metal pollution and chemical and profile of Cauvery river water. J. chem., 6(1):47-52.
5. Bhaskar, B., Mukherjee, S., Chakraborty, R. and Nanda, A.K. (2003). Physico – chemical and bacteriological investigation on the river Torsa of North Bengal. J. Environ. Biol., 24: 125-133.
6. Bhatt, J.P., Jain, A, Bhaskar, A. and Pandit, M.K. (2001). Pre-impoundment study of biotic communities of Kishtobazar nala in purulia, west Bengal. curr. Sci. 81(10): 1332-1337.
7. BIS, 10500(1991), specification for drinking water quality, Indian standard institute New Delhi P.P. 1-4.
8. Datar, M.O. and R.P. Vashishtha (1992) : Physico-chemical aspects of pollution in river Betwa. Ind. J. Environ. Protect. 12, 577-580
9. Ellis, M.M. (1937): Detection and measurement of stream pollution. U.S. Bur. Fish. Bull. Washington, 22, 367-437
10. Fokmare, A.K. and M. Musaddiq (2002) : A study of Physico-chemical characteristics of Kapsi lake and Purna river waters in Akola district of Maharashtra, India. Nat. Environ. Pollut. Technol., 1, 261-263
11. Ghosh T.K. Shakila B. and Kaul S.N., (2004) protection of ecologically sensitive areas: origin of rivers and upper catchment areas, J. of Indian Association for Enviro. Management, Vol. 31, 59-64
12. Gupta, S.M. Bhatnagar and R Jain, (2003): Physico-chemical characteristics and analysis of Fe and Zn in tubwell water and sewage water of Bikaner city. Asian J. Chem. , 15:727.
13 Hiware, C.J. and B.V. Jadhav (2001): Biological studies of Manjar river near Kallam, district Osmanabad, Maharashtra, India, J. Aqua. Biol., 16, 11-13
14. Johal, M.S. (2005). Biodiversity with special reference to Indian Freshwater Fishes. Proceeding. Natl. Sem., 'New Trends in fishery Development in India'. (Ed.: M.S. Johal). February, 16-18, 2005. Punjab University, Chandigarh: 11-22.
15. Khangenbam, B. and Gupta, A. (2008). Limnology studies of Nambul River with reference to its resources. Flora and Fauna. 12(2): 193-198.
16. Kulshrestha, H. and Sharma, S. (2006). Impact of mass bathing during Ardh Kumbh on water quality status of river Ganga. J. Environ. Biol., 27(2): 437-440.
17. Meitei, N.S.,V. Bhargava and P.M. Patil (2004a): water quality of Purna River in Purna town, Maharashtra state.J.Aqua.Biol.,19,77-78
18. Mishra. A. and Tripathi, B.D. (2007). Seasonal and temporal variation in physico-chemical and bacteriological characteristics of river Ganga in Varanasi. Cuur. World Environ., 2(2): 149-154.
19. Nath, D. and N.P. Srivastava (2001) : physico-chemical characteristics of Narmada for the stretch Sandia to Mola in M.P. state in the context of construction of reservoirs on the river or its tributaries. J. Inland Fish. Soc. India, 33, 17-24
20. Pandey, N.C. (1985): Pollution of river Ganga in U.P. with specific reference to Varanasi. Civic affairs. 32, 52-59
21. Pillay, .T.V.R. (2004). Aquaculture and the environment. Blackwell publishing, U.K. 16-18p.
22. Prasad, G.B. (2005). Assessment of water quality in canals of Krishna Delta area of Andhra Pradesh, Natl.Environ. Pollu Technol., 4(4): 521-523.
23. Rafeeq, M.A. and A.M. Khan(2002): Impact of sugar mill effluents on the water quality of the river Godavari near Kandakurthi village, Nizamabad district, Andhra Pradesh. J.Aqua. Biol., 17, 33-35
24. Rao, K.S., D. Pandmrathy and Babu Ram (1993): Monitoring the quality of Godavari waters during and after the 1991 Pushkaram at Rajamundry. Pollut. Res., 12, 191-195
25. Saksena, D.N., Garg, R.K. and Rao, R.J.(2008). Water quality and pollution status of Chambal River in National Chambal sanctuary, Madhya Pradesh. J. Environ. Boil. 29(5):701-710.
26. Sharma et al., (2011). Evaluation of water quality of Narmada River with reference to physico - chemical parameters at Hoshangabad city, M.P., India.
27. Shrivastava, V.S. and Patil, P.R.(2002). Tapti river water pollution by industrial wastes. A stastical approach. Natl. Environ. Pollu. Technol.1:285-290.
28. Singh, M. and Singh, A.K. (2007). Bibliography of environmental studies in natural characteristics and anthropogenic influences on the Ganga River. Environ. Monit. Assess. 129: 421-432.
29. Singh, B.N. and S. Rai (1999): Physico-chemical studies of Ganga river at Varanasi. J. Environ. Pollut. 6, 43-46

30. Singh, H.P. (1999): Limno-chemistry of river Ganga and some of its major tributaries. J. Inland Fish. Soc. India, 31, 31-35
31. Singh R.K. Singh, K.N. (2007). Physico – chemical and biological analysis of Gomati river water affected by unban wastes. Mar. Sci. Res. India, 4 (2): 233-236.
32. Sivkumar A.A., Arunadevi P., Aruchami M., (2003): studies on water quality of the river Ambarapalaym, Coimbatore district, Tamil Nadu. Nature Env. Polln. Techno, 2 (3), 305-308
33. Tiwari, R.K., Rajak, G.P. and Mondal M.R. (2005). Water quality assessment of Ganga River in Bihar region, India. J. Environ. Scei Eengng., 47(4): 326-355.
34. Trivedy, R.K. and P.K. Goel: Chemical and biological methods for water pollution studies. Environmental Publication Karad India (1984).
35. Verma, S. and Khan, S.A. (2007). Water quality criteria and Arpna River water of Bilaspur city (C.G.). Curr. World Environ. 2(2):199-204.
36. Ward A.D., Elliot W.J. (1995): Environment Hydrology. Lewis publishers, Boca Radittation, Florida.
37. WHO, (1992): Guidelines for drinking water quality, Vol.1. Recommendations, World Health Organization Geneva.P.130.

Table - 1
Seasonal Variation Of Physico-Chemical Parameters In Narmada River West Nimar M.P. **During – 2012**

No	Parameters	Station I			Station – II			Station – III			Station – IV			Station - V		
		Rainy	Winter	Summer	Rainy	Winter	Summer	Rainy	Winter	Summer	Rainy	Winter	Summer	Rainy	Winter	Summer
1	Transparency	89	117	105	98	140	136	100	118	106	102	117	104	103	119	108
2	Temperature	22	20	36.2	23	21	36	25	22	37	24	21	37	28	20	44
3	Turbidity	25	21	23	26	20	22	27	20	24	26	23	25	26	21	23
4	Conductivity	273	330	361	270	327	348	272	340	364	276	321	360	270	317	355
5	P^H	7.1	7.3	7.6	7.3	7.7	8.0	7.0	7.5	8.3	7.2	7.3	8.0	7.2	7.6	7.9
6	DO*	5.6	8.7	8.0	5.8	8.9	7.8	5.7	10.0	6.9	6.0	8.8	7.2	6.8	8.9	7.6
7	BOD *	5.6	3.8	8.0	5.2	3.4	8.1	5.8	3.5	8.4	5.6	4.0	8.2	5.4	3.9	8.1
8	COD *	27	33	29	27	35	30	26	37	32	25	34	22	26	30	24

Note – Turbidity = NTU, conductivity μ mhos/cm, Temperature = 0^0C, * = mg/l

Table - 2
Seasonal Variation Of Physico-Chemical Parameters Of Narmada River West Nimar M.P. **During – 2013**

No	Parameters	Station I			Station – II			Station – III			Station – IV			Station - V		
		Rainy	Winter	Summer	Rainy	Winter	Summer	Rainy	Winter	Summer	Rainy	Winter	Summer	Rainy	Winter	Summer
1	Transparency	88	118	106	97	138	135	101	117	106	103	117	105	104	118	108
2	Temperature	24	21	35	22	20	34	26	21	36	23	21	36	27	19	43
3	Turbidity	24	20	23	25	20	21	26	19	25	26	24	25	26.1	20.1	23
4	Conductivity	271	331	362	268	235	349	272	341	362	275	319	358	265	318	356
5	P^H	7.0	7.2	7.9	7.3	7.7	8.2	7.0	7.4	8.4	7.1	7.3	7.7	7.2	7.5	7.8
6	DO*	5.5	8.5	8.1	5.1	6.8	7.0	5.7	10.1	6.8	6.0	8.9	7.1	6.6	8.8	7.7
7	BOD *	5.7	3.9	8.1	8.2	5.7	3.8	8.0	5.7	3.9	8.1	5.6	4.0	8.1	5.7	8.2
8	COD *	28	32	29	27	34	30	25	38	33	26	35	25	26	31	26

Note – Turbidity = NTU, conductivity μ mhos/cm, Temperature = 0^0C, * = mg/l

****

Pteridophyta Of Mandugadh Dhar (M.P.) India

Prof. Nirbhay Singh Solanki * Prof. S. C. Mehta **

Abstract - *Pteridophyta* is beautiful small and important group of plant kingdom.The study area of Mandu is hilly area. 6 species have recorded during annual survey like *Marselia minuta, Seliginella krausiana, Cheilnthes firosa,Actinopteris radiate,Adianthum philippense,Azolla pinnata*. The leaves of *Azolla* contain the *cyanobacterium Anabaena* which is a symbiont that fixes nitrogen from the atmosphere that the fern can use.
Key Words - Rhizomatous, Sporocarp, Heterosporous, lanceolate, bipinnate, Ecological indicator.

Introduction - *Peridophytes* are not economically important as seed plant but still have considerable importance. Some are used as food plants and cooked as vegetables,other are well known biological fertilizers.The medicinal value of several peridophytes is widely accepted.

Pteridiophytes such as *Marselia minuta, Seliginella krausiana, cheilnthes firosa,Actinopteris radiate,Adianthum philippense,Azolla pinnata* has found in study area of Mandu District Dhar. All these plants have Medicinal value along with Ornamental value. *Selaginella krausiana* is the native plant of South Africa,Marselia minuta is mainly found in Africa and Asia region. Adianthum philippense is the species of Bangladesh, India, Thiland and combodia.Azolla pinnata found inTasmania.Actiniopteris radiate are grown in Africa, Iran, Australia, India Nepal ,Sri lanka. Cheilnthes farinose-Africa .

Study area-Mandu :- (historical palace –City of joy)
The hill fort of Mandu 22degree 2 minute N &75degree 26 minute E is situated about 35km south of Dhar .

Methodology
I took some Photographs by Digital Camera.

Geographical Distribution
Selaginella krausiana- South Africa
Marselia minuta -Africa and Asia
Adianthum philippense–Bangladesh, India, Thiland and combodia.
Azolla pinnata –Tasmania
Actiniopteris radiate -Africa, Iran, Australia, India Nepal ,Sri lanka
Cheilnthes farinose –Africa

Botanical Distribution

1. Marselia minuta

Scientific classification
Kingdom- Plantae
Division-Pteridophyta
Class- Polypodiopsida
Order-Salviniales
Family- Marseleaceae
Genus- Marselia
Species-M. minuta

Herbs,rhizomatous, ca. 5-10 cm tall.Leaves with 4 leaflets; leaflets deltoid, obtuse, margins entire, crenate or serrate, petioles delicate,4-8 cm long. Sporocarps bean-shaped, rounded or oval, basal.

Uses - The juice of fresh shoots as a remedy for cough, respiratory troubles, especially for babies. Juice or paste of the whole plant is applied externally on the head of patients

*Asst. Professor (Botany) Govt. P.G. College, Dhar (M.P.) INDIA
** Professor (Botany) Govt. P.G. College, Jaora (M.P.) INDIA

suffering from sleeping disorder and hypertension; the patients reported they have got relief from sleeping disorder and hypertension (sarker and Hossain, 2009)

2. Adiantum philippense -

Scientific classification
Kingdom- Plantae
Division-Pteridophyta
Class- Polypodiopsida
Order-Polypodiales
Family- pteridaceae
Sub-family-Vittarioideae
Genus- Adiantum
Species- A. phillippens

Herbs, 20-40 cm tall, rhizomes densely covered with dark brown scales. Stipes 6-15 cm long, tufted, wiry, polished, dark brown. Fronds 10-20 cm long, simple –pinnate; pinnae suborbicular or oblong- ovate, oblique at base, margins slightly lobed in upper part.

Uses-The plant is cooling, alternative, alexiteric,useful in dysentery, ulcers,erysipelas, burning sensation and epileptic fits. Roots are good for strangury and for fever due to elephantiasis. For the treatment of febrile affections in children, the leaves are rubbed with water and given with sugar.

3. Cheilnthes farinosa -

Scientific classification
Kingdom- Plantae
Division-Pteridophyta
Class- Polypodiopsida
Order-Polypodioales
Family- Pteridaceae
Genus- Cheilnthes
Species- C. farinosa

Herbs,20-40 cm tall.Stipes elongated glossy with deciduous scales.Fronds 15-30 cm long, deltoid- lanceolate; pinnae lanceolate, pinnatified, two lower most pairs of pinnae half deltoid, bipinnate, pinnatified at apex, margins entire or toothed, white powdery beneath. Sori. Scarious, rounded, marginal.

Uses-Cheilanthes farinosa (Forsk.) Kaulf., family: Adianthaceae, is a fern of immense medicinal properties used in ethno-medicine. a fern used in many parts of Ethiopia to treat inflammatory skin disorders, were studied using in vivo models of inflammation and pain. The results of the study showed that the fronds Cheilanthes farinosa possess strong anti-inflammatory and anti-nociceptive properties.

4. Azolla pinnata -

Scientific classification
Kingdom- Plantae
Division-Pteridophyta
Class- Polypodiopsida
Order-Salviniales
Family- Azollaceae
Genus- Azolla
Species- A. pinnata

Aquatic ferns with feathered root fibres and single and crowded fronds. This is a small fern with a triangular frond measuring up to 2.5 centimeters in length which floats on the water. The frond is made up of many rounded or angular overlapping leaves each 1 or 2 millimeters long. They are green, blue-green, or dark red in color and coated in tiny hairs, giving them a velvety appearance.The hairs make the top surface of the leaf water-repellent, keeping the plant afloat even after being pushed under.

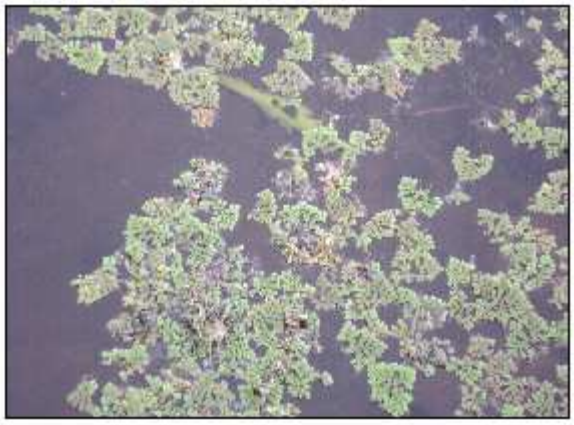

Uses-Azolla is rich in protein, essentials amino acids, vitamins and minerals, describing feeding azolla to, chickens and egg production of layers, as compared to conventional food.
The leaves contain the cyanobacterium Anabaena

which is a symbiont that fixes nitrogenfrom the atmosphere that the fern can use.This gives the fern the ability to grow in habitats that are low in nitrogen. The plant reproduces vegetatively when branches break off the main axis, or sexuallywhen sporocarps on the leaves release spores.

5. Actinopteris radiate -

Scientific classification
Kingdom -Plantae-Plants
Division - Pteridophyta
Class-Polypodiopsida
Order –Polypodiales
Family-Pteridaceae
Genus –Actiniopteris
Species- A. radiate

Terestrial fern .rhizom very short .lamina fan –shapped , all arising from the rhizome ,pinnae clustered .deeply dissected ,lobes linear glabrous , sori arranged in two rows on the lower side of the pinnae lobes

Uses- The whole plant of the Fan- leaved fern is used in a glass of water and taken orally in morning for control of blood pressure and tuberculosis. Plants are dried and one teaspoonful powder is taken orally, once a day for 4 days in the case of cough.

The plant is used in bronchitis and gynecological disorders . The plant is administered in burns, wounds and scalds . The dry leaves are used in tuberculosis

6. Selaginella kraussiana -

Scientific classification
Kingdom plantae-Plants
Subkingdom Tracheobionta- Vascular plants
Division Lycopodiophyta- Lycopods
Class Lycopodiopsida
Order Selaginellaceae- Spike-moss family
Genus Selaginella P. Beauv.- Spikemoss
Species Selaginella kraussiana (Kunze) A. Braun- Krauss' Spikemoss

Selaginella is the only genus in the family *Selaginellaceae*. These plants belong to the lycopods, one of the groups previously referred to as fern allies. *Selaginella* is one of two groups of vascular plants that show heterospory – male (microspores) and female (megaspores) are produced in different sporangia and are of different sizes,

Selaginella species are creeping or ascendant plants with simple, scale-like leaves (microphylls) on branching stems from which roots also arise. The plants are heterosporous (megaspores and microspores), and have structures called ligules, scale-like outgrowths near the base of the upper surface of each microphyll and sporophyll. Under dry conditions, some species of Selaginella roll into brown balls. In this state, they may be uprooted. Under moist conditions the brown balls become green, because of which these are also known as resurrection plants (as in Selaginella bryopteris).

Unusually for the lycopods, each microphyll contains a branching vascular trace.

Uses- Apart from it being use as a horticulture subject either for indoor and outdoor cultivation.

Discussion - We know very well that All plants are important for the environment but one of the plant kingdom, Pteridopyhtes which have special characteristics. Some pteridophytes are used as ecological indicator and biofertilizers. Many pteridophyte have been found to be used as food, medicines,oils, fibres and biogas production . So, we should conserve pteridophytes.

References :-

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Azolla_pinnata
2. http://plants.usda.gov/java/Classification Servlet?source=profile&symbol=SELAG&display=31
3. www. Wikiwand .com/en/ Adianthum_phillippens
4. www.mpbd.info/plants/adianthum_phillippens
5. www.toxicologycentre.com/English/ Plants/Botanical/mailosikha.html
6. https://www.bowdenhostas.com/products/Cheilanthes-farinosa.html
7. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16876348
8. https://en.wikipedia.org
9. Sharma O.P. (2012) Pteridophyta Tata Mcgraw hill education pvt. Lt., New Delhi https//books.google.com.in
10. Pradhan S.G. ,Sharma B.D. and Singh N.P. [2005] Flora of Sanjay Gandhi National Park Borivali –mumbai (Bombay) B.S.I.
11. http://www.plantzafrica.com/plantqrs/selaginellakraus. htm.
12. http://plants.usda.gov/java/Classification Servlet?source=display&classid=SEKR
13 www.google.in
14. Patil D.R. (2004) Mandu ,Archaeological survey of India.

****

Ethno-Medicinal Studies On Skin Diseases In Kol Tribes Of Jaisinghnagar Tehsil District Shahdol Central India

Dr. Radheshyam Napit *

Abstract - For a long period of time plants have been a vulnerable sources of neutral products for maintaining health especially in the last decade with more intensive studies for natural. About 75% of individual from developed countries use traditional medicine, which has compounds derived from medicinal plants.

Jaisinghnagar the remote region 45 Km. of Shahdol District was given the scheduled tribe status by the Government of India in 1951-52. The ethnic communities of Jaisinghnagar include the Kol, Mohni Sarbari, Devra, Katira, Pathra Pani, Amjhor, Chandella, Barna, Nigai, Markhoi, Balaundi, Amdeeh, Tihki, Amdeeh, Kubra, Tetka and Dholar dominated by the majority of Kol tribes. The present study deals with the Ethnobotanical uses of 16 species belonging to 16 families of Jaisinghnagar Shahdol among Kol tribes.

Key words - Ethno-medicinal studies on Skin diseases of Kol trbes; of Jaisinghnagar.

Introduction - Jaisinghnagar lies between 23^0-45^0N Latitude and 81^0 - $81^0$45' E Longitude has a total area of 1532.43 Km^2 of which 504.90 Km^2 is private land 753.76 Km^2 of forest land of which 504.76 Km^2 is demarcated as reserved forest and 248.73 Km^2 is demarcated as protected forest and 273.77 Km^2 of Govt. Land. Which has an altitude of 440-500 mt. above sea level? There are five small rivers Banas, Odari, Chundi, Akhrar, Jhapar and one big river is Sone. Of these Odari and Chundi rivers originate from Koria district of Chhattisgarh (C.G.) state. Forest hill area is known an "Aratoji", kakrandi hill (Kumarpur) village and Banas river originate from Barail hill range running through South West part of Koria district (C.G.).

Jaisinghnagar is a plateau area dominated by hills of Vindhya mountain systems and Sone is the master river of the area. Which are originated from Amarkantak district Anuppur.

According 2001 census the total population of Jaisinghnagar was 1, 61,717 out of which 86,330 are Adivasis tribe and 13,042 schedule caste. Literacy is about 27.6%.

Due to the summer harsh climate and remoteness the whole Shahdol district has been brought under schedule tribe status by the Government of Madhya Pradesh. It is the least populated area of M.P. with a population density of 2-4 persons per Sq. Km. Many tribal communities reside in Shahdol district such as Gond, Baigas, Kols, Agaria, Pav, Bharia, Kanvar, Khairvar, & Paliha but the area has scattered dominated by Baigas community. They wearing traditional culture, costumes & Language.

Jaisinghnagar has two times cropping season from 15 Jun – 20 December and second season start 15 November-20 April. Vegetation growth starts at the beginning of summer season and the flora reaches to full bloom during March and starts vanishing by the end of October. Propagation through vegetative means such as roots, root-stocks runners, bulbs, rhizome tuber seeds, fruits etc. is the most remarkable feature of altitude plants. Most of the altitude plants are perennial in nature and multiply through vegetative methods. The tropical flora of Shahdol district is highly important for tribal communities of Shahdol because they utilize various part of plants viz. Roots, Root Barks, Leaves, Stems, Gums, Stem Barks, Tannins', Flower, Fruit & Seeds etc. in daily life for different diseases.

Materials and Methods - Keeping in view the rich ethnomedicinal flora of Jaisinghnagar district Shahdol. For ethnomedicinal surveys tours were conducted in different tribal localities inside reserve forest protected forest and agriculture land etc. Over a period of four year (2003-2005) voucher specimens and ethno-medical information were collected form the field. Vaidya, Gunia knowledgeable person were interviewed and cross-questioning etc. while noting ethnomedicinal information. Every care was taken to record the local name of the plants parts of the plants used, method of drug preparation and dosage. The collected voucher specimens were critically identified with help of various floras in the enumeration, the plants have been arranged alphabetically the specimen is deposited in Pt. S.N.S. Govt. P.G. College Shahdol (M.P.).

Enumeration

Skin Disease

1. Abutilon indicum, Linn. (Malvaceae), "Kanghi" - Annual or perennial shrub. Stem - woody. Leaves - simple. Flower - yellow. Fruit – more seeded.

The leaves paste is applied on boils twice a day for 3-4 days to treat boils.

*Guest Faculty (Botany) Govt. Degree College, Birsinghpur, Pali Distt. Umaria (M.P.) INDIA

2. Achyranthes aspera, Linn. (Amaranthaceae), "Chirchira" - The water after boiling with seeds is used for bathing once a day for 7 days and applied orally to cure itch. And is also used with "Rai" (Brassica compestris, Linn.) oil to cure scabies.

3. Abelmoschus moschatus, Medic. (Malvaceae), "Van Bhindi" - Annual under shrub, wild. Stem - erect, below semi woody, branched. Leaves - simple, large and palmately veined with petioles alternate, axillary or terminal. Flower - pentamerous, bisexual, regular, hypogynous. Fruit - angular, hairy, capsular .Seeds - grey.

The root powder mixed with coconut oil externally used thrice a day for 7-9 days to cure itch and also treat scabies.

4. Albizzia lebbeck, Benth. (Fabaceae) , "Sirish/ Karhi" - A large tree. Stem - erect, woody, bark, fissured branched. Leaves - compound, bipinnate petiolet, long large gland at the base of petiole, leaflets 3-9 pairs. Flower - racemose, axillary cluster of 2-4 bisexual. Fruit - pod 6 inch in length.

The bark paste is orally used twice a day for 2 months to cure Kodha (Leprosy), and its bark after boiling (bath) is also used to cure leprosy.

5. Eichhornia crassipes,Solms.(Pontederiaceae) "JalBhata/Jal Kumbhi" - Plant herbs, aquatic & dump place in habitat, herbaceous, aerial erect, cauline petiole leaf simple. Inflorescence - cyme, flower complete & colour purple.

The leaves or roots paste along with "Gudsakri" (Grevia hirsuta, Vahl.) root external use twice a day for 3-4 weeks bandaged at wound (sore) to treat cancer like sore.

6. Allium sativum, Linn. (Liliaceae), "Lehsun" - The bulb's juice applied externally 2-3 times a day for 3-7 days to treat 'dad' (ringworm).

7. Amaranthus spinosus, Linn. (Amaranthaceae), "Kantili Chauli" - Annual or perennial spiny herb. Stem – branched greenish weak. Leaves - simple, large, petiole. Flower - spike. Seed hard and blackish.

The root paste is applied orally twice a day for seven days to cure 'dad' (ringworm).

8. Barleria cristata, Linn. (Acanthaceae) , "Bajradanti / Pathar phor" - A perennial under shrub, prickly 1.5 mt. tall. Stem - branches angular, glabrous. Leaves - simple, acute, spine tipped, Flower - terminal, spike, yellow, in cluster. Fruit - capsule 2 seeded.

The leaves juice used externally thrice a day for 10 days to treat itches and scabies.

9. Cassia fistula, Linn. (Fabaceae), "Karkacha / Amaltas" - Perennial tree, it is called Indian laburnum (golden shower). Stem - woody. Leaves - compound, large, pinnate, and smooth. Flower – yellow raceme. Fruit - Long Cylindrical brown colour pod.

The leaves paste is applied externally twice a day for a week to cure itch and scabies.

10. Calotropis gigantea, (Linn.) R.Br. exait. (Asclepiadaceae), "Akwan / Madar" - A perennial shrub, 5.5 mt. tall. Stem - branches, glabrous. Leaves - simple, opposite, decusate Flower – terminal axile, white in cluster. Fruit – Follicle, coma seed.

The milk of plant is used externally 2-3 times a day for 5-6 days to treat itch and also to cure ringworm & Leucoderma.

11. Caesalpinia bonducela, Fleming. (Fabaceae), "Gataran" - Perennial spiny climber shrub. Stem - woody. Leaves - compound, large, pinnate, and spiny. Flower - yellow. Fruit - flat pod, Seed hard.

The seed oil used 2-3 times a day for 4-5 days to treat scabies and also to cure itch.

12. Cassia occidentalis, Linn. (Fabaceae), "Bada Chakauda" - Annual or perennial under shrub. Stem - semi woody. Leaves - compound, large, pinnate, and smooth. Flower - yellow. Fruit - flat pod.

The leaves paste applied externally twice a day for 7-15 days to cure itches.

13. Cassia tora, Linn. (Fabaceae), "Chakauda" - Annual under shrub. Stem - semi woody. Leaves - compound, trifoliate, and smooth. Flower - yellow. Fruit – 15" long pod.

The leaves or whole plant paste applied externally twice a day for 7-15 days to cure itches.

The plant's paste is applied externally twice a day for a week to cure scabies and also to cure itch.

14. Azadirachta indica, A. Juss. (Meliaceae), "Neem"

Neem is common tree in MP state.

The leaves juice, 1 spoon taken once a day for a week to treat itch. The paste of bark powder and oil applied orally twice a day for 7-8 days to cure scabies.

15. Centella asiatica, Linn. (Apeaceae), "Bramhi" - This plant is mostly found along the river and canal side, prostrate herb with rounded leaves, inflorescence simple, and umbel.

The paste of leaves mixed with "Tulsi" (Ocimum sanctum, Linn.) leaves applied externally twice a day for 5-7 days to treat scabies and also to cure ringworm.

16. Celastrus paniculatus, Willd. (Celastraceae), "Malkangni" - *Perennial, climber, woody. Leaves - small, alternate. Flower - small, greenish or white, bisexual. Fruit - dehiscent.*

The root or leaves powder used once or twice a day for 7-9 days to treat itch.

Discussion - Prescriptions of skin disease, making use of 16 plant species have been discussed. It is evident from the present study that the tribal's (Kols) are dependent on different variety of plants to meet their requirement. It also noted that some of the common plants are used only on their beliefs to cure skin diseases by Kol tribes. Kol tribes are most dependent on forests. Some healers (experienced) Kol tribes have shared their information (knowledge) with the research scholars about the cure of the diseases like- **Skin disease.** Jain (1991) has reported Dictionary of Indian folk medicine and Ethno botany P. 135. Since this is first hand knowledge about ethnobotanical uses. There is need for Pharmacological investigations. We may get an

acceptable solution to the problem.

Acknowledgements - The research scholars are thankful to Dr. S.K.Mishra Head Department of Botany Govt .P.G. College Shahdol M.P. for kind cooperation and providing necessary facilities, and also thankful to the medicine men who willingly provided the information and cooperated with the scholars throughout the field survey.

References :-

1. Anonymous 1994 Ethno biology in India- A status report Ministry of Environment and forests Govt of India New Delhi.
2. Jain, S.K (Ed.) 1990. Contribution to Indian Ethnobotany. Scientific Publishers, Jodhpur.
3. Jain, S.K. & Tarafder, C.R. 1970. Medicinal plant lore of the Santals. Revivals of P.O. Bodings' work Econ. Bot. 24: 241-278.
4. Jain S.K. 1991 Dictionary of Indian Folk Medicine and Ethno botany Deep Publications , New Delhi, India P.135
5. Jain, S.K. 2001. Ethnobotany in Modern India. Phytomorphology. Golden Jubilee Issue, pp. 39-54.
6. Napit, Dr. Radheshyam, 2015. Ethnomedicinal Studies on Baiga Tribes in Jaisinghnagar Block District Shahdol M.P. Central India. Research Hunt An International Multi Disciplinary e-journal, Issue. I Jan-Feb -2015 Pag. 1- 4.
7. Napit, Dr. Radheshyam, 2015. Medicinal Plant King of Bitters "Swertia chirata Buch.Ham." (Gentianaceae) Chirayata Used by Tribals of Amarkantak regions District Anuppur Central India. Research Hunt An International Multi Disciplinary e-journal,. Issue. I Jan-Feb -2015 Pag.5-8.
8. Napit, Dr. Radheshyam, 2015. ETHNOMEDICINAL PLANTS (PTERIDOPHYTES) STUDY AND INDIGENOUS KNOWLEDGE OF PUSPRAJGARH BLOCK WITH SPECIAL REFERENCE TO AMARKANTAK ANUPPUR DISTRICT M.P. INDIA. Research Hunt An International Multi Disciplinary e-journal, Issue. I Jan-Feb -2015 Pag.9-12.
9. Napit, Dr. Radheshyam, 2015. Calotrapis (Asclepiadaceae) used by the tribal and local peoples. In the administered of skin disease "Leucoderma" District Shahdol Central India.Naveen Shodh Sansar (An International Refereed Research Journal) Jan. to March Vol.1 Pag.34-35.

****

Industrial Effluent Affecting Hydrophytes In Tapti-River At Burhanpur, M.P. India

Prof. I.A. Siddiqui *

Introduction - Fresh water is one of the most primary human needs since the beginning of civilization, man has tried to got acquired with supply of fresh water for basic physiological needs as well as for various socio-economic requirements.

Pollution and its effects constitute one of man's greatest crimes against humanity. Thus pollution hazards cause to human health was realized by the union govt. and hence prevention and control of water pollution act, 1947 was passed by the govt. In industries and homes no. of toxic chemicals are used and these are waste in human bodies. These chemicals kills the biots of the water bodies. These chemicals gets accumulated in plants and animal bodies and enter in human beings through food chain causing health hazards as mercurial compounds cause minemata syndrome. The present study was selected with particular reference to identify the contaminants of released wastewater, in Tapti River, downstream to the discharge point. So, the present study has been carried out on same hydrophytic plants with reference to the effects of $HgCl_2$ effluents on spirogyra weeds, green algae up to 20 kms. Down stream flow and the discharge points in the river.

Experimental Study (Material and methods) - Under this study two samples of effluents were brought to the laboratory for determining the presence of pollutants like $HgCl_2$ which is injurious to the plants and animal life beyond permissible limit of its concentration and it was found that both the above samples contaminated $HgCl_2$. Hence it was felt desirable to see the effect of different concentration of $HgCl_2$ on the aquatic algal flora. The study was restricted to single alga i. e. Spirogyra SP.

Considering that higher than 0.005 mg/lit conc.(Permissible conc) of $HgCl_2$ existed in the effluents of Nepa Mills waste coming out of E.T. plant where pollutant water was treated for eliminating the pollutants. Three different concentrations of $HgCl_2$ i.e. 0.0074, 0.0142 and 0.0220 mg/lit were prepared. The filaments of spirogyra sp were placed in all the above three concentrations of $HgCl_2$ contained in covered petri dishes.

The observations of the effects of all the three concentrations of $HgCl_2$ under question were made after 6,12,24,48 and 72 hours. The studies were maintained in triplicate.

Result and Discussion - In experimental studies for determining the effect of 0.0074 mg/lit cone on Spirogyra sp., the toxic effect was noticed after 72 hours. The experimental results reveal that the time factor is inversely proportional to the concentration of $HgCl_2$ in respect to toxic effect on the spirogyra sp. (see fig no. 1+2)

Conclusion - In future with increasing human interference at the same rate, it is possible that the river Tapti will further be polluted. Therefore further studies need to be under taken to suggest restorative measures, which are of great socio-economic importance to the region.

Albert Einstein rightly said "Two thing are unlimited, one the universe, the other man's foolishness." It is certainly foolishness on our part to degrade the environment in order to become more and more civilized.

Acknowledgment - I am grateful to the worthy members of the Saifee Golden Jubliee Quaderia College, Burhanpur(M.P.) (Quaderia Educational and Cultural Society, Burhanpur) for permitting me to carry out these studies.

References :-

1. Biswas, A.K. 1981 water for the third world. In C.K. Varshey(ed.) water pollution and management Review South Asian Publisher Pvt. Ltd. New Delhi, Nadras. PP.1-16
2. Matson et al. 1972. Mercuric Chloride inhibited the biosynthesis of lipids, especially galacto lipids and chlorohylls in photosynthetically grown fresh water algae, Ankistrodesmus beaunii and Buglena Grecilis.
3. Seth, G.K.1975, water pollution control in India, Science Reporter, 12:47-477.
4. Trivedy, R.K. Journal of Industrial Pollution control vol. 5.No. 1 June 1989.
5. Chow , V.T. 1964 Handbook of applied Hydrology. Mc Graw Hill Book Company Inc. N. York.
6. Sampatkumaran, N.A. 1972, environmental pollution in a Developing economy. Socio and cult. 38:468-471

* H.O.D. (Botany) S.G.J.Quaderia College, Burhanpur (M.P.) INDIA

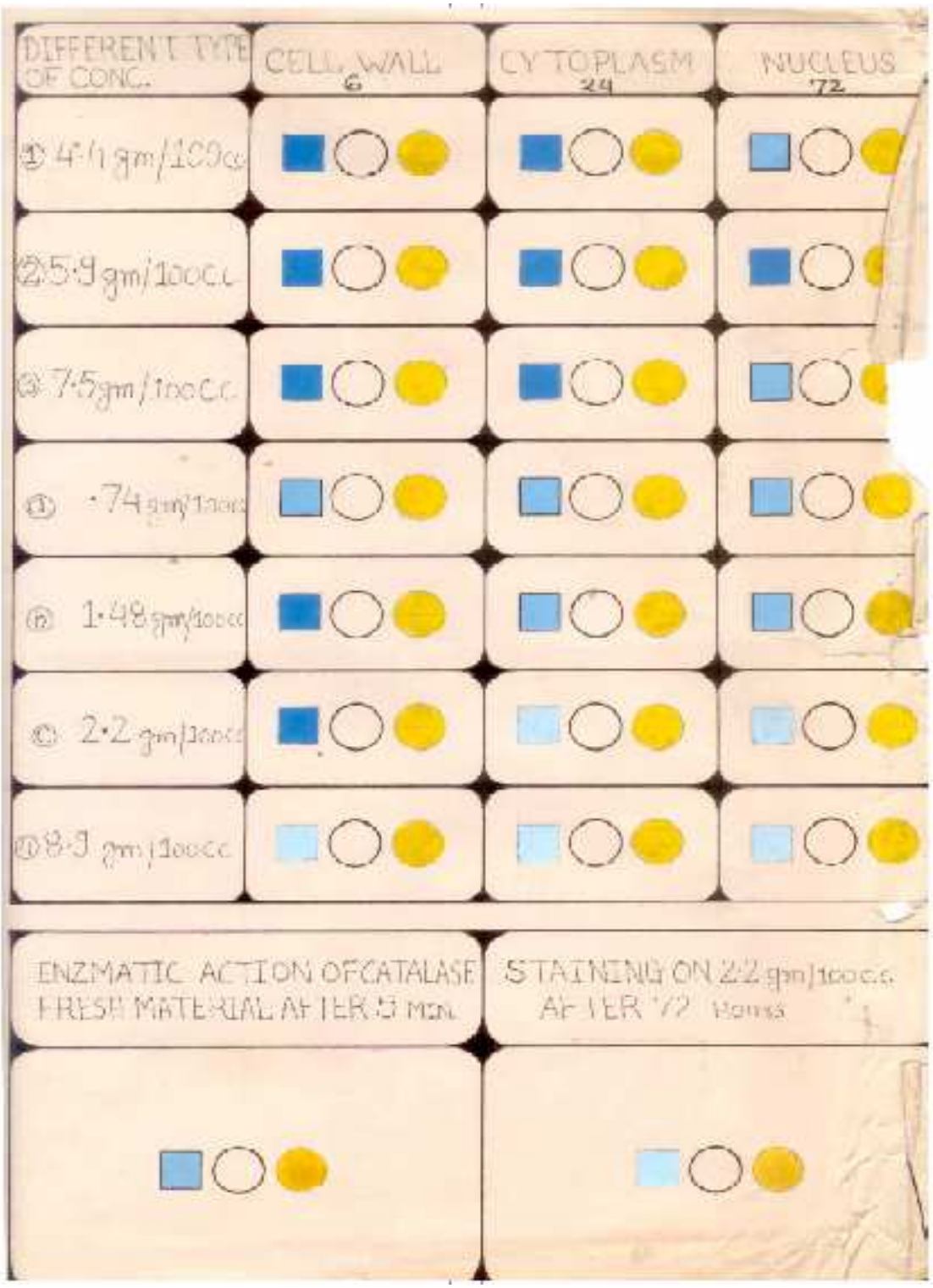

DIFFERENT TYPE OF CONC.
CELL WALL 6
CYTOPLASM 24
NUCLEUS 72
① 4·1 gm/100cc
② 5·9 gm/100cc
③ 7·5 gm/100cc
·74 gm/100cc
1·48 gm/100cc
ⓒ 2·2 gm/100cc
8·9 gm/100cc
ENZMATIC ACTION OFCATALASE FRESH MATERIAL AFTER 5 MIN.
STAINING ON 2.2 gm/100cc AFTER 72 Hours

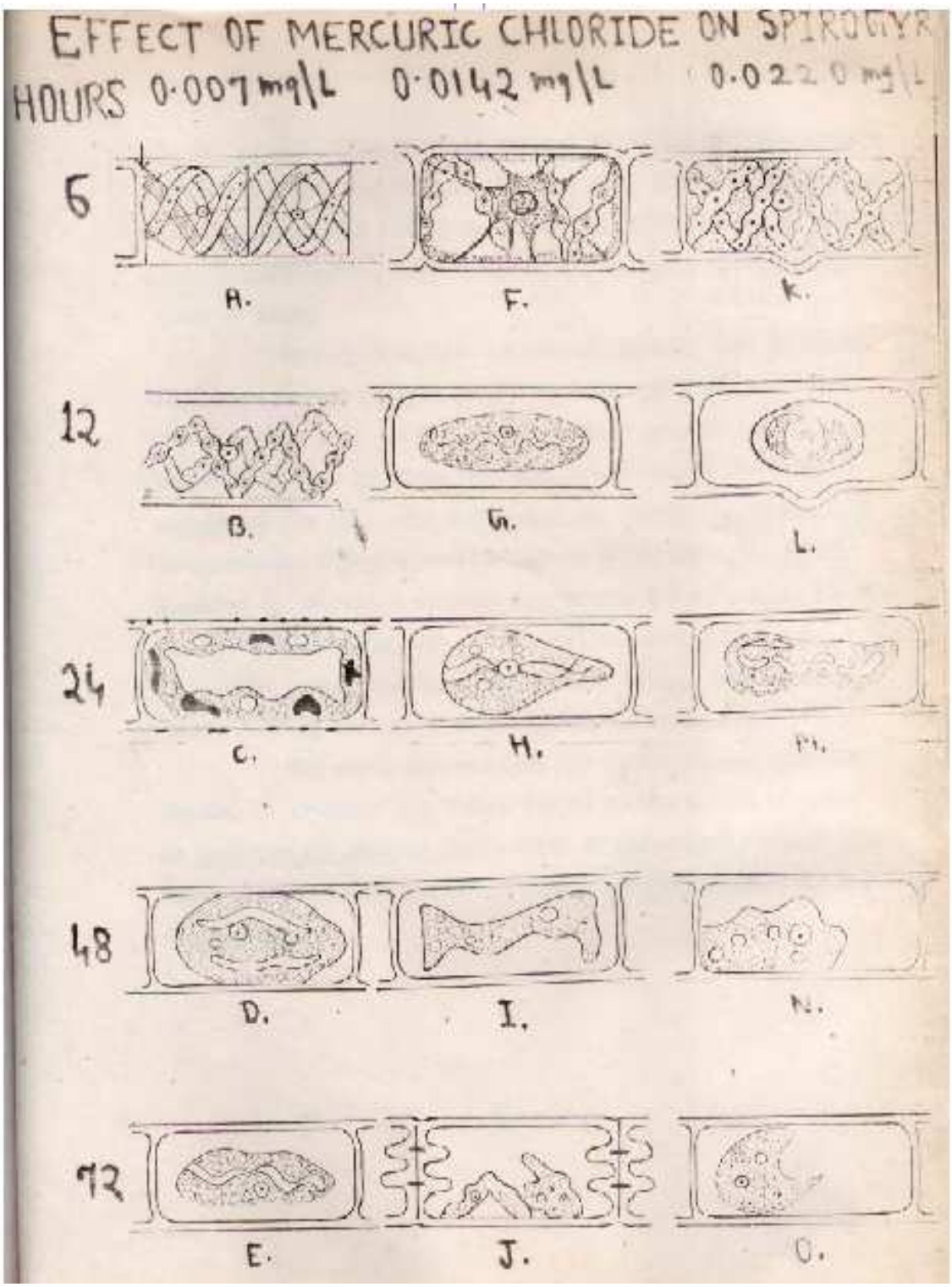
EFFECT OF MERCURIC CHLORIDE ON SPIROGYR
HOURS 0·007 mg/L 0·0142 mg/L 0·0220 mg/L
6
A.
F.
K.
12
B.
G.
L.
24
C.
H.
M.
48
D.
I.
N.
72
E.
J.
O.

Study on Traditional Knowledge Anti-Diabetic Plants Used By Local People of Shahdol District (M.P.) India

Dr. Radheshyam Napit *

Abstract - The present study carried out in Shahdol district, Madhya Pradesh India led to documentation of 21 Plant's species used as anti-diabetic medicines. The paper discloses details of botanical identity, local names, parts of the plant used, mode of preparation and administration of the drug and diseases for which the given plants are used.
Keyword's: - Anti-diabetic Plants, Shahdol District (M.P.)

Introduction - Ancient people closely observed the diabetic disease of **rich man** (like of king Raja, Maharaja) over centuries through trial and error and acquired knowledge on curative properties of plant's against various diseases of men. This knowledge about diseases and their treatment was transmitted by one generation to the other only verbally. Due to modernization the traditional knowledge is vanishing rapidly day by day. In the present study, an attempt has been made to investigate and document this oral heritage that has occurred over the age.

Shahdol district is rich in herbal wealth. The area is predominantly tribal and rural. People of this area usually practice agriculture for meeting their economic needs. Most of the population depends largely on plant resources growing in their surroundings to meet their requirements, including herbal therapy for sick men.

Shahdol district lies between 23.15^0 - 24.3^0 N Latitude and 18^0 - 81.45^0 E Longitude. It is surrounded by Anuppur district on East, Dindauri on South, Umaria on West and Satana on North, Sidhi on North East side. The total area of Shahdol district is 14028 Sq .Km. Total population of the district is about 9.5 Lac (2011 Census) Maikal Mountain range on its southern boundary and Son river flanks on its western with northern boundary. Its major part is covered with dense forest. The survey was conducted repeatedly from January 2012 – December 2013. In different seasons and areas detailed information was documented about plants, human diseases and recipes.

Methodology - The main covering 89 villages were surveyed to observe the use of anti-diabetic plants by the local inhabitants. A very small number of tribals (about 15) were found to treat the diabetic persons by anti-diabetic plants. Majority of such persons were found illiterate while a few with primary or middle education practices to treat diabetic patients. Such persons treating diabetes are usually called as medicine men. The quantity of plant parts used to treat diabetes was not standard. Most of the published and reporter work deal with anti-diabetic plants studies as Binu Nayar, T.S.R. et al.1992; Jain, S.K. 1963; Jain. S. K. (Ed.), 1987; Maheshwari, J.K.1970; Shah, N.C. 1987; Shah, N.C.1994 a; Agarwal, J.L. 2003; Das, A. 1976; Bhattacharjee, S.K. 1998; Anonymous, 1968.

Enumeration - Based on the information collected from the local inhabitants and tribal communities living in the area following plants with botanical names, habit and habitat, distribution and mode of uses are given below –

1. Abutilon indicum (Linn.) Sw. (Malvaceae) 'Kanghi' - A wild shrub with rough leaves and yellow flower's without epicalyx carpals two or more seeded and also found is dry land, loamy soil etc.

Parts used - Fresh leaves is pasted along with "Neem" **(Azadirachta indica A. Juss.)** leaves and "Tulsi" **(Ocimum sanctum Linn.)** together taken orally ½ spoon once a day early in the morning for seven days to check blood and continue till 21 days to cure diabetes.

2. Achyranthes aspera Linn. (Amaranthaceae) 'Chirchira' Annual or perennial herb, Root - tap. Stem – angular, branched, 1 - 3 ft high, often woody below, Inflorescence – Spike. A common weed of field and water place in winter.

(Eugenia Jambos Linn.) seeds powder use orally ½ spoons twice a day for eight weeks to cure diabetes.

3. Adhatoda vasica Nees. (Acanthaceae) 'Adusa' - Wild, shrub some xerophytes Root – tap branched. Stem - woody branched Leaf: opposite simple exstipulate, Flower - cymose white flower fruit- capsule.

Part Used- decoction of roots 40-50g and its boiled in 150ml of cow milk along with "Tulsi" **(Ocimum sanctum Linn.)** leaf applied orally a cup once a day for seven day and check sugar then continue a month to treatment of diabetes.

4. Adiantum caudatum Linn. (Adiantaceae), 'Muyurshikha' - Annual or perennial herb ½-1 ft. high, rhizomes, Roots- rachis, leaflets or pinnules, sori in sporophyll. Adiantum is found in sub tropical and worm temperate regions. They usually grow in moist and shady, bolder places.

*Guest Faculty (Botany) Govt. Degree College, Birsinghpur, Pali Distt. Umaria (M.P.) INDIA

Part Used- Pasted form mixed with 40g "Onion" **(Allium cepa Linn.**) Pyaj bulb taken orally one spoon once or twice a day for 8-10 weeks to check diabetes and then forward applied to cure of diabetes.

5. Aegle marmelos Linn. (Rutaceae) 'Bel'- Throughout India, wild and cultivated, Tap root and branching, Stem woody branched, thorny small tree, Leaves, trifoliate Fruit-hard-shelled, up to 3-6 Inches in diameter yellowish.

Part Used- Fresh tender leaves is pasted or in combination with "Jamun" **(Eugenia jambos Linn.)** 7 leaf & "Karella**" (Momordica charantia L.) 7** leaf "Tulsi" **(Ocimum sanctum L.),** 7 leaf **"**Neem**" (Azadirachta indica A.Juss.)** 7 leaf together ½ cup taken orally once a day for 8-12 weeks to treatment of diabetes.

6. Alangium salviifolium (Linn.F.) wnag. (Alangiacea) 'Kolha' - Wild, shrub, or medium tree, Root-tap stem-woody, branched, Leaf-simple Flowering June-July, Corolla-white-fruit –black.

Part used- Pasted leaves mixed with "Gurij" **(Tinospora cordifolia (willd) Miers. Ex. Hook.F. & Thoms.)** Stem ½ spoons together taken orally once a day for 2-3 months to cure of diabetes.

7. Albizzia lebbeck (Linn.) Willd. (Fabaceae) 'Kala Siris'- Large unarmed trees; stem-woody, branched flowers in round heads; stems united at the base several times as long as the corolla; pod long, thin strap- shaped. A large deciduous tree popularly known as Kala Siris.

Part used- Seeds powder along with "Gudmar" **(Gymnema sylvestre (Retz.) R. Br. ex Schultes.)** leaves log. And "Aainthi" **(Marorphali) (Helicteres isora Linn.)** fruits one parts together one spoon taken orally once a day for 9-10 weeks to cure of diabetes.

8. Andrographis paniculata (Burm.f.) Wall.ex.Nees. (Acanthaceae) 'Bhui Neem' - An erect 25-30 cm.tall annual, branch 4-angled. Leaves 5-6 cm.long, Lanceolate, acute, short stalked or sessile. Flowers small solitary, arranged in lax spreading auxiliary or terminal racemose, Inflorescence; bract 1mm. Calyx minuit, Carolla white, capsul 1 cm.

Part used- Powdered leaves along with Chirayata **(Swertia chirata (Buch. Ham.),** whole plant, Neem **(Azadirachta indica A.Juss)** leaves, Brahmi **(Centella asiatica L.)** 'Karkcha' **(Amaltas) (Cassia fistula Linn.)** Leaves stem bark together one spoon daily morning before meals taken orally about 2-3 months to cure of diabetes.

9. Anthocephalus cadamba (Roxb.) Miq. (Rubiaceae) 'Kadam' - Cultivated as ornamental tree throughout India, near temples. It is woody stem and branched simple leaves, flowering within same time. (Show like star). It is also very much connected with the unedifying history of Lord Krishna and therefore is held in reverence by his devotees.

Part used- Bark powder of the tree (1 teaspoonful) taken with water one times per day for 90 days to treatment of diabetes.

10. Boerhaavia diffusa Linn. (Nyctaginaceae) 'Punarnava'- Hog weed Root-taproot, Stem- herbaceous Leaves-opposite simple Fruit-small grow rainy season.

Part used- Two teaspoonful of juice taken two times daily for 2 months or powder of whole plant's along with "Vajaradanti" **(Barleria prionitis Linn.)** leaves & Stems one spoon applied orally once a day for 3-4 months to control diabetes.

11. Boswellia serrata (Roxb.) ex. Colebr. (Burseraceae) 'Salain' - Wild, Large trees, deciduous, Stem woody, bark thick, exstipulate leaves. Flower are small & bisexual actinomorphic and hypogynous, flowers may be solitary axillary, Fruit- capsule Gum is obtain from stem parts.

Part used- Decoction of stem (small part) along with "Isharmul" **(Aristolochia indica Linn.)** root and leaves, "Semal" **(Bombax malabaricum D.C.)** Roots & "Palas"**(Butea monosperma (Lam.) Kuntze.)** Leaves, together prepared decoction some quantity 1 hour, and ½ cup taken orally morning once a day for 3 months to control diabetes.

12. Celastrus paniculatus Willd. (Celastraceae) 'Malkangni / Amjin' - Stem woody climbers with simple alternate or opposite leaves. White dot spot on the stem flower are small; greenish white actinomorphic, hypogynous inflorescence is cymose. Ovary - tricarpalary, mature three vlaved dehiscent. Fruits- present.

Part used- Grinded extract of roots along with "Madar" **(Calotropis** procera **Ait. Ait. f.)** roots 1 spoon a day given orally for 2-3 months to cure diabetes.

13. Citrullus colocynthis Schard; (Cucurbitaceae) 'Indraman' - Wild, Root-taproot, Stem-herbaceous weak usually climbing by means of tendrils leaves – alternate broad, usually simple, but often deeply lobed or divided and palmately veined. Inflorescence - flower **solitary monocious, Fruit highly bitter.**

Part used- Crusted Juice of fruits along with "Karella" **(Momordica dioica Roxb.)** raw fruits, root & leaves 2 spoon two time a day applied orally for 3 months to cure diabetes.

14. Curculigo orchioides Gaertn. (Amaryllidaceae) 'Kalimusli' - Root-adventitious fibrous, Stem- rootstock perennials herbs, Leaf Alternate, narrow, entire cauline parallel venation, flowers are borne on a leaf less escape yellow colour, cymose, Fruit - A loculicidal capsule.

Part Used- Powdered of rhizome and leaves mixed with "Amarbel" **(Cuscuta reflexa Roxb.)** seeds "Vibirang" **(Embelia ribes Burm.)** seeds and "Gurij" **(Tinospora cordifolia Willd.),** Stem together one spoon taken orally once a day for 2-3 months to cure diabetes.

15. Euphorbia hirta Linn. (Euphorbiaceae) 'Badi Dudhi' - A slender, prostrate, ascending annual clothed with long hairs. Leaves- elliptical and slightly oblique, opposite reddish, green and light green under inflorescence, a cyathium. Flower- unisexual, male flowers more in number having a single stamen. Ovary - trilocular. Stigma bifid. Fruit - a capsule. A very common weed.

Part used- Pasted of whole plant along with "Gudmar" **(Gymnema sylvestre (Retz.) R.Br. ex. Schultes.)** leaves and "**Gurij" (Tinospora cordifolia Willd.) Miers. Ex. Hook. F. Thomas.)** Stem, prepared equal quantity and given orally

one spoon once or twice a day for 2 - 3 months to treatment of diabetes.

16. Ficus Benghalensis Linn. (Moraceae) 'Bargad' A large tree branched with its canopy and produces aerial roots which reach the ground and act as supports as well as absorptive organs. A famous example exists in the **Calcutta** Botanical Garden's covering several acres of ground and possessing several hundreds of aerial roots which have reached the ground and act as supports. Leaf - simple fruit- red colour.

Part used- Decoction of stem-bark leaves and as well that of aerial roots along with "papal" **(Ficus religiosa Linn.)** stem bark and "Umar" **(Ficus glomerata Roxb.)** roots together taken orally two spoons daily in the morning for 3 month's to cure of diabetes.

17. Helicteres isora Linn. (Sterculiaceae) 'Marorphali' - A shrub, Root-taproot, branched. Stem - woody Leaves - simple, Fruit follicle and spirally twisted into the shape of a screw.

Part used- Powdered of fruits and root along with "Amla" **(Emblica officinalis Gaertn.)** fruits and "Anantmula" **(Hemidesmus indicus R.Br.)** root bark together equal quantity one tea spoonful applied orally early morning before meals once or twice a days for 2-3 months to treatment of diabetes.

18. Holarrhena antidysenterica (Roth) DC. (Apocynaceae) 'Koraya' - A medium tree Root- taproot branched. Stem - woody with latex. Leaf-simple opposite, Inflorescence- cymose flower white colour fruit long and seeds-hairy.

Part used - Powdered of fruits and bark mixed with "Jamun" **(Syzgium cuminii Linn. Skeels.)** fruit (Seeds), "Methi" **(Trigonella foenum-graecum Linn.)** seeds and "Phulchuhiya" **(Woodfordia friticosa, Kurs.)** flowers taken orally one tea spoonful equal quantity in morning before breakfast to check sugar level in diabetes.

19. Ougeinia oojeinensis (Roxb.) Hochr. (Fabaceae) 'Sandan / Tinsa' Medium trees Root-taproot, branched Stem-woody Leaf – simple. Inflorescene - racemose bisexual flower. Fruit - legume.

Part Used- Bark powder of plant or extract along with "Bhumi Amla" **(Phyllanthus niruri act. Non. Linn.)** roots, "Gurij" **(Tinospora cordifolia Willd.)** stem, leaf together 2 spoon once a day applied orally for 3 month to control of diabetes.

20. Pueraria tuberosa (D.C.) (Fabaceae) 'Patal Kohnda' Plant are climber shrub Root- taproot stored food material, structure pumpkin like alternate leaf simple, the leaf base is swollen (Pulvinus). Flowers are zygomorphic. Inflorescence – racemose. Fruit - legume.

Part Used - Root powder or Juice along with "Kanji **(Pongamia pinnata (Linn.) Merr)** flower, "Amrud**"(Psidium guajav Linn.)** leaves and fruit, "Bijhra" **(Pterocarpus marsupium Roxb.)** Bark, or (Heart wood small parts kept into water overnight 10 hours any container then use.) and "Bahera" **(Terminalia belerica (Gaertn. Roxb.)** fruit bark together taken orally 2 spoon once or twice a day for 2-3 months to control of diabetes.

21. Sphaeranthus indicus Linn. (Asteraceae) 'Gorakhmundi / Bhumudii' - An annual with low spreading branches, hairy, annual herb typical terpentine like sweet smell. Leaf sessile, oblong, toothed, and covered with minute hairs disk like flower bisexual outer flower on the heads flowering. Nov - April. Common weed dry & moist place and rice fields.

Part Used- Powdered of flowering head or whole plant, along with "Jamun" **(Eugenia jambolana,.Linn.)** seed, leaf, bark, "Bariyari" **(Sida rhombifolia Linn.)** whole plant, "Gokhuru" **(Tribulus terrestris, Linn.)** root and fruits, "Methi" **(Trigonella foenum, Linn.)** seeds, "Gudmar" **(Gymnema sylvestre, Retz.)** leaf, "Nirgundi" **(Vitex negundo Linn.)** Leaf, "Baramsi" **(Tridex procumbens Linn.)** whole plant and "Phulchuhiya (Dhavaii)" **Woodfordia fruticosa, Kurs.)** flowers and "**Indraman" (Citrullus colocynthis, Schrad.)** fruit together applied orally one spoon once a day for 3 months to control of diabetes.

Discussion - Whole **21** plants species are generally used by the local inhabitants for the treatment of diabetes. The knowledge about medicines was acquired by the local inhabitants through prolonged experience of ages and passed on by word of mouth from generation to generation as a part of their culture heritage. In this context medicinal surveys of this type are very important.

They will not only lead to discovery of new medicinal plants, but also result is better understanding of the relationship between the local inhabitants. The benefit of indigenous knowledge can be harnessed and improved upon by its appropriate use, establishing validity of such knowledge and integrating it with health care programmes.

Acknowledgement - The author is thankful to head of Department of Botany Dr. S. K. Mishra Pt. S.N.S. Govt. PG. College Shahdol for kind cooperation & also thankful to local inhabitant of Shahdol district for the completing the questionnaire and lucid discussion pertaining to the anti diabetic medicine.

References :-

1. Agarwal, J.L. 2003. Defeating Diabetes Sci. Reporter: 44-47.
2. Anonymous, 1968. Medicinal Plants of india.Vol.1. ICMR, New Delhi.
3. Bhattacharjee, S.K. 1998. Hand Book of Medicinal Plants Pointer Publishers, New Delhi.
4. Binu, Nayar, T.S.R, & Pushpangadan, P. 1992. An outline of ehtnobotanical research in India. J.econ.taxon. Bot. (Addl.Ser.) 10:405-428.
5. Das, A. 1976. Bitters and Diabetes. Indian Drugs. 14:168.
6. Jain, S.K. 1963. Studies in Indian ethnobotany Plants used in medicine by tribals of Madhya Pradesh Bull. Reg. res. Lab. Jammu. 1126-128.
7. Jain S.K. (Ed.) 1987 A manual of Ethnobotany. Scientific Publishers, Jodhpur.
8. Maheshwari, P. & Singh, W. 1965.Dictionary of Economic Plants in India. I. C. A. R. New Delhi.

9. Napit, R. S. and Kumar, K. 2012. Ethnomedicinal use Euphorbia Plants by Tribal Communities of Shahdol District of M. P. Agrobios News Letter Pag. N0. 47- 48.
10. Napit, R. S., Shrivastava D. K. & Mishra S. K. 2011. Ethno-medico Botanical Study of Paliha Tribe of Gohparu Block Distt. Shahdol M. P. (India). Journal of Tropical Forestry, Vol. 27. Pag N0. 62-64.
11. Napit, Dr. Radheshyam, 2015.Ethnomedicinal Studies on Baiga Tribes in Jaisinghnagar Block District Shahdol M.P. Central India. Research Hunt An International Multi Disciplinary e-journal, Vol.÷ Issue. I, Jan-Feb -2015 Pag. 9- 12.
12. Napit, Dr. Radheshyam, 2015. Medicinal Plant King of Bitters "Swertia chirata Buch.Ham." (Gentianaceae) Chirayata Used by Tribals of Amarkantak regions District Anuppur Central India. Research Hunt An International Multi Disciplinary e-journal,. Vol.÷ Issue. I, Jan - Feb - 2015 Pag.1-4.
13. Napit, Dr. Radheshyam, 2015. Ethnomedicinal Plants (Ptreridophytes) Study and Indegenous Knowledge of Pushprajgrah block with Special Reference to Amarkantak Anuppur District M.P. India. Research Hunt An International Multi Disciplinary e-journal, Vol.÷ Issue. I Jan-Feb -2015 Pag.5-8.
14. Napit, Dr. Radheshyam, 2015. Calotrapis (Asclepiadaceae) Plants Used By The Tribal A n d Local Peoples. In The Administered Of Skin Disease "Leucoderma" District Shahdol Central India. Naveen Shodh Sansar (NSS, An International Refereed Research Journal) Jan. to March Vol.1 Pag.34-35.
15. Napit, Dr. Radheshyam, 2015. Ethnic plants to cure stone disease of Shahdol district central India. Naveen Shodh Sansar (NSS, An International Refereed Research Journal) Jul. to Sep. Vol.1 Pag.24-27, Issue Xl.
16. Napit, Dr. Radheshyam, and Rawat Dr. P D, 2015. Ethno-biological Studies of Traditional knowledge of Medicine of Shahdol district Central India. Naveen Shodh Sansar (NSS, An International Refereed Research Journal) Jul. to Sep. Vol.1 Pag.28-30, Issue XI.
17. Napit, Dr. Radheshyam, 2015. Anti cancerous plants of Amarkantak region of Shahdol division, Madhya Pradesh, India. Divya ShodhSamiksha (DSS, An International Refereed Research Journal) Jul. to Sep. Vol.1 Pag.21-23, Issue VI.
18. Napit, Dr. Radheshyam, and Rawat Dr. P D, 2015. Studies on floral diversity in the tribal areas of Shahdol district (M.P.) India. (DSS, An International Refereed Research Journal) Jul. to Sep. Vol.1 Pag.18-20, Issue VI.
19. Sinha, A. 1959 a, Chemical examination of the seeds of Jatropha curcas Linn. J. Inst. Chem. (India) 31, 213.
20. Ramachandran, V.S. and Nair, N.C. 1981 Ethnobotanical observation on rurals of Tamil Naidu (India). J.Econ. Taxon. Bot. 2:183-190.
21. Sinha, B.K. and Dixit, R.P. 2001 Ethnobotanical studies on Sarcostemma acidum (Asclepiadacea) from Khargaon Distt. Madhya Pradesh Ethnobotany 13:116-117.
22. Shah, N. C. 1987. Ethnobotany in the mountainous Region of Kumaon Himalaya. Thesis submitted to the Kumaon University, Nainital for the Degree of Doctor of Philosophy in Botany. 1-255.

****

Digital Electronics

Dr. Neeraj Dubey *

Introduction - Digital electronics or digital electronic circuits are electronics that handle digital signals- discrete bands of analog levels, rather than by continuous ranges. All levels within a band of values represent the same numeric value. Because of this discretization, relatively small changes to the analog signal levels due to manufacturing tolerance, signal attenuation or parasitic noise do not leave the discrete envelope, and as a result are ignored by signal state sensing circuitry.

In most cases the number of these states is two, and they are represented by two voltage bands: one near a reference value (typically termed as "ground" or zero volts), and the other a value near the supply voltage. These correspond to the "false" ("0") and "true" ("1") values of the Boolean domain, respectively, yielding binary code.

Digital techniques are useful because it is easier to get an electronic device to switch into one of a number of known states than to accurately reproduce a continuous range of values. Digital electronic circuits are usually made from large assemblies of logic gates, simple electronic representations of Boolean logic functions

A digital circuit is often constructed from small electronic circuits called logic gates that can be used to create combinational logic. Each logic gate represents a function of Boolean logic. A logic gate is an arrangement of electrically controlled switches, better known as transistors. The output of a logic gate is an electrical flow or voltage that can, in turn, control more logic gates.

Logic gates often use the fewest number of transistors in order to reduce their size, power consumption and cost, and increase their reliability.

Integrated circuits are the least expensive way to make logic gates in large volumes. Integrated circuits are usually designed by engineers using electronic design automation software

Integrated Circuits or IC's as they are more commonly called, can be grouped together into families according to the number of transistors or "gates" that they contain. For example, a simple AND gate my contain only a few individual transistors, were as a more complex microprocessor may contain many thousands of individual transistor gates. Integrated circuits are categorised according to the number of logic gates or the complexity of the circuits within a single chip with the general classification for the number of individual gates given as -

The most widely used simplification is a minimization algorithm like the Espresso heuristic logic minimize within a CAD system, although historically, binary decision diagrams, an automate, truth tables, Karnaugh maps, and Boolean algebra have been used.

The most general-purpose register-transfer logic machine is a computer. This is basically an automatic binary abacus. The control unit of a computer is usually designed as a micro program run by a micro sequencer. A micro program is much like a player-piano roll. Each table entry or "word" of the microprogram commands the state of every bit that controls the computer. The sequencer then counts, and the count addresses the memory or combinational logic machine that contains the micro program. The bits from the micro program control the arithmetic logic unit, memory and other parts of the computer, including the micro sequencer itself. A "specialized computer" is usually a conventional computer with special-purpose control logic or micro program. The complex task of designing the controls of a computer is reduced to a simpler task of programming a collection of much simpler logic machines.

Computer architecture is a specialized engineering activity that tries to arrange the registers, calculation logic, buses and other parts of the computer in the best way for some purpose. Computer architects have applied large amounts of ingenuity to computer design to reduce the cost and increase the speed and immunity to programming errors of computers. An increasingly common goal is to reduce the power used in a battery-powered computer system, such as a cell-phone. Many computer architects serve an extended apprenticeship as micro programmers.

There are several reasons for testing a logic circuit. When the circuit is first developed, it is necessary to verify that the design circuit meets the required functional and timing specifications. When multiple copies of a correctly designed circuit are being manufactured, it is essential to test each copy to ensure that the manufacturing process has not introduced any flaws.

A large logic machine can have an astronomical number of possible states. Obviously, in the factory, testing every state is impractical if testing each state takes a microsecond, and there are more states than the number of microseconds since the universe began. Unfortunately, this ridiculous-sounding case is typical.

Fortunately, large logic machines are almost always

* Prof. & HOD (Physics) Govt. Art & Commerce College, Sagar (M.P.) INDIA

designed as assemblies of smaller logic machines. To save time, the smaller sub-machines are isolated by permanently installed "design for test" circuitry, and are tested independently.

Reliability: The "reliability" of a logic gate describes its mean time between failure (MTBF). Digital machines often have millions of logic gates. Also, most digital machines are "optimized" to reduce their cost. The result is that often, the failure of a single logic gate will cause a digital machine to stop working. It is possible to design machines to be more reliable by using redundant logic which will not malfunction as a result of the failure of any single gate (or even any two, three, or four gates), but this necessarily entails using more components, which raises the financial cost and also usually increases the weight of the machine and may increase the power it consumes.

Digital machines first became useful when the MTBF for a switch got above a few hundred hours. Even so, many of these machines had complex, well-rehearsed repair procedures, and would be nonfunctional for hours because a tube burned-out or a moth got stuck in a relay. Modern transistorized integrated circuit logic gates have MTBFs greater than 82 billion hours (8.2×10^{10}) hours, and need them because they have so many logic gates.

The "switching speed" describes how many times per second an inverter can change from true to false and back. Faster logic can accomplish more operations in less time. Digital logic first became useful when switching speeds got above fifty hertz, because that was faster than a team of humans operating mechanical calculators. Modern electronic digital logic routinely switches at five gigahertz (5×10^{9} hertz), and some laboratory systems switch at more than a terahertz (1×10^{12} hertz).

Digital Electronics, there are two types of signals, one is analog or continuous signal and the second one is Digital or discrete signal. So the science or field of research in the area of engineering is termed as Analog and **Digital Electronics** respectively. Now coming to the area of **Digital Electronics,** it is essential to understand wide range of applications from industrial electronics to the fields of communication, from micro embedded systems to military equipment. The main and perhaps the most revolutionary advantage of Digital electronics is the decrease in size and the improvement in technology.

An advantage of digital circuits when compared to analog circuits is that signals represented digitally can be transmitted without degradation due to noise. a continuous audio signal transmitted as a sequence of 1s and 0s, can be reconstructed without error, provided the noise picked up in transmission is not enough to prevent identification of the 1s and 0s. An hour of music can be stored on a compact disc using about 6 billion binary digits.

In a digital system, a more precise representation of a signal can be obtained by using more binary digits to represent it. While this requires more digital circuits to process the signals, each digit is handled by the same kind of hardware, resulting in an easily scalable system. In an analog system, additional resolution requires fundamental improvements in the linearity and noise characteristics of each step of the signal chain.

Computer-controlled digital systems can be controlled by software, allowing new functions to be added without changing hardware.

digital circuits use more energy than analog circuits to accomplish the same tasks, thus producing more heat which increases the complexity of the circuits such as the inclusion of heat sinks. In portable or battery-powered systems this can limit use of digital systems.

Even when more significant noise is present, the use of redundancy permits the recovery of the original data provided too many errors do not occur. Digital circuits are sometimes more expensive, especially in small quantities. Most useful digital systems must translate from continuous analog signals to discrete digital signals.

Digital memory and transmission systems can use techniques such as error detection and correction to use additional data to correct any errors in transmission and storage.

Some techniques used in digital systems make those systems more vulnerable to single-bit errors. These techniques are acceptable when the underlying bits are reliable enough that such errors are highly unlikely.

A single-bit error in audio data stored directly as linear pulse code modulation (such as on a CD-ROM) causes, at worst, a single click. Instead, many people use audio compression to save storage space and download time, even though a single-bit error may corrupt the entire song. Design issues in digital circuits: Digital circuits are made from analog components. The design must assure that the analog nature of the components doesn't dominate the desired digital behavior. Digital systems must manage noise and timing margins, parasitic inductances and capacitances, and filter power connections. Bad designs have intermittent problems such as vanishingly fast pulses that may trigger some logic but not others, "runt pulses" that do not reach valid "threshold" voltages, or unexpected combinations of logic states.

References :-

1. In 1946, ENIAC required an estimated 174 kW. By comparison, a modern laptop computer may use around 30 W; nearly six thousand times less. "Approximate Desktop & Notebook Power Usage". University of Pennsylvania. Retrieved 20 June 2009.
2. The Chip that Jack Built, (c. 2008), (HTML), Texas Instruments, Retrieved 29 May 2008.
3. "ASODA sync/async DLX Core". OpenCores.org. Retrieved September 5, 2014.
4. Clarke, Peter. "ARM Offers First Clockless Processor Core". eetimes.com. UBM Tech (Universal Business Media). Retrieved 5 September 2014.
5. Brown S & Vranesic Z. (2009). Fundamentals of Digital Logic with VHDL Design. 3rd ed. New York, N.Y.: Mc Graw Hill.

Carbon-Sequestration, A way to management of global warming

Kumud Dubey* **Avinash Dube****

Abstract - Increase in atmospheric carbon dioxide concentration may be generating increase in average global temperature and other climate change impacts and cause serious environmental consequences. Carbon-sequestration is helpful in management of environment, as by this carbon is removed in the form of carbon dioxide. One type of sequestration is the long term storage of carbon in trees and plants, as carbon dioxide removed from the atmosphere is stored in growing plants in the form of biomass.

Key Words - Carbon- sequestration , biomass.

Introduction - Due to the cycle of inhalation and exhalation of carbon dioxide, the atmosphere maintains optimum level of carbon dioxide in air. It does not allow exceeding minimum levels of carbon dioxide in atmosphere, thereby preventing warming of earth and atmosphere. By the combustion of the fossil fuels, industrial, domestic and transportation activities, percentage of carbon dioxide increases and which is highly dangerous to promote warming of the earth. Global warming has gained wider acceptance by the international scientific community as one of the potential threats to the existence of mankind coupled with extinction of other flora and fauna.

Increasing concentration of greenhouse gases in the atmosphere leads to global warming. These gases affect the heat balance of the earth of observing long wave radiations, which would otherwise escape to space. It behaves like a glass in a green house. All these affect the life of the earth in many ways.

Carbon - sequestration and management of global warming - Atmospheric carbon dioxide and other green house gases act to trap heat that is reflected from the earth surface. This buildup of heat could lead to global warming. Maintenance of soil organic carbon is essential for long term sustainable agriculture, since declining levels generally lead to decreased crop productivity. Now a-days, emphasis is given on sequestration of organic carbon in terrestrial agro-ecosystem as a measure to offset the steadily rising levels of carbon dioxide in the atmosphere.

Through carbon sequestration, atmospheric carbon dioxide levels are reduced, as soil organic carbon - levels increase. If the soil organic carbon is undisturbed, it can remain in the soil for many years as stable organic matter. This carbon is then sequestered or removed from the pool available to be recycled to the atmosphere. This process reduces carbon dioxide levels in the atmosphere reducing the chances of global warming.

Measures to enhance carbon - sequestration

1. Using higher residue crops.
2. Using cover crops.
3. Crop varieties that store more carbon.
4. Reduced use of nitrogenous fertilizers.
5. Increased crop rotation intensity by eliminating summer fallow.
6. Buffer strips.
7. Conservation from soil erosion.
8. Need based fertilizers application.
9. Encouragement of massive aforestation.

To enhance carbon sequestration rapid development of carbon free energy source such as solar, wind, hydro, geo-thermal and nuclear energy and consumption of less carboniferous fuels and more hydrogen rich fuels such as natural gases are beneficial.

Conclusion - Soil is one of the important sink for carbon-sequestration. Adoption of appropriate soil and crop management practices holds promise to sequester greater amounts of carbon in soil,thus decrease the concentration of carbon dioxide in atmosphere. Increased sequestration of carbon in agricultural soils has potential to mitigate the increase in atmospheric green house gases.

References :-

1. Khopker S.M. (2005), Env. Pollution- Monitoring abd control, New Age Int. Pub. New Delhi, pp120-124
2. Kishore P. (2010), Agrobios Newsletter,Agrobios India Jodhpur, pp 386-395.

***Asst. Professor (Botany) M.L.C. Govt. Girls College, Khandwa (M.P.) INDIA**
****Asst. Professor (Physics) S. N. Govt. P. G. College, Khandwa (M.P.) INDIA**

To Assess the Nutritional Status of the Adult Females

Madhu Kagat *

Abstract - During present investigation hundread middle aged women (50-55years) residing in ten poshed colonies of Bikaner belonging to MIG and HIG were selected in equal numbers i.e. 50 from each group on the basis of convenient sampling. Immaterial of their income majority (59%) of the subjects were found to be obese with 27.34 to 28.09 kg/m^2 BMI and 0.86 to 0.87 WHR. Mean Blood pressure levels were also found to be normal. Majority (78%) of subjects were anaemic (9.55 g/dl to 10.44 g/dl Hb). Body weight, BMI and WHR were positively and significantly correlated with energy, protein and total fat intakes. Nutritional status of the adult females under study was not found to be satisfactory and indicates the need for nutritional education of the subjects.

Introduction - Nutritional status is the condition of health of the individual as influenced by the utilization of the nutrients. It can be determined only by the correlation of information obtained through a careful medical and dietary history, a through physical examination and appropriate laboratory investigation. To maintain a healthy weight, our energy intake should equal the energy expended ICMR (1990). Because of our sedentary life style, some of us need less energy than standard energy requirement. If energy intake is in excess of expenditure it is stored for later use, mostly as fat and results as gain in body weight. If energy intake is less than that of expenditure, the stored energy is used as a fuel and the body weight is lost.

When a woman approaches 50 years of age, she has passed through the many trials and tribulations of puberty, adolescent and child bearing stages. Although by this time, a woman arrives at the end of her reproductive and child bearing life, still she plays dominant and responsible role in the family. Middle age is a period of life when aging process starts. Menopause during this age period may lead to various physiological and psychological changes which in turn affect their nutritional status. The prevalence rate of obesity and coronary heart disease has been found to be higher in females in both the areas as compared to males (NIN,1998).

In India, in the context of malnutrition, under nutrition has been given greater consideration. But another profile of malnutrition i.e. over nutrition has not been investigated in much detail. There is a need of consideration and investigation because obesity is most likely to occur after age of 50 to 55 years due to lessened physical work and modified food consumption patterns. So keeping all this in view the present investigation was undertaken to find out nutritional profile of selected middle aged female subjects residing in Bikaner city of Rajasthan.

Methodology -

1. Selection of subject:- Subjects was taken from Bikaner city. Bikaner is one of the prominent cities of Rajasthan, situated in the northwest of the state. Hundred middle aged women of 50-55 years (Diane et.al,1978) residing in the ten poshed colonies of Bikaner belonging to MIG and HIG were selected in equal number i.e 50 from each group on the basis of convenient sampling technique. Willingness of the subject to co-operate during the study was considered as an important criteria for their selection. The subjects selected for the study were then interviewed to collect all the relevant information with the help of pretested structural interview schedule.

2. Collection of data - An interview schedule was developed to collect detailed information from selected subjects regarding background information (age, educational level, occupation, religion, food habits, type of family, income, physical activity pattern), food intake, frequency and type of fats &oils consumed, incidence of various diseases and activity pattern, anthropometric parameters, biophysical and biochemical measurements.

3. Anthropometric parameters - Height and weight of the subjects were measured for calculating their body mass index. Along with waist and hip circumference of the subjects were also measured to calculate the waist hip ratio, in order to assess prevalence of abdominal adiposity.

4. Biophysical assessment - Blood pressure is the lateral pressure exerted by the blood on the vessel walls while flowing through it. Sphygmomanometer was used to measure the blood pressure of the subjects in the present study. Obese subjects are more likely to develop hypertension than subjects of normal weight (Berchtold et al.,1981). So the blood pressure of all subjects was estimated.

5. Biochemical assessment - Haemoglobin was estimated by using cyanment haemoglobinometer method as described by Dacie and Lewis (1975).

6. Statistical Analysis of Data - Observation collected on the various aspects of the study have been statistically analyzed as suggested by Gupta(1997). Mean and standard deviation was calculated for each set of observation.

*Research Scholar (HomeScience) Jai Narain Vyas University, Jodhpur (Raj) INDIA

Results and discussion - Table 1. (See in the last page) Anthropometric measurements are an important method for assessing the nutritional status of the subjects, as these measurements are partially dependent upon nutrient intake. Therefore during present study weight, height, BMI and WHR of all the subjects were measured. The nutritional status of the subjects was assessed using pertinent standards as mentioned in Table 1. During present study mean height of MIG and HIG subjects was noted to be 1.55 ± 0.053 m and 1.54 ± 0.056 m respectively. The difference in mean height of the subjects was found to be statistically non-significant. At the time of survey the mean weight of the subjects was 65.38 ± 10.25 kg and 66.72 ± 10.18 kg for MIG and HIG respectively against 50 kg body weight suggested by (ICMR,1990) for a reference women. Difference of both the values was noted to be non significant. Weight of all subjects was recorded to be higher than the standard value. This may be due to higher consumption of energy dense foods and their sedentary life style. The ratio of weight in kg/height m^2 is referred to as Body Mass Index. BMI has a good correlation with fatness. The mean body mass index of the subjects belonging to MIG and HIG was recorded to be 27.34 ± 3.95 and 28.09 ± 4.17 against the standard 18.50 – 20.99 with statistically non-significant difference between both the income groups. Immaterial of their income groups all subjects were having higher BMI than the normal range (18.50 to 24.99) indicating health risk for the subjects. Waist hip ratio gives distribution of fat in the human body. The mean WHR of the subjects belonging to MIG and HIG was noted to be 0.867 ± 0.063 and 0.860 ± 0.049 respectively with non-significant differences. The mean for WHR of the subjects was noted to be slightly higher than the standard value (0.85) pointing towards greater risk for their health problem.

Table 2. (See in the last page) - Blood pressure was estimated to find out the prevalence of hypertension and hypotension among the subjects. The mean systolic blood pressure for MIG subjects was noted to be 126.1 ± 8.05 mmHg and for HIG it was 125.7 + 9.76 mmHg. Similarly mean diastolic BP was recorded to be 87.4 ± 6.85 mmHg and 82.9 ± 6.43 for MIG and HIG subjects respectively. A non significant difference existed between both the group for their systolic as well as diastolic blood pressure.

Table 3. (See in the last page) - Level of haemoglobin (Hb) in an individual is widely used as an index in the assessment of nutritional status, because its synthesis is sensitive to the deficiency of several nutrients such as protein, iron, vitamin B_{12} and folic acid (Anderson, 1982). The mean haemoglobin values for MIG and HIG was noted to be 9.55 ± 2.40 g/dl and 10.44 ± 1.48 g/dl respectively which is less than standard value (>12). A significant difference (P<0.1) was noted between both the groups due to difference in their iron intakes (Table 3).

Conclusion - The result of present study revealed that, immaterial of their income groups values for height, weight, BMI, WHR were higher for all the subjects than the standard value. This may be due to higher consumption of energy dense foods and their sedentary life style. The blood pressure were within the normal range for the subjects in both the groups, with non significant differences. The mean haemoglobin level for MIG and HIG subjects was noted to be below than the normal (>12g/dl). Irrespective of their income groups majority of subjects (78%) were anaemic with different grades and only (22%) were found to be normal. Thus results of study clearly indicates need for nutrition education. **(Graph see in the last page)**

References :-

1. Anderson, L., Dibble, M.V., Turkki, P.R., Mitechell, H.S. and Rynbergen, HJ.J. (1982). Nutrition in Health and Disease, 2. J.B. Lippincott company, Philadelphia.
3. Berchtold, P., Jorgens, V., Finke, C. and Berger, M., (1981). Epidemiology of obesity and hypertension. Int. J. obesity 5 (Suppl.1) c.f. Nutr. Abs. and Rev. (1982) 52 (4) : 340.
4. Dacie, J.V. and Lewis, S.M. (1975). Practical haematology, 5 : 31. Churchill and Livingstone.
5. Diane Papalia, E., Sally Wendkos olds, Ruth Deskin 6. Feldman (1978). Chronological terms as the year between 40 to 65. Human development, 9th edition, P.52.
7. Ghafoorunissa and Krishnaswamy (ed.) (2000). Diet and Heart Disease, NIN, Hyderabad.
8. Gupta, S.P. (1997). Statistical methods, Sultan Chand and Sons Publishes, New Delhi.
9. ICMR (1990). Nutrient requirements and recommended dietary allowances for Indians. NIN, Hyderabad.
10. NIN (1998). Dietary Guidelines for Indians – A manual, National Institute of Nutrition, ICMR, Hyderabad.
11. Robbins, S.L., Vinay and Cotran, R.S. (1994). Pathological Basis of Disease. 5th edition, W.B. Sounders Company. Harcourt Brace and Company. Prism Books Pvt. Ltd., Banglore, India.
12. Sachdev, H.P.S. and Choudhary, P. (1999). Nutrition in Adults. Developing country concerns. Deptt of Health, Mulana Azad Medical College, New Delhi- 110002.
13. WHO (2000). Obesity preventing and managing the global epidemic. WHO expert committee. WHO (Technical Report Series, No.894, 253.)

Table 1. Anthropometric parameters of the subjects (Mean±SD) according to their income groups

Parameters	Mean ± SD			
	MIG (n=50)	HIG(n=50)	'Z' value	Standard value
Height (m)	1.55 ± 0.053	1.54 ± 0.056	0.71^{NS}	1.52*
Weight (kg)	65.38 ± 10.25	66.72 ± 10.18	0.65^{NS}	50.00*
BMI (kg/m^2)	27.34 ± 3.95	28.09 ± 4.17	0.919^{NS}	18.50-24.99**
WHR	0.867 ± 0.063	0.860 ± 0.049	0.77^{NS}	0.85***

^{NS} = Non significant
*= ICMR(1990)
**=WHO(2000)
***=Ghafoorinissa and Krishnaswamy(2000)

Table 2. Mean + SD blood pressure levels of the subjects

Blood pressure (mmHg)	MIG(n=50)	HIG(n=50)	'Z'value	StandardValue*
Systolic	126.1 ± 8.05	125.76 ± 9.76	0.22^{NS}	<140
Diastolic	87.4 ± 6.85	82.9 ± 6.43	1.5^{NS}	<85

^{NS}= Non significant
*= Robbins et.al.(1994)

Table 3. Mean + SD Haemoglobin level of the subjects

Parameter	MIG(n=50)	HIG(n=50)	'Z'value	Standard value*
Haemoglobin(g/dl)	9.55 ± 2.40	10.44 ± 1.48	0.29**	>12

**= Significant at 1% level of significance
*= Sachdeva and Choudhary 1999

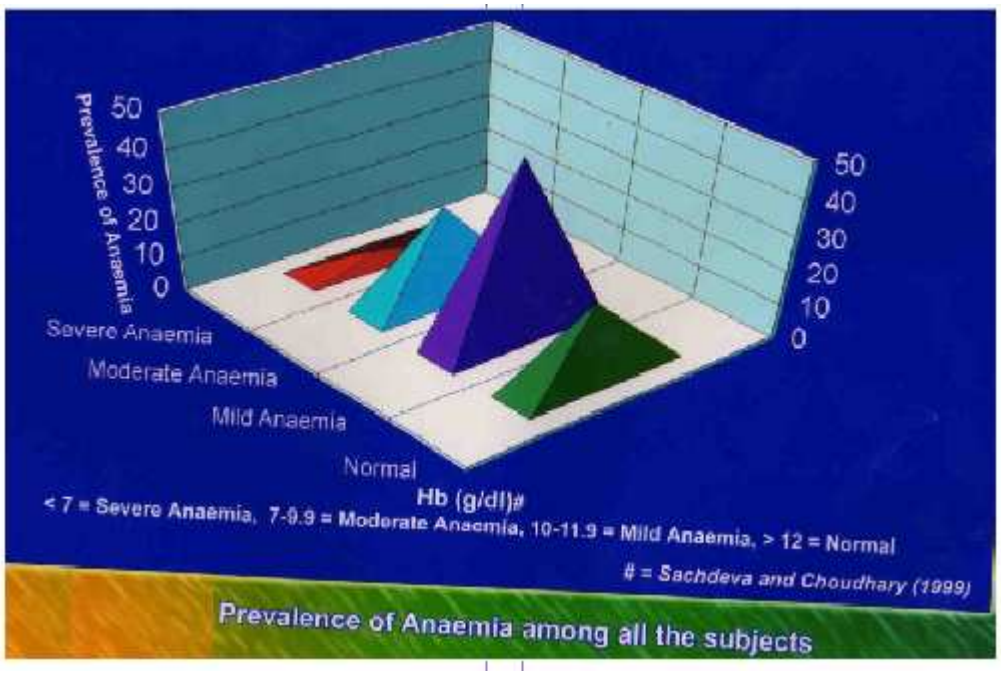

****

Pulses Intake Among Adolescent Girls And Boys Of HIG And MIG

Dr. Madhubala Verma* **Pranita Bahutra****

Abstract - To investigate the pulses intake of adolescent girls and boys; food intake was examined using a 7-day food frequency questionnaire of HIG and MIG in Bhopal city. A total of 100 girls and boys, aged from 18-21 years, residing in Indore city were selected by systematic random sampling method. Nutrient intake was assessed using the 24-h recall method and the usual pattern of food intake was examined using a 7-day food frequency questionnaire. The result reveals highly significant difference (P > 0.05), for intake of pulses of adolescent girls and boys in MIG and HIG groups.

Introduction - To overcome daily wear and tear of body muscles it is must to consume protein regularly in our routine as per the RDA. Also, adolescent is a phase of life when reserves are needed to compensate daily loses and future requirement of protein for growth and protect body from weakened tissues. Also, it is observed that adequate protein intake avoid many health issues. To understand protein intake of adolescents of Indore city the following research was done with below objective.

Objectives - To investigate the pulses intake of adolescent girls and boys of HIG and MIG in Bhopal city

Materials and Methods - This entire study was conducted in Bhopal City. In this research study 100 adolescent girls and boys of age 18-21 years were selected by purposive random sampling technique. Nutrient intake was determined by 24 hour recall method. In this study, a structured questionnaire was used regarding dietary intake and the usual pattern of food intake was examined using a 7-day food frequency questionnaire. Statistical analysis was done by using statistical tools like Z-test, mean, standard deviation, percentage, chi square test etc.

Results -

Table 1 (See in the last page)

Table 1 reveals that 7.6 %, 0.0 %, 14.0 %, 25.2 %, 21.2 % and 32.0 of adolescent girls and boys were taking moong dal daily, twice a day, twice a week, weekly, monthly and occasionally in MIG group as compared to 0.0 %, 0.0 %, 46.0 %, 48.8 %, 4.0 % and 1.2 % in HIG group respectively, whereas, 21.2 %, 0.0 %, 21.2 %, 24.4 %, 9.6 % and 23.6 % of adolescent girls and boys were taking tuar dal daily, twice a day, twice a week, weekly, monthly and occasionally in MIG group as compared to 0.0 %, 0.0 %, 66.8 %, 33.2 %, 0.0 % and 0.0 % in HIG group respectively. It was observed that 0.0 %, 0.4 %, 0.0 %, 9.2 %, 21.6 % and 68.8 of adolescent girls and boys were taking mosoor dal daily, twice a day, twice a week, weekly, monthly and occasionally in MIG group as compared to 0.0 %, 0.0 %, 5.2 %, 26.8 %, 32.4 % and 35.4 % in HIG group respectively, whereas, 0.0 %, 0.0 %, 0.0 %, 13.2 %, 47.2 % and 39.6 of adolescent girls and boys were taking chole daily, twice a day, twice a week, weekly, monthly and occasionally in MIG group as compared to 0.0 %, 0.0 %, 0.4 %, 24.8 %, 44.0 % and 30.8 % in HIG group respectively. It was found that 1.6 %, 0.0 %, 0.0 %, 11.6 %, 33.2 % and 53.6 % of adolescent girls and boys were taking rajmah daily, twice a day, twice a week, weekly, monthly and occasionally in MIG group as compared to 0.0 %, 0.0 %, 0.0 %, 19.6 %, 42.4 % and 38.0 % in HIG group respectively.

Conclusion - The findings indicate that highly significant difference for intake of moong dal, taur dal and massor dal; and non significant difference (P > 0.05), was observed for intake of chole and Rajmah in pulses intake of adolescent girls and boys in MIG and HIG groups. Highly significant difference (P < 0.05), was observed between the two groups in their percentages with a Chi- values of 72.5, 79.4 and 27.1 for moong dal, tur dal and massor dal, respectively, which implies that frequency of consumption of pulses in both the groups is different.

References :-

1. Gopalan C, Rama Shastri BV, Balasubramanium SC. Nutritive value of Indian Foods. Hyederabad, India: National Institute of Nutrition, Indian Council of Medical research. 1993.
2. Kaplan, M., N.E., & James, L. - Journal of Nutrition Education and Behavior.
3. Ahmed F, Khandker MAI. Dietary pattern and nutritional status of Bangladeshi manual workers (rickshaw pullers). Int J Food Sci Nutr 1997; 48: 285-91.

*Professor (Home Science) O.S.D. Directorate of Higher Education Of M.P. Govt. (M. P.) Bhopal (M.P.) INDIA
** Research Scholor (Home Science) Govt. Girl's Geetanjali College, Bhopal (M.P.) INDIA

Table 1
Distribution of adolescent girls and boys of MIG and HIG as per their pulses intake

Pulses	Indices	MIG		HIG		'Chi' Value($ë^2$)
		No	%	No	%	
Moong Dal	Daily	19	7.6	-	-	72.5**
	Twice a day	-	-	-	-	
	Twice a Week	35	14.0	15	46.0	
	Weekly	63	25.2	22	48.8	
	Monthly	53	21.2	10	4.0	
	Occasionally	80	32.0	3	1.2	
Tuar Dal	Daily	53	21.2	-	-	79.4**
	Twice a day	-	-	-	-	
	Twice a Week	53	21.2	67	66.8	
	Weekly	61	24.4	83	33.2	
	Monthly	24	9.6	-	-	
	Occasionally	59	23.6	-	-	
Masoor Dal	Daily	-	-	-	-	27.1**
	Twice a day	1	0.4	-	-	
	Twice a Week	-	-	13	5.2	
	Weekly	23	9.2	67	26.8	
	Monthly	54	21.6	81	32.4	
	Occasionally	172	68.8	89	35.4	
Chole	Daily	-	-	-	-	5.15 NS
	Twice a day	-	-	-	-	
	Twice a Week	-	-	1	0.4	
	Weekly	33	13.2	62	24.8	
	Monthly	18	47.2	10	44.0	
	Occasionally	99	39.6	77	30.8	
Rajmah	Daily	4	1.6	-	-	7.43 NS
	Twice a day	-	-	-	-	
	Twice a Week	-	-	-	-	
	Weekly	29	11.6	49	19.6	
	Monthly	83	33.2	6	42.4	
	Occasionally	34	53.6	95	38.0	

df =5

****

ग्रामीण क्षेत्रों में किशोर-किशोरियों में रोजगार के अवसर का अध्ययन

शारदा भिण्डे * डॉ. मंजू शर्मा **

शोध सारांश – ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर विगत वर्षो में सामाजिक संगठनात्मक ढाँचे में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं ग्रामों में रोजगार की तलाश में ग्रामीणों का शहरों की ओर पलायन की संख्या निरंतर बढ़ रही है इसका मुख्य कारण तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या एवं उतनी तेजी से गाँवों में घटते आजीविका के अवसर हैं शहरीकरण एवं औद्योगिकीकरण के फैलाव के फलस्वरूप कृषि योग्य भूमि कम होती जा रही हैं कृषि भूमि का आवासीय और औद्योगिक उद्देश्य से उपयोग होने का कारण आजीविका एवं रोजगार के अवसर भी समाप्त प्राय: होते जा रहे हैं।

प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य आलीराजपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में किशोर एवं किशोरियों में रोजगार के अवसर का अध्ययन किया गया हैं इनमें कुछ 72 किशोर-किशोरियों प्रतिदर्श में से 31 प्रतिशत कृषि में, 15 प्रतिशत अन्य रोजगार में संलग्न पाये गये हैं जबकि पारंपरिक एवं अन्य व्यवसाय में, 32 प्रतिशत मिश्रित व्यवसाय में, 13 प्रतिशत परंपरागत व्यवसाय में संलग्न पाये गये हैं। ग्रामीण क्षेत्र में किशोर-किशोरियों के लिए संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद भी आजाद भारत में ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति बेहतर नही हो पायी हैं।

प्रस्तावना – भारत में बेरोजगारी एवं अल्प बेरोजगारी की समस्याऐं एक लम्बे समय से चली आ रही है पिछले चार दशकों से चली आ रही हैं पिछले चार दशकों में कई पंचवर्षीय योजनाओं में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से गरीबी उन्मूलन की बात दावों से कही जा रही है परंतु यह धारणा मात्र एक दिवास्वप्न सिद्ध हुई हैं। लगभग 50 वर्षो के नियोजित विकास काल के बाद आज भी राष्ट्रीय स्तर पर जीवन की अनिवार्यताओं अर्थात रोटी व रोजगार की समस्याओं से ही जूझना पड़ रहा हैं, हम निर्धनता के निवारण, बेरोजगारी में कमी व आर्थिक विषमता में कमी का लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रहे हैं परिणामस्वरूप रोजगार के अभाव में एवं गलत चयन से आर्थिक स्थिति और भी कमजोर होती चली जा रही हैं।

विगत वर्षो में सामाजिक संगठनात्मक ढाँचे में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, ग्रामों में रोजगार की तलाश में ग्रामीणों का शहरों की ओर पलायन की संख्या निरंतर बढ़ रही हैं इसका मुख्य कारण तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या एवं उतनी तेजी से गाँवों में घटते आजीविका के अवसर हैं 'शहरीकरण एवं औद्योगिकीकरण के फैलाव के फलस्वरूप कृषि योग्य भूमि कम होती जा रही है, कृषि भूमि का आवासीय और औद्योगिक उद्देश्य से उपयोग होने का कारण आजीविका एवं रोजगार के अवसर भी समाप्त प्राय: होते जा रहे हैं जो पूर्व में कृषि कार्य या कृषि भूमि के कारण ग्राम में भी उपलब्ध हो जाया करते थे।

सामाजिक ढाँचे एवं अर्थव्यवस्था में आये इन परिवर्तन ने पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले अन्य वर्गो के साथ-साथ आदिवासियों के जीवन को भी प्रभावित किया हैं, आदिवासी साधारणतय मुख्य बसाहट से दूर निवास करते हैं इनकी आजीविका का मुख्य साधन वन एवं वनोपज हैं विकास की अंधी दौड़ के चलते और बढ़ते हुए शहरीकरण ने उन्हें भी अपनी चपेट में ले लिया हैं इसके परिणामस्वरूप इनकी आजीविका के परम्परागत साधन/अवसर भी तेजी से परिवर्तन दृष्टिगत हो रहा हैं।

आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र सामान्यत: आर्थिक पिछडेपन के शिकार होते हैं विकास के क्षेत्रीय असंतुलन के ऐसे क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता हैं। पिछड़ेपन के कारण एवं विभिन्न परिवर्तनों के परिणामस्वरूप ऐसे क्षेत्रों में भी बेरोजगारी एक गंभीर समस्या हैं।

नगरीकरण एवं औद्योगिकीकरण से गाँव से रोजगार के साधन न होने के कारण एवं आमतौर से ग्रामीण एवं अपने परम्परागत उद्योग धंधों का छोड़ने के कारण किशोर वर्ग गाँव छोड़कर चला जाता हैं ऐसे युवकों को शहरों में अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता हैं।

शोध की समस्या की आवश्यकता – आज आवश्यकता है कि गाँव के उन तमाम कमजोर वर्गो के युवाओं को बेरोजगारी की गर्त से निकालना है जो युवक बेरोजगारी के कारण अपना गाँव एवं घर छोड़कर महानगरों की अंधेरी गलियों में भटकने जा रहे हैं। इसलिए वर्तमान समय में इस विषय का अध्ययन करना आवश्यक ही नही वरन अनिवार्य भी हैं जिससे इस योजना के अध्ययन द्वारा हितग्राहियों की स्थिति में आये परिवर्तन समस्याओं को सामने लाने का अवसर मिलेगा एवं उनके द्वारा प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखकर नई योजनाएँ आरम्भ की जा सकेगी।

युवाओं में बढ़ती हुई बेरोजगारी वर्तमान समय की ज्वलंत समस्या हैं इस समस्या से निपटने के लिये अनेकों कार्यक्रम राज्य एवं केंद्रीय सरकारों द्वारा चलाये जा रहे हैं जिसमें से अधिकांश: कार्यक्रमों का मूलभूत उद्देश्य युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में प्रशिक्षित प्रोत्साहित करना हैं क्योंकि सभी बेरोजगारी युवाओं को नौकरी प्रदान नही की जा सकती।

अत: रोजगार ही ऐसा माध्यम है जो इस समस्या का सही हल सिद्ध हो सकता हैं। रोजगार उद्योग स्थापना न केवल बेरोजगारी से निदान पाने के लिए आवश्यक हैं।

शोध अध्ययन के उद्देश्य –

1. आदिवासी क्षेत्रों में किशोर-किशोरियों के लिए उपलब्ध रोजगार के अवसरों का अध्ययन करना।
2. आदिवासी किशोर-किशोरियों में परम्परागत व्यवसाय एवं उसमें आये परिवर्तन का अध्ययन करना।

* शोधार्थी, माता जीजाबाई शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मोती तबेला, इंदौर (म.प्र.) भारत
** प्राध्यापक (गृह विज्ञान) माता जीजाबाई शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मोती तबेला, इंदौर (म.प्र.) भारत

शोध अध्ययन की उपकल्पना –

1. आदिवासी क्षेत्रों में किशोर–किशोरियों के लिए उपलब्ध रोजगार के अवसरों में सार्थक अंतर नही होगा।
2. आदिवासी किशोर–किशोरियों में परम्परागत व्यवसाय एवं उसमें आये परिवर्तन में सार्थक अंतर नही होगा।

शोध प्रविधि – शोध प्रविधि शोध अध्ययन हेतु तथ्यों एवं घटनाओं को समझने की एक निश्चित कार्य पद्धति है जो हमें अनुसंधान के लिए विभिन्न चरणों के माध्यम से दिशा निर्देशन का कार्य करती है। शोध प्रविधि के अंतर्गत निम्न चरण को सम्मिलित किया जाता हैं।

अध्ययन का समग्र – अध्ययन समग्र के रूप में मध्यप्रदेश के अलीराजपुर जिले में निवास करने वाले आदिवासी किशोर–किशोरियों को लिया गया हैं।

अध्ययन का क्षेत्र – प्रस्तुत शोध में अध्ययन क्षेत्र के रूप में मध्यप्रदेश के अलीराजपुर के संपूर्ण विकासखण्ड लिए गए हैं। द्वितीय चरण में प्रत्येक विकासखण्ड से 2–2 गाँवों का चयन किया गया हैं। प्रत्येक गाँव में 12 निदर्शन 6 किशोर 6 किशोरियों का चयन किया गया हैं इस प्रकार कुल 72 निदर्शन के रूप में किशोर–किशोरियों को अलीराजपुर जिले से चयनित किया गया हैं।

शोध अध्ययन की निदर्शन इकाई – शोध अध्ययन में शोध इकाई के रूप में मध्यप्रदेश के अलीराजपुर जिले के उन आदिवासी किशोर–किशोरियों का चयन निम्न विशेषताओं के आधार पर किया गया हैं।

1. उन्हीं किशोर–किशोरियों को लिया गया हैं जो अलीराजपुर जिले में निवास करते हैं।
2. वे किशोर–किशोरियों जो आदिवासी वर्ग से हो।
3. प्रस्तुत शोध अध्ययन में उन्हीं किशोर–किशोरियों को सम्मिलित किया गया हैं जिनकी आयु 17 से 24 के बीच हैं।

निदर्शन का आकार –प्रस्तुत शोध अध्ययन में कुल 72 निदर्शन लिये गये हैं जिनमें 36 किशोर, 36 किशोरियों को सम्मिलित किया गया है।

निदर्शन विधि – 'निदर्शन समग्र का एक छोटा सा अंश है जो कि समग्र का प्रतिनिधित्व करता है तथा जिसमें समग्र की मौलिक विशेषताएँ पायी जाती है' प्रस्तुत शोध में कुल 72 निदर्शन का चयन हेतु दैव निदर्शन एवं उद्देश्यपूर्ण विधि से आवयकतानुसार किया गया हैं।

उपकरण का चुनाव – प्रस्तुत शोध कार्य में शोध उपकरण के रूप में स्वनिर्मित साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया हैं।

समंक संकलन के स्त्रोंत –

1. प्राथमिक समंको का संकलन – प्राथमिक समंको के संकलन हेतु स्वनिर्मित साक्षात्कार अनुसूची का उपयोग किया गया हैं।

2. द्वितीय समंको का संकलन –द्वितीय समंक संकलन के लिये संबंधित शोध पुस्तकों, पत्र–पत्रिकाओं, समाचार–पत्र, संबंधी योजनाओं की रिपोर्ट, शोध–ग्रंथ, इंटरनेट अन्य सूचना माध्यमों का उपयोग किया गया हैं।

प्रयुक्त सांख्यिकी विधि – प्रस्तुत शोध अध्ययन में संकलित तथ्यों का वर्गीकरण, सारणीयन किया गया हैं, सारणी में प्रतिशत के आधार पर तथ्यों का प्रस्तुतीकरण किया गया हैं, संबंधित तथ्यों का चित्रमय प्रदर्शन भी किया गया हैं। निष्कर्षो की विश्वनियता हेतु उपकल्पना की सार्थकता ज्ञात करने के लिए काई वर्ग परीक्षण का प्रयोग किया गया हैं।

अध्ययन की सीमाएँ –प्रस्तुत शोध अध्ययन में निम्नलिखित सीमाओं का निर्धारण किया गया हैं।

1. अध्ययन का समग्र – प्रस्तुत शोध अध्ययन का क्षेत्र के रूप में मध्यप्रदेश के आदिवासी जिला अलीराजपुर ही शामिल किया गया हैं।

2. निदर्शन का आकार – प्रस्तुत शोध अध्ययन के लिए कुल 72 निदर्शन का चयन जिसमें से 36 आदिवासी किशोर और 36 आदिवासी किशोरियाँ हैं।

3. अध्ययन का क्षेत्र – प्रस्तुत शोध अध्ययन में अध्ययन क्षेत्र के रूप में मध्यप्रदेश के अलीराजपुर जिले के संपूर्ण विकासखण्ड लिए गए हैं। प्रत्येक विकासखण्ड से दो–दो गाँवों का चयन किया गया हैं।

4. शोध उपकरण – स्वनिर्मित साक्षात्कार अनुसूची का उपयोग किया गया हैं।

तालिका क्रमांक व ग्राफ– 1 (देखे अगले पृष्ठ पर)

प्रस्तुत शोध में कुल 72 आदिवासी किशोर–किशोरियों प्रतिदर्श में से 31 प्रतिशत कृषि में, 22 प्रतिशत व्यवसाय में, 10 प्रतिशत नौकरी में, 22 प्रतिशत मजदूरी में, 15 प्रतिशत अन्य रोजगार में संलग्न पाये गये हैं।

आदिवासी किशोर में कुल 36 आदिवासी किशोर प्रतिदर्श में से 33 प्रतिशत कृषि में, 19 प्रतिशत व्यवसाय में, 9 प्रतिशत नौकरी में, 25 प्रतिशत मजदूरी में, 14 प्रतिशत अन्य रोजगार में संलग्न पाये गये है।

आदिवासी किशोरियों में कुल 36 आदिवासी किशोरियों प्रतिदर्श में से 28 प्रतिशत कृषि में, 25 प्रतिशत व्यवसाय में, 11 प्रतिशत नौकरी में, 19 प्रतिशत मजदूरी में, 17 प्रतिशत अन्य रोजगार में संलग्न पाये गये हैं।

तालिका क्रमांक व ग्राफ – 2 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

प्रस्तुत शोध अध्ययन में कुल 72 आदिवासी किशोर–किशोरियों प्रतिदर्श में से 13 प्रतिशत परम्परागत व्यवसाय में, 31 प्रतिशत परिवर्तित व्यवसाय में, 31 प्रतिशत मिश्रित व्यवसाय में, 25 प्रतिशत अन्य व्यवसाय में संलग्न पाये गये हैं।

आदिवासी किशोर में कुल 36 आदिवासी किशोर प्रतिदर्श में से 11 प्रतिशत परम्परागत व्यवसाय में, 28 प्रतिशत परिवर्तित व्यवसाय में 39 प्रतिशत मिश्रित व्यवसाय में, 22 प्रतिशत अन्य व्यवसाय में संलग्न पाये गये हैं।

आदिवासी किशोरियों में कुल 36 आदिवासी किशोरियों प्रतिदर्श में से 17 प्रतिशत परम्परागत व्यवसाय में, 33 प्रतिशत परिवर्तित व्यवसाय में, 22 प्रतिशत मिश्रित व्यवसाय में, 28 प्रतिशत अन्य व्यवसाय में संलग्न पाये गये हैं।

तालिका क्रमांक व ग्राफ – 3 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

प्रस्तुत शोध अध्ययन में कुल 72 आदिवासी किशोर–किशोरियों प्रतिदर्श मे से 32 प्रतिशत साज–सज्जा व बैठक व्यवसाय में, 33 प्रतिशत तकनीक संबंध में, 25 प्रतिशत उन्नत बीज में, 10 प्रतिशत अन्य व्यवसाय में परिवर्तन देखा गया हैं।

आदिवासी किशोर में कुल 36 आदिवासी किशोर प्रतिदर्श में से 22 प्रतिशत साज–सज्जा व बैठक में, 39 प्रतिशत तकनीक संबंध में, 28 उन्नत बीज में, 11 प्रतिशत अन्य व्यवसाय में परिवर्तन देखा गया हैं।

आदिवासी किशोरियों में कुल 36 आदिवासी किशोरियों प्रतिदर्श में से 41 प्रतिशत साज–सज्जा व बैठक व्यवसाय में, 28 प्रतिशत तकनीक संबंध में, 22 प्रतिशत उन्नत बीज में, 11 प्रतिशत अन्य व्यवसाय में देखा गया हैं।

समस्याएँ एवं सुझाव –

1. कृषि क्षेत्र में घटते लाभों के कारण आदिवासी वर्ग अन्य कार्यो की ओर उन्मुख हो रहे हैं। इस हेतु उन्हें अपने गाँव के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर

भी कार्य करने जाना पड़ता हैं। इस वजह से उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता हैं। इस हेतु महत्वपूर्ण यह सुझाव हैं कि इन आदिवासियों को स्वरोजगार हेतु कुशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाये ताकि कृषि में लाभ कम होने पर मजदूर बनने और इधर-उधर भटकने के बजाय अपना स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ कर सके।

2. आदिवासियों के समक्ष एक समस्या यह है कि उन्हे वर्ष में कुछ ही महीने काम मिलता हैं। इस स्थिति में उन्हें अनेक कठिनाईयों का सामना करते हुए अन्य कार्य करने अन्यत्र जाना पड़ता हैं। आज भी अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों का सही क्रियान्वयन नहीं हो पाया हैं। इस हेतु सुझाव यह हैं कि यदि वास्तव में आदिवासियों का विकास करना हैं, तो नीतिगत निर्णयों में उनके प्रतिनिधित्व को भी स्वीकार किया जाए तथा ऐसी नीतियाँ बनाई जाएँ जिससे कि आदिवासियों को अपने गाँव में ही वर्ष भर काम उपलब्ध हो सके और उन्हें अन्यत्र जाने की आवश्यकता न पडे।

संदर्भ गंथ सूची :-

1. शर्मा एवं अग्रवाल एस.सी. एवं श्रीमति आर 'जनजातिय समाज का समाजशास्त्र' विद्या भवन प्रकाशन (म.प्र.)।
2. मुखर्जी रविन्द्र (2011), 'सामाजिक अनुसंधान का पद्धतिशास्त्र' अलंकार प्रकाशन इंदौर।
3. कपिल एच.के. (2012), 'अनुसंधान विधियाँ' एस.पी. भार्गव बुक हाऊस आगरा।
4. कुल श्रेष्ठ महेन्द्र प्रताप 'कृषि सांख्यिकी एवं प्रयोग अभिकल्पनायें' भारती भंडार, बडौत (मेरठ)।
5. कोठारी डॉ. मिलिंद (2009), 'व्यवसायिक संगठन' रमेश बुक डिपो जयपुर।
6. प्रसाद एन (1961), 'भारतीय समाज में जनजातियाँ' बिहार जनजातीय शोध संस्थान बिहार सरकार, राँची।
7. सिकलीगर, पूनमचंद (1994), 'वन एवं आदिवासी सामाजिक जीवन' शिवा पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, उदयपुर।
8. धरामी, अजय कुमार, ए.एन. (2001), 'जनजातीय क्षेत्रों में रोजगार की समस्या जनजाति, भारतीय आदिम जाति सेवक संघ नई दिल्ली वॉल्यूम X,LIX, NO.4

तालिका क्रमांक - 1

ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध रोजगार के विभिन्न अवसरों में संलग्नता संबंधी विवरण

क्रमांक	रोजगार के अवसरों का विवरण	किशोरों की संख्या %	किशोरियों की संख्या %	कुल योग की संख्या %
1.	कृषि	33	28	31
2.	व्यवसाय	19	25	22
3.	नौकरी	9	11	10
4.	मजदूरी	25	19	22
5.	अन्य रोजगार	14	17	15
	योग	100 N=36	100 N=36	100 N=72

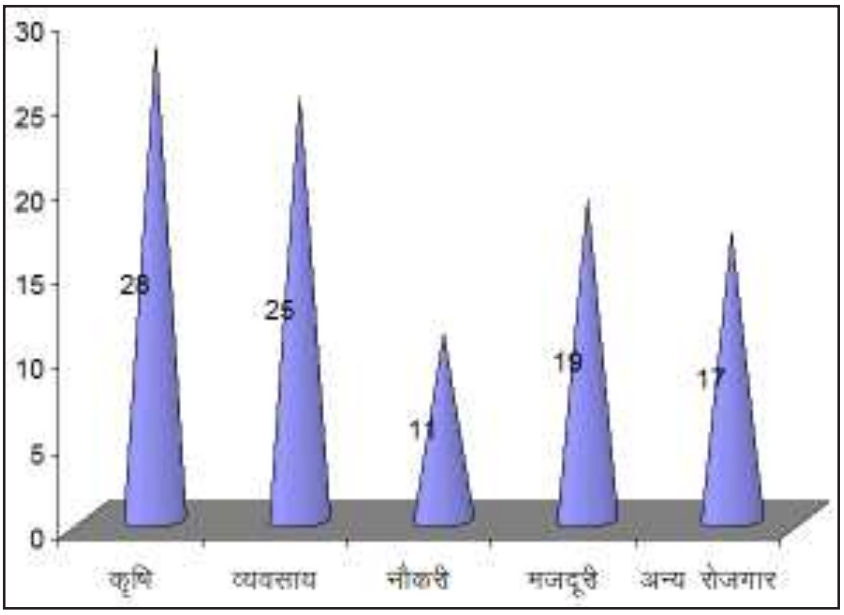

तालिका क्रमांक – 2

ग्रामीण किशोर–किशोरियों के पारम्परिक एवं अन्य व्यवसाय में संलग्नता संबंधी विवरण

क्रमांक	पारम्परिक एवं अन्य व्यवसाय में संलग्नता संबंधी विवरण	किशोरों की संख्या %	किशोरियों की संख्या %	कुल योग की संख्या %
1.	परम्परागत व्यवसाय	11	17	13
2.	परिवर्तित व्यवसाय	28	33	31
3.	मिश्रित व्यवसाय	39	22	31
4.	अन्य व्यवसाय	22	28	25
	योग	100 N=36	100 N=36	100 N=72

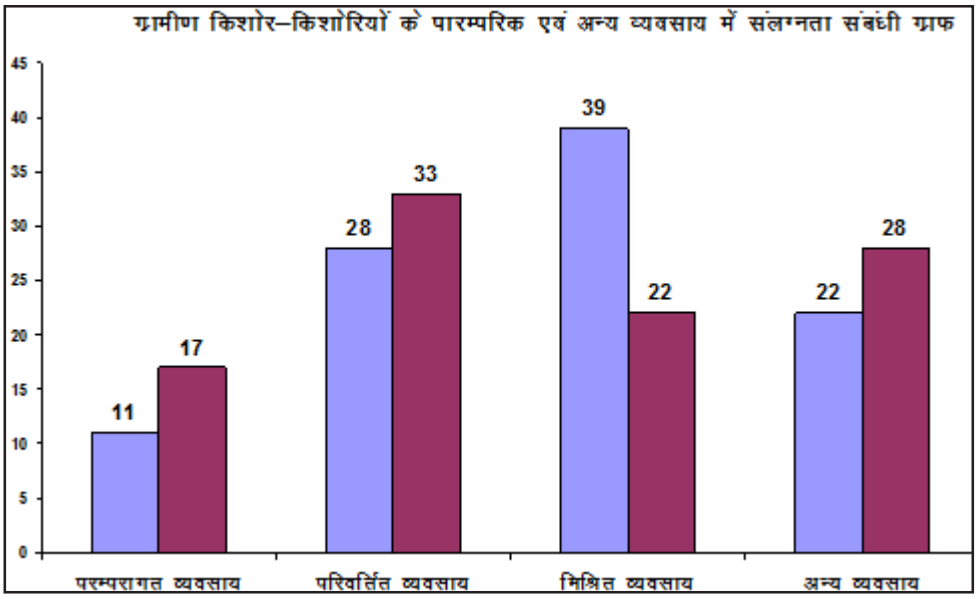

तालिका क्रमांक – 3

ग्रामीण किशोर–किशोरियों के पारम्परिक व्यवसाय में परिवर्तन संबंधी विवरण

क्रमांक	पारम्परिक व्यवसाय में परिवर्तन का विवरण	किशोरों की संख्या %	किशोरियों की संख्या %	कुल योग की संख्या %
1.	साज–सज्जा व बैठक व्यवसाय	22	41	32
2.	तकनीक संबंध	39	28	33
3.	उन्नत बीज	28	22	25
4.	अन्य योग	11 100 N=36	9 100 N=36	10 100 N=72

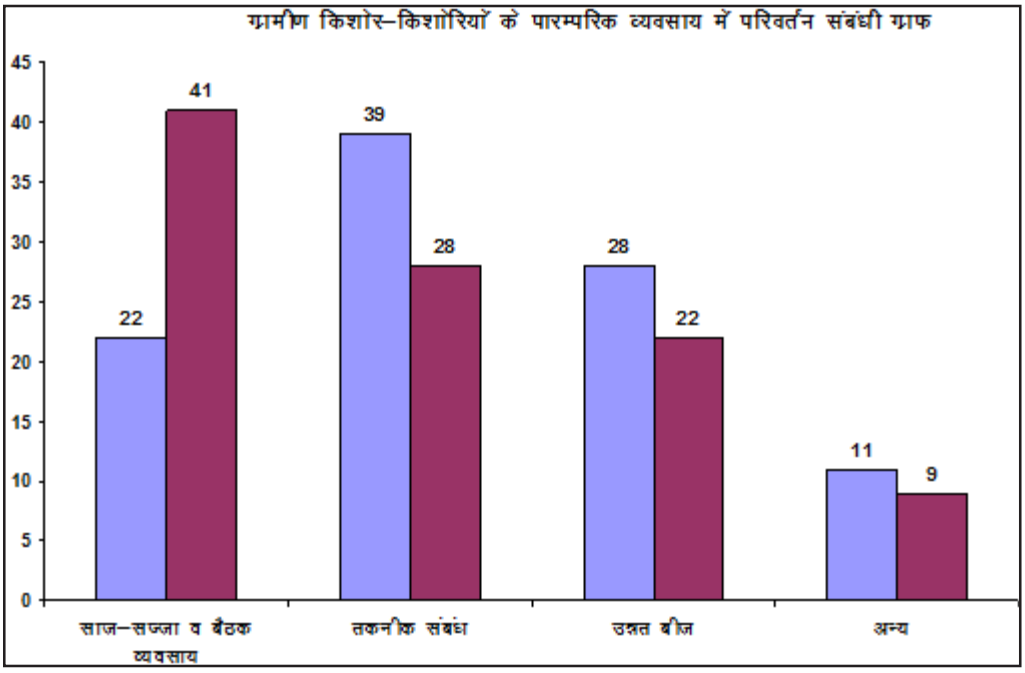

****

इंटरनेट की लत का किशोर बालक एवं बालिकाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव

डॉ. आभा तिवारी * निरंजना धोटे **

शोध सारांश – प्रस्तुत शोध में इंटरनेट की लत का किशोर बालक एवं बालिकाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन किया गया है। अध्ययन हेतु न्यादर्श में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल एवं मध्यप्रदेश शिक्षा मण्डलों के 150–150 किशोर बालक एवं बालिकाओं को लिया गया है। शोधकर्त्ता द्वारा निर्मित इंटरनेट की लत मापनी से छाटे गये अधिक एवं कम लत वाले बालक एवं बालिकाओं पर डॉ. श्रीमती कमलेश शर्मा द्वारा निर्मित मानसिक स्वास्थ्य मापनी का प्रशासन कर निष्कर्ष प्राप्त किये गये, निष्कर्षो से ज्ञात होता है कि इंटरनेट की लत का किशोर बालक एवं बालिकाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर सार्थक प्रभाव पड़ता है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल के किशोर बालक एवं बालिकाओं के इंटरनेट की लत का उनके मानसिक स्वास्थ्य पर सार्थक प्रभाव पड़ता है एवं सम्मिलित समूह के बालक एवं बालिकाओं पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है। माध्यमिक शिक्षा मण्डल के किशोर बालक एवं बालिकाओं के इंटरनेट की लत का उनके मानसिक स्वास्थ्य के बालकों पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है, बालिकाओं एवं सम्मिलित समूह के बालक एवं बालिकाओं पर सार्थक प्रभाव पड़ता है।

शब्द कुंजी – किशोरावस्था, इंटरनेट की लत, मानसिक स्वास्थ्य ।

प्रस्तावना – किशोरावस्था सबसे अधिक वृद्धि और विकास का समय है। इस उम्र में बुद्धि अपनी चरम सीमा तक पहुँचने का प्रयत्न करती है तथा तार्किक चिन्तन, सूक्ष्म और गहन विचार शक्ति, एकाग्रता आदि सभी मानसिक शक्तियाँ पर्याप्त विकसित हो जाती है। किशोरावस्था में भावना, कल्पना, मौलिकता का सम्मिलित अनुकूल प्रवाह अनेक लेखक, कवि, चित्रकार, मूर्तिकार, संगीतज्ञ, दर्शन–शास्त्री तथा अन्वेषकों को जन्म देता है, दूसरी ओर कल्पना की निष्क्रियता और लक्ष्यहीनता किशोर को दिवास्वरूप देखने वाला और अकर्मण्य व्यक्ति बना सकती है। कुन्हन के अनुसार 'किशोरावस्था बाल्यकाल और प्रौढ़ावस्था के मध्य का परिवर्तन काल है।'

किशोरावस्था में वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप व्यक्तित्व के सभी आयामों शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, आदि विकसित हो जाते हैं। जिसके कारण हम किशोरावस्था को एक नया जन्म की संज्ञा देते हैं। किशोरावस्था संपूर्ण जीवन की इमारत होती है, शैक्षणिक दृष्टि से किशोरावस्था का सर्वाधिक महत्व है, इसके लिये आवश्यकता इस बात की है कि हम किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताओं तथा शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास से अच्छी तरह से अवगत हो। एल.टी.लाम (2009) ने इंटरनेट की लत एवं किशोरावस्था में आत्म हानिकार व्यवहार एवं मानसिक स्वास्थ्य के मध्य संबंध का अध्ययन किया। अध्ययन से जो निष्कर्ष प्राप्त हुए इनसे यह ज्ञात हुआ कि किशोरों में इंटरनेट की लत मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है एवं किशोरों में स्वयं को चोट पहुँचाने की प्रवृत्ति को अधिक बढ़ाती है।

मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक शक्तियों के उचित विकास तथा मन को स्वस्थ एवं सुखी बनाने के लिए आवश्यक है। जे.ए. हैडफील्ड के अनुसार 'मानसिक स्वास्थ्य से तात्पर्य है व्यक्ति के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का अपने पूर्णरूप से अच्छी तरह तालमेल बिठाते हुए कार्य करते रहना। वर्तमान समय में जो पर्यावरण है वह नित्य बदलता जा रहा है, इंटरनेट सोशल, नेटवर्किंग साइटों का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है तथा किशोरावस्था में इंटरनेट की लत एक सामाजिक समस्या के रूप में सामने आयी है, इंटरनेट के अधिक उपयोग के कारण किशोरों के स्कूल उपलब्धि में कमी देखने को मिलती है एवं इसकी वजह से किशोरों को समय से पहले गलत जानकारी प्राप्त होती है, जिसकी वजह से किशोरों का मानसिक स्वास्थ्य का विकास एक गलत तरीके से विकसित होता हैं।

हुसैन (2013) ने ईरान के किशोरों में इंटरनेट का उपयोग करने और मानसिक स्वास्थ्य के मध्य संबंध का अध्ययन किया। अध्ययन से जो निष्कर्ष प्राप्त हुए इनसे यह ज्ञात हुआ कि किशोरों में इंटरनेट का उपयोग और मानसिक स्वास्थ्य के मध्य महत्वपूर्ण सहसंबंध पाया गया।

अत: इंटरनेट का प्रभाव किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है या नहीं ? यदि प्रभावित करता है तो हमें प्रयास करना होगा कि हम किशोर बालक एवं बालिकाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर इंटरनेट की लत का प्रभाव न पड़ सके साथ ही अध्ययन के आधार पर न केवल बालक को वरन् उनके अभिभावकों को भी परामर्श दिया जा सकेगा।

उद्देश्य –

1. इंटरनेट की लत का किशोर बालक एवं बालिकाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन।
2. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल एवं मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डलों के किशोर बालक एवं बालिकाओं के इंटरनेट की लत का उनके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन।

परिकल्पना –

1. इंटरनेट की लत किशोर बालक एवं बालिकाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है।
2. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल एवं मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डलों के किशोर बालक एवं बालिकाओं के इंटरनेट की लत का उनके मानसिक स्वास्थ्य पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है।

न्यादर्श – शोध कार्य हेतु निम्नानुसार न्यादर्श लिया गया है –

* प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (मानव विकास) शासकीय मो.ह.गृहविज्ञान एवं विज्ञान महिला महाविद्यालय (स्वशासी) जबलपुर (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, शासकीय मो.ह.गृहविज्ञान एवं विज्ञान महिला महाविद्यालय, (स्वशासी) जबलपुर (म.प्र.) भारत

न्यादर्श तालिका

क्र.	माध्यम	बालक	बालिका	योग
1	केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल	150	150	300
2	मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल	150	150	300
	योग	300	300	600

उपरोक्त प्रारंभिक न्यादर्श में किशोरों पर इंटरनेट उपयोग मापनी का प्रशासन किया गया। फलांकन के उपरान्त इंटरनेट का अधिक एवं कम उपयोग करने वाले किशोरों को निम्नानुसार लिया गया, बालक एवं बालिकाओं की संख्या निम्नांकित तालिका में अंतिम न्यादर्श के रूप में प्रदर्शित की गयी है –

अंतिम न्यादर्श

इंटरनेट	बोर्ड	छात्र	छात्राएँ	योग
अधिक लत	केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल	39	50	89
	मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल	39	32	71
कम लत	केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल	44	38	82
	मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल	36	42	78
	योग	158	162	320

आवश्यक उपकरण –

1. मानसिक स्वास्थ्य मापनी – डॉ. श्रीमती कमलेश शर्मा
2. इंटरनेट का उपयोग संबंधी स्वनिर्मित परीक्षण।

विधि – केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल एवं मध्यप्रदेश शिक्षा मण्डलों के विद्यालयों के न्यादर्श में चयनित छात्र एवं छात्राओं पर इंटरनेट की लत मापनी का प्रशासन कर फलांकन किया गया एवं इंटरनेट की अधिक एवं कम लत वाले छात्र–छात्राओं को अलग–अलग कर उन पर मानसिक स्वास्थ्य मापनी का प्रशासन किया गया, फलांकन के उपरान्त सांख्यिकीय विश्लेषण कर निष्कर्ष प्राप्त किये गये।

परिणामों का विश्लेषण एवं व्याख्या – इंटरनेट की लत का किशोर बालक एवं बालिकाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव हेतु न्यादर्श से प्राप्त परिणामों का विश्लेषण निम्नानुसार है –

तालिका क्रमांक – 01 (देखे आगे वाले पृष्ठ पर)

तालिका क्रमांक 01 में इंटरनेट की अधिक व कम लत वाले बालक एवं बालिकाओं के सम्मिलित समूह के मानसिक स्वास्थ्य पर इंटरनेट की लत में अंतर संबंधी परिणामों से स्पष्ट होता है कि इंटरनेट की लत का मानसिक स्वास्थ्य पर सार्थक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि क्रांतिक अनुपात का मान 0.01 स्तर के न्यूनतम सारणी मान की अपेक्षा अधिक है। अत: पूर्व में ली गई परिकल्पना अस्वीकृत होती है।

तालिका क्रमांक – 02 (देखे आगे वाले पृष्ठ पर)

तालिका क्रमांक 02 में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल के इंटरनेट की अधिक व कम लत वाले बालक एवं बालिकाओं के सम्मिलित समूह के मानसिक स्वास्थ्य पर इंटरनेट की लत में अंतर संबंधी परिणामों से स्पष्ट होता है कि इंटरनेट की अधिक व कम लत वाले बालक एवं बालिकाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर सार्थक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि प्राप्त क्रांतिक अनुपात का मान 0.05 स्तर के न्यूनतम सारणी मान की अपेक्षा अधिक है। इंटरनेट की अधिक व कम लत वाले सम्मिलित समूह के बालक एवं बालिकाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि प्राप्त क्रांतिक अनुपात का मान 0.05 स्तर के न्यूतनम सारणी मान की अपेक्षा कम है। अत: पूर्व में ली गई परिकल्पना आंशिक रूप से सत्यापित होती है।

तालिका क्रमांक – 03 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

तालिका क्रमांक 03 में मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डलों के इंटरनेट की अधिक एवं कम लत वाले बालक एवं बालिकाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर इंटरनेट की लत संबंधी परिणामों से स्पष्ट होता है कि इंटरनेट की अधिक एवं कम लत वाले बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि प्राप्त अनुपात 0.05 स्तर के न्यूनतम सारणी मान की अपेक्षा कम है। इंटरनेट की अधिक एवं कम लत वाली बालिकाओं एवं सम्मिलित समूह के बालक एवं बालिकाओं में सांख्यिकीय दृष्टिकोण से सार्थक प्रभाव पड़ता है, प्राप्त क्रांतिक अनुपात का मान 0.05 स्तर के न्यूनतम सारणी मान की अपेक्षा अधिक है। अत: पूर्व में ली गई परिकल्पना आंशिक रूप से सत्यापित होती है।

ग्रिटसेलिस (2011) ने इंटरनेट की लत, सामाजिक विकास एवं मानसिक विकार के मध्य संबंध का अध्ययन किया। अध्ययन से जो निष्कर्ष प्राप्त हुए इनसे यह ज्ञात हुआ कि माता–पिता के पारिवारिक संबंध, किशोरों का स्कूल में अनुपस्थित, स्वयं को चोट पहुँचाने की प्रवृत्ति किशोरों में 3.81 प्रतिशत अधिक एवं इंटरनेट की लत, मानसिक विकार की प्रवृत्ति किशोरों में 3.89 प्रतिशत होने की संभावना पायी गई।

उपरोक्त परिणामों से स्पष्ट होता है कि इंटरनेट की अधिक लत वाले बालक एवं बालिकाओं का मानसिक स्वास्थ्य पर कम लत वाले बालक एवं बालिकाओं की अपेक्षा अधिक अच्छा है। इंटरनेट का उपयोग विद्यार्थी शैक्षिक जानकारी, प्रोजेक्ट कार्य, अपने विभिन्न विषयों में दक्षता हासिल करने के लिए इन साइटों का उपयोग करके अपने ज्ञान को और अधिक विकसित करते हैं। इंटरनेट की कम लत वाले बालक एवं बालिका इंटरनेट का उपयोग केवल उन साइटों को देखते हैं जो उनके उपयोग की है। अत: किशोर बालक एवं बालिकाओं के अभिभावकों को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि बालक एवं बालिका अन्य साइटों की अपेक्षा उन साइटों को भी देखे जो उनके भावी जीवन के लिए उपयोगी हैं, जिससे उनके जीवन में विविध ज्ञान की प्राप्ति में सहायक होगी जो उनके मानसिक स्वास्थ्य में उन्नयन हो सके।

निष्कर्ष –

1. इंटरनेट की लत का किशोर बालक एवं बालिकाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर सार्थक प्रभाव पड़ता है।
2. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल के किशोर बालक एवं बालिकाओं के इंटरनेट की लत का उनके मानसिक स्वास्थ्य पर सार्थक प्रभाव पड़ता है एवं सम्मिलित समूह के बालक एवं बालिकाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है।
3. माध्यमिक शिक्षा मण्डल के किशोर बालक एवं बालिकाओं के इंटरनेट की लत का उनके मानसिक स्वास्थ्य पर इंटरनेट की अधिक एवं कम लत वाले बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है एवं इंटरनेट की अधिक एवं कम लत वाली बालिकाओं एवं सम्मिलित समूह के बालक एवं बालिकाओं पर सार्थक प्रभाव पड़ता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. सुरेश भटनागर, बाल विकास एवं बाल मनोविज्ञान, पृ.सं. 355–361.

2. एस.के. मंगल (2013) शिक्षा मनोविज्ञान तथा पी.एच.आई. लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली, पृ.सं. 172-182
3. www.fubmed.com
4. www.google.com
5. www.wikipedia
6. www.hchi.nim-nih.20V

तालिका क्रमांक - 01

इंटरनेट की अधिक व कम लत वाले बालक एवं बालिकाओं के सम्मिलित समूह के मानसिक स्वास्थ्य में अंतर संबंधी परिणाम

लिंग	इंटरनेट की लत	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	क्रांतिक अनुपात	'पी' मान
बालक	अधिक	78	78.32	15.33	2.82	< 0.01
	कम	80	70.89	18.38		
बालिका	अधिक	82	80.29	12.60	3.15	< 0.0
	कम	80	73.99	12.87		
बालक एवं बालिका	अधिक	160	79.33	13.99	4.12	< 0.01
	कम	160	72.49	15.89		

स्वतंत्रता के अंश - 158,162
0.05 स्तर पर सार्थकता हेतु मान - 1.98
0.01 स्तर पर सार्थकता हेतु मान - 2.61

स्वतंत्रता के अंश - 320
0.05 स्तर पर सार्थकता हेतु मान - 1.97
0.01 स्तर पर सार्थकता हेतु मान - 2.59

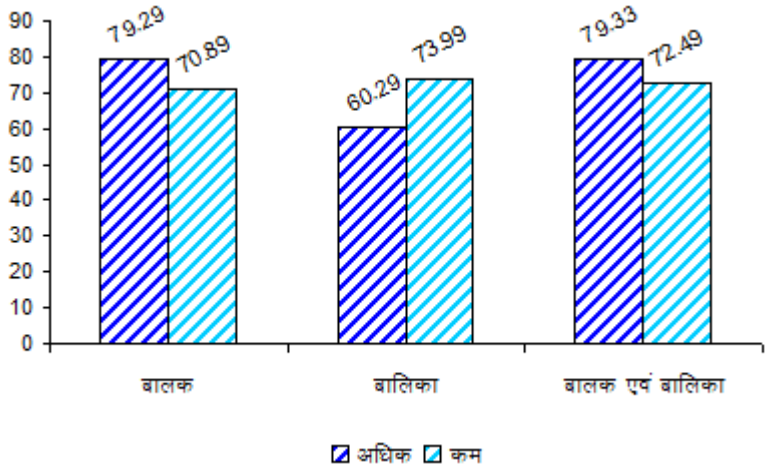

तालिका क्रमांक - 02

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल के इंटरनेट की अधिक व कम लत वाले बालक एवं बालिकाओं के सम्मिलित समूह के मानसिक स्वास्थ्य में अंतर संबंधी परिणाम

लिंग	इंटरनेट की लत	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	क्रांतिक अनुपात	पीमान
बालक	अधिक	39	75.56	17.74	2.20	< 0.05
	कम	44	67.93	13.24		
बालिका	अधिक	50	79.74	12.99	2.27	< 0.05
	कम	38	73.61	18.19		
बालक एवं बालिका	अधिक	89	77.91	15.30	3.40	0.05
	कम	82	70.56	13.01		

स्वतंत्रता के अंश - 81,86
0.05 स्तर पर सार्थकता हेतु मान - 1.99
0.01 स्तर पर सार्थकता हेतु मान - 2.63,2.64

स्वतंत्रता के अंश - 169
0.05 स्तर पर सार्थकता हेतु मान - 1.98
0.01 स्तर पर सार्थकता हेतु मान - 2.61

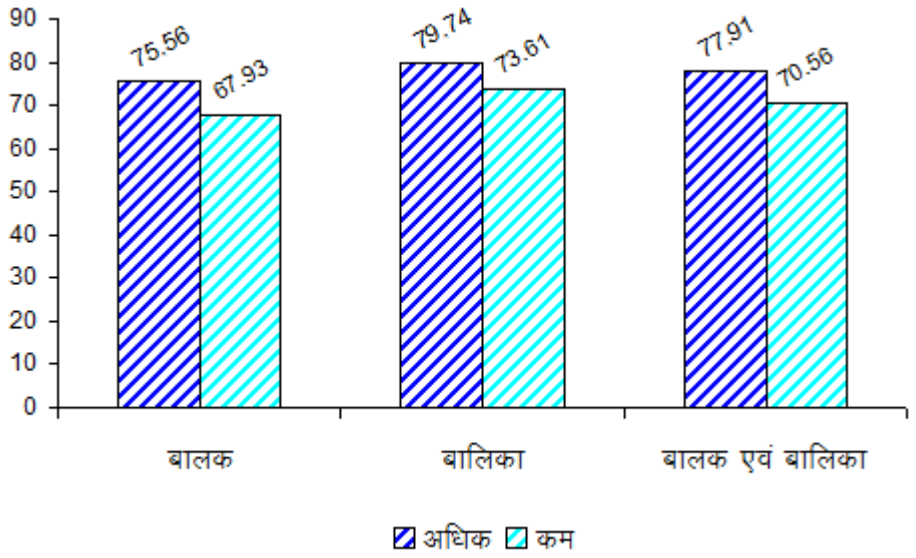

तालिका क्रमांक – 03मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल के इंटरनेट की अधिक व कम लत वाले बालक एवं बालिकाओं के सम्मिलित समूह के मानसिक स्वास्थ्य में अंतर संबंधी परिणाम

लिंग	इंटरनेट की लत	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	क्रांतिक अनुपात	पीमान
बालक	अधिक	39	81.03	12.06	1.54	0.05
	कम	36	74.50	22.36		
बालिका	अधिक	32	81.16	12.13	2.27	< 0.05
	कम	42	74.33	13.59		
बालक एवं बालिका	अधिक	71	81.11	12.01	2.06	< 0.05
	कम	78	74.41	18.33		

स्वतंत्रता के अंश – 75,74

0.05 स्तर पर सार्थकता हेतु मान – 1.99

0.01 स्तर पर सार्थकता हेतु मान – 2.63

स्वतंत्रता के अंश – 149

0.05 स्तर पर सार्थकता हेतु मान – 1.98

0.01 स्तर पर सार्थकता हेतु मान – 2.61

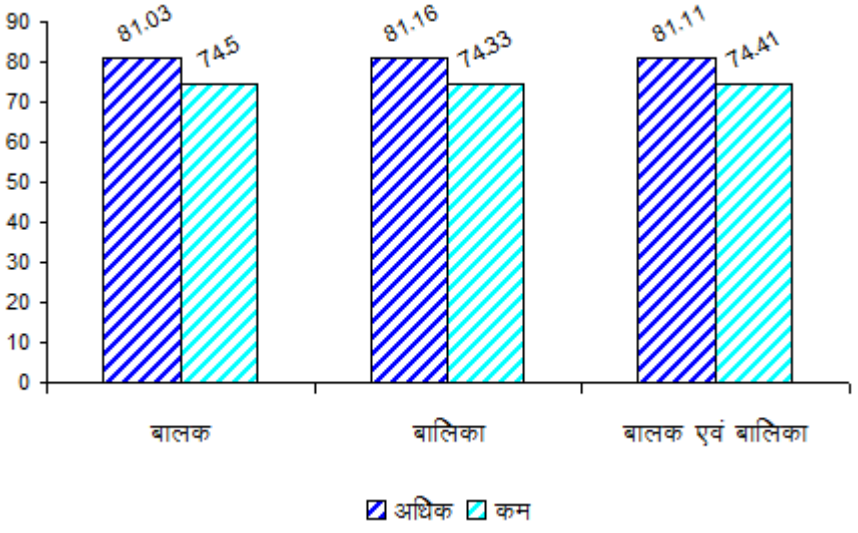

****

हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम के किशोर बालक एवं बालिकाओं की आध्यात्मिक बुद्धि में लिंग भिन्नताओं का अध्ययन

डॉ. आभा तिवारी * आहुति साहू **

शोध सारांश – अध्ययन का उद्देश्य हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम के बालक एवं बालिकाओं की आध्यात्मिक बुद्धि में लिंग भिन्नताओं का अध्ययन करना है। अध्ययन हेतु न्यादर्श में हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम के 120–120 किशोर बालक एवं बालिकाओं को लिया गया है। डॉ. संतोष धर एवं डॉ. उपेन्द्र धर (1971) के आध्यात्मिक बुद्धि परीक्षण का उपयोग किया गया। अध्ययन के परिणामों से ज्ञात होता है कि हिन्दी माध्यम के बालक एवं बालिकाओं की आध्यात्मिक बुद्धि में सार्थक अंतर है, जबकि अंग्रेजी माध्यम के बालक एवं बालिकाओं की आध्यात्मिक बुद्धि में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

शब्द कुंजी – किशोरावस्था, माध्यम, आध्यात्मिक बुद्धि।

प्रस्तावना – किशोरावस्था महान्, तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है। इस अवस्था में किशोरों में तीव्र शारीरिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होते हैं। किशोरावस्था जीवन की नाजुक अवस्था है जहां बालक का झुकाव जिस दिशा में हो जाता है वह उसी दिशा में आगे बढ़ता जाता है। इस समय बालक में कर्त्तव्यों, जिम्मेदारियों, विशेष अधिकारों, सामाजिक उद्देश्यों में बहुत परिवर्तन आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में किशोरों का माता–पिता, संगी–साथियों और अन्य किशोरों के प्रति दृष्टिकोण बदलना अनिवार्य हो जाता है। अभिभावकों द्वारा किशोरों को आध्यात्मिकता से जोड़े रखना चाहिए, यह जीवन को सही दिशा प्रदान करती है। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है, जिसमें वे कभी–कभी अपना मानसिक संतुलन भी खो बैठते हैं। ऐसी परिस्थिति में आध्यात्मिकता एक मात्र कारक है जो किशोरों को इन परिस्थितियों से उबारने में उनकी मदद करती है।

आध्यात्मिकता, विश्वासों का वह समूह है जिसमें प्रेम, सहिष्णुता एवं जीवन जीने के लिये आदर का भाव समाहित है। साधारण रूप में यह माना जाता है कि सभी धर्मों के मूल में आध्यात्मिकता होती है। कुछ मात्रा में यह परम पिता के साथ संचार होता है। यह व्यक्ति के स्वयं के अनुभवों पर आधारित होती है। आध्यात्मिकता का संबंध व्यक्ति के ब्रह्मांड के साथ संबंधों के रूप में लिया जा सकता है। आध्यात्मिक विकास में सामान्य रूप से व्यक्ति का अन्य लोगों के साथ अंतर्दृष्टि का विकास होता है। यह व्यक्ति को विभिन्न प्रकार से सहायता करती है कि उसका व्यवहार आक्रमक और दूसरों के कष्ट पहुँचाने वाला ना हो। इसमें जहां एक ओर व्यक्ति की दृढ़ इच्छा शक्ति, बौद्धिकता एवं मन की शुद्धता होती है, वहीं दूसरी ओर इच्छा पर नियंत्रण होता है। रार्बट ईमॉस के अनुसार 'प्रतिदिन के जीवन से संबंधित समस्याओं का समाधान ढूढ़ना, लक्ष्य प्राप्त करना ही आध्यात्मिक बुद्धि का महत्वपूर्ण पहलू है। फॉसेस वॉघन के अनुसार 'आध्यात्मिक बुद्धि मन, आत्मा और बाहरी दुनिया से संबंधित जीवन का समावेश है। रार्बट के अनुसार 'आध्यात्मिक बुद्धि से किशोरों को उन विश्वासों के विकास का सुअवसर प्राप्त होता है जो उसके जीवन के अनिवार्य अंग है। वर्तमान समय में जो पर्यावरण है वह नित्य बदलता जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में माध्यम का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिल रहा है। शिक्षार्थियों की ऐसी मान्यता है कि माध्यम का विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। **मोल्हर** (1966) में किशोर विद्यार्थियों की आध्यात्मिक बुद्धि एवं आत्मबोध के मध्य संबंध का अध्ययन किया, अध्ययन का उद्देश्य यह जानना था कि क्या विद्यार्थियों की आध्यात्मिक बुद्धि एवं आत्मबोध में सहसंबंध होता है। अध्ययन हेतु न्यादर्श के लिए किशोर विद्यार्थियों का चयन किया गया। आध्यात्मिक बुद्धि एवं आत्मबोध परीक्षण का उपयोग किया गया। परिणामत: पाया गया कि किशोरों की आध्यात्मिक बुद्धि और आत्मबोध के मध्य सकारात्मक सहसंबंध होता है। **साबंकर** (1998) में किशोर विद्यार्थियों की आध्यात्मिक बुद्धि का उनकी जीवन संतुष्टि पर प्रभाव का अध्ययन किया। अध्ययन का उद्देश्य आध्यात्मिक बुद्धि का किशोर विद्यार्थियों के जीवन संतुष्टि पर प्रभाव का अध्ययन करना था। न्यादर्श में 14–16 वर्ष के किशोर बालक एवं बालिकाओं का चयन किया। आध्यात्मिक बुद्धि एवं जीवन संतुष्टि मापनी का प्रशासन विद्यार्थियों पर किया गया। अध्ययन के प्रमुख निष्कर्षो से ज्ञात होता है कि आध्यात्मिक बुद्धि का जीवन की संतुष्टि पर गहन और सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। **जावरदन एवं निकेरदाल** (2011) ने आध्यात्मिक बुद्धि एवं अभिभावकीय शैली के मध्य संबंध का अध्ययन किया। अध्ययन का उद्देश्य था किशोर विद्यार्थियों की आध्यात्मिक बुद्धि एवं अभिभावकीय शैली के मध्य क्या संबंध होता है ? न्यादर्श में 160 किशोर विद्यार्थियों का यादृच्छिक विधि से चयन किया। आध्यात्मिक बुद्धि एवं अभिभावकीय शैली प्रश्नावली का प्रशासन किया। अध्ययन के प्रमुख निष्कर्षो से ज्ञात होता है कि अभिभावकीय शैली एवं आध्यात्मिक बुद्धि के मध्य सकारात्मक सार्थक सहसंबंध होता है। उपरोक्त शोध अध्ययनों से यह ज्ञात होता है कि आध्यात्मिक बुद्धि किशोर विद्यार्थियों को, उनके जीवन को अर्थपूर्ण एवं आनंदमय बनाने में मदद करती है।

चर –

स्वतंत्र चर	–	1. हिन्दी माध्यम
		2. अंग्रेजी माध्यम
परतंत्र चर	–	आध्यात्मिक बुद्धि
नियंत्रित चर	–	किशोरावस्था
		कक्षा नवमीं के किशोर बालक–बालिका
आयु	–	14–16 वर्ष

* प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (मानव विकास) शासकीय मो.ह.गृहविज्ञान एवं विज्ञान महिला महाविद्यालय (स्वशासी), जबलपुर (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी, शासकीय मो.ह.गृहविज्ञान एवं विज्ञान महिला महाविद्यालय (स्वशासी), जबलपुर (म.प्र.) भारत

उद्देश्य – हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम के किशोर बालक एवं बालिकाओं की आध्यात्मिक बुद्धि में लिंग भिन्नताओं का अध्ययन।

परिकल्पना – हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम के किशोर बालक एवं बालिकाओं की आध्यात्मिक बुद्धि में लिंग भिन्नता में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।

शोध विधि –

न्यादर्श–

क्र.	माध्यम	बालक	बालिका	योग
1	हिन्दी	60	60	120
2	अंग्रेजी	60	60	120
	योग	120	120	240

विधि –

1. हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की सूची बनायी गयी।
2. इन सूचियों में से दो-दो विद्यालयों का यादृच्छिक विधि से चयन किया गया।
3. इन विद्यालयों के 60-60 बालकं एवं बालिकाओं को न्यादर्श में चुना गया।
4. न्यादर्श में चयनित किशोर बालक एवं बालिकाओं पर आध्यात्मिक बुद्धि का परीक्षण का प्रशासन किया गया।
5. आध्यात्मिक बुद्धि परीक्षण का फलांकन कर परिकल्पनाओं के सत्यापन हेतु प्रदत्त की सांख्यिकीय गणना की एवं निष्कर्ष प्राप्त किया।

उपकरण – आध्यात्मिक बुद्धि परीक्षण - डॉ. संतोष धर एवं डॉ. उपेन्द्र धर (1971)

परिणामों का विश्लेषण एवं व्याख्या – हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम के सहशिक्षा एवं एकलशिक्षा में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की आध्यात्मिक बुद्धि के परिणाम निम्नानुसार है -

तालिका क्रमांक - 01 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

परिणामों के आधार पर निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि हिन्दी माध्यम के बालक एवं बालिकाओं की आध्यात्मिक बुद्धि में अंतर है, बालिकाओं की आध्यात्मिक बुद्धि बालकों से अधिक है। जबकि अंग्रेजी माध्यम के बालक एवं बालिकाओं की आध्यात्मिक बुद्धि में कोई अंतर नहीं है।

आध्यात्मिकता और धर्म अलग-अलग होते है। एक व्यक्ति आध्यात्मिक अनुभवों को बिना किसी धर्म से जुड़े हुए भी अनुभव कर सकता है, जबकि एक अत्याधिक धार्मिक व्यक्ति के लिये जरूरी नहीं कि वह आध्यात्मिक हो। दनाह जौहर एवं ईआन मारशल (2001) के अनुसार 'आध्यात्मिक बुद्धि धर्म से संबंधित नहीं है। यह व्यक्ति को रचनात्मक बनाती है, नियमावली और परिस्थितियाँ बदलती है, नैतिकता सिखाती है। कठोर अनुशासन और नियमावली को सहानुभूति से परिवर्तित कर सकती है, एक दृष्टिकोण बनता है और उसके निर्णय में तर्क होता है।' आध्यात्मिक बुद्धि किसी एक मार्ग पर चलकर विकसित नहीं होती, बल्कि वास्तविक जीवन से ही अभिभावक के प्रेम, त्याग, सहनशीलता, धर्म आदि से बच्चों में हस्तांतरित होती है। धार्मिक रीति-रिवाजों का इसमें इतना महत्व नहीं है, जितना आत्म समझ से है। स्व. को जानना, शक्तियों व कमजोरियों को पहचानना आध्यात्मिक बुद्धि के लिए आवश्यक तत्व माने जाते है। आध्यात्मिक अनुभव से ही आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति मिलती है। जब एक बालक अपनी बाल्यावस्था को पूर्ण कर किशोरावस्था में कदम रखता है तो यह अवस्था उसके लिए एक नवीन जीवन जैसी होती है। इस अवस्था में परिवार में माँ ही एक मार्गदर्शक, साथी एवं सच्ची मित्र होती है। ऐसी अवस्था में किशोरों को माँ के सानिध्य और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती हे। घर के वातावरण में मिली हुई शिक्षा, किशोरों के संपूर्ण जीवन में विशेष रूप से काम में आती है। मानव जीवन की दो तिहाई शिक्षा माता-पिता की छत्रछाया में घर के वातावरण में सम्पन्न होती है। घर के वातावरण की उपयुक्तता, श्रेष्ठता पर ही किशोरों के जीवन की उत्कृष्टता निर्भर करती है।

उपरोक्त परिणामों से स्पष्ट होता है कि हिन्दी माध्यम के बालक एवं बालिकाओं की आध्यात्मिक बुद्धि में सार्थक अंतर है, जबकि अंग्रेजी माध्यम के बालक एवं बालिकाओं की आध्यात्मिक बुद्धि में कोई अंतर नहीं है। हिन्दी माध्यम की बालिकाओं की आध्यात्मिक बुद्धि, बालकों से अधिक है। यह परिणाम इस बात के द्योतक है कि हिन्दी माध्यम के बालक, बालिकाओं के साथ-साथ अंग्रेजी माध्यम की बालिकाओं की अपेक्षा अधिक धर्म परायण होती है, बालिकाओं में धर्म के प्रति रूचि अपेक्षाकृत अधिक होती है, क्योंकि परिवार में सभी धार्मिक कार्यों में बालिकाओं की सहभागिता बालकों की अपेक्षा अधिक रहती है। अधिक सहभागिता रहने से जब उनका इन गतिविधियों में उनकी सम्मिलिति अधिक होती है तो वे आध्यात्मिकता के सोपानों की ओर अधिक उन्मुखीकृत हो जाती है, आदि ग्रंथों में महिलाओं की आध्यात्मिक क्षेत्र में भूमिका को भी स्पष्ट रूप से बताया गया है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में भी जब हर क्षेत्र में बालिकाओं, महिलाओं की सहभागिता देखी जा रही है तो वहीं हिन्दी माध्यम की बालिकाओं में आध्यात्मिकता इस बात का भी संकेत है कि भारत में आध्यात्मिकता को अक्षुण्य बनाये रखने में बालिकाओं का समुचित योगदान होता है।

हसन एवं शबानी (2001) ने आध्यात्मिक बुद्धि एवं संवेगात्मक बुद्धि का किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन किया। अध्ययन का उद्देश्य किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पर आध्यात्मिक बुद्धि एवं संवेगात्मक बुद्धि के प्रभाव का अध्ययन करना था। यह अध्ययन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के 247 विद्यार्थियों पर किया गया जिसमें 124 छात्र एवं 120 छात्रायें थी। विद्यार्थियों की आयु सीमा 14-16 वर्ष के मध्य थी। अध्ययन से जो निष्कर्ष प्राप्त हुए उसमें ज्ञात होता है कि उच्च आध्यात्मिक बुद्धि एवं संवेगात्मक बुद्धि वाले किशोरों का मानसिक स्वास्थ्य, निम्न आध्यात्मिक बुद्धि एवं संवेगात्मक बुद्धि वाले किशोरों की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है।

अध्ययन में लिंग भेद भी पाया गया। छात्रों की अपेक्षा छात्राओं के मानसिक स्वास्थ्य पर आध्यात्मिक बुद्धि एवं संवेगात्मक बुद्धि का अधिक प्रभाव पाया गया। स्प्रिंगर (2012) ने विद्यार्थियों के जीवन की गुणवत्ता का आध्यात्मिक बुद्धि से संबंध का अध्ययन किया। अध्ययन का उद्देश्य था कि क्या किशोर विद्यार्थियों की आध्यात्मिक बुद्धि एवं उनके जीवन की गुणवत्ता में सकारात्मक संबंध होता है ? अध्ययन हेतु न्यादर्श में 142 किशोर बालक एवं बालिकाओं को लिया गया, उन पर आध्यात्मिक बुद्धि और जीवन की गुणवत्ता परीक्षण का उपयोग किया गया। अध्ययन में पाया गया कि जिन विद्यार्थियों की आध्यात्मिक बुद्धि अधिक उच्च होती है, उनके जीवन की गुणवत्ता का स्तर कम आध्यात्मिक बुद्धि वाले विद्यार्थियों की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है।

निष्कर्ष – हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम के बालक एवं बालिकाओं की आध्यात्मिक बुद्धि में सार्थक अंतर है। बालिकाओं की आध्यात्मिक बुद्धि, बालकों से अधिक है जबकि अंग्रेजी माध्यम के बालक एवं बालिकाओं की आध्यात्मिक बुद्धि में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. कपिल, एच.के. (1975), सांख्यिकीय के मूल तत्व, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा, पृ.सं. 607.
2. गुप्त, रामबाबू, (2000), विकासात्मक मनोविज्ञान, अष्टम संस्करण, रतन प्रकाशन मंदिर, प्रोफेसर्स कॉलोनी, दिल्ली गेट, आगरा, पृ.सं. 469-470.
3. सिंह, अरूण, (2006), आधुनिक सामान्य मनोविज्ञान, चतुर्थ संस्करण, बंगला रोड, दिल्ली, 110007 मोतीलाल वनारसी दास प्रकाशन।
4. Springes. L. (2012) Study of the spiritual intelligence role in prediciting student Quality of life. J. Religion and health.
5. Vaughan, F. (2002). What is spirital intelligence, Journal of Mumenistic Psychology. Vol. 42(2).
6. Zohar, D., Marshall.I. (2001) , Spirital intelligence the ultimate intelligence Bioomsbury London.
7. Hassan, S.A.; J shabani and A Ahmand, (2011), Moderating influence of gerider on the link of spritiual and emotional intelligence with mental health among adolescent. J. Life science. 8(1).

तालिका क्रमांक - 01

हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम के किशोर बालक एवं बालिकाओं की आध्यात्मिक बुद्धि के तुलनात्मक परिणाम

माध्यम	समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	क्रांतिक अनुपात	पीमान
हिन्दी	बालक	60	228.78	24.46	2.87	< 0.01
	बालिका	60	239.57	15.78		
अंग्रेजी	बालक	60	201.88	26.54	0.61	0.01
	बालिका	60	204.75	25.03		

स्वतंत्रता के अंश - 118

0.05 स्तर पर सार्थकता हेतु मान - 1.97

0.01 स्तर पर सार्थकता हेतु मान - 2.62

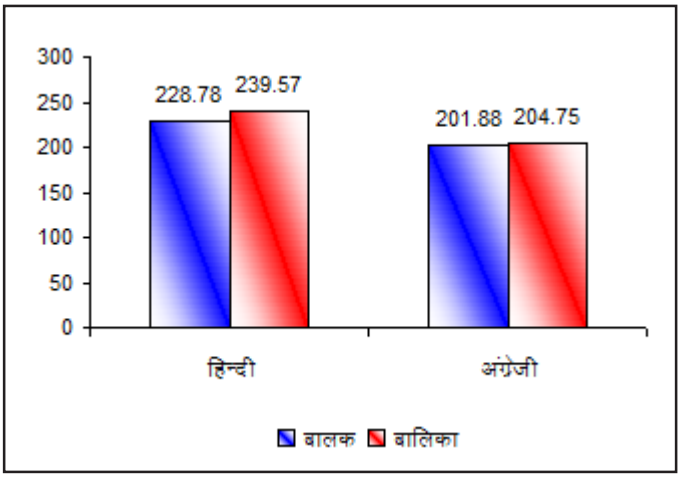

****

A Study Regarding The Brand Awareness Of News Channel IBC24 "Sawaal aapka hai" - Chhattisgarh Region

Vikas Sharma *

Abstract - Media technology has made communication increasingly easier as time has passed throughout history. It can be termed as "Media Explosion". News Channels are continuously engage in entertaining as well as updating theirs viewers. The competition in news channel industry hinges on this very factor. The brand awareness is primary goal of advertising which helps in the understanding of present position of the product. This paper is the case study of very known news channel in Chhattisgarh Region IBC24.This study analyzes the reach and brand awareness of IBC24 in the minds of the people in the state. This study not only helps us in understanding the awareness level of IBC24 but also the position of its competition. Formative research process was applied in the study keeping both qualitative and quantitative methodology in mind.
Key words - Brand Awareness, News Channel.

Introduction - Media technology has made communication increasingly easier as time has passed throughout history. Today, children are encouraged to use media tools in school and are expected to have a general understanding of the various technologies available. The internet is arguably one of the most effective tools in media for communication. Tools such as e-mail, Skype, Facebook etc., have brought people closer together and created new onlinecommunities.

In a large consumer-driven society, electronicmedia (such as television) and printmedia (such as newspapers) are important for distributing advertisementmedia. More technologically advanced societies have access to goods and services through news rmedia than less technologically advanced societies.The term 'Electronic Media' is also relevant to professional career development regarding related skill set **Primary uses of electronic media:**is in Journalism, Commerce, Industry, Entertainment,Government and many more fields.

News Channel Industries are continuously engage in providing latest updates to the viewers about the happening in our surroundings. Various channelslike to put their news to be served to viewers with all the possible garnishing and topping. The competition in the news channel industry in the current scenario hinges on this very factor.

As in very known news channel in Madhya Pradesh &ChhattisgarhRegion IBC24.

Brand awareness is the extent to which a brand is recognized by potential customers, and is correctly associated with a particular product. Expressed usually as a percentage of the targetmarket, brand awareness is the primary goal of advertising in the early months or years of a product'sintroduction.

Brand awareness is related to the functions of brand identities in consumers' memory and can be reflected by how well the consumers can identify the brand under various conditions.Brand awareness includes brand recognition and brand recall performance. Brand recognition refers to the ability of the consumers to correctly differentiate the brand they previously have been exposed to. A brand name that is well known to the great majority of households is also called a **household name.**

Channel Introduction - IBC24 is a major Hindi language current affair channel of Central India, providing news and happenings from across the states of MADHYA PRADESH & CHHATTISGARH. IBC24 is from Goel Group of Industries, headquarter at Raipur, Chhattisgarh.

Today, IBC24 is considered to be the most credible, trustworthy, unbiased & reliable news channel. IBC24 has always emphasized on Unique & Topical Programming Content with rolling news bulletin throughout the day with important happenings in both Madhya Pradesh & Chhattisgarh.

Objectives -

- To understandthe brand awareness in the minds of the viewers based on age and gender of IBC24 "SawaalAapkahai"

Hypothesis -

1. There is a need to change current brand awareness among the viewers of the company "SawaalAapkahai"
2. There is no need to change the current Brand Awareness among the viewers of the company "SawaalAapkaHai".

Methodology -

Project approach - This study was conducted in 7 towns namely Mahasamund, Balada Bazaar, Gariyaband, Jagdalpur, Geedam, Kondagaon and Kankerwhere in a set of questionnaire was floated amongst the people the state.

*Asst. Manager, Marketing & Research, IBC 24, Raipur (C.G) INDIA

The objective behind this study was to understand the perception and the opinion of viewers of the channel.

Data analysis & Observation -

Age group -

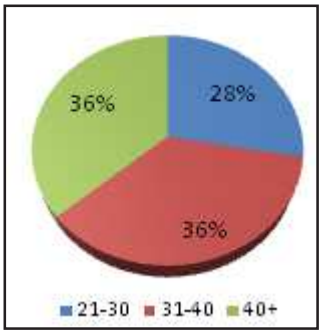

This part of study was conducted with the target of 560 samples; however we ended up collecting 498 samples. There were several unforeseen incidents occurred which impacted the sample collection such as Naxal attack in Bastar region and communal disruption in Gariyaband and Rajim region. For the better understanding of viewer's taste and behaviour three age categories has been defined. The sample collected has fair distribution amongst all predefined categories to meet our objectives.

Sample has been collected from seven towns namely Mahasamund, Balada Bazaar, Gariyaband, Jagdalpur, Geedam, Kondagaon and Kanker.

Gender -

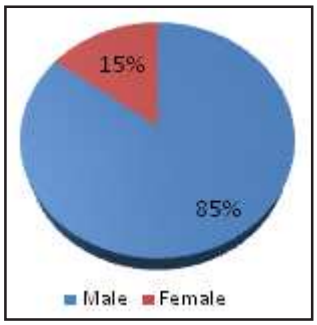

During data compilation we found that female percentage in our sample is 15% which is lower than our expectation of 70:30. The similar composition can be obsevered under defined age groups.

However, this low female count was expected, as most of the data collection is from small towns where female participation was very low. This low gender composition would not affect our study much.

Respondents Profile- Educational qualification

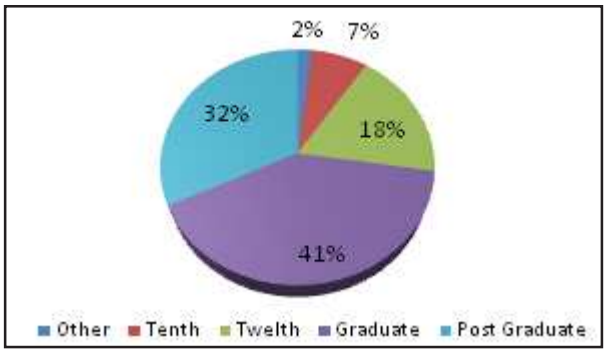

Out of 471 samples, 41% of respondents were graduate where as 32% of the respondents were post graduate in the sample collected.

Job status -

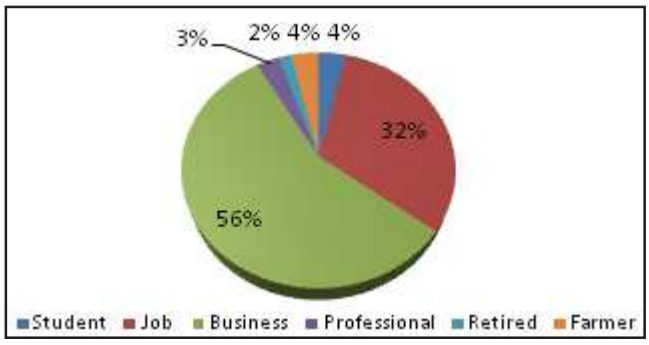

Out of 471 samples, 56% of the respondents are engaged in business activity where as 32% are in Job. Rest 13% falls under the category of student, professional, retired and farmer.

Viewer's preference -

Preferred medium for News - (See in the last page)

Television has emerged as the most prefered medium for getting news. Out of 471 sample, 98% of respondents have shown their preference towards Electronic media where as 64% of respondents have also shown their preference towards Print media followed by Internet.

Preferred Regional news channel (See in the last page)-

Out of 471 samples, 42% respondents prefer watching IBC24 for regional news followed by ZPMCG 26% and ETV 20%. IBC24 has been recognised as the most preferred news channel for the regional news however several comments were made by the respondents in this regard.

Comments for IBC24 -

- We watch IBC24 because of trust we have on it, the channel shows news from every part of the state
- IBC24 updates us about the happening of the state however we have noticed drop in its content quality and presentation, I have always been its fan since the time of Z24 but now they just show news do not raise concern. However it stand better off than its rival channels
- IBC24 is a good news channel; whenever there is naxal attack they are first but they do not raise any other concern of our area

Comments for ETV MPCG

- ETV shows local news of Chhattisgarh
- ETV news content is good however presentation is the concern, we have been watching it from many years
- ETV has the local connect specially their agricultural based program.

Comments for ZMPCG

- It's the only channel we have on our DTH and it shows news of the state
- ZMPCG is the exclusive news channel of Chhattisgarh we have been watching it since past 5-6 years but now their content is going down

Most preferred news channel for cable viewers - We further analysed which is the preferred regional news channel for those respondents who have cable connection at home. We found that out of 205 respondents 56% prefers watching IBC24 followed by ZMPCG with 21%.

Liking in the favourite news channel - For IBC24 **(See in the last page)** Out of 471 samples 220 prefers watching IBC24. 60%-62% of them have marked news quality and current updates as the reason for watching IBC24, followed by news presentation and popularity as the reason for watching IBC24.

The only worrying aspect is News projection and presentation aspect which has always been the strength of the channel stands no.3. There were certain comments made by the respondents on this regard:

- IBC24 is a good channel but somehow it doesn't interest me much now there are several reasons like availability of other channels and average news presentation of IBC24
- IBC24 should focus more on news projection and presentation, they should groom their anchors and reporters, they seems immature at times
- Today every channel has more or less same content its just a matter of its presentation and the way anchor deals with it
- I am watching this channel since past 5-6 years but as IBC24 it's news quality & presentation performance has gone down. Channel need to work on its content
- IBC24 is regional news channel of Chhattisgarh and shows us whatever happening in our state however i feel they should also focus on discussing the matter and not just stop by showing it

Observation -

- IBC24 is the most prefered news channel in the region however ZMPCG and ETV MPCG are also gaining momentum in terms of brand preference
- Channel enjoys the reputation of being regional news channel of Chhattisgarh
- It is observed that channel has lost its perception as exclusive news channel of Chhattisgarh
- During the course of study few critical remarks were made on the content of the news such as earlier content was created and presented today just news is served
- Critical remarks were made on the body posture and news reading skills of the anchors and reporters. It is been said that lack of preparation on topic can be seen in the anchors
- Confusion persists with respect to the name of the channel, many respondents found to be confused between IBC24 and Z24

Limitations -

- Human error:- filling survey and data tempering
- It was assumed that the respondents was unbiased while responding the questionnaire and best of their knowledge
- Data on certain questions were not up to the set standard hence not been considered for analysis
- Lack of data availability on public domain

Conclusion - The paramount significance of media in today's society can hardly be over-emphasised. The role of media has become so all-pervasive that it has become an integral part of the fabric of society and whether we acknowledge it or not, it plays a very influential role in shaping our thought processes and attitudinal patterns.There is a need to do a rigorous rethink on its positioning strategy visa- vis the ever-changing dynamics of the viewers. News channels in India are not just information-providers; they are expected to cater to the need for infotainment, which has become very rampant in the TV-viewing audience in two decades of prevalence of cable and satellite television in India.

The brand awareness of IBC24 is far better than other regional news channel of Chhattisgarh. As we say about the Age group we got the outmost response from the 30+ and males prefer it over females which are the common parlance. IBC24 is preferred over BansalNews, ETV MPCG, Saharasamay etc.

It has also been observed that lack of synchronised marketing effort has led to lower brand recognition. Today's era is of integrated marketing approach, nothing works in isolation; therefore marketing should be treated as a central point for sales and editorial event. Sales and editorial team should leverage the strength of marketing efforts. At the end of each marketing activity an audit process should be carried for accessing the outcome.

References :-

1. Ahluwalia, A.K and Singh, R. (2011), TV Viewing Habits Amongst Urban Children, IUP Journal Of Marketing Management, Vol. 10(1),45-62
2. Bukhari, Bushra (2002).The Effect of Television Programmes on Youth. M.A. Thesis, University of the Punjab, Lahore, 67
3. Malhotra, Naresh, K. (2002), Marketing Research -An Applied Orientation, 3rd Edition, Pearson Education: New Delhi.
4. Kotler Philip, Marketing Management, Vth Edition, Tata McGraw Hills.

Preferred medium for News

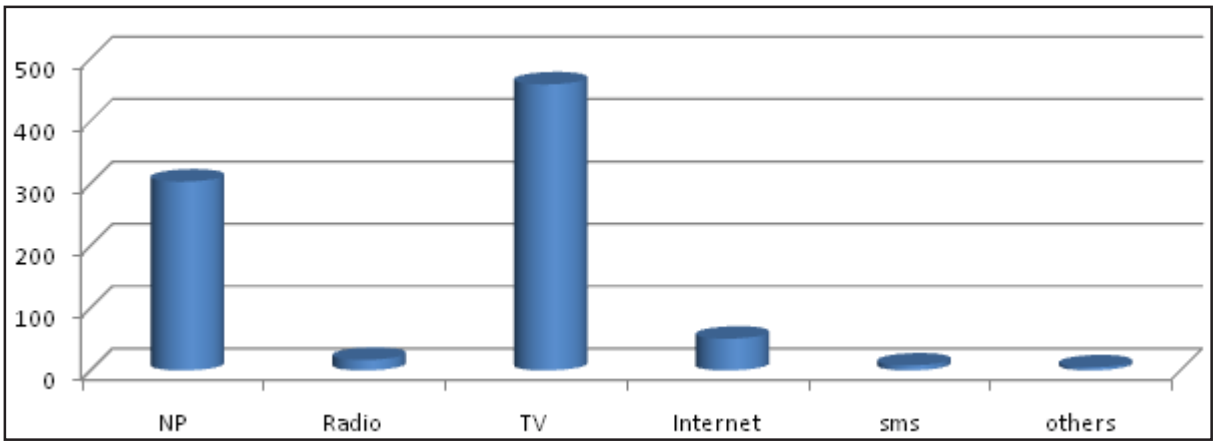

Preferred Regional news channel

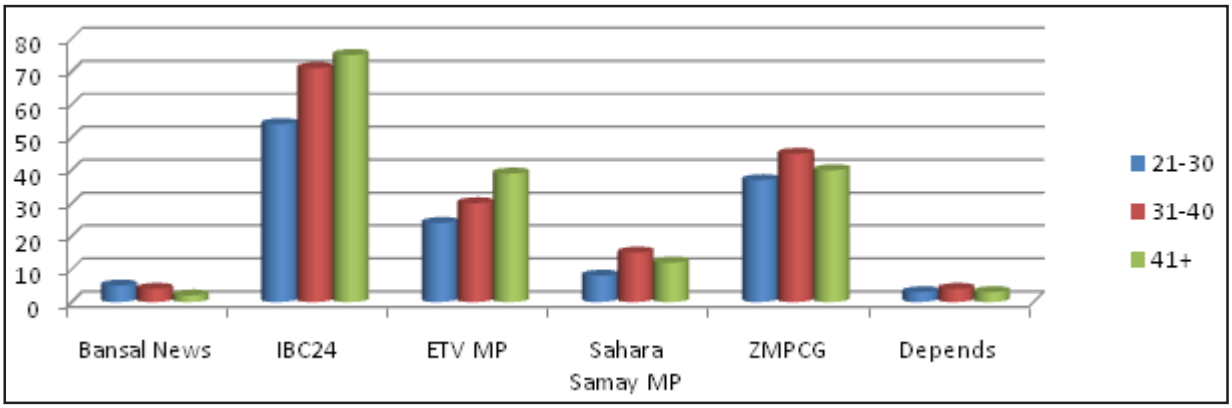

Liking in the favourite news channel - For IBC24

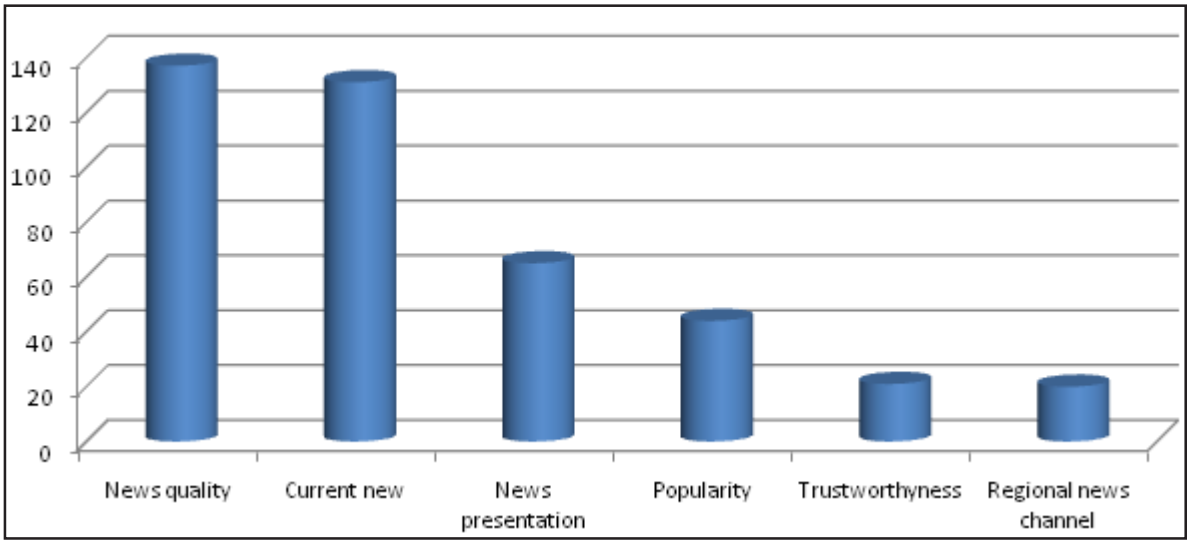

****

Study of Agriculture Growth in Madhya Pradesh in Post Liberalization Period

Rajesh Kumar Gautam * Dr. Pawan Kumar Jaiswal ** Dr. Ajay Waghe ***

Introduction - Agricultural sector plays a strategic role in the process of economic development of any country. It has already made a significant contribution to the economic prosperity of advanced countries and its role in the economic development of less advanced countries is of vital importance.[1] Nicknamed the "Heart of India" due to its geographical location in India, Madhya Pradesh is the second largest state in the country by area. The undivided Madhya Pradesh was founded on November 1, 1956. Its present form came into existence on November 1, 2000 following its bifurcation to create a new state of Chhattisgarh. According to the provisional results of census 2011, population of Madhya Pradesh consists of six percent population of India. As earlier stated Madhya Pradesh is second largest state, spread over 307.56 lakh hectares that comprises of nine per cent of the total geographic area of the country. The state of Madhya Pradesh is endowed with rich natural resources including eleven agro-climatic zones, five crop zones and varying land use, rainfall and water resources, forest, minerals distributed across fifty districts in the state. Present land use classification suggests that nearly half of the state's total geographical area come under net sown. According to census 2001 census, work participation rate for the state is 42.74 per cent with 25.8 million workers, wherein seventy five per cent are main workers and twenty per cent are marginal workers. Out of total workers in state, 71.5 per cent are dependent on agriculture and allied sectors. Only 4 per cent of the workforce is engaged in household industry and rest 24 per cent in services[4]. Thus it is very clear that with non agriculture sector only a quarter of the workforce is engaged while agriculture is the principal livelihood source for the state from the employment point of view. According to a report on estimates of State domestic product of Madhya Pradesh, primary sector contributes only 22.34 per cent to the GSDP of state economy in the year 2011-12 while contribution of service sector to the GSDP in increasing gradually. Many milestones have been touched by Madhya Pradesh in the ten year journey of Madhya Pradesh after its separation. But when we compare the growth story of Madhya Pradesh to the state of Chhattisgarh, we can find many discrepancies in the development of Madhya Pradesh. In the year 2000-01 when the bifurcation held, adverse impact on the economic growth rate of both the state had been observed. But after it Chhattisgarh got the momentum and within two year it attains 16 percent of the growth rate.

Review of Literature - Mathur, Das and **Sircar (2006),** in their article entitled "Status of Agriculture in India: Trends and Prospects" analyzed the status of agriculture in India and suggest that government expenditure in agriculture including public investment and subsidy for fertilizer usage and electricity consumption for agriculture are the major factors affecting agricultural production in the country. Further they analyzed that the agricultural output at current prices is significantly and positively dependent on government expenditure on agriculture, fertilizer usage, rainfall, and population. On the front of state-wise analysis of agriculture with regard to the period 1993-2003, they found wide variations in agricultural growth of Madhya Pradesh. According to **Shankar Vijay P.S. (2005)** the agricultural development of Madhya Pradesh is highly varied. He has found that even within a backward state like Madhya Pradesh, there has been considerable divergence in the agricultural growth performance between ecological regions.

Objectives

1. To evaluate the shift in the production of major crop-groups and crops in Madhya Pradesh after its division.
2. To estimate the growth rate of the cultivated area under different crop-groups and crops between the two sub periods.

Research Methodology -

1. Area of Research Study - One of the basic things of Madhya Pradesh economy is that it is an agrarian economy.

* Assistant Professor, National Law Institute University, Bhopal (M.P.) INDIA
** Assistant Professor (Commerce) Vidyodaya College, Manawar (M.P.)INDIA
*** Assistant Professor (Commerce) Vidyodaya College, Manawar (M.P.) INDIA

As we aware that Madhya Pradesh was bifurcated in the year 2000. Over the period of time in each and every five year plan government has shown interest in the field of agricultural development. Green revolution, White revolution and many other revolutions have been initiated by government of India. But the benefits of such revolutions and programs were restricted to some states only like Punjab and Haryana etc. For this purpose we have selected two sub-periods of 1990-1991 to 1999-2000 and 2000-2001 to 2010-11.

2. Variables used in study -

I. Area under different crops - In this variable we took the area of cultivation of different crops cultivated in Madhya radish during the period 1990-91 to 2010-11. Many crops like Paddy, Wheat, Maize, Jowar, Soybean, Cereal, Tur, Gram, Sugar cane and Pulses, Food grain, Groundnut, Cotton, Oilseed and Mustard have been taken to analyze the shift or change after the bifurcation of Madhya Pradesh. This area is measured in terms of thousand hectares.

II. Crop production - Production of fifteen crops has been taken into consideration for the research purpose. The unit of production in our research is lakh metric tones.

III. Yield of Different Crops - Productivity of nine major crops has been taken into consideration for the analysis. Paddy, Wheat, Maize, Tur, Gram, Soybean, Groundnut, Cotton and Sugarcane are the name of nine crops. Yield of all the crops that we have taken are important to determine to economic growth of Madhya Pradesh.

3. Tools and Techniques of Analysis Employed - For evaluating the objectives of the paper following models have been used.

Model No. 1: $\text{Log } Y_{t1} = \beta 0 + \beta_1 X_t + D + Ut$

In this model area under cultivation is the dependent variable while Xt is the independent variable. . Xt is the period of time from 1990 to 2011. D is the dummy variable. In the dummy variable we have taken "0" as years till 2000 and "1" after year 2000. Ut in the model is the stochastic variable.

Model No. 2: $\text{Log } Y_{t2} = \beta 0 + \beta_1 X_t + D + Ut$

In this model production of crops and crop group is the dependent variable while independent variables are same as model no.1.

Model No. 3: $\text{Log } Y_{t3} = \beta 0 + \beta_1 X_t + D + Ut$

In this model productivity of crops and crop group is the dependent variable while independent variables are same as the above models.

U_t = Stochastic term.

The Compound Annual Growth Rate is obtained by the following formula.

CAGR = (Antilog â - 1) * 100

Results - The main findings of the study are briefly summarized below:

1. Growth of Agricultural Output

Table No.2 (See in the last page)

It would be seen from table no.1, during the period, before the bifurcation of Madhya Pradesh, Soybean's production increased at the rate of 10.32per cent per annum. This growth was shared with oilseeds (8.25%) and gram (5.22%). In the same period Jowar has shown a negative sign in term of production. The CAGR for was recorded negative for Jowar and Tur from 19990-91 to 1999-01. The growth rate of production of Cotton (12.83%), Mustard (10.37%), Sugarcane (5.33%), and Groundnut (2.21%) during post bifurcation period accelerated while in case of Soybean (7.94%), oilseeds (7.52%) and Pulses (3.61%) witnessed a negative growth

Growth in Cropped Area of different crops - It would be seen from table no.4 that compound annual growth rate of crop-area of Wheat, Maize, Jowar, Tur, Ground nut and Cotton was negative during the period of 1990-2000. Among them Jowar (-9.19) has shown a most negative trend in respect of cropped area. In the post bifurcation period of Madhya Pradesh Jowar's area (-4.42) has still negative but an improvement can be seen as compared to pre bifurcation area. Cropped area under sugarcane, mustard and oilseed witnessed an increasing trend.

Table No.3 - (See in the last page)

2. Growth in yield of Selected Crop-group and crops- The productivity of Soybean and cotton has been increased 5.06 and 16.98 per cent per annum. It is also an important thing to note that after bifurcation of Madhya Pradesh cropped area of paddy has been decreased but state has increased the productivity of paddy up to 3.52 per cent per annum. Wheat, Maize, Tur, Gram, and Sugarcane recorded decreasing growth rate in the period of 2000-01 to 2010-11 while the average productivity for the period of 2000-01 to 2010-11 has been increased to 4.79.

Table No.4 - (See in the last page)

3. Instability of Growth - The impact of bifurcation of Madhya Pradesh on the stability of agricultural growth is presented in Table no.5. From the table we would be seen that gram, pulses, Foodgrain, Cereals, Wheat and Oilseeds grow under the low or moderate fluctuations. Only maize, Soybean shows the moderate fluctuation.

Table No. 5 (See in the last page)

Conclusion - In conclude that there is a positive correlation between the productions of crops and crop- groups in Madhya pradesh. Less irrigation, ground water level depletion particularly during the summer month and less road density are the factors which adversely affecting the production of crops and crop groups in Madhya Pradesh. The key challenges that may impede agricultural growth in Madhya Pradesh are scanty and erratic rainfall. Irrigated area in the state is increasing year by year but only one-third gross sown area in the state is irrigated while, remaining two-third area is still depended on monsoon. Madhya pradesh is endowed with major rivers like Narmada, Chambal, Tawa, Son, Kalisindh etc but still the state is fail to take benefit from such water resources. Not only the establishment of scale large irrigation project in the state is sufficient for the betterment of agriculture but also the availability of power during the various phase of agriculture like harvesting season etc, seeds, modern agricultural equipment, use of fertilizers and other inputs are necessary.

References :-

1. Mathur S. Archana, Das Surjit and Sircar Subhalaxmi (2006): 'Status of Agriculture in India, Trends and Prospects,' EPW, December 30
2. Shanker Vijay P.S.,(2005): 'Four Decades of Agricultural Development in Madhya Pradesh, An Agro-Ecological Sub-Region Approach', EPW, November 26
3. Dhar and Murli Kallumal (2004), 'Trade liberalization and Agriculture: Challenges Before India', http://www.macroscan.com

Table No.2

Compound Annual Growth Rate of **Production** of Selected Crop-groups and Crops in two Sub-periods in Madhya Pradesh

S.No.	Crops	Compound Annual Growth Rate	
		1990-91 to 1999-00	2000-01 to 2010-11
1	Paddy	2.71	2.64
2	Wheat	5.66	5.99
3	Maize	1.15	(-)3.34
4	Jowar	(-)9.58	0.04
5	Foodgrain	3.28	3.34
6	Crereals	3.09	3.22
7	Tur	(-)2.95	(-)0.71
8	Gram	5.22	4.29
9	Pulses	4.09	3.61
10	Soybean	10.32	7.94
11	Groundnut	1.65	2.21
12	Cotton	3.95	12.83
13	Sugarcane	3.54	5.33
14	Oilseeds	8.25	7.52
15	Mustard	2.02	10.37
	CAGR	**4.22**	**5.33**

Table No.3

Compound Annual Growth Rate of Crop-Area of Selected Crop-groups and Crops in two Sub-periods in Madhya Pradesh

S.No.	Crops	Compound Annual Growth Rate	
		1990-91 to 1999-00	2000-01 to 2010-11
1	Paddy	1.17	(-) 0.76
2	Wheat	3.19	2.5
3	Maize	(-) 0.20	(-) 0.32
4	Jowar	(-) 9.19	(-) 4.42
5	Foodgrain	0.61	1.26
6	Cereals	0.17	0.56
7	Tur	(-) 2.77	2.29
8	Gram	2.36	2.99
9	Pulses	1.54	2.43
10	Soybean	8.5	2.73
11	Groundnut	(-) 1.27	(-) 0.60
12	Cotton	(-) 1.25	2.01
13	Sugarcane	1.35	5.59
14	Oilseeds	5.2	2.68
15	Mustard	2.23	6.6
	CAGR	**2.63**	**2.87**

Table No.4
Compound Annual Growth Rate of Yield of Selected Crop-groups and Crops in two Sub-periods in Madhya Pradesh

S.No.	Crops	Compound Annual Growth Rate	
		1990-91 to 1999-00	2000-01 to 2010-11
1	Paddy	2.01	3.52
2	Wheat	3.03	2.78
3	Maize	1.27	(-) 3.01
4	Tur	(-)0.36	(-) 3.14
5	Gram	2.8	1.26
6	Soybean	1.96	5.06
7	Groundnut	2.97	3.06
8	Cotton	5.45	16.98
9	Sugarcane	2.56	0.89
10	**CAGR**	**2.75**	**4.79**

Table No. 5
Classification of crops according to Growth and Fluctuations in Output

S. No.	Growth of Output	Degree of Fluctuations		
		Low (< 7.5)	Moderate (7.5 > 15)	High (Above 15)
1	Negative	-	Maize	Tur
2	Low (0 – 1.5%)	Gram, Pulses	-	Paddy, Jowar
3	Moderate (1.5 3.0%)	Food grain, Cereals	-	Groundnut
4	High (Above 3%)	Wheat, Oilseeds	Soybean	Cotton, Sugarcane, Mustard

****

A Comparative Study of Consumer Attitudes towards Pricing Strategy of Dabur & Himalaya

Prof. Vishwas Sharma * Dr. Pradeep Kumar Sharma **

Abstract - In present scenario, it has become very difficult to grow, stabilize and excel in business performance in the absence of proper marketing strategies and consumer attitudes play important role in framing effective marketing strategy. The Ayurvedic medicines industry is also facing the same problem. This paper is focused towards revealing, evaluating and comparing the consumer attitudes towards pricing strategy adopted by Dabur and Himalaya. Both the companies have a wider range of Ayurvedic products & have a huge presence in the overseas markets and are today available in more than 80 countries across the world, hence Their comparative study reveals various marketing related issues in this sector.

Key Words - Marketing Strategy, Marketing Mix, Ayurvedic Industry, Pricing Strategy, Consumer Attitudes, Dabur, Himalaya

Introduction - In this competitive world, it has become very difficult to grow, stabilize and excel in business performance in the absence of proper marketing strategies. Marketing plays a prominent role in every industry. Marketing strategy allows firms to develop a plan that enables them to offer the right product to the right market with the intent of gaining a competitive advantage. We can also say that marketing strategy provides an overall vision of how to correctly position products in the marketplace while accounting for both internal and external constraints. The business environment is changing drastically. It is very difficult to predict about the future of any firm.

The Ayurvedic medicines industry is also facing the same problem. Consumer attitudes play important role in framing effective marketing strategy. That's why this paper is focused towards revealing, evaluating and comparing the consumer attitudes towards pricing strategy adopted by Dabur and Himalaya. Dabur and Himalaya are the two major players in Ayurvedic industry. Both the companies have a wider range of Ayurvedic products & have a huge presence in the overseas markets and are today available in more than 80 countries across the world, hence Their comparative study reveals various marketing related issues in this sector.

Literature Review -

- Gaski and Etzel (1986)Consumers' attitudes towards marketing activities are important from both a theoretical and a managerial standpoint.
- Chopin and Darrat (2000), consumer attitudes significantly affect their behavioral responses to marketing activities, knowledge of consumers' attitudes toward marketing has been used in economic forecast and found to be linked to several key macroeconomic variables.
- Barksdale et al, reported that during periods of rising inflation and financial crisis, pricing policies had been blamed by consumers.
- French et al. (1982), stated that most of the consumers held middlemen like wholesalers and retailers responsible for the key problem of high prices.
- Gaski & Etzel (2005), Peterson & Ekici (2007) reported in their studies that consumers seemed to be despondent with the prices of products.
- Jain (2011) found that consumers in India, Poland and Turkey respectively had negative sentiment towards price.

Objective - The objective of this paper is to compare the consumer attitudes towards pricing strategy of Dabur & Himalaya.

Methodology - Hypothesis: H0- Consumers are equally inclined towards pricing strategy of Dabur & Himalaya.

The Study: The study was descriptive in nature and survey based method was used to complete the study.

Sampling Design- Population: The population includes the consumers of all age and income group of Indore City.

Sampling Element - Consumers using products of Dabur & Himalaya.

Sample Size: The sample size was 300.

Sampling Method: Purposive sampling technique

Tools used for data collection: Consumers attitudes towards marketing have been measured through the use of Gaski and Etzel s scale (1986), recognized as Consumer Sentiment towards Marketing (CSM).

*Asst. Professor, Acropolis Technical Campus, Faculty of Management Studies, Indore (M.P.) INDIA
**Professor (Commere) Govt. Hamidia Arts and Commerce College, Bhopal (M.P.) INDIA

The questionnaire was on a Likert type scale and the sensitivity of the questionnaire was 1-5, where 1 indicated strongly dissatisfied and 5 indicated strongly satisfied.

Tools Used For Data Analysis - T-test has been used to test the hypothesis. It was applied to compare the consumer attitudes towards product strategy of Dabur & Himalaya.

Reliability: The reliability was evaluated through Chronbach Alpha.

Interpretation and Discussion

Consumer Attitudes toward Product price of Dabur & Himalaya

Scale/ItemConsumer attitudes towards Product Price of Dabur	Aggregative Mean
Most products of Dabur are overpriced.*	2.42
Dabur could charge lower prices and still be profitable.*	2.51
Most prices of Dabur's Products are reasonable given the high cost of doing business.	3.44
Most prices of Dabur's Products are fair.	3.53
In general, I am satisfied with the prices	3.57
I pay for Dabur's Products.	
Mean Score	**3.10**

Scale/ItemConsumer attitudes towards Product Price of Himalaya	Aggregative Mean
Most products of Himalaya are overpriced.*	2.40
Himalaya could charge lower prices and still be profitable.*	2.46
Most prices of Himalaya's Products are reasonable given the high cost of doing business.	3.35
Most prices of Himalaya's Products are fair.	3.49
In general, I am satisfied with the prices I pay for Himalaya's Products.	3.44
Mean Score	**3.03**

It can be observed from above mentioned tables that consumer attitudes towards Price of Dabur's Product range from 2.42 to 3.57 and for Himalaya it range from 2.40 to 3.49 The aggregative mean score of consumer attitudes towards Product Price of Dabur is 3.10 and for Himalaya it is 3.03. It means that consumers have more favorable attitude towards the Price of Dabur's Product than Himalaya's Product. However the difference of their mean (i.e o.o7) is small and their significance is further tested in Hypothesis Testing.

Hypothesis Testing -

H0:- Consumers are equally inclined towards the Product Price of Dabur & Himalaya.

H1:- Consumers are not equally inclined towards the Product Price of Dabur & Himalaya. **(See in the last page)**

Interpretation - An independent-samples t-test was conducted to compare the means consumers' attitude towards the Product Price of Dabur and Himalaya. There was not a significant difference in the scores for Dabur (M=3.10, SD=.499) and Himalaya (M=3.03, SD=.496) conditions; t (598) =1.689, p = 0.092. These results suggest there is no significant difference between the consumers' attitude towards the product price of Dabur and Himalaya. Hence H0 is accepted. Specifically, our results suggest that Consumers are equally inclined towards the Product price of Dabur and Himalaya.

Conclusion - Product pricing is one of the major elements of companies' product strategy. Dabur and Himalaya are the two big players of Ayurvedic Industry and their products' pricing hold good position in the eyes of consumers. Consumer attitudes clearly indicate that there is cut throat competition in this Industry. Companies need to focus on attractive pricing strategy and product innovation to survive in the market.

References :-

1. Chopin, Marc C. and Ali F. Darrat (2000), "Can Consumer Attitudes Forecast the Macroeconomy," American Economist, 44(1), 34-42
2. Barksdale, H.C. and Darden, W.R. (1972), "Consumer Attitudes toward Marketing and Consumerism", Journal of Marketing, Vol. 36, October, pp. 28-35.
3. Gaski, John F. and Michael J. Etzel (1986), "The Index of Consumer Sentiment toward Marketing," Journal of Marketing, (50)3, 71-82.
4. French, W.A.; Barksdale, H.C. and Perreault, W.D. (1982), "Consumer Attitudes towards Marketing in England and the United States", European Journal of Marketing, Vol. 16, No.6, pp. 20-30.
5. Gaski, John F. & Etzel, Michael J. (1986), "The Index of Consumer Sentiment towards Marketing", Journal of Marketing, Vol. 50, No. 3, pp. 71-81.
6. Peterson, M. & Ekici, A. (2007), "Consumer Attitude toward Marketing and Subjective Quality of Life in the Context of a Developing Country", Journal of Macromarketing, Vol. 27, No. 4, pp. 350-359.
7. Jain, Sanjay K. (2011), "Sentiment towards Marketing in a Big Emerging Market: An Empirical Investigation of Consumers in India", an invited paper presented at the 5th Indian Marketing Summit on Innovative Marketing Strategies for Big Emerging Markets, Organized by Birla Institute of Management Technology (BIMTECH), Noida (UP), India on January 22-23, 2011.

Group Statistics

	Company	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Consumers' attitude for product price	Dabur	300	3.10	.499	.029
	Himalaya	300	3.03	.496	.029

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	T	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Consumers' attitude for product price	Equal variances assumed	.054	.816	1.689	598	.092	.069	.041	-.011	.149
	Equal variances not assumed			1.689	597	.976	.092 .069	.041	-.011	.149

****

The Transitional Phase Of Goods And Service Tax In India- With Special Refrence To Madyaprdesh

Prof. Pratap Rao Kadam *

Introduction - Justifiaction Of Gst - In the view of fedreal structure of the goverenance in India. There is multiplicity of taxes on goods and services. Excise duty on manufacture customs duty on imports and exports, and service tax on services are levied by Central Government . On the other hand, VAT, Entry Tax, Octroi and duty on liquor are levid by the State Governments. Besides, there are plethora of taxes such as cesses, surcharge, stamp duty, entertainment tax and road tax.

Such multiplicity of taxes distorts the tax structure and brings in complexities. Reforms in Taxes are of course a continuous process. Central Value addea Tax (CENVAT) which was that time termed as 'MODVAT' was introduced in 1986 in Central Excise to avoid casading effect of excise duties. Introduction of state VAt stated in 2005 and now most of the states have implemented State VAT.

The Goods and service Tax (GST) in logical consequence of state of state VAT. Idea of national GST was fitst mooted by Kelkar Task Force in 2004. A task force formed under Chairmanshsisp of Shri Vijay kelkar on Implementation of Fiscal Responsibility and budget management Act. The kalkar committee strongly recommended fully integrated Goods and service Tax (GST) on national basis.

Goods and Serivice Tax - India is a country of varied tradition1s and customs : same is the case in its Tax regime structure. Recently the Governament has initated its efforts towards introduction of a new tax regime GST. This effort will bw made to identify the issues significnt in the context of this transitionla phase. The implementation of GST has been postponed till 2011. This postponement is due to the reason that the states have there own issues unresolved. Now the 13th Finance commission has given its views and in the light of the concerns expressed by the different states, the excrcise for redesigning the GST structure is taling place. Thus this transitional phase is very impotant and no specific study has yet been done in this perspective.

One of the biggest taxtation reforms in india – the Goods and Service Tax (GST) – is all set to integrate State economies and boost overall growth. GST will create a single, unified indian market to make the economy stronger. Finace Minister Pranab Mukherjee while presenting the Budget on July 6, 2009 had proposed that GST would come into effect from April 2010. Till now, the date of inplementation has been purhed beyond form April 1, 2011 to April 1, 2012.

History of GST - France was the first country which introduced a comprehensive gooods and service tax Regime in 1954. The Gooods and service Tax (GST) is proposed to be a comprehensive indirect tax levy on manufacture, sale and consumption of goods as well as service at a national level. The GST rate in various countries ranges from 5 per cent in Taiwan to 25 per cent in Denmark.

In the late 1980s, the federal government of Canada replaced its MST (Manufacture's Sale Tax) with a new value-add sales tax called the Goods and Services Tax (GST). The basic motive behind this reform was to introduce a new nationallly harmonized sales tax which would replace individual provincial sales taxes (PST), and both the levels of government would share the revenues generated there from.

Subsequest negotiations to harmonize the provincial and national sales taxes proved unsuccessful for the Canadian Government. Various provinces challenged the introduction of national sales tax on the ground that the federal government was exceeding its constitutional poewrs by operating in a taxation field historically reserved for the provinces. But as a result of constructive efforts by the Canadian Governmet National sales Tax was implemented in 1989-90.

France was the first country which introduced a comprehensive goods and service tax regime in 1954. The Goods and Service Tax (GST) in proposed to be a comprehensive indirect tax levy on manufacture, sale and consumption of goods as well as services at a national level. The GST rate in various countries ranges from 5 per cent in Taiwan to 25 per cent in Denmark.

Objective behind GST - The incidence of tax only falls on domestic consumption.

a) The efficiency and equity of the system in optimized.
b) There should be no export of taxes across taxing jurisdictions.
c) The Indian market should be integrated into a single common market.
d) It enhances the cause of co- operative federalism.

Our comparative discussion will be based only on significant points constructing overall GST.

What are the benefits of GST? - Under GST, the taxtion burden will be divided equitably between manufacturing and services, through a lower tax rate by increasing the tax and minimizing exemptions.

* Professor (Commerce) M.L.C. Govt. P.G. Girls College, Khandwa (M.P.) INDIA

It is expected to help build a transparent and corrption-free tax administration. GST will be is levied only at the destination point, and not at various points (from manufacturing to retail outlets). Currently, a manufacturer needs to pay tax when a finished product moves out from a factory, and it is again taxed at the retail outlet when sold. How will it benefithe centre and the states?

It is estimanted that India will gain $15 billion a year by implementing the goods and services Tax as it would promote exports. Raise employment and boost growth. It will devide the tax burden equivitably between manufacturing and servies.

Waht are the benefits of GST for individuals and companies ?

In the GST system, both central and state taxes will be collected at the point of sale. Both components (The central and state GST) will be charged on the manufacturing cost. This will benefits individuals as prices are likely to come down. Lower prices will lead to more consumption, there by helping compaines.

Which other nations have a similar tax structure? - lmost 140 countries have already implemented the GST, most of the countries have a unified GST system. Brazil and Canada follow a dual system where GST is levied both the union and state government. France was the first country to introduce GST system in 1954.

What will be the rate of GST? - The combined GST rate is being discussed by government. The rate is expected around 14-16 percent. After the total GST rate is arrived at, the state and the central will decide on the CGST and SGST rates. Currently services are texed at 10 per cent and the combined charged indirect taxes on most goods are around 20 per cent.

The govenment of Madhya Pradesh, Chattisgarh adn Tamil Nadu say that the information technology systems and the administrative infrastruture will not be ready by April 2010 to implement GST. States have sought assurances that theri existing revenues will be protected. The cenrtal govenment has offered to compensate states in case of a loss in revenues. Some state here that if the uniform tax rate is lower than their existing rates. It will hit their tax kitty. The govenment belives that dual GST will lead to better revenue collection for states. However, backward and less-developed state could see a fall in tax collections. GST could see better revenue collection for some state as the consumption of goods and services will rise.

How will GST be implemented? - The empowered committee was likely to finalize the details of GST by Auguest 2009. But states have to sort out several issues like agreement on GST rates, constitutional amendments and holding talks with industry associations. Experts feel the drafting of legislation and the implementation of law will take time.

Features of GST -

1. Centre will give input Tax Credit (ITC) only for CGST and the state only for SGST. Cross utilization of ITC between CGST & SGST shall not be allowed.
2. Center will legislate, levy & administer the CGST portion on its own and the state the SGST portion on their own.
3. To avoid deviations by the states, there shall be a mechanism (e.g. EC), where in the rates and other relevant paramenters will be decided upon by the centre & the states. The rates can there after not be changed by the centre or any of the states, without apporval of the same mechanism. A Constitutional mechanism will be introduced.
4. Destination principle for inter state sales of goods. For services, the rules are yet to be formulated; Sub- working Group has been constituted.
5. Administraion of CGST will be centre's responsibility; Administraion of SGST will be the responsibility of each state- Concurrent jurisdiction for entire value chain and all taxpayers will cause diffculties. A solution will have to be found for this.

What is GST? - GST is a tax goods and services with comprehensive and continuous chain of set-off benefits form the producer's point and service provier's point up to the retailer level. It is essentially a tax only on value addition at each stage and a supplier at each stage is permitted to set-off through a tax credit mechanism.

Under GST structure, all different stages of production and distribution can be interpreted as a mere tax pass thought and the tax essentially sticks on final consumption within the taxing jurisdiction.

Objective behind GST - The incidence of tax only falls on domestic consumption.

a) The efficiency and equity of the system is optimized.
b) There should be no export of taxes across taxing jurisdictions.
c) The Indian market should be integrated into a single common market.
d) It enhances the cause of co- operative federalism.

GST MODEL - A dual structure had been recommended by the EC. The two components are: central GST (CGST) to be imposed by the centre and state GST (SGST) by the states.

The task force has also recommended for the dual levy imposed concurrently by the centre and the state, but independently to promote co-operative federalism. Both the CGST and SGST should be levied on a common and identical base.

Both have suggested for consumption type GST, that is, there should be no distinction between raw materials and capital goods in allowing input tax credit. The tax base should comprehensivey extend over all goods and services up to final consumption point.

Also both are of the view that the GST should be strutured on the destination principle. According to task force this will result in the shift from production to consumption wherby imports will be liable to both CGST and SGST and exports should be relieved of the burden of goods and services tax by zero Conequently, revenues will accrue to the state in

which the consumption takes place or is deemed to take place.

The task force on GST said the computation of CGST and SGST liabilty should be based on the invoice credit method. i.e., allow credit for tax paid on all intermediate goods and services on the basis of invoices issued by the supplier. As a result, all diffrent stages of production and distribution can be interpreted as a mere tax pass- through and the tax will effectively 'stick' on final consumption within the taxing jurisdiction. This will facilitate elimination of the cascading effect at various stages of production and distribution.

Treatment of central GST and state GST - Both the Ec and the task force on GST have recommended treating the central GST and the state GST separately. The CGST and SGST should be credited to the accounts of the centre and the states separately. Taxes paid against the CGST should be allowed to be taken as input credit (ITC) for the CGST and could be utilized only against the payment of CGST. The same principle will be applicable to the SGST. Corss utilization of ITC between CGST and the SGST should not be allowed.

While the task force on GST insisted that the full and immediate input credit should be allowed for tax paid (both CGST and SGST) on all purchases of capital goods (including GST on capital goods) in the year in which the capital goods are acquired. Similarly, any kind of transfer of the capital goods at a later stage should also attract GST liability like all other goods and services.

Exemption from GST - The EC favoured the impostion of GST to be based on 'negative list' and for few exemptions if necessary but didn't provide any list of exemption. However the task Force also said that there shouldn't be any exemption form CGST and SGST but if for some reason, it is condidered necessary to provide exemption, the centre and states should draw a common exemption which be restricted to the following -

a) All pubilc services of Government (central, state and municipal/ panchayti rej) including civil- administration, health service and formal eduction services provided by Govt. schools and colleges, Defence, para- military, police, intelligence and Government Departments. Public services will not include the following :

1) Railways;
2) Post and telegraph;
3) Other commercial departments;
4) Public sector Enterprises;
5) Banks and insurance
6) Health and Educcation services.

b) Any service transactions between an employer and employee either as a service provider, recipient or vice versa.

c) Andy unprocessed food article which is covered under the public distribution system shold be exempt reagardless of the outlet through which it is sold;

d) Education services provided by non- government schools and colleges; and

e) Health services provided by non- Government agencies.

Experiences of Goods and Services Tax in federal countries

History of GST - France was the first country which introduced a comprehensive goods and service tax Regime in 1954. The Goods and service tax (GST) in proposed to be a comprehensive indirect tax levy on manufacture, sale and consumption of goods as well as services at a national level. The GST rate in various countries ranges form 5 per cent in Taiwan to 25 per cent in denmark.

In the late 1980s, the federal government of chanda replaced its MST (Manufacturer's Sale Tax) with a new value-added sales tax called the Goods and Services Tax (GST), The basic motive behind this reform was to introduce a new nationally harmonized sales tax which would replace individual provincial sales taxes (PST), and both the level of government would share the revenues generated there from. Subseqent negotiations to harmonize the provincial and nation sales taxes proved unsuccessful for the Canadian Government Various provinces challenged the introduction of national sales tax on the ground that the federal government was exceeding its constitutional powers by operating in a taxation field historically reserved for the provinces. But as a result of constructive efforts by the Canadian Government Nationl Sales Tax was implemented in 1989-90. In Australia it was introduced by the howard Govenment on 1 july 2000, replacing the previous Federal wholesale sales tax system and designed to phase out a number of various State and Territory Government taxes, dutied and levies such as banking taxes and stamp duty. This proved a milestone in the taxonomy of Australia.Today, it has spreda to about 150 coutries.

Reference:-

1. Personal Survey.

****

Workers Participation In Management in India

Dr. Rakhi Saxena * Deepika Shrivastava **

Introduction - Workers Participation In Management, Offers a decent and respectable platform for workers to share the decision- making powers with management ,It helps workers to look at the arena from a place of pride and importance , it helps them to know more about things that affect their daily lives. For harmonious industrial relation, not surprisingly, in most countries WPM is being advanced as an important tool of joint consultation and collective decision-making.

Objectives of the study -

- To study about the concept of worker participation in India.
- To explain the different perspective of worker participation in India.
- To discuss about the different forms & function of worker participation in India.

Concept of worker participation in India - Workers participation in management is an essential ingredient of Industrial democracy. The concept of workers participation in management is based on Human Relations approach to Management which brought about a new set of values to labor and management. Traditionally the concept of Workers Participation in Management (WPM) refers to participation of non-managerial employees in the decision-making process of the organization. Workers participation is also known as „labor participation or "employee participation in management. In Germany it is known as co-determination while in Yugoslavia it is known as self-management

Definition of WPM - A system of communication and consultation, either formal or informal, by which employees of an organization are kept informed about the affairs of the undertaking and through which they express .

Participation refers to the mental and emotional involvement of a person in a group situation which encourages him to contribute to group goals and share the responsibility of achievement. Participation in Management gives the worker a sense of importance, pride and accomplishment; it gives him the freedom of opportunity for self-expression; a feeling of belongingness with the place of work and a sense of workmanship and creativity.

Different perspectives of WPM - The Workers Participation Management is inevitable from the economic psychological and sociological point of view -

1. **The Economic perspective -** Economically, it flows from the assumption that employee contribute substantial to the progress and prosperity of the enterprise, and that they have therefore legitimate right to share equally in the gains of higher productivity .The higher productivity achieved through the fullest cooperation between labor and management for poor labour management relation do not encourage the workers to give more than the minimum necessary to the retain the job in many cases is all that he gives.
2. **The psychological perspective** - Psychologically, it implies recognition of employees not economic needs , the satisfaction of these needs. Through effective participation can help to rise the label of motivation participation gives the workers sense of importance, pride and accomplishment it gives them freedom and opportunity for expression a feeling of belonging to the place of work and a sense of workmanship and creativity .
3. **The sociological perspective -** Sociologically the need for the participation arises because modern industries are a social institution with the interest of the owner, the employer, the community and the workers equally bested in it. It aims at reducing the number of industrial disputes and creates positive conditions and an atmosphere in which industrial harmony and peace can develop

Forms of workers participation in India - The following participating forms are prevalent in India

- Works committees
- Joint management councils
- Join councils
- Unit councils
- Plant councils
- Shop councils
- Workers representative on the board of management and Workers participations in share capital

Works committee - The industrial dispute act, 1947, provides for the setting up of bipartite workers committees as a scheme of worker's participation in management which consists of representatives of employers and employees. The Act provides these bodies in every undertaking employing 100 or more workmen. the aim of setting up of these bodies is to promote measures for maintaining harmonious relation in the work place and to sort out differences of opinion in respect of matters of common interest to employers and employee.

Functions - The workers committees /joint committees are consultative bodies. There functions include discussion of conditions of work like lighting, ventilation, temperature, sanitation, etc.amenities like water supply for drinking

***Asst. Professor, Career College, Bhopal (M.P.) INDIA**
****Asst. Professor, Career College, Bhopal (M.P.) INDIA**

purpose, provision of canteens medical services, Safe working conditions, administration of welfare funds, educational and recreational activities and encouragement of thrift and savings.

It shall be the duty of the works committees to promote measures for securing and preserving amity and good relations between the employers and workmen. these committee s functioning actively in some organizations like Tata Iron and Steel co.(TISCO),Indian Aluminum Works at Belur and Hindustan Lever.

JOINT MANAGEMENT Councils (JMCs 1958) - The second five year plan recommended the setting up of joint councils Of management of representation of workers and management. The objectives of JMCs are follows -

- To improve the operational efficiency of the workers;
- To provide welfare facilities to them
- To satisfy the psychological needs of workers

Funcations -

- To be consulted on matters like standing orders, retrenchment, rationalization, closure of operations, etc.
- To receive information, to discuss and offer suggestions.
- To shoulder administrative responsibilities like maintaining welfare measures, safety training schemes, working hours, payment of rewards.

JMCs in some of the public sector undertakings, for example, Bharat Heavy Electrical have provided an appropriate forum for effective communication and managements unreserved all facts and information sought for.

JOINT Councils - At every division/ region/Zonal level, or as may be considered necessary In a particular branch of an organization /service employing hundred or more people, their shall be a join council. Every decision of joint council shall be on the basis of consensus and not by a process of voting; it shall be binding on the management and workers and shall be implemented within one month unless otherwise stated in the decision.

Functions -

- Settlement of the matters which remain unresolved by unit level councils and arranging joint meetings for resolving inter council problem
- Review of the working of the unit level council for improvement in the customer services
- Development of skills of workers and adequate facilities for trading
- Improvement in the general conditions of work

Unit councils - After the success of joint council scheme in manufacturing and mining new scheme of workers participation in management in commercial and service organizations public sector, having large-scale public dealing, was announced on 5th Jan. 1977. The organization include hotels restaurant hospitals air sea railway and road transport services shops schools provident fund and pensions trust organizations all financial institution banks insurance companies establishment of public amusement.

Functions -

- To create conditions for achieving optimum efficiency
- To identify area of chronically bad in adequate services and to take necessary corrective actions
- To study absenteeism problem and recommend steps to reduce it.
- To ensure a proper flow of to way communications between management and workers

Plant councils - The plant councils is formed in pursuance of recommendations of the second meetings of the group on labor at New Delhi on 23 september 1985.

The scheme is applicable to all central public scoter under takings accept those which are given specific exemption from the operation of the scheme by the government.

Functions - The plant Council deal with the following matters-

Operational Areas -

- Determination of productivity schemes taking into consideration the local condition.
- Material supply & preventing its shortfall
- Housekeeping activities
- Quality and technological improvements
- Improvement in productivity in general and in critical areas in particular

Economic and Financial Areas -

- Profit and loss statement ,balance sheet
- Review of operating expenses, financial result, and cost of sales
- Enterprise performance in financial terms, labor and managerial cost and market condition etc.

Personal Matters -

- Family welfare , Health education
- Special problems of women workers

Environmental Areas -

- Environmental protection
- Extension activities and community development projects.

Conclusion - Worker's participation is a system where workers and management share important information with each other and participate in decision taking. It provides scope for employees in decision-making of the organization. The participation may be at the shop level, departmental level or at the top level. The participation includes the willingness to share the responsibility of the organization by the workers. It is conducted through the mechanism of forums which provide for association of workers representatives. It rests on the basic assumption that a worker is more than a pair of hands .WPM aims to improving the quality of working life and thereby secure co-operation and commitment from workers .

References :-

1. Arun Monappa, "Industrial Relations", Tata McGraw Hill, New Delhi ,1989.
2. Bhabotosh Sahu , "Dynamics of Participation Management", Himalya,Mumbai ,1985.
3. "Seminar on Labour Participation Management " GOI, New Delhi, 1990.
4. N.N. Chatterji,"Industrial Relations in a Developing Economy", New Delhi 1984.
5. C.B. Mamoriya & V.S. P. Rao Personnel Mangement, Himalaya Publishing House (Thirteen edition) 2012.

Emerging Trends Of Hospitality Sector

Dr. L. N. Sharma *

Introduction - The hotel industry forms an integral part of the hospitality industry. The major fields within the hospitality industry include lodging, restaurants, event planning, theme parks, cruise line, etc. The hospitality industry is a multi-billion dollar industry that mostly depends on the availability of leisure time and disposable income. A hospitality unit such as a restaurant, hotel, or even an amusement park consists of various groups within it, including facility maintenance, direct operations (servers, housekeepers, porters, kitchen workers, bartenders, etc.), management, marketing, and human resources.

The global hotel industry is a prosperous industry and according to a report published by New Industry Report by Global Industry Analysts, Inc. in 2012, the Global Hotel Industry is expected to reach USD 479 billion by 2015.

As per the Economic Impact Report issued by the World Travel and Tourism Council, the direct contribution of travel and tourism to GDP worldwide in 2013 was USD 2,155.4 billion (2.9 % of GDP). Travel and tourism industry is expected to add more than 70 million jobs over the next decade, with two-thirds of those jobs to be created in Asia.

In India alone, the total market size of the tourism and hospitality industry stood at USD 117.7 billion in 2011 and is anticipated to touch USD 418.9 billion by 2022. The success of the hotel industry in India is second only to China in the entire Asia Pacific5. Further, India is a developing global business hub which offers attractive investment propositions for both luxury and moderate-tier hotels.

India is projected to be number one for growth globally in the wellness tourism sector in the next five years, clocking over 20 % gains annually through 2017. With opportunities aplenty, the future of the hotel industry in India looks very promising.

Important Trends In The Industry -

1. The Indian hospitality sector falls within the spectrum of travel and tourism. The sector's contribution to GDP is expected to grow at 7.8 % per annum during the period 2013-2023.
2. 100 % FDI is permitted on the Indian hotel industry under the automatic route. Foreign Direct Investment in this sector has also seen a surge with the inflow during the period of April 2000–March 2014 being estimated at USD 7,348.09 million.
3. Over the last few years, the hotel industry has observed a shift towards the budget and mid- market hotels. Renowned hotel companies have launched brands [eg. Ginger by Indian Hotels (IHCL)] catering to the budget and mid-market customers, who were thus far being served by the unorganized sector.
   Investment Information and Credit Rating Agency (ICRA) estimates 8-13 % growth in revenues for the industry over the next three years, with growth picking up in line with the macro-economic outlook for the country leading to mobilisation of travellers and pick up in FTAs.
4. The Hotel Industry is intricately associated to the tourism industry and the growth in the Indian tourism industry has in turn resulted in development in the Indian Hotels Industry. The Government of India increased resources on advertising campaigns like "Incredible India" and "Athithi Devo Bhava" to emphasize the rich variety of tourism in India.
5. The ministry even granted Tourist Visa on Arrival for the citizens of a number of countries including, Finland, Japan, Luxembourg, New Zealand and Singapore. The tourism ministry has envisaged a budgetary allocation of INR 200 billion in the Twelfth Five Year Plan.
6. According to market analysis, the number of tourists availing the tourist Visa on Arrival (VOA) scheme during January- June 2014 has recorded a growth of 28.1 %.
7. According to World Economic Forum Travel & Tourism Competitiveness Report 2013, India ranked 65th out of 144 countries in terms of Foreign Tourist Arrivals (FTAs)14 The WTO (World Travel Organization) predicts that India will receive 25 million tourists by the year 2015.15 By 2015, China and India will have absolute year on year growth equal to or greater than the UK, France or Japan.
8. The hospitality sector in India expects 52,000 new hotel rooms to be added in five years (2013-17). This will lead to a rise of over 65 % in total hotel inventory in India.
9. The demand-supply gap in India is very material and there is need for more hotels in all major cities. The shortage is especially acute within the budget and the mid- market segment.
10. Talent management is a major challenge for the sector. Inadequate supply of quality talent and increased competition for talent within the sector and from competing service sectors has made attrition a significant issue for the industry.
11. In the near term, despite an anticipated revival in room demand, hotels will not be able to hike ARRs significantly as the expected additions to room inventory

* Professor (Commerce) Govt. P.G. College, Neemuch (M.P.) INDIA

will intensify competition.

Conclusion - The future for the hospitality sector looks very promising. With the growth of the economic scenario gathering momentum and companies increase spending on travel, demand for the industry is very likely to improve. With salary increases within the corporate world, leisure travel and disposable income are likely to be on the rise.

Further, the number of foreign tourists coming to India is expected to reach USD 11.1 m by 202123. The demand-supply gap in India is very acute and there is need for more hotels in all major cities. The shortage is especially palpable within the budget and the mid- market segment. There is an urgent need for budget and mid- market hotels in the country as travelers look for safe and affordable accommodation.

The Indian hotel industry is expanding at a massive rate, with several companies envisaging investment plans. Investment in Travel & Tourism is estimated at INR. 2.8 trillion by 2021 (implying a CAGR of 8.7 %), according to World Travel and Tourism Committee (WTCC) estimates.24

Demand continues to rise in the hospitality sector due to growing business and commercial activities; escalation of disposable income; the improved portfolio of the international tourism sector; increased leisure time; improved transport facilities; and technological advancements facilitating remote tour management from overseas.

However, due to the cash crunch and high interest rates and the sector being highly dependent on external factors, the investors and hotel groups are approaching fresh expansion projects with caution.

To solve these issues and to do away with the constraints being faced by the hotel industry in addition to limited availability of land like procurement of multiple clearances / approvals which are required from the Central and State Government agencies for hotel projects which may be as many as 65 or more clearances/approvals are required by hotel projects which varying from State to State, the Government has approved the setting up of a 'Hospitality Development and Promotion Board (HDPB)' for hotel projects.25 Further, the government has extended its full support to the hospitality industry by introducing friendly legislation, a liberal policy framework, and support infrastructure and open-sky policies.

All in all, great progress can be hoped for the Hotel Industry in India in the recent future with both the Government and Private sector working towards the massive expansion of the industry.

References :-

1. World Travel and Tourism Council, Economic Impact Report, 2014;
2. Hotels in India, available at http://www.tphtours.com/ tphtours page/pages/show ex pages/1/hotels-in-india.html
3. India Brand Equity Foundation: Tourism and Hospitality Industry in India : According to a study conducted by SRI International, available at http://www.ibef .org/ industry/tourism-hospitality-india.aspx
4. India Brand Equity Foundation: Tourism and Hospitality Industry in India: available at http://www.ibef.org/industry/ tourism-hospitality-india.aspx
5. Foreign Direct Investment Policy, 2014, available at http:/ /dipp. nic.in/English /Policies/FDI_ Circular_ 2014. pdf;
6. Hotels Sector Analysis Report, available at http:// www.equitymaster.com/ research-it/sector-info/hotels/ Hotels-Sector-Analysis-Report.asp
7. Indian Hotel Industry Report 2013- ICRA, available at http://www.icra.in/All Types Of Reports. aspx? Report Category=Hotels
8. The Growing Indian Hospitality Industry, available at http:/ /www.hostsindia.in/ index. php? option= com_ content & task=view&id=18&Itemid=32
9. Indian hospitality: the industry, regulations and incentives (January 2008), available at http://www.singhania.com/ Publication/IHL156_india-B.pdf
10. Indian Hotels Industry, Quarterly Review, available at http://www.icra.in/Files/ ticker/ Indian%20Hotels%20Industry%2030032012.pdf
11. Hospitality Development and Promotion Board (HDPB), available at http://www. tourism.gov.in/writereaddata/ CMSPagePicture/file/Hotel/HDPB.pdf

****

M - कॉमर्स व इसकी भारत में संभावना

डॉ. पारितोष अवस्थी *

प्रस्तावना – इन्टरनेट का जैसे जैसे वाणिज्य में उपयोग बढ़ने लगा वैसे–वैसे ए–कॉमर्स का जन्म हुआ और यह विश्वव्यापी आवश्यकता के रूप स्वयं को स्थापित कर चुका है और अब समय के साथ साथ जैसे जैसे सूचना प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है वैसे–वैसे इस क्षेत्र में और नये आयामों का विकास हो रहा है। इसी क्षेत्र में एक नये सिद्धांत को जन्म दिया जिसे हम M-कॉमर्स के नाम से जानने लगे है। यह E - कॉमर्स की तरह ही उपयोग किया जा रहा है तथा यह उससे अधिक उन्नत व आधुनिक हो रहा है। अब E - कॉमर्स डेस्क टॉप कम्प्युटर के साथ अब मोबाईल फोन, टेबलेट, लेपटॉप, इत्यादि तक पहुँच कर अपनी पैठ बना रहा है। यही बगैर तारो के प्रयोग से चलने वाले उपकरण जो तेज इन्टरनेट की सेवा से युक्त होते है, इनके माध्यम से किया जाने वाले समस्त वाणिज्यिक गतिविधियाँ ही M - कॉमर्स कहलाती है। यह तकनीकी व्यक्ति को किसी भी स्थान से किसी भी समय पर विभिन्न प्रकार की वाणिज्यिक गतिविधियों को संचालित करने की सुविधा प्रदान करती है। जैसे बैंकिंग, विज्ञापन, वस्तुओं के खरीदने बेचने से संबंधित क्रियाएँ, ऑन लाईन भुगतान करना, इसी प्रकार समस्त वाणिज्य से संबंधित क्रियाएं M - कॉमर्स में शामिल की जा रही है।

परिचय – मोबाईल फोन का उपयोग अब केवल बात करने तक ही सीमित नहीं है, अपितु इन्टरनेट के साथ जुड़कर इसने एक विशेष तकनीक को जन्म दिया है, जो M - कॉमर्स के रूप में वाणिज्य के क्षेत्र को नये आयाम दे रही है। मोबाईल फोन, स्मार्ट फोन, टेबलेट, लेपटॉप व इनसे जुड़े अन्य उपकरणों के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही समस्त प्रकार की वाणिज्य संबंधित गतिविधियाँ, M - कॉमर्स के अतंर्गत शामिल होती है। इनके माध्यम से की जा रही बैंकिंग गतिविधियाँ, खरीदी–बिक्री, विज्ञापन प्रचार–प्रसार, इत्यादि यह सब M - कॉमर्स की अवधारणा से जुड़े तत्व है। इसके अलावा भी अनेक क्षेत्रो में यह माध्यम तेजी से सक्रिय होता जा रहा है, जैसे सामाजिक स्तर पर, शिक्षा के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में व अन्य कई जानकारियों के भंडार के रूप में भी यह प्रौद्योगिकी विकसित हो रही है। स्मार्ट फोन विभिन्न प्रकार के एप्लिकेशन के माध्यम से यह सुविधाएँ प्रदान कर रहे है। मोबाईल एप्लिकेशन का निर्माण व उसे संचालित करना भी अब एक उद्योग के रूप में प्रकट हो रहा है।

ऑन लाईन खरीदी करनी हो, बैंकिंग व्यवहार करना हो, बिलों का भुगतान, इत्यादि गतिविधियाँ भी M - कॉमर्स से संबंधित है। लगभग सभी बैंक व कई ऑन लाईन व्यापार करने वाली कम्पनियाँ अपनी इन्टरनेट वेबसाईट के साथ–साथ अपना मोबाईल एप भी प्रस्तुत कर रही है, इनकी संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है।

यह क्षेत्र सभी आयामों जैसे Customer to Customer, Business to Business, Government to Government, Business to Customer में उपलब्धता उत्पन्न कर रहा है। यह भारत की वर्तमान स्थिति में निरंतर प्रचलित हो रही एक प्रभावी तकनीक है, इसी कारण कई कार्पोरेट समूह अपने व्यवसाय को यह नया प्लेटफार्म प्रदान कर रहे है।

शोध के उद्देश्य – इस शोध पत्र के उद्देश्य निम्नलिखित है –

1. वाणिज्य के निरंतर हो रहे विकास व उसमें सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग पर प्रकाश डालना।
2. M - कॉमर्स के उपयोग व इसके मुख्य पक्षकारों के आधार पर विश्लेषण करना।
3. भारत के सन्दर्भ में इसके लाभ व हानियों का अध्ययन करना।
4. इस प्रौद्योगिकी की भारतीय समाज में संभावनाएं व भविष्य में इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालना।
5. मनुष्य के जीवन स्तर पर इसके हो रहे प्रभाव का अध्ययन करना।

शोध विधि – यह एक नवीन विषय है जिसमें अभी बहुत अधिक शोध की आवश्यकता है, साथ ही यह निरंतर परिवर्तित व प्रगतिशील विषय है, इसी कारण इस विषय पर शोध की प्रक्रिया अधिक जटिल हो जाती है, लगातार हो रहे अविष्कार बदलाव इसे क्षेत्र को अधिक आयाम प्रदान कर रहे है। इस क्षेत्र में शोध हेतु गहन रूप से लगभग सभी उपलब्ध साधनों से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। विभिन्न शोध पत्रिकाएँ, जर्नल, केस स्टडी, इस सन्दर्भ में प्रकाशित पुस्तकों के आधार पर व अलग अलग प्रकार के आंकड़ो की सहायता से यह शोध का प्रयास किया जा रहा है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मोबाईल कॉमर्स की अवधारणा क्या है, व इससे संबंधित कुछ विशेष पक्षों के बीच होने वाली व्यापारिक गतिविधियों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने व उन्हें समझने का प्रयास किया जाएगा, व इस प्रकार के व्यापार की भारत की पृष्ठभुमि पर क्या संभावनाएं है, व इसकी सफलता के लिये अवसर व चुनौतियों का अध्ययन किया जायेगा व अन्त में निष्कर्ष में मनुष्य के जीवन स्तर में इसके लाभ व हानियों का अध्ययन व भारत के विकास में इसकी भूमिका पर चर्चा के साथ सम्पन्न किया जायेगा।

M - कॉमर्स का मूल सिध्दांत – विश्व में सभी स्थानों पर वॉणिज्य ने प्रौद्योगिकी को नये अविष्कार के लिए प्रोत्साहित किया है, प्रौद्योगिकी ने भी हर समय वाणिज्य को नये–नये अकल्पनीय माध्यम उपलब्ध कराएँ है। सूचना प्रौद्योगिकी के विकास ने वॉणिज्य को भी चहुँमूखी विकास प्रदान किया है। इतिहास हो चुके टेलीग्राम से वर्तमान के स्मार्ट फोन तक सभी वॉणिज्य की गतिविधियों को सहायता प्रदान करते रहें है। इन्टरनेट के बाद तो जैसे वाणिज्य के क्षेत्र में क्रांति ला दी। इन्ही प्रौद्योगिकी व वॉणिज्य के संबंध को हम अलग–अलग नामों से जानते है। डेस्कटॉप कम्प्युटर के माध्यम से की जा रही वॉणिज्य की गतिविधियों काए–कॉमर्स के नाम से जाना जाने लगा। अब यह कार्य एक कदम और आगे जाकर M - कॉमर्स की और बढ़ गया जो अब अपने मोबाईल फोन के माध्यम से ही यह सारे कार्यों को करने में सक्षम होने

*प्राचार्य, श्री वैष्णव वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

लगे। मोबाईल फोन व अन्य वायरलेस उपकरणों के माध्यम से की गई वॉणिज्य कि गतिविधियों को ही M - कॉमर्स की संज्ञा दी जाती है। मोबाईल फोन विशेषकर स्मार्ट फोन कई अन्य क्षेत्र जैसे शिक्षा, समाज कार्य, यात्रा व टिकट की जानकारी, मनोरजंन, संबंधी जानकारी, यातायात संबंधी जानकारी इन सभी क्षेत्रों में अलग-अलग अप्लीकेशन के माध्यम से यह सेवाएँ प्रदान की जा रही है।

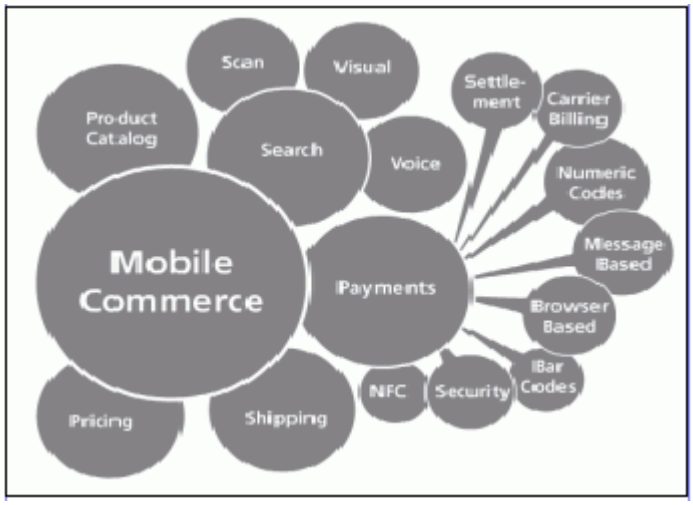

M - कॉमर्स के उपयोग – M - कॉमर्स का उपयोग वर्तमान समय में लगातार बढ़ता जा रहा है, इसे अलग-अलग क्षेत्रों के आधार पर निम्नलिखित प्रकार से समझने का प्रयास करेगें –

1. **कॉमर्स** – इस क्षेत्र में M - कॉमर्स का अधिक उपयोग प्रयोग किया जा रहा है, और निरंतर प्रयास किया जा रहा है कि इसे अधिक से अधिक विकसित किया जा सके। कई कंपनिया जैसे फ्लिपकार्ड, स्नेपडील, अमेजन, मंत्रा, इत्यादि जो ऑनलाईन खरीदी-बिक्री के व्यापार में संलग्न है उनके द्वारा वेब साईट के साथ-साथ मोबाईल अप्लिकेशन भी उपलब्ध किये जा रहे है व मोबाईल अप्लिकेशन के माध्यम से खरीदी करने पर विशेष छुट आदि उपलब्ध कराकर उपभोक्ता को इस ओर अधिक आकर्षित किया जा रहा है। इनके माध्यम से उपभोक्ता से इसी माध्यम से आर्डर प्राप्त किये जाते है जो सामान्यत: 7 से 10 दिन के भीतर सुपुर्द कर दिये जाते है यह राज्य स्तर पर व अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकते है। यह ऑनलाईन भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध कराते है जिसकी सहायता से बैंक के माध्यम से सीधे भुगतान किया जा सकता है। साथ ही यह अपनी पंसद की वस्तुएं खरीदने बेचने का भी प्लेटफार्म बन रहा है, ईबे ओएलएक्स व इस प्रकार के कई और मोबाईल एप्प यह सुविधा प्रदान कर रहे है व इस प्रकार की कई ऑन लाईन व्यापार करने वाली कंपनियों के माध्यम से यह क्षेत्र भी लगातार प्रगतिशील है।

2. **शिक्षा**– शिक्षा प्रदान करने के माध्यम अब केवल किताबें व स्कूल-कॉलेज या लाईब्रेरी न होकर मोबाईल फोन भी है, इसके माध्यम से शिक्षा में एक क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। किसी भी प्रकार की जानकारी चाहे वह विश्व के किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो व इंटरनेट के माध्यम से मोबाईल, लेपटॉप या टेबलेट आदि पर आसानी से खोजी जा रही है। इसमे गूगल, विक्किपिडीयाँ, यूट्यूब् जैसी साईट यह जानकारी आसानी से उपलब्ध करा रही है। वर्तमान समय में शिक्षा प्राप्त करने के लिये पढ़ने के साथ देख व सुन कर मनोरंजक तरीके से ज्ञान प्राप्त करने के साधन M - कॉमर्स की सहायता से उपलब्ध है, इसका सबसे अच्छा लाभ यह है कि इसे किसी भी समय किसी भी स्थान पर उपयोग किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के मोबाईल अप्लिकेशन भी विद्यार्थियों की सहायता के लिये तैयार किये गये है, जिनका लाभ विद्यार्थी प्राप्त कर रहे है। इसकी उपयोगिता को जानकर ही सरकार द्वारा छात्रों को आकाश टेबलेट प्रदान करने की महत्वकांक्षी योजना सरकार द्वारा चलाई गई थी। मध्य प्रदेश शासन द्वारा सभी शासकीय महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं को स्मार्ट फोन प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया तथा अन्य कई राज्यो में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर लेपटॉप या डेस्कटॉप कम्प्युटर प्रदान करने की योजना चलाई जाती है।

3. **मनोरंजन**– युवा वर्ग के मनोरजंन के सबसे प्रमुख साधनो में स्मार्ट फोन का स्थान है, इसका उपयोग गेम, सोशल मीडियाँ, फिल्में, इन्टरनेट ब्राउसिंग, इत्यादि कार्यो के लिये प्रयोग किया जा रहा है। शोध के अनुसार मोबाईल का उपयोग युवा वर्ग में 80 प्रतिशत मनोरंजन के लिये ही किया जाता है।

4. **यात्रा व टिकट**– मोबाईल के माध्यम से यात्रा संबंधी भी कई सुविधाएँ उपलब्ध की गई है। *गूगल मेप* के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी व आवागमन के साधन सभी की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। साथ ही *यात्रा डॉट कॉम, मेक माय ट्रिप* जैसी वेब साईट के माध्यम से यात्रा की पूरी व्यवस्था आसानी से की जा सकती है, साथ ही अनेक स्थलो की जानकारी देखने योग्य स्थलों की दूरी व स्वयं की स्थिति जानने के लिये भी स्मार्ट फोन अत्यन्त उपयोगी सिध्द होता है।

5. **स्वास्थ्य सेवाएँ** – तेजी से विकसित हो रही तकनीक का उपयोग अब मनुष्य की सेहत संबंधी कार्यो में भी उपयोग किया जा रहा है। एप्पल आई फोन में प्रयोग की गई तकनीक के माध्यम से मनुष्य की शरीर की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी फोन के माध्यम से ही उपलब्ध होने लगी है जैसे कितनी कैलोरी उपयोग की गई, हृदय गति कितनी है, कितनी कैलौरी की शरीर को आवश्यकता है। इस प्रकार की बेहद महत्वपूर्ण जानकारी फोन के माध्यम से ही उपलब्ध हो जाती है। इसके साथ *1एमजी व नेटमेट, लेब्रेट* जैसे एप भी विभिन्न प्रकार की दवाईयों की जानकारी के लिये अतिउपयोगी होते है।

M - कॉमर्स के लाभ – भारत तेजी से विकसित होता मोबाईल बाजार है, यहाँ कुल 960,579,472 मोबाईल उपभोक्ता है और यह संख्या लगातार बढ़ रही है, और इसके साथ ही भारत के सन्दर्भ में उपयोग होने वाले मोबाईल एप की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसके लाभ को हम निम्न बिन्दूओं के आधार पर प्रस्तुत कर सकते है:-

1. **व्यक्तिगत**– मोबाईल फोन एक व्यक्तिगत वस्तु है, जिसे व्यक्ति अपनी सुविधा व पसन्द के अनुसार खरीदता व उपयोग करता है। इसका लाभ सभी व्यापारिक संस्थाओ को भी होता है इसके माध्यम से वह उपभोक्ता की जानकारी अपने पास सुरक्षित रख सकती है, जिसका भविष्य में अन्य व्यवहार के समय इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कई सोशल साईट

जैसे फेसबुक, ट्वीटर, व वाट्सअप जैसे एप को भी व्यक्तिगत रूप से आसानी से उपयोग किया जा सकता है। इसी कारण से यह भारत में व्यापक रूप से प्रगति कर रहा है।

2. **सार्वभौमिकता**– मोबाईल फोन लगभग सभी स्थानो में उपयोग किया जा सकता है, यदि नेटवर्क उपलब्ध है तो यह घर, ऑफिस, बगीचे, बाजार किसी भी जगह उपयोग किया जा सकने वाला उपकरण है। इसकी यही उपयोगिता व भारतीय लोगों की अधिक सामाजिक होने का स्वभाव उन्हें इसकी और आकर्षित करता है।

3. **विकल्पों की अधिकता**– ऑन लाईन खरीदी करने का विशेष लाभ यह है कि यहाँ विकल्प की अधिकता होती है। उपभोक्ता अपनी आवश्यकता व पसंद के अनुसार वस्तु का चयन कर सकता है। उसे मुल्य,किस्म व ब्राण्ड इत्यादि का चयन करने की सुविधा उपलब्ध होती है।

4. **भुगतान की सुविधा**– ऑन लाईन व्यवहार में भुगतान हेतु कई विकल्प उपलब्ध होते है जैसे बैंक के माध्यम से भुगतान, डिलिवरी के समय भुगतान, ई–वॉलेट के माध्यम से भुगतान (मोबाईल विक्कि,पैटिएम,नेटएलर) इन साधनों की सहायता से आसानी से व सुरक्षित प्रकार से भुगतान किया जा सकता है।

5. **सभी उम्र के उपयोगकर्ता**– मोबाईल फोन का उपयोग लगभग सभी उम्र के व सभी वर्ग के द्वारा किया जा रहा है। इसलिये यह एक अधिक संभावनाओं से युक्त क्षेत्र है।

M - कॉमर्स की चुनौतियाँ

1. **नई तकनीक का भय**– यह मानव स्वभाव है कि किसी भी नई व्यवस्था को आसानी से स्वीकार नहीं कर पाता है। मोबाईल कॉमर्स भी नई तकनीक है जो धीरे–धीरे समाज में अपनी जगह बना रही है, परन्तु अभी भी एक बड़ा वर्ग इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा है।

2. **निजता का भय**– उपभोक्ता को इस बात की भी चिंता होती है कि उसकी जानकारी किसी गलत हाथों में न चली जाए, जिससे उसे भविष्य में परेशानी उठानी पडे।

3. **मोबाईल की स्क्रीन**– मोबाईल की स्क्रीन अधिक से अधिक 5 या 6 इंच तक की ही उपलब्ध होती है। इससे बड़ी स्क्रीन फोन के लिये व्यावहारिक नहीं होती है, पर यह कुछ वर्ग विशेष के लिये पर्याप्त नही होती वह डेस्कटॉप कम्प्युटर के माध्यम से ही ऑनलाईन शॉपिंग पसंद करते है।

4. **तकनीकी का ज्ञान**– मोबाईल कॉमर्स का उपयोग करने के लिये तकनीकी ज्ञान का होना आवश्यक है। भारत में आई फोन, ऍन्राईड, व विन्डोस फोन उपलब्ध है, जिनमे अलग–अलग तकनीकी का प्रयोग होता है। इसी कारण इसे समझना व उपयोग करना अधिक सरल नहीं होता है।

5. **नेटवर्क की समस्या**– भारत में सभी जगह विशेष कर ग्रामीण इलाको में मोबाईल नेटवर्क की समस्या रहती है। अभी 3जी व 4जी जैसे नेटवर्क शहरों में ही ठीक प्रकार से व्यवस्थित नहीं हो सके है। बिना अच्छे नेटवर्क के मोबाईल सेवा व च–कॉमर्स एक स्वप्न मात्र ही है।

निष्कर्ष – भारत निश्चित ही एक उद्योग जगत की बड़ी संभावनाओं के रूप में उभर रहा है। यहाँ विकास में तकनीकी का भी महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। जिसमें मोबाईल फोन की भूमिका भी अति महत्वपूर्ण होगी। यह वाणिज्य के व्यवहार करने का अत्यन्त सुगम माध्यम के रूप में उभरा है। साथ ही अन्य कई क्षेत्रो में भी इसकी महता सिद्ध हो रही है, जैसे शिक्षा , बैकिंग, रोजगार, यात्रा व टिकट बुकिंग इत्यादि। इन्ही सभी क्षेत्रों की कई संभावनाओं व चुनौतियों का सामना करते हुए च–कॉमर्स लगातार विकसित हो रहा है। लगभग हर क्षेत्र की आवश्यकता को ध्यान में रख कर विभिन्न प्रकार के एप्स फोन में उपलब्ध किये जा रहे है। नेटवर्क कंपनियों पर नियंत्रण करने हेतु Telephone Regulatory Authority of India (TRAI) कार्यरत् है, जो निरंतर इन पर नजर बनाये रहती है, व इन्हे बेहतर सेवाएं उपलब्ध करने हेतु प्रोत्साहित करती है। 3जी व 4जी नेटवर्क का फैलाव इस क्षेत्र को और शक्तिशाली बनाएगाँ।

इसी प्रकार इसका एक अन्य सामाजिक पहलु है जो इसकी नकारात्क छवि को प्रस्तुत कर रहा है कि आज समाज विशेष कर युवा वर्ग मोबाईल फोन का गुलाम हो रहा है, यह उसे अधिक खर्चीला बना रहा है व इसके कारण वह अपना बहूमुल्य समय बर्बाद कर रहा है। आज फेसबुक, वॉट्स अप जैसे एप्प युवा वर्ग को एकांकी बना रहे है उनकी सामाजिक होने की प्रकति व मेल जोल की भावना को कम कर रहे है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची:–

1. What is the Advantages and disadvantages of mobile commerce? http://wiki.answers.com/What_is_the_Advantages_and_disadvantages_of_mobile_commerce.
2. M-commerce: The Next Big Hope! http://voicendata.ciol.com/content/top_stories/112050906.asp.
3. Mobile Commerce in India: BuzzCity's Report http://www.imediaconnection.in/article/806/Research/mobilecommerce-in-india-buzzcitys-report.html.
4. M Commerce and its applications. http://www.articlesbase.com/ecommerce-articles/mcommerce-and-itsapplications-1011452.html.
5. M-commerce (mobile commerce) hhttp://searchmobilecomputing.techtarget.com
6. Afshar, J. A. & Navaser, Kh. (2010), Mobile Commerce: the Force of Electronic Commerce Future: International Seminar On `Innovations in Strategic Management for Organizational Excellence',Pune, India Au, Y.A. & R.J. Kauffman, (2007),
7. The economics of mobile payments: Understanding stakeholder issues for an emerging financial technology application, Electronic Commerce Research and Applications Bahlman, D. T. and F. C. Johnson, (2005), Using

****

सिलाई, बुनाई दस्तकारी से संबंधित महिलाओं की आर्थिक दशाओ का अध्ययन (रीवा जिले के विशेष संदर्भ में)

डॉ. रूपेश द्विवेदी * राजेश कुमार विश्वकर्मा **

प्रस्तावना – कपड़ा, चमड़ा, फर, बार्क या किसी अन्य लचीली 'वस्तु' को आपस में सुई एवं धागों की सहायता से बांधना, सिलना या किसी भी मनुष्य के शरीर की नाप तथा शरीर की बनावट को ध्यान में रखते हुए नाप के अनुसार काटे गए कपड़े को सिल कर तैयार करने की कला सिलाई कहलाती है।

इसी प्रकार बुनाई खासतौर से उन्नी एवं अन्य प्रकार के धागे से कि जाने वाली कला है जिसमें विभिन्न प्रकार के धागों को इस्तेमाल करके वस्तु बनाए जाते हैं, ऐसी कला को बुनाई कहा जाता हैं। इसी प्रकार दस्तकारी का अर्थ है, किसी भी कपड़े में हांथ से की जाने वाली कलाकारी अर्थात् कढाई या कपड़ों में की जाने वाली पेंटिग या रंग।

परिकल्पना –

1. सिलाई बुनाई एवं दस्तकारी का कार्य अनुपयोगी कार्य है।
2. सिलाई, बुनाई एवं दस्तकारी से धन का अपव्यय होता है।
3. इसका सामाजिक कल्याण में किसी प्रकार का योगदान नहीं होता।
4. सिलाई, बुनाई एवं दस्तकारी से अधिक रोजगार संभव नहीं है।

शोध प्रविधि – प्रस्तुत शोध में प्राथमिक एवं द्वितीयक समंको का संकलन किया जायेगा। संमको का वर्गीकरण, सारणीयन एवं विश्लेषण कर वास्तविक परिणाम प्राप्त किया जायेगा। यदि परिणाम वास्तविकता से मेल नहीं खाते तो पुन: सर्वेक्षण करके शोध कार्य को दोहराया जाएगा।

उद्देश्य –

1. महिलाओं की आर्थिक दशाओं में सुधार ।
2. सिलाई,बुनाई जैसे गृह उद्योगो को बढ़वा देना।
3. महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करना।
4. बेरोजगारी दूर करना।

शोध विश्लेषण – रीवा शहर में वार्ड क्रमांक 07 में महिलाओं द्वारा एक व्यवसाय संचालित किया गया,जिसमें सिलाई, बुनाई एवं दस्तकारी सम्बधित कार्य किए जाते है।उसका सम्पूर्ण खर्च इसी संस्था द्वारा उठाया जाता है,इस संस्था में एक अधिकारी तथा कई प्रतिनिधि कार्यरत है।

आधुनिक युग के बदलते परिवेश में अनेक परिर्वतन हुए है,जिनमें से एक है मनुष्य का पहनावा समय परिवर्तन के साथ-साथ फैशन भी परिवर्तित हुआ है,आज लोग कई प्रकार के फैशनेबल वस्त्रो का उपयोग करना पसंद करते है,और यह कार्य सिलाई बुनाई एवं दस्तकारी द्वारा ही किया जाता है।

जिस प्रकार किसी कार्य को करने से पूर्व उसका प्रारम्भिक ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार सिलाई व्यवसाय में कार्य करने से पूर्व सिलाइयों एवं उनमें प्रयुक्त टाको का का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए।

इसलिए सर्वप्रथम सिलाई व्यवसाय में प्रयोग किए जाने वाले समस्त टाको एवं उनकी उचित प्रयोग विधि को जानना आवश्यक है।

सारणी क्रमांक 1 **(देखे अगले पृष्ठ पर)**

सारणी में कपडे के मुल्य एवं सिलाई की दर के आधार पर कपडे का कुल मूल्य ज्ञात किया जाता है।

जैसे फ्राक सूट का कपडा 1100रू-1200रू के दर से क्रय किया जाता है। एवं 250रू-500रू तक सिलाई ली जाती है। इसके पश्चात वह सूट कुल 1360रू1450रू अथवा 1600रू 1700रू तक का पडता है।

विश्लेषण के आधार पर परिणाम – महिलाओं एवं वच्चो के लिए कपडों का सिलने का व्यवसाय वहुआयामी लाभ देने वाला है। एक ओर सिलाई कार्य करने वालो को रोजगार मिलता है। उनके समय का सदुपयोग होता है। और कम पूँजी से लाभकारी व्यवसाय प्रारंभ करने का अवसर मिलता है। दूसरी ओर मोहल्ले के रहवासियों को सस्ते दर पर यह कपडा सिलवाने का लाभ मिलता है। कुल मिलाकर समाज का सामाजिक स्तर भी उच्चा उठता है।

समस्याए/जोखिम –

1. प्रशिक्षण की कमी के कारण जानकारी उपलव्ध न होना ।
2. प्रवंधन व्यवस्था की समस्या।
3. संबंधित सामग्री का उपजब्ध न होना ।
4. पूँजी एवं कर्मचारी की कमी।

सुझाव –सिलाई वुनाई एवं दस्तकारी से संबंधित कठिनाइयों के साथ कई समाधान भी पाए गए है। बेहतर कैरियर के लिए जगह का चुनाव मशीने व अन्य जरूरी चीजो लागत लोन कमाई का ध्यान रखकर व उचित जानकारी प्राप्त कर ही इस व्यवसाय का संचालन करना लाभदायक होगा।

निष्कर्ष– सिलाई बुनाई एवं दस्तकारी का कार्य आधुनिक युग की एक आवश्यकता है। यह नए नए परिवर्तनो के साथ वस्त्रो को नए स्वरूप में परिवर्तित करने का माध्यम है। इस कार्य के आधार पर यह ज्ञात हुआ की महिलाओं को स्वयं निर्भर बनाने का साधन है। जिसके माध्यम से महिलाओ को आसानी से रोजगार प्राप्त होता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. शोध प्रविधि- सी आर कोठारी, 2013-2014
2. शोध प्रविधि- एस सचदेव, 2010-11
3. टेलरिग कटिग एण्ड फैशन डिजाइन -जी एल रमठा, 2010-11
4. उद्धमिता विकास - त्रिभुवन नाथ शुक्ला, 2008-09
5. वित्तीय प्रवंधन - एम एम शुक्ला, 2013-2014

* अतिथि शिक्षक (वाणिज्य) अ0 प्र0 सि0 वि. वि., रीवा (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी (वाणिज्य) अ0 प्र0 सि0 वि. वि., रीवा (म.प्र.) भारत

सारणी क्रमांक 1

क्र.	कपडे	कपडे का रेट	सिलाई का रेट	कुल
1.	ब्लाउज सिंपल स्तर	50 रू	30.से 35	80 से 85 रू
2.	पेटी कोट	100 रू	40-50 रू	140-150 रू
3.	सलवार सूट	250-300 रू	100 रू	350-400 रू
4.	फ्राक सूट	1100-1200 रू	250-500 रू	1350-1700 रू
5.	पटियाला सूट	1000 रू	450 रू	1450 रू
6.	छोटी फ्राक	200 रू	50 रू	250 रू
7.	कुरती	250 रू	50 रू	30 रू
8.	स्कर्ट	250 रू	100 रू	350 रू
9.	टाप	250-300 रू	150 रू	400 रू
10.	साडी पीको फाल	20 रू	20 रू	60 रू

स्त्रोत साक्षात्कार

****

मुर्गी पालन फर्म की लागत लाभ विश्लेषण का अध्ययन (रीवा जिले के रतहरा फर्म के संदर्भ मे)

राजेश कुमार विश्वकर्मा * डॉ. रूपेश द्विवेदी **

शोध सारांश – मुर्गी पालन व्यवसाय से संबंधित बहुउद्देशीय शाखा है। इसका विकास मांस एवं अंण्डे कि उत्पादन एवं से संबंधित है। मुर्गी पालन किसी भी समाज के व्यक्ति कर सकते हैं। इसके शासन स्तर में मुर्गी पालन विभाग का गठन किया गया। जिससे लाभ की प्राप्ति होती है तथा लोगों को रोजगार प्राप्त होता है।

प्रस्तावना – मुर्गी पालन कुटीर उद्योग के अन्तर्गत किया गया व्यवसाय है। जिसे कुक्कुड पालन भी कहते है। मुर्गी पालन को English में Poultry Form कहा जाता है। मुर्गी पालन दो शब्दो से मिलकर बना है। मुर्गी +पालन मुर्गीपालन, मुर्गी से आशय छोटे–छाटे चूजों से है तथा पालन से आशय चूजों को पालने व उनकी देख– रेख करने से है। वर्तमान में यह व्यवसाय वृहद उद्योग का रूप धारण कर चुका है। मुर्गी पालन व्यवसाय आय बढ़ने का एक बेहतर साधन वन चुका है।

इस व्यवसाय में कम कीमत पर अधिक खाद्य पदार्थ प्राप्त होता है। उदाहरण के लिये वायलर मुर्गे का भार 1 k.g. शरीर भार 2 k.g. दाना मिश्रण खिलाकर प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार मुर्गी से एक दर्जन अण्डे पाने के लिये उसे सिर्फ 2.2 k.g. दाना मिश्रण ही खिलाना जरूरी होता है। मुर्गी पालन व्यवसाय अण्डा एवं मांस दोनों के लिये किया जाता है। इसके माल इलाहाबाद व जबलपुर से मगांया जाता है।

परिकल्पना –

1. मुर्गीपालन कार्य कठिन होता है।
2. मुर्गीपालन से सभी के लिये उपयोगी नहीं है।
3. मुर्गीपालन के लिये अनुकूलित स्थान व वातावरण का होना।
4. मुर्गीपालन में अधिक रोजगार सम्भव नहीं है।

शोध प्रविधि – प्रस्तुत शोध में प्राथमिक एवं द्वितीयक समंको का किया जायेगा। समंको का वर्गीकरण, सारणीयन एवं विश्लेषण कर वास्तविक परिणाम वास्तकिता से मेल नहीं खाते तो शोध को दोहराया जायेगा।

उद्देश्य –

1. मुर्गीपालन व्यवसाय का अध्ययन करना।
2. मुर्गीपालन व्यवसाय को अधिक लाभकारी बनाना।
3. मुर्गियों में लगने वाले रोग व उनके उपचार का पता लगाना।
4. मुर्गीपालन व्यवसाय की प्रबंधन व्यवस्था को सुधारना।
5. मुर्गीपालन व्यवसाय की समस्या एवं निवारण का अध्ययन करना।

शोध विश्लेषण – रीवा शहर में रतहरा (नईवस्ती) स्थिति मुर्गीपालन की स्थापना सन् 2005 में हुई। इसकी स्थापना में कुल 1,40000 (एक लाख चालीस हजार रुपये) पूंजी के रूप में लगाया गया था। इस फर्म के मालिक का नाम श्री रविनाथ पटेल है।

मुर्गीपालन कार्य मुख्य रूप से मुर्गियों का व्यवसाय किया जा रहा है उन्हें इलाहाबाद जबलपुर से लाया जाता है।.इस फर्म में देशी , व्रायलर, लेयर काकरेल, इत्यादि किस्म की मुर्गियों को पाला जाता है। उपरोक्त किस्मों में सबसे ज्यादा मुनाफा वायलर किस्म के मुर्गो में होता है। क्योंकि वायलर की प्रजाति 30–45 दिन तक में तैयार हो जाते हैं। आज के परिवेश में मुर्गो का उपयोग ज्यादातर पार्टियों में भी किया जाता है तथा यह स्पष्ट भी होता है। कि मौसम कि आधार पर मुर्गो की कीमत में भी परिवर्तन होता रहता है। वायलर मुर्गे सबसे सस्ते गर्मी के दिनों में मिलते है। गर्मी में 70 रूपये प्रति तथा ठण्डी में 90 रूपये प्रति किलोग्राम तक हों जाता है। देशी प्रजाति कि मुर्गे का मांस हर मौसम में महंगा होता है इसलिये इसका उपयोग लोग कम करते हैं इसका मूल्य गर्मी के दिनो में 180 रुपये प्रति किलोग्राम तथा ठण्डी में 200 रुपये प्रति किलोग्राम तक हो जाता है।

लागत लाभ प्रति महीना – सारणी क्रमांक – 1 **(देखे अगले पृष्ठ पर)**

सारणी विश्लेषण – सबसे ज्यादा लाभ लेयर में जो पड़ा और कम का विश्लेषण करना। सबसे ज्यादा लाभ देशी प्रजाति में होता है जो 80/प्रति कि.ग्रा. एवं सबसे कमवायलर तथा माध्य में लेयर 45/कि.ग्रा. प्रजाति में लाभ प्राप्त होता है।

समस्याएं/जोखिम –

1. प्रबंधन व्यवसाय का सही न होना।
2. व्यवसाय से संबंधित सामग्री उपलब्ध न होना।
3. वितरण व्यवसाय का सही न होना।
4. यातायात की व्यवस्था न होना।
5. स्टाक की व्यवस्था न होना।

सुझाव –

1. वायलर की चूजे की खरीददारी में ध्यान दे कि जो चूजा खरीद रहें है उनका वजन 6 सप्ताह में 3कि.ग्रा. दाना खाने कि बाद कम से कम 1.5कि.ग्रा. हो जाय तथा मृत्युदर 3प्रतिशत से ज्यादा न हो।
2. यदि अण्डे देने वाली मुर्गी अर्थात लेयर के चूजे हो तो उन्हें हैचरी से ही रानी खेती एफ का टीका तथा पहले दिन ही मेरेक्स का टीका लगाना चाहिए।

* शोधार्थी (वाणिज्य) अ0 प्र0 सि0 वि0 वि., रीवा (म.प्र.) भारत
** अतिथि शिक्षक (वाणिज्य) अ0 प्र0 सि0 वि0 वि., रीवा (म.प्र.) भारत

3. पहले सप्ताह का तापमान 90डिग्री सेल्सियस एफ होना चाहिये प्रत्येक सप्ताह 5डिग्री सेल्सियस एफ तापमान कम करते हुये 70 डिग्री सेल्सियस एफ से नीचे ले जाना चाहिए।
4. आठवें दिन से 28 दिन तक चूजे को स्टार्टर दाना दें।
5. पहले दिन जो पानी पीने के लिये चूजे को दे उसमें ओ.आर.एस. पावडर या ग्लूकोज मिलायें।
6. शुरू के दिनों में विछाली को रोजाना साफ करें।

निष्कर्ष – परियोजना के विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि मुर्गी पालन से माँस तथा अण्डे की उपयोगिता के लिये चूजों को पालने से हैं। तथा उनकों रोगों से बचाने एवं बड़ा करके उन्हें बाजार में बेचकर अधिक से अधिक लाभ कमाना है। इसके लिये हमें चूजों की अच्छी देखभाल करनी चाहिये। पालन के लिये चूजों कों (इलाहाबाद, जबलपुर, से खरीदा जाता है। मुर्गी फार्म में चूजों को लाने के बाद उन्हें शुद्ध पोषण तैयार करना होता है) एवं उनके आवास की अच्छी व्यवस्था करना होता है। ये सारी प्रक्रिया करने के बाद उसे टीके लगवाते रहना चाहिये जिससे की रोग न हों जब मुर्गा 1 या 1 कि.ग्रा. का हो जाय तो उसे बाजार में भेज देना चाहिये। जिसमें लाभ की मात्रा में वृद्धि की जा सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. विज्ञान का विकास –शिवलाल दिग्दर्शिका –शिवलाल, 20/10/11
2. शोध प्रविधि – हिमालय परबलेकेशन– हिमालयपब्लिकेशन, 20/2 /13 डॉ. सी.आर.कोठारी
3. शोध प्रविधि –एस0सचदेव – हिमालय प्रकाशन, 20/10/11
4. शोध प्रविधि– एम0के0जैन–हिमालय प्रकाशन, 20/2/13
5. www.wikipidiya.
6. google.com.

लागत लाभ प्रति महीना

सारणी क्रमांक – 1

क्रमांक	प्रजाति	खरीद मूल्य/ प्रति चूजा	लागत मूल्य/चूजा	विक्रय मूल्य प्रति कि.ग्रा.	लाभ प्रति कि.ग्रा.
1.	वायलर	21	32	70	17
2.	देशी	55	85	220	80
3.	लेयर	45	80	170	45
	Total	121रु.	197रु.	460रु.	142रु.

स्रोत साक्षात्कार

****

उद्योगों में कार्यशील पूँजी के प्रबंधन का महत्व

डॉ. सपना सोलंकी *

प्रस्तावना – प्रत्येक व्यावसायिक संस्था को दो प्रकार की पूँजी की आवष्यकता होती है–स्थिर पूँजी व कार्यशील पूँजी। व्यवसाय के संचालन में स्थायी रूप से प्रयोग हेतु कुछ सम्पत्तियों की आवश्यकता पड़ती है, जिन्हें स्थायी सम्पत्ति कहते हैं और इनमें लगाई गई पूँजी स्थायी पूँजी कहलाती है। इसके विपरीत, व्यवसाय के संचालन संबंधी दिन–प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु भी सम्पत्तियों की आवश्यकता पड़ती है, जिसे चल सम्पत्ति कहते है और इनमें लगाई गई पूँजी को कार्यशील पूँजी या चालू पूँजी कहते है।

व्यवसाय के अन्तर्गत कार्यशील पूँजी की एक पर्याप्त मात्रा अपरिहार्य होती है। व्यवसाय की आवश्यकता को ध्यान में रखकर कार्यशील पूँजी की मात्रा न तो उससे अधिक होनी चाहिए और न उससे कम। दोनों स्थितियाँ व्यवसाय के लिए हानिकारक सिद्ध होती है। परन्तु कार्यशील पूँजी की मात्रा निर्धारित करने के साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि विभिन्न चल सम्पत्तियों में विनियोग का अनुकूलतम स्तर क्या हो और उस विनियोग हेतु अल्पकालीन व दीर्घकालीन दायित्वों के बीच अनुकूलतम मिश्रण क्या हो।

अन्य शब्दों में हमें यह निर्धारित करना पड़ता है कि चल सम्पत्तियों में चल दायित्वों का मात्रा स्तर क्या होना चाहिए। इस प्रकार के निर्धारण में संस्था की तरलता और चरणों की अदायगी के संबंध में मूलभूत निर्णय शामिल होते हैं। हमें यह देखना होता है कि संस्था की तरलता की आवश्यकता क्या है और विभिन्न चल दायित्वों का भुगतान कब और किस अन्तराल पर करना है। संस्था के पास जितनी चल सम्पत्तियाँ है, उन्हें किस दर से या किस सीमा तक नगद में परिवर्तित कर सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि नगद व बिक्री योग्य प्रतिभूतियों का प्रबंध कैसे किया जा रहा है। संस्था की साख नीति एवं विधि क्या है।

कार्यशील पूँजी का अर्थ व अवधारण – पूँजी किसी भी व्यवसाय की रक्त होती है पर्याप्त पूँजी के अभाव में व्यवसाय का सुचारू संचालन असंभव होता है। उपलब्ध पूँजी का उचित संयोजन ही सभी व्यवसाय की सफलता का मुख्य आधार होता है। प्रत्येक व्यावसायिक संस्था में दो प्रकार की पूँजी की आवश्यकता होती है। पहली स्थायी पूँजी व दूसरी कार्यशील पूँजी।

स्थायी पूँजी से आशय उस पूँजी से है, जो स्थायी सम्पत्तियों जैसे–भूमि भवन, मशीन, औजार, फर्नीचर एवं फिटिंग्स आदि में विनियोजित होती है। इन सम्पत्तियों का व्यवसाय के संचालन में इनका उपयोग स्थायी रूप से किया जाता है।

कार्यशील पूँजी से आशय उपक्रम की चल सम्पत्ति में लगी अस्थायी पूँजी से है। चल सम्पत्ति में, रोकड़, कच्चा माल, अर्द्ध–निर्मित एवं निर्मित माल, कम्पनी द्वारा दिए गए अल्पकालीन ऋण, प्राप्य विपत्र, विनियोग आदि सम्मिलित है। कार्यशील पूँजी व्यवसाय की सामयिक आवश्यकताओं जैसे कच्चे माल का क्रय, कर्मचारियों के वेतन मजदूरी, दैनिक व्यय आदि में विनियोजित की जाती है।

स्थिर सम्पत्ति एवं चल सम्पत्ति में मूलभूत अन्तर यह है कि स्थिर सम्पत्ति की प्रकृति स्थायी एवं दीर्घकालीन होती है जबकि चल सम्पत्ति में व्यवसाय की सामान्य प्रगति के साथ–साथ परिवर्तन होता रहता है। स्थिर सम्पत्ति में विनियोजित पूँजी को स्थायी पूँजी व चल सम्पत्ति में विनियोजित पूँजी को चक्रशील या चल पूँजी कहा जाता है।

कार्यशील पूँजी को अल्पकालीन पूँजी तरल पूँजी, निरंतर पूँजी, चक्रशील पूँजी एवं शीघ्र पूँजी भी कहते है।

कार्यशील पूँजी के प्रकार – कार्यशील पूँजी को हम मुख्यत: दो भागों में बाँट सकते है –

1. स्थायी या नियमित या स्थिर कार्यशील पूँजी।
2. परिवर्तनशील, मौसमी या अस्थायी या विशिष्ट कार्यशील पूँजी।

कार्यशील पूँजी का महत्व – किसी भी संस्था के दैनिक कार्यों को सुचारू रूप से सम्पत्ति करने के लिए तथा संस्था की साख को बनाए रखने के लिए प्रारम्भ से ही पर्याप्त कार्यशील पूँजी की व्यवस्था करना अत्यन्त आवश्यक है। इसके अभाव में प्रबंधकों को कई प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। किसी भी व्यवसाय की सामान्य प्रगति के लिए आवश्यक है कि स्थिर सम्पत्ति के लिए आवश्यक पूँजी के साथ–साथ चल सम्पत्तियों के लिए उचित पूँजी की व्यवस्था की जाए। कच्चा माल खरीदने की व्यवस्था व ग्राहकों को उधार माल देने के लिए भी पूँजी की आवश्यकता होती है। पूँजी की यह व्यवस्था व ग्राहकों को उधार माल देने के लिए पूँजी की आवश्यकता होती है, पूँजी की यह व्यवस्था अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन दोनों प्रकार के कोषों द्वारा की जाती है।

कार्यशील पूँजी की स्थिति व्यवसाय में वैसी ही है जैसे मानव शरीर में हृदय की होती है। जिस प्रकार हृदय के दुर्बल हो जाने पर मनुष्य के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है उसी प्रकार कार्यशील पूँजी की कमी होने पर व्यवसाय भी अवनति की ओर अग्रसर होने लगता है।

कार्यशील पूँजी को प्रभावित करने वाले तत्व – कार्यशील पूँजी की मात्रा पर अनेक आन्तरिक व बाहरी घटकों का प्रभाव पड़ता है जो कि निम्नलिखित है –

- व्यवसाय की प्रकृति।
- वस्तु उत्पादन की अवधि।
- व्यवसाय का आकार।
- इनवेण्ट्री का आकार।
- परिचालन चक्र।

* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, किला मैदान, इन्दौर (म.प्र.) भारत

- क्रय की शर्तें एवं रीति।
- विक्रय की शर्तें।
- क्रय एवं विक्रय की शर्तों में संबंध।
- व्यवसाय की मौसमी प्रकृति।
- व्यवसायिक उच्चावचन।
- विकास की सामान्य दर।
- बैंकिंग संबंध।
- अन्य कारण।

कार्यशील पूँजी की कमी के परिणाम – व्यवसाय के अन्तर्गत कार्यशील पूँजी की एक पर्याप्त मात्रा अपरिहार्य होती है। व्यवसाय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कार्यशील पूँजी की मात्रा न तो उससे अधिक होनी चाहिए और न उससे कम दोनों ही स्थितियाँ व्यवसाय के लिए हानिकारक सिद्ध होती है। कार्यशील पूँजी का कुप्रबंध अथवा कार्यशील पूँजी की अपर्याप्तता व्यवसाय की असफलता का प्रमुख कारण बन सकता है। अत: कार्यशील पूँजी की कमी के परिणाम का विवेचन निम्नानुसार है –

1. रोजमर्रा के कार्यो को पूरा करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है जिसके कारण संचालनात्मक अक्षमता व अकुशलता पैदा हो सकती है।
2. जब संस्था अपनी अल्पकालीन दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ हो तो अपनी विश्वसनीयता तथा ख्याति को भी खो देती है। जिसके फलस्वरूप फर्म को कडी उधार शर्तो का सामना पड़ता है।
3. कार्यशील पूँजी की कमी के कारण साख उत्पन्न करने वाले अवसरों को प्राय: खोना पड़ता है।
4. कार्यशील पूँजी की कमी के कारण स्थायी सम्पत्तियों का पूर्ण क्षमता से उपयोग नहीं हो पाता है। इस प्रकार विनियोगों पर उचित प्रत्याय की दर प्राप्त नहीं हो पाती है।
5. फण्ड की अनुपलब्धता के कारण लाभदायक योजनाओं को क्रियान्वित करना कठिन हो जाता है जिससे विकास की मात्रा प्रभावित होती है।
6. संचालनात्मक योजनाओं का क्रियान्वयन जटिल हो जाता है और फलस्वरूप फर्म का लक्ष्य प्रापत नहीं हो पाते है।

कार्यशील पूँजी की अधिकता के परिणाम – जिस प्रकार किसी व्यवसाय में कार्यशील पूँजी की मात्रा की कमी अनेक समस्याओं को जन्म देती है उसी प्रकार कार्यशील पूँजी की अधिक मात्रा भी संस्था के लिए उचित नहीं होती है। यदि किसी संस्था में कार्यशील पूँजीआवश्यकता से अधिक हो तो उसके अनेक दुष्परिणाम होते है जिसका प्रभाव संस्था की लाभदायकता व कार्यकुशलता पर पड़ता है। अत: कार्यशील पूँजी की अधिकता के परिणाम निम्नानुसार है –

1. कार्यशील पूँजी की अधिकता प्रबंध को ऐसी निश्चितता प्रदान करती है कि अब उसे कुछ करना ही नहीं है, फलस्वरूप प्रबन्धकीय अक्षमता पैदा होने लगती है।
2. कार्यशील पूँजी की अधिकता से दोषपूर्ण साख नीति और देनदारों से वसूली में ढ़िलाई को भी प्रोत्साहित करता है जिसके कारण अशेध्य ऋण का भार बढ़ने लगता है और इसका प्रभाव लाभ पर पड़ता है।
3. कार्यशील पूँजी की अधिकता अनावश्यक रूप से स्टॉक का संचय, स्टॉक का दोषपूर्ण व गलत ढंग से उड़ाना, रखना, चोरी आदि को प्रोत्साहित करता है।
4. कार्यशील पूँजी की अधिकता सट्टे के लाभ को कमाने के लिए स्टॉक संचय की प्रवृत्ति को उत्साहित कर सकती है, जिससे उदार लाभांश नीति अपनानी पड़ती है, और जब सट्टे का लाभ नहीं होता है तो इस उदार लाभांश नीति को बनाए रखने में कठिनाईयां आने लगती है।

निष्कर्ष – उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि किसी भी संस्था में कार्यशील पूँजी की मात्रा न तो अधिक होना चाहिए और न ही आवश्यकता से कम होना चाहिए। अत: वित्तीय प्रबंधक को हमेशा कार्यशील पूँजी का उचित मात्रा सतत् रूप से बनाए रखना चाहिए तभी संस्था अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकती है।

कार्यशील पूँजीका कुप्रबंध अथवा कार्यशील पूँजी की अपर्याप्तता व्यवसाय की असफलता का प्रमुख कारण बन सकता है। कार्यशील पूँजी का प्रबंध का अभिन्न अंग होता है और अन्तत: समूचे निगम प्रबंध का भी। इस प्रकार कार्यशील पूँजी का प्रबंध एक बड़ी चुनौती खड़ी करता है और एक वित्तीय प्रबंध के लिए यह सुअवसर प्रदान करती है जिसका सही दिशा में उपयोग करके वित्तीय कुशलता व क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। कार्यशील पूँजी के प्रबंध के प्रति किसी भी प्रकार की उदासीनता करना तकनीकी दिवालियेपन की स्थिति पैदा कर सकता है और कभी–कभी व्यावसायिक इकाई का विभाजन भी हो सकता है।

कार्यशील पूँजी के प्रबंध की अक्षमता व अकुशलता के फलस्वरूप या तो कार्यशील पूँजी की अपर्याप्तता हो सकती है या कार्यशील पूँजी की अधिकता और दोनो ही स्थिति खतरनाक होती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. प्रबंधकीय लेखांकन – अग्रवाल एण्ड अग्रवाल।
2. मैनेजमेंट अकाउन्टेंसी 1963 – बेट्टी जे.।
3. प्रिंसिपल ऑफ मेनेमेंट अकाउन्टेंसी–ब्राउन एण्ड हार्बर्ट।
4. वित्तीय लेखांकन – डॉ. एस.पी. गुप्ता।
5. वित्तीय लेखांकन – डॉ. आर.एस. कुलश्रेष्ठ।

****

रीवा शहर में सिरमौर चौराहे में स्थिति फल विक्रेताओं की आर्थिक स्थिति अध्ययन

रूपेश द्विवेदी * क्रितिका सिंह **

प्रस्तावना – किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि व देशवासियों का जीवन स्तर का आकलन वहॉ के फलोत्पादन की मात्रा से किया जाता है। मानव पोषण के लिए फलों का महत्व सर्वसव्य है। ये विटामिन्स के मुख्य स्त्रोत हैं, जिनके बिना मानव शरीर की पूर्ण वृद्धि नहीं हो पाती है तथा बहुत सी बीमारियो के प्रति सुग्राही हो जाता है। फलों में अनेकों प्रकार के खनिज लवण पाये जातें है। जिसकी कमी से अनेको प्रकार की चयापचयी व्याधियॉ हो सकती है। इसके अतिरिक्त फलों में प्रोटीन और सेलुलोज भी पाया जाता है। जो कि अमाशय की क्रिया को उत्प्रेरित करता है, और मानव शरीर को अनेकों प्रकार की बीमारियों से बचाता है। बहुत से फूलों का औषधीय महत्व है। इन्हीं सभी कारणों से हमारे दैनिक आहार में फलों का बहुत ही अधिक महत्व है।

फलों में पाये जाने वाले पोषक तत्व –

विटामिन 'ए' (कैरोटीन)– कैरोटीन से विटामिन बहुत फलों में अलग अलग मात्रा में पाया जाता है जिनमें खासकर आम, पपीता, कटहल, पर्सीमोन खजूर आदि के अच्छे स्त्रोत है।

बिटामिन 'बी' –1 (थाइमिन) इसके मुख्य स्त्रोत, काजू, अखरोट, सुबानी, बादाम, केला, सेब, आडू आदि फल है।

बिटामिन 'बी' –2 (राइबोफ्लेविन) – यह बिटामिन स्वस्थ त्वचा के लिए आवश्यक है इसके मुख्य स्त्रोत् अनन्नास, बेल, लीची, अनार, पपीता, आदि फल हैं।

फल व्यवसाय – इस व्यवसाय में फल विक्रेता फलों को मण्डी से लाकर चौराहे में बिक्री करते हैं। यह मण्डी घोड़ा चौराहा में फोर्ट रोड खटकहाई बाजार के मंडी है, वहॉ लगती है, यह मंण्डी सुबह 6 से 8 और रात में 9–11 लगती है।

परिकल्पना–

- फल विक्रेताओं या फल बिक्री का कार्य अनुपयोगी कार्य है।
- फल के व्यापार से किसी चीज की उत्पादकता संभव नहीं होती।
- फल बिक्री में धन एवं समय का अपव्यय होता है।
- फल बिक्री मं किसी प्रकार का रोजगार संभव नहीं है।

शोध प्रविधि – प्रस्तुत शोध में प्राथमिक एवं द्वितीयक समंकों का संकलन किया जायेगा। समंको का वर्गीकरण, सारणीयन,एवं विश्लेषण कर वास्तविक परिणाम प्राप्त किया जायेगा।

निष्कर्ष का वास्तविकता से मिलान किया जायेगा अन्तर आने पर पुन: सर्वेक्षण करके शोध कार्य को दोहराया जायेगा।

उद्देश्य –

- फल विक्रेताओं की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।
- फल विक्रेताओं के प्रबंधन व्यवस्था का अध्ययन।
- नए उत्पादों के विकास को प्रोत्साहन देना।
- व्यापार का वैज्ञानिक अध्ययन।
- समाज में फल की उपयोगिता को बढ़ाना।

शोध विश्लेषण – रीवा शहर में फल विक्रेताओं द्वारा संचालित एक फल बिक्री प्रक्षेत्र विकसित किया गया है, यह सिरमौर चौराहे में विस्तृत रूप से फैला हुआ है।

जिसमें 70.80 फल विक्रेता है जिसमें से कुछ फल विक्रेता अपने ठेलों में फलों को बेचते हैं तो कुछ अपनी दुकानों में। ये फल विक्रेता फलों को घोड़ा चौराहा में, फोर्ट रोड में, खटकहाई, बाजार के पीछे जो मण्डी लगती है, वहीं से लातें हैं।

मण्डी सुबह 6 बजे से 8 बजे तक लगती है तथा रात में 9–11 बजे तक लगती है। इसी समय में फल विक्रेता फलों को खरीदने के लिए जाते हैं, और फिर वहॉ से कम कीमतों में फल खरीदकर सिरमौर चौराहे में लाकर अधिक कीमतों में बेंचते हैं।

ऐसा करने से फल विक्रेता को अत्याधिक लाभ मिलता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सृदृढ़ बनी रहती है।

सारणी क्रमांक –1

चौराहे में बेचे जाने वाले फलों की सारणी

1. सेब	2. लीची	3. खीरा	4. संतरा
5. बेर	6. गाजर	7. अनार	8. तरबूज
9. शहतूत	10. पपीता	11. खरबूज	12. आम
13. अंगूर	14. नाशपाती	15. केला	16. जामुन
17. अनानास फल	18. शकरकंद	19. मौसम्मी	20. स्ट्राबैरी
21. अमरूद	22. खजूर	23. चीकू	24.ककडी

स्त्रोत– प्रत्यक्ष साक्षात्कार

सारणी क्रमांक –2

वर्ष बाट फल विक्रय की स्थिति

वर्ष	बिक्री	खर्च	बचत
2010	30 लाख	0.9	4.1
2011	32 लाख	0.95	3.05
2012	35 लाख	1.07	2.93
2013	38 लाख	1.12	1.88
2014	42 लाख	1.15	2.85

स्त्रोत – व्यक्तिगत साक्षात्कार

* अतिथि शिक्षक (वाणिज्य) अ. प्र. सि. वि., रीवा (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी (वाणिज्य) अ. प्र. सि. वि., रीवा (म.प्र.) भारत

उपयुक्त सारणी से स्पष्ट है कि फल विक्रेताओं की सर्वाधिक बिक्री 2014 में हुई जो 42 लाख है। तथा दूसरे स्थान पर 2013 की रही सारणी से स्पष्ट है कि फल की बिक्री प्रतिवर्ष बढते क्रम में हैं लाभ के मामले में सर्वाधिक लाभ वर्ष 2010 में हुआ जो 4.7 लाख है, तथा सबसे कम 2013 में हुआ जो मात्र (1.88) लाख है। अर्थात् लाभ वर्ष बार घटता है।

समस्याएँ/ जोखिम – फल विक्रेताओं का व्यवसाय समस्याओं एवं जोखिम भरा हुआ है। सब कुछ ठीक रहने पर भी थोड़े समय के मौसम से अथवा सही समय पर फलों की बिक्री न कर पाने पर सम्पूर्ण व्यावसाय को अत्याधिक हानि हो जाती है।

चूँकि फल अधिक दिनों तक ताजे नहीं रह सकतें हैं, अत: उनको समय रहते बेचना अत्यन्त आवश्यक है, नहीं तो फल विक्रताओं को अधिक हानि उठानी पड़ती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है।

सुझाव – फल विक्रेता का व्यापार एक सतर्कतापूर्ण व्यवसाय है, जहॉ जोखिम की संभावना बनी रहती है, किन्तु चतुराई एवं धैर्य से सबका सामना किया जा सकता है।

समय एवं मॉग को ध्यान में रखकर हि विक्रेता मण्डियों से फल का क्रय करें अधिक क्रय से उचित समय पर विक्रय न होने पर उन्हें भारी हानि उठानी पड़ सकती है।

निष्कर्ष – फल विक्रेता का व्यापार आधुनिक युग की एक आवश्यकता है। यह स्वास्थ्य वर्धक हेतु आवश्यक है।

मनुष्यों को फलों के सेवन से विभिन्न प्रकार के प्रोटीन एवं विटामिन्स मिलतें हैं, जो उनके स्वास्थ्य को स्वस्थ बनाए रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसके हमारे जीवन में कई लाभ हैं।

इस व्यापार केा और विकसित किया जाना चाहिए और इसे रोजगार एवं लाभ को धंधा बनाया जाना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. फल एवं बागानी फसलें–डॉ राजमणि पटेल, प्रकाशक किताब महल, 22 ए0 डॉ0 राजेश प्रसाद पटेल सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।

शोध प्रविधि –

1. सी0आर0 कोठारी प्रकाशक – हिमालया पब्लिकेशकन 2013–14
समाचार पत्र– दैनिक भास्कर,दैकिन जागरण, पत्रिका समाचार।

****

मध्यप्रदेश में शक्कर उद्योग के विकास की संभावनाओं का अध्ययन

डॉ. प्रताप राव कदम *

प्रस्तावना – आज संसार में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे 'शक्कर' शब्द सुनते ही मिठास व मधुरता का अनुभव न हो। जीवन में मिठास का बहुत महत्व है। शरीर विज्ञान के अध्येता इसे शरीर के लिए अनिवार्य मानते हैं। हमारे दिन की शुरूआत सुबह चाय की प्याली से होती है। और दिनभर में अनेक शक्कर से निर्मित पदार्थों का सेवन हम करते हैं। हमारे भारतीय समाज के कुछ वर्गों में तो यह प्रथा ही है कि बालक के जन्म पर उसे सबसे पहले शक्कर की चासनी का रसा स्वादन कराया जाता है व मनुष्य जब मृत्यु शैया पर लेटा हो वे अपने जीवन की अंतिम सांसे गिर रहा हो, तब भी उसे गंगा जल के अभाव में शक्कर का पानी पिलाया जात है। शक्कर शब्द के उद्भव के संबंध में ज्ञात होता है कि संस्कृत के 'शर्करा' शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, अर्थात जिसका अर्थ होता है 'बजरी' अर्थात ठोस दानेदार पदार्थ्। कालांतर में 'र' का लोप हो गया और शकरा एवं शकर शब्द बना। समय के साथ–साथ उच्चारण में परिवर्तन हुआ और शक्कर शब्द प्रचलन में आ गया।

मध्यप्रदेश के बुराहनुपर, खरगोन, गुना एवं मुरैना क्षेत्रों के सहकारी शक्कर कारखानों ने सामुदायिक कल्याण की भावना से अपने क्षेत्रवासियों के लिए स्कूल, कॉलेज व अस्पतालों के संचालन का उल्लेखनीय कार्य किया है। इनर सहकारी कारखानों से गन्ना उत्पादकों का आर्थिक व सामाजिक उत्थान तो हुआ ही है, साथ ही साथ सार्वजनिक हित की इन कल्याणकारी गतिविधियों से अन्य क्षेत्रवासी भी लाभान्वित हुए व हो रहे हैं। यह बात गौरतलब है कि कृषि फसलें तो और भी बहुत सी हैं। उनमें से गेहूं, चावल, आलू सोयाबीन, मूंगफली, केला और कपास जैसी जिस भी हैं, जो अनेक कृषि आधारित उद्योग की जननी है। लेकिन गन्ने की भांति अतुलनीय और विशद प्रतिफल किसी अन्य फसल से किसानों को नहीं मिलता। नि:संदेह इस प्रगति यात्रा का श्रेय सहकारिता की अनुपम प्रणाली, सहकारी सोसायटियां तथा सहकारी शक्कर कारखानों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन व संचालन करने वाले संचालक मण्डलों को जाता है।

अध्ययन के उद्देश्य – संसार में मानव ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसमें सोचने, समझने एवं विचार करने की क्षमता है। मानव प्रत्येक कार्य किसी न किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए करता है। किसी भी कार्य की सफलता के लिए पूर्व निर्धारित उद्देश्य अति आवश्यक होते हैं। उद्देश्यों के अभाव में लक्ष्यों तक पहुंचने में अधिक समय व कठिनाईयॉ प्रतीत होती है। उद्देश्यों के अभाव में दिशा भ्रम भी हो सकता है। किसी भी शोध कार्य की रूपरेखा नियमित करने के पूर्व उनके उद्देश्यों को निर्धारित करना आवश्य होता है। अत: मुख्य उद्देश्य शक्कर उद्योग (विशेषत: मध्यप्रदेश में) को शोध के माध्यम से वस्तु स्थिति की जानकारी प्रदान कर प्रदेश व उद्योग की आर्थिक समृद्धि के लिए विशेष योगदान देना है, अत: शोध के प्रमुख उद्देश्य निम्न प्रकार है –'

1. मध्यप्रदेश में शक्कर उद्योग के विकास की संभावनाओं को ज्ञात करना।
2. शक्कर उद्योग की स्थापना, उत्पादन, विनिमय तथा वितरण की नीतियों का अध्ययन करना।
3. प्रस्तुत शोध का उद्देश्य यह ज्ञात करना है कि शक्कर उद्योग में क्या समस्याएं हैं ताकि इस संबंध में सुझाव दिए जा सकें।
4. शक्कर उद्योग पर शासकीय नीति एवं सरकारी नियंत्रण का प्रभाव ज्ञात करना।
5. मध्यप्रदेश के निकटवर्ती राज्य महाराष्ट्र में शक्कर उद्योग की स्थिति ज्ञात करना ताकि तुलनात्मक अध्ययन का लाभ लिया जा सके।
6. प्रस्तुत शोध प्रबंध के अध्ययन का उद्देश्य सर्वेक्षण के माध्यम से गन्ना विकास, गुणवत्ता एवं लाभदायक के बारे में जानकारी एकत्रित कर उसकी समीक्षा करना ताकि किसान इससे अधिक लाभ उठा सकें।
7. बंद कारखानों की समस्याओं को उजागर कर सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना।
8. मध्यप्रदेश के अन्य प्रमुख उद्योगों में शक्कर उद्योग का स्थान निर्धारित कर, निवेशकों, एवं उद्योगपतियों का इस ओर आकर्षण पैदा करना।

अध्ययन की परिकल्पनाएं – मध्यप्रदेश के शक्कर उद्योग के विकास की संभावनाओं का अध्ययन में अनुसंधान कार्य के लिए निम्न परिकल्पनाएँ मानी गई है–

1. मध्यप्रदेश में शक्कर उद्योग के विकास की अपार संभावनाएं विद्यमान हैं।
2. मध्यप्रदेश के शक्कर कारखानों की उत्पादन क्षमता बहुत कम है।
3. मध्यप्रदेश में शक्कर उत्पादन से प्राप्त उपोत्पाद का उचित प्रयोग नहीं हो रहा है।
4. मध्यप्रदेश में शक्कर उद्योग पर सरकारी नियंत्रण की परिस्थिति अनुकूल नहीं है।
5. मध्यप्रदेश की तुलना में महाराष्ट्र के शक्कर उद्योग की स्थिति संतोषजनक है।
6. मध्यप्रदेश में शक्कर उद्योग के पिछडेपन का मुख्य कारण गन्ना फसल की कमी है।
7. वित्तीय सुविधाओं की कमी से भी यह उद्योग प्रभावित हुआ हैं।

नवलसिंह सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, नवल नगर जिला बुरहानपुर –

इकाई परिचय – नवल नगर 2105 एवं 2137 उत्तरी अक्षांश तथा 7513 एवं 7648 पूर्वी देशांश पर सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। समुद्र तल से इनकी ऊंचाई 258.97 मीटर है। इसी नगर में नवलसिंह सहकरी शक्कर कारखाना मार्यादित स्थित है जो ब्रॉडगेज रेल्वे लाईन के असीरगढ़ रोड़ रेल्वे स्टेशन से 4 कि.मी. दूर मुंबई दिल्ली सेंट्रल रेल्वे लाईन के पास स्थित है। सड़क मार्ग से यह कारखाना बुरहानपुर खण्डवा अंतर्राज्यीय राजमार्ग क्रं. 27 पर, खण्डवा से लगभग 58 कि.मी. तथा बुरहानपुर से लगभग 11 कि.मी. की दूरी पर झिरी ग्राम के समीप स्थित है।

वास्तव में सहकारिता पर आधारित इस कारखाने की स्थापन हुत सर्वाधिक प्रयास इसके संस्थापक ठा. शिवकुमार सिंह जी ने किए थे।

* प्राध्यापक (वाणिज्य) माखनलाल चतुर्वेदी शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खंडवा (म.प्र.) भारत

1. लायसेंस की प्राप्ति –
2. भूमि एवं स्थान का चयन–
3. कारखाना भवन निर्माण –
4. विद्युत एवं जल व्यवस्था–
5. मानव संसाधन प्रबंध –

3.1 नवलसिंह सहकारी शक्कर कारखाने में विभागवार कार्यरत कर्मचारियों की स्थिति

क्रमांक	विभाग	नियमित	सीजनल	योग
1.	प्रशासकीय	90	18	108
2.	गन्ना विभाग	46	98	144
3.	इंजीनियरिंग	93	113	206
4.	मेन्युफैक्चरिंग	07	139	146
	योग	236	368	604

कर्मचारियों व कृषकों का शैक्षणिक भ्रमण –

कारखाना संचालन –

गन्ना विकास कार्यक्रम – जिसमें स्टाफिंग पैटर्न (नियुक्ति संरचना) तथा कार्य विभाजन निम्नानुसार है –

1. गन्ना प्रबंधक (विभाग प्रमुख)
2. गन्ना क्रय अधिकारी/कृषि अधिकारी
3. गन्ना विकास अधिकारी –
4. गन्ना विपणन पर्यवेक्षक –
5. गन्ना विकास पर्यवेक्षक –
6. गन्ना कृषि सहायक –
7. चिट ब्वाय (सीजनल कर्मचारी)

गन्ना विकास परियोजना –

1. गन्ना बुआई योजना – कारखाने की पेराई क्षमता अनुसार प्रति वर्ष जड़ी एवं तिरी फसल का आंकलन कर गन्ना बुआई के लक्ष्य महावार तथा किस्मवार गट/सेंटर की Potentiality के आाधार पर निर्धारित किए जाते हैं। जिससे कृषकों का गन्ना, किस्म एवं पक्कता अवधि अनुसार कृषकों द्वारा कटाई एवं परिवहन कर कारखाने को प्रदाय किया जाता है। गन्ना बुआई योजना प्रतिवर्ष तैयार की जाती है।

2. त्रि–स्तरीय बीज प्रगुणन पद्धति – कारखाने द्वारा यह पद्धति विगत चार–पांच वर्षों से संचालित की जा रही है। इसमें कारखाने द्वारा गन्ना अनुसंधान केन्द्र जैसे – वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट, पूना तथा मध्यवर्ती ऊस संशोधन केन्द्र, पाडेगॉव महाराष्ट्र से प्रजनक बीज/टिश्यू कल्चर के पौधे क्रय कर कारखाना स्थित गन्ना नर्सरी में बुआई की जाती है

3. पॉली बैग सीडलिंग योजना – कारखाना परिसर में स्थित नम गर्म हवा संयंत्र द्वारा गन्ना बीज उपचारित कर पॉली बैग हाऊस में पॉली बैग सीडलिंग पद्धति से उन्नत किस्म के पौधे तैयार कर कारखाना क्षेत्र के उन्नतशील कृषकों को बीज उत्पादन हेतु उपलब्ध कराए जाते हैं।

4. जैविक कीट नियंत्रण कार्यक्रम – कारखाना क्षेत्र के गन्ना उत्पादक कृषकों की गन्ना फसल पर लगने वाले कीट जैसे– पायरिला एवं सफेद मक्खी (White Fly) के नियंत्रण हेतु जैविक कीट नियंत्रण प्रक्रिया के तहत परजीवी कीट क्रमश: एपीपायराप्स तथा क्रायसोपर्ला कॉर्निया परजीवी कीट कृषकों की कीट–ग्रसित गन्ना फसल पर लाकर छोडे ज़ाते है।

5. भ्रमण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम – कारखाना समय–समय पर कारखाना क्षेत्र के उन्नत गन्ना उत्पादक कृषकों को प्रशिक्षण हेतु वंसत दादा शुगर इंस्टीट्यूट, पूना एवं अन्य गन्ना अनुसंधान केन्द्रों के अवलोकन हेतु भी कृषकों को भ्रमण कराने की व्यवस्था कारखाने द्वारा की जाती है।

6. जैविक खाद उत्पादन तथा विक्रय – कारखाने द्वारा माह मार्च 2007 में जैविक खाद निर्माण इकाई स्थापित की गई है जिसमें वर्तमान में एजोटो वेक्टर, पी.एस.बी. एवं डी– कम्पोजिंग कल्चर का उत्पादन कर कृषकों को ऋण पर उपलब्ध कराया जाता है।

बायोअर्थ (सेन्द्रिय खाद) निर्माण इकाई – वर्ष 200—08 में कारखाने द्वारा बायोअर्थ निर्माण इकाई भी शुरू की गई है। इसमें कारखाने के उप–उत्पाद प्रेसमड से सेन्द्रिय खाद का निर्माण कर क्षेत्र के कृषकों को ऋण पर प्रदाय किया जाता है।

मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला – मध्यप्रदेश के शक्कर कारखानों में एकमात्र नवलसिंह सहकारी शक्कर कारखाना द्वारा मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला का संचालन मानक स्तर एवं न्यूनतम शुल्क पर किया जा रहा है।

'आपका कारखाना आपके द्वार' कार्यक्रम का आयोजन – कारखाना 'आपका कारखाना आपके द्वार' कार्यक्रम आयोजित करता है। इसमें कारखाने के अध्यक्ष एवं संचालक सदस्य क्षेत्र के कृषकों की समस्या के समाधान हेतु तथा उनके सुझाव जानने हेतु कृषकों से रूबरू होते हैं तथा कारखाने की वस्तु स्थिति तथा संचालित की जा रही गतिविधियों से कृषकों को अवगत कराते हैं। इसके लिए ग्रामों में संगोष्ठी आयोजित की जाती है। इन्ही संगोष्ठियों के माध्यम से कृषक एवं प्रबंधन के विचारों का आदान–प्रदान होता है।

जवाहरलाल नेहरू सहकारी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्रोसेसिंग सोसायटी लिमि. खरगोन (शक्कर इकाई)

इकाई परिचय – निमाड़ में गन्ना उत्पादक किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने तथा गन्ना उत्पादक किसानों को निजी मिल मालिकों के शोषण से मुक्ति मिल सके इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर 2055 मै.टन प्रतिदिन पेराई क्षमता के सहकारी शक्कर कारखाने की स्थापना की आधारशिला दिनांक 02 अगस्त, 1998 को कसरावद तहसील के ग्राम सखर देवला में रखी गई।

1. लाइसेंस प्राप्ति –
2. भूमि एवं स्थान का चयन –
3. कारखाना भवन निर्माण –
4. विद्युत एवं जल व्यवस्था –
5. मानव संसाधन प्रबंध –

जवाहरलाल नेहरू सहकारी शक्कर कारखाने में कार्यरत कर्मचारियों की स्थिति

क्रमांक	विभाग	नियमित	सीजनल	योग
1.	प्रशासकीय	93	27	120
2.	गन्ना विभाग	53	96	149
3.	इंजीनियरिंग	82	105	187
4.	मेन्युफैक्चरिंग	09	117	126
	योग	237	345	582

कारखाना संचालन – मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अंतर्गत संचालित यह कारखाना प्रतिवर्ष निर्वाचन द्वारा 'संचालक मण्डल' का गठन करता है।

संचालक मण्डल के अंतर्गत, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं अन्य संस्थाओं में भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों का निर्वाचन संपन्न किया जाता है।

कृषि उपज मण्डी करहिया (रीवा) की कार्यालयीन एवं समग्र प्रबन्ध प्रणाली का अध्ययन

क्रितिका सिंह* रूपेश द्विवेदी**

प्रस्तावना – देश के विकास के लिए कृषि उपज मण्डी का अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। यह एक ऐसी विपणन संस्था है जहाँ कृषि उत्पाद के क्रय भण्डारण तथा विक्रय की व्यवस्था की जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वापूर्ण स्थान है; हमारे राष्ट्रीय आय का एक बड़ा भाग कृषि उत्पाद से पूरा होता है।

अनाज की पैदावार में वृद्धि कर भारत के अर्थव्यवस्था में सुधार लाना देश की जनसंख्या की खाद्य व्यवस्था को पूरा करने में तथा किसानो को पूरा करने में तथा किसानो को प्रोत्साहन देने में कृषि उपज मण्डी की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात किए गये सुधारो में कृषि को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।

परिकल्पना–

1. कृषि उपज मंण्डी कार्य अनुपयोगी कार्य है।
2. कृषि उपज मण्डी से किसी चीज की उत्पादकता से नहीं है।
3. कृषि उपज मण्डी में धन एवं समय का अपव्यय होता है।
4. कृषि उपज मंण्डी में अधिक रोजगार संभव नहीं है।

शोध प्रविधि – समंको का संकलन प्राथमिक एवं द्वितीयक विधि से किया जायेगा तथा आकड़ो के समुचित वर्गीकरण के पश्चात सारणीयन में दर्शाया जायेगा। सारणीयन का विश्लेषण कर आवश्यक परिणाम प्राप्त किये जायेगे व अवलोकन विधि द्वारा भी आकड़ो का सग्रहण एवं अध्ययन किया जायेगा तत्पश्चात निष्कर्ष का वास्तविकता से मिलान किया जायेगा;यदि परिणाम वास्तविकता से मेल नहीं खाते तो शोध को दोहराया जायेगा।

उद्देश्य–

1. कृषि उपज मंडी क्षेत्र का विस्तृत अध्ययन करना।
2. कृषि उपज मंडी में नये–नये उत्पादो के क्रय–विक्रय की व्यवस्था करना।
3. कृषि उपज मंडी को अधिक विकसित एवं जनोपयोगी बनाना।
4. कृषि उपज मंडी में रोजगार अवसरो को तलाशना।
5. कृषि उपज मंडी द्वारा कृषक समाज का कल्याण करना ।

शोध विश्लेषण–'कृषि उपज मंडी समिति रीवा' के नाम से रीवा शहर के पश्चिमोत्तर रीवा से 7 कि0मी0 दूर रीवा सेमरिया मार्ग के बगल में 1 जून 1967 में स्थापित की गई तथा इसकी श्रेणी'ब'वर्ग की है।

इसका कार्य क्षेत्र –तहसील हुजूर(रीवा),रायपुर कर्चुलियान (रीवा), विकास खण्ड हुजूर रीवा,

इस मंडी के क्षेत्र म्रें दोनों तहसीलों को मिलाकर कुल 548 गॉव सम्मिलित है तथा कुल ग्राम पंचायते 193 है।

इस मंण्डी कें अन्तर्गत दो नगर पंचायतें गुढ़ एवं गोविन्दगढ़ तथा एक नगर निगम रीवा आता है।

नवीन प्रांगण की स्थापना – 38.78एकड़ भूमि मे फैली नवीन मण्ड़ी प्रागण की स्थापना 29 जुलाई2001 को की गई थी।

कृषि उपज मण्डी समिति रीवा की प्रबंध व्यवस्था सहकारिता के सिध्दान्तो पर आधरित है।मंडी का अध्यक्ष पद अनु0जनजाति हेतु आरक्षित है, समिति का गठन अध्यक्ष कृषक सदस्य,व्यापारी सदस्य तथा तुलैया सदस्य,बिधायक प्रतिनिधि व एक जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष का है।

कृषि उपज मण्डी की प्रबंध व्यवस्था सुचारु रुप से की गयी है, मण्डी प्रांगण मे लेखाकन से लेकर अनेक प्रकार की व्यवस्था सम्मिलित की गयी हैं। प्रबंध व्यवस्था के आधार पर जो भी नियम बनाये जाते हैं, वह सभी मण्डी के कर्मचारी के लिए समान रुप से होते हैं।

कृषि उपज मण्डी का संगठन –

क्र.	नाम एवं पद	संख्या
1.	अध्यक्ष	01
2.	उपाध्यक्ष	01
3.	कृषक सदस्य	08
4.	व्यापरिक सदस्य	01
5.	तुलैया सदस्य इस्माल सदस्य	01
6.	विधायक प्रतिनिधि	01
7.	सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी	02
8.	रीवा शासकीय प्रतिनिधि	01
9.	अध्यक्ष जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैक रीवा बैंक प्रतिनिधि –	01

व्यापरियो को अनुज्ञप्ति स्वीकृत करना

अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन के साथ न्यूनतम निम्न दर से फीस जमा की जाती है–

1.	व्यापारी	100रू.मात्र
2.	परिवहनकर्ता	800रू.मात्र
3.	दलाल	800रू.मात्र
4.	तुलैया	500रू.मात्र
5.	हम्माल	200रू.मात्र

विश्लेषण

* शोधार्थी (वाणिज्य) अ0 प्र0 सि0 वि. वि., रीवा (म.प्र.) भारत
** अतिथि शिक्षक (वाणिज्य) अ0 प्र0 सि0 वि. वि., रीवा (म.प्र.) भारत

उपयुक्त सारणी से स्पष्ट है कि व्यापारी को 1000रू.परिवहनकर्ता एवं दलाल दोंनो को 800रू.तुलैया को 500रू.और सबसे कम राशि हम्माल को। इस प्रकार फीस निर्धारित मापदण्डो को ध्यान रखकर जमा की जाती है।

समस्याएँ/जोखिम – कृषि उपज मण्डी का कार्य विभिन्न प्रकार की समस्याओ एवं जोखिम से भरा हुआ है।सब कुछ ठीक रहने पर भी थोड़े समय के खराब मौसम से व्यवसाय को काफी नुकसान पहुँचता है। मण्डी के कार्यालय की सुरक्षा हेतु सी.सी.टी कैमरे का न होना, मण्डी के अनुज्ञाधिकारी व्यापारियो के लिए भण्डारण के लिए उचित गोदाम की व्यवस्था न होना,एडी प्रॉगण में निकासी के दौरान व्यापारियों की सुविधा के लिए इलेक्ट्रॉनिक तौल कांआ (धर्मकाटा) की व्यवस्था का न हो। इसके अलावा किसानो के रूकने के लिए विश्राम गृह का न होना,अनुज्ञाधिकारी व्यापारियो के भुगतान को जटिल बनाने हेंतु राष्ट्रीयकृत बैंक का न होना,आदि का जोखिम सदैव बना रहता है।

सुझाव।

1. मण्डी प्रांगण में किसानो के लिए उचित कैटीन की व्यवस्था होनी चाहिए।
2. किसानो को रूकने के लिए विश्राम गृह की व्यवस्था होनी चाहिए।
3. मण्डी के अनुज्ञाधिकारी व्यापारियो के लिए ओर भण्डारण के लिए गोदामो की व्यवस्था करनी चाहिए।
4. विशेषत: अनुज्ञाधिकारी व्यापारियों की व्यवस्था को सरल बनाने हेतु व मण्ड़ी प्रांगण में राष्ट्रीय कृत बैंक को स्थापित किया जाना चाहिए।
5. कार्यालय 'व ' मण्डी प्रांगण में सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से cctv कैमरे को लगाया जाना चाहिए ,साथ ही सुरक्षा गार्ड की भी व्यवस्था होनी चाहिए।

निष्कर्ष– कृषि उपज मण्डी से सम्बन्धित विभिन्न तक्ष्यों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि कृषि उपज के विपणन के लिए ये मण्डियाँ अत्यधिक उपयोगी व्यवस्था है।

यद्यपि आर्थिक लाभ की दृष्टि से इनके लाभ सीमित है, किन्तु किसानों की स्थानीय स्तर पर विपणन सुविधा एवं उचित मूल्य दिलाकर निश्चय ही से सराहनीय कार्य कर रही है।

नवाचारों के समावेश के साथ इसकी कार्यकुशलता में निरंतर सुधार आ रहा है, भविष्य में इनके कृषक हित में अधिक उपयोगी होने की आशा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

कृषि विपणन –

1. कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 प्रकाशन – म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल
2. म0प्र0 कृषि विपणन बोर्ड अधि.सन् 2000, प्रकाशन – जनरल

सांख्यिकी के सिद्धान्त –

1. डॉ0 एस0एम0 शुक्ल, प्रकाशन – साहित्य भवन पब्लिकेशन् 2010

शोध प्रविधि – 1. सी0आर0 कोठारी, प्रकाशन – हिमालय पब्लिकेशन 2010–11

****

प्रबंध में कर्मचारी सहभागिता

डॉ. दिनेश कुमार चौधरी *

शोध सारांश – कर्मचारियों की सहभागिता के क्षेत्र में यह नवीनतम तकनीक है। यह प्रणाली ऐसी किसी भी कम्पनी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा लागू की जा सकती है जिसके शेयर देश के प्रमुख शेयर बाजारों की सूची में हो। वास्तव में, यह एक प्रकार का प्रोत्साहन योजना है। अमेरिका में यह बहुत प्रचलित है। भारत में यह अनेक बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में लागू है। अनेक सॉफ्टवेयर कम्पनियाँ इस प्रोत्साहन प्रणाली का प्रयोग करती है। इस योजना को शुरू करने का मूल उद्देश्य कर्मचारियों द्वारा जब–तब कम्पनियाँ बदलने की प्रवृत्ति पर अंकुष लगाना है जो कि सॉफ्टवेयर उद्योग में बहुतायत से विद्यमान है।

शब्द कुंजी –अभिसार, सांविधि, आरोही, साहचर्य, संचरण, प्रवर्तक कोटा, अभिमान्य निर्गम ।

प्रस्तावना – संगठन लोगों(कर्मचारियों) के माध्यम से ही अपनी लक्ष्य–प्राप्ति के लिये संघर्ष करता है। उन्हीं के माध्यम से परिणाम प्राप्त होते है इसलिए वे प्रबंधन–प्रक्रिया में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण और सार्थक भूमिका निबाहते है। प्रत्येक संगठन अनिवार्यत: ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिसे मोटे तौर पर दो भागों में बांटा जा सकता है (क) कर्मचारी व प्रचालक तथा (ख) पर्यवेक्षी व प्रबंधक अर्थात प्रबंधन। हमने यह भी देखा कि द्वंद्वों और परिवादों का कारण भी मूलत: इन्हीं दो समूहों के हितो के टकराव में निहित रहता है। सामंजस्य को बनाये रखने और परिवादों व द्वंद्वो के समाधान हेतु बहुत शक्ति और श्रम की बरबादी होती हैं यदि कर्मचारियों के मन में यह भावना बिठा दी जाये कि संगठन का लक्ष्य वास्तव में उन्हीं का लक्ष्य है तो हितों के टकराव को भारी मात्रा में न्यूनतम किया जा सकता है यह लक्ष्यों का अभिसार और एकाकार होना है। यह अनुभूति संगठन और कर्मचारियों को प्रभावित करने वाले मामलों में कर्मचारियों को निर्णय लेने देना, यद्यपि मूल रूप से यह केवल प्रबंधन का ही विशेषधिकार माना जाता रहा है।

उद्देश्य –

- प्रबंधन में कर्मचारी की सहभागिता क्या है
- सहभागिता की पद्धतियाँ जानना
- इस सम्बन्ध में भारतीय बैंकों के अनुभव का मूल्याकंन करना।
- प्रबंधन–प्रणाली में कर्मचारियों की सहभागिता के लाभों को परखना।

शोध प्रविधि एवं क्षेत्र– प्रस्तुत शोध पत्र में प्राथमिक एवं द्वितीयक संमको का प्रयोग किया गया है शोध आंकड़ो हेतु बैंकिग क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारी संगठनों के अधिकारीयों एवं कर्मचारियों से मौखिक साक्षात्कार विधि एवं प्रश्नावली भरवाकर आंकड़ो का एकत्रिकरण किया गया है शोध पत्र क्षेत्र बैंकिग व्यवसाय से जुड़े बैंको तक ही रखा गया है।

शोध व्याख्या – सहभागिता क्या है –

प्रबंधन के लिये इसका अर्थ निर्णय से पूर्व परामर्श लेने तक सीमित है, जबकि कर्मचारियों के लिये इसका अर्थ है संयुक्त रूप से निर्णय लेना, और सरकार के लिये चाहे किसी भी पारित संविधि से या अपनाई गई संहिता से इसका अर्थ है निर्णय लेने के लिए कर्मचारियों का प्रबंधन के साथ बिना अधिकार या दायित्व के शामिल होना। स्पष्ट है कि ये सभी अवधारणायें सम्बद्ध पक्षों द्वारा अपने–अपने हितों को प्रमुखता देने के रवैये के कारण बनी हैं। अपने वास्तविक भावार्थ में सभी पक्षों के लिये–विशेषकर प्रबंधन और कर्मचारियों के लिये सहभागिता का अर्थ एक ऐसा संयुक्त निर्णय होना चाहिये जिसका दायित्व भी संयुक्त रूप से निभाया जाये और उस निर्णय को कार्यान्वित करने का कर्तव्य भी। परन्तु एक ऐसी आदर्श स्थिति तभी संभव है जब प्रबंधन और कर्मचारियों दोनों की पारस्परिक सूझ–बूझ जहां उदारता और आपसी विश्वास का वातावरण हो तथा साथ उस संगठन में कर्मचारियों के विभिन्न वर्ग या श्रमिक संघ न हो परंतु आदर्श स्थिति और वास्तविक स्थिति इन दोनों के बीच बहुत फासला रहता है। अवधारणाओं में अंतर के बावजूद यह स्वीकार कर लिया गया है। कि सहभागिता संगठन की सर्वसमावेशी समक्षमता को बेहतर बनाने में कर्मचारियों को सहायता देती है। व्यवहार में सहभागिता का स्तर निम्नानुसार क्रमबद्ध किया जा सकता है।

- **सूचनाप्रद सहभागिता–** यह मूलत: तुलन पत्र उत्पादन कार्यक्रमों आदि से सम्बधित सूचनाओं में सहभागिता के संदर्भ में है।
- **परामर्शी सहभागिता–** इसमें एक संयुक्त परिषद का गठन किया जाता है जो कल्याण कार्यक्रमों, सुरक्षा पद्धतियों आदि मामलों में विचार–विमर्श करती हैं तथापि इसमें निर्णय लेने का अधिकार प्रबंधन के पास सुरक्षित रहता है।
- **सहचारी सहभागिता–** इसमें संयुक्त परिषद की भूमिका एक सलाहकार समिति के रूप तक सीमित नहीं रहती कुछ निषिध क्षेत्रों में परिषद की संस्तुतियाँ प्रबंधन द्वारा कार्यान्वित भी की जाती है।
- **प्रशासनिक सहभागिता–**इसमें परिषद के समक्ष कार्यान्वयन के लिए निर्णय (कुछ विकल्पों के साथ) चयन हेतु आते है। यद्यपि इसमें निर्णय लेने कि प्रक्रिया कोई भागीदारी नहीं होती है तथापि कुछ विकल्पों में से चयन करने की स्वंत्रता होती है और संयुक्त रूप से चयनित विकल्प कार्यान्वयन के लिये स्वीकृत कर लिया जाता है।
- **निणर्यात्मक सहभागिता–** इसमें उत्पादन व कल्याण आदि मामलों के सम्बध में संयुक्त रूप से निर्णय लिये जाते है।

कर्मचारियों की सहभागिता का प्रयोजन/लाभ – सहभागिता के माध्यम से कार्यस्थल पर 'हम' और 'वे' की विरोधात्मक भावना के बजाय केवल 'हम' की संबध मय भावना का अभ्युद्य होता है इससे कर्मचारियों के उत्प्रेरित करने में और संगठन की कार्य–क्षमता को बढ़ाने में सहायता मिलती है। लिये

* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय राजमाता सिंधिया कन्या महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा (म.प्र.) भारत

गये निर्णय में 'कर्ता' का भाव आने के कारण संसाधनों का सर्वाधिक सदुपयोग भी सुनिश्चित हो जाता है।

- विरोध या प्रतिरोध का स्तर तथा परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध न्यूनतम हो जाता है। परिवर्तन प्राय: परिवर्धन का प्रतीक होता है और परिवर्तन को स्वीकार करने की सदिच्छा संगठन को नई पद्धितियाँ सरलतापूर्वक अपनाने में सहायक होती है।
- इसमें सम्प्रेषण में निश्चित रूप में मुक्तता आती हैऔर आरोही सम्प्रेषण का मार्ग प्रशस्त होता है। यही स्थिति सम्प्रेषण की विकृति या विफलता को कम करने और इसके परिणामस्वरूप निर्णयों के कार्यान्वयन में सहायक होती है।
- संयुक्त निर्णय द्वंद्धात्मक स्थितियों को दूर करते है और विवादों को भी। फलस्वरूप, इकाई की उत्पादकता में अभिवृद्धि होती है।

बोर्ड में कर्मचारियों की सहभागिता –प्रबंधन में एक निर्णयात्मक स्तर पर कर्मचारियों की सहभागिता का उल्लेखनीय प्रयास उनके प्रतिनिधि को कंपनी के निर्देशक मंडल के लिए मनोनीत करना है, वर्ष 1965 में कभी सहभागिता के इस स्वरूप को प्रमुख रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उपक्रमों में एक प्रयोग की तरह लाया गया। जैसे एच.एम.टी.एल.आई.सी.और बैंक। इस योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा कर्मचारी–संघ के एक प्रतिनिधि को निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है। वह बोर्ड की सभी बैठकों में भाग लेता है और बोर्ड के किसी भी अन्य निदेशक की भांति पूर्ण अधिकार सम्पन्न होता है। यह एक नवोन्मेशी और प्रशंसनीय विचार है। इससे उच्चतम स्तर पर कर्मचारियों की सहभागिता सुनिश्चित हो जाती है। इस दृष्टिकोण के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया का अनुभव करते हुए सरकार ने इस अवधारणा को अन्य क्षेत्रों में भी प्रयोग किया–विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र कि बैंकों में और निदेशक मंडल में अधिकारियों के प्रतिनिधि को नियुक्त करते हुए उसे भी अन्य निदेशकों के समान ही प्रतिष्ठा व अधिकार दिये।

सामान्यतया, अधिकांश संघों के प्रतिनिधियों यह नियुक्ति प्राप्त हो जाती हैं। परन्तु संघों की बहुलता के कारण यह नियुक्ति तब विरोध और विवााद का विषय बन जाती है जब कोई दूसरा संघ इस नियुक्ति को चुनौती देता है तथा सदस्य संख्या की सत्यापन प्रक्रिया को भी चुनौती देता है। कुछ मामलों में यह विषय अधिनिर्णय के लिये न्यायालय तक पहुचंता है।

निष्कर्ष – सहभागिता का अर्थ क्या है और उसके विभिन्न स्तर कौन से है। हमने उन कारणों का भी अध्ययन किया कि क्यों भारत में यह प्रयोग बहुत सफल नहीं रहे हैं। अन्तत: इस क्षेत्र में बैंकिंग उद्योग के अनुभवों का हमने अध्ययन किया। अन्तिम विश्लेषण में हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि प्रबंधन और कर्मचारी दोनों ही के दृष्टिकोण और दिशा में अनुकूल परिवर्तन की आवश्यकता है जिससे सहभागिता कार्यक्रम सफल हो सके।

प्रबंधन को यह समझने की आवश्यकता है कि कर्मचारियों के लक्ष्यों और संगठन के लक्ष्यों को एकाकार होना ही होगा जिससे संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। यदि प्रबंधन यह समझ ले और स्वीकार कर ले कि परिणाम लोगों (कर्मचारियों) के माध्यम से ही प्राप्त किये जाते है, तो वह इकाई के प्रशासन में और दिन–प्रतिदिन के कार्यो में निर्णय लेने में कर्मचारियों को शामिल करने के प्रति अधिक उन्मुख हो जायेगा।

कर्मचारियों और संघों को भी यह समझने की आवश्यकता है कि यह कर्मचारियों के हित में है। कि उनकी इकाई समुचित रूप से कार्य करती रहे, इसके क्षमता स्तर उंचे रहें और इसका उत्पादन अपनी अधिकतमक सीमा को छू ता रहे। छोटे–मोटे मुद्दों में ही उलझें रहने के बजाय इन्हें इन से ऊपर उठकर अपनी इकाई की प्रगति में तन–मन से योगदान करना चाहिये। उन्हें इस तत्य का बोध हो जाना चाहिये कि संगठन की अभिवृद्धि निहित है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. आर्थिक एवं साख्यिकी संचनालय मध्यप्रदेश सरकार की वार्षिक रिर्पोट 2009–2010
2. दैनिक भास्कर समाचार पत्र जबलपुर संस्करण दिनांक 10 एवं 11 अक्टूबर 2010
3. योजना सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार जून 2010
4. मानव संसाधन विकास मंत्रालय बैंकिग शाखा वार्षिक रिर्पोट 2012
5. शर्मा एच के (2005) प्रथम सर्वे भाग एक नई दिल्ली एनसीईआरटी, एच आर टी।

****

Make In India - A Ray Of Hope For India Economy

Dr. R. P. Saharia *

Abstract - "Make in India" campaign is launched with an aim of making India a manufacturing hub, and the government is putting all efforts for ensuring a smooth sailing for investors and the business environment friendly, by setting up a dedicated cell of experts to answer queries of business entities within 72 hours. It attempts to encourage higher inflow of FDI in the country and improve services by partial privatization and disinvestment of loss-making government firms. This initiative is being considered as the major decision by many economic experts since LPG (Liberalization, Privatization, and Globalization) was introduced in the beginning of the 1990's. The main aim of this campaign is to bring overall development across various sectors in India like Infrastructure, Power Sector, Banking, Oil and Gas, Metals and Mining etc. This campaign may impact the Indian manufacturing sector positively. The Prime Minister Narendra Modi has emphasized the policy of zero effect which would leave a positive impact on Global manufacturers. This will lead the economy and the markets effectively in the desired manner and further it will help in boosting growth, in job creation and revival of investment cycle in Asia's third largest economy. This campaign will be unwontedly seen as healthy response to counter China's 'Made in china' campaign. This paper will emphasize the various dimensions of the campaign "Make in India" and its impact on various sectors of the economy and how ultimately this initiative will bring changes in the lives of common man of India.

Introduction - The main objective of 'Make in India' campaign is to consider it as a major national program designed to enhance skill development, facilitate investment, foster innovation, protect intellectual property and highly advanced manufacturing infrastructure. Seeking to make India a global manufacturing hub, Prime Minister Narendra Modi launched the ambitious 'Make in India' campaign in the presence of global and domestic industrialists on 25-September-2014. This 'Make in India' campaign may attract foreign multinationals to build their manufacturing units in India itself and will impact the Indian manufacturing sector positively. 'Make in India' or 'Invest India' campaign will be the first initiative to attract foreign investors. It will act as a guide which would provide help on regulatory and policy issues, and assist in obtaining regulatory clearances.

India is well-known for its workforce that makes it as world largest exporter of services, but many doubt its ability to produce and export manufactures and that is the perception which our Prime Minister Modi wants to change. For making his own initiative possible on practical grounds, Prime Minister Modi rolled out a red carpet to industrialists, both domestic and international, inviting them to make investment through FBI's (Foreign Direct investments) and purposefully makingIndia a manufacturing hub that will boost Indian economy and jobs opportunities in India. The campaign is backed by full proof planning of dedicated cabinet ministers and bureaucrats and the government is pulling out all the steps for ensuring a smooth sailing for investors, by setting up a dedicated cell to answer queries of business entities within 72 hours. All this steps will give positive effects and help economy to grow. It will help in boosting growth, in job creation and revival of investment cycle in Asia's third largest economy.

The government will select domestic companies having leadership in innovation and new technology. The idea is to turn these into global champions and promote green and advanced manufacturing and help these companies to integrate into global value chain. The once booming services sector has slowed, but it is the manufacturing sector that has performed especially poorly by recording an expansion of barely 1.1 percent growth in 2012-13 followed by the contraction of 0.7 percent in 2013-14 India's Make in India campaign has been positioned in such a way that will be unwontedly compared with China's 'Made in China' campaign. The World's fastest growing economy launched the campaign at the same day as India seeking to develop its image as "Manufacturing hub". India should constantly upgrade its technology and enhance its strength so as to surpass China's supremacy in the manufacturing sector.

The government has started taking all possible steps to lure global investors and has been very particular about issuing strict guidelines to all ministries asking them to give preference to domestically manufactured electronic products, a move aimed at boosting electronics production to bolster the "Make in India" drive. All government departments have been instructed to follow a tender template already issued by the department of electronics and information technology, for acquirement of electronic items. This will boost the sales of domestically manufactured items which will ultimately foster the Indian economy.

* H.O.D. (Economics) Govt. J.M.P. College,Takhatpur, Bilaspur (C.G.) INDIA

FDI and Economic Growth in India - Bearing in mind the national interests, policy makers designed the policy of FDI as a means to acquire advanced technologies and mobilize foreign exchange. In the critical face of the Indian economy, the Government of India with the help of the World Bank and IMF introduced the macroeconomic stabilization and structural adjustment program. As the result of this reform India opened its doors for FDI inflows and adopted a more liberal foreign policy in order to restore the confidence of foreign investors. According to GYANPRATHA- ACCMAN Journal of Management, Volume 5, Number 1.2013) FDI for 2009-10 at US $ 25.88 billion was less than 5 per cent from US $ 27.33 billion in the previous fiscal. Foreign direct investment in August plunged by about 60 percent to approx. $ 34 billion, the lowest in the data of the Ministry of Industry in fiscal 2010 released published showed, In 2013, the government standards of FDI in several sectors, including telecommunications, defense, PSU oil refineries, power exchanges, and exchanges of shares among others. In detail, TESCO in the UK presented its application to initially invest $ 110 million to launch a chain of supermarkets in collaboration with Trent, an initiative of TATA group. In civil aviation, Malaysia-based Ah* Asia and Singapore Airlines have teamed up with the Tata Group to launch two new airlines services. Also, Abu Dhabi Etihad picked up a stake of 24 percent in Jet Airways which was worth over Rs 2,000 crore (US $319.39 million).

India has received total foreign investment of US$306.88 billion since 2000 with 94 percent of the amount coming during the last nine years. During FY 2012-13, India attracted FDI worth US$ 22.42 billion. Tourism, Pharmaceuticals, services, chemicals and construction were among the biggest beneficiaries. The January-November period in 2013 witnessed mergers and acquisitions deals worth US $ 26.76 billion in India, according to a survey by tax advisory firm Grant ?, Thronton

Major Economic Reforms - The economy of India had undergone significant policy shifts in the beginning of the 1990s. This model of economic reforms is commonly known as the LPG model or Liberalization, Privatization and Globalization model. The primary objective of this model was to make the economy of India as the fastest developing economy on the globe with capabilities that helps it match up with the biggest economies of the world. The chain of reforms that took place with regards to business, manufacturing, and financial services industries targeted at lifting the economy of the country to a more proficient level. These economic reforms had influenced the overall economic growth of the country hi a significant manner.

Effects of 'Make in India' Campaign on the IndianEconomy -

1. Encouraging foreign investors - Investment by both international and domestic companies has decreased in recent years. While foreign direct investment has pushed up in 2013, sentiment was largely skeptical. Some of the measures taken by India in recent years have been seen to be hostile to foreign companies. A bitter tax row with Vodafone and policies flip flops made investors worried. The Union Cabinet has approved FDI proposals in the areas of defense and railways. In defense, the investment cap was increased from 26 to 49 percent, while in the railway sector, some projects were allowed 100 percent FDI. Considered to be the first major economic reform by the new government NDA, the Committee of Economic Affairs Office (CCEA) approved an increase in foreign direct investment (FDI) cap in insurance from 26 percent to 49 percent. This will ensure more capital in the insurance sector. Even the investment cap is raised to 49 percent; the complete management control will remain with the Indian entity.

2. GDP on the rise - The Indian economy grew at its fastest pace in more than two years during the April-June quarter, revitalized by a decisive political mandate for the Narendra Modi-led BJP and subsequent actions by his government, suggesting that growth can be lasted long. India's GDP grew at 5.7% in the first quarter of 2014-15, exceeding expectations. This was the fastest pace since the fourth quarter of fiscal 12, while being considerably higher than the 4.6% increase in the previous quarter. Both the IMF and the World Bank see India's growth may reach 7.5 percent in 2015 from 7.2 percent the previous year, but assessments for 2016. IMF, which last January 2015 forecast a growth of 6.3 percent in 2016 and growth of 6.5 percent, penciled in 7.5 percent growth next year while the World Bank in 2016 the figure above 7.9percent . The bank last January hook the 6.4 percent growth rate this year and 7 percent in 2016, The Centre had budgeted growth of 8.1-8.5 percent of GDP in the year to end March here 2016.

3. Inflation on a low-down - The inflation rate in India was recorded at 7.96 percent in July 2014. Inflation rate in India averaged 9.49 percent from 2012 to 2014, reaching a record of all time 11.16 percent in November 2013 and a record low of 7.31 percent in June 2014.

4. Sensex on all time high - Investors have experienced a bullish trend in the Indian stock market since the day it was announced that Mr Narendra Modi would be the BJP led NDA's prime ministerial candidate. After the Loksabha poll results, Sensex expanded gains for the sixth straight session and also gained for the seventh straight month, rising the most in May, after the Modi-led NDA government took charge and announced a slew of initiates that helped improve business sentiment and lifted the economy back on the growth track. Both the benchmark share indices gained record closing highs.The 30-share Sensex reached at 30,000 mark after hitting a fresh infra-day high on March 4, 2015. For the nine months since March 2014, the benchmark index surged nearly 37%. Tracking the momentum, the 50-share Nifty index also breached 9,100 levels for the first time.

5. Announcement of Good and Services Tax (GST) - GST will result in a change in the tax firmament by redistributing the weight of equitable taxation between manufacturing and services. It will reduce the tax rate by broadening the tax base and minimizing exemptions. It will

reduce distortion by completely switching to the destination principle. It will promote a common market across the country and reduce the costs of compliance. It will facilitate the investment decisions made on purely economic concerns, independent of tax considerations. It will promote exports. GST will also promote employment. Above all, it will boost growth.

6. Growth of Manufacturing Sector - On August 15, 2014, Prime Minister Narendra Modi, in his inaugural speech on Independence Day, calls for businesses around the world to come to India'. He urged world powers to "Come, manufacture in India". Sell in any country of the world but make your product over here. We have skill, talent, discipline and determination to do something.

7. Bringing Black Money - The government's decision to set up a special investigation team (SIT), headed by former Supreme Court judge MB Shah, to unearth illegal money hidden in tax havens. The SIT has already prepared a comprehensive action plan, including the creation of an institutional structure that could allow India to fight against black money.

8. Infrastructural Development - "Economy is bleak without Infrastructure. Hence, the prime focus of my government is Infrastructure." Narendra Modi

The focal point of the Union Budget 2014 was infrastructure, a sector which was neglected in the last 10 years under the Congress-led UFA rule. The Government has attracted large-scale investments in infrastructural sector by reviving the Special Economic Zone (SEZ), streamlining the Public Private Partnership (PPP) models and creating Infrastructural Investment Trusts (InvITs). Work for the ambitious Diamond Quadrilateral rail network — connecting major metros across the country — is in the full swing. The Government has laid the groundwork for its ambitious '100 smart cities' project. To develop infrastructure in rural areas, the Government has launched Syama Prasad MookerjeeRurban Mission and DeendayalUpadhyaya Gram JyotiYojana. The Government is also working onstrengthening and modernizing the boarder infrastructure.

9. Bringing Economy Back on Track - In a bid to arrest inflation, Government asked States to delist fruits and vegetables from the Agriculture Produce Marketing Committee (APMC Act). This decision has protected farmers from the middle men and succeeded in preventing hoarding. This in turn has helped in taming inflation. With inflation on check, economic growth is picking up steadily. It is important to note that Indian economy has thrown up the best growth figures in two-and-a-half years. The GDP growth in April-June quarter is the highest in the last nine quarters. This is a sufficient indication that economy is turning around.

Six ways Modi's 'Make in India' Benefits our Country -

1. Kick Start Robust Hiring as Government invests in industrialization - With the introduction of Make in India campaign, rapid industrialization can be achieved with the help of government investment in all sectors. To restart the process, our government will pump investment in various sectors which will eventually increase the industrialization process. The campaign has certainly provided the necessary thrust to push the decelerating Indian economy on the mission of growth. This initiative will bring positive impact on job creation and skills development.

2. Improve GDP Contribution manufacturing - Major focus of Make in India campaign is on the manufacturing sector of our economy. With the increase in the manufacturing sector, our country will be able to reduce imports which will eventually increase the Gross Domestic Product of our country.

3. Improve GDP Contribution from manufacturing - Major focus of the campaign is on the manufacturing sector of our economy. With the increase in the manufacturing sector, our country will be able to reduce imports which will eventually increase the Gross Domestic Product of our country.

4. Focus on manufacturing will stimulate growth in other sectors - The focus on manufacturing will drive the development of other key sectors such as infrastructure and energy, they serve as growth catalysts. As it is known that the development of a country depends on its manufacturing sector and the introduction of Make in India campaign, India can achieve growth of this major sector of the economy.

5. Make in India will promote human capital at grassroot level - The skilled labor demand is widespread in the international labor market. Taking steps to meet this demand, the Prime Minister is focused on the skill development in its "Make in India 'and[1]DeenDayalUpadhyay-GrameenYojanaKaushalya (DDU-GKY)" campaigns. These initiatives will promote human capital at the roots of the grass.

6. Transforming Domestic Manufacturers into global multinationals - This is a major advantage of "Make in India 'campaign which will develop the nation. With the emphasis on the manufacturing sector, the campaign aims to make India a global manufacturing hub.

7. Enabling Indian manufacturing to become globally competitive - Offering different benefits of "Make in India 'campaign,the Indian manufacturing will develop and that ultimately make it competitive globally.

Five Challenges that the could face -

'Make in India' campaign -

1. Abolition of Red Tapism - Creating healthy business environment will be possible only when the administrative machinery is efficient. But, with the excessive interference of bureaucracy, 'Make in India' campaign can face challenge to implement effectively.

2. Stringent Tax Regimes - Due to the presence of stringent rules relating to the tax regimes, the 'Make in India' campaign can face problem for efficient implementation. To make it a success, our government must ease the burden of tax from the manufacturing sector so that it can blossom.

3. Ignorance of MSMEs - It has been seen that the MSMEs (Micro Small and Medium Enterprises) sector of our country lacks in contributing to the development of our nation. This can also hinder the success of 'Make in India'

campaign.

4. Lack of R and D - This is also a major challenge which will affect the success of 'Make in India' Campaign. It is due to the lack of research and development our country lags behind in terms of development in core sector. To make 'Make in India' Campaign a success story, our country must also focus on the research and developmental activities.

5. Lack of Consistency - This can also be a barrier in the success of 'Make in India' Campaign. There must be a consistency in the implementation and functioning of the campaign so that it can give fruitful results to our nation.

Conclusion - The 'Make in India' campaign will bring the positive results for the economy of India which has been facing very bad time since last 8 years and the optimism showed by the MNC's and delegates of different foreign countries has made this initiative more effective and influential. The struggling manufacturing sector will be revived through new investment and it will increase the employment opportunities in India. Though, there are certain challenges which could be overcome by sincere efforts. Prime Minister Narendra Modi has got the experience of managing Gujarat which will help as an engine for this campaign.

References :-

1. Narendra. Modi's Make in India Campaign: Five challenges(2014,September 27) http://zeenews.india.com
2. The 'Make-in-India' Shove-The "Make-in-India" slogan will call for degrading labour, land and the environment Economic andPolitical Weekly-October 11,2014 Vol XLIX No 41
3. Panagariya, A. India-The Emerging Giant. Oxford UniversityPress, Madison Avenue, New York
4. http://firstbiz.firstpost.com/economy/rnake-in-india-live-fdi-means-first-develop-india-says-pm-mpdi-101584.html
5. http://businesstoday.intoday.in/story/narendra-modi-make-in-india-campaign-september-25-global-business-community/l/210482.htmls
6. http://indiatoday.intoday.in/gallery/pm-modi-launches-ambitious-make-in-india-project/l/12900.htmls
7. Dr. M. Kabir Hassan, The impact of globalization on the developing countries, Journal of Economic Cooperation Among Islamic Countries, 19, 1-2(1998)71-135.
8. Indian Entrepreneurs in Import Substitution - Need of the Hour for Indian Economy, Mrs. KamnaDhawan, A1SECT UniversityJournal Vol. II/Issue IV Sep. 2013. ISSN: 2278-4187.
9. MalhotraBhavya, "Foreign Direct Investment-Impact on Indian economy", Global Journal of Business Management andInformation Technology, Volume 4, Number 1(2014), Pp 17-23.
10. R. Bhattacharyya, (2012). The Opportunities and Challenges of FDI in Retail in India, IOSR Journal of Humanities and SocialScience, 5(5), pp. 99-109
11. Skill development for the youth-A Global Quest, SiddharthChaturvedi, AISECT University Journal Vol. II/ Issue IV Sep.2013. ISSN: 2278-4187.
12. The Forthright, Make in India: A Positive Impact on Manufacturing Sector, October 18,2014.
13. http://www.narendramodi.in/pm-launches-make-in-india-g
14. http://timesofindiaindiatimes.com/india/Purchase-only-made-in-India-gadgets-PMO-tells-ministries/articleshow/45664173.cms.
15. http://business.mapsofindia.com/india-policy/liberalization-privatization-globalization.html
16. http://articles.economictimes.indiatimes.com /2015-04-15/news/61.180189south-asia-economic-focus-cent-gdp-growth-investment-growth.
17. http://www.thehindubusinessline.com/economy/macro-economy/modi-for-zero-defect-make-in-india-products/article6736084.ece.
18. http://www.thehindu.com/news/national/centre-states-to-ready-make-in-india-plan/article6731594. ece? ref= relatedNews.
19. http://www.hindustantimes.com/business-news/live-coverage-launch-of-modi-s-make-in-india-campaign/article 1 -1268119.aspx.

✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻

Achieving Food Security Through Agricultural Growth: In Indian Context

Sunil Sharma * Dr. Rajeev Singh Chauhan ** Dr. Kamlesh Kumar Shrivastava ***

Abstract - On the 2 % world's geographical area, India has the responsibility to feed 18 % of world population. Since independence, our country is continuously increasing foodgrain production and now it is 204.6 million tons in 2004-05 four times more than the 50.8 million tons in 1950-51. With the success of green, white and blue revolution, we are now in the position of self-reliance in foodgrain production but possessing a comfortable buffer stock also for food security. After independence, all indicators of food security/ availability increased due to extension of irrigation facilities, HYV seeds, use of fertilizers and chemicals and mechanization of agriculture.

The production of foodgrain increased over the increase in population so the per capita food availability increased. The consumption and availability of food increase in India after independence. About pulses, negative trend emerged. Both ,the production and per capita availability of pulses decreased during this period. the production of pulses decreased by 3.6 percent and the per capita per day availability of pulses decreased by 36.64 percent during this period. For edible oil and Vanaspati, Both the production and per capita availability increased. The production of edible oil increased by 214.3 percent.. Similarly, the per capita per year availability of edible oil and Vanaspati increased by 139.0 percent and 101.43 percent respectively. The production and availability if milk and sugar also increased. Production by 306.8 percent and 92 .74 percent respectively.

Today, the question is , not how increase food production, but it is that how to make the balanced distribution of available food production to secure people and protect them against hunger and malnutrition. As available data shows, 18.4 % world's poor population lies in India and 26.1 percent Indian population is poor and they are jobless and income less.

Introduction - On the 2 % world's geographical area, India has the responsibility to feed 18 % of world population. Since independence, our country is continuously increasing foodgrain production and now it is 204.6 million tons in 2004-05 four times more than the 50.8 million tons in 1950-51. It is also similarly true that our population, 1027.million, has grown three times more than361.0 in 1951.With the success of green, white and blue revolution, we are now in the position of self-reliance in foodgrain production but possessing a comfortable buffer stock also for food security. After all these favorable statistics, we have very complex situation with food security conditions in the society. Although foodgrain production increased at high rate, all its components registered remarkable growth and per capita food availability index but the reality of food security is deferent. 26.1 % population is living below the poverty line and this situation is rather serious about rural population (27.09 % rural poverty 2000). This poor population is excluded in the per capita food availability calculations. After independence, all indicators of food security/ availability increased due to extension of irrigation facilities, HYV seeds, use of fertilizers and chemicals and mechanization of agriculture. Land reforms program also played very decisive role in increasing food production.

Today, the question is , not how increase food production, but it is that how to make the balanced distribution of available food production to secure people and protect them against hunger. As available data shows, 18.4 % world's poor population lies in India and 26.1 percent Indian population is poor and they are jobless and income less.

Objectives -

The main objectives of this paper are –

i) To know the status of food security in India.
ii) To examine the per capita availability of various food in India.
iii) To know the trends of availability of food to Indian.
iv) To examine the consumption pattern in India after independence.
iv) To know the main causes of low availability of food in India.
v) To examine the role of various determinants of agricultural productivity like-irrigation, agriculture inputs, transportation means,. marketing facilities, farm credit availability etc

*Research Scholar, SOS in Economics Jiwaji University, Gwalior (M.P.) INDIA
**Asst. Professor (Economics) Vijaya Raje Govt. Girls P.G. College, Morar, Gwalior (M.P.) INDIA
***Professor (Economics) Vijaya Raje Govt. Girls P.G. College Morar, Gwalior (M.P.) INDIA

vi) To suggest effective measures about efficient public distribution system as well as public delivery system in India.

Data Base & Methodology - This paper is based on secondary data. Various rates relating to food availability are calculated to analyze the status of food security in India. Under the food terminology, foodgrain, including cereals, pulses, edible oil, Vanaspati, sugar, tea and coffee items are taken into consideration.

Data relating to total foodgrain production, cereals production, pulses production, edible oil and Vanaspati production, sugar, milk, tea and coffee production are used to analyze the food security status. Various index numbers and ratios are calculated to analyze the progress of food security after independence in India. Per day and per year availability of food items to Indians are also used as parameters of food security status in India. This paper deals with the period since 1950-51 to 2004-05.

Results Analysis -

Foodgrain Production Increased - Constant increase in foodgrain production since independence is a positive symbol of food security conditions in India. it is also good news that the foodgrain production growth rate has been higher then the growth rate of population growth. During this period from 1950-51 to 200405 the foodgrain production grew four times while population grew three times.

Per Capita Availability Of Food Increased - The per capita consumption of food increased after independence. The per capita availability of cereals was 334.2 grams per day in 1950-51, which increased to 488.12 grams per day in 2004-05. It is 46.10 % increase during this period. Form the point of view of protein as nutrient, the per capita per day availability of pulses was 60.7 grams in 1950-51, decreased by 39.64 percent in 2004-05 and lowered to 36.64 grams per capita per day. It is disappointing for combating malnutrition.

Nutritional Food Availability Increased - During this period, all the main nutrients like-Sugar, milk, Edible oil and Vanaspati registered very remarkable increase. The per capita availability of sugar was 5 kg per year and increased to17.07 kg. It is 241.4 percent remarkable increase. Milk, edible oil and Vanaspati registered 92.94 percent, 139.0 percent and 101.43 percent increase respectively.

Tea And Coffee Consumption Increased - The consumption and availability of hot drinks also increased during this period. The availability of tea was 362. 0 grams per capita per year and increased to 626.45 grams. It is 72.93 percent increase. Similarly, the per capita per year availability of coffee was 67.0grams, which increased to 74.5 grams per capita per year. It is 11.19 percent increase.

Vegetables And Non-Vegetarian Food Consumption - After independence, the consumption of fruits, raw vegetables and eggs,Meat,Chickensand fish has become the main part of our food and these food items are very rich from the point of view of rich nutrient. The production, availability and consumption of all these food items is increasing at very high rate.

Findings -

1. The production of foodgrain increased over the increase in population so the per capita food availability increased.
2. The consumption and availability of food increase in India after independence.
3. About pulses, negative trend emerged. Both ,the production and per capita availability of pulses decreased during this period. the production of pulses decreased by 3.6 percent and the per capita per day availability of pulses decreased by 36.64 percent during this period.
4. For edible oil and Vanaspati, Both the production and per capita availability increased. The production of edible oil increased by 214.3 percent.. Similarly, the per capita per year availability of edible oil and Vanaspati increased by 139.0 percent and 101.43 percent respectively.
5. The production and availability if milk and sugar also increased. The Production of milk and sugar increased by 92.94 percent and 241.4 percent respectively. The per capita availability of milk and sugar increased by 92.74 percent and 306.83 percent respectively.
6. The food consumption and security status is improving, but not satisfactory.

Suggestions - The situation of foodgrain production is unsatisfactory in India. the production and availability of food should be increased. Production of food may be increase by intensive farming increasing irrigation, farm credit, use of HYV seeds, use of chemicals and fertilizers and after all performing Second green revolution.

Efficient public distribution system is an important tool of food security. The food security will be dream only, until the mass unemployment is exist in India. Job should be given to the jobless people to ensure income security. The food security cannot be imagine without income security.

Conclusions - Production and availability of food increased during this period. Per capita availability of food also increased. Thus food security and nutritional status improved after independence in India. But the salutation is not yet satisfactory. A lot of efforts are to be made in this regard. The availability and consumption of Cereals, Edible oil, Vanaspati, sugar, milk, tea and coffee increased but the conclusions about pulses are disappointing because of negative results. Pulses are the main source of protein for vegetarians.

As the conclusion of this paper, Production of foodgrain needed to increase and balanced distribution of food products are also needed. There are various measures to improve agricultural productivity upto second green revolution. Rural infrastructural development, job creation and income security are important tools for combating food insecurity and malnutrition in India.

References :-

1. Census of India 1991 & 2001, Registrar General of India, New Delhi.

2. Dev, S.Mahendra,K.P.Kannam and Nira Ramchandrean(2002) 'Towards A Food Secure India: Issues and Policies 'published by Institute for Human Develoment, New Delhi
3. Economic Survey of India (2005-2006) Economic Division, Ministry of Finance, Govt. of India Publication, New Delhi.
4. Jugale, V.B. (2003) 'Globalization Of Indian Agriculture' In Y.K.Alagh (Edited) Globalization And Agricultural Crisis In India., Deep And Deep Publication, New Delhi.
5. India (2005) Ministry of information and broadcasting, Government of India
6. Rajakutty, S. (2004) 'Self And Wage Employment Programmes For Poverty Alleviation In Rural India- An Overview,' Journal Of Rural Development, Vol.23, No.02 April-June 2004
7. Statistcal outline of India 2004-05,Tata Service Limited, Department Of Economics And statistics, Bombay House, Mumbai.
8. The National Rural Employment Guarantee Act. 2005, Ministry Of Rural Development , Govt .Of India

****

Economic Effects Of Drugs - An Analysis

Nisar Ahmad Wani * Pavan Kumar Shrivastava **

Introduction - Twentieth century may have moved towards over emphasizing the damaging effects that psychoactive drug consumptionhas on society. While the regulation of such dangerous drugs such as heroin and caffeine may be necessary to protect citizens from them, the use of criminal law to prohibit the use of drugs such as cannabisand ecstasy, which are less likely to cause damage, is less rational. Drug use can harm virtually every aspect of people's lives. Harms to health include death,illusions, disease, mental health problems and injury. Harms may be chronic such as depression of heart disease of acute such as injuries from falls of traffic crashes.Social harms are associates with drug use. These include interpersonal violence, family and relationship breakdowns and child neglect. In addition the use of illegal drugs inherently involved individuals in criminal activity of particular concern are situations where users commit. Properlycrime of supply of illegal drugs to support their habits. Economic harms include the costs of health services properly damage low productivity and work absenteeism. A more recent example of changing attitude is the way we view tobacco, smoking, cigarette smoking grew rapidly in the western world in the first part of the twentieth century. In the US by 1945 half of all adult men were smokers consuming anaverage of 20 Ciggarates per day.

Drug abuse is an increasingproblem in our affluent society and carries great economic and social costs through its impacts of crime and health, official policy in the western world for the past 50 years has been to treat addicts as criminals and to punish them but this has manifestly failed to prevent the increase in drug abuse. Nor have campaigns to educate people about the dangers of drug, tobacco and alcohol had anything other than relatively minor effects. The drugs recruit brain mechanisms that have a normal place in emotional and cognitive behavior and cause these to malfunction, so theaddict learns to continue using the drug. An important trade commodity from turkey and India, opium was widely used in all strata of British society in the 18th and 19thcentury. The poor sought solace from the miseries of their daily lives, working mother used opium- containing cordials to calm their children while they went out to work, middle class house wives book laudanum too calm their nerves and artists soughtinspiration from it.

In india it's estimated 65% of all men and 33% of all women use some form of tobacco, the prevalence of smoking among men and women differs substantially : 35% of men and 3% of women smoke , while both use smokeless tobacco products to approximately the same extent. Tobacco consumption continuous to grow in India at 2% to 3 % per annum by 2020 , its predicted that it will account for 13% of all deaths in India, on tobacco consumption are scarce in India . The 52nd national sample survey conducted by the national sample survey organization in 1995-1996 was the first nationally representative household survey to collect data on tobacco consumption in population. 10 years and older using surrogate house hold informants, the prevalence rates ofconsumption of tobacco in any form were found to be 1.3 for men 10.3 for women, 1 year and olden, the study provides an insight into the socio-economic, culture and demographic correlates of tobacco consumption. It concluded that the prevalence of both chewing and smoking forms of tobacco was significantly high in rural, poor and uneducated population. In the initial decades of independent India, tobacco merely had a pecuniary status and was considered as a source of revenue from taxes and exports rather than as aharmful commodity. The pioneering anti tobacco activity in Indian legislature dates back to 1975 when the government of India implemented the "Cigarettes act" mandating display of statutory health warning on all packages and advertisements on cigarettes. The growth index of industrial production of beverages, tobacco and tobacco products is the highest compared with other industries being 314.7 in 2003-04, compared to the base year of 1980-81. The retained earnings of tobacco product manufacturing companies as percentage of profit after tax are 73%.

The positive impact of anti-tobacco activities in the developed world has fostered thedevelopment of a social stigma towards smoking , The overall effect of fiscal measures for tobacco control on the economic , social and human development including , its contribution to the goal of health for all the 21st century, is likely to outweigh any short term dislocation that may follow. The positive pay off from tobacco control is substantial in terms of multiplied effects of improvement in public health and reduced diseases and death that inevitably follow measures toward the tobacco epidemic.

* Research Scholar (Economics) Jiwaji University, Gwalior (M.P.) INDIA
** Asst. Professor (Economics) Govt. S.M.S. P. G. College, Shivpuri (M.P.) INDIA

Tobacco control can be integrated into the existing delivery systems such as the health care systems and developmental programs. The revenues earned from such a taxes have been utilized for funding not only tobacco control programs but also a variety of other health promotion activities. The World Health Organization (WHO) estimated that the proportion of deaths resulting from tobacco related diseases will rise in Indiafrom 1.4% of all the deaths in 1990 to 13.3% of all the deaths in 2020 . The complete ban on advertising and the country wide ban on smoking in closed places in India can go a long way to eliminate the menace. India should aim to achieve at least a 30% reduction in the prevalence of tobacco consumption by the year 2020 and a 25% reduction in tobacco related mortality by 2050. A comprehensive tobacco control program which combines high levels of passion,planning performance and perseverance.

The genesis and development of the Indian drug trafficking scenario are closely connected with the strategic and geographical location of India which has massive inflow of heroin and hashish from across the indo-pak border originating from “golden crescent” comprising of Iran, Afghanistan and Pakistan which is one of the major illicit drug supplying areas of the world. On the north eastern side of the country is the “gold triangle” comprising of Burma , Laos and Thailand which is again one of the largest illicit suppliers of opium in the world. Illicit drug trafficking from the through India is concerned, these three sources of supply have been instrumental in drug trafficking. Prior to the enactment of the narcotic drug and psychotropic substances act 1985, the statutory control over narcotic drugs was exercised in India through a number of state and central enactments. The principal central acts were (1) the opium Act 1857 (2) the opium Act 1878 (3) the dangerous drugs act 1930.

Heroin and Cocaine continue to be illicit drugs that have the most socio-economic impact worldwide, in terms of morbidity, mortality and treatment needs for illicit drug use as well as in monetary terms.Illicit trafficking in heroine and cocaine account for the bulk of the global illicit drug trade in monetary terms. The international narcotics control board therefore has reviewed the impact of illicit opium poppy and coca bush cultivation, as well as trafficking in and abuse of heroin and cocaine on overall economic development. In the rural areas of many countries the illicit drug industry provides jobs in the agricultural sector to a large number of people with limited skills and education small farmers and itinerant laborers. In the short term, providing income generating activities for the people could be regarded as economically favorable. In the long term the illicit drug industry causes major problems that eventually affect the economic development of the country concerned. In general the aggregate economic benefits resulting from the inflow of money from illicit drug production into national economy are likely to exceed the initial inflow of money because of the ripple effects of that inflow. Thus, the multiplier effects of the actual amounts initially injected is important in understanding the potential impact of such activity on the economy. Much of the drug related income of farmers for instance is used to purchase goods and services to meet their daily needs, which in turn provides local traders with additional income that is then spent on other goods and services. The illicit drug industry automatically faster economic development, there are no indication that the expansion of illicit crop cultivation had led to an overall improvement in the economic situation of to the improvement of any trodden development indicator at the national level. While there is evidence that sale of illicit drugs can foster economic development in short term.

Illicit drug are not only the reason for changes in income distribution but they often contribute to it. This is particularly problematic because perceived income equality is at the heart of various social problems faced by many countries including illicit production and trafficking thus forming a vicious cycle. Another negative aspect of investment derived from illicit drug moneyis the lack of continuity. Much of the investment actually depends on the continuity of the illicit drug operation may be suddenly disrupted and related investments may decline of disappear due to law enforcement actions and prosecution. There is no doubt that the foregoing analysis indicates a very big threat that drugs pose to the world economies and countries. The problem is more compounded by the existence of strong organized criminal groups and mafia that are engaged in this trade, scattered around the world and earning big amount of money that makes their financial position stronger than economies of some independent states yet their trade negatively affects the world economies and destroys right of an individual. Every day 1500 people die in india from alcohol, tobacco and other drugs and thousands more and thousands more are admitted to hospitals , psychiatric facilities, jails and prisons of divorce court. The economic effects of alcohol abuse are as damaging to nation as the health affects , affecting the family, community and persons of all ages. Under aged drinking is interfering with children’s development, affecting the nation ability to respond to economic challenge in the future.

The national drug policy 2007-2012 builds on the first national drug policy 1999-2003 (ministry of health 1998). It sets out the government’s policy for tobacco, alcohol, illegal and other drugs within a simple framework having a strong inter-sectoral focus brings together health, justice, enforcement, social development and education agencies that are working towards the common goal of preventing and reducing the health, social and economical harms that are linked to tobacco, alcohol and other drug use.The effective drug education project aims to identify best practice for alcohol and drug education for young people, families and communities that not only raises awareness but also results in sustained behavioral change. Effective drug policy is based on a careful analysis of the most up to date information available strategies to prevent and reduce drug related harm sill be focused on substances that cause the most harm

and where appropriate on the population groups that experience the highest levels of harm. The most effective strategy that we have currently is to treat addicts with methadone, the cigarette smoker with nicotine patches of gum. We mustlearn approaches that are both sophisticated and more effective if we are to make any real impact on the problem.

The bulk of the profits from the illicit drug trade are made in developed countries; however the economic impact of the drug problem is felt more in the developing countries. There is generally a negative correlation between illicit drug production and the economic growth of a country. Account of the following -

"Illicit drugs provide short term gains for few but long term losses for many"

References :-

1. Drug addiction - Bad habits add-up (Robbins T.W.)
2. The Economics of Tobacco control (N.Jha)
3. Combating synthetic drugs, a Global challenge (Thomas A Schweich)
4. Portrait of the enemy (Smith Graeme)
5. Opium-Poppy cultivation, morphine and heroine manufacture (Jim Hogshire)
6. Tobacco of oral health.FDI World Dental Press Ltd. Lowesoft
7. International Narcotics Control Board, Report 2004
8. Tobacco of health? First GlobalStatus report Geneva.
9. www.poppyformedicine.com
10. www.regional.org
11. www.int/tobacco/framswork/finaltest/engassessed/19August2008

****

गरीबी - समस्या एवं समाधान

एस. एल. रजक * डॉ. सुनीता बाथरे **

प्रस्तावना - ***जब आदमी के हाल पे आती है मुफलिसी***
किस-किस तरह से उसको सताती है मुफलिसी

Think of the poorest person you have ever seen, and ask if your next act will be of any use to him. - **Gandhi**

गरीबी मूलत: वंचन (deprivation) से संबंधित है। गरीबी से आशय जीवन की कुछ निर्दिष्ट आवश्यकता की पूर्ति से वंचित रहने (deprivation from necessaries of lite) से है। विकासशील देशों के संबंध में पहला वैष्विक गरीबी अनुमान वर्ल्ड डेवलपमेन्ट रिपोर्ट 1990 में मिलता है। एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह गरीब है क्योंकि वह निर्दिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा है यदि वह जीवन निर्वाह की आवश्यकताओं-भोजन तथा कपड़ा की पूर्ति नहीं कर पा रहा है तो वह बहुत गरीब है। अल्प विकसित देशों में जहां प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, आय की असमानताओं ने कई बुराईयों को जन्म दिया है जिनमें से सबसे गंभीर बुराई गरीबी है। भारत में योजना अवधि के दौरान तमाम आर्थिक विकास के बाबजूद 2004-05 में 41.6 प्रतिशत जनसंख्या विश्व बैंक द्वारा परिभाषित 1.25 डालर प्रति व्यक्ति प्रति दिन की गरीबी रेखा से नीचे थी। गरीबी के संदर्भ में अमर्त्य सेन का यह कथन महत्वपूर्ण है कि-गरीब कोई एक आर्थिक वर्ग नहीं है। गरीबी बहुत सी आर्थिक परिस्थतियों का परिणाम है। दांडेकर व रथ के अनुसार-'जहां तक शहरी क्षेत्र के गरीबों का प्रश्न है, ये लोग भी ग्रामीण क्षेत्रों से ही आए है और इनकी जड़े भी गांवों में ही है। इसलिए वे भी उसी वर्ग विशेष का हिस्सा हैं, जिसका हिस्सा ग्रामीण गरीब लोग हैं। लेकिन लंबे अरसे तक शहरों में रहने के कारण इन लोगों की कुछ स्पष्ट विशेषताएं बन जाती हैं। बढ़ते हुए और फैलते हुए शहरों के माहौल में इन लोगों की जिंदगी के बारे में कोई खास जानकारी उपलब्ध नहीं है।'

एशियन डेवलपमेंट बैंक ने - 1.35 डालर तथा भारत ने 1.02 डालर प्रतिदिन आय को मापक के रूप में लिया है। विश्व बैंक जो विकासशील देशों में गरीबी रेखा के अनुमान के संबंध में 1.25 डालर प्रतिदिन आय को मापक के रूप में लेता था, अब वह 2.50 डालर प्रतिदिन आय को माप के रूप में ले रहा है। अब 2014 के अनुसार 2.50 डालर प्रतिदिन के आधार पर भारत में 2010 में गरीबी 21.1 प्रतिशत रही।

भारत में गरीबी रेखा की माप-हेतु 02 महत्वपूर्ण बातें पाई जाती -

- किसी व्यक्ति के लिए पोषाहार न्यूनतम, स्तर का निर्धारण तथा
- न्यूनतम पोषाहार की लागत का निर्धारण जो वास्तव में किया जाने वाला आवश्यक न्यूनतम उपभोग व्यय होगा जिससे कम व्यय पर व्यक्ति गरीब कहलाता है।

भारत में गरीबी की माप के साथ अनेक अर्थशास्त्रियों के नाम जुडे हैं, जिनमें प्रमुख हैं- दांडेकर तथा रथ, बी. एस. मिनहास, प्रनव बर्धन, आई. जे. अहलूवालिया, एस. पी गुप्त, तेन्दुलकर आदि। इसके अतिरिक्त योजना आयोग व वित्त आयोग के माप मिलते हैं। भारत में निर्धनता रेखा के निर्धारण का पहला अधिकारिक प्रयास योजना आयोग द्वारा जुलाई 1962 में किया गया। योजना आयोग ने गरीबी रेखा के निर्धारण व जीवन-निर्वाह के न्यूनतम स्तर के निर्धारण के संबंध में एक कार्य दल का गठन किया जिसके सदस्य थे- डी. आर. गाडगिल, अशोक मेहता, बी. एन. गांगुली, पी. एस. लोकनाथन, पीतांबर पंत, वी. के. आर. वी. राव, श्रीमन्ननारायण तथा अन्ना साहव सहस्त्रवुद्धे। इस कार्यदल ने 1960-61 न्यूनतम पर ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के लिए बिना किसी आधार को स्पष्ट किए हुए, प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 20 रूपए वांछित न्यूनतम उपभोग व्यय का सुझाव दिया। योजना आयोग के इस दृष्टिकोण की बहुत अधिक आलोचना हुई।

ग्रामीण क्षेत्र मं 1967-68 में गरीबी के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण अनुमान इस प्रकार है-

अनुमानकर्त्ता	गरीबी का आघात (ग्रामीण जनसंख्या के रूप % में)
बी.आर. मिनहास	37.1
एम.एस. अहलूवालिया	56.3
पी.के. बरघक	54.0
वी.एम. दांडेकर तथा एन. के. रथ (1968-69)	40

गरीबी रेखा के निर्धारण के संबंध में अधिक प्रभावी तथा अधिकारिक प्रयास पांचवी योजना के दौरान1977 में हुआ जबकि योजना आयोग ने 'न्यूनतम आवश्यकता तथा प्रभावपूर्ण मांग के पूर्वानुमान के लिए एक कार्यदल गठित किया। कार्यदल ने गरीबी निर्देशांक तैयार किया। इस कार्यदल ने 1958 के भारतीय चिकित्सा शोध परिषद के न्यूनतम पोषाहार आवश्यकता रिपोर्ट के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी व शहरी क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरी की संस्तुति की। जिनका व्यय कैलोरी आवश्यकता की पूर्ति से कम होगा वे गरीबी रेखा के नीचे होगें। गरीबी की इस माप प्रणाली को भोजन ऊर्जा प्रणाली (Food Energy Method) भी कहते है। इस आधार पर 1973-74 कीमत पर ग्रामीण क्षेत्र के लिए कटान बिंदु 49 रूपया तथा शहरी क्षेत्र के लिए 57 रूपया आता है।

सातवें वित्त आयोग (1978) ने विस्तारित गरीबी रेखा (Augmented Poverty line) की धारणा प्रतिपादित की, जिससे उन्होंने प्रतिव्यक्ति मासिक निजी व्यय तथा शिक्षा प्रशासन आदि पर मासिक सार्वजनिक व्यय को एक साथ जोड़ दिया। निर्धनता पर 1989 में प्रो. डी.टी.

* विकास अधिकारी, भारतीय जीवन बीमा निगम, शहडोल (म.प्र.) भारत
** प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) पं. शंभूनाथ शुक्ल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शहडोल (म.प्र.) भारत

लकड़ावाला की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल का गठन किया। 1993 में इस दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति के सुझावों को 9 वीं पंचवर्षीय योजना में निर्धनता की माप के लिये योजना आयोग ने स्वीकार कर लिया। लकड़ावाला समिति के अनुसार 'प्रत्येक व्यय में निर्धनता रेखा भिन्न 2 होगी। इस प्रकार इसके अनुसार इस समय 35 गरीबी रेखायें हैं, जो शुरू में 28 थीं।' इस विशेषज्ञ दल ने प्रत्येक राज्य में ग्रामीण व शहरी निर्धनता के लिए अलग-अलग मूल्य सूचकांकों की बात की-

1. ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता रेखा- इसके लिए लकडावाला विशेषज्ञ दल ने कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI for Agricultural labour) का सुझाव दिया।
2. शहरी क्षेत्र में निर्धनता रेखा- इसके लिए समिति ने औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI for Industrial workers) और शहरी भिन्न कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का सुझाव दिया।

आठवीं योजना में 'कैलोरी प्राप्ति' 2400 ग्रामीण तथा 2100 शहर-आधार को ही स्वीकार किया गया तथा 1973-74 मूल्य पर ग्रामीण क्षेत्र के लिए 49.09 रूपया तथा शहरी क्षेत्र के लिए 56.64 रूपया प्रति व्यक्ति प्रतिमाह उपभोग व्यय लिया गया। नवीं व दसवीं योजना में गरीबी रेखा के अनुमान के लिए कैलोरी आधार ही स्वीकार किया गया। 1992-93 मूल्य पर गरीबी रेखा ग्रामीण क्षेत्र के लिए उपभोग व्यय 228.90 रूपया तथा शहरी क्षेत्र के लिए 264.10 रूपया प्रतिमाह आता हैं। गरीबों के संबंध में राष्ट्रीय प्रतिवर्ष सर्वेक्षण (जुलाई 1993 जून 1994) के आधार पर निष्कर्ष मिलता कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का प्रतिशत जो 1973-74 मे 56.4 प्रतिशत था वह 1993-94 में घटकर 37.3 प्रतिशत हो गया व शहरी क्षेत्र में इसी अवधि में इसका प्रतिशत 49 से घटकर 32.4 प्रतिशत हो गया है। सम्पूर्ण देश में इसका प्रतिशत 54.9 से घटकर 36 हो गया। आठवीं योजना में निर्धनता को पूर्णत: समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया। नवीं पंचवर्षिय योजना में गरीबी रेखा से नीचें की जनसंख्या का अनुपात 1996-97 के 29.18 से घटाकर योजनावधि के अंत तक 17.98 प्रतिशत करने का लक्ष्य था। दसवीं पंचवर्षिय योजना में वर्ष 2007 तक निर्धनता अनुपात में 5 प्रतिशत की कमी करके 21 प्रतिशत पर लाने और 2012 तक 15 प्रतिशत कमी करने का लक्ष्य है। ग्याहरवीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी को 2005-06 के 27.8 प्रतिशत के स्तर से कम करके 2011-12 तक 16.2 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य रखा गया। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार हेड काउन्ट रेशियों आधारित गरीबी निर्धारण के प्रत्यागम के आधार पर गरीबी को कम से कम 10 प्रतिशत बिंदु की कमी करनी होगी।

बहुआयामी गरीबी निर्देशांक (MPI) - एच. डी. आर. 2010 में विकसित एम.पी.आई की धारणा उपलब्धता (कैपेबिलिटी) प्रत्यागम (अमर्त्य सेन) पर आधारित है। इसे यू.एन.डी.पी के साथ से आक्सफोर्ड पावरटी एण्ड ह्यूमन डेवलपमेंट इन्सीयेटिव द्वारा विकसित किया गया। यह गरीबी की माप का अधिक व्यापक दृष्टिकोण है। यह तीन आयामों पर आधारित है जो एच.डी.आई में लिए गये- स्वास्थ्य (Health) शिक्षा (Education) तथा जीवन-निर्वाह का स्तर (Living Standards) समान भारत के साथ इसके 10 संकेतक हैं। जैसा आगे प्रदर्शित है- **(देखे अन्तिम पृष्ठ पर)**

चार्ट से स्पष्ट है कि एम.पी.आई. को प्रभावित करने वाले 10 संकेतक हैं, जो मुख्य आयाम स्वास्थ्य, शिक्षा तथा जीवन-निर्वाह के स्तर से संबंधित है। ये तीनों आयाम मानव विकास सूचकांक (एच.डी.आई.) पर निर्भर करता है। एम.पी.आई. की गणनायें अधिकतम स्कोर 100 प्रतिशत रखा गया तथा तीनों आयामों को बराबर-बराबर अर्थात् प्रत्येक को 33.3 प्रतिशत भार दिया गया। एम.पी.आई. का मूल्य दो मापकों- (ए) बहुआयामी हेटकाउन्ट अनुपात (एच) (बी) गरीबी की गहनता (Intensity of poor) (अ) का गुणनफल होता इसमें बहुआयामी जनसंख्या का कुल जनसंख्या में अनुपात प्रदर्शित करता है-

$H = a / n$

जिसमें a बहुआयामी गरीबों की संख्या तथा n कुल जनसंख्या प्रदर्शित करता है।

$A = Ec / (a)$

सूत्र में प्रयुक्त A उन भारित संकेतों के अनुपात को प्रदर्शित करता है जिसमें औसतन गरीब लोग बंचन की स्थिति में है। केवल गरीब परिवारों के लिए वंचन स्कोर का योग किया जाता है। c भारांकित बंचन की कुल संख्या है, जिसे गरीबों द्वारा महसूस किया गया संकेत की कुल संख्या है।

MPI के आधार पर कुछ देशों के महत्वपूर्ण निष्कर्ष

देश	MPI	बहुआयामी हेड काउन्ट अनुपात
भारत (2005)	0.283	53.7
श्रीलंका (2003)	0.021	5.3
चीन (2003)	0.056	12.5
बाग्लादेश (2007)	0.292	57.8
नेपाल (2011)	0.217	44.2
ब्राजील (2006)	0.011	2.7
यूनाइटेड अरब अमीरात (2003)	0.002	0.6
लैटविया (2003)	0.006	1.6
सरबिया (2005)	0.003	0.8
दक्षिण अफ्रीका (2008)	0.057	13.4
पाकिस्तान (2007)	0.264	49.4

आय सूचकांक 1999-2000 तथा 2007-08 के बीच आय सूचकांक में देश में 21% की वृद्धि दर्ज हुई। दिल्ली (0.678), केरल (0.629), पंजाब (0.495), हिमाचल प्रदेश (0.491) तथा जम्मू एवं कश्मीर (0.495) ऊपरी पांच राज्य रहे, जबकि बिहार (0.127), छत्तीसगढ़ (0.133), उड़ीसा (0.133), झारखंड (0.142), मध्यप्रदेश (0.173), उत्तरप्रदेश (0.175) निचले आय समूह हैं, जिनकी आय सूचकांक राष्ट्रीय औसत 0.217 से नीचे है।

आय की असमानता एच. डी. आर. रिपोर्ट असमानता का गिनी गुणांक

देश	गिनी गुणांक %
भारत	36.8
दक्षिणी अफ्रीका	57.8
ब्राजील	55
मलेशिया	37.9
चीन	41.5
श्रीलंका	41.1
अमेरिका	40.8
थाइलेंड	53.6
यू.एस.ए	40.8
अर्जेनटीना	45.8

योजना आयोग के अनुसार विभिन्न राज्यों में गरीबी की स्थिति (2011-12)

राज्य जनसंख्या में गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत

राज्य	ग्रामीण	शहरी	राज्य	ग्रामीण	शहरी
आंध प्रदेश	10.9	5.8	उड़ीसा	35.69	17.29
असम	33.9	20.5	पंजाब	7.66	9.24
बिहार	34.05	21.23	राजस्थान	16.05	10.7
गुजरात	21.5	10.1	तमिलनाडु	15.8	16.5
हरियाणा	11.6	10.2	उत्तर प्रदेश	30.4	26.06
हिमाचल	8.5	4.3	पं बंगाल	22.5	14.6
कर्नाटक	24.53	15.25	छत्तीसगढ़	44.61	24.6
केरल	9.1	4.9	झारखण्ड	40.8	24.3
म.प्र.	35.7	21.0	उत्तराखण्ड	11.6	10.5
महाराष्ट्र	24.2	9.1	उत्तर भारत	25.7	13.7

तेंदुलकर कमेटी – सुरेश तेन्दुलकर कमेटी संस्तुतियाँ भी गरीबी के परंपरागत रूप से हटाकर इसे बहुआयामी रूप में लेती हैं। तेंदुलकर कमेटी ने अब तक चली आ रही गरीबी के अनुमान से संबंधित कार्यपद्धति की प्रमुखता से तीन कमियों की ओर संकेत किया है। प्रथम गरीबी रेखा के अनुमान के संबंध में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में उपभोग ढाँचे में आने वाली वस्तुओं को तीन दशक पहले 1973-74 में निश्चित किया गया पर इनमें इधर हाल के वर्षो में बहुत अधिक परिवर्तन हुए हैं, जिनकी दृष्टि में रखना आवश्यक है। दूसरा मूल्य समायोजन की एक ऐसी पद्धति अपनायी गयी जिसकी वजह से एक अव्यावहारिक परिणाम प्राप्त हुआ कि कुछ राज्यों के शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या अधिक देखी गयी, तथा तीसरा – गरीबी रेखा के अब तक के अनुमान यह मानकर चलते हैं कि शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर होने वाले व्यय केवल राज्य द्वारा किये जायेंगे, निजी क्षेत्र द्वारा नहीं।

तेंदुलकर कमेटी के अनुसार गरीबी रेखा का निर्धारण उपयोग में लाये जा रहे खाद्यान्नों के अलावा छ: बुनियादी आवश्यकताओं – शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी संरचना, स्वच्छ वातावरण तथा महिलाओं की काम तथा लाभ तक पहुंच के आधार पर होगा। समित ने ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2004-05 मूल्य पर 446.68 रूपया प्रति व्यक्ति प्रतिमाह तथा शहरी क्षेत्र के लिए इसे 578.68 रूपया मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग रखा।

रंगराजन पद्धति एवं तेंदुलकर पद्धति के आंकड़ों की तुलनात्मक स्थिति गरीबी अनुपात (%में)

	2009-10			2011-12		
	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल
(रंगराजन पद्धति के अनुसार)						
भारत	39.6	35.1	38.2	30.9	26.4	29.5
उत्तरप्रदेश	46.3	49.8	47.0	38.1	45.7	39.8
उत्तराखंड	22.5	36.4	26.7	12.6	29.5	17.8
(तेंदुलकर पद्धति के अनुसार)						
भारत	33.8	20.9	29.8	25.7	13.7	21.9
उत्तरप्रदेश	39.4	31.7	37.7	30.4	26.1	29.4
उत्तराखंड	14.9	25.2	18.0	11.6	10.5	11.3

उल्लेखनीय है कि प्रस्तावित रंगराजन पद्धति में वर्ष 2011-12 में प्रतिमाह प्रति व्यक्ति उपभोग पर अखिल भारतीय ग्रामीण स्तर पर 972 रू. एवं अखिल भारतीय शहरी स्तर पर 1407 रू. से कम व्यय करने वाला व्यक्ति गरीब माना गया है।

विश्व बैंक के अनुसार भारत में विश्व की 1/3 गरीबी – विश्व बैंक द्वारा जारी 10 अप्रैल 2014 को जारी 'सभी के लिए समृद्धि' (Prosperity for all) नामक रिपोर्ट के मुताबिक विश्व की एक तिहाई गरीब आबादी भारत में निवास करती है। चरम गरीबी वाले पांच सबसे बड़े देश निम्नांकित हैं –

चरम गरीबी वाले पांच सबसे बड़े देश

रैंक (%)	देश	चरम गरीबी
1	भारत	33 प्रतिशत
2	चीन	13 प्रतिशत
3	नाइजीरिया	7 प्रतिशत
4	बांग्लादेश	6 प्रतिशत
5	डी आर कांगों	5 प्रतिशत

विश्व बैंक के अनुसार उपर्युक्त पांच देशों में समन्वित रूप से विश्व के 76 करोड़ गरीब आबादी रहती है। यदि इसमें पांच अन्य देशों, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तंजानिया, इथोपिया और केन्या को शामिल कर लिया जाये तो विश्व की 80 प्रतिशत गरीब आबादी इन्हीं 10 देशों में रहती है।

गरीबी के लिए उत्तरदायी वजह – निर्धनों के जीवन को चिन्हित करने वाले संस्थागत और सामाजिक कारकों पर आधारित है। निर्धन गुणवत्ता शिक्षा से दूर हैं और अच्छी आय प्राप्त करने के लिये वांछित ज्ञान प्राप्त करने में असक्षम है। स्वास्थ्य की देखरेख से भी अनभिज्ञ है। मुख्य रूप से जाति, धर्म एवं अन्य ऐसी भेदभावपूर्ण रीतियों से निर्धन प्रभावित हैं।

- सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक असमानता।
- सामाजिक बहिष्कार।
- बेरोजगारी।
- ऋणग्रस्तता।
- धन के वितरण की असमानता।

गरीबी उन्मूलन की रणनीतियाँ – भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय व कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात की गई। इस हेतु पंचवर्षीय योजनाओं में सामाजिक न्याय को सरकार की विकास रणनीतियों का प्राथमिक उद्देश्य माना है। वर्ष 1951 से आरंभ पंचवर्षीय योजनाओं में गरीबी उन्मूलन हेतु प्रयास किये गये-

- प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56) के अनुसार वर्तमान परिस्थितियों में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन की अंत:प्रेरणा का उदय निर्धनता और आय, सम्पत्ति तथा अवसरों की असमानताओं से होता है।
- दूसरी योजना (1956-61) में कहा गया- 'आर्थिक विकास के अधिकाधिक लाभ समाज के अपेक्षाकृत कम भाग्यशाली वर्गो तक पहुँचने चाहिये।'
- सरकार के निर्धनता निवारण रणनीति को चतुर्थ आयामी नीति कही जा सकती है। पहली संवृद्धि आधारित रणनीति है। यह रणनीति इस आशा पर आधारित है कि प्रभाव समाज के सभी वर्गो तक पहुंच जायेंगे। 1950 से 1960 के दशक में औद्योगिक विकास, हरित क्रांति के माध्यम से कायाकल्प की बात कहीं गई। जनसंख्या वृद्धि के परिणामस्वरूप प्रति व्यक्ति आय में कमी व धनी व निर्धनों के बीच खाई बढ़ गई। अर्थशास्त्रियों के कथनानुसार आर्थिक संवृद्धि के लाभ निर्धनों

तक नहीं पहुंच पाएं।

- दूसरी रणनीति कार्य सृजन पर आधारित है। तीसरी पंचवर्षीय योजना (1961-66) से इसे आरंभ किया गया। इसके अंतर्गत आय व रोजगार को बढ़ाने के प्रयास किये गये। 1970 के दशक में काम के बदले अनाज एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहा। दसवीं पंचवर्षीय योजना में भी इसे प्राथमिकी में रखा गया। अब स्वरोजगार तथा मजदूरी पर आधारित रोजगार कार्यक्रमों को निर्धनता निवारण का मुख्य माध्यम माना जा रहा है। स्वरोजगार कार्यक्रमों के उदाहरण है - ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (REGP) प्रधानमंत्री की रोजगार योजना (PMRY) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (SJSRY) आदि।
- तीसरी रणनीति स्वरोजगार हेतु योग्य बनाने की है। पहले के स्वरोजगार कार्यक्रमों के अंतर्गत परिवारों और व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी पर 1990 के दशक में इसमें बदलाव आया। अब इन कार्यक्रमों का लाभ चाहने वालों को स्वयं सहायता समूहों का गठन करने के लिए प्रेरित किया जाता। बचत एकत्रित कर परस्पर उधार देने हेतु प्रोत्साहित किया जाता। बाद में सरकार बैंकों के माध्यम से इन्हें आंशिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती। ये समूह निश्चित करते कि किसे ऋण दिया जाये। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ऐसा ही एक कार्यक्रम है। अगस्त 2005 में संसद में विधेयक पास कर प्रत्येक ग्रामीण परिवार के एक इच्छुक वयस्क को वर्ष में 100 दिनों तक के लिए अकुशल शारीरिक श्रम कार्य उपलब्ध कराने की गारंटी देने का निर्णय किया गया। इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का नाम दिया गया। 2011-12 में लगभग 4 करोड़ परिवारों को रोजगार दिया गया।
- चतुर्थ रणनीति लोगों को न्यूनतम आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की रही हैं। भारत विश्व के उन प्रथम देशों में से एक है जहां ऐसा सोचा गया- सस्ता अनाज, शिक्षा, स्वास्थ्य, जलपूर्ति व स्वच्छता आदि सामाजिक उपयोग आवश्यकताओं पर सार्वजनिक व्यय लोगों के जीवन स्तर को सुधार सकता है। इस विधि के अंतर्गत निर्धनों के उपभोग, रोजगार अवसरों का सृजन तथा स्वास्थ्य व शिक्षा में संपूर्ति की जायेगी। निर्धनों के खाद्य उपभोग और पोषण को प्रभावित करने हेतु तीन महत्वपूर्ण कार्यक्रम - सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, एकीकृत बाल विकास योजना तथा मध्यावकाश भोजन योजना। साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना और वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना भी इसी दिशा में किये जा रहे प्रयास हैं। केन्द्र सरकार राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम भी चला रही जैसे - निराश्रित वृद्धजन पेंशन योजना। साथ ही गरीब लोगों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने की योजनाएँ भी आरंभ की है। विश्व बैंक के अनुसार गरीबी से निजात पाने के लिए समझ की जरूरत है, साथ ही जहाँ जीवन की कठिनाई अधिक व्यापक है वहां पर संकेन्द्रण भी जरूरी है।

उपसंहार - गरीबी दूर करने हेतु सिर्फ सरकारी प्रयास ही पर्याप्त नहीं है। सामाजिक जागरूकता की नितांत आवश्यकता है। एक बड़ी जनसंख्या को शिक्षित करते हुए उनमें आत्म विकास की कमी को दूर करने की आवश्यकता है। चाईना की तर्ज पर प्रत्येक व्यक्ति के अन्दर आत्मनिर्भरता की भावना पैदा होना चाहिये। ऐसे संयुक्त प्रयासों से ही भारत जैसी विशाल जनसंख्या वाले देश में गरीबी पर विजय पाई जा सकती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. इंटरनेट
2. भारतीय अर्थव्यवस्था - एस. के. मिश्र और पुरी
3. भारतीय आर्थिक समीक्षा
4. दैनिक भास्कर

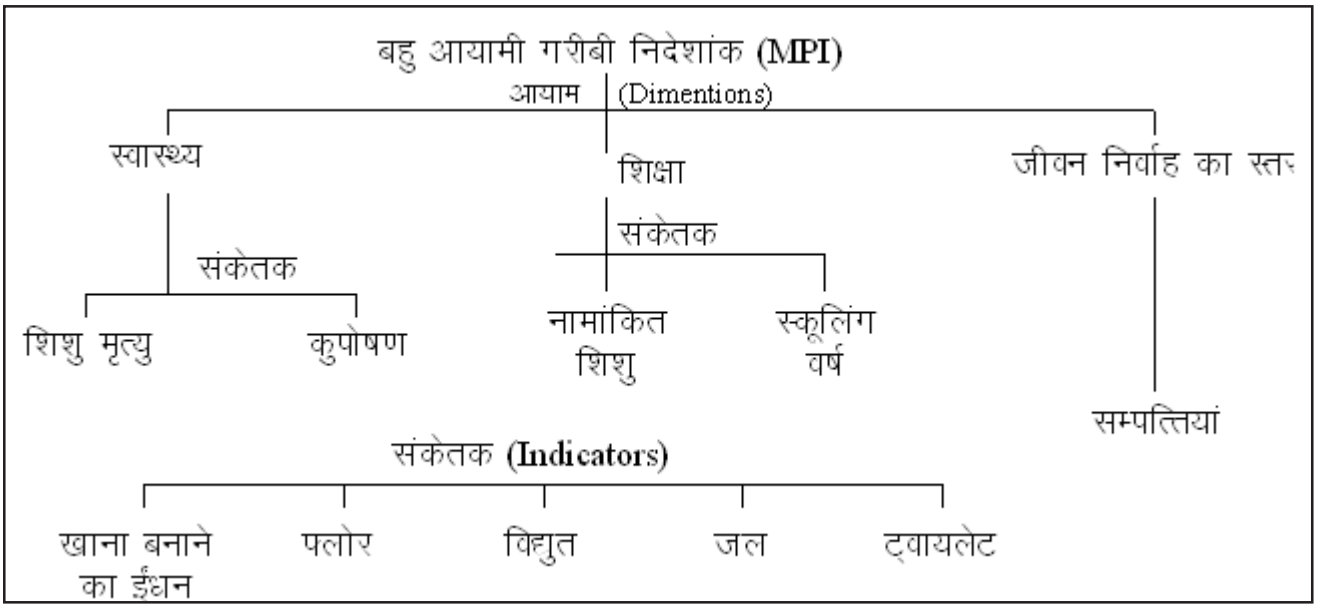

****

भारतीय विदेशी व्यापार की दशा एवं दिशा

रावेन्द्र सिंह पटेल *

शोध सारांश – विश्व की उभरती अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भारत का विदेशी व्यापार परिदृश्य कोई विशेष उत्साहजनक नहीं है। विश्व व्यापार में भारत का योगदान अभी भी बहुत कम है। सकल घरेलू उत्पाद के लिहाज से विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले भारत का स्थान विश्व निर्यात के क्षेत्र में बीसवां और आयात के क्षेत्र में तेरहवां है, जबकि विश्व निर्यात में इसका अंश केवल 1.44 प्रतिशत है और आयात में इसका योगदान कुल 2.12 प्रतिशत है। भारत का निर्यात 1954 तक चीन से अधिक था लेकिन उसके बाद पिछड़ने लगा। 1990 में विश्व निर्यात में चीन का अंश 1.8 प्रतिशत था जबकि भारत का 0.5 प्रतिशत था लेकिन 2009 तक भारत का अंश बढ़कर मात्र 1.3 प्रतिशत हो गया। यदि भारत निर्यात के क्षेत्र में चीन का आधा भी हासिल कर लेता है तो इससे रोजगार एवं विनिर्माण क्षेत्र में सकारात्मक असर पड़ेगा।

शब्द कुंजी – निर्यात, आयात, आर्थिक वृद्धि, विश्वव्यापार संगठन, यूरोपियन यूनियन, भूमण्डलीकरण, सकल घरेलू उत्पाद।

प्रस्तावना – आज भूमंडलीकरण के युग में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आदान-प्रदान अनिवार्य सा हो गया है। विभिन्न देश अपने उत्पादों का निर्यात बढ़ाकर और आयात घटाकर अपने नागरिकों की समृद्धि के लिए काम कर रहे हैं। भारत भी विदेशी व्यापार से अछूता नहीं है। भारत में विदेशी व्यापार की प्रथा बहुत पुरानी है। अंग्रेजों के गुलामी से पूर्व भारत से बहुत सारी वस्तुओं का निर्यात होता था। भारत कपड़ों के निर्यात में विश्वविख्यात था। उसके बाद देश में अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का भरपूर दोहन किया। भारत से कच्चे माल का निर्यात किया गया और विदेशी निर्मित माल का आयात किया गया। उस दौर में हमारा आयात, निर्यात की तुलना में बहुत अधिक था। स्वतंत्रता के बाद 1951-52 में आयात 890 करोड़ रू. एवं निर्यात 716 करोड़ रू. था अर्थात 174 करोड़ रू. का व्यापार घाटा था, जो बढ़कर 2000-01 में 27302 करोड़ रू. एवं 2013-14 में 810423 करोड़ रू. हो गया।

पिछले कुछ वर्षों में भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं और सेवाओं तथा बाजारों में कुछ विविधता आई है तथापि विश्व माँग के अनुसार काम नहीं हो सका है। विश्व में सबसे अधिक आयात की जाने वाली सौ वस्तुओं की सूची में ऐसी बहुत-सी वस्तुएँ हैं जिनमें भारत की मौजूदगी नगण्य है। विश्व व्यापार वार्ता में भारत एक महत्वपूर्ण पक्ष बन चुका है और विश्व व्यापार की नीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, परन्तु इस क्षेत्र में उसकी भूमिका एक मामूली खिलाड़ी जैसी है। भारत में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की विपुल संभावनाएँ है, लेकिन चुनौतियाँ भी कम नहीं है।

Research Methodology –

1. **Area of the study** – प्रस्तुत शोध पत्र में अध्ययन हेतु अध्ययन क्षेत्र के रूप में विश्व के उन देशों को सम्मिलित किया गया है, जिनमें भारत वस्तुओं एवं सेवाओं का आयात एवं निर्यात करता है।
2. **Period of the study** – इस शोध पत्र में 1970 से 2013 के मध्य भारत से होने वाले आयात एवं निर्यात को सम्मिलित किया गया है।
3. **Applied variables** – प्रस्तुत शोध पत्र में अध्ययन हेतु निम्नलिखित चरों का प्रयोग किया गया है – (1) आयात (2) निर्यात (3) आर्थिक वृद्धि (4) उद्योग क्षेत्र में वृद्धि (5) सेवा क्षेत्र में वृद्धि
4. **Data Collection** – प्रस्तुत शोध में द्वितीयक समंकों का प्रयोग किया गया है। इनके संग्रहण हेतु योजना आयोग की रिपोर्टों, आर्थिक सर्वेक्षण तथा केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन का सहारा लिया गया है।

Objectives –

1. भारत से वस्तुओं एवं सेवाओं के आयात एवं निर्यात की मात्रा का अध्ययनकरना।
2. विश्व व्यापार में भारत की व्यापारिक भागीदारी का अध्ययन करना।
3. भारत से आयातित एवं निर्यातित वस्तुओं एवं सेवाओं का अध्ययन करना।
4. भारतीय व्यापार की दिशा का अध्ययन करना।

भारत का निर्यात एवं आयात – वास्तव में किसी भी देश का निर्यात, आयात की तुलना में तीव्र गति से बढ़ना उस देश के विकास का सूचक है। लेकिन भारत में इस तरह की प्रवृत्ति देखने में नहीं मिली है।

भारत का आयात एवं निर्यात (मिलियन यू.एस.डालर)

वर्ष	निर्यात	आयात	व्यापार संतुलन
1970-71 से 1980-81	52265	70727	-18465
1981-82 से 1990-91	116601	151825	-35224
1991-92 से 1999-2000	255176	302675	-47499
2000-01 से 2010-11	1295820	1900859	-605039
2011-12 से 2013-14	920770	1025256	-932379

Source- Economic Survey 2014-15

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि किसी भी दशक में भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल नहीं रहा है और इसका प्रमुख कारण निर्यात की तुलना में आयात का तीव्र गति से बढ़ना रहा है।

आयात की दिशा–भारत ने एशियाई देशों से सबसे ज्यादा आयात किया है जो कुल आयात का 60.7 प्रतिशत है, उसके बाद यूरोपियन देशों से 15.8 प्रतिशत, अमेरिका से 12.8 प्रतिशत, अफ्रीका से 8.1 प्रतिशत और अन्य देशों से 1.7 प्रतिशत आयात किया है। **(सारणी देखे)**

* सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सतना (म.प्र.) भारत

आंकड़ों से स्पष्ट है कि 2013-14 में 2012-13 की तुलना में आयात में गिरावट आई है जो भारत के लिए शुभ संकेत है और यह व्यापार संतुलन को अनुकूल बनाने में मदद करेगा।

भारत के निर्यात की दिशा – भारत ने अपना सबसे ज्यादा निर्यात एशिया में किया है और यह कुल निर्यात का 49.4 प्रतिशत है, उसके बाद यूरोपियन देशों में 18.6 प्रतिशत, अमेरिका में 17.2 प्रतिशत, अफ्रीका में 9.9 प्रतिशत एवं अन्य देशों में 1.1 प्रतिशत निर्यात किया है। **(सारणी देखे अगले पृष्ठ पर)**

आंकड़ों से स्पष्ट है कि भारत का अन्य देशों में निर्यात लगातार बढ़ रहा है साथ ही 2012-13 की तुलना में 2013-14 में सभी देशों में (सी.आई.एस, बालिटिक्स को छोड़कर) बढ़ोत्तरी देखने को मिली है जो भारत के लिए आदर्श स्थित है और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

भारत के पाँच प्रमुख आयातक एवं निर्यातक देश –भारत ने सबसे ज्यादा आयात चीन से 11.3 प्रतिशत उसके बाद संयुक्त अरब अभी रात से 6.4 प्रतिशत, यू.एस.ए. से 5 प्रतिशत, स्वीटजरलैण्ड से 4.3 प्रतिशत एवं साउदीअरब से 8.1 प्रतिशत आयात किया है।

भारत में 5 सर्वाधिक आयातक देश

देश	आयात(मिलियन यू.एस. डालर में)	भारत के कुल आयात में हिस्सा
चीन	51035	11.3
साउदी अरब	36404	8.1
संयुक्त अरब अमीरात	29020	6.4
यू.एस.ए	22505	5.1
स्वीजरलैण्ड	19311	4.3

Source- Economic Survey 2014-15

भारत ने अपना सबसे ज्यादा निर्यात यू.एस.ए में 12.5 प्रतिशत उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात में 9.7 प्रतिशत, चीन में 4.7 प्रतिशत, हागकांग में 4 प्रतिशत और सिंगापुर में 4 प्रतिशत निर्यात किया है।

भारत में 5 प्रमुख निर्यातक देश

देश	आयात(मिलियन यू.एस. डालर में)	भारत के कुल आयात में हिस्सा (%में)
यू.एस.ए	39158	12.5
संयुक्त अरब अमीरात	30520	9.7
चीन	14867	4.7
सिंगापुर	12511	4.0
हांगकांग	12732	4.1

Source- Economic Survey 2014-15

Research Findings And Conclusion -

1. भारत का सबसे ज्यादा आयात एवं निर्यात एशिया महाद्वीप के देशों में हुआ है। भारत ने अपने कुल आयात का 60.7 प्रतिशत आयात एवं कुल निर्यात का 49.4 प्रतिशत निर्यात एशिया महाद्वीप से किया है।
2. भारत के लिए सबसे निराशाजनक बात रही कि किसी भी दशक में भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल नहीं रहा है, इसकी प्रमुख वजह रही निर्यात का आयात की तुलना में कम होना।
3. भारत का आयात निर्यात की तुलना में बहुत ज्यादा है लेकिन आयात की मात्रा लगातार घट रही है, यह भारत के लिए शुभ संकेत है और निश्चय ही भारतीय अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करेगा।
4. भारत ने सबसे ज्यादा आयात क्रमश: चीन, संयुक्त अरब अमीरात, यू.एस.ए. स्वीजरलैण्ड, साउदी अरब से किया है जबकि सबसे ज्यादा निर्यात क्रमश: यू.एस.ए., संयुक्त अरब अमीरात, चीन, सिंगापुर एवं हांगकांग में किया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. विपुल चटर्जी, जोसेफ जार्स मुक्त व्यापार समझौते और भारत आलेख, योजना, फरवरी 2012
2. दत्त गौरव, महाजन अश्विनी, भारतीय अर्थव्यवस्था एसचन्द्र एण्ड कंपनी लिमि. नई दिल्ली, संस्करण 2012
3. मिश्र एवं पुरी भारतीय अर्थव्यवस्था हिमालय पब्लिकेशन नई दिल्ली, संस्करण 2010
4. आर्थिक सर्वेक्षण 2014-15
5. आर्थिक सर्वेक्षण 2013-14
6. सिंह रमेश भारतीय अर्थव्यवस्था टाटा मैग्रा हिल नई दिल्ली संस्करण 2013

भारत के आयात की दिशा (मिलियन यू.एस.डालर)

देश	2012-13	2013-14	परिवर्तन(% में)	कुल आयात में हिस्सा (% में)
यूरोप	87528	424266	-18.9	15.8
अफ्रीका	41011	36627	-10.9	8.1
अमेरिका	59540	57454	-3.5	12.8
एशिया	242686	273198	-6.7	60.7
सी.आई.एस. बालिटिक्स	7880	7723	-2.0	1.7

Source- Economic Survey 2014-15

भारत के निर्यात की दिशा (मिलियन यू.एस.डालर)

देश/महाद्वीप	2012-13	2013-14	परिवर्तन(% में)	कुल आयात में हिस्सा (% में)
यूरोप	56050	58326	4.1	18.6
अफ्रीका	29143	31226	9.1	9.9
अमेरिका	53344	54245	1.6	17.2
एशिया	152699	155426	1.8	49.4
सी.आई.एस. बालिटिक्स	3683	3492	-5.2	1.1

Source- Economic Survey 2014-15

****

इन्दौर नगर के कुड़ा बीनने वाले श्रमिकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन

डॉ. अंजना जैन *

प्रस्तावना – पूर्व केन्द्रीय श्रम मंत्री पी.एम. संगमा ने कहा था कि, 'बाल मजदूरी बच्चों का षोषण है, नैतिक अन्याय है यही नहीं मानवता के नाम पर कलंक है।'[1] भारत के 70 प्रतिशत बच्चे अपने भविष्य को ताक पर रखकर वर्तमान चुनौतियों को स्वीकारते हुए उनसे संघर्ष कर रहे हैं।'[2] बच्चे देश का भविष्य होते हैं और राष्ट्र का उत्थान और सुरक्षा बालकों के विकास व सुरक्षा पर निर्भर है। लेकिन रोजी–रोटी के लिए अपने स्वास्थ व शिक्षा की परवाह न करते हुए देश के बच्चे जब कम मजदूरी पर बाल श्रमिक बनने को बाध्य हो तो उस देश के विकास पर प्रश्न चिन्ह अंकित होता है।

बाल श्रमिक के रूप में बच्चे कई कार्य करते हैं उसमें एक कार्य है – कुड़ा बीनना और पैसे कमाना। बाल श्रम का अभिप्राय है जब 6 से 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों द्वारा पूर्णरूप से या आंषिक रूप से कुड़ा बीनने का कार्य भुगतान मिलने की आषा से करता है उसे कुड़ा बीनने वाले बाल श्रमिक की श्रेणी में माना जाता है।'[3] भारतीय समाज में बच्चों को कल का नागरिक माना गया है। अत: किसी भी राष्ट्र की विकास की स्थिति उस देश के बच्चों की स्थिति देख कर जाना जा सकता है।

शब्द कुंजी – कुड़ा बीनने वाले बाल श्रमिक।

अध्ययन का उद्देश्य –

1. कुड़ा बीनने वाले बाल श्रमिकों की आर्थिक स्थिति का अध्ययन।
2. कुड़ा बीनने वाले बाल श्रमिकों की शिक्षा, स्वास्थ, आवास एवं मादक पदार्थों के सेवान की स्थिति का अध्ययन।

सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन –

1. दुबे प्रशांतकुमार (2004) – बालश्रम कानूनी मान्यता विषय का अध्ययन किया। विभिन्न बाल मजदूरी करने वाले बाल श्रमिकों का अध्ययन कर निष्कर्ष निकाला की बाल श्रमिक 14 घण्टे से अधिक कार्य करते हैं। नगरीय क्षेत्र भोपाल के 148 संगठनों के 9 से 12 वर्ष के 200 बाल मजदूरों का अध्ययन करने पर यह तथ्य उभर कर सामने आया कि 97 बाल श्रमिक बीमार, 160 बच्चे नशाखोर से ग्रस्त है।'[4]

2. सोमीत्र मोहन (बाल मजूदरी देश के लिए अभिशाप 2014) – कुछ मामलों में बाल श्रमिकों के लिये परियोजनाओं में कुछ बुनियादी संशोधनों की आवश्यकता है। बाल मजदूरी से निपटने के लिये अधिक समन्वित और सहयोगात्मक रवैये की आवश्यकता है।

आंकड़ों एवं तथ्यों का संकलन –प्रस्तूत अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक समंकों का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक समंक 200 बाल श्रमिकों से अनुसूचि के आधार पर प्रश्न पुछकर जानकारी एकत्र की गई है। द्वितीयक तथ्य प्रकाशित पुस्तकों, जर्नलस, समाचार पत्रों में प्रकाशित लेख से लिये गये हैं।

तालिका क्रमांक 1 – कुड़ा बीनने के कारणों का वर्गीकरण

क्र.	कुड़ा बीनने के कारण	बाल श्रमिक संख्या	कुल से प्रतिशत
01.	आर्थिक तंगी	074	37%
02.	मजबुरी	100	50%
03.	स्वयं की इच्छा	002	01%
04.	परिवार की इच्छा	024	12
	कुल	**200**	**100**

स्त्रोत – सर्वेक्षण पर आधारित 2015।

तालिका क्रमांक 2 – कुड़ा बीनने वाले बाल श्रमिकों की दैनिक आमदनी के आधार पर वर्गीकरण

क्र.	आमदनी राशि (रु.)	संख्या	प्रतिशत
01.	20 से कम	52	26%
02.	21 से 40	76	38%
03.	41 – 60	44	22%
04.	61 – 80	20	10%
05.	81 – 100	06	03%
05.	100 से अधिक	02	01%
	कुल	**200**	**100**

स्त्रोत – सर्वेक्षण पर आधारित 2015।

तालिका क्रमांक 3

कुड़ा बीनने वाले बाल श्रमिक तथा परिवार की शैक्षणिक स्थिति

क्र.	सदस्य	प्रशिक्षित (200 में से)	साक्षर	शिक्षित कुल	
01.	पिता	124	56	20	200
02.	माता	178	18	–	196
03.	स्वयं	168	22	10	200

स्त्रोत – सर्वेक्षण पर आधारित 2015।

तालिका क्रमांक 4 – कुड़ा बीनने वाले बाल श्रमिकों की आवास स्थिति

क्र.	आवास का प्रकार	कुल संख्या	कुल से प्रतिशत
01.	झुग्गी–झोपड़ी व गंदी बस्ती	178	89%
02.	कच्चे मकान	22	11%
03.	पक्के मकान	Nil	–
04.	अन्य	Nil	–
	कुल	**200**	**100**

* प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

स्त्रोत : सर्वेक्षण पर आधारित 2015।

तालिका क्रमांक 5 – कुड़ा बीनने वाले बाल श्रमिकों व उनके परिवार के स्वास्थ सम्बन्धी स्थिति

क्र.	स्वास्थ स्थिति	कुल संख्या	कुल से प्रतिशत
01.	अच्छी	–	–
02.	खराब	179	89.5%
03.	सामान्य	21	10.5%
	कुल	**200**	**100**

स्त्रोत – सर्वेक्षण पर आधारित 2015।

तालिका क्रमांक 6 – कुड़ा बीनने वाले बाल श्रमिक के मादक पदार्थ सेवा करने सम्बन्धी स्थिति

क्र.	मादक पदार्थों का सेवन	कुल संख्या	कुल से प्रतिशत
01.	क्या आप मादक पदार्थों का सेवन करते हैं?	172	86%
02.	मादक पदार्थों का सेवन नहीं करते हैं?	28	14%
	कुल	**200**	**100**

स्त्रोत – सर्वेक्षण पर आधारित 2015।

तालिकाओं का विश्लेषण – तालिका क्रमांक 1 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि 77 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो 60/– रु. से कम प्रतिदिन कमाते हैं। 100/ – रु. से अधिक कमाने वालों की संख्या मात्र 01 प्रतिशत है। कुड़ा बीनने के बावजूद बाल श्रमिक को इतना कम प्राप्त होता है कि वे अपना ठीक से भरण–पोषण नहीं कर पाते हैं और कुपोषण का शिकार रहते हैं।

तालिका क्रमांक 2 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि, कुड़ा बीनने का प्रमुख कारण 87 प्रतिशत लोग आर्थिक तंगी और मजबुरी तथा अन्य कोई रोजगार न मिलने से कुड़ा बीनते हैं।

तालिका क्रमांक 3 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि, अधिकांश बाल श्रमिकों के माता–पिता व बच्चे अशिक्षित हैं, उन्हें अक्षर ज्ञान भी नहीं है।

तालिका क्रमांक 4 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि, 89 प्रतिशत कुड़ा बीनने वाले बाल श्रमिक झुग्गी–झोपड़ी व गंदी बस्तियों में रहते हैं। यही उनकी बीमारी का कारण है।

तालिका क्रमांक 5 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि, 89.5 प्रतिशत बाल श्रमिक गंदी जगह रहने, गन्दगी बीनने व पोषण आहार न मिलने, व मादक पदार्थों का सेवन करने से उनकी सेहत खराब रहती है।

तालिका क्रमांक 6 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि, 86 प्रतिशत कचरा बीनने वाले बाल श्रमिक गन्दे माहोल में रहने से, अशिक्षित होने तथा खेलकूद व मनोरंजन के साधन उपलब्ध न होने से तथा गलत संगत होने से बीड़ी सीगरेट, स्मेक, शराब आदि मादक पदार्थों का सेवन करते हैं।

डिशकशन – अशिक्षा, परिवार की कम आय, कुड़ा बीनने के बावजूद कम मेहनताना मिलना, कुपोषण तथा अस्वास्थकर आवास व्यवस्था ने बाल श्रमिकों को बचपन से ही बुढ़ा बना दिया है। गलत संगत ने उन्हें मादक पदार्थों के सेवन के लिए प्रेरित किया है। बाल श्रम को रोकने के कई प्रयास शासकीय व सामाजिक स्तर पर हुए हैं लेकिन वे ऊँट के मुंह में जीरे के समान रहे है।

निष्कर्ष – बालश्रम एक बड़ी सामाजिक बुराई है और देश के विकास के नाम पर एक धब्बा है। लेकिन आर्थिक तंगी तथा मजबुरी के कारण कुड़ा बीनना आज शहरी सभ्यता का एक अंग बन गया है। जिन चीजों को हम फेंक देते हैं उस गन्दगी में निकली चीजें इन बच्चों के रोजी–रोटी का साधन है। इनके कार्यक्षेत्र का पर्यावरण स्वास्थ्य के दृष्टि व मानसिक, सामाजिक दृष्टिकोण से विपरीत प्रभाव डालता है। सरकार और समाज द्वारा इसे रोकने के लिये कई योजनाएं बनाई गई लेकिन वे सिर्फ कागजों पर चल रही हैं। आवश्यकता है एक दृढ़ इच्छा शक्ति की ताकि भारत का भविष्य कुड़ा बीनते हुए बर्बाद न हो।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची :–

1. Basu K, The Global Child Labor Problem, World Bank Econo Rev, 2003, 17: 147-73.
2. Basu K (1999) Child Labor cause consequence and cure with remarks on International Labor Standards" Journal of Economics Literature 37 PP 1083-1119.
3. Ranjan Priya 1999 "An Economic Analysis Letlers 64, 99-105.
4. Ranjan Priya 2000 "Credit constraints and the phenomenon of Child Labor Journal of Development Economics 64, 81-102.

****

Decentralization And Women Empowerment - A Step Towards Development

Dr. Sushma Saini * Dr. Abha Saini **

Abstract - Women empowerment is the vital instrument to expand women's ability to have resources and to make strategic life choices. It is also essential for the development of country. Empowerment is multi-dimensional social process that helps women to gain controls their own lives and thus enhancing their position in the power structure of the society.

There are several constraints that check the process of women empowerment in India. Social norms and family structures in developing countries like India, manifests and perpetuate the subordinate status of women. The need of the hour is to identify those limitations which are obstructing the realization of empowerment of women and this initiative must be started from the women folk itself as well as more importantly policy initiative taken by the state and society. Decentralization is used as a tool in the direction of empowerment of woman. Decentralization provides greater opportunities for the citizen to participation in governance at the local level and hence could be a good policy option for enhancing women's political participation. It does so by increasing representation of women which in turn leads to women's responsive policies. They can best take part in the decision making process and hence can best influence the formulation of policies affecting them.

Keywords - Empowerment, Decentralization, Development, Decision-making.

Introduction - The knowledgeable Indian women have to go a long way to achieve equal rights and position because customs are deep rooted in Indian society where the sociological set up has been a male dominated one. Despite all the social hurdles, Indian women stand tall from the rest of the crowd and are applauded for their achievements in their respective field.

The present paper is an attempt to develop conceptual clarity of the term empowerment with decentralization and advocate an inclusive approach of policy measures whereby the planners working towards an empowerment approach, enabling women themselves to critically review their own situation and participate in decision making and shaping the society as agents of change themselves.

Review of Literature - Women empowerment is as a re-distribution of social power and control of resources in favor of Women (Goswami, 2013). So, it is a multidimensional social process that helps people to gain controls their own lives and thus enhancing their position in the power structure of the society (Baruah, 2013). Empowering women and girls with more choices and more freedoms is crucial to achieving a better future for all. He also added that Women agency and freedom are among the crucial means for enhancing development (Sen, 2012).

As Goetz (2001) rightly points out that in addition to take affirmative action, there is a need to overcome the rigid social and cultural barriers, which hinders women's participation in the public sphere.

Objectives of the Study - The objectives of present study are

1. To assess the effects of decentralization on women empowerment and its impact on development.
2. To know the historical perspective about the Political participation of women.
3. To identify the constraints to women's participations in Politics.
4. To know the policy measures adopted by the Indian Government for women empowerment.
5. To analyse the women empowerment through decentralization.

Concept of Development - Development is a phenomenon that is taking place in all walks of life. It aims at improving the quality of life (e.g. increasing access to education, health, sanitation and other basic needs) of all people regardless of their sex, color or caste. For the process of development to be more efficient and effective, both women and men should equally participate in the decisions and processes that shape their lives.

Women Empowerment - "Gender Empowerment defined as improving the ability of women to access the constituents of development – in particular health, education, earnings opportunities, rights, and political participation." This understanding of women's empowerment gives a direct link between empowerment and equality of opportunities.

Decentralization - Decentralization is the transfer of political, administrative and fiscal responsibilities to locally

*Asst. Professor (Economics) D.A.V. (P.G.) College, Muzaffarnagar (U.P.) INDIA
**Asst. Professor (Political Science) J.K.P. (P.G.) College, Muzaffarnagar (U.P.) INDIA

elected bodies in urban and rural areas, and the empowerment of communities to exert control over these bodies. In India, locally elected bodies are the Panchayati Raj Institutions (PRIs) at the district, block and village levels. The decentralization process is distinct for urban and rural areas. The 73rd amendment governs rural decentralization, whereas the 74th amendment mandates urban decentralization.

Historical Perspective: Political Participation of Women- The involvement of women in the development process and political decision making process has always been advocated by social and political thinkers. United Nations adopted the Convention on the Political Rights of Women in 1952. The world-wide concern for women's participation was noticed in 1975 when the United Nations declared the decade as the Women Development Decade and adopted resolutions accordingly. In 1975, the World Plan of Action, adopted in the First World Conference held in Mexico City, put forward various suggestions for the recruitment, nomination and promotion of women in various branches of government, public bodies, trade unions and pressure groups.

The Nairobi Forward Looking Strategies, adopted in the Third World Conference on Women, Nairobi (1985) stressed that "Women by virtue of their gender, experience discrimination in terms of equal access to the power structure that controls society and determines development issues and peace initiatives". The issue of women's political empowerment had gained momentum in the global debate for women's rights at the time of the Fourth World Conference on Women held at Beijing in 1995.

The Report of the Committee on status of women in India (CSWI: 1974), which is considered as a significant document on the socio-economic conditions of Indian women says, "though women's participation in the political process has increased, their ability to produce an impact on the political process has been negligible because of the inadequate attention paid to their political education and mobilization by both political parties and women organizations.

Constraints to Women's Participation in Politics - Taking the economy as a whole, Indian women perform two-thirds of the work, but, earn only one-tenth of the income. Women do have unequal access to land and property rights. Nearly 89 percent of women population earns their livelihood from agriculture. Women do have heavy work load with dual responsibility for farm and household production. Compared to male members, women have low life expectancy at birth, low educational attainment, low income and gender disparities. In 2005, women made up of just twelve percent of the World's Parliamentarians, while for India the share is only eight percent. Studies on Indian women in politics, in aggregate, indicate that women in Indian society have been deprived of fundamental social, economic and political rights. The social hierarchies and inequalities that exist in Indian society deter the women for centuries to play an active role in the social activities including participation in political institutions.

Policy measures adopted by Indian Government for Women Empowerment - The principle of gender equality is enshrined in the Indian Constitution in its Preamble, Fundamental Rights, Fundamental Duties and Directive Principles. The Constitution not only grants equality to women, but also empowers the State to adopt measures of positive discrimination in favour of women.

Within the framework of a democratic polity, our laws, development policies, Plans and programmes have aimed at women's advancement in different spheres. From the Fifth Five Year Plan (1974-78) onwards has been a marked shift in the approach to women's issues from welfare to development. In recent years, the empowerment of women has been recognized as the central issue in determining the status of women. The National Commission for Women was set up by an Act of Parliament in 1990 to safeguard the rights and legal entitlements of women.

The 73rd and 74th Amendments (1993) to the Constitution of India have provided for reservation of seats in the local bodies of Panchayats and Municipalities for women, laying a strong foundation for their participation in decision making at the local levels. India has also ratified various international conventions and human rights instruments committing to secure equal rights of women. Key among them is the ratification of the Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) in 1993.

The strategy is to adopt an integrated approach towards empowering women in all fronts like social, economic, political and legal. The Government of India has also prepared a National Policy for the empowerment of women in 1996 which recommended adoption of the policy along with gender development index.

Women's Empowerment through Decentralization (73rd & 74th Amendment Act) - The 73rd and 74th Constitution Amendment Act (1993) has ushered in watershed in the history of state initiatives with regard to political empowerment of women. The Parliament of India in April 1993 passed these Acts, providing 33% reservations in panchayat structure for all rural women and in Municipal authority for urban women. The Act has provided a definite space for women to participate in politics and to involve in local political decision making process. This legislative innovation has enabled women to participate in decentralized governance, planning and development. Politics has been the principal pillar of empowerment. The more the participation of women in politics, the more they can change the modalities and outcomes of politics.

Decentralization has created space for women's needs within the structural framework of politics and has legitimized the women's issues. Women's successes in Panchayats are creating an encouraging trend all over the country. Women in India have been able to influence social choices and decisions affecting rural society. This opportunity has

provided women a sense of recognition and respect as equal citizens and human being with a contribution to make for the society. A large majority of them has been elected for the first time for any political representation. The reservation of seats in political institutions has greatly contributed to the political empowerment of women and marginalized communities in the society.

Conclusion - It can be said that today we are in a better position wherein women participation in all field of is increasing at a considerable rate. Efforts are being taken at the economy as brought promise of equality of opportunity in all spheres to the Indian women and laws guaranteed equal rights of participation in political process and equal opportunities and rights in education and employment were enacted.

No doubt women have the potential to achieve an equal footing with men. But, it is the social practices and male attitudes that are making an effective and invisible barrier preventing women from rising above a certain point. Empowerment of women could only be achieved if their economic, social and political status is improved. This could be possible only by adopting definite policies with a view of total development of women and to make them realize that they have the potential to be strong human beings.

Swami Vivekananda had said **"That nation which doesn't respect women will never become great now and nor will ever in future"** and in pursuit of making India a great nation, let us work and strive hard in empowering women to the maximum.

References :-

1. Chandra, S.K. (1997) : Women and Empowerment. Indian Journal of Public Administration, 43(4), pp.395-99.
2. Goetz, A. M. (2004) : Decentralization and Gender Equality. Chapter 12 in UNDP (Forthcoming). Striving for Gender Equality in an Unequal World, UNDP report for Beijing+10.
3. Kishor, S. and Gupta, K. (2009) : Gender Equality and Women's Empowerment in India, International Institute for Population Science, Deonar, Mumbai.
4. Sen, Amartya (2012) : "Securing The Future We Want : Gender Equality, Economic Development, and Environmental Sustainability", 67th UN General Assembly, 2012.
5. Seth, M. (2004) : Women and Development - The Indian Experience. New Delhi: Sage Publication.
6. UNDP (1995) : Human Development Report 1995, Oxford University Press, Oxford.

****

भारत की संसदीय व्यवस्था में चुनाव आयोग की बहुमुखी और बहु-आयामी भूमिका

डॉ. जे.के. संत *

प्रस्तावना – अनुच्छेद 324 के अन्तर्गत चुनावों का निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने के लिए एक चुनाव-आयोग की व्यवस्था की गयी है, संविधान का एक पूरा भाग- 15 चुनावों से ही सम्बद्ध किया गया है, इस भाग में अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनावों के सम्बन्ध में विभिन्न सांविधानिक व्यवस्थाएँ की गई हैं, इन्हीं प्रावधानों के अन्तर्गत भारत में चुनाव की सही व्यवस्था के लिए एक स्वतन्त्र प्रशासकीय निकाय की स्थापना संविधान द्वारा की गयी है, जिसे चुनाव आयोग नाम दिया गया है। यह एक स्वतन्त्र निकाय है और संविधान यह सुनिश्चित करता है कि यह उच्चतम और उच्च न्यायालयों की भाँति कार्यपालिका के बिना किसी हस्तक्षेप के स्वतन्त्र और निष्पक्ष रुप से अपने कार्यों को सम्पादित कर सके, मुख्य चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य उतने चुनाव आयुक्त होते हैं, जितने कि राष्ट्रपति समय-समय पर नियत करे, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा निर्मित किसी विधि के अधीन रहते हुए, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति चुनाव आयोग से परामर्श करके आयोग की सहायता के लिए ऐसे प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है जैसा कि वह आवश्यक समझे, मुख्य चुनाव आयुक्त अपने पद से उन्हीं कारणों पर और उन्हीं रीतियों से हटाया जाएगा, जिन कारणों और रीतियों से उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हटाया जा सकता है अर्थात उसे केवल महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है,इस प्रकार संविधान चुनाव आयोग के पदाधिकारियों को पूर्ण संरक्षण प्रदान करता है, जिससे वे अपने कार्यों को निडरता, निष्पक्षता और बिना किसी हस्तक्षेप के सम्पादित कर सके।

चुनाव आयोग के मुख्य कार्य – भारत में संसदीय तथा राज्य विधान सभाओं के चुनावों से सम्बन्धित समस्त व्यवस्था करना चुनाव आयोग का कार्य है, संविधान के अनुच्छेद 324 में आयोग को निम्नलिखित कार्य करने का दायित्व सौंपा गया है-

1. **चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन या सीमांकन –** चुनाव आयोग का मुख्य कार्य चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन या सीमांकन करना है, चुनाव-क्षेत्रों के परिसीमन की व्यवस्था संसद द्वारा पारित परिसीमन आयोग अधिनियम, 1952 के अनुसार की जाती है, इस अधिनियम का प्रावधान है कि प्रति दस वर्ष बाद होने वाली जनगणना के बाद एक परिसीमन आयोग चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करेगा, परिसीमन आयोग का गठन चुनाव आयुक्त की अध्यक्षता में होता है तथा सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के दो अवकाश प्राप्त न्यायाधीश इसके सदस्य होते हैं।
2. **मतदाता सूचियाँ तैयार करना –** इसका दूसरा महत्वपूर्ण कार्य लोक सभा या विधान सभा के प्रत्येक चुनाव या मध्यावधि चुनाव के पूर्व मतदाता सूचियाँ तैयार करवाना है, इस कार्य के सम्पन्न होने पर ही चुनाव होते हैं।
3. **राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना –** यह राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है, इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा कोई आधार निश्चित किया जा सकता है, दलों द्वारा मान्यता प्राप्त किए जाने के इन आधारों में चुनाव आयोग द्वारा समय-समय पर परिवर्तन किए जा सकते हैं और किए जाते रहे हैं। वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन किए गये हैं, वर्तमान व्यवस्था के अनुसार -

राज्य स्तरीय दल को मान्यता देने की शर्त – राज्य स्तरीय दल की मान्यता के लिए सम्बन्धित राजनीतिक दल को लोकसभा अथवा विधान सभा चुनावों में कुल वैध मतों के कम से कम 6 प्रतिशत मत और विधान सभा में कम से कम दो सीटें जीतना, अथवा राज्य विधान सभा में कुल सीटों की कम से कम तीन प्रतिशत सीटें अथवा कम से कम तीन सीटें(इनमें जो भी अधिक हो) जीतना आवश्यक है।

राष्ट्रीय स्तरीय दल के रुप में मान्यता देने की शर्त – किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय स्तरीय दल के रुप में मान्यता प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि लोकसभा अथवा विधान सभा चुनावों में पड़े कुल वैध मतों के कम से कम 6 प्रतिशत मत कम से कम 4 अथवा अधिक राज्यों में उसे प्राप्त हों, अथवा कम से कम तीन राज्यों से लोकसभा में उस राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व कुल सीटों का 2 प्रतिशत (वर्तमान में 543 सीटों के हिसाब से कम से कम 11 सीटें) होना चाहिए।

4. **राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना –** यह आयोग राजनीतिक दलों व निर्दलीय रुप से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को चुनाव चिन्हों का आवंटन करता है, चुनाव चिन्हों को लेकर यदि किन्हीं राजनीतिक दलों में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो आयोग उस विवाद का निर्णय भी करता है, चुनाव- चिन्ह के विवाद में अपील की जाने की व्यवस्था है।
5. **विधायकों की अयोग्यता के सम्बन्ध में परामर्श देना –** ये आयोग को सौंपे गए अर्द्ध-न्यायिक कार्य हैं, संसद सदस्य की अयोग्यता या राज्य विधान सभा की सदस्य की अयोग्यता सम्बन्धी प्रष्न पर क्रमश: राष्ट्रपति या सम्बन्धित राज्यपाल को परामर्श देना भी आयोग का कार्य है।
6. **चुनाव प्रक्रिया का संचालन –** चुनाव प्रक्रिया का आरम्भ जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की 14वीं धारा के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी अधिसूचना से होता है, यह अधिसूचना वर्तमान लोकसभा की अवधि की समाप्ति या मध्यावधि चुनाव होने की स्थिति में जारी की जाती है, इस अधिसूचना में राष्ट्रपति मतदाताओं से संसदों और विधायकों के चुनाव का आह्वान करता है, इसके उपरान्त चुनाव आयोग मतदान की तिथियों की घोषणा करता है, जिसे चुनाव प्रक्रिया का दूसरा चरण कहा जाता है, इस

* सहायक प्राध्यापक (राजनीति शास्त्र)शासकीय तुलसी महाविद्यालय, अनूपपुर (म.प्र.) भारत

घोषणा में नामांकन पत्र भरे जाने की, उनकी जॉच किए जाने की, नामों की वापसी की ओर मतदान किए जाने की तिथियों का उल्लेख होता है।

7. राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करना – निर्वाचन प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों से, राजनीतिक दलों में परस्पर सहमति के आधार पर निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित की गई, आदर्श आचार संहिता के अनुपालन की अपेक्षा की जाती है। आदर्श आचार संहिता निर्वाचन प्रचार की अवधि में राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के आचरण के बारे में विस्तृत दिशानिर्देश स्थापित करती है। इसका अभिप्राय प्रचार को स्वस्थ दिशा में चलाए रखना, प्रचार के दौरान और उसके पश्चात् परिणामों की घोषणा तक, राजनीतिक दलों या उनके समर्थकों के बीच टकराव और विरोध को दूर रखना, और शान्ति तथा व्यवस्था को सुनिश्चित करना है। आदर्ष आचार संहिता केन्द्र या राज्य में सत्तारुढ़ दल तथा अन्य दलों के लिए बराबर स्तर सुनिश्चित करती है ताकि किसी ऐसी शिकायत, कि सत्तारुढ़ दल ने अपने निर्वाचन प्रचार के लिए अपनी शासकीय स्थिति का उपयोग किया है, के लिए कोई कारण न हो पाये, के लिए भी दिशा निर्देश निर्धारित करती है।

8. प्रत्याशियों द्वारा अपने-अपने प्रचार के नियम निर्माण करना – प्रत्याशियों द्वारा अपने-अपने प्रचार के नियम निर्माण कराना जिससे आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए नियम के दायरे में रहकर अपने-अपने प्रचार प्रसार कर सके, इसका अभिप्राय प्रचार को स्वस्थ दिशा में चलाए रखना, प्रचार के दौरान और उसके पश्चात् परिणामों की घोषणा तक, राजनीतिक दलों या उनके समर्थकों के बीच टकराव और विरोध को दूर रखना, और शान्ति तथा व्यवस्था को सुनिश्चित करना है। आदर्ष आचार संहिता केन्द्र या राज्य में सत्तारुढ़ दल तथा अन्य दलों के लिए बराबर स्तर सुनिश्चित करती है ताकि किसी ऐसी शिकायत, कि सत्तारुढ़ दल ने अपने निर्वाचन प्रचार के लिए अपनी शासकीय स्थिति का उपयोग किया है, के लिए कोई कारण न हो पाये, के लिए भी दिशा निर्देश निर्धारित करती है।

9. प्रत्याशियों द्वारा चुनाव के व्यय की सीमा निर्धारित करना – अक्टूबर, 2003 में हुए संशोधन ने इन सीमाओं को बढ़ा दिया है। बडे राज्यों में लोक सभा स्थानों के लिए अब यह 25 लाख रु0 है अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में यह सीमा 10 लाख रु0 से 25 लाख रु0 के बीच भिन्न-भिन्न है। इसी प्रकार बड़े राज्यों में विधान सभा के स्थानों के लिए अब यह 10 लाख रु0 है जब कि अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में यह 5 लाख रु0 से 10 लाख रु0 के बीच भिन्न-भिन्न है। यद्यपि किसी अभ्यर्थी के समर्थन प्रचार में सहायता करने के लिए वे जितना चाहे व्यय कर सकतें हैं, तथापि उन्हें अभ्यर्थी की लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी और दलों को भी वे जितना चाहें प्रचार पर व्यय करने की अनुमति है, वहीं सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों में कहा गया है कि जब तक कोई राजनीतिक दल प्रचार की अवधि में व्यय की गई राशि के लिए विशेष स्पष्टीकरण न दे दे , वह किसी भी क्रियाकलाप को अभ्यर्थी के द्वारा धन सुलभ किया हुआ मानेगा और निर्वाचन व्यय में गिनेगा।

10. मतदाताओं को मतदान कार्य का प्रशिक्षण देना – निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं को मतदान कार्य का प्रशिक्षण दिलाना जिससे मतदान के समय अपने मत का सही उपयोग कर सके

11. राजनीतिक दलों के लिए चुनाव-प्रचार की उचित सुविधाएँ (आकाशवाणी व दूरदर्शन आदि) उपलब्ध कराना – निर्वाचन आयोग द्वारा सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्यीय दलों को निर्वाचन की अवधि में राज्य के इलैक्ट्रोनिक मीडिया- आकाशवाणी और दूरदर्शन तक विस्तृत पैमाने पर पहुॅच की अनुमति प्रदान की गई है। राज्य के आकाषवाणी और दूरदर्शन चैनलों पर आबंटित नि:शुल्क समय 122 घटों तक बढ़ाया गया है। इसे हाल ही के, पिछले निर्वाचनों में आधार सीमा और अतिरिक्त सीमा को मिला कर दल के प्रदर्शन से जोड़ कर आबंटित किया जाता है।

12. चुनाव याचिकाओं के सम्बन्ध में सरकार को परामर्श देना – निर्वाचन आयोग से अर्द्ध-न्यायिक कार्य, जैसे- अनुच्छेद 103 के अन्तर्गत राष्ट्रपति संसद के सदस्यों की अयोग्यताओं के सम्बन्ध में परामर्श करता है। तथा अनुच्छेद 192 के अन्तर्गत राज्यपाल राज्य विधानमण्डलों के सदस्यों की अयोग्यताओं के सम्बन्ध में चुनाव आयोग से परामर्श करता है।

13. अपने कार्यों के विषय में तथा चुनाव प्रक्रिया में सुधारों के सम्बन्ध में सरकार को प्रतिवेदन देना – निर्वाचन आयोग के द्वारा समय-समय पर चुनाव प्रक्रिया में आये विभिन्न समस्याओं के समाधान एवं सुधार हेतु सरकार को प्रतिवेदन देना।

14. निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराने हेतु पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करना- स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने एवं उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले कुछ व्यय की राशि पर्यवेक्षकों के माध्यम से जॉच करना है।

15. किसी चुनाव में हुई अनिमितताओं के आधार पर उस चुनाव को रद्द करना – चुनावों में जीत के लिए अपराधियों की सहायता लेना, हिंसा एवं बल का प्रयोग करना मतदाताओं को उम्मीदवार विशेष के पक्ष में मत देने के लिए बाध्य करना, मतदान केन्द्रों पर कब्जा करना आदि अनिमितताओं के आधार पर उस चुनाव को चुनाव आयोग रद्द कर सकता है।

16. किसी चुनाव क्षेत्र में पुन: मतदान करवाना और पुन: मतगणना करवाना – चुनाव आयोग, द्वारा यदि किसी चुनाव क्षेत्र में हिंसा, बूथ कैप्चरिंग आदि की स्थिति बनी हो तो चुनाव रद्द कर पुन: मतदान करवाना और यदि मतगणना में अनियमताऐं हुई हो तो पुन: मतगणना करवा सकता है।

17. मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन करना – राष्ट्रपति द्वारा चुनाव अधिसूचना के बाद चुनाव आयोग मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन एवं मतदान की तिथियों की घोषणा करता है। इस घोषणा में नामजदगी, पत्रों की जॉच की तिथि, चुनाव संघर्ष के नाम वापस लेने की तिथि का उल्लेख होता है।

18. राज्य सभा के द्विवार्षिक चुनावों की व्यवस्था करना – राज्य सभा एक स्थायी सदन है। अत: इसे लोकसभा के भॉति भंग नहीं किया जा सकता है और यह निरन्तर कार्य करता रहता है। परन्तु प्रत्येक दो वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवा मुक्त हो जाते हैं, एवं 1/3 सदस्य सेवा में आ जाते हैं। जिनकी प्रत्येक द्विवार्षिक चुनावों की व्यवस्था चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है।

19- प्रत्याशियों के चुनाव-व्यय का हिसाब मॉगना – उम्मीदवारों का चुनावी खर्च लगातार बढ़ रहा है। वैसे तो कानून द्वारा लोकसभा चुनाव में 25 लाख, विधानसभा चुनाव में 10-15 लाख सीमा निर्धारित है, परन्तु कानून प्रभावी न होने के कारण एक उम्मीदवार का खर्च करोड़ पर पहुॅच जाता है। यह बढ़ता खर्च अनैतिकता, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। ऐसी स्थिति में ईमानदार व कुशल उम्मीदवार द्वारा चुनाव लड़ना मुश्किल हो गया है। इसलिये चुनाव आयोग द्वारा पारदर्षिता लाने के लिये प्रत्याशियों के चुनाव-व्यय का हिसाब मॉगता है।

20. राजनीतिक दलों से चुनाव में किए व्यय का हिसाब मॉगना – चुनावों में जीत को ही अन्तिम लक्ष्य मानने वाले दलों ने धन शक्ति के साथ-

साथ बाहुबल की शक्ति का भी दुरुपयोग करने में नहीं हिचकिचाते बेहिसाब धन खर्च कर जीत हासिल करना चाहते है। इसके साथ भारी खर्च करके जब दल को सत्ता प्राप्त होती है तो वह चुनाव में खर्च किए गए धन की उगाही सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग, रिश्वत एवं घोटालों से करता है। इन बुराईओं को दूर करने के लिए चुनाव आयोग राजनीतिक दलों से चुनाव में किए व्यय का हिसाब मॉगता है।

21. जाली मतदान को रोकने के लिए राज्य सरकारों को मतदाताओं को पहचान-पत्र जारी करने का निर्देश देना – निर्वाचन नामावलियों में शुद्धता लाने के प्रयास करने के लिए और निर्वाचन धांधलियों को रोकने के लिए निर्वाचन आयोग ने अगस्त 1993 में देश के सभी मतदाताओं के लिए फोटो पहचान-पत्र बनाने के आदेश किए। नवीनतम तकनीकी तरीकों का लाभ उठाने के लिए आयोग ने ई. पी. आई. सी. कार्यक्रम के लिए मई, 2000 में संशोधित दिशा निर्देश जारी किए।

भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त –

क्र.	नाम	पदावधि
1	सुकुमार सेन	21 मार्च, 1950 – 19 दिसम्बर, 1958
2	के वी के सुन्दरम	20 दिसम्बर, 1958–30 सितम्बर, 1967
3	एस पी सेन वर्मा	1 अक्टूबर, 1967 – 20 सितम्बर, 1972
4	डॉ. नगेन्द्र सिंह	1 अक्टूबर, 1972 – 6 फरवरी, 1973
5	टी स्वामीनाथन	7 फरवरी, 1973, – 17 जून, 1977
6	एस एल शकधर	18 जून, 1977 – 17 जून, 1982
7	आर के त्रिवेदी	18 जून, 1982 – 31 दिसम्बर, 1985
8	आर वी एस पेरिशास्त्री	1 जनवरी, 1986 – 25 नवम्बर, 1990
9	श्रीमती वी एस रमादेवी	26 नवम्बर, 1990 – 11 दिसम्बर, 1990
10	टी एन शेषन	12 दिसम्बर, 1990 – 11 नवम्बर, 1996
11	एम एस गिल	12 दिसम्बर, 1996 – 13 जून, 2001
12	जे एम लिंगदोह	14 जून, 2001 – 7 फरवरी, 2004
13	टी एस कृष्णामूर्ति	8 फरवरी, 2004 – 15 मई, 2005
14	बी बी टण्डन	16 मई, 2005 – 29 जून, 2006
15	एन गोपालास्वामी	30 जून, 2006 – 20 अप्रैल, 2009
16	नवीन चावला	21 अप्रैल, 2009 – 29 जुलाई, 2010
17	एस वाई कुरैसी	30 जुलाई, 2010 – 10 जून, 2012
18	वी एस सम्पत	11 जून, 2012 –

निष्कर्ष – निर्वाचन आयोग द्वारा सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्यीय दलों को निर्वाचन की अवधि में राज्य के इलैक्ट्रोनिक मीडिया- आकाशवाणी और दूरदर्शन तक विस्तृत पैमाने पर पहुॅच की अनुमति प्रदान की गई है। राज्य के आकाशवाणी और दूरदर्शन चैनलों पर आबंटित नि:शुल्क समय 122 घटों तक बढ़ाया गया है। इसे हाल ही के, पिछले निर्वाचनों में आधार सीमा और अतिरिक्त सीमा को मिला कर दल के प्रदर्शन से जोड़ कर आबंटित किया जाता है। जरुरत ऐसी चुनाव प्रणाली की है जिसमें जनता के हाथ में सत्ता की सीधी बागडोर हो। अपने चुने प्रतिनिधि को वापस बुलाने की शक्ति मतदाता के हाथ में हो। ऐसी चुनाव प्रणाली जो बहुत खर्चीली न हो और लोकतन्त्र को भीड़तन्त्र अथवा अराजकतन्त्र में बदलने से रोक सके आज कारगर साबित होगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. पॉपुलर मास्टर गाइड यू. जी. सी. जूनियर रिसर्च फैलोशिप तथा लैक्चरशिप परीक्षा राजनीति शास्त्र- सुनील कुमार शर्मा।
2. उपकार यू. जी. सी. जूनियर रिसर्च फैलोशिप तथा लैक्चरशिप परीक्षा राजनीति शास्त्र- सुरेन्द्र कौशिक।
3. यू. जी. सी. जूनियर रिसर्च फैलोशिप तथा लैक्चरशिप हेतु राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा राजनीति शास्त्र-अरुण दत्त शर्मा।
4. यूनीफाइड राजनीति विज्ञान प्रथम वर्ष – नन्दलाल।
5. वेब साइट।

****

राजनैतिक दल, घोषणा-पत्र और मतदाता

भावना ठाकुर *

प्रस्तावना – आम निर्वाचन के समय प्राय: प्रत्येक राजनैतिक दल राष्ट्र की सुरक्षा, समृद्धि एवं विकास की दृष्टि से अपने को अन्य राजनीतिक दलों की अपेक्षा अधिक उपयुक्त, सक्षम एवं योग्य सिद्ध करने के लिये जो वैचारिक योजना आम जनता के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, उसे ही, दलीय घोषणा पत्र कहा जाता है। दलीय घोषणा पत्र राजनीतिक दलों की भूतकालीन उपलब्धियों, भावी योजनाओं एवं विकास कार्यक्रम का लेखा-जोखा होता है। चुनाव घोषणा पत्र कमोबेश दलों के कल्पित आत्मकथा होते हैं और बहुविध अलंकरण के अनुष्ठान होते हैं। वे राजनीतिक दलों के सिद्धान्तों को प्रतिपादित करते हैं और मतदाताओं को अपने आदर्शमय वादों से बाँधते हैं। वे मुद्दों को प्रस्तुत करते हैं, देश की समस्याओं से आम जनता को अवगत कराते हुये दल की योजना व नीति तथा मूल्य परक उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं। ये घोषणा पत्र देश की क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के सम्बन्ध में पार्टी द्वारा अपनायी जाने वाली नीतियों के सूत्रबद्ध वाक्य एवं भावी राष्ट्रीय परिवेश की प्रतिछाया प्रस्तुत करते है तो दूसरी ओर, राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करते हैं। ये घोषणा पत्र चुनाव की अवधि में दलों द्वारा जनता को दिये गये आश्वासन होते हैं। इन घोषणा पत्रों के अध्ययन से जनता को यह स्पष्ट होने लगता है कि विजयी होने के बाद कौन दल राष्ट्र समस्याओं के समाधान की दिशा में कौन-सा कदम उठायेगा। मतदाता इन घोषणा-पत्रों के माध्यम से यह समझने का प्रयास करने लगता है कि किस दल के विजयी होने पर इसका हित सर्वाधिक सुरक्षित रहेगा। इन्हीं घोषणा-पत्रों के माध्यम से मतदाता दलों की उपलब्धियों एवं भावी योजनाओं का आकलन अपने हितों के सन्दर्भ में करने लगता है।

दलीय घोषणा-पत्र की प्रभावशीलता, उसके प्रस्तुतीकरण की शैली, उनके राष्ट्रहित एवं लोकतन्त्र विन्यासित स्वरूप, आम जनता की समस्याओं एवं सवालों को अपने में केन्द्रित करने की उनकी क्षमता तथा मतदाताओं की भावनाओं को झकझोरने की क्षमता पर निर्भर करती है। इसीलिए इन्हें तैयार करते समय दल के नीति-निर्देशकों को ऐसे कुशल लोगों का सहयोग लेना पड़ता है, जो दल की उपलब्धियों एवं भावी योजनाओं को कम से कम शब्दों में लोक लुभावन ढंग से प्रस्तुत कर सकें, जो इस विधा से सम्पन्न हों कि किन शब्दों एवं वाक्यों से मतदाता के अन्तरतम को छूने वाला घोषणा पत्र बनाया जा सकता है। किस प्रकार शब्दों एवं वाक्यों को व्यवस्थित किया जाय कि मतदाता यह महसूस करने लगे कि ये सभी माँगें उनकी अपनी समस्याएँ है। 1959 में ब्रिटेन में मैकलायड ने पार्टी घोषणा-पत्र के निर्माण के सन्दर्भ में कहा था कि घोषणा-पत्र आम मतदाताओं को शिक्षित करने एवं निवेदित करने की प्रक्रिया है। इसके द्वारा पार्टी के विश्वासों, महत्वाकांक्षाओं एवं अभिलाषाओं की अभिव्यक्ति होती है। इसके निर्माण के लिये ऐसी विधा अपेक्षित होती है जो पुराने शब्दों एवं मुहावरों को नवीन सन्दर्भ प्रदान कर सके, तार्किक योजना बना सके, मूल्यों को आकर्षक ढंग से व्यवस्थित कर सके। यह राजनीतिक विश्वास का ऐसा टेस्टामेन्ट है जो कभी कल्पनावादी, कभी आदर्शवादी, कभी सार्वदेशिक और कभी क्षेत्रीय हो जाया करता है। भारत के आम निर्वाचनों में प्रारम्भ से लेकर अब तक दलीय घोषणा-पत्रों की भूमिका एक सी नहीं रहा है।

प्रारम्भ के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय आम-निर्वाचनों में राजनीतिक दलों ने अपने-अपने दलीय घोषणा-पत्रों में अपने द्वारा परिकल्पित राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था को स्थापित करने का वादा किया। काँग्रेस ने प्रजातांत्रिक समाजवाद, साम्यवादियों ने मार्क्सवादी चिन्तन पर आधारित समाजवाद तथा जनसंघ ने भारतीय मूल्यों पर आधारित राजनीतिक व्यवस्था सम्बन्धी विभिन्न तरह के विकल्प आम जनता के समक्ष प्रस्तुत किए। उनके घोषणा पत्रों में व्यवस्था परिवर्तन को महत्व दिया गया, सत्ता परिवर्तन को नहीं। उस समय सभी पार्टियों के अपने-अपने सपने थे, अपनी-अपनी जीवन दृष्टि थी।

किन्तु बुद्धिजीवियों को छोड़कर न तो कोई उनके घोषणा-पत्रों को पढ़ सका न समझ सका। जीवन-दर्शन पर आधारित राजनीतिक दलों की वैचारिक योजनाएँ जनभावनाओं को अपने अनुकूल बनाने की दृष्टि से उपयोगी सिद्ध नहीं हुई और गाँधी, नेहरू तथा कांग्रेस की स्वतन्त्रता प्रदायी छवि कांग्रेस पार्टी की विजय को सुनिश्चित करती रही। दलीय छवि एवं वैचाारिक योजनाओं का आम जनता की समझ से परे होने के कारण विपक्षी नेता हमेशा हारते रहे। इन दलों में जिन नेताओं की कोई अपनी छवि रही वही लोकसभा में पार्टी की उपस्थिति का एहसास कराते रहे। ऐसी ही स्थिति में व्यवस्था परिवर्तन विन्यासित वैचारिक योजना के प्रति प्रारम्भिक वर्षो में राजनीतिक दलों में जो रूझान विकसित हो रहा था, आगे चलकर उससे उसका मोह भंग होने लगा और वे विजय दिलाऊ मुद्दे की तलाश करने लगे।

चौथे आम निर्वाचन में डॉ, राम मनोहर लोहिया द्वारा प्रायोजित गैर कांग्रेसवाद का अभियान विपक्षियों की इसी मानसिकता का परिणाम रहा। 1967 में पहली बार विपक्ष ऐसे मुद्दे पर केन्द्रित रहा जिसका समबन्ध सत्ता परिवर्तन से रहा, किन्तु वैकल्पिक व्यवस्था से नहीं रहा। इस निर्वाचन में गौ-रक्षा जैसे मुद्दे को उठाकर जनसंघ ने दिल्ली की 7 सीटों में 6 सीट, उ.प्र. में 12 सीट, राजस्थान में 3 सीट, मध्यप्रदेश में 10 सीट, हरियाणा, पंजाब, चण्डीगढ़ और बिहार में एक-एक सीट प्राप्त कर स्वतन्त्र भारत के इतिहास में पहली बार सिद्ध कर दिया कि साम्प्रदायिक, भावनात्मक मुद्दों के आधार पर भी जन समर्थन प्राप्त किया जा सकता है। 1967 से 71 तक राजनीतिक दलों के भीतर इस प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक विचार होता रहा कि आम जनता का समर्थन प्राप्त करने हेतु कौन सी रणनीति अपनायी जाए। व्यवस्था परिवर्तन विन्यासित मुद्दों को ज्यादा महत्व दिया जाय या समस्या विन्यासित मुद्दों को।

* सहायक प्रध्यापक (राजनीति विज्ञान) शासकीय महाविद्यालय, रेहटी, जिला-सीहोर (म.प्र.) भारत

इसी वैचारिक मन्थन एवं नीति निर्धारित करने के सन्दर्भ में कांग्रेस का विभाजन अनुशासन बनाम अन्त:करण, संगठन बनाम सत्ता, दक्षिण पंथ बनाम वाम पंथ के आधार पर हो गया। कांग्रेस का एक धड़ा जो इन्दिरा जी के नेतृत्व में कांग्रेस से अलग हुआ था। 1967 से ही विकास के लाभों से वंचित बहुसंख्यक मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित करने तथा उनके बीच अपनी विश्वसनीयता स्थापित करने हेतु समयबद्ध आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों द्वारा प्रजातन्त्र, धर्मनिरपेक्षता एवं सामाजिक न्याय के मूल्यों को व्यवहारिक रूप देने के लिये छटपटा रहा था।

1971 के निर्वाचन से दलीय घोषणा-पत्र का मुख्य बिन्दु वैकल्पिक व्यवस्था विन्यासित योजना न होकर समस्या विन्यासित वैचारिक योजना हो गयी। किन्तु, जहाँ इन्दिरा कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा देकर समस्याओं के समाधान की ओर मतदाताओं का ध्यान आकर्षित करने की पहल की, वहीं विपक्षियों ने 'इन्दिरा हटाओ देश बचाओ' का नारा देकर तथा इन्दिरा जी को प्रजातान्त्रिक एवं संवैधानिक मूल्यों का विरोधी बताकर मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का असफल प्रयास किया।

यदि 1971 एवं 77 में दलीय घोषणा-पत्रों में समस्या विन्यासित मुद्दों को पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से उठाया गया, तो 1980 के घोषणा-पत्र में व्यक्ति विन्यासित मुद्दे प्रभावी हो गये। इन्दिरा-कांग्रेस के घोषणा-पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया कि कांग्रेस 'इ' ही केवल एक राजनीतिक दल है और श्रीमती इन्दिरा गाँधी ही ऐसी नेता हैं, जो देश का सफल नेतृत्व कर सकती हैं, स्थिर सरकार दे सकती हैं। जनता पार्टी ने अपने दलीय घोषणा-पत्र में यह नारा दिया कि 'सदियों का कलंक मिटाना है, बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बनाना है।' लोकदल ने अपने घोषणा-पत्र में किसानों एवं मजदूरों की आर्थिक स्थिति सुधारने का आश्वासन देते हुये आम जनता से चौधरी चरण सिंह को जिताने की अपील की।

1991 में दलीय घोषणा पत्रों में मुख्य रूप से मण्डल के माध्यम से श्री वी.पी. सिंह का जाति युद्ध, बाबरी मस्जिद के माध्यम से श्री आडवाणी का धार्मिक उन्माद तथा श्री चन्द्रशेखर की सरकार बनाने एवं गिराने के माध्यम से श्री राजीव गाँधी की नीति मुद्दे के रूप में छाया रहा।

1996 का चुनाव आते-आते मुद्दों की अहमियत दलीय घोषणा-पत्रों से समाप्त होने लगी। 1971 के चुनाव में गरीबी हटाओं, 1977 में लोकतन्त्र बनाम तानाशाही, 1989 में भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों की जगह दलीय घोषणा-पत्र में गरीब बच्चों को विद्यालयों में दोपहर के भोजन ने ले लिया। इस निर्वाचन में वोट चाहने वालों का यह विश्वास भी जाता रहा कि उन्हें किसी सिद्धान्त, नीति एवं मुद्दों के नाम पर वोट मिलेगा।

भारतीय राजनीति में चुनावी मुद्दों एवं दलीय घोषणा पत्रों के स्वरूप में क्रमश: जो परिवर्तन आता गया, उससे हमारे लोकतन्त्र की प्रतिबद्धता समाप्त हुई। राजनीतिक दलों की विश्वसनीयता एवं मतदाताओं की राष्ट्रीय मुद्दों के प्रति आस्था समाप्त होने लगी। राष्ट्रीय मुद्दों के अभाव में यह बात स्पष्ट होने लगी कि आज सभी राजनीतिक दलों के पास जनता के बुनियादी सवालों का जबाव नहीं है, वैकल्पिक योजनाएँ नहीं है। दलों के अन्दर अन्दरूनी लोकतन्त्र नहीं है, जिससे वैकल्पिक व्यवस्था पर बहस हो सके।

ऐसी स्थिति में यह प्रश्न विचारणीय हो जाता है कि बहुसंख्यक जनता के जो सवाल है, जो मुद्दे हैं, वे राजनीतिक दलों के केन्द्रीय सवाल या मुद्दे क्यों नहीं बन पाते? जनता के सवाल चुनाव में हाशिये पर क्यों छूट जाया करते हैं। मतदाता और उसके बेहतर जीवन से सम्बन्धित मुद्दे हर चुनाव के दायरे से बाहर क्यों रह जाते है? राजनीतिक दलों के नेता मतदाताओं की भावनाओं (जाति और सम्प्रदाय सम्बन्धी) को सीढ़ी बनाकर सत्ता के गलियारे में क्यों पहुंच जाते हैं? इन प्रश्नों पर यदि गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाये तो यह तथ्य स्पष्ट होता है कि प्रारम्भिक चुनावों के दलीय घोषणा-पत्रों में और आज के दलीय घोषणा-पत्रों के स्वरूप में परिवर्तन आने के कारण ऐसा हो रहा है।

आरम्भ के चुनावों में दलीय घोषणा-पत्र का आधार वैकल्पिक जीवन-दर्शन एवं जीवन-दृष्टि हुआ करता था। उन चुनावों के साथ मतदाताओं के सपने जुड़े रहते थे। वे सपने बदलाव के थे, नये समाज और सरकार के थे, नई संस्कृति के थे। उन सपनों को रूप देने की ललक एवं उत्साह राजनेताओं में हुआ करती थी। इसी कारण अपनी हार सुनिश्चित जानकर भी नेतागण लोक जागरण के लिये चुनावों का इस्तेमाल करते थे, किन्तु अब दलीय घोषणा-पत्र वैकल्पिक जीवन-दर्शन पर आधारित नहीं होते। उनका उद्देश्य लोकहित एवं लोक जागरण नहीं होता। अब उनका उद्देश्य किसी भी तरह चुनाव जीतना होता है। अब नेतागण चुनावों में सम्मिलित होते हैं चुनाव जीतने के लिए, सत्ता के गलियारे में पहुँचने के लिए, न कि राष्ट्रीय एवं प्रजातान्त्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए।

पहले घोषणा पत्र व्यापक चिन्तन और व्यापक दृष्टिकोण पर आधारित होते थे। उनका सम्बन्ध राष्ट्र की समृद्धि, जनता के बेहतर जीवन एवं प्रजातान्त्रिक मूल्यों से होता था। उनके स्वरूप एवं उपयोगिता पर, जीवन मूल्यों के आधार पर विचार किया जाता था किन्तु अबके घोषणा-पत्र संकीर्ण चिन्तन और संकीर्ण दृष्टिकोण पर आधारित होने के कारण सतही होते है, मतदाताओं की भावनाओं को उभारने वाले होते है। उनका सम्बन्ध सम्पूर्ण राष्ट्र से नहीं, राष्ट्र के वर्ग-विशेष एवं जाति-विशेष के सतही स्वार्थ से होता है। उनमें राष्ट्रीय समृद्धि, प्रजातान्त्रिक मूल्यों एवं आम नागरिकों के बेहतर जीवन के प्रति प्रतिबद्धता नहीं होती।

पहले राजनीतिक दलों के घोषणा-पत्रों में एक बुनियादी अन्तर होता था, जो विकल्प को प्रोत्साहित करता था। किन्तु आज राजनीतिक दलों द्वारा जो घोषणा-पत्र तैयार किये जाते हैं, उनमें शब्दों के अंतर तो होता है, किन्तु उनमें सन्निहित तथ्यों के बीच कोई ऐसा बुनियादी अन्तर नहीं होता जो गुणात्मक एवं सृजनात्मक विकल्प को स्पष्ट कर सके। 1991 में कांग्रेस द्वारा प्रस्तुत 'राम-रहीम, रोजी-रोटी', भाजपा द्वारा प्रस्तुत 'राम, रोटी इन्साफ' और राष्ट्रीय मोर्चे द्वारा प्रस्तुत सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों एवं नारों में कोई बुनियादी अन्तर नहीं रहा है। भाजपा का स्वराज से सुराज की ओर, कांग्रेस का स्वराज के साथ सुराज में कोई बुनियादी अन्तर नहीं है।

पहले के घोषणा-पत्रों में जो वादे किये जाते थे, जो मुद्दे उठाये जाते थे, उनमें दोहरापन नहीं होता था। अब तो वादे किये जाते हैं, मुद्दे उठाये जाते हैं, उनके दो रूप होते है-एक आदर्श निष्ठ और दूसरा स्वार्थ निष्ठ। मंच से पूरे समाज के लिये आदर्श निष्ठवाद किये जाते हैं, किन्तु पर्दे के पीछे वर्ग-विशेष के लिये एवं जाति-विशेष के लिये तथा वोट के ठेकेदारों के लिये स्वार्थनिष्ठ वादे किये जाते हैं। आदर्श निष्ठ वादों को पूरा करने से उनका व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा नहीं होता। उनके जीवन में भौतिक सुख-समृद्धि की सम्भावना नहीं बढ़ती, उनका वोट बैंक सुरक्षित नहीं रह पाता। अत: वे स्वार्थनिष्ठ वादों को ही पूरा करने में अपनी रूचि प्रदर्शित करते हैं। नेता और जनता द्वारा इन्हीं स्वार्थनिष्ठ वादों को अपने जीवन में महत्व देने का परिणाम है-घोटालों की अनवरत श्रृंखला।

पहले के निर्वाचनों में राजनीतिक दल जो वादे करते थे, उन पर जनता विश्वास करती थी। किन्तु अब नेता जो वादे करते है, उन पर जनता विश्वास

नहीं करती। आज यदि थोड़े से बौद्धिक वर्ग को छोड़ दिया जाये, तो आम जनता का चुनाव घोषणा–पत्रों से कोई लेना देना नहीं है। सारे दिन दाल–रोटी के जुगाड़ में लगे रहने वालों के पास न तो इन उबाऊ कागजी पुलिंदों को पढ़ने में कोई रूचि है और न ही कोई इच्छा। नेताओं की वादा खिलाफियों के कारण इनमें 'कोई नृप होय, हमें का हानि' की धारणा बलवती होती जा रही है। क्योंकि 1971 में इन्दिरा जी ने गरीबी हटाने का वादा किया, किन्तु पूरा नहीं कर सकीं। 1979 में जनता पार्टी ने जो वादा किया उसे पूरा नहीं कर सकी। 1989 में राष्ट्रीय मोर्चे ने सामाजिक न्याय दिलाने का वादा किया, किन्तु जातीय राजनीति के अभ्युदय ने सामाजिक न्याय की उपेक्षा कर दी।

डॉ. प्रभा भार्गव का मानना है कि घोषणा–पत्र अपने को राष्ट्रीय प्रश्नों तथा सामाजिक मुद्दों से अछूते रखते हुये शुद्ध रूप में वर्तमान जीवी बनते जा रहे हैं। भारतीय मतदाता अपने चुनावी अनुभवों के आधार पर उन घोषणा–पत्रों की निरर्थकता के प्रति ही अधिक आश्वस्त रहता है। वह इन्हें एक चुनावी औपचारिकता मानता है। आम मतदाता की यह धारणा है कि राजनीतिक दल घोषणा–पत्र पर अमल करने को न तो जरूरी मानते हैं, और न करने की स्थिति में हैं और न किसी नैतिक शर्मिन्दगी से गुजरते हैं। राजनीतिक दलों तथा मतदाताओं के लिये कागज के ये पुलिन्दे अब एक थकाऊ और उबाऊ रस्म–अदायगी रह गये हैं।

आज भारत की निर्वाचन राजनीति की सबसे महत्वपूर्ण समस्या है–जनता के वास्तविक सवालों को दलीय घोषणा–पत्रों एवं चुनावी मुद्दों का विषय बनाना। गरीबी, बेरोजगारी, महँगाई, अशिक्षा, भ्रष्टाचार एवं साम्प्रदायिकता जैसे सवालों को दलीय घोषणा–पत्रों में सम्मिलित किया जाना। यह तभी सम्भव है जब राजनीतिक दलों के पास विकास की अवधारणा और उसमें व्यक्ति का स्थान तथा उसकी भूमिका के सम्बन्ध में कोई वैकल्पिक चिन्तन हो। इस वैकल्पिक चिन्तन की पृष्ठभूमि तभी निर्मित हो सकती है, जब लोकतान्त्रिक प्रक्रिया के आधार पर दलों का संगठन हो और उस संगठन से शीर्ष नेतृत्व शक्ति प्राप्त करें।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. डॉ. सच्चिदानन्द मिश्र, 'भारतीय निर्वाचन संस्कृति – दशा एवं दिशा', वसुन्धरा प्रकाशन गोरखपुर, 1996, पृ. 46
2. एन.एस.मल्होत्रा, 'इलेक्शन पालिटिक्स इन इण्डिया', पृ. 56
3. पालिटिक्स क्वार्टरली, अप्रैल–जून 1965
4. डॉ.प्रभा भार्गव, 'चुनाव घोषणा पत्र – सिद्धांत एंव स्थिति' राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 2006 पृ.–261

****

महात्मा गाँधी का आर्थिक चिन्तन

डॉ. अनिल कुमार जैन *

प्रस्तावना – बीसवीं शताब्दी के युग पुरूष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भारत ही नहीं वरन् संपूर्ण विश्व में एक महान विभूति के रूप में गौरवशाली पद पर प्रतिष्ठित है। गांधीजी के बारे में विश्व के महान वैज्ञानिक आईन्स्टीन ने लिखा था, कि आने वाली पीढ़ियाँ शायद ही इस बात पर यकीन कर पाऐ कि हाड–मांस का ऐसा इन्सान भी कभी धरती पर चला था।

गांधीजी राजनीतिक नेता के साथ ही प्रथम कोटि के समाज सुधारक, शिक्षा शास्त्री, अर्थशास्त्री तथा विचारक थे। महात्मा गांधी व्यक्ति के पूर्ण विकास के पक्षधर थे तथा वे मानते थे कि मानव धर्म नैतिकता पर आधारित है और कोई भी गतिविधि नैतिकता से परे नहीं हो सकती है। हालांकि वे अर्थशास्त्री नहीं थे पर उन्होंने भारतीय आर्थिक समस्याओं का क्रमबद्ध अध्ययन किया उन्होंने कहा भारतीय आर्थिक समस्याओं का अध्ययन और उचित आर्थिक नीतियों का निर्माण ही भारतीय अर्थशास्त्र की विषय सामग्री है। गांधीजी के आर्थिक विचार जीवन के सर्वांगीण विकास भावना से प्रेरित है। उनका मानना था कि आर्थिक प्रणाली ऐसी होनी चाहिये जिससे कोई भी व्यक्ति भूखा, नंगा न रहे। चाहे यह भारत हो या विश्व का अन्य कोई राष्ट्र। प्रत्येक व्यक्ति को कार्य करने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। ताकि वह दो समय की आजीविका स्वाभिमानपूर्वक प्राप्त कर सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि मैं अर्थशास्त्र और नीतिशास्त्र में किसी प्रकार का अन्तर नहीं मानता, वह अर्थशास्त्र जो व्यक्ति या राष्ट्र के नैतिक कल्याण पर प्रहार करता है, अनैतिक है, इसलिये पापमय है। गांधी ने माना कि वह अर्थशास्त्र झूठा है, जो नैतिक मूल्यों की उपेक्षा और अवहेलना करता है। वह अर्थशास्त्र जो धनिक और शक्तिशाली लोगों की पूजा करता है और दुर्बल लोगों से धनसंग्रह करते है वह शास्त्र सर्वदा झूठा और भयानक है। सच्चा अर्थशास्त्र तो सामाजिक न्याय का प्रतीक है। एक ओर गांधीजी के विचार मानवीय मूल्यों पर आधारित है पर दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्र में आज गरीबी, बेरोजगारी, असमानता इन समस्याओं के साथ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा सार्वजनिक जीवन, उपभोक्तावाद आदि प्रश्न केवल मूल्यों को त्यागने में निर्मित हुए है।

जब गांधीजी के जीवन दर्शन का हम अध्ययन करते है तो उनके आर्थिक विचारों पर सहज प्रकाश पड़ सकता है। तद्धुसार ज्ञात होता है कि वे विकास के लिए प्रकृति का दोहन नहीं पोषण के पक्षपाती थे। वे चाहते थे कि उत्पादन के सभी साधनों में समन्वय हो न कि प्रतियोगिता। इसका अर्थ स्पष्ट है कि वे भूमिपति, पूंजीपति, श्रम तथा साहसी के मध्य समन्वय के समर्थक थे। इसी प्रकार वे उपभोक्ता की अनिवार्य आवश्यकता के अनुसार उत्पादन पर बल देते थे। बाजारवाद का उन्होंने सदैव विरोध किया।

गांधीजी ने अपनी समन्वयात्मक आर्थिक आदर्शवादी विचारधारा के अनुरूप ट्रस्टीशिप का एक अभूतपूर्व सिद्धान्त प्रस्तुत किया जो विशुद्ध नैतिकतावादी सत्य पर आधारित, आदर्शवादी बेजोड़ चिन्तन माना गया है। यद्यपि उनके इस सिद्धान्त के व्यवहारिक होने पर विद्वानो को संशय बना रहा है तथा इसे प्रयोग में भी नहीं लाया जा सका है। वर्तमान देशकाल में इसके क्रियान्वयन को दिवा स्वप्न माना गया है।

महात्मा गांधी के ट्रस्टीशिप सिद्धान्त में पूंजीपति की यद्यपि महत्वपूर्ण भूमिका है, परन्तु मूलत: पूंजीपति भूमि स्वामी तथा श्रमिक सभी समाज में ट्रस्टी के रूप में सम्मिलित माने गये है। पूंजीपति से अपेक्षा की गई है कि वह सम्पत्ति के वैयक्तिक अधिकार को स्वेच्छा से त्याग दे और स्वयं समाज के प्रति अपने नैतिक दायित्व का निर्वाह करें। वस्तुत: इसका उद्देश्य व्यक्तिगत बचत का सामाजिकरण है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि यह सिद्धांत व्यक्तिगत सम्पत्ति के निरीक्षण के साथ–साथ सार्वजनिक संस्थाओं का संचालन, सरकार द्वारा चलाने का भी विरोध करता है।

इसके लिये गाँधीजी का तर्क है कि संसार ईश्वर की सत्ता का रूप है। हम सभी उसके सेवक है, हमारा शरीर, हमारी क्षमता, हमारा कौशल सब कुछ हमारा अपना नहीं उस परम सत्ता की देन है, अत: उसके प्रति समर्पण भाव के अभाव के कारण सम्पत्ति के स्वामित्व की अवधारणा का अस्तित्व है, जो शोषण पर आधारित है। अत: गांधीजी ने सामान्य रूप में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व ट्रस्ट को बनाया। उत्पादन व वितरण सभी ट्रस्ट के क्रियाकलाप होगें।

गाँधीजी का समस्त चिन्तन लोक जीवन पर आधारित था वे पहले स्वयं करते, उसमें जनता की भागीदारी बढ़ाते फिर उसे कहते थे। यद्यपि यह सब कुछ संभव प्रतीत नहीं होता है क्योंकि व्यक्ति अपने उपलब्ध अधिकारों का त्याग क्यों कर सकेगा ? तदर्थ प्रमाण है कि अप्रैल 1957 में विनोबा भावे ने भूदान और ग्राम दान का आंदोलन चलाया जो अपेक्षाओं के विपरीत सफल रहा। इसमें 46 लाख करोड़ एकड़ भूमि दान में प्राप्त हुई।

गाँधीजी द्वारा पूंजीपतियों को समाज का ट्रस्टी बनाये जाने के सिद्धान्त के कारण उन्हें पूंजीवाद का समर्थक भी कहा गया है। वे सार्वजनिक क्षेत्र के भी पक्षधर नहीं थे। वे किसी इकाई का संचालन सरकार करें यह स्वीकार नहीं करते थे। यह प्रतिपादित किया जा सकता है कि उत्पादन के विकेन्द्रीकरण का सिद्धान्त कभी भी पूंजीवाद का सर्मथक मत नहीं हो सकता है। पूंजीवाद तथा बाजारवाद की व्यवस्था में भी गांधीजी विश्वास नहीं रखते सिर्फ हिंसा और दबाव या अनैतिक रूप से धन आहरण या पूंजीपतियों के विरोध का वे समर्थन करते हुए, उन्हें अहिंसा और धर्म के नैतिक आदर्शों के अनुसार समाज के प्रति अपने दायित्व की ट्रस्टीशिप के रूप में शिक्षा देते है।

गांधीजी को अपनी कल्याणकारी नीतियों के आधार पर समाजवादी माना जा सकता है। यद्यपि उन्होंने समाजवाद की प्रतिक्रिया व स्वरूप को कभी भी स्वीकार नहीं किया। उन्हें हिंसा द्वारा प्राप्त कोई परिवर्तन किसी भी शर्त या लाभ की स्थिति में स्वीकार नहीं था। वे स्पष्ट रूप में साध्य के प्रति साधनों की भी पवित्रता के प्रति कटिबद्ध थे।

गांधीजी का अर्थशास्त्र धर्म के नैतिकता पक्ष के साथ संबद्ध है। वे

* सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) शासकीय कन्या महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.) भारत

उत्पादन तंत्र, मशीन तथा तकनीक सभी को मनुष्य के हित में उपयोगी स्वीकार करते है, परन्तु जब ये माध्यम मनुष्य को काम से बेदखल करते है तो गांधीजी इनका विरोध करते हुए स्पष्ट करते हैं कि मशीन के लिये काम नहीं, बल्कि काम के लिये मशीन तथा तकनीक की खोज की जाती है।

महात्मा गांधीजी का ट्रस्टीशिप सिद्धान्त उनके आर्थिक चिन्तन का मूल है। इसमें शोषण के विपरीत स्वेच्छा से 'सब एक दूसरे के लिये' आदर्श का प्रतिपादन है। यह आवश्यकता आधारित उत्पादन तथा विकास का समर्थक है। ग्राम स्वराज्य सर्वोदय तथा रामराज्य इसके व्यक्ति और समाज के न्यायोचित तदर्थ, नैतिक स्वरूप है।

गांधीजी के अनुसार सच्ची अर्थरचना तो ऐसी होनी चाहिये कि किसी को भी रोटी, कपड़ा का अभाव की तकलीफ न सहनी पड़े। आज यंत्रों के प्रति लोगों में पागलपन सा साकार हो रहा है, इससे श्रम की बचत तो हो सकती है पर उनके कारण लाखों लोगों की रोटी छिन रही है और वे राह के भिखारी बनकर घूम रहे है। बड़े पैमाने पर यंत्रों की वजह से रोजगारों के अवसरों में कमी आई और गरीबी को बढ़ावा मिला। देश में बहुत हाथों की कमी नहीं है, लोग बेकार है।

अत: आज सबसे पहले तो समूचे अर्थ तंत्र में बुनियादी परिवर्तन करना होगा तथा गांधीवादी क्रांतिकारी पद्धति को आत्मसात करना होगा, गांधीजी द्धारा प्रतिपादित मूल्यों को अपनाना होगा। सादगी को स्थान देना होगा। भारत गांवों में बसता है, भारत की ग्रामीण दुर्दशा दूर करने हेतु आज गांधीजी की ग्राम स्वराज्य की विचारधारा की उपयोगिता और बढ़ गई है। आज गाँवों में लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। जिससे गांवों में बेरोजगारी की समस्या कम हो सके। कृषि सुधार को बढ़ावा देना होगा और बड़ी मात्रा में अच्छे कृषि साधनों का प्रयोग आवश्यक है। ग्रामवासी ग्राम उद्योगों के विकास एवं गठन में सक्रिय भाग अदा करें। दस्तकारों तथा हस्तशिल्पियों को प्रशिक्षण की सुविधाऐं उपलब्ध करानी होगी। कुटीर उद्योगों को बड़ी ईकाईयों के विरूद्ध सुरक्षा प्रदान करना होगी।

गांधीजी ने अपने आर्थिक विचारों के अंतर्गत श्रम का सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। उनके अनुसार व्यक्तियों को धन के पीछे नहीं भागना चाहिए बल्कि एक ऐसी आर्थिक प्रणाली का विकास करना चाहिए कि ऐसा लगे कि श्रम ही धन है न कि धातु का सिक्का।

भारत जैसी अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में आज निर्माण हुई आर्थिक समस्याओं का हल केवल गांधीजी के विचारों को स्वीकारने से ही हो सकता है। आज हमारे गांव उजड़े हुये तथा कुडे कचरे के ढ़ेर बने हुए है। जहां रोजगार की संभावनायें कम हो रही है और वे शहरी गुलामी का शिकार हो रहे है। बहुराष्ट्रीय निगमों ने ग्रामीण उद्योगों को क्षति पहुँचाई है। गांधीजी के विचारों के अनुसार गांव में कृषि से जुड़े उद्योग चलाये जाते है तो कृषि की निर्भरता कम होगी। भारत में सामाजिक न्याय और समता प्रस्थापित करनी है तो ग्रामीण क्षैत्र का विकास करना होगा। जिसमें लोगों को दो वक्त की रोटी की चिंता नहीं होगी तो गुनहगारी भी कम होगी। एक शोषण मुक्त समाज हेतु महात्मा गांधी के आर्थिक विचारों का सर्वाधिक महत्व है। आर्थिक व सामाजिक समस्याओं से जूझने के लिए गांधीजी की ग्राम स्वराज्य की विचारधारा की उपयोगिता बढ़ गई है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. एस. कुमार, दिप्ती शर्मा – महात्मा गांधी–अुर्जन पब्लिशिंग हाउस।
2. रूद्र दत्ता – भारतीय अर्थव्यवस्था, एस. चंद कंपनी दिल्ली।
3. शर्मा मुकेशकुमार – आर्थिक के गांधीवादी मॉडेल की प्रासंगिकता।
4. रामजी सिंह – गांधी और मानवता का भविष्य।
5. मिश्रा डॉ. एम.के. दाघीच डॉ. कमल – गांधी का आर्थिक चिंतन, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस।
6. गांधी मोहनदास करमचंद – हिन्द स्वराज – नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद।

****

विकासशील भारत में भ्रष्टाचार का स्वरूप एवं निदान

डॉ. अलका भार्गव *

प्रस्तावना – भारत एक विकासशील देश है, दूसरा यहाँ विभिन्न संस्कृतियाँ है। इन दोनों ही बातों को आधार मानकर हम भारत में प्रशासनिक स्तर पर भ्रष्टाचार के स्वरूप पर बात करेंगे।

यहाँ विकासशील शब्द से तात्पर्य है कि वर्तमान में अधूरे विकास की स्थिति स्थाई नहीं है विकास का क्रम निरन्तर जारी है भारत ब्रिटिश साम्राज्य का अंग रहा है। विकास भी यहीं से प्रारंभ हुआ है। एशिया के लोगों की उन सांस्कृतिक विशेषताओं, जिनका राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर प्रभाव पड़ता है, के संबंध में का कथन है – कि एशिया के देशों में व्यक्तिगत सबंध अत्यधिक महत्व के होते हैं लोगों को समान न मानकर कई मानकों के आधार पर एक लम्बे पदसोपान में वर्गीकृत किया जाता है। भौतिक सुख के स्थान पर आध्यात्मिक कल्याण को अधिक महत्व दिया जाता है।[1]

उपरोक्त पृष्ठभूमि में हम देखें तो विकासशील देशों में पूंजीवाद बढ़ रहा है। समाज का पुराना ढाँचा विघटित हो रहा है। विकास के चरणों को कम से कम समय में पूरा करने के प्रयास किये जा रहे हैं। उत्पादन के सामंती तथा पूँजीवादी तरीकों का एक प्रकार से मिश्रण हुआ है। कृषि अर्थव्यवस्था का आज भी आधार है। सरकारी मशीनरी समाज की ज्यों की त्यों स्थिति बनाये रखने तथा सम्पत्ति के वर्तमान सम्बन्धों को ज्यों का त्यों बनाये रखने के पक्ष में है। राष्ट्रीय नेतृत्व एक ओर भूमिपतियों, बड़े किसान तथा दूसरी तरफ पूँजीपतियों के बीच संतुलन बनाये रखने का कार्य करता है।

इन वर्गो के हित में नौकरशाही द्वारा श्रमिक वर्ग को दबाकर, कानून और व्यवस्था को बनाये रखना है।[2]

भ्रष्टाचार तथा एकाधिकार के विकास पर बहुत कम रोक है। भारत में समाजवाद के नाम पर सरकार के कार्यो में बहुत बढ़ोतरी हुई है किन्तु यह समाजवाद केवल नाम मात्र का है। वास्तव में इससे सरकार की शक्ति में केन्द्रीयकरण का विकास हुआ है।[3] फलस्वरूप सामंती समाज की भाँति अधिकारियों अथवा कर्मचारियों का एक ही समूह बिना किसी विभेदीकरण के राजनैतिक, प्रशासनिक, धार्मिक तथा आर्थिक सभी प्रकार के कार्यो को करता चला जाता है। ऐसी स्थिति में भ्रष्टाचार का पनपना स्वाभाविक है।

यहाँ आधुनिकीकरण की जो प्रक्रिया अपनाई गई है वह पश्चिमी नमूने की है पश्चिमी मॉडलों के नमूनों पर बनाये गये संस्थान तथा देशी पम्परागत संस्थान साथ-साथ रहते हैं। इस प्रकार विषमजातीय जटिल नमूना बन जाता है। इनमें नये नमूने केन्द्र तथा समाज के उच्च स्तरों पर अधिक अच्छे तरीके से पनपते हैं, तथा परम्परागत नमूने ग्रामीण, भीतरी प्रदेशों और समाज के निम्न स्तरों पर अधिक सशक्त रूप से प्रचलित रहते हैं। इस कारण भी भ्रष्टाचार को बल मिलता है।[4] क्योंकि यह मिश्रण न तो पश्चिमी है और न पूरा परम्परागत, वरन व्यक्ति हित में संचालित होने से स्वाभाविक रूप से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है।

इस विषय में रिग्स का कथन है कि, विकासशील देशों को विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में परिवर्तन की गति एकसार नहीं होती। लोक प्रशासन की प्राविधि में विकास जितना तेजी से हो पाता है उतनी तेजी से राजनैतिक संस्थानों जैसे- राजनैतिक कार्यकारिणी, विधान मण्डल, चुनाव प्रणालियों आदि में नहीं हो पाता इसका परिणाम यह होता है कि विकासशील समाजों में नौकरशाही अधिक प्रभुत्वशाली बन जाती है,और यह केवल प्रभाव का उपयोग करती है। जिसके बहुत गंभीर परिणाम होते है।[5] रिग्स का कहना है कि राजनैतिक पिछड़ापन नौकरशाही को भ्रष्ट बनाता है। कहा भी गया है 'सत्ता पाय को न मदरायें'

फिर चूंकि आधुनिकीकरण में प्रशासन आगे निकल जाता है और राजनीति एवं समाज पर प्रभावी भी इसी वजह से हो जाता है। इसके कुछ कारण फेरल हेड्डी ने इस प्रकार बतायें है 'प्रशासन का मूल स्वरूप देशी न होकर अनुकरणात्मक है' अर्थात् प्रशासन का मूल ढाँचा अधिकतर विकासशील देशों में साम्राज्यवाद के अवशेष के रूप में आजादी के बाद अवस्थित रह जाता है, और फिर विकसित देशों का अनुकरण करने लगता है।

दूसरा नौकरशाही ऐसी घटनाओं पर बल देती है जो उत्पादनोन्मुख नहीं होती अर्थात् वे कार्यक्रमों के लक्ष्यों को छोड़कर अन्य लक्ष्यों को पूरा करने के लिये कार्य करती है यानि कुनबापरस्ती, भाई भतीजावाद, सरकारी पैसे का दुरूपयोग आदि करने लगती है।

इसका एक तीसरा 'नतीजा आकार और यर्थाथता के बीच विशाल भेद होता है अर्थात् कर्मचारियों की आवश्यकता से अधिक भर्ती और देश पर आर्थिक बोझ ज्यादा।'

इस तरह भाई भतीजावाद, पक्षपात, तथा भ्रष्टाचार विकासशील देशों के लोक प्रशासन में सामान्य सा लक्षण है, और भारत में यह उग्र है कारण यह है कि हमारे यहाँ पारिवारिक या रकत सम्बन्ध अभी तक बहुत सशक्त है जबकि पश्चिमी देशों में यह बहुत हद तक कम हो गये हैं।

दूसरा आधार संस्कृति है- और इस आधार पर भारत को देखें तो भारत में खण्डित राजनैतिक संस्कृति है तात्पर्य ब्रिटिश राजनैतिक संस्कृति को धीरे-धीरे देशी संस्कृति में ढालने का प्रयास कर रहे हैं, पर गति धीमी है, जब तक पूर्ण देशीकरण नहीं होता तब तक खण्डित राजनैतिक संस्कृति के स्वरूप का एक परिणाम यह होता है कि यदि एक अधिकारी जो समूह से संबंध रखता है अपने पद पर कार्य करते हुये किसी ऐसे नागरिक से लेनदेन करता है जो किसी अन्य धार्मिक, जातीय अथवा भाषा समूह के हों, तो उसके निर्णय की निष्पक्षता को संदेह से देखा जाता है। जो समाज षड़यंत्र, कबीलों की शत्रुता, बदले की भावना और पक्षपात के लिये अविश्वसनीय बिरादरी दबाव से भरा हो वहां जान पहचान का केवल रूख मात्र ही अवश्यसंभावी तौर पर पक्षपात के लिये संदेह पैदा कर देता है। जिसके परिणामस्वरूप पक्षपात होने

* प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (राजनीति विज्ञान) महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय उत्कृष्ट महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत

लगता है। इस सिन्ड्रोम का कठोर आरोहरण रात ही रात में नौकरशाही के न्याय के भवन को गिरा डालता है।[6]

इसके साथ ही सांस्कृतिक विभिन्नता ने इस वजह को और बढ़ाया है, इनके विपरीत अन्य राष्ट्रों में यह भाषा, जाति, धर्म की विविधता इतनी ज्यादा नहीं है जहाँ समन्वय, सामंजस्य, और एकीकृत व्यवस्था में विश्वास देखा गया उन्नति भी हुई, और भ्रष्टाचार निषिद्ध समाज भी हुआ है। हमारे देश में आजादी के 68 साल बीतने पर भी भ्रष्टाचार बढ़ा है कम नहीं हुआ है अत: इसके उपाय सोचने जरूरी है। हमारी समझ में।

1. पहला विकासशील देशों का स्वाभाविक भ्रष्टाचार, राजनैतिक संस्थाओं का आधुनिकीकरण करके कुछ हद तक दूर किया जा सकता है।
2. दूसरा विकासशील देशों में नौकरशाही के आकार के बजाय यथार्थता की वास्तविक आवश्यकता को ध्यान में रखा जाये।
3. देश में स्थित विविधता को प्रशासन स्तर पर न स्वीकारा जाये, प्रशासन की एक भाषा एक उद्देश्य व एक संगठित राष्ट्रीय भावना प्रधान हो।
4. चौथा पूरे देश में मीडिया - टेलीविजन, समाचार पत्र पत्रिकाओं की भाषा एक हो।

ताकि सार्वजनिक जीवन में समान जीवन मूल्य विकसित हो सके, तथा सामाजिक स्तर पर अपनी -अपनी संस्कृति के अनुसार रहने का आधार भी बना रहे।

जब तक हमारी समझ में ये क्रांतिकारी कदम भारत में नहीं उठेगें तब तक सुधार की संभावना कम रहेगी।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची :-

1. एम.पी. शर्मा एंव सडाना- किताब महल -पृ. 136
2. सत्यवेदा- एडिमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग सोसायटी- अजंता प्रकाशन-पृ. 89
3. उपरोक्त एडिमिनिस्ट्रेशन इन डेवललिंग सोसायटी- अजंता प्रकाशन- पृ.90-91
4. उपरोक्त एडिमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग सोसायटी- अजंता प्रकाशन- पृ. 123
5. के.के. पुरी- पब्लिक एडिमिनिस्ट्रेशन इन इण्डिया किताब महल इलाहाबाद पृ. 72-80
6. एम.पी. शर्मा एवं सडाना- किताब महल -पृ. 11

****

सौराष्ट्र विलय में सरदार बल्लभ भाई पटेल का योगदान

डॉ. पूर्णिमा शर्मा * अशोक कुररिया **

प्रस्तावना – सौराष्ट्र का इतिहास प्राचीन है। सौराष्ट्र की भूमि ने भारत को धार्मिक पुरूष दिये हैं और वीर योद्धा भी दिये हैं। भगवान श्री कृष्ण की द्वारका सौराष्ट्र में ही थी। भक्त सुदामा और नरसिंह मेहता सौराष्ट्र में ही जन्मे थे। वंदनीय पुरूष स्वामी दयानन्द सरस्वती सौराष्ट्र के ही सपूत थे। वीरांगना सती रणुकदेवी सौराष्ट्र की ही पुत्री थी और युग पुरूष महात्मा गाँधी का जन्म स्थल भी सौराष्ट्र में ही है। हिन्दू धर्म के चार मुख्य धर्मों में एक द्वारका सौराष्ट्र में समुद्र तट पर स्थित है तथा बारह ज्योर्तिलिंगो में से एक सोमनाथ में हैं। अशोक के अभिलेख गिरनार व जूनागढ़ में मिले है। इस प्रकार ऐतिहासिक, धार्मिक व राजनीतिक दृष्टि से यह क्षेत्र महत्वपूर्ण माना जाता है।

सौराष्ट्र में जूनागढ़, नवानगर, भावनगर, ध्रांगध्रा, पोरबंदर, मोरवी, गोंडल, जाफराबाद, बीकानेर, पालीताना, ध्रोल, लीम्बड़ी, राजकोट और बढवाण जैसे चौदह सलामी का अधिकार रखने वाले बडे राज्य थे। सत्रह अ – सलामी राज्य थे और 191 अन्य दूसरे छोटे राज्य या तालुके थे। इन राज्यों के कुल क्षेत्रफल 22000 वर्गमील क्षेत्रफल में लगभग 40 लाख की आबादी थी। इस क्षेत्रफल और आबादी में अलग–अलग हुकूमत वाले लगभग 860 घटक थे। एक राज्य के प्रदेश में अन्य 20 राज्यों के प्रदेश मिले होते थे। इसलिये कानून और व्यवस्था की रक्षा करना भी कठिन हो जाता था। ऐसी परिस्थिति में भारत की स्वतंत्रता के बाद तथा अंगरेज सरकार के पोलिटिकल विभाग का अन्त हो जाने के बाद रिक्त स्थान को यदि भरा न जाता, तो राजकाज और शासन व्यवस्था में कठिनाई पैदा हो जाती। इसलिए भारत सरकार के रियासती मंत्रालय ने यह जिम्मेदारी सौराष्ट्र के कमिश्नर के रूप में श्री एम.एम.बूच नामक एक आई.सी.एस. अधिकारी को सौंपी।

सौराष्ट्र की प्रजा राजनीतिक दृष्टि से जाग्रत थी। काठियावाड़ की राजनीतिक परिषद को वर्षों तक महात्मा गाँधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था। पहले छोटे राजा प्रजा द्वारा राज्य के खिलाफ चलाये जाने वाले आन्दोलनों को दबाने के लिये ब्रिटिश सरकार की मदद लेते थे, लेकिन बाद में छोटे–छोटे राज्यों की प्रजा की राजनीतिक लड़ाई में देश की समस्त जनता का तथा कांग्रेस का समर्थन और बल उसे प्राप्त हो गया। इससे वहां का वातावरण उग्र हो गया था और कुछ राज्य तो अपने प्रदेश में कानून और व्यवस्था की रक्षा करने में बिल्कुल असमर्थ हो गये थे। जैसे मूली नामक एक छोटा सा राज्य था। उसकी प्रजा ने जबरन राज्य के दफ्तरों, अदालतों, सरकारी इमारतों तथा जेलों पर अधिकार कर लिया था। इसी तरह ध्रागध्रा के किसानों ने ऐसा ही आन्दोलन खड़ा किया और राजा के महल की ओर प्रयाण करने की तैयार की। सरदार पटेल ने इस हिंसक और गैर जिम्मेदारी से किये जाने वाले आन्दोलन की कड़े शब्दों में निन्दा की और ध्रांगध्रा की प्रजा को सलाह दी कि उससे जिम्मेदार प्रजाकीय संस्था के द्वारा भारत से न्याय मांगना चाहिये।

इस प्रकार सौराष्ट्र के प्रत्येक राज्य में उत्तरदायी शासन तंत्र रचने की मांग प्रजा द्वारा की जाने लगी। भावनगर पहला राज्य था जिसने उत्तरदायी शासन तंत्र की मांग को महसूस किया। भावनगर के महाराजा इस विषय में मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु गांधीजी के पास गये। गांधी जी ने उन्हें सरदार पटेल के पास भेजा। सरदार पटेल ने महाराजा को सलाह दी कि आपको प्रजा की मांग स्वीकार करना चाहिये। यह निर्णय किया गया कि श्री बलवंतराय मेहता को मुख्यमंत्री बनाकर प्रजा के प्रतिनिधियों का मंत्रिमण्डल बनाया जाए। इसके अलावा गांधी जी राजा के लिये व्यक्तिगत खर्च की जितनी रकम तय कर दें उतनी रकम स्वीकार करने के लिये भावनगर के राजा तैयार हो गये।भावनगर के इस शुभारम्भ का सौराष्ट्र के सभी कार्यों पर गहरा प्रभाव पड़ा, परन्तु सरदार पटेल मात्र इससे संतुष्ट नहीं थे कि छोटे बडे राज्यों में उत्तरदायी प्रजातंत्र की स्थापना हो जाये वरन् वे चाहते थे कि समस्त सौराष्ट्र के राज्यों को मिलाकर एक संघ बना दिया जाये। रियासत मंत्रालय ने इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु एक योजना प्रस्तुत की थी जो इस प्रकार थी सौराष्ट्र के चार राज्य समूह रचे जायें– भावनगर, नवानगर, जूनागढ़ और ध्रांगध्रा। इन चार समूहों में सौराष्ट्र के सारे छोटे–छोटे राज्यों को मिला दिया जाये। परन्तु इसमें एक समस्या थी कि छोटे राज्य ऐसा मानते थे कि उनके साथ अन्याय हुआ है तथा बडे राज्यों को इससे लाभ होगा। इसके अलावा ये चार घटक प्रशासन को चलाने में भी सफल नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में सरदार पटेल को एकमात्र संभव मार्ग यही दिखाई दिया कि जूनागढ़ के साथ सौराष्ट्र का एक घटक रचा जाये, इस संबंध में सरदार पटेल ने सौराष्ट्र के नेताओं से स्वयं तथा श्री वी.पी. मेनन को भेजकर विचार विमर्श करके एक योजना बनाई। जिसके अनुसार सौराष्ट्र के छोटे – बडे सब राज्यों को मिलाकर संयुक्त सौराष्ट्र का एक घटक रचा जाये। दो लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि के चुनाव के आधार पर संविधान सभा की स्थापना की जाये। संविधान सभा जो नियम और कानून बनाये उसके अनुसार चुने गये प्रजा के प्रतिनिधियों की विधानसभा सम्पूर्ण उत्तरदायी राजतंत्र के सिद्धांत पर संयुक्त सौराष्ट्र का शासन चलाये। विधानसभा के बनाये हुए कानून कायदों के अनुसार राज्य का मुल्की विभाग और न्याय विभाग कार्य करें, भविष्य में यदि भाषावार राज्यों की रचना का निर्णय हों तो सौराष्ट्र का यह घटक उस राज्य में मिला दिया जाये। इस घटक के बने हुए राज्यों में एक मुख्य जिम्मेदार व्यक्ति (गर्वनर) के बदले तीन मुख्य व्यक्तियों की एक समिति रहेगी जिनमें नवनगर के राजा, भावनगर के राजा तथा तृतीय सदस्य होगा सलामी के अधिकार वाले अन्य बडे राज्यों द्वारा चुना गया प्रतिनिधि।

उपर्युक्त योजना भारत सरकार ने सौराष्ट्र के राजाओं के सामने रखी। 15 जनवरी 1948 को भावनगर में उत्तरदायी शासन का उद्घाटन सरदार पटेल द्वारा हुआ। इस अवसर पर सौराष्ट्र के सभी राजा इस योजना पर

* शोध निर्देशक (राजनीति विज्ञान) रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी (राजनीति विज्ञान) रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) भारत

विचार-विमर्श करने के लिये एकत्र हुए। इस योजना में इस बिन्दु पर विचार किया गया कि सौराष्ट्र की उन्नति और प्रगति किस प्रकार हो। भावनगर व ध्रांगध्रा के महाराजा तो सौराष्ट्र संघ हेतु सहमत थे, नवानगर के महाराजा ने भी भारत सरकार की इस योजना पर स्वीकृति दे दी। भावनगर के जाम साहब ने यह समझ लिया था कि संयुक्त काठियावाड़ का विकल्प रियासतों का विघटन होगा, जो या तो बम्बई में मिला दी जायेंगी या किसी दूसरे प्रकार से समाप्त कर दी जायेंगी। इस प्रकार आपसी विचार विमर्श के बाद, काठियावाड़ के शासक एक संघ बनाने के लिये सहमत हो गये। सलामी रियासतों के शासकों ने अपनी एक परिषद् बनाई और जाम साहब को रियासत का प्रथम अध्यक्ष या राजप्रमुख चुना। अन्य शर्तें एक प्रतिज्ञापत्र में लिखा ली गई, जिस पर सब शासकों ने हस्ताक्षर कर दिये। यह प्रतिज्ञापत्र एक आदर्श समझा जाने लगा और बाद में अन्य रियासत संघ ने भी उसका अनुसरण किया। प्रतिज्ञापत्र पर सलामी रियासतों और सलामी रियासतों के शासकों ने हस्ताक्षर किये परन्तु अर्ध अधिकार क्षेत्रीय एवं गैर-अधिकार क्षेत्रीय रियासतों और तालुके के शासकों से एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करने को कहा गया, जिसके द्धारा वे अपनी जागरों और तालुकों को संयुक्त काठियावाड़ रियासत में विलय करने के लिये सहमत हो गये। इसके पश्चात् राजाओं के प्रिवीपर्स की रकम तय की गई थी। जो इस प्रकार थी- पिछले तीन वर्ष की आय की जो औसत वार्षिक रकम थी उसमें से प्रथम पाँच लाख की रकम का 15 प्रतिशत, फिर दूसरे पाँच लाख अर्थात् दस लाख तक की रकम का 10 प्रतिशत और दस लाख से अधिक की रकम का 7.5 प्रतिशत देना तय हुआ, लेकिन किसी भी राजा को दस लाख से ज्यादा प्रिवीपर्स की रकम नहीं मिल सकती थी। इसके अलावा राजाओं की निजी सम्पत्ति, जमीन जायदाद, महल वगैरह के तथा अन्य अधिकार उसी तरह स्वीकार किये गये जिस तरह उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के मामले में स्वीकार किये गये थे। यह बात भी स्वीकार कर ली गई कि उन्हें मिलने वाली प्रिवीपर्स की रकम सभी प्रकार के कर से मुक्त होनी चाहिये। ये सभी बातें ब्यौरेबार निश्चित हो जाने के बाद और सौराष्ट्र के सभी राजाओं ने 23 जनवरी 1948 को सौराष्ट्र के संयुक्त राज्य के करार पर हस्ताक्षर कर दिये। इस अवसर पर श्री वी.पी. मेनन ने कहा कि - 'एक महीने पहले तक भी कोई शासक यह नहीं सोचता था कि उसे इतनी जल्दी अपनी रियासत और शासन से विदाई लेनी पडेग़ी। जो चीज इनके वंश में पीढी दर पीढ़ी चली आई थी और जिसे वे पवित्र समझते थे वह मानो निमेषमात्र में ही लोप गई थी, यद्यपि सभी अपने को साहसी, प्रसन्न दर्शाते थे फिर भी मानसिक वेदना की मोटी रेखाएं उनके चेहरों पर उभरी हुई थीं। न तो कटक में और न कानपुर में ही ऐसा दृश्य देखा था जैसा राजकोट में दिखा। यहाँ का दृश्य अन्तिम अंश तक हृदय द्रावक था और मेरे स्मृति पटल पर हमेशा अंकित रहेगा।'

सौराष्ट्र संघ की योजना से गाँधीजी बहुत प्रसन्न हुए, परन्तु वे यथार्थवादी थे, इसलिये श्री मेनन की सारी बातें सुनकर उन्होंने कहा था कि यह तो बड़ी जिम्मेदारी हमारे सिर पर आ गई है। सौराष्ट्र के संयुक्त राज्य की शासन व्यवस्था कुशलता से चलाने वाले कुशल शासक हमें कहाँ से मिलेंगे फिर वे बोले कि 'अच्छा अब सरदार को ही यह काम सौंपना होगा। वे ही व्यवस्था कर सकते हैं।'

संयुक्त काठियावाड़ संघ का शुभारम्भ सरदार वल्लभभाई पटेल ने जामनगर में 15 फरवरी 1948 को किया। जामसाहब को राजप्रमुख के पद की शपथ दिलाई गई। मुख्यमंत्री उछारंगराय ढेबर तथा मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की उस अवसर पर जवाहरलाल नेहरू ने जाम साहब का अभिनन्दन करते हुए कहा कि - 'सौराष्ट्र के भावी उत्कर्ष और प्रगति की दिशा में यह इस युग का सर्वोत्तम कार्य कहा जायेगा।' जाम साहब ने उस अवसर का अपने हृदय की भावना व्यक्त करते हुए कहा - 'कोई ऐसा न माने कि सौराष्ट्र के सब राजा राज्य करते थक गये थे इसलिये अथवा किसी धमकी से दबकर उन्होंने संयुक्त सौराष्ट्र की योजना स्वीकार की है। हमने इस उद्देश्य से यह योजना सहर्ष स्वीकार की है कि इससे समस्त सौराष्ट्र की प्रगति होगी, भारत देश की अखंडता स्थापित होगी और सौराष्ट्र की प्रजा की उत्तरदायी राज्य तंत्र की अभिलाषा पूरी होगी।'

नये संघ की राजधानी हेतु जामनगर व राजकोट में विवाद हो रहा था। इस समस्या को सुलझाने हेतु एक समिति नियुक्ति की गई। सभी बिन्दुओं को मद्देनजर रखते हुए यह निर्णय किया गया कि राजधानी राजकोट में ही रहेगी।

नवम्बर 1948 में एक पूरक प्रतिज्ञा पत्र तैयार किया गया। इस संयुक्त कठियावाड़ संघ का नाम परिवर्तित कर 'संयुक्त सौराष्ट्र राज्य' कर दिया गया। जनवरी 1949 में दूसरा पूरक प्रतिज्ञा पत्र तैयार किया गया, जिसमें जूनागढ़, माणाबदर, मांगरोल, बांतवा, बावरियावाड़ और सरदारगढ़ के सौराष्ट्र के साथ एकीकरण और उनका एक एकक में संगठन पूरा हुआ।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. पटेल राजवी, हिन्द के सरदार, पृष्ठ-270
2. मेनन वी.पी. दि स्टोरी आफ दि इंटीग्रेशन ऑफ इण्डियन स्टेट्स पृष्ठ-179-80
3. वही, पृष्ठ-181
4. गुजरात समाचार, दिनांक 16-01-48
5. हॉडा राजेन्द्र लाल, देशी रियासतों में स्वाधीनता संग्राम का इतिहास, पृष्ठ-262
6. व्हाईट पेपर ऑन इण्डियन स्टेट्स, पृष्ठ-50-51
7. मेनन वी.पी. दि स्टोरी आफ दि इंटीग्रेशन ऑफ इण्डियन स्टेट्स पृष्ठ-195
8. वही, पृष्ठ-195
9. संदेश, दिनांक 16-02-48

****

भारत - नेपाल सम्बंधों की एक झलक

डॉ. अनिल दीक्षित *

शोध सारांश – भारत–नेपाल के बीच शताब्दियों से भौगोलिक और सांस्कृतिक सम्बंध रहे हैं। 1947 से वर्तमान तक दोनों देशों के बीच उतार–चढ़ाव के सम्बंधों की कहावत चरितार्थ होती सी दिखाई देती है। क्यों कि राजशाही से लेकर लोकतंत्र के बीच में बहुत से दृष्टिकोणों की चाल समझ से परे दिखाई देती है। नेपाल की चीन के साथ बढ़ती मित्रता इस बात ही घोतक है कि भारत को अब नए सिरे से सम्बंधों की कहानी गढ़नी होगी। यदि भारत नेपाल की सम्प्रभुत्ता व स्वतंत्रता के बारे में तथा नेपाल भारत की सुरक्षा पहलुओं पर ध्यान देंगे तो दोनों के बीच मधुर सम्बंधों का विकास निरन्तर बना रहेगा। अत: निष्कर्षत: कह सकते हैं कि भारत–नेपाल सम्बंध मूलत: मित्रतापूर्ण रहे हैं लेकिन कभी–कभी मतभेदों के शिकार भी रहे है। मुख्य तौर पर चीन को लेकर दोनों के सम्बंधों में टकराव आया है, लेकिन दोनों ओर से संयम बरतने से स्थिति में सुधार हो गया है। अत: दोनों देशों के सम्बंधों के विकास से भविष्य में मित्रतापूर्ण सम्बंधों की कल्पना की जा सकती है।

कुंजी शब्द –ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं भौगोलिक समानताएं, प्रारम्भ सुखद एवं मैत्रीपूर्ण तरीके से होना, नेपाल का चीन की तरफ झुकाव से स्पष्ट है भारत से दूरियां बढ़ना, भारत–चीन युद्ध से दोनों देशों के बीच नए दृष्टिकोण का प्रारम्भ, 1980 के दशक के अंत में दोनों के बीच मतभेद बढ़ना, नेपाल द्वारा चीन से हथियारों का आयात, परमिट व्यवस्था लागू करना, नागरिक की समस्या तथा गुजराल सिद्धांत के आधार पर सम्बंधों में विकास आदि।

प्रस्तावना – भारत व नेपाल के बीच सदियों से गहन ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं भौगोलिक समानताएं रही है। दोनों देशों के बीच 1700 कि.मी. की खुली सीमा आपसी सामारिक महत्व का प्रतीक है। नेपाल की भौगोलिक स्थिति जहां एक और इसे भारत के लिए महत्वपूर्ण स्थिति वाला देश बना देता है, वहीं दूसरी ओर नेपाल का भू–बद्धय राष्ट्र होना इसे काफी हद तक भारत पर निर्भर बना देता है। चीन और भारत के मध्य स्थिति होने से यह अवरोधक राष्ट्र की भूमिका भी निभाता है। अत: दोनों देश एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखते है।

भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरुने 6 नवम्बर 1950 में भारत–नेपाल संबंधों के बारे में कहा था कि 'हम नेपाल की स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान करते है तथा उसका भला चाहते है। लेकिन एक बच्चा भी यह जानता है कि भारत में से गुजरे बिना कोई भी नेपाल नहीं पहुंच सकता। अत: अन्य किसी देश के नेपाल के साथ उतने धनिष्ठ सम्बंध नहीं हो सकते जितने भारत के। इसलिए हम प्रत्येक राष्ट्र द्वारा भारत व नेपाल के बीच स्थापित घनिष्ठ भौगोलिक एवं सांस्कृतिक सम्बंधों की स्वीकृति व सराहना चाहते है।'

भारत–नेपाल सम्बंधो की झलक उचित विश्लेषणों एवं चरणों में आए बदलावों के आधार पर देख सकते हैं –

- 1947 से 1955 तक दोनों देशों के बीच मित्रतापूर्ण सम्बंधों का युग कहा जा सकता है। जिसमें यथास्थिति का समझौता, भारतीय सेना में गोरखा जाति के लोगों की भर्ती समझौता, भारत–नेपाल के बीच 'शांति व मित्रता' की संधि, नेपाल की उत्तरी सीमा पर भारत ने सैनिक चौकियां स्थापित की ताकि तिब्बत व भूटान की ओर के दर्रो से नेपाल की सुरक्षा व्यवस्थित की जा सके। 1950 में भारत ने नेपाल में राणाशाही का अन्त करने में सक्रिय भूमिका अदा की। भारत ने समय–समय पर नेपाल की संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता दिलाने का भी प्रयास किया तथा अन्तत: 1955 में नेपाल को स्वतंत्र राज्य के रुप में इस अन्तर्राष्ट्रीय संगठन में सम्मिलित कर लिया गया।
- 1956 से 1962 का काल परिवर्तन का युग कहा जा सकता है। इसमें नेपाल का झुकाव चीन की तरफ देखा गया था। भारत के अथक प्रयासों के बाद नेपाल से सम्बंधों में दरार की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। मूलत: कारण स्पष्ट है –
- 1956 में नेपाल के प्रधानमंत्री ने चीन की यात्रा की।
- 20 सितम्बर, 1956 को चीन–नेपाल के बीच मैत्री संधि हुई।
- 1957 में चीन के प्रधानमंत्री चाउ–इन–लाई नेपाल आए।
- 5 अक्टूबर, 1961 को चीन–नेपाल के बीच सीमा सम्बंधी समझौता हुआ।
- 16 अक्टूबर, 1961 को चीन ने नेपाल को लहासा से काठमाण्डू तक की सड़क निर्माण करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की।

इस दौर में जहां एक ओर नेपाल ने चीन से घनिष्ठता का रुख अपनाया वहां भारत ने नेपाल के साथ सहजता से काम लेते हुए भविष्य में अच्छे सम्बंध बनाने का प्रयास किया यद्यपि यह सत्य था कि भारत–नेपाल के इस परिवर्तित रुप से नाखुश अवश्य था।

- 1963 से 1971 का काल दोनों देशों के बीच एक **नए दृष्टिकोण का प्रारम्भ** का युग कहा जा सकता है। 1962 में भारत से चीन का युद्ध के उपरान्त नेपाल के रवैये को देखते हुए भारत अधिक चिन्तित हो उठा। अत: यहीं से भारत ने नेपाल के साथ नए दृष्टिकोण की शुरुआत की और भारत ने नेपाल के बारे में ज्यादा संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाया। भारत और नेपाल के राजनेताओं व शासकों द्वारा एक दूसरे देशों में यात्राओं के ब्यौरे से सम्बंधों में नए दृष्टिकोण का आगाज दिखाई देता है।

भारत व नेपाल के राजनेताओं की यात्राओं का विवरण –

* सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) शासकीय कालिदास कन्या महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

(क) भारत के राजनेताओं की यात्राऐं –

1.	लाल बहादुर शास्त्री	गृहमंत्री	4–6 मार्च, 1963
2.	डॉ. राधाकृष्णन	राष्ट्रपति	4–8 नवम्बर, 1963
3.	इंदिरा गांधी	प्रधानमंत्री	4–7 अक्टूबर, 1966
4.	दिनेश सिंह	विदेशमंत्री	जून 1969

(ख) नेपाल के राजनेताओं की यात्राएं –

1.	महाराजा महेन्द्र	सम्राट	27–31 अगस्त, 1963
2.	सूर्यबहादुर थापा	प्रधानमंत्री	मार्च, 1966
3.	महेन्द्र कुमार भण्डारी	विदेशमंत्री	मई, 1969

इस दृष्टिकोण के अन्तर्गत भारत ने नेपाल द्वारा किसी महत्वपूर्ण विषय पर मतभेद रखने पर भी ज्यादा आपत्ति नहीं की। 1965 के भारत–पाक युद्ध के दौरान नेपाल का रुख तटस्थता का रहा।

- **1972 से 1979** का काल सामान्य सम्बंधों का युग रहा। दोनों देशों में सम्बधों को सुधारने के लिए सिंचाई, विद्युत, उद्योग तथा कृषि के क्षेत्रों में सहयोग के समझोतों पर हस्ताक्षर हुए। इस काल का सबसे विवादास्पद विषय नेपाल को **शांति क्षेत्र** घोषित करना रहा है। यह विषय आज भी भारत–नेपाल सम्बंधों में शंका पैदा कर देता है।
- 1980 से 1999 का काल उतार–चढ़ाव, परन्तु सुखद सम्बंधों का काल रहा। 1970 के अंतिम वर्षों में दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जिनका दक्षिण एशिया तथा भारत–नेपाल सम्बंधों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। सर्वप्रथम महाराजा वीरेन्द्र ने नेपाल में एक राष्ट्रीय जनमत संग्रह कराने की बात की जिसके आधार पर लोगों को अपने लिए प्रणाली चुनने का अवसर प्रदान किया जायेगा। इससे वहां प्रजातंत्र की बहाली की प्रक्रिया शुरु हुई जिसका भारत हमेशा पक्षधर रहा है। दूसरी 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया। इस मामले पर भारत व नेपाल में पूर्ण एकमत था कि इस समस्या का हल राजनैतिक तरीकों द्वारा निकाला जाय, सैनिक तरीकों से नहीं।

1980 के दशक के अंतिम वर्षों में दोनों देशों के बीच मतभेद बढ़ने लगे। वे विवादास्पद विषय थे –

- नेपाल द्वारा हथियारों का आयात।
- परमिट व्यवस्था लागू करना।
- नागरिकता की समस्या।
- व्यापार तथा पारगमन संधि पर विवाद।

इस समय के 3 महत्वपूर्ण तत्व इनके सुखद सम्बंधों में सहायक हैं – एक तो भारत व चीन के मध्य सुधरते सम्बंध, दूसरा दक्षिण के माध्यम से दक्षिण एशिया के देशों मे बढ़ता सहयोग तथा 1997 से भारत द्वारा गुजराल सिद्धांत के अन्तर्गत पड़ौसी राज्यों से सम्बंध सुधार की प्रक्रिया। अत: जब तक इस प्रकार की प्रवृत्तियां सुचारु रहेंगी, दोनों देशों के मध्य अच्छे सम्बंधों की कामना की जा सकती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. एस.डी. मुनि, इंडिया एण्ड नेपाल : टूआर्डज दॉ नेक्सर सेंचुरी नई दिल्ली, 1998, पृ. 142।
2. ईयरबुक ऑन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, 1987–88 नई दिल्ली, 1988, पृ. 181–196।
3. जवाहरलाल नेहरु, इंडियाज फॉरिन पॉलिसी : स्लेक्टिड स्पीचज, सितम्बर 1946 से अप्रेल 1961, नई दिल्ली, पृ. 436।
4. एस.डी. मुनि, इंडिया–नेपाल : द चेन्जिग रिलेशनशिप, नई दिल्ली 1992, पृ. 40।
5. ए.अप्पादोराय एवं एम.एस. राजन, इंडियाज फॉरेन पालिसी एण्ड रिलेशंज, नई दिल्ली 1985, पृ. 166।
6. एल.एस. बराल, इंडिया एण्ड नेपाल इंटरनेशनल स्टडीज, वाल्यूम 17, अंक 3–4, जौलाई–दिसम्बर 1978 पृ. 547।

****

भारत में जन आन्दोलन एवं संवैधानिक मर्यादायें

डॉ. कविता चौकसे *

प्रस्तावना– वैदिककाल से ही भारत में लोकतंत्र को सम्पूर्ण सम्मान प्रदान कर जन भावनाओं एवं जन आकांक्षाओं को शासन व्यवस्था में पर्याप्त भागीदारी प्रदान की गई हैं। विदथ, सभा एवं समिति जैसी वैदिक कालीन लोकतांत्रिक संस्थायें न केवल राजा को निर्वाचित करती थी, बल्कि राजकीय कार्यों का मूल्यांकन कर उन परनियन्त्रण रखने का कार्य भी सम्पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ करती थी। मौर्यकाल में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सर्वोत्तम स्वरूप प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण के रूप में दिखाई देता हैं जिसका वर्णन मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इण्डिका में किया हैं। स्वतंत्रता पश्चात् भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया गया, विगत 6 दशकों से भी अधिक समय सेभारतीय उपमहाद्वीप में भारत एकमात्र देश है जिसमें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था न केवल और अधिक मजबूत हुई हैं बल्कि उसने देश को विकास और स्थायित्व के नये मानदण्डों में स्थापित किया है।हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के इस सनातन कालीन सफलता के मूल में जन सहभागिता तथा जन नियंत्रण का प्रभावी महत्व है जिसका उद्भम एवं विकास जन आन्दोलनों के रूपमें देखा जाताहैं।

लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनआन्दोलनसिविलसोसायटी द्वारा सरकार पर नैतिक नियंत्रण स्थापित करने का सर्वश्रेष्ठ प्रयास होता है । प्रसिद्ध राजनीतिकचिन्तक आचार्य विष्णुगुप्त ने राजा के पथभ्रष्ठ होने पर प्रजा द्वारा उसे पदच्यु तक रहने का आह्वान किया था जिसका समर्थन कन्फ्यूशियस के विचारों में भी मिलता है। राज्य पर नैतिक नियंत्रण का सर्वप्रथम स्पष्ट उल्लेख प्लेटों ने रिपब्लिक में किया था जिसको व्यवहारिक एवं प्रचलित स्वरूप जॉन लोक ने दिया।भारतीय सन्दर्भ में महात्मा गांधी जयप्रकाश नारायण, अन्नाहजारे एवं राजगोपाल द्वारा जन आंदोलनों का सार्थक प्रयोग किया गया। भारतीय जनता के आदर्शो एवंविचारधारा, शासन व्यवस्था राजनीति संस्कृति एवं परिवेश तथा समकालीन इतिहास को प्रमाणित करने वाले जन आंदोलनों में महात्मा गांधी का चम्पारण सत्याग्रह एवं अहमदाबाद मिल मजदूर केस, सरदार वल्लभ पटेल का बारदोली आन्दोलन, सीमान्त गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान का खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती आन्दोलन, आचार्य विनोबा भावे का भुदान आंदोलन, जयप्रकाश नारायण का सम्पूर्ण क्रान्ति, अन्ना हजारे का RT। लाने तथा लोकपाल लाने हेतु तथा राजगोपाल के जनआन्दोलनमील के पत्थरसिद्ध हूये हैं।

भारत में महात्मागांधी, विनोबा भावे, जयप्रकाशनारायण, अन्ना हजारे एवं राजगोपाल द्वारा संचालित जनआंदोलन सक्षम नेतृत्व, संविधान मर्यादा, प्रजातांत्रिक मूल्यों, कुशल रणनीति तथा जन आकांक्षाओं एवं भावनाओं से परिपूर्ण थे। फलस्वरूप ये व्यवस्थागत खामियों को दूर कर शांतिपूर्वक अपने उद्देश्य को प्राप्त कर पाने में सफल हुये।भारत के जन आन्दोलनों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता इनका शांतिपूर्ण व मर्यादित होना हैं। जो विश्व में अन्यत्र कम ही देख ने को मिलते हैं । पिछले दिनों उत्तरी अफ्रीकी देशों में सम्पन्न जास्मीन क्रान्ति का स्वरूप हिंसात्मक रहा हैं जब कि चौरी चौरा में घटित हिंसात्मक घटना के कारण गांधीजी ने असहयोग आन्दोलन को वापस ले लिया था। साधनों की यही पवित्रता भारतीय संस्कृति व दर्शन को रेखांकित कर हमारी सनातन कालीन लोकतांत्रिक व्यवस्था को पावन एवं ग्राध्य बनाती हैं।

वर्तमान जन आन्दोलन के प्रचार प्रसार एवं प्रभावोत्पादक बनाने में सोशल मीडिया का महत्वपूर्ण योगदान हैं। सोशल मीडिया द्वारा संचालित ये जनआंदोलन केन्द्रीय नेतृत्व के स्थान पर अनेक समूहों एवं वर्गो द्वारा संचालित किये जा रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में उदारवादी उग्रवादी, क्रान्तिकारी, समाजवादी, वामपंथीतथा कृषक मजदूर संगठनोंआदि की अलग अलग भूमिका थी किन्तु उच्च आदर्शो, नैतिक मूल्यों तथा अंतिम उद्देश्य में समानता के कारण ये सभी विचार धारायें एक दूसरे के पूरक व सहयोगी थी। वर्तमान परिदृश्य में विचार करने पर हम पाते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत के निर्माण में प्रयासरत अन्नाहजारे, बाबा रामदेव, अरविन्द केजरीवाल तथा किरण बेदी एक मंच पर रहकर भी एक दूसरे के विरोधी के रूप में प्रचालित प्रसारित हो रहे हैं। सोशल मीडिया द्वारा संचालित ये जन आन्दोलन केन्द्रीय नेतृत्व के स्थान पर अनेक समूह एवं वर्गो द्वारा संचालित किये जा रहे हैं। फलस्वरूप संवैधानिक मर्यादाओं के अतिक्रमण का खतरा उत्पन्न हो गया हैं।

संचार माध्यमों द्वारा वर्तमान में सचालित जनआन्दोलनों से सर्वाधिक प्रभावित युवा वर्ग हैं। संक्रमणकालीन वर्तमान व्यवस्थात के युवावर्ग अनेक समस्याओं जैसे बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, नैतिक मूल्यों के पतन, आधुनिक व परम्परावादी समाजों के संक्रमण से ग्रसित हैं। इन समस्याओं के निराकरण में शासन, प्रशासन, सामाजिक, धार्मिक संगठनों की निराशाजनक भूमिका ने स्थिति की भयावहता को और भीषण कर दिया हैं। संसदीय परम्पराओं लोकतांत्रिक व्यवस्था तथा सामाजिक समस्याओं की वास्तविक से अनभिज्ञ युवालोक लुभावन नारों तथा विज्ञापन सामग्री से प्रभावित होकर नैतिक एवं संसदीय मर्यादाओं की अनदेखी कर रहा हैं। राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करने के पश्चात् प्रणब मुखर्जी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाना था बिल न भरे जाने के कारण काटे विद्युत कनेक्शन को गैर कानूनी तरीके से जोडना इसी के परिणिति हैं।

युवा शिक्षितवर्गो के इन जन आन्दोलन में अभी ग्रामीण, कृषक एवं मजदूर वर्ग की सहभागिता नगण्य हैं, जो हमारी जनसंख्या का एक बड़ा प्रतिशत हैं। यह वर्ग संचार माध्यमों के जरिये इन आन्दोलनों से परिचित तो हैं किन्तु इनकी मूल भावना व उद्देश्य से अनभिज्ञ हैं। जन संसद की मांग कर रहे जन आन्दोलन में इस वर्ग की भागीदारी से आरक्षण की मांग कर रहे हैं। गुर्जर आन्दोलन जैसे आन्दोलन का स्वरूप ग्रहण करने का खतरा उत्पन्न हो सकता हैं।

* (राजनीति विज्ञान) शासकीय महाविद्यालय, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) भारत

सिविल सोसाइटी, NGO'S, सरकार, राजनीतिज्ञों बुद्धिजीवियों, जनप्रतिनिधियों एवं मिडिया को राष्ट्रहित एवं जनहित में बौद्धिक मंथन करना चाहिए। किस तरह इन आन्दोलनों की दशा एवं दिशा को सार्थकता प्रदान की जाये।किस तरह जन आक्रोश, क्षोभ तथा पीडा से समस्या ग्रस्त सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण बदलाव लाया जाये जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर जन विश्वास कायम रहें तथा संवैधानिक मर्यादायें तार-तार होने के बजाय और मजबूत हो सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भारतीय शासन एवं राजनीति डॉ. पुखराज जैन एवं बी.एल. फड़िया।
2. आधुनिक भारत का इतिहास आर. सी. मजूमदार।
3. आधुनिक भारत का उद्य रोमिलाथा पर।
4. इण्डिया टूडे, प्रतियोगिता दर्पण (पत्रिका)।
5. दैनिक भास्कर, नई दुनिया (अखबार)।

****

भारत-पाक सम्बंधों में कड़वाहट की मुख्य जड़ - कश्मीर समस्या

डॉ. अनिल दीक्षित *

शोध सारांश – दुनिया के हर हिस्से में पाकिस्तान रोता फिरता है कि कश्मीर हमारा है लेकिन अब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का सच लोगों के सामने आने लगा है। वहॉ की आम जनता पाक सरकार और सेना के विरोध में उतर आई है। उन्होंने न केवल सरकार के विरुद्ध बल्कि भारत के समर्थन में – **पाकिस्तान से कहीं अच्छा है भारत** नारे लगाए। 68 सालों से कश्मीर का राग अलापने वाले पाकिस्तान को हासिल क्या हुआ ? कश्मीर तो मिला नहीं, उल्टे वह खुद आतंकवाद की आग में झुलसने को मजबूर हो गया। विकास के लिए कर्ज लेना तो ठीक है लेकिन गोला-बारुद के लिए उसे कर्जा कौन देगा ? पिछले शासकों की गलती का खामियाजा पाक नागरिक आज भी भुगत रहे हैं। पाक जमीनी हकीकत को समझे, मंथन करे कि बर्बादी का रास्ता चुनना है या अमन के रास्ते पर चलकर थोड़ा विकास करना है। दोनों देश आपसी कड़वाहट को भुलाकर प्रगति के मार्ग पर प्रशस्त हों यही जनता का सपना है।

कुंजी शब्द – कश्मीर समस्या एवं हथधर्मिता, आतंकवाद, परमाणु हथियारों की धमकी देना, सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दा उठाना पाक द्वारा, हुर्रियत नेताओं की शरण में जाना, पाक सेना के कहने पर चलना, युद्ध विराम का उल्लंघन, विश्व समुदाय के सामने पाक-साफ रहना।

प्रस्तावना – आजादी के 68 साल बाद भी जो देश अपने पैरों पर खड़ा होने की ताकत नहीं जुटा पाया उसके पीछे एक ही कारण सामने दिखाई देता है वह है कश्मीर समस्या। कश्मीर का भारत के लिए सामरिक महत्व है क्योंकि इसकी सीमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन और रुस से लगी हैं। इसके 5 मुख्य क्षेत्र है – जम्मू, कश्मीर-घाटी, लद्दाख, पहाड़ी जिले और आदिवासी क्षेत्र।

वर्तमान में विभाजन के बाद जम्बू, कश्मीर घाटी और लद्दाख भारत के नियंत्रण में हैं। आदिवासी क्षेत्र (आजाद कश्मीर) पाकिस्तान के नियंत्रण में है और पहाड़ी जिलों का नियंत्रण दोनों राष्ट्रों में विभाजित है।

भारत स्वतंत्र होने के बाद देशी रियासतों को यह मौका दिया गया था कि वे चाहे तो वे अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें अथवा भारत या पाकिस्तान में अपना विलय करें। कश्मीर के राजा हरीसिंह ने स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया, परन्तु एक माह के भीतर ही कश्मीर पर विलय हेतु दबाव डालने के उद्देश्य से पाकिस्तान कश्मीर को दी जाने वाली खाद्य सामग्री व ईधन की आपूर्ति को अवरोधित करने लगा। अक्टूबर 1947 में आदिवासियो की वेशभूषा में पाकिस्तानी सैनिकों ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया पाकिस्तानी सेना का सामना करने में विवश होकर राजा हरीसिंह ने कश्मीर के भारत में विलय की घोषणा कर दी। भारत ने विलय को स्वीकार करते हुए कश्मीर में सैन्य बल भेज दिया और यह वायदा किया कि **'जैसे ही कश्मीर आक्रमणकारियों से मुक्त हो जायेगा और वहॉ विधि एवं व्यवस्था की स्थिति स्थापित हो जावेगी, राज्य के भारत में विलय का प्रश्न जनमानस के संदर्भ द्वारा मिरर्धारित किया जायेगा'**। भारतीय सेना कश्मीर के शासक के वैधानिक आग्रह पर कश्मीर में विद्यमान है, जबकि पाक सेना 'आक्रमणकारी' है। दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध अवश्यम्भावी हो गया। ऐसी परस्थिति में भारत ने इस मामले को सुरक्षा परिषद में ले जाने का निर्णय लिया।

5 जनवरी 1949 को सुरक्षा परिषद ने अपने प्रस्ताव में अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण में कश्मीर में जनमत संग्रह, भारतीय सेना द्वारा कश्मीर की सुरक्षा के वैद्य अधिकार और पाकिस्तानी सेना की वापसी की बात कही गई। भारत ने शर्त मान ली लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया नतीजा यह हुआ कि संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव निष्प्रभावी हो गया और आज भी, अनेक व्यक्तियों एवं संगठनों के प्रयासों के बावजूद कश्मीर समस्या यथावत विद्यमान है। भारत-पाक के बीच हजारों बार वार्ता हुई लेकिन आतंकवाद के चलते किसी प्रकार की सफलता नहीं मिली।

भारत-पाक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वार्ता पर साफ किया, तयशुदा एजेंडे पर ही बातचीत होगी। हुर्रियत नेताओं से बात की पाकिस्तान की शर्तो पर एनएसए वार्ता नहीं होगी। पाक का रुख उफा सहमति के खिलाफ है। भारत ने अब गेंद पाकिस्तान के पाले में डाल दी है। उधर पाक विदेश मंत्रालय ने कहा था, कश्मीर विवादित क्षेत्र है। हुर्रियत से बात नहीं करने की भारत की सलाह नहीं मानेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरुप ने 21 अगस्त शुक्रवार 2015 को कहा, पाक एनएसए सरताज अजीज की अलगाव वादियों से मुलाकात को लेकर भारत गुरुवार को चेता चुका है। ऐसी मुलकात आतंकवाद का मिलकर सामना करने के उफा समझौते की भावना और निष्ठा के अनुरुप नहीं होगी। भारतीय एनएसए अजीत डोभाल से अजीज का मिलने का दिल्ली में कार्यक्रम है। 'उधर अलगाववादी नेताओं मीरवाइज उमरफारुख, शब्बीर शाह और सैय्यद अली, शाह गिलानी के घर के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई।'

भारत ने पाक से दो टूक कहा, एनएसए बैठक में सिर्फ आतंकवाद पर बात होगी न कि कश्मीर मुद्दे पर। किसी और पक्ष से बात बाद में की जा सकती है। उधर नवाज शरीफ की अध्यक्षता में हुई बैठक में पाक ने कहा, हुर्रियत को लेकर भारत की शर्त नहीं मानेंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की वेबसाईट पर जारी प्रेस रिलीज में लिखा है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लागू नहीं किए गए प्रस्तावों के मुताबिक कश्मीर विवादित इलाका है। भारत यात्रा के दौरान पाकिस्तानी नेतृत्व ने हमेशा हुर्रियत/कश्मीरी नेताओं से बातचीत की है। हुर्रियत के नेता ही कश्मीर के लोगों के सच्चे नुमाइंदे है।

भारत-पाक के बीच सफल वार्ता न होने देने के पीछे पाक सेना है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की मुलाकात रद्द होने के पीछे भी उसने बड़ी भूमिका निभाई है। पाकिस्तानी सेना को लेकर हमें चार अहम बातें समझ लेनी चाहिए।

* सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) शासकीय कालिदास कन्या महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

1. नवाज शरीफ भारत से बातचीत का रास्ता अख्तियार करना चाहते है लेकिन समझौते से पाक सेना का क्या फायदा ? पाकिस्तानी सेना का फायदा इसी में है कि भारत से दुश्मनी जारी रहे। पाकिस्तानी की कुल फंडिंग का 50 फीसदी से ज्यादा सेना को मिलता है।
2. पाकिस्तानी सेना पाक को अपनी अहमियत बताती रहती है कि हमारी वजह से आप लोग महफूज है।
3. पाक सेना का एक ही मकसद है कश्मीर समस्या की आग को सुलगा कर रखना। अगर अमन हो गया तो सेना का धंधा ही बंद हो जायेगा।
4. लश्कर-ए-तैयबा जैसे जिहादी संगठन पाक सेना ने चला रखे हैं, उनका पाक सेना पर दबाव रहता है। अगर कश्मीर में शांति हो गई तो वे पाक सेना के खिलाफ बगावत कर देंगे।

इन सभी बातों के मद्देनजर नवाज शरीफ शांति प्रक्रिया की जरुरत नहीं समझते। 91 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है पाक ने उफा वार्ता के बाद। पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बात-बात पर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दे रहे हैं। पाक के डॉन अखबार ने लिखा है कि परमाणु हथियारो की धमकी देने की जरुरत नहीं है। पाकिस्तान की नेशनल असेम्बली के कार्यवाहक अध्यक्ष, मुर्तुजा जावेद अब्बासी ने कहा कि दक्षिण एशिया में शांति और विकास के लिए भारत-पाक के बीच कश्मीर मसले को सुलझाना आवश्यक है। अब्बासी यहां संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में वैश्विक संसदीय सम्मेलन में बोल रहे थे। रेडियो पाकिस्तान के अनुसार, अब्बासी ने कहा कि अब समय आ गया है जब कश्मीर के लोग आत्म निर्णय करें। हाल के समय में जम्मू एवं कश्मीर सीमा पर भारत और पाक में तनाव बढ़ता जा रहा है। राज्य के एक तिहाई उत्तरी भाग पर पाक का नियंत्रण है और दो तिहाई दक्षिणी भाग पर भारत का नियंत्रण है।

मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य सम्बंध शुरु से ही संदेह की राजनीति से ग्रस्त रहे है। पाकिस्तान को हमेशा यह लगता रहा है कि विभाजन से असंतुष्ट भारत कभी भी विभाजन को समाप्त कर सकता है। फिर बांग्लादेश की दु:खद स्मृतियों को पाक कभी विस्मृत नहीं कर पाया। कश्मीर मुद्दा पहले से ही एक नासूर के रुप में दोनों देशों के मध्य विद्यमान है। इधर कुछ वर्षो में पाक समर्थित आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि ने दोनों देशों के सम्बंधों में और खटास भर दी है। आपसी बातचीत, समझ और सौहार्द्र तभी विकसित होगा जब दोनों देश परस्पर संदेह से मुक्त हो सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. नंदलाल-भारत-पाक सम्बंध।
2. पत्रिका समाचार पत्र : यआतंक ही मुद्दा वरना वार्ता बंद 22 अगस्त, 2015
3. न्यूयार्क टाइम्स अमेरिका (सम्पादकीय)-युद्ध हुआ तो भारत को ज्यादा नुकसान 19 अगस्त, 2015
4. मारुफरजा - फैसला सही, बात नहीं स्पाट लाइट, पत्रिका समाचार 24 अगस्त, 2015
5. पत्रिका इस्लामाद टॉक ऑफ वार डॉन सम्पा. 2 सितम्बर 2015।
6. सम्पादकीय, पत्रिका समाचार गीदड़ भभकी 8 सितम्बर, 2015।
7. मो. सैयद अतहर हुसैन देहलवी : सामने आने लगी हकीकत 2 अक्टूबर 2015

****

नारी शक्ति

डॉ. टी. एम. खान * प्रो. वीणा बरड़े **

प्रस्तावना – नारी वह सनातन शक्ति हैं, जो अनादि काल से उन सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करती आ रही हैं जिन्हे पुरूषो का कंधा संभाल नही पाता। नारी इस सृष्टि में विधाता की सबसे खूबसूरत नियामत हैं। नारी का स्वभाव हैं रिश्तों में जीना, रिष्तो को निभाना नारी को प्रकृति ने स्नेह, प्रेम, करूणा, दया, सहिष्णुता, धैर्य और वात्सल्य रूपी गुणो से सुशोभित किया हैं साथ ही दृढ़निश्चयी, साहसी, वज्र की भांति कठोरता दी हैं।

'यदि आपको विकास करना हैं तो महिलाओं का उत्थान करना होगा। महिलाओं का विकास होने पर समाज का विकास स्वत: ही हो जायेगा।' (नेहरू)

किसी भी देश में स्त्रियां समाज का घटक मानी जाती हैं। भारतीय संस्कृति महिला पुरूष समानता पर बल देती है। स्त्री को शक्ति स्वरूप माना गया हैं परन्तु सदियों से पितृसतात्मक सामन्तवादी सामाजिक ढ़ाचे में स्त्रियां धर्म, मान्यताओं, परम्पराओं और रूढ़ियों के नाम पर शोषण का षिकार रही हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक क्षेत्र में पुरूष वर्ग ने योजनाबद्ध तरीके से स्त्रियों को पीछे रखने का षड़यंत्र किया हैं। सात वचन, सात फेरे, सात जनम वाली कहावत कहकर हमेशा छला हैं।

'गांधी जी के अनुसार हमारे समाज में कोई सबसे अधिक हताश हुआ हैं तो वे स्त्रिया ही हैं इस वजह से हमारा अध: पतन हुआ हैं। स्त्री–पुरूष के बीच जो फर्क प्रकृति के पहले से हैं जिसे खुली आंखो से देखा जा सकता हैं उसके अलावा मैं किसी किस्म के फर्क को नही मानता।'

भारतीय समाज में नारी की स्थिति का मूल्यांकन विद्धानो ने अपनी–अपनी दृष्टि से किया। सभी ने इस तथ्य को स्वीकार किया हैं कि नारी उपभोक्ता हैं, तथा पुरूष उत्पादक, समाज में स्त्रियों की स्थिति भिन्न–भिन्न युगों मे भिन्न रही हैं इसका कारण सामाजिक व्यवस्था जिसमें पुरूषो का एकाधिकार, स्त्रियों को शिक्षा से वंचित करना हैं नारी जीवन कुरूतियों, रूढ़ियों, परम्पराओं, कर्मकाण्डों और पाखण्डो में उलझ कर रह गया।

समाज रूपी गाड़ी के नर और नारी दो पहिए है। गाड़ी को चलाने के लिए दोनो की भागीदारी बराबर होनी चाहिए यदि एक वर्ग को अधिक मान्यता देते रहे तो गाड़ी कभी भी पटरी छोड़ सकती हैं। मनुस्मृति स्त्री को पिता, पति तथा पुत्र के आश्रय में रहने पर जोर देते हैं। कर्मकाण्डो, अंधविश्वासो ने स्त्री को कभी भी स्वतंत्र इंसान माना ही नही।

नारी पुरूष के बराबर शारीरिक रूप से भले पुष्ट न हो, मगर पुरूष के समान कार्य करने में सक्षम हैं। महिलाएं घर की चार दिवारी तक ही सीमित नही हैं, बल्कि एक साथ अपने दो कर्तव्यों को निभा रही हैं। प्रथम वह अपने परिवार के प्रति और दूसरा समाज के प्रति।

भारतीय समाज में नारी को जला देना, कन्या को कोख में ही मार देना, नारी को पांव की जुती मानना, उसे पराया धन एवं महाठगीनी कहना समाज की पुरानी परम्परा हैं आज भी नारी का कमजोर, दयनीय एवं अबला रूप देखने को मिलता हैं। परम्परा से धार्मिक, सामाजिक विधि विधानो से लेकर शास्त्रों ने नारी की चार छबियां स्वीकार की हैं। जिसमें बालिका, युवती, प्रौढ़ तथा समग्र नारी हैं।

विकास के साथ ही नारी उत्पीड़न के क्षेत्र में वृद्धि होती जा रही हैं। महिलाओं के उत्पीड़न में जितना समाज दोषी हैं उतनी ही स्वयं महिलाएं भी। अपनी मानसिक दुर्बलता एवं हीन भावना के कारण वह विरोध नही करती हैं। महिलाओं के प्रति अन्याय के दो क्षेत्र हैं पारिवारिक मामले और दूसरा सामाजिक क्षेत्र। महिलाओं के लिए न्याय पाना कठीन अवश्य हैं लेकिन असंभव नही। महिलाओं के लिए स्वयं सेवी संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही हैं। महिलाएं शोषण, त्रिस्कार तथा कुप्रथा जैसी विसंगतियों का शिकार थी और हैं भी। महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा चाहे वह शारीरिक, मानसिंक, घरेलू या सामाजिक हो वह हिंसा में शामिल हैं जो रीति–रिवाज, परम्पराओं एवं प्रचलित रूढ़ीयों से जनमी हैं उन्हे रोकने के लिए प्रभावशाली कदम उठाए गए हैं। 08 मार्च को महिला दिवस, 18 जनवरी को महिला अत्याचार निवारण जागरूकता दिवस, 24 जनवरी को बालिका दिवस मनाकर महिलाओं को अपने अधिकारो के प्रति जागरूक किया जा रहा हैं।

वर्तमान में नारी उत्पीड़न एक चुनौती हैं, परिवार, समाज, रेलगाड़ी या कार्यक्षेत्र हो नारी असुरक्षित दिखायी देती है। सुबह का अखबार देखे या टी.वी चेनल खोलकर देखे हमें नारी के प्रति होने वाले अत्याचार, बलात्कार या शोषण की घटनाएं ही दिखायी देती हैं। हम विकास और उन्नति की बात करते हैं, चांद, तारो की चर्चा करते हैं लेकिन हमार संस्कृति, मर्यादा पर कलंक लग रहा हैं, उस ओर कम ही ध्यान जाता हैं बलात्कार एवं हिंसा रूपी आग ने चाहे वह साल दो साल की बच्ची हो या उम्र दराज महिला हो सभी को अपनी चपेट में ले लिया हैं।

नारी सुरक्षा के लिए अनेक कानून बने किन्तु नारी को सुरक्षा रूपी हथियार कभी मिला ही नही। नारी सुरक्षा का मामला 16 दिसम्बर 2012 में निर्भया काण्ड के बाद से अधिक चर्चा में आया, जिसमें कमेटी बनी, नया कानून बना, किन्तु नारी असुरक्षित ही रही। नारी सुरक्षा के लिए ठोस कदम की आवश्यकता हैं जिसके अन्तर्गत अपराध के प्रति लोगो की सोच में बदलाव। व्यक्ति की सोच में बदलाव परिवार के पालन पोषण, शिक्षा एवं पारिवारिक वातावरण के द्धारा हो सकता हैं विषेषकर बालको पर ध्यान देने की जरूरत हैं जिसमें माता–पिता को जागरूक बनाना होगा स्कूल, कॉलेज में गुरू ऐसी शिक्षा दे जिसमें वातावरण सात्विक बना रहे।

दण्ड विधान – कठोर दण्ड का प्रावधान हो अपराध करते वक्त डर की भावना हो। यदि व्यक्ति संस्कारी हैं अर्थात अच्छे परिवेश में पला बड़ा हैं तो

* प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) शासकीय महाविद्यालय, धामनोद, जिला- धार (म.प्र.) भारत
** सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) शासकीय महाविद्यालय, धामनोद, जिला- धार (म.प्र.) भारत

निश्चित ही बुरे कर्मो की ओर उसका ध्या नही नही जायेगा। वर्तमान में न्याय प्रक्रिया इतनी लम्बी खीच जाती हैं कि अपराधी का दण्ड से खोफ ही समाप्त हो जाता हैं कानून की लड़ाई में 5 से 10 प्रतिशत् तक मुश्किल से दण्ड पाते हैं। नारी को यदि पूर्ण सुरक्षा रूपी हथियार देना हैं तो दण्ड प्रक्रिया को कठोर एवं न्यायिक को समय सीमा में बांधना होगा साथ ही महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भारत में महिला अपराध - अंजली।
2. महिला एवं विकास - राजकुमार।
3. महिला सशक्तिकरण - निधि भारद्धाज।
4. महिलाओं के मौलिक अधिकार - रमा शर्मा।
5. हिन्दू महिलाओं के जीवन में धर्म का महत्व - निधि भारद्धाज।

****

महात्मा गांधी के समाजवादी विचार एक अध्ययन

डॉ. पी.के. चतुर्वेदी * डॉ. पुष्पलता मिश्रा **

प्रस्तावना – महात्मा गांधी ने सत्याग्रह और अहिंसात्मक जनमानस में अद्भुत संघर्ष के भाव जगाकर राष्ट्र को ब्रिटेन की दासता से मुक्त कराने में बहुत बडी भूमिका निभाई। उनके द्वारा प्रयोग में लाई गई संघर्ष की अनोखी पद्धति सारी दुनिया के लिए मिसाल बन गई तथा अहिंसा में आस्था रखने वाले लोगों को विचार करने और कार्य करने के लिए एक नया मार्ग प्रकाश में आया।

गाँधीजी ने केवल अहिंसात्मक प्रतिरोध का ही मार्ग नहीं दिखाया बल्कि उन्होंने अपने समय की प्राय:सभी समस्याओं का अपने ढंग से विश्लेषण किया तथा उनके हल भी सुझाए। उस समय विश्व में समाजवादी विचारों का बहुत जोर था। गांधीजी ने समाजवाद के संबंध में भी अपने महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किये है। सुप्रसिद्ध अमेरिकी पत्रकार श्री लुई फिशर को सन् 1946 में दिये अपने साक्षात्कार में गांधीजी ने कहा था–सच्चा समाजवादी तो मैं हूँ।

मेरे समाजवाद का अर्थ है सर्वोदय .... मैं अपने व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आजादी चाहता हूँ। सन् 1947 मैं उन्होने लिखा था समाजवाद एक सुन्दर शब्द है और जहां तक मुझे मालुम है, समाजवाद में समाज के सब सदस्य बराबर होते हैं। यहाँ न कोई नीचा होता है, न कोई ऊँचा। किसी व्यक्ति के शरीर में सिर सबसे ऊपर होने के कारण ऊँचा नहीं होता और न पैर के तल्वे जमीन को छूने के कारण नीचे होते है। जैसे व्यक्ति के शरीर के सब अंग बराबर होते हैं, वैसे ही समाजरूपी शरीर के सारे अंग भी बराबर होते हैं। यही समाजवाद है। यह समाजवाद स्फटिक की तरह शद्ध है। इसलिये उसे सिद्ध करने के साधन भी शुद्ध ही होने चाहिये। अशुद्ध साधनों से प्राप्त होने वाला साध्य भी अशुद्ध ही होता है। इसलिये राजा का सिर काट डालने से राजा और प्रजा बराबर नहीं हो जायेगे। और न मालिक का सिर काटने से मालिक और मजदूर बराबर हो जायेगे। हम असत्य से सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते। सत्यमय आचरण द्धारा ही सत्य को प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिये सत्य–परायण, अहिंसक और शुद्ध हृदय समाजवादी ही भारत और संसार में समाजवादी समाज स्थापित कर सकेंगे। जहाँ तक मैं जानता हूँ, संसार में कोई भी देश ऐसा नहीं है जो शुद्ध समाजवादी हो। उपरोक्त साधनों के बिना ऐसे समाज का अस्तित्व में आना असम्भव है।

भारतीय परम्परा में समाजवाद –गॉधीजी मानते थे कि सच्चा समाजवाद तो हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त हुआ है जो हमें यह सीखा गये है – सब भूमि गोपाल की है, इसमें कहीं मेरी और तेरी की सीमायें नहीं है। ये सीमाऐं इन्सानों की बनाई हुई हैं और इसलिये वे इन्हें तोड़ भी सकते है। आधुनिक भाषा में गोपाल यानी राज्य यानी जनता। यह बात सही है कि आज जमीन जनता की नहीं हैं। पर इस आदर्श को हम हिंसा का आश्रय लिये बिना भी प्राप्त कर सकते है।

संरक्षता सिद्धांत –गाँधीजी के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को विरासत में या उद्योग–व्यवसाय के द्धारा बहुत बडी सम्पत्ति प्राप्त हो जाय तो भी उसे यह नहीं मानना चाहिये कि सारी सम्पत्ति उसी की है। बल्कि उसे यही मानना चाहिये कि उस सम्पत्ति पर उसका इतना ही हक है कि वह इज्जत के साथ अपना जीवन गुजार सके। शेष सम्पत्ति पर राष्ट्र का हक है और उसी के हित के लिये उसका उपयोग होना चाहिये। समाजवादी, विशेष सुविधाएँ पाए हुए वर्गो को खत्म कर देना चाहते है जबकि गाँधीजी के अनुसार यदि ऐसे सम्पतिवान लोग लोभ और परिग्रह की भावना को कम करके स्वयं भी मेहनतकश बन जाऐं तथा स्वयं को उन लोगों के समकक्ष ही समझें तो इससे समाजवाद के लक्ष्य को वास्तव में प्राप्त किया जा सकता है।

गाँधीजी ने यह स्वीकार किया था कि इस प्रकार की पूर्ण ट्रस्टिशिप तो युक्लिड की बिन्दु की व्याख्या की तरह एक कल्पना ही है तथा उतनी ही अप्राप्त भी है। लेकिन उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि यदि कोशिश की जाय तो दुनिया में समानता की स्थापना की दिशा में अन्य किसी भी उपाय से जितनी प्रगति हो सकती है, संरक्षकता सिद्धान्त से उससे अधिक प्रगति हो सकती है साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि यदि लोग स्वेच्छा से ट्रस्टियों की तरह व्यवहार करने लगें तो यह अत्यंत प्रस्न्नता की बात है किन्तु यदि ऐसा नहीं होता तो राज्य के द्धारा भरसक कम हिंसा का आश्रय लेकर उनकी सम्पत्ति ले लेनी पडेगी। गांधीजी व्यक्तिगत तौर पर यह चाहते थे कि राज्य के हाथों में शक्ति का ज्यादा केन्द्रीकरण होने के बजाय ट्रस्टीशिप की भावना का विस्तार होना चाहिये। लेकिन यदि राज्य की मालिकी अनिवार्य हो तो कम से कम होना चाहिये।

समाज का समाजवादी ढाँचा – गाँधीजी का स्पष्ट मत था कि आजादी नीचे से शुरू होनी चाहिये। भारत का प्रत्येक गाँव आत्मनिर्भर होना चाहिये। लोगों की बुनियादी जरूरतें गाँव में ही और गाँव के लोगों के द्धारा ही पूरी हो जानी चाहिये। ग्राम स्तर का कारोबार गाँव के लोगों के हाथों मे ही होना चाहिये। गॉधीजी तो यहां तक कहते थे कि गाँव में इतनी ताकत होनी चाहिये कि वह सारी दुनिया के खिलाफ अपनी हिफाजत खुद कर सके। जिस समाज का हरेक आदमी यह जानता है कि उसे क्या चाहिये और इससे भी बढकर जिसमें यह माना जाता है कि बराबरी की मेहनत करके भी दूसरों को जो चीज नहीं मिलती है, वह खुद भी किसी को नही लेनी चाहिये, वह समाज जरूर ही बहुत उँचे दरजे की सभ्यतावाला होना चाहिये।

निष्कर्ष – इस प्रकार महात्मा गाँधीजी के समाजवादी विचारों का विशेषकर भारत में समाजवादी समाज की स्थापना करने की दृष्टि से असाधारण महत्व है। उन्होंने कहा था कि हम जिस चीज को चाहते है, उसकी सही–सही तस्वीर हमारे सामने होनी चाहिये। तभी हम उससे मिलती–जुलती कोई चीज पाने की आशा रख सकते है।

उन्होंने बहुत जोर देकर यह कहा था कि यदि हिन्दुस्तान के हर एक गाँव में पंचायती राज्य कायम हुआ तो मैं अपनी इस तस्वीर की सचाई साबित कर सकूँगा जिसमें सब से पहला और सबसे आखिरी दोनों बराबर होंगे या यों कहिये कि न कोई पहला होगा न आखिरी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. पंचायत राज्य – गाँधीजी।
2. रचनात्मक कार्यक्रम – गाँधीजी।
3. सर्वोदय – गाँधीजी।
4. हमारे गाँव का पुनर्निमाण – गाँधीजी।
5. ग्राम सेवा के 10 कार्यक्रम – जुगलराम दवे।
6. भूदान–यज्ञ –विनोबा।
7. गाँधजी के पावन प्रसंग – लल्लूभाई मकनजी।
8. बापू के जीवन प्रसंग – मनुबहन गाँधी।

* सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) शासकीय स्नातक महाविद्यालय, हाटपीपल्या, जिला–देवास (म.प्र.) भारत
** सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) शासकीय स्नातक महाविद्यालय, हाटपीपल्या, जिला–देवास (म.प्र.) भारत

An Analysis Of The Success Of Magadhan Imperialism (Upto The Reign Of Ashoka)

Dr. Preeti Prabhat *

Abstract - Magadha can be identified with the modern districts of Patna, Gaya, Nalanda and parts of Shahabad in the present day state of Bihar. It was the first to make a successful bid for supremacy and establish its suzerainty. The Magadhan kingdom began to grow during the sixth century B.C. itself. This process accelerated considerably under the Nandas and the Mauryas. Geographically, Magadha's location is such that it has in its vicinity large tracts of alluvial soil. Recent researches have suggested that accessibility to the iron mining areas in particular enabled Magadha to not only produce good weapons of warfare but also in other ways. It facilitated expansion of agrarian economy and thereby, the generation of substantial surplus, extracted by state in the form of taxes. This in turn enabled Magadha to expand and develop its territorial base. In this research paper an attempt has been made to analyse the causes responsible for the rise of Magadha from among the sixteen mahajanapadas and ten republican states of sixth century B.C.
Key word - Sixteen Mahajanapadas, Bureaucracy, Military organization, Unorthodox, Brahmanical.

Introduction - The age of the Buddha (6th century B.C) is noted for the formation of a large number of terrestrial states mostly located in northern India. Anguttara Nikaya informs about sixteen Mahajanapadas. The existence of so many states in the middle Gangetic zone and its periphery is supported by the finds of Northern Black Polished Ware, punch mark coins and craft activities. The great Magadha empire which the Nanda's had built survived them. The rise of Magadha to the zenith of political greatness may be attributed to many factors. Three important elements are mentioned as forming state—a taxation system, a professional army and a cadre of officials. Some scholars add judicial organ to the list. The ancient thinkers regarded the territory and fortified capital as important elements. Territory assumed great importance when people discovered its potentialities for regular food production and used it for permanent habitation.

The geographical position was indeed an important factor which contributed to its rise. Magadha lay at the centre of middle Gangetic plain. The alluvium, once cleared of the jungles, turned out to be very fertile. The heavy rainfall made the area productive even without irrigation. This naturally enabled the peasants to produce enormous surplus which could be mopped up by the rulers in the form of taxes. The kings of Magadha also benefited from the rise of towns and the use of coins. On account of trade and commerce in the north east India, the rulers could levy tolls on use of commodities and accumulate wealth. The enormous wealth enabled the rulers to maintain a vast army. The mighty Ganges with its feeders, the Son, the Gandak and the Gogra served as an admirable means of defence and communication both with the upper India and the sea. Rajagriha, the old capital surrounded by a group of five hills and Pataliputra at the junction of Ganges and the Son, were well protected by nature. The richest iron deposits were situated not far away from Rajagriha. The ready availability of the rich iron ores in the neighbourhood enabled the Magadhan kings to equip themselves with effective weapons which were not easily available to their rivals. The geographical situation of Magadha enabled it to effectively command the Uttarapatha which lay on the north of river Ganges, along the foot hills of the Himalayas. The river also came to be used as one of the main arteries connecting Magadha with different regions and making heavy transport along river possible.

Another important factor was the financial stability enjoyed by Magadha. The success of any state depends on its financial strength. Of these the revenue system is the most critical. Without a regular supply of resources in cash or kind it is not possible to maintain a central establishment comprising the King, or the ruling aristocracy, a professional army, the executive officers, the judicial officers. Hence it is said that the origin and growth of the system of taxation determined the rise and development of the state. The Nandas augmented the state's finances by introducing methodical collection of taxes by regularly appointed officials. The wealth of the Nandas became proverbial. The Greek writers and Mamulanar, the Tamil Sangam poet, allude to it. The Nandas built canals and carried out irrigation projects to augment their land revenue. It was under them that the possibility of an imperial structure based on an essentially agrarian economy began to germinate in Indian mind. The Mauryas took every conceivable measure to augment land revenues. New settlements were found to rehabilitate the

* Asst. Professor (History) Pt. Deen Dayal Upadhyaya Government P.G. College, Lucknow (U.P.) INDIA

decaying ones by drafting surplus population from over populated regions. The Sudras were for the first time helped by the state to settle down as farmers in these settlements. Over 150,000 thousand people from Kalinga were forced to settle in the new settlement. Often the cultivators were forced to raise two crops. Every possible measure was taken to prevent any possible decrease in the supply of labour. The Mauryas fostered trade by developing the means of communication and by making travel comfortable. The state exercised rigid control over trade and industry, which yielded huge profit, through a number of superintendents.

The success of Magadha was also due to its vast bureaucracy. The Mauryas had a large body of superintendents to attend the details of administration. The administrative system was backed by an elaborate system of espionage. There was a department of information and criminal intelligence manned by secret agents called the Gudha-purushas organized into special service under its own minister. The service was organized into two branches called the Samastha (stationery) and Sanchara (touring).

Magadha enjoyed a special advantage in military organization. The Mauryas in India maintained an army bigger than any other contemporary dynasty. According to Plutarch and Justin, Chandragupta Maurya overran the whole of India with 600,000 men, which is thrice the number of the infantry of the Nandas. Megasthenes puts the total number of the Mauryan army at 400,000. He also furnishes valuable information regarding the administration of the army. He says that the administration of the army was in the hands of a body consisting of thirty members who were divided in six boards of five members each. Each committee was in charge of one of the following departments—navy, transport and commissariat, infantry, cavalry, chariots and elephant corps. The tremendous increase not only in numbers but also efficiency together with coercive power of the State seems to have enhanced the prestige and glamour of the Mauryan kings. Kautilya maintained that the army existed because of the treasure, and that the territory of the state was won by the treasury and the army. It was Magadha which first used elephants on large scale in its war against its neighbors. Eastern part of the country supplied Elephants to the Magadhan rulers. The elephants were useful in storming fortresses and in marching over marshy and other areas which lacked roads and other means of communication.

The widespread use of Iron created conditions for the formation of large territorial states. Agriculture based on the use of iron ploughshare enabled the people to set up their farms and households and tied them down firmly to the soil. The extra product obtained as a result of using superior iron ploughshare was collected by rulers to meet their military and administrative requirements. The surplus could also be made available to the towns. The use of iron weapons helped the rulers to expand at the cost of neighbours. In the middle Gangetic plain iron was available in large quantities. The smiths were capable of putting more carbon in them and thus making tools lasting and more serviceable. The people developed the art of transplanting paddy. As a result of improved Iron tools and new methods of cultivation, production may have doubled. The farmers were, therefore, in a position to support their households and able to pay taxes.

Another factor responsible for the success of Magadhan imperialism was the unorthodox character of Magadha society. Magadha was inhabited by the Kiratas and Magadha who were held in low esteem by the orthodox Brahmins. But it underwent a happy radical admixture on account of the advent of the Vedic people. As it was recently Aryanised, it showed more enthusiasm than the kingdoms which had been brought under the Vedic influence earlier. It is quite possible that the Vedic polity by now had spent its force and it was now the turn of the sturdy people of the east, who were not much affected by the Aryan invasion, to play their part. It is rightly said that, 'the laxity of social restrictions imposed by the orthodox Brahmanical culture and the universal aspect of Buddhism and Jainism which found a congenial home in Magadha, must have considerably widened the political outlook of the region and contributed to make it the nucleus of a mighty empire'.

As a family, the Mauryas tended to favour the heterodox sects, although they never attacked Brahmanism. The impact of these sects and dissidents created conflicts in the social fabric and thereby tended to weaken the political dominance of Magadha. Asoka's Dharma was meant to ease social tensions and to bring all people together and give them a feeling of unity. Asoka's twelfth Rock Edict is a passionate appeal not only for toleration of all religious sects but also for developing a spirit of reverence for them. He himself set an example by honouring all sects and making gifts for them. He dedicated the Barabar Hill caves to the Ajivikas.

Conclusion - Thus, of all the states that flourished in the sixth century B.C. the kingdom of Magadha was the first to rise to the position of an imperial power. Magadha had certain natural advantages over the contemporaneous kingdoms. The situation of Asokan inscriptions prove that a major part of the Indian sub continent had come under the Magadhan suzerainty. The early Saisunaga kings Bimbisara, Ajatsatru and Nandas realized the potential of Magadha and established a strong Magadhan state which was turned into a mighty empire by the efforts of Mauryan kings Chandragupta Maurya and Asoka.

References :-

1. Altekar, A.S., State and Government in Ancient India, New Delhi.
2. Basham, A.L., A Cultural History of India, New Delhi.
3. Dikshitar,V.R.R, The Mauryan Polity, New Delhi.
4. Jha, D.N, Ancient India, New Delhi.
5. Mookerji, R.K, Local Government in Ancient India, Oxford, 1919.
6. Panikhar, K.M, Origin and Evolution of Kingship in India, Baroda, 1938.
7. Sharnma, R.S, Perspectives in Social and Economic History of Early India, New Delhi.
8. Tripathi, R.S, History Of Ancient India, New Delhi.

प्राचीन भारतीय वैदिक शिक्षण पद्धति

डॉ. नितिन सहारिया *

प्रस्तावना – 'अक्षण्वन्त: कर्णवन्त: सखायो मनोजवेष्वसमा बभूवु:'[1]– ऋग्वेद में वर्णित इस ऋचा का अर्थ है– विद्या मनुष्य की श्रेष्ठता का आधार है। विष्णुपुराण में वर्णित श्लोक तो अत्यन्त प्रचलित है जिसमें कहा गया है कि वास्तविक विद्या वही है जो मुक्ति का साधन हो, विद्या का दूसरा स्वरूप वह है जिसके द्वारा मनुष्य शिल्प–नैपुण्य प्राप्त करने में सफल होता है।[2] भारत में वैदिक युग से शिक्षा मनुष्य के सर्वांगीण विकास, संस्कृति के संच्चरण तथा मनुष्य के उत्थान के लिए आवश्यक समझी जाती रही है। प्राचीन शास्त्रकारों ने अनेक उपयोगी व्यवस्थाएँ दी हैं, जिनमें राज्य द्वारा अनिवार्य शिक्षा का प्रबन्ध न होने पर भी शिक्षा का व्यापक प्रसार हुआ। प्राचीन ऋषियों ने मानव–जीवन को जिन चार आश्रमों में बाँटा था जिसमें पहला ब्रह्मचर्याश्रम, विद्याभ्यास के लिए ही था। ऋषियों ने ब्रह्मचर्य और उपनयन–संस्कार की व्यवस्था द्वारा समुचे समाज को शिक्षित करने का कार्य किया था। शिक्षा का महत्व ऐसा था कि समाज में स्नातक छात्र को राजा से अधिक सम्मान प्राप्त था। प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य समझा जाता था किवह न केवल पुत्र को जन्म देकर पितृ–ऋण से मुक्त हो, बल्कि शिक्षा देकर ऋषि–ऋण भी उतारे। राजाओं ने अपने उदार दानों से नालन्दा, विक्रमशिला, उदन्तपुरी–जैसे शिक्षणालयो के विकास में पूरी सहायता दी, यही कारण था कि प्राचीन काल में जितनी साक्षरता भारतवर्ष में थी, उतनी अन्यत्र नही थी। प्राचीन शिक्षा–पद्धति से भारत ने न केवल लाखो वर्षो तक मौखिक परम्परा द्वारा विशाल वैदिक वाड्मय को ही सुरक्षित रखा अपितु दर्शन, न्याय, गणित, ज्योतिष, वैद्यक, रसायनादि शास्त्रों में ऐसे मौलिक विचारक विद्धान् उत्पन्न किए, जिनसे भारतवर्ष का मस्तक आज भी उँचा है।

विद्यारम्भ – द्रविष्णुपुराण का कथन है कि शिक्षार्थी को उपनयन–संस्कार से सुसंस्कृत होने के उपरान्त विद्याध्ययनार्थ गुरू–गृह का आश्रय लेना चाहिये।3 अथर्ववेद से ज्ञात होता है कि उस समय ब्रह्मचर्य–पद्धति प्रचलित थी। ब्रह्मचर्य का अर्थ वेदाध्ययन था। तपोमय ब्रह्मचर्य–जीवन का पालन करते हुए छात्र वेदाध्ययन करते थे। ब्रह्मचर्य का पालन स्त्री व पुरूष– दोनों के लिए आवश्यक था। यहाँ तक कि राजा और देवों के लिए भी अपने कर्तव्य–पालन के लिए ब्रह्मचर्य आवश्यक माना गया।[4]उपनयन–संस्कारोपरान्त ही श्रीकृष्ण और बलराम विद्या–लाभार्थ अवन्तिपुरवासी सान्दीपनी मुनि के यहॉ गये थे।[5]उपनयन का अर्थ है समीप जाना। इस संस्कार द्वारा बालक गुरू के समीप जाकर, विद्याभ्यास के लिए शिष्य बनता था। पौराणिक व्यवस्थाएँ यह बताती हैं कि प्राचीन भारत में शिक्षा–पद्धति के आरम्भ का समय बाल्यकाल ही मान्य था। स्मृतियों में स्थान–स्थान पर प्रस्तुत प्रसंग पर बल दिया गया है।[6] हितोपदेश में भी वर्णित है कि बालकों पर नीति–उपदेश द्वारा उसी प्रकार प्रभाव डाला जाता है, जैसे नवीन भाण्ड को आकार देने से पूर्व शुद्धीकृत किया जाता है।[7]

गुरू–शिष्य–उपनयन–संस्कार के बाद ब्रह्मचारी गुरू से विद्याध्ययन करता था। विद्याध्ययन–काल में ब्रह्मचारी को अनेक आवश्यक नियमों का पालन करना पड़ता था। प्राचीन शिक्षा–पद्धति का आदर्श सादा जीवन और उच्च विचार था, अत: सभी नियम इसी को ध्यान में रखकर बनाए गये थे।8ब्रह्माण्डपुराण में वर्णन आता है कि गुरू गुणवान् शिष्य पर अनुग्रह दिखाता है9 तथा गुरू के उपदेश अच्छे शिष्य के कान में प्रवेश करते हैं।[10] कच के विषय में निरूपित है कि उसके शील, दाक्षिण्यादि गुणों से तुष्ट होने पर ही शुक्र ने उसे अपना शिष्य बनाया था शिष्य के लिए कहा गया है कि उसे शील आदि निर्मल गुणो से संपन्न होकर गुरूगत ज्ञान के ग्रहणार्थ प्रयत्नशील रहना चाहिये।[12] शिष्य को कठोरता से ब्रह्मचर्य के नियमो में संयम और सदाचार की शिक्षा पर बल दिया जाता था। पुराणों में विद्या की साधना और ब्रह्मचयसर्स में अभिन्न संबंध बताया गया है।[13] विष्णुपुराण में विहित है कि गुरू के आश्रम में ब्रह्मचर्या में बाधक कार्य कदापि नहीं करना चाहिये।[14] मनुस्मृति में भी विद्याध्ययन–काल में ब्रह्मचर्या ब्रह्मचारी का परम कर्तव्य माना गया है।[15]

कई स्मृतियों में यह व्यवस्था मिलती है कि ब्रह्मचारी प्रतिदिन अपने लिए गाँव से भिक्षा माँगकर लाये। अथर्ववेद में भी भिक्षाचरण का उल्लेख मिलता है।[16] यहाँतक की उस समय की सामाजिक व्यवस्था भी इसी के अनुरूप चलती थी। विष्णुपुराण में यह उल्लेख आया है कि भोजन से पूर्व गृहस्थ को भोज्य–पदार्थ विद्यार्थियों को प्रदान करना चाहिये।[17] विद्यार्थी की भिक्षावृत्ति में कर्तव्य–भावना प्रबल थी। समाज से भिक्षा प्राप्तकर वह समाज के प्रति अपने कर्तव्य का अनुभव करता था। लेकिन साथ ही साथ बाद के काल में कुछ ऐसी व्यवस्था की गई थी शिष्यों को भिक्षा के लिए समाज पर निर्भर नही रहना पउ़ता था। नालन्दा, बल्लभी, तक्षशिला–जैसे बडे विश्वविद्यालयों में, जहाँ हज़ारों विद्यार्थी पढ़ते थे, भिक्षा–वृत्ति सम्भव ही नही थी। नालन्दा की खुदाई में कुछ भट्ठियाँ मिली हैं। ह्वेनत्सांग (युवान–त्सांग :602–664) ने लिखा है कि भारतीय विद्धानो के गम्भीर पाण्डित्य का एक कारण यह है कि उन्हे भोजन,वस्त्र तथादवाई की चिन्ता नहीं करनी पड़ती।18 भिक्षा की व्यवस्था समाज को भी इस कर्तव्य का बोध कराती थी कि नयी पीढ़ी की शिक्षा के लिए उसे यत्न करना चाहिये। विष्णुस्मृति में इस बात का वर्णन है कि ब्रम्हाचारी, यति और भिक्षु–गृहस्थाश्रम से ही जीवित रहते हैं। अतएव गृहस्थ को ऐसे अभ्यागतों का अपमान नहीं करना चाहिए।[19]

भारत में गुरू–शिष्य परम्परा वैदिक शिक्षा का आधार रही है। मनु ने गुरूओं के तीन विभेद किए हैं– 1. आचार्य, 2. उपाध्याय और 3. गुरू।[20] यथा–

'उपनीय तु य: शिष्यं वेदमध्यापयेद्विज: ।
सकल्पं सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचक्षते ।।'21

अर्थात् 'जो ब्राह्ण शिष्य का उपनयनकर यज्ञ, विद्या एवं उपनिषद् के सहित वेद पढ़ाए, वह 'आचार्य' कहलाता है।'

* शासकीय एम.एम. महाविद्यालय, कोतमा, जिला -अनूपपुर (म.प्र.) भारत

'एकदेशं तु वेदस्य वेदांगान्यपि वा पुन: ।
योऽध्यापयति वृत्यर्थमुपाध्याय: स उच्यते।।'[22]

अर्थात् 'जीविका के लिए जो वेद के एक भाग या वेदांगों को पढ़ाता है, वह 'उपाध्याय' कहलाता है।'

'निषेकादीनि कर्माणि य: करोति यथाविधि।
संभावयति चान्नेन स विप्रो गुरूरूच्यते।।'[23]

अर्थात् 'जो विप्र निषेकादि कर्मो को विधिपूर्वक करता है और दूसरे उपायों से सम्मानित बनाता है, वह 'गुरू' कहलाता है।'

शिक्षक के इन तीनों भेदों में शिष्य को पूर्ण विद्वान् बनाने की प्रवृत्ति है। शिक्षक में केवल इतनी ही बात आवश्यक नहीं है कि वह शिष्यों को जिस किसी भाँति शास्त्रीय ज्ञान से परिचित या संयुक्त कर दे, अपितु उन उदात्त वृत्तियों को जीवन के साँचे में ढालने की श्रद्धा भी उनमें पैदा कर दे, जिससे ज्ञान और क्रिया का संयोग हो जाए।[24] भारतीय धर्मशास्त्रों और पुराणो में वैदिक शिक्षा-पद्धति के जो वर्णन आते हैं उनमें गुरू की तुलना स्वयं भगवान् से की गई है। मत्स्यपुराण में आचार्य को ब्रह्मा की मूर्ती कहा गया है।[25] ब्रह्माण्डपुराण में गुरू को साक्षात् शिव कहा गया है जो ज्ञान बाँटने के लिये पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं।[26]

प्राचीन शिक्षा-पद्धति की एक बड़ी विशेषता गुरू और शिष्य का सुमधुर पारिवारिक संबंध था। शिष्य गुरू के घर जाकर उसके परिवार का सदस्य बनकर रहता था।गुरू अपने पुत्र की तरह उसका पालन करता था। महात्मा बुद्ध ने कहा था, 'गुरू को चाहिए कि वह शिष्य को पुत्र समझे और शिष्य को उचित है कि वह गुरू को पिता माने।' पुराणों में गुरू को अभिभावक कहा गया है। ब्रह्ाण्डपुराण में निरूपित है कि शिष्य को गुरू और गुरू-पत्नी को माता-पिता की दृष्टि से देखना चाहिए।[27]प्राय: गुरू के पास 10-15 शिष्य होते थे और वह न केवल इनके अध्ययन, अपितु खान-पान और चिकित्सा की भी पूरी चिन्ता करते थे। महात्मा बुद्ध ने उपाध्याय के लिए यह नियम बनवाया था कि वे अपने शिष्यों की देखभाल, उनके वस्त्रों तथा भिक्षापात्रादि का ध्यान रखें। सातवीं शती में भारत आनेवाले चीनी यात्री इत्सिंग (673-695) के विवरण से यह ज्ञात होता है कि वे इस नियम का पूरा पालन करते थे। जब शिष्य बीमार पड़ते थे, तो गुरू उनकी परिचर्या भी किया करते थे।[28] अथर्ववेद में आचार्य और शिष्य का बहुत ही सुन्दर वर्णन मिलता है। आचार्य के समीप ले जाए गए बालक को आचार्य उसी प्रकार धारण करता है, जिस प्रकार माता शिशु को गर्भ में धारण करती है। उस बालक को आचार्य तीन रात्रिपर्यंत अपने उदर में (समीप, आश्रम में) रखता, उसे शिक्षित करता, जिसे बाद में देवता देखने को आते।[29] मुण्डकोपनिषद् में स्पष्ट कहा गया है कि ब्रह्मज्ञ-गुरू समीप में आए हुए संयत, इंद्रियसम्पन्न, प्रशान्तचित्त शिष्य को तत्व के अनुरूप ब्रह्मविद्या का उपदेश दे।[30]

गुरू द्वारा शिक्षा देने से पूर्व शिष्य की परीक्षा का भी प्रसंग मिलता है। अयोग्य शिष्य को मंत्र देने पर देवता के अभिशाप की सम्भावना रहती है। यदि स्नेह या लोभवश अयोग्य शिष्य को दीक्षा दी जाती है तो गुरू और शिष्य-दोनों को अभिशाप लगता है। इसलिए शिष्य बनाने से पहले उसकी परीक्षा अवश्य करनी चाहिये। सारसंग्रह के अनुसार एक वर्ष शिष्य की परीक्षा का समय निर्धारित किया गया है। वर्ण के अनुसार परीक्षा-काल का भेद भी शारदातिलक में वर्णित है, यथा- ब्राह्मण का एक वर्ष, क्षत्रिय का दो वर्ष, वैश्य का तीन वर्ष और शूद्र का चार वर्ष। तंत्रराज में योग्य शिष्य के लक्षण बताए गए हैं, यथा- सुन्दर, स्वच्छ, सुलभ, श्रद्धावान्, निश्चित आशयवाला, लोभरहित, स्थिर-शरीर, ऊपापोह-कुशल (प्रेक्षाकारी), जीतेन्द्रिय, आस्तिक, गुरू मंत्र और देवता के प्रति दृढ़ भक्तिसम्पन्न शिष्य गुरू के लिए सुखप्रद होता है। आचार्यो ने त्याज्य शिष्यों का लक्षण भी बताया है। रूद्रयामल के अनुसार कामुक, कुटिल, लोकनिन्दित, असत्यवादी, अविनीत, असमर्थ, प्रज्ञाहीन, शत्रुप्रिय, सदा पापक्रिया में रत, वैदिक क्रिया से रहित, आश्रम के आचार से शून्य, सदा परस्त्रीआतुर, भक्तिहीन आदि निन्दाओं का पात्र शिष्य वर्जित माना गया है।[31]

इस प्रकार वेद, पुराणों और धर्मग्रन्थों में गुरू-शिष्य के विषय में विशद वर्णन मिलता है। गुरू की महिमा का वर्णन करते हुए मुण्डमालतंत्र में सम्पूर्ण विश्व को गुरूमय माना गया है।[32] कौलावलीनिर्णय में कहा गया है कि ब्रह्मा, पराशर, व्यास, विश्वामित्र आदि ने गुरूशुश्रूषा के कारण की सिद्धि-लाभ किया था। योगसूत्र में भी ईश्वर को गुरू-रूप में वर्णित करते हुए कहा गया है कि अनविछिन्नकाल से ही वह सभी का गुरू है।[33] इस प्रकार के महत्व के लिए गुरू शब्द से उनका अभिधान किया गया है। अनेक उपनिषदों में शिष्यों की गाथाएँ उपलब्ध हैं, जिनके द्वारा यह सिद्ध है कि सद्गुरू के समीप आत्मनिवेदन या शरणागति के द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान की उपलब्धि हो जाती है। पौराणिक और आधुनिक गाथाएँ भी इनका साक्ष्य वहन कर रही है।[34] गुरू-शिष्य के पावन संबंध के कुछ आदर्श युग्मक हैं- नारद-सनत्कुमार, भृगु-वरूण, श्वेतकेतु-उद्दालक, राम-वसिष्ठ, कृष्ण-सांदीपनि, युधिष्टिर-धौम्य अर्जुन-द्रोणाचार्य आदि।

पाठ्यक्रम-वैदिक शिक्षा में वेद प्रमुख थे जिनका पूर्ण ज्ञान गुरू के द्वारा शिष्यो को कराया जाता था। इसके प्रमाण मत्स्यपुराण में मिलते हैं जहाँ ऐसा वर्णन आया है कि वेद में प्रत्येक का अध्ययन कर विशिष्टता भी प्राप्त की जाती थी। विष्णुपुराण के अनुसार राम के राज्याभिषेक के अवसर पर कुलपुरोहित ऋक्, यजु और साम के द्वारा स्तुति कर रहे थे।[35] आरम्भिक वैदिक युग में मुख्य पाठ्य विषय वेदमंत्र[36], इतिहास[37], पुराण[38], और नाराशंसी गाथाएँ[39]थीं। यास्क के अनुसार वेद के विद्यार्थी को व्याकरण की पूरी जानकारी आवश्यक थी।[40] तैतिरीयोपनिषद् में वेदोच्चारण के लिए वर्ण, स्वर, बल, साम तथा सन्धान (सन्धि) पर उचित ध्यान देने का आदेश दिया गया है।[41] तदनन्तर धर्मशास्त्र[42], उपनिषद् व्याकरण, कल्प ज्योतिष, आयुर्वेद[43], धनुर्वेद[44], छन्द, निरूक्त तथा अनेक प्रकार के शिल्पादि वैदिक शिक्षा के पाठ्य विषय बने। छांदोग्योपनिषद् का वर्णन प्रसिद्ध है जिसमें नारद ने कहा है, 'भगवान! मैने वेद-वेदांग के अतिरिक्त इतिहास, पुराण, गणित, ज्योतिष, नक्षत्रविद्या, सर्पविद्या, दैव (भूकम्प, वायुकोपादि प्राकृतिक भूगोल अथवा भविष्यत्कथन की विद्या), निधि (खनिज-विद्या), वाकोवाक्य (तर्कशास्त्र), ब्रह्मविद्या, भूतविद्या (प्राणिशास्त्र), राजशासन-विद्या (सैनिक-विज्ञान तथा राजशास्त्र), एकायन विद्या (नीतिशास्त्र) का अध्ययन किया है।[45] स्त्री-शिक्षा का वर्णन भी मिलता है जिसमें उच्च शिक्षा में धर्म और दर्शन, ऐसी शिक्षा के ग्रहणार्थ कन्याएँ ब्रह्मचर्य-व्रत धारण करती थीं ओर व्यावहारिक शिक्षा में संगीत, कला, चित्रकला तथा गृहविज्ञान की शिक्षा प्रमुख थी। उन्हें युद्ध-कला में भी कुशल बनाने का उदाहरण प्राप्त होता है।[46]

बौद्ध-ग्रन्थ मिलिन्दपह में बौद्ध तथा ब्राह्मण-शिक्षा के पाठ्य विषयों का भी संकेत मिलता है। इसमें चतुर्वेद, इतिहासपुराण, छन्द, ध्वनि, पद्य, व्याकरण, ज्योतिष, खगोल, वेदांतिक षड्दर्शन, आकस्मिक घटनाओ के अध्ययन, अपसकुन, स्वप्न, कड़क तथा तारा टूटना, भूकम्प, ग्रहण, षड्रसायन, पक्षियों तथा जन्तुओं की बोलियाँ, संगीत, ओषधिविज्ञान, यंत्र-तंत्र, युद्धविद्या, कवित्व आदि शामिल हैं। विभिन्न कलाओं (शिल्पों)

की संख्या 17 थीं। हाथी,घोड़े, रथ, धनुष-वाण, तलवार आदि का विशेष ज्ञान अपेक्षित था। अंगुलियों की गाँठों के सहारे गणना करना, सामान्य गणना, उपज आदि का अनुमान लगाना, लेख पत्रलेखन, आदि विषय भी प्रचलित थे।[47]

प्राचीन भारतीय-शिक्षा में कलाओं की शिक्षा भी महत्वपूर्ण थी जिनका वर्णन पुराण, रामायण, महाभारत आदि काव्य-ग्रन्थों में प्रचुर मात्रा में मिलता है। शुक्राचार्य के नीतिसार नामक ग्रन्थ के चतुर्थ अध्याय के तीसरे प्रकरण में कलाओं के विभिन्न प्रकारों का वर्णन मिलता है जिनमें 64 कलाएँ मुख्य हैं। केलदि-नरेश श्रीबसवराजेन्द्रविरचित शिवतत्वरत्नाकर में 64 कलाओं का नाम-निर्देश इस प्रकार किया गया है-[48] 1. इतिहास, 2. आगम, 3. काव्य, 4. अलंकार, 5. नाटक, 6. गायकत्व, 7. कवित्व, 8. कामशास्त्र, 9. दुरोदर (द्यूत), 10. देशभाषालिपिज्ञान, 11. लिपिकर्म, 12. वाचन, 13. गणक, 14. व्यवहार, 15. स्वरशास्त्र, 16. शकुन, 17. सामुद्रिक, 18. रत्नशास्त्र, 19. गजश्वरथकौशल, 20. मल्लशास्त्र, 21. सूपकर्म (रसोई पकाना), 22. भुरूहदोहद (बागवानी), 23, गन्धवाद, 24. धातुवाद, 25. रससंबंधी खनिवाद, 26. बिलवाद, 27. अग्निसंस्तम्भ, 28. जलसंस्तम्भ, 29. वाच:स्तम्भन, 30. वय:स्तम्भन, 31. वशीकरण, 32. आकर्षण, 33. मोहन, 34. विद्धेषण, 35. उच्चाटन, 36. मारण, 37. कालवञ्चन, 38. परकायप्रवेश, 39. पादुकासिद्धि, 40. वाक्सिद्धि, 41. गुटिकासिद्धि, 42. ऐन्द्रजालिक, 43. अञ्जन, 44. परदृष्टिवञ्चन, 45. स्वरवञ्चन, 46. मणिमन्त्रौषधादिसिद्धि, 47. चोरकर्म, 48. चित्रक्रिया, 49. लोहक्रिया, 50. अश्मक्रिया, 51. मृत्क्रिया, 52. दारूक्रिया, 53. वेणुक्रिया, 54. चर्मक्रिया, 55. अम्बरक्रिया, 56. अदृश्यकरण, 57. दन्तिकरण, 58. मृगयाविधि, 59. वाणिज्य, 60. पाशुपाल्य, 61. कृषि, 62. आसवकर्म, 63. लाव-कुक्कुट-मेषादियुद्धकारक कौशल तथा 64. शुकसारिकाप्रलापन।

वैदिक शिक्षा के मूल उद्देश्य - मानव के दैनिक जीवन में ज्ञान, इच्छा तथा क्रिया का समन्वय रहा है। जीवन का प्रथम भाग ब्रह्मचर्य-ब्रतपालनपूर्वक विद्याध्न, द्वितीय भाग गृहस्थाश्रम, तृतीय भाग पुनर्शान्ति और निवृत्ति के अम्यासपूर्वक वन में निवास अर्थात् वानप्रस्थाश्रम और चौथा भाग ब्रह्मचिन्तन, एषणा-त्याग तथा ब्रह्मविलयन के लिए निर्धारित किया गया है। ब्रह्मचर्य ही मुख्यत: शिक्षा का विधान है; किन्तु यह शिक्षा केवल अक्षर-ज्ञान और पुस्तक पढ़नामात्र नहीं थी। ब्रह्मचर्य जीवन की एक निराली पद्धति है। प्राचीन भारत में शिक्षा जीवन की साधना मानी गई है जो जीवन के चरम लक्ष्य तक पहुँचने में साधक हो। गुरूकुल में निवास, गुरू-शुश्रूषा, ग्रन्थों का अध्ययन-अभ्यास, ब्रह्मचर्यव्रत-पालन, भिक्षाचर्या आदि ब्रह्मचारी के दैनिक जीवन के अभिन्न अंग हैं। महाकवि कालिदास ने रघुवंश में राजकुमार ब्रह्मचारियों के तपोमय जीवन का वर्णन किया है। भारतीय प्राचीन शिक्षा-प्रणाली का अनुसरण समाज के सभी अंग समान रूप से करते थे।[49]

धनवान्, धनहीन, राजा और रंग की शिक्षा में कोई भेद-भाव नही था। शिक्षा का क्षेत्र केवल धननिरपेक्ष ऋषियों के हाथ में था और ब्रह्मचारी के अध्ययनकाल में माता-पिता पर कोई आर्थिक बोझ नही पड़ता था। यह एक बहुत गम्भीर व ध्यान देने योग्य बात है कि भारत की प्राचीन शिक्षा न तो शासको के हाथ में थी ओर न राजनीतिक अथवा अन्य संसारी नेताओं के प्रभाव में। राजा हो या ब्रह्मचारी, विद्यार्थी की शिक्षा पर उसका कोई प्रभाव नही था। इसी कारण से लाखो वर्ष तक इस संस्कृति का लोप नही हुआ। शासक के हाथ से शिक्षा की बागड़ोर न होने से देश की संस्कृति के अनुरूप शिक्षा रहने में बाधा नहीं थी, इसी कारण लाखो वर्ष में भी प्राचीन वेदानुसारी प्राचीन आर्य'-संस्कृति अक्षुण्ण रही। पवित्र शिक्षा ओर निष्कलंक नित्य जीवन के कारण प्राचीन भारत का ब्रह्मचारी, राजा के लिए भी पूजनीय माना जाता था। ब्रह्मचर्याश्रम में अर्थ, काम से सर्वथा अस्पृष्ट होने से ब्रह्मचारी के प्रति सबकी श्रद्धा रहती और उसे सम्मान दिया जाता था।

प्राचीन भारत में शिक्षा के केन्द्र ऋषि होते थे। महर्षि दुर्वासा का चलता-फिरता विश्वविद्यालय प्राय: दस हजार शिक्षार्थियों से पूर्ण था। बाल्मीकि, वसिष्ठ, अधोर, अंगिरा, भरद्धाज आदि प्राचीन कुलपति थे।50 सांदीपनि ऋषि भगवान् श्रीकृष्ण और सुदामा के गुरू थे। तक्षशिला, राजगृह नालन्दा, काशी, बल्लभी, विक्रमशिला, जगदल, उदन्तपुरी, मिथिला, काच्ची आदि प्राचीन शिक्षा-केन्द्र थे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. ऋग्वेद, 10.71.7
2. '.....सा विद्या या विमुक्तये।.....विद्यान्या शिल्पनैपुणम्।।'- विष्णुपुराण, 1.19.41
3. 'ततोऽनन्तरसंस्कारसंस्कृतो गुरूवेश्मनि।....कुर्याद्विद्यापरिग्रहम्।।'- वही, 5.10.12
4. 'ब्रह्मचर्येन तपसा राजा राष्ट्रं वि रक्षति। आचार्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारि-णमिच्छते।।'- अथर्ववेद, 11.5.17
5. विष्णुपुराण, 5.2.19
6. 'ब्रह्मवर्चसकामस्य कार्यं विप्रस्य पञ्चमें। राज्ञो बलार्थिन: षष्ठे वैयस्यार्थिनाऽष्टमे।।' - मनुस्मृति, 2.37
7. 'यङ्गवे भाजने लग्न: संस्कारो नान्यथा भवेत् कथा-च्छलेन बालानां नीतिस्तदिह कथ्यते'-हितोपदेश, प्रस्तावना,8
8. भारत का सांस्कृतिक इतिहास, लेखक: हरिदत्त वेदालंकार, प्रकाशक। आत्माराम एण्ड सन्स, काश्मीरी गेट, दिल्ली, 1952 पृ. 247
9. ब्रह्माण्डपुराण, 4.43.68
10. मत्स्यपुराण, 151.9
11. वही, 151.9
12. ब्रह्माण्डपुराण, 4.43.39-44
13. वायुपुराण, 3.11.121
14. विष्णुपुराण, 3.11.121
15. मनुस्मृति, 2.175
16. अथर्ववेद, 11.5.9
17. विष्णुपुराण, 3.11.81
18. हरिदत्त वेदालंकार, पूर्ववर्ती, पृ. 247
19. विष्णुस्मृति, 59.26
20. 'शिक्षांक' (कल्याण, जनवरी, 1988) गीताप्रेस, गोरखपुर।
21. मनुस्मृति, 2.140
22. वही, 2.141
23. वही, 2.142
24. ब्रह्मलीन स्वामी श्रीमहेश्वरानंदजी सरस्वति, छात्र और अध्यापक, कल्याण, शिक्षांक, गीताप्रेस, गोरखपुर (उ.प्र.)
25. मत्स्यपुराण, 211.21,
26. ब्रह्माण्डपुराण, 4.43.68
27. वही, 4.43.87
28. हरिदत्त वेदालंकार, पूर्ववर्ती, पृ. 249
29. अथर्ववेद, 11.5.3

30. मुण्डकोपनिषद, 1.2.13
31. कल्याण, शिक्षांक, जनवरी, 1988, गीताप्रेस, गोरखपुर, पृ. 260
32. मुण्डमालतंत्र, कल्याण, शिक्षांक में उद्धृत
33. योगसूत्र, 1.26
34. कल्याण, शिक्षांक, पूर्वोक्त।
35. विष्णुपुराण, 4.4.99
36. ब्रह्माण्डपुराण, 2.38.3
37. मत्स्यपुराण, 57.15
38. विष्णुपुराण, 5.20.49
39. वायुपुराण, 93.64
40. प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति, लेखक: लज्जाराम तोमर, प्रथम संस्करण, प्रकाशक: सुरूचि प्रकाशन, नई दिल्ली, 2000, पृ. 30
41. तैतिरीयोपिनिषद्, 1.2, शिक्षाध्याय, लज्जाराम तोमर: 2000, पूर्वोक्त
42. मत्स्यपुराण, 204.17
43. ब्रह्माण्डपुराण, 4.20.52
44. मत्स्यपुराण 220.2
45. छांदोग्योपनिषद् 10.1.2, वेदालंकार पूर्ववर्ती, पृ. 251
46. पौराणिक धर्म एवं समाज, लेखक: सिद्धेश्वरी नारायण राय, प्रकाशक: पंचनद पब्लिकेशन प्रयाग, 1968,पृ. 260
47. मिलिन्दपंह, 1.22.6, लज्जाराम तोमर, पूर्वोक्त
48. कल्याण, 'शिक्षांक', पूर्वोक्त, पृ. 121
49. वही।
50. वही।

****

आदिम जन जातियों की स्वातंत्र्य चेतना

डॉ. ऊषा मिश्रा *

शोध सारांश – आदिम और पिछड़ी कही जाने वाली किन्तु अत्यधिक स्वतंत्रता प्रिय इन जनजातियों ने साहूकारों, जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो संघर्ष किया वह अविस्मरणीय है। पहले साहूकारों और जमींदारों के खिलाफ खड़े हुये, किन्तु बाद में उन्हें समझ में आया कि उनका एक ही शत्रु हैं, वह ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता है। तीरकमान भालों के बल पर विश्व की अत्याधुनिक शक्तिशाली सेना से मुकाबला करने का साहस ही उनकी स्वतंत्र चेतना का प्रमाण है। इन विद्रोहों का दमन कर दिया गया, किन्तु इन आंदोलनों ने सभ्य समाज को भी राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिये संघर्ष करने की प्रेरणा दी।

प्रस्तावना – कोल, किरात भील भारत की आदिम जातियां थी। जो दुर्गम पहाड़ी और वन्य क्षेत्र में निवास करती थीं। बाहरी संसार से उनका विरोध उसी स्थिति में होता है, जब बाहरी लोग जंगलों में अतिक्रमण करने लगते है। वनोपज व लकड़ी पर सरकारी नियंत्रण बढ़ने लगता है। उनकी स्वंतत्रता बाधित होती है, ऐसे अतिक्रमणकारियों को वे 'दिकू' कहते हैं, अर्थात परेशान करने वाला[1]और अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिये तत्पर हो जाते हैं।

स्वतंत्रचेता आदिम समुदाय ने 19वीं शताब्दी में अत्याचारी अंग्रेज सत्ता से लम्बा संघर्ष किया। अंग्रेज प्रशासक आदिवासियों को जंगली लुटेरे मूर्ख और अन्धविश्वाशी समझते थे। औपनिवेशिक राज की घुसपैठ ने उनकी सामाजिक व्यवस्था को ही उलट–पलट कर दिया। ब्रिटिश शासकों ने जंगल से उनके गहरे रिश्ते को तोड़ दिया। खेती के उनके अपने अलग तरीके थे। वे झूम और पडु खेती करते थे। पर औपनिवेशिक राज ने जंगल, भूमि, वन उत्पाद, सभी पर अधिकार कर लिया।[2]

असंवेदनशील अंग्रेज शासकों ने आदिवासियों की परम्पराओं मान्यताओं और रीति रिवाजों को समझने की कोशिश नहीं की। दूसरी और ईसाई धर्म प्रचारकों एवं मिशनरियों ने उनकी संस्कृति नष्ट करने का प्रयास किया तब भारत के इस प्राचीन और स्वतंत्रचेता समाज ने अत्याचारी सत्ता के खिलाफ लम्बा संघर्ष किया जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का एक गौरव पूर्ण अध्याय है, जो निम्न हैं –

1. खासी विद्रोह (1829) – बंगाल में जयन्तिया और गारों पहाड़ियों के बीच 3500 वर्गमील पहाड़ी क्षेत्र में बहादुर व लड़ाकू खासी जाति निवास करती थी। इनके 30 अलग–अलग शक्ति सम्पन्न राज्य थे। प्रत्येक की अपनी परिषद थी। उनकी जनता जनतांत्रिक व्यवस्था व नागरिक स्वतंत्रता को देख कैप्टन ह्वाइट ने कहा था कि उसने योरोपीय समाज में भी ऐसी उत्तम शासन व्यवस्था नहीं देखी। और जब ऐसी जागरूक जाति को गुलाम बनाने का प्रयास किया गया तो विद्रोह स्वाभाविक था। वर्मा युद्ध के उपरान्त असम और सिलहट को खासी पहाड़ियों से होकर जोड़ने वाली सड़क का सामारिक महत्व था। 1827 में खासी मुखियाओं से वार्ता की गई। पर अंग्रेजों के अहंकार पूर्ण व्यवहार के कारण खासी पहाड़ियों के 36 छोटे–छोटे राजाओं ने खासी नेता तिरूत सिंह के नेतृत्व में खासी एवं असम से अंग्रेजों को बाहर निकालने हेतु संगठित हो गये। तिरूत सिंह ने आस–पास के पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियों को भी अंग्रेजी सत्ता नष्ट करने के अभियान में साथ देने की अपील की। तिरूत सिंह ने दस हजार सेना के साथ अंग्रेजों पर अचानक आक्रमण कर दिया। लेफ्टीनेंट बेडिंगफील्ड मारा गया।[3]विद्रोही पोलिटिकल एजेन्ट डेविड स्काट को पकड़ने के लिये चेरापूंजी की और बढ़े। समस्त खासी क्षेत्र में विद्रोह फैल गया। तिरूत सिंह ने असम में अंग्रेज सत्ता के मुख्य केन्द्र गुवाहाटी तक हलचल मचा दी। लगभग चार वर्ष तक संघर्ष चलता रहा। अंग्रेजों ने खासियों की आर्थिक नाके बंदी कर दी, एक के बाद एक खासी गांवों को जलाना शुरू कर दिया। अन्त में 1833 में तिरूत सिंह ने इस शर्त पर आत्म समर्पण किया कि उसे मृत्यु दण्ड नहीं दिया जायेगा और उसके भतीजे को उसके प्रदेश सौंप दिया जायेंगे।

कोल विद्रोह 1831–32 – बंगाल के छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल जाति निवास करती थी। इनकी अनेक शाखायें थीं, और अलग–अलग मुखियायों के स्वतंत्र राज्य थे। कोल विद्रोह का मूल कारण ब्रिटिश भू–राजस्व व्यवस्था से उपजा असंतोष था। अनुचित लगान वसूली से उनकी जमीन खेत पशु यहां तक स्त्रियां भी सुरक्षित नहीं थें। सामाजिक–आर्थिक असमानता से उग्र होकर कोलों ने 1831 में सिंहभूमि, रांची, पलामू आदि में एक साथ विद्रोह कर दिया।[4]कोलो ने सरकारी खजाने को लूटा, थाना कचहरी पर आक्रमण कर सरकारी कागजात नष्ट कर दिये। पुलिस दरोगा एवं चौकीदारों की हत्या कर दी।

कोल आंदोलन का नेतृत्व बुद्धो भगत, जोआ भगत, केशो भगत, नरेन्द्र शाह मनकी और मदरा महतो ने किया। इनके सुयोग्य नेतृत्व में कोलों का सशक्त, आंदोलन चला। कोलों को अन्य आदिवासियों जैसे चेरो ओराव और मुण्ड़ा जनजातियों से भी पर्याप्त सहयोग मिला। अंग्रेज सरकार भी कोल विद्रोह से आंतकित हो गई। और रामगढ़ बटालियन के साथ अनेक जमींदारों ने भी विद्रोह दमन के लिये अपनी सेना भेजी बैरकपुर और दानापुर छावनी से भी कोलों के दमन के लिये सेना भेजी गई। कोलों ने छापामार युद्ध प्रणाली से संघर्ष किया। किन्तु विशाल और संगठित अंग्रेजी सेना ने कोल विद्रोह का दमन कर दिया। बुद्धो भगत एवं सैकड़ो आदिवासी मारे गये। जो बचे उन पर मुकदमें चलाये गये एवं कठोर दण्ड दिया गया। और 1832 की गर्मियों तक कोल विद्रोह दबा दिया गया।[5]

पूर्वी भारत में अंग्रेजी शोषण के विरूद्ध कोलों ने पहली बार संगठित होकर सरकार और उसके समर्थकों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष किया। कोलो ने जो रास्ता अपनाया वह अन्य आदिवासियों के लिये प्रेरणा स्त्रोत बन गया। शीघ्र ही इसी क्षेत्र में संथालों का व्यापक आंदोलन हुआ। कोल विद्रोह यद्यपि असफल हुआ। लेकिन कोलों की शहादत व्यर्थ नहीं गई। असमानता और शोषण के विरूद्ध संघर्ष जारी रहा। जिस कारण इस क्षेत्र में 'दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेन्सी' का गठन किया गया। और 1854 में इस इलाके को छोटा नागपुर डिवीजन के नाम से संगठित किया गया।

* प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (इतिहास) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पन्ना (म.प्र.) भारत

संथाल मुक्ति संघर्ष 1855 – आदिवासी आंदोलन में संथाल मुक्ति संघर्ष सबसे जबरदस्त था। दामन–ए–कोह के नाम से ज्ञात भागलपुर से राजमहल तक का भू–भाग संथाल बहुल क्षेत्र था।[6] पूर्णिया छोटा नागपुर कटक घलभूम, मानभूम, बड़ाभूम, भागलपुर, पलामू, मेदिनीपुर, बांकुड़ा तथा मुर्शिदाबाद संथालों के निवास स्थान थे।

कोलों केही समान संथालों ने उन्हीं कारणों से त्रस्त होकर 1857 के विद्रोह के दो वर्ष पूर्व ही 1855 में ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ विद्रोह का शंखनाद कर दिया।

अंग्रेजीस्थायी बंदोबस्तकी अन्यायपूर्ण भू–राजस्व व्यवस्था से संथालों की अधिकांश जमीने उनके हाथ से निकल गई। तब संथालों ने राजमहल की पहाड़ियों में जंगलों को साफ कर नई खेती योग्य भूमि तैयार की। यही दामन–ए–कोह कहलाता था। इस नई भूमि पर भी अनुचित लगान वसूली और शोषण पुन: आरम्भ हो गया। भारी लगान चुकाने के लिये आदिवासी जमींदारों, सूदखोरो से 50%से 500%की दर तक पैसा उधार लेते। सूदखोर महाजन उनसे वनोपज खरीदने के लिये बड़ा बांट रखते और उन्हें सामान देने के लिये छोटा बांट प्रयोग में लाते। परिणाम स्वरूप ये बंधुआ मजदूर गुलामी के लिए बाध्य हो जाते।उन्हें मारा–पीटा जाता, उनकी स्त्रियों को अपमानित किया जाता। उनकी खड़ी फसलों पर जानवर छोड़ दिये जाते। जमींदार, महाजन, पुलिस, राजस्व विभाग, अदालते सरकारी कर्मचारी सभी संथालों पर अत्याचार करते।

संथालों में इन जमींदारों साहूकारों और सरकारी अधिकारियों के प्रति घोर घृणा थी। वे नहीं चाहते थे कि ये उनके नये प्रदेशों में प्रवेश करें। उनका कहना था 'वे मैदानों में बसे हैं, हम पहाड़ियों और जंगलों में' अर्थात उनके क्षेत्र में अनाधिकार प्रवेश न हो।

इसी समय अंग्रेजी सरकार इस क्षेत्र में रेलवे लाइन बिछाने का कार्य कर रही थी। उन ठेकेदारों द्वारा भी संथालों के साथ शोषण लूट एवं स्त्रियों पर घोर अत्याचार किये जा रहे थे, इन्ही कारणों से संथाल विद्रोह आरम्भ हुआ। 30 जून 1855 को भगनीडीह 400 आदिवासी गांवों के छह हजार आदिवासी एकत्र हुये और सभा की। और सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि 'विदेशियों का राज खत्म कर न्याय और धर्म पर आधारित स्वयं का राज स्थापित करने के लिये खुला विद्रोह किया जाये।' आदिवासी नेता सीदो और कान्हू ने कहा कि 'ठाकुर जी (ईश्वर) ने उन्हें कहा है कि आजादी के लिये अब हथियार उठा लो। यह देश साहबों का नहीं है। ठाकुर जी खुद हमारी तरफ से लड़ेगें।[8] संथालों ने इसे बुराई पर अच्छाई की विजय का नाम दिया। उन्हें विश्वास था कि ब्रिटिश शासन का अंत ही उनकी स्थिति में सुधार ला सकता है। क्योंकि अंग्रेज हमेशा उनके शोषकों का ही साथ देते हैं। जुलाई माह में पुलिस द्वारा एक आदिवासी को बुरी तरह प्रताड़ित करने के मामले को लेकर संथाल विद्रोह भड़क उठा। लगभग 60 हजार हथियार बंद संथालों के साथ कई हजार आदिवासी भी तैयार थे। संथाल नेता हाथी, घोड़े, पालकियों में चलते।संथालों को अपने नेता सीदो और कान्हू के नेतृत्व में प्रगाढ़ आस्था थी। नेताओं ने अंग्रेज सरकार भागलपुर कलेक्टर, कमिश्नर, मजिस्ट्रेट , थानों के दरोगा, जमींदारों को 15 दिन का एक अल्टीमेटम भेज कर जमींदारों, महाजनों, साहूकारों की बाहर निकाल कर स्वाधीन शासन स्थापित करने की घोषणा की। साथ ही कुम्हारों, जुलाहों, तेलियों, लुहारों, चमारों और डोमां को सुरक्षा देने की बात भी कही गई।[9]

संथालों ने साहूकारों, जमींदारों के साथ रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, डाक ढोने वाली गाड़ियों पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने औपनिवेशिक सत्ता के प्रतीक सभी स्थानों पर हमला किया।

सरकार इस संगठित विद्रोह से घबरा गई कलकत्ता से मेजर बरो के आधीन एक सेना भेजी गई। लेकिन विद्रोहियों ने मेजर बरो की सेना को पराजित कर दिया।[10] तब उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। विद्रोही नेताओं को पकड़ने हेतु दस हजार का इनाम घोषित कर दिया गया। एक तरफ आधुनिक हथियारों से लैस फौज थी। दूसरी तरफ धनुष बाण, भाले, पत्थर लिये जूझते बहादुर आदिवासी पुरूष और औंरते, जिन्हें विश्वास था कि उनका ठाकुर (ईश्वर) उनके साथ लड़ रहा है। संथालों ने अदम्य साहस दिखाया, असहय यातना सही। पर किसी ने आत्म समर्पण नहीं किया, किन्तु सत्ता के अत्याचार एवं निरंकुशता ने विद्रोह कुचल दिया। पन्द्रह हजार संथाल मारे गये, गांव के गांव उजाड़ दिये गये। सीदों और कान्हू मारे गये राजमहल की पहाड़ियों संथालों के खून से लाल हो गई।[11]

संथालों ने कोलों के समान ही यह सिद्ध कर दिया कि निरीह आदिवासी भी अत्याचार एवं शोषण को अधिक समय तक बर्दाशत नहीं कर सकते। विद्रोह के बाद सरकार को उनकी समस्याओं की ओर ध्यान देने को बाध्य होना पड़ा। संथाल परगना केा जिला बनाया और संथालों को कुछ राहत दी पर उनका शोषण समाप्त नही हुआ। संथालों से प्रेरणा लेकर आगे भी आदिवासी विद्रोह होते रहे।

बिरसा मुण्डा विद्रोह – मुण्डा आदिवासी विद्रोह 1899–1900 के बीच हुआ। इसका नेतृत्व बिरसा मुण्डा ने किया। दक्षिणीबिहार के छोटा नागपुर इलाके के लगभग 400 वर्गमील क्षेत्र में मुण्डा निवास करते थे। उनमें सामूहिक खेती का प्रचलन था। लेकिन जागीदारों, ठेकेदारों (लगान वसूली करने वाले) बनिओं और सूदखोरों ने सामूहिक खेती की परम्परा पर हमला बोल दिया। मुण्डा सरदार 30 वर्ष तक सामूहिक खेती के लिये लड़ते रहे।[12] मुण्डाओं कीखूंट कट्टी भू व्यवस्थाठेकेदारों के लिए धन वसूली का अच्छा शिकारगाह थी। बारी– बारी से लुथेरियन, ऐंग्लिकन, केथौलिक, मिशनरियों ने उन्हें ईसाई बनाने के बदले उनकी सहायता का वचन दिया लेकिन उनका वादा झूठा निकला। मुण्डाओं ने कलकते के एक एंग्लों इंडियन वकील के माध्यम से न्यायालय में लड़ने का प्रयास किया, पर वकील ने ही उन्हें ठग लिया। एक चर्च में उन्होंने कहा 'हमने सरकार के सामने दुखड़ा रोआ हमें कुछ नहीं मिला, हम मिशनरियों के पास गये, उन्होंने भी हमें डाकुओं से नहीं बचाया। अब हमारे पास इसके अतिरिक्त और कोई चारा नहीं कि हम अपने ही किसी आदमी से आशा करें।'[13]

तब उनके बीच मसीहा बनकर बिरसा मुण्डा (1874–1901) का उदय हुआ। बिरसा ने मुण्डा समाज का पुर्नगठन करने के साथ अंग्रेजी भू–राजस्व व्यवस्था का विरोध करना आरम्भ कर दिया। वनों पर आदिवासियों के परम्परागत अधिकारों की पुन: स्थापना पर जोर दिया। मुण्डाओं में आत्मबल भरने हेतु बिरसा ने स्वयं को पैगम्बर रहस्यमयी शक्ति सम्पन्न और मुण्डाओं का उद्धारक होने की बात भी कहने लगा।

बिरसा की बढ़ती हुई लोक प्रियता से भयभीत होकर सरकार ने उसे दो साल के लिये जेल भेज दिया। जेल से निकल कर बिरसा और भी ताकतवार होकर उभरा। उसने मुण्डाओं को शस्त्र निर्माण और सैन्य प्रशिक्षण आरम्भ किया, अकाल तथा संक्रामक रोगों से त्रस्त आदिवासियों की मदद की। रात्रि सभायें की जाती, जिसमें बिर्सा ठेकेदारों,जागीरदारों, हाकिमों को मार डालने की बात कहता और यह भी कि हमारे सामने उनकी बन्दूके और गोलियां पानी बन जायेंगी। ब्रिटिश राज के पुतले जलाये जाते। मुण्डा बड़े उत्साह से गाते–

कटोंग बाबा कटोंग,
साहेब कटोग कटोंग,
रारी कटोंग कटोंग,
(काटो बाबा काटो, साहबों के काटो, और दूसरों को काटो)

1899 में क्रिसमस की पूर्व सन्ध्या पर बिरसा ने मुण्डा जाति का शासन स्थापित करने के लिये विद्रोह का ऐलान किया, और ठेकेदारों, जागीरदारों, राजाओं हाकिमों और ईसाइयों को कत्ल करने का आहवान किया। कहा कलयुग को खत्म कर सतयुग लायेंगें और घोषणा कि 'दिकुओं (गैर आदिवासी) से अब हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झण्डा।' मगर उसने यह भी हिदायत दी कि गरीब गैर आदिवासी पर हाथ न उठाया जाये।[14]

5 जनवरी 1900 को लगभग छह हजार मुण्डाओं ने तीर, तलवार, कुल्हाड़ी लेकर बिरसा के नेतृत्व में अपने शोषकों पर आक्रमण कर दिया। पुलिस चौकी, सरकारी दफ्तर, चर्च, महाजनों, साहूकारों पर हमला बोल दिया। सरकार ने दमन के लिये बन्दूकों एवं तोपों के साथ सेनायें भेजी। अंतत: तीन सप्ताह बाद बिरसा गिरफ्तार कर लिया। जहां जेल में ही उसकी मृत्यु हो गई। तोपों बन्दूकों से विद्रोह कुचल दिया गया। 1908 में सरकार ने मुण्डाओं की सामूहिक खेती (खूंटी कट्टी) के अधिकार को मान्यता दे दी, बेगारी पर प्रतिबंध लगाया गया। लम्बे संघर्ष के बाद मुण्डाओं ने अपने भूमि अधिकारों के लिये कानूनी संरक्षण प्राप्त किया, हिंसक आंदोलन सदैव असफल ही नहीं होते।[15]

बिरसा आज भी अपनी जनता की स्मृतिओं में एक हीरो के रूप में जिन्दा है। अतिमानवीय शक्तियों से सम्पन्न राष्ट्रवादी नायक एक पैगम्बर के रूप में बिरसाआदरणीय और पूज्य है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. पी.एल.गौतम आधुनिक भारत पृष्ठ -411
2. विपिन चन्द्र भारत का स्वतंत्रता संघर्ष पृष्ठ- 14
3. एल.पी.माथुर आ0भारत का इतिहास पृष्ठ- 591
4. कामेश्वर प्रसाद, भारत का इतिहास पृष्ठ- 130
5. पी.एल.गौतम आधुनिक भारत पृष्ठ - 417
6. ताराचन्द्र, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास पृष्ठ-5
7. अयोध्या सिंह भारत का मुक्ति संग्राम पृष्ठ- 285
8. कालीकिंकर दत्त-द संथाल इन्स्योरेक्शन पृष्ठ - 16
9. पी.एल. गौतम आ0भारत पृष्ठ- 421
10. एल.पी.माथुर आ0भारत का इतिहास पृष्ठ- 596
11. विपिनचन्द्र भारत का स्वाधीनता संघर्ष पृष्ठ-17
12. वही पृष्ठ 17
13. सुमित सरकार, आधुनिक भारत पृष्ठ- 65
14. विपिनचन्द्र भारत का स्वाधीनता संघर्ष पृष्ठ-18
15. सुमित सरकार आधुनिक भारत पृष्ठ-66

****

सन्त कालूदास

डॉ. मधुसूदन चौबे *

प्रस्तावना – निमाड़ भू क्षेत्र दार्षनिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से उन्नत रहा है। यहां ऐसी विभूतियों का कर्मक्षेत्र रहा है, जिन्होंने अपने चिंतन, मनन और गतिविधियों से मानव जाति को प्रकाश दिखाया, उन्हें उज्जवल पथ पर प्रशस्त किया। ऐसे ही महनीयजनों में सन्त कालूदास भी सम्मिलित हैं। प्रस्तुत शोध पत्र में उनके व्यक्तित्व और कृतित्व का विवेचन किया गया है।

जन्म एवं प्रारंभिक जीवन – सन्त कालूदास की जन्म तिथि और उनके माता–पिता का नामोल्लेख कहीं नहीं मिलता है। यह ज्ञात होता है कि कालूदास के पिता सामान्य मजदूर थे। अत्यधिक परिश्रम करने के बाद भी उनकी आय बहुत सीमित थी। आर्थिक दृष्टि से उनकी पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं थी। किसी तरह जीवन यापन हो जाता था। अभावों ने पारिवारिक जीवन को कष्टप्रद बना दिया था, किन्तु माता–पिता के संयमित चरित्र के कारण कलहपूर्ण होने से बचा रहा। जितना मिला उतना ही ग्रहण कर संतुष्ट होने की प्रवृत्ति सभी में विकसित हो गई थी।

कालूदास का प्रारम्भिक जीवन अभावों में व्यतीत हुआ। उनकी अनिवार्य आवश्यकता भी पूर्ण नहीं हो पाती थी। आठ–दस वर्ष की अवस्था में ही वे अपने माता–पिता के हाथ बंटाने लग गये थे। उन दिनों निमाड़ क्षेत्र में सन्त अफजल की बहुत ख्याति व्याप्त थी। कालूदास के पिता अपने परिवारजनों के साथ सन्त अफजल के दर्शन करने एवं उनके प्रवचन सुनने जाते थे। पूरे परिवार पर सन्त का अत्यधिक प्रभाव था। अपने दैनिक आचरण में ये सन्त के उपदेशों का अनुसरण करने का पूर्ण प्रयास करते थे।

दीक्षा एवं साधना – कालूदास के युवावस्था में पहुंचने तक उनके माता–पिता का देहावसान हो गया। अब उन पर परिवारजनों की देखभाल का कोई दायित्व नहीं रह गया था। फलत: वे 'सन्त अफजल के सान्निध्य में अधिक से अधिक रहने लगे और उन्होंने सन्त अफजल से गुरु दीक्षा ग्रहण कर ली।'[1] अपने सेवा एवं समर्पण भाव के कारण कालूदास सन्त अफजल के परम प्रिय शिष्य बन गये थे। सन्त अफजल उनसे अत्यंत स्नेह करते थे और उन पर पूर्ण विश्वास करते थे। यही कारण है कि सन्त अफजल ने अन्त में इन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और गुरुगादी इन्हें सौंपी। कालूदास ने अपने एक पद में उल्लेख किया है–

भक्त जान मोहे पावन किनों, काया निर्मल किवी निचोड़।
गुरु गादी बकसी गुरु कृपा करी, मुख में अमरित दियो निचोड़।।[2]

कालूदास के मन में अपने गुरु के प्रति अत्यधिक श्रद्धा भाव था तथा वे अपने गुरु को अत्यधिक क्षमतावान मानते थे। उन्हीं के शब्दों में –

तुम अविगत गत कलइ न जाय साहब तुम गत अपरंपार हो।
साहेब चाहे तो सिर पर क्षत्र धरावों चाहो तो राखो उतार हो।।
साहेब चाहो तो रंक करो सुल्ताना, करी राखो अपणो दिवाण हो।
साहेब चाहे तो भीख मंगवाओ कोइयन दे आदर मान हो।।
साहेब मान घटाओ न घर–घर फिराओ, गुरु पर्वत करो विरण हो।
साहेब राई का पर्वत करी देखों, तुम छें तारण हार हो।।
अहीन समान मेरों जीवन कपें, सोस रह्यो दिल माँय हो।
साहेब अनेक अवगुण किया हम, तुमसे कहाँ लग करूँ प्रकाश हो।।
साहेब भला बुरा जन तेरा हो घर का, छोडि द्वारा कहाँ जावाँ हो।
सतगुरु अफजल कालू के दाता, पैया लागू मनाय हो।।[3]

इसी प्रकार वे अपने एक अन्य पद में लिखते हैं कि – साहब, तुम गरीब नवाज हो। मुझे गरीब जानकर मेरी प्रार्थना सुन लो। मुझे दर्शन देकर अपना बना लो और तीनों तापों से मुक्त करो। आप पूर्ण समर्थ हैं। मेरे मन के कल्मष धोकर इसे निर्मल कर दो। कालूदास हाथ जोड़कर कहता है कि इस जन की लाज रख लो।

सन्त कालूदास भक्ति की निर्गुण धारा के अनुयायी थे। गुरु के आदेश का यथावत् पालन ही उनकी साधना थी।

सन्त कालूदास का कार्यक्षेत्र बड़वानी और उसके आसपास था।

रचनाएँ – सन्त कालूदास ने भक्ति पदों की रचना की। उनके पदों की विषय वस्तु मुख्यत: गुरु भक्ति एवं गुरु कृपा थी। उनके पदों का संकलन अफजल साहब की वाणी नामक रचना में हुआ है। पूर्व पृष्ठ पर उल्लेखित उनके एक भजन से उनकी रचनाधर्मिता का ज्ञान होता है। उन्होंने निमाड़ी बोली में काव्य का सृजन किया है। उनका शब्द चयन उत्कृष्ट है तथा वे गागर में सागर भरने की कला में निष्णात हैं।

उपदेश – भक्ति काल के अन्य सन्तों की भांति सन्त कालूदास ने भी गुरु भक्ति का उपदेश दिया। वे प्राय: कहते थे कि गुरु की कृपा हो जाने पर और किसी की कृपा की आवश्यकता नहीं रहती है। गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिये सच्चा शिष्य बनना आवश्यक है।

उन्होंने धर्म के नाम पर बाह्य आडम्बरों में उलझने को निरर्थक निरूपित किया और निर्मल मन से सात्विक भक्ति की प्रेरणा दी। वे प्राय: कहा करते थे कि मनुष्य के रूप में जन्म मिलना अत्यन्त महत्व की बात है। इसका उपयोग व्यक्तिगत एवं पारिवारिक हितों के लिये तो किया ही जाना चाहिये, साथ ही सामाजिक कल्याण के लिये भी जीवन का सदुपयोग हो सके, इस बात का पूर्ण प्रयास किया जाना चाहिये।

उनकी मान्यता थी कि समाज में अच्छी विचारधारा वाले लोगों की कमी है और संकीर्ण दृष्टिकोण वाले लोगों की बहुतायत है। यही असंतुलन कई बुराइयों का कारण है। वे चाहते थे कि उनके अनुयायी अच्छे बने और अपने सम्पर्क में आने वाले लागों को भी सद्मार्ग अपनाने के लिये प्रेरित करें।

अनुयायी – सन्त कालूदास के व्यक्तित्व की सरलता एवं सहजता तथा उनके उपदेशों में विद्यमान आत्मीयता के कारण उनके अनेक अनुयायी बन

* सहायक प्राध्यापक (इतिहास) शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत

गये थे। उनके अनुयायियों में सभी वर्गों के लोग सम्मिलित थे। उनके द्वारा रचित एक पद की निम्नांकित पंक्तियों से स्पष्ट होता है कि ब्राह्मण वर्ग के व्यक्ति भी उन्हें गुरु के रूप में स्वीकार करते थे–

सतगुरु अफजल कारण तरैया, कालूदास ने आरती लेकर बधाया,
तुममे जोत जगदीश है, एक जान ब्राह्मण ने शीष नमाया।।[4]

यद्यपि सन्त कालूदास का जाति–पाति में विश्वास नहीं था, तथापि उन्होंने यहाँ ब्राह्मण शब्द का उल्लेख जिस सन्दर्भ में किया है, उससे प्रतीत होता है कि उस समय के सामाजिक संगठन में ब्राह्मणों की स्थिति उच्च थी और वे सन्त कालूदास के प्रति श्रद्धाभाव रखते थे। अपने प्रति ब्राह्मणों के इस दृष्टिकोण को कालूदासजी अपने गुरु सन्त अफजल का प्रताप निरूपित करते हैं।

निर्वाण – सन्त कालूदास दीर्घजीवी रहे। उन्होंने लगभग सत्तर वर्ष की आयु तक अपने सन्तत्व से समाज का कल्याण किया। कालूदासजी के निर्वाण के पश्चात् अनामी सम्प्रदाय की गुरु गादी बड़वानी से नागझिरी अंतरित हो गई।

मूल्यांकन एवं उपसंहार – सन्त कालूदास ने अनामी सम्प्रदाय के संस्थापक सन्त अफजल के शिष्य के रूप में अपने गुरु की शिक्षाओं का कुशलतापूर्वक प्रसार किया। उनकी सक्रियता के कारण समाज में अनामी मत के प्रभाव और प्रसार क्षेत्र में वृद्धि हुई। उनके द्वारा रचित पद निमाड़ी वाड.मय की धरोहर है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. नर्मदाचंल के संत कवि, लेखक – बाबूलाल सेन, प्रकाशक – माहिष्मती प्रकाशन, महेश्वर, संस्करण – 1995, पृष्ठ – 64.
2. निमाड़ी साहित्य के कलमकार – कलाकार, सम्पादक – बाबूलाल सेन, प्रकाशक – माहिष्मती प्रकाशन, महेश्वर, संस्करण – 2003, पृष्ठ – 56.
3. वहीं, पृष्ठ – 56.
4. निमाड़ के भक्त सन्तों की परम्परा तथा उनका समाज पर प्रभाव, डॉ. जे.सी. उपाध्याय के निर्देशन में एम.फिल. के विद्यार्थी महेश द्वारा देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को प्रस्तुत लघु शोध प्रबन्ध – 2004 – 05, पृष्ठ – 102.

****

मन्दसौर जिले में दालों की कृषि : स्थानिक तथा कालिक अध्ययन

डॉ. अख्तर बानो *

प्रस्तावना – मध्यप्रदेश के निवासियों का प्रमुख व्यवसाय कृषि है। मन्दसौर जिले में अनाज, दालें, तिलहन फसलों की कृषि की जाती है, किन्तु जिले में दालों का उत्पादन बहुत कम है, क्योंकि दालों के अन्तर्गत क्षेत्र ही कम है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश में बच्चों में कुपोषण पाया जाता है। अत: दालों के क्षेत्र को बढ़ाकर बच्चों को सुपोषित किया जाय तथा दालों का देश को आयात न करना पड़े और दालों का मूल्य कम हो, इस हेतु मन्दसौर जिले में दालों के अंतर्गत कृषि क्षेत्र का अध्ययन किया गया है।

प्रस्तुत शोधपत्र में मन्दसौर जिले का तहसीलवार दालों के क्षेत्र का विश्लेषण किया गया है। मन्दसौर जिले में पांच तहसीलें हैं, जिनके नाम भानपुरा, गरोठ, मल्हारगढ़, मन्दसौर और सीतामऊ हैं। जिले का कुल क्षेत्रफल 5535 वर्ग किलोमीटर तथा कुल जनसंख्या 1339832 (वर्ष 2011) है।

उद्देश्य –अध्ययन क्षेत्र में दालों के अन्तर्गत कम क्षेत्र के कारणों को खोजना तथा क्षेत्र में वृद्धि के सुझाव देना अध्ययन का उद्देश्य है।

विधि तंत्र –आंकड़ों की उपलब्धता के आधार पर प्रस्तुत शोध पत्र में दालों की कृषि से संबंधित द्वितीयक आंकड़े जिला सांख्यिकी पुस्तिका मन्दसौर से (वर्ष 1971–72 तथा 2009–10) लिये गये हैं। आंकड़ों का प्रतिशत निकालकर तहसीलवार विश्लेषण किया गया है। वर्तमान में मन्दसौर जिले में सुवासरा, शामगढ़ तथा दलौदा नवीन तहसीलें बनाई गई हैं, किन्तु इनके पर्याप्त आंकड़े अध्ययन हेतु उपलब्ध नहीं होने से इन तहसीलों के क्षेत्र को संबंधित पुरानी तहसीलों में जोड़कर अध्ययन किया गया है।

तालिका क्रमांक : 1 (देखे अगले पृष्ठ पर)

तालिका क्रमांक 2 (देखे अगले पृष्ठ पर)

मन्दसौर जिला – तहसीलवार दालों के अन्तर्गत क्षेत्र (प्रतिशत में)

चित्र क्र. 1**(देखे अगले पृष्ठ पर)**

मन्दसौर जिले में दालों के क्षेत्र में परिवर्तन – तालिका क्रमांक 2 से स्पष्ट है कि वर्ष 1971–72 की तुलना में अध्ययन क्षेत्र में चने को छोड़कर सभी दालों के क्षेत्र में कमी आई है। तुवर के क्षेत्र का प्रतिशत 1971–72 में 1.72 था जो वर्ष 2009–10 में 0.27 प्रतिशत रह गया। जिले की सभी पांच तहसीलों में भी यह प्रतिशत घटा है।

उड़द दाल में केवल भानपुरा तहसील (8.36 प्रतिशत से बढ़कर 14.40) को छोड़कर सभी चारों तहसीलों में उड़द के बोये गये क्षेत्र के प्रतिशत में कमी आई है। भानपुरा में इस फसल के क्षेत्र में वृद्धि का कारण सिंचाई सुविधा का विकास है। उड़द के क्षेत्र के प्रतिशत में सर्वाधिक कमी मल्हारगढ़ तहसील में 11.24 प्रतिशत क्षेत्र के स्थान पर वर्ष 2010 में केवल 1.27 प्रतिशत रह गया है। इसी प्रकार मन्दसौर तथा सीतामऊ तहसीलों में भी इसके क्षेत्र के प्रतिशत में कमी हुई है। गरोठ तहसील में वर्ष 1972 में उड़द का रकबा 9.99 प्रतिशत था जो वर्ष 2010 में घटकर 6.18 प्रतिशत रह गया। मन्दसौर जिले में अन्य दालों में मसूर, मूंग, मोठ, मटर की कृषि भी की जाती है। इन दालों के क्षेत्र में भी जिले के साथ ही सभी तहसीलों में इनके क्षेत्र के प्रतिशत में कमी आई है।

इसी प्रकार सभी दालों के योग की तुलना दोनों ही वर्षों में की जाय तो वर्ष 1971–72 में 21.75 प्रतिशत भूमि पर दालों की कृषि की जाती थी वही वर्ष 2010 में यह प्रतिशत 17.75 प्रतिशत रह गया।

दालों के क्षेत्र में कमी के कारण –

- मन्दसौर जिले में सोयाबीन की कृषि की जाना। जिसके कारण दालों के कृषि क्षेत्र में कमी आई और दालों का उत्पादन भी कम हो गया।
- सरकार द्वारा दालों की कृषि को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना भी इनके क्षेत्र में कमी का महत्वपूर्ण कारण है।
- जिले की कृषि वर्षा पर अधिक निर्भर है, अत: जिस वर्ष वर्षा अच्छी नहीं होती उस वर्ष सिंचाई भी नहीं हो सकती और रबी तथा खरीफ दोनों ही ऋतुओं में दालों के क्षेत्र में कमी आ जाती है।
- अध्ययन क्षेत्र में किसानों का रूझान सोयाबीन की तरफ है जो कि बहुउद्देश्यीय फसल है, क्योंकि सोयाबीन से मुद्रा अधिक प्राप्त होती है तथा यहां की मिट्टी व जलवायु इसके अनुकूल है।

दालों के क्षेत्र को बढ़ाने के उपाय – सरकार द्वारा दालों की कृषि को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। इसके लिये बीज, खाद पर अनुदान देना चाहिये तथा सिंचाई की सुविधा रबी में उपलब्ध करवानी चाहिये। सिंचाई हेतु बिजली 24 घंटे उपलब्ध कराना चाहिये।यदि फसल वर्षा या अन्य कारण से खराब हो जाती है तो सरकार को ऋण देते समय यह ग्यारंटी देना चाहिये कि उनके ऋण माफ कर दिये जाएंगे।

निष्कर्ष – अध्ययन क्षेत्र में दालों की बहुत कमी है यह कारण है कि दालों की कीमतों में बहुत अधिक वृद्धि हो गई है जिसके कारण गरीब तबका दाल खाने में असमर्थ है और इनके बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। सरकार को चाहिये कि एक निश्चित रकबा दाल बोने के लिये कृषक की जमीन के अनुपात से तय कर दें ताकि किसान दालों का उत्पादन करें और देश दालों के आयात से बचे। विगत 40 वर्षों में दालों के क्षेत्र के प्रतिशत में दोगुना से अधिक वृद्धि होना थी किन्तु इसके स्थान पर इस प्रतिशत में कमी ही हुई है जबकि क्षेत्र की जनसंख्या दुगुने से अधिक हो गई है (तालिका क्रमांक 1)। इस प्रकार दालों की कृषि में उन्नत तरीके अपनाकर सरकार का सहयोग लेकर सभी दालों के क्षेत्र में अध्ययन क्षेत्र की सभी तहसीलों में वृद्धि की जा सकती है तभी क्षेत्र के बच्चे कुपोषण से बच सकेंगे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. Agrwal, P.C. and Gupta H.S. (1975-75) Recent Trend in

* विभागाध्यक्ष (भूगोल) आर.जी.शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, मन्दसौर (म.प्र.) भारत

the Yield Rates of Major Food Grains in M.P., Geographical outlook, Vol.11, pp 15.24

2. Shafi, M. (1960) Measurement of Agricultural Efficiency in Uttar Pradesh, Economic Geography, Vol.36, No. 4, pp 296-304

तालिका क्रमांक – 1

मन्दसौर जिला – तहसीलवार क्षेत्रफल तथा जनसंख्या (हेक्टेयर में)

क्रमांक	तहसील	भौगोलिक क्षेत्रफल	जनसंख्या	
			वर्ष 1971	वर्ष 2011
1	भानपुरा	103918	65633	151135
2	गरोठ	113669	110000	260953
3	मल्हारगढ़	80605	95525	203822
4	मन्दसौर	126608	195913	445692
5	सीतामऊ	127369	126194	278230
	मन्दसौर जिला	**552169**	**593265**	**1339832**

तालिका क्रमांक – 2

मन्दसौर जिला – तहसीलवार दालों के अन्तर्गत क्षेत्र (प्रतिशत में)

क्र.	तहसील	चना		तुवर		उड़द		अन्य दालें	
		1972	2010	1972	2010	1972	2010	1972	2010
1	भानपुरा	6.27	5.25	0.53	0.19	8.35	14.40	2.01	0.62
2	गरोठ	8.56	8.28	1.68	0.22	9.99	6.18	1.06	0.41
3	मल्हारगढ़	11.51	10.64	0.93	0.18	11.24	1.27	1.27	0.54
4	मन्दसौर	11.64	20.94	1.82	0.43	9.2	0.73	2.65	1.47
5	सीतामऊ	8.45	13.90	2.78	0.23	4.62	1.36	2.05	0.48
	मन्दसौर जिला	9.63	13.11	1.72	0.27	8.53	3.61	1.87	0.75

नोट – शुद्ध बोए गए क्षेत्र से प्रतिशत

मन्दसौर जिला – तहसीलवार दालों के अन्तर्गत क्षेत्र (प्रतिशत में)

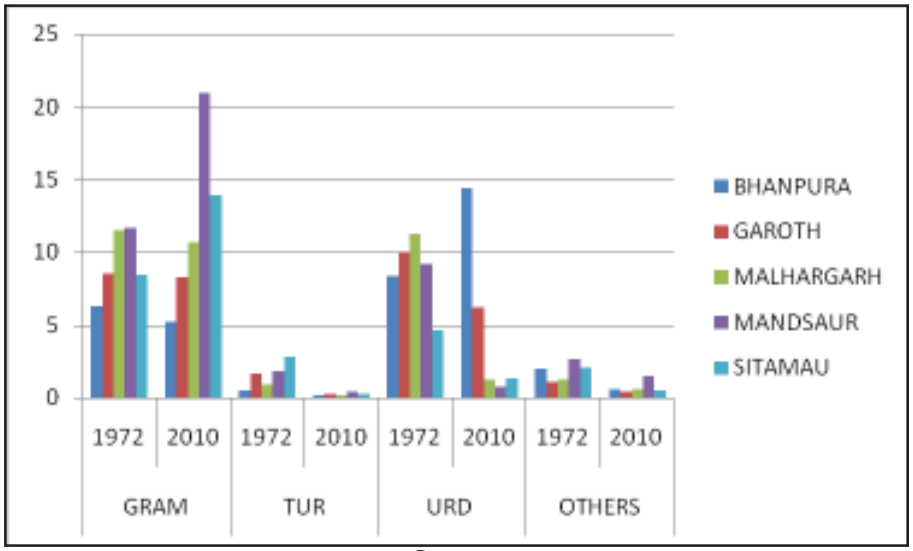

चित्र क्र. 1

****

रायगढ़ जिले के भौतिक परिदृश्य का भौगोलिक विश्लेषण

डॉ. कपूरचंद गुप्ता *

प्रस्तावना – छत्तीसगढ़ राज्य के सुदूर-पूर्व में रायगढ़ जिला अवस्थित है। यह ओडिशा राज्य के साथ सीमा बनाता है। इसका क्षेत्रफल 6527.74 वर्ग किलोमीटर है। यह छ.ग. की 09 भू-आवेष्ठित जिलों में से एक है। इसके उत्तर-पूर्व में जशपुर नगर, उत्तर-पश्चिम में सरगुजा, पश्चिम में कोरबा व जांजगीर-चाम्पा तथा दक्षिण-पश्चिम में बलौदाबाजार तथा दक्षिण में महासमुंद जिला अवस्थित है। यह पूर्व में ओडिशा सीमा से लगा हुआ है। यह जिला बिलासपुर से अलग होकर जनवरी 1948 को अस्तित्व में आया।

2011 जनगणनानुसार यहॉ की कुल जनसंख्या 1493984 है जिसमें 750278 पुरूष तथा 743706 महिला हैं। जिले का जनसंख्या घनत्व 211 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी है। लिगांनुपात 991 है तथा साक्षरता दर 73.26% है। जनसंख्या वृद्धि दर 18.05% है जो राज्य के 22.6% से कम है।

जिला ग्रामीण जनसंख्या 1247.682 जो कि कुल जनसंख्या का 83.5% तथा नगरीय जनसंख्या 246302 जो कि कुल जनसंख्या का 16.49% है यहॉ कि कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 5,05,609 जो 33.84% है तथा अनुसूचित जाति की जनसंख्या 224942 है जो कुल जनसंख्या का 15.06% है। यह उल्लेखनीय है कि 0-6 आयु वर्ग में राज्य में लिंगानुपात न्यूनतम 947 है। प्रशासनिक दृष्टि से जिले में 09 तहसीलें एवं 09 विकासखंड, उदयपुर (धरमजयगढ़) लैलूंगा, घरघोड़ा, तमनार,खरसिया,रायगढ़, पुसौर,सारंगढ़, बरमकेला (सरिया) हैं।

जिलें में 01 नगर निगम 01 नगर पालिका 08 नगर पंचायतें एवं 705 ग्राम पंचायतें हैं।

विगत दशकों से लौह इस्पात उत्पादन के कारण स्टील सिटी एवं तापीय ऊर्जा में तीव्र प्रगति के कारण इसे उर्जा नगरी की संज्ञा दी जाने लगी है। कला संस्कृति एवं प्रागैतिहासिक स्थलों के कारण इसकी पहचान अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है।

अध्ययन विधि :- प्रस्तुत शोध पत्र में प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों का उपयोग किया गया है। प्राथमिक आंकड़ों एवं तथ्यों का संकलन प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से साक्षात्कार एवं पर्यवेक्षण कर किया गया है।

अध्ययन का उद्देश्य :-

1. जिले के भौतिक परिदृश्यों का विश्लेषण कर यहां की कृषि, पशुपालन, उद्योग एवं पर्यटन की संभावनाओं को तलाशना।
2. जिले के भौतिक विशेषताओं को वर्तमान संदर्भ में अद्यतन रुप में प्रस्तुत करना।
3. जिले के अनछुए भौतिक पहलुओं एवं तथ्यों को उजागर करना।

भौतिक परिदृश्य – भूगर्भिक बनावट की दृष्टि से रायगढ़ जिले में मुख्य रूप से कड़प्पा और लोअर गोंडवाना शैल समूह की चट्टानें पायी जाती है। इस आधार पर जिले को दो भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है।

1. मैदानी प्रदेश 2. पहाड़ी प्रदेश।

(क) मैदानी प्रदेश – रायगढ़ जिले के दक्षिण भाग में महानदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा मैदानी प्रदेश का निर्माण हुआ है। इस प्रदेश को मुख्य रूप से तीन नदी बेसिनों से विभक्त किया जा सकता है।

1. **महानदी बेसिन –** इसके अन्तर्गत जिले के पुसौर बरमकेला तहसीलें आती है। जहॉ धान,गन्ना एवं सब्जियों की बहुतायत खेती होती है। क्योंकि यहां कि मिट्टी जलोढ़ होने के कारण अधिक उपजाऊ है।
2. **मांड नदी बेसिन –** इसके अन्तर्गत खरसिया तहसील का भाग शामिल है। जहाँ विपुल मात्रा में धान की खेती की जाती है साथ ही समतल व उपजाऊ क्षेत्र होने के साथ मांड नदी घाटी कोयला के लिये प्रसिद्ध है।
3. **लात नदी बेसिन –** सारंगढ़ तहसील में स्थित यह क्षेत्र की धान व सब्जियों तथा दलहन की खेती के लिए अधिक उपयुक्त है।

(ख) पहाड़ी प्रदेश - रायगढ़ जिले के उत्तर एवं दक्षिण भाग में मुख्य रूप से पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। इस पहाड़ी प्रदेश को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है-

1. **छुरी-उदयपुर की पहाड़ियाँ –** इसका विस्तार जिले के धरमजयगढ़, घरघोड़ा, लैलूंगा तहसीलों में है। साथ ही कोरबा, पोड़ी, उपरोड़ा एवं उत्तरी करतला क्षेत्रों में ये पहाड़ियाँ विच्छिन रूप से फैली है। इन क्षेत्रों में लेटराइट मृदा के कारण दलहन, तिलहन फसलें ली जाती है साथ ही यह क्षेत्र वन संसाधन की दृष्टि से सम्पन्न है। विशेष पिछड़ी जनजाति कोरबा भी इसी पहाड़ी में निवासरत हैं।
2. **महासमुन्द उच्च भूमि सीमांत क्षेत्र –** जिले के दक्षिण भाग में बरमकेला, सारंगढ़, तहसील की पहाड़ियों को इसमें शामिल किया जा सकता है। जहाँ गोमर्डा अभ्यारण स्थित है। वन्य जीव एवं वन सम्पदा की दृष्टि से यह क्षेत्र अधिक महत्व का है।

मृदा – जिले की भौतिक संरचना के भिन्नता के आधार पर मृदा को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है -

1. **लेटराइट मृदा –** स्थानीय भाषा में इस मृदा को 'भाठा' भी कहा जाता है। जिले में इस मृदा का विस्तार उँचाई वाले क्षेत्रों में पायी जाती है। धरमजयगढ़, लैलूंगा व घरघोड़ा के क्षेत्रों में यह मृदा पायी जाती है। जहाँ मोटे अनाज कोदो कुटकी व तिलहन फसले उगाए जा सकते हैं।
2. **लाल-पीली मृदा –** जिले के मैदानी क्षेत्रों में मृदा का विस्तार है इसे चावल मृदा की संज्ञा दी जाती है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में धान की खेती अधिक होती है।

प्रमुख नदियाँ – यहाँ की नदियाँ महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत शामिल की जा सकती हैं, जिसमें प्रमुख नदियाँ निम्न है -

1. **महानदी –** यह रायगढ़ जिले में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी में से एक है यह नदी खरसिया, बरमकेला , पुसौर तहसीलों से होकर प्रवाहित होती है।

*सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (भूगोल) बटमूल आश्रम महाविद्यालय, साल्हेओना (महापल्ली) जिला रायगढ़ (छ.ग.) भारत

2. मांड नदी – यह नदी रायगढ़ एवं खरसिया तहसील में प्रवाहित होकर महानदी में मिल जाती है। कुरकुट इसकी प्रमुख सहायक नदी है। मांड नदी के निकटवर्ती गांवों में धान, गेंहू एवं सब्जियों की खेती की जाती है।

3. केलो नदी – यह रायगढ़ जिले की सबसे प्रमुख नदी है जो रायगढ़ शहर के बीचों-बीच गुजरती है। यह जिले की जीवन रेखा है। केलो नदी पर ग्राम दनौत में केलो परियोजना निर्माणाधीन है। यह परियोजना रायगढ़ तथा जांजगीर-चाम्पा जिले के 175 गावों की 24396 हेक्टेयर भूमि में से 22810 हेक्टेयर खरीफ की सिंचाई की जायेगी। रायगढ़ शहर को पेयजल के रूप में 4.44 मीट्रिक घनमीटर एवं उद्योगों का भी 4.44 मीट्रिक घनमीटर दिया जाना प्रस्तावित है। प्रमुख रूप से पुसौर, डभरा, रायगढ़ एवं खरसिया तहसील केलो से लाभान्वित होंगे।

4. लात नदी – यह नदी मुख्य रूप से सारंगढ़ एवं बरमकेला तहसीलों में प्रवाहित होती है। यहाँ ग्रीष्म में जल का अभाव पाया जाता है। किन्तु जनवरी से मार्च तक इसके तटवर्ती क्षेत्र में शाक-सब्जी की खेती की जाती है।

प्रमुख जलाशय –

1. किंकारी जलाशय – बरमकेला से लगभग 15 किमी दूर धौरादरहा नामक गांव में किकारी जलाशय बनाया गया है। इस जलाशय से बरमकेला तहसील के अनेक गावों में सिंचाई की जाती है जिससे दुफसली खेती की सुविधा उपलब्ध है।

2. केडार जलाशय – सारंगढ़ से लगभग 12 किमी की दूरी पर केडार नामक स्थान पर जलाशय निर्मित किया गया है। इससे 36 गावों में 11862 एकड़ भूमि सिचिंत होती है। बांध की ऊँचाई 65 फीट है तथा इसकी जल संग्रहण क्षमता 17.84 वर्गमील है।

3. खम्हार पाकूट – लैलूंगा विकासखंड में लैलूंगा के निकट खम्हार पाकुट बांध बनाया गया है। इस बांध से दो-फसली कृषि एवं मत्स्य पालन को प्रोत्साहन मिला है।

4. टीपाखोल – रायगढ़ नगर से 5 किमी की दूरी पर टीपाखोल नामक गांव में जे.एस.पी.एल द्वारा इस्पात एवं पावर प्लांट के लिए इस जलाशय को निर्मित किया गया है।

5. राबोडेम – यह घरघोड़ा तहसील के राबो नामक गांव में निर्मित है जिसे जे.एस.पी.एल. ने अपने उद्योगों के लिए जल पूर्ति के उद्देश्य से बनाया है। इसके निचले भागों में धान की दो फसली खेती की जाती है।

6. सपनई डेम – रायगढ़ पूर्वांचल स्थित गांव सपनई में बना है। यह कुछ वर्ष से उपयोग नहीं हो रहा था, पुन: इससे नाले में पानी छोड़ने हेतु शासकीय प्रयास प्रारंभ हो रहा है।

जल प्रपात – जिले में पूर्णत: विकसित जलप्रपातों का अभाव है किन्तु कहीं-कहीं पर पहाड़ी की तलहटियों में बारहमासी जल-स्त्रोत हैं।

1. रामझरना – रायगढ़ नगर से लगभग 15 किमी दूरी पर स्थित रामझरना प्राकृतिक सौन्दर्य से परिपूर्ण है। यहॉ पर निर्मित ईको पार्क दर्शनीय है। इसके अलावा कबरापहाड़, बोतल्दा, घरघोड़ा तहसील के देलारी, सारंगढ़ के गोमर्डा पहाड़ी एवं तमनार में भी इस तरह के जलस्त्रोत हैं। जिनमें पर्यटन विकास की संभावनाएं हैं।

पर्वत – भौगौलिक दृष्टि से जिले में पर्वतों के अवशिष्ट विद्यमान हैं। इसके उत्तर-पूर्व में छुरी-उदयपुर की पहाड़ियों का क्रम तथा दक्षिण में पश्चिमी सीमांत उच्च-भूमि के क्रम में सारंगढ़ एवं बरमकेला की पहाड़ियां तथा पश्चिम में छिटपुट रूप से अवशिष्ट पहाड़ियां स्थित हैं। इन पहाड़ियों पर मानव के हस्तक्षेप बढ़ने के कारण इनका अस्तित्व खतरे में है।

मौसम – जलवायिक दृष्टिकोण से कोपेन के जलवायु वर्गोकरण के अनुसार यहॉ उष्णकटिबंधीय शुष्क आर्द्रता प्रकार की जलवायु पायी जाती है। यहॉ बंगाल की खाड़ी की शाखा वाली मानसून से अधिकांश वर्षा होती है। शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभों से लगभग 5 से 10 सेमी वर्षा होती है। जिले का औसत वार्षिक वर्षा 127 सेमी है। ग्रीष्मऋतु का औसत तापमान लगभग 320 हैं। किन्तु मई माह का तापमान 47^0C तक चला जाता है। शीतऋतु के दिसम्बर माह का तापमान न्यूनतम 6^0C तक दर्ज किया जाता है।

वन – जिले में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती मानसूनी वन पाये जाते हैं। यहाँ कुल भौगोलिक क्षेत्र के 31% भाग वनाच्छादित हैं। धरमजयगढ़, लैलूंगा व घरघोड़ा में सघन वन पाये जाते हैं। जिसमें प्रमुख रुप से साल वृक्ष मिलते हैं। इसके अलावा महुआ, आम, साजा, बीजा, तेन्दू, नीम, जामून आदि वृक्ष पाये जाते हैं। जिले के मैदानी भागों में आम, नीम, पीपल, बरगद, करंज, बेर, बबूल, पलाश, कहवा के वृक्ष बहुतायत मिलते हैं। सारंगढ़ तहसील में 278 वर्ग किमी क्षेत्र में गोमर्डा अभ्यारण स्थित है, जिसे 1975 में अभ्यारण्य घोषित किया गया। यहां तेन्दुआ, साम्हर, चीतल, गौर, भालू आदि जंगली पशु पाये जाते हैं।

निष्कर्ष – इस अध्ययन से स्पष्ट होता है कि रायगढ़ जिला भौतिक उपादानों के दृष्टिकोण से संपन्न हैं यहाँ कृषि, पशुपालन, उद्योग एवं पर्यटन विकास की संभावनाएं मौजूद हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. कमलेश एस.आर.-छत्तीसगढ़ की भौगोलिक समीक्षा 2002 वसुंधरा प्रकाशन गोरखपुर (उ.प्र.)
2. दैनिक भास्कर, समाचार पत्र 11 अगस्त 2015 रायगढ़ संस्करण
3. पटेल, डी.सी. - भारत का भूगोल
4. खुल्लर, डी.आर. - भूगोल 2014 सप्तम संस्करण, मैकग्रा हिल एजुकेशन प्राईवेट लिमि. नई दिल्ली।
5. जिला सांख्यिकी पुस्तिका - 2014
6. व्यक्तिगत पर्यवेक्षण।

****

Global Warming, An Unfortunate Truth

Girish Makwana * Dr. Shraddha Malviya**

Introduction - Last 100 years of development and growth changed the life of mankind very sharply. After the industrial revolution each person of world get smoothly going life but since civilizations started growing, at the same time they started digging the grave of humanity in the form of Global Warming. GW is a reply of Mother Nature for what we have done with her. In specific words GW means increased temperature of our climate or in the form of definition 'GW is a gradual increase in the temperature of the earth's atmosphere generally attributed to the greenhouse effect caused by increased levels of carbon dioxide, CFCs and other pollutants'. This definition makes sense about what is happening with our planet and how. Now if we focus over last 50 years climatic paradigm, we can see the results of GW, like changed pattern of rain and winter, increased power and frequency of hurricanes, increased surface and average temperature of atmosphere, and the most importantly melting of glaciers of Polar Regions these melt downs are increasing the ocean level and disturbing the ocean currents which are responsible for weather system. Just recently scientists saw a hole in ozone layer of size of Australian continent, it is also result of emission of carbon dioxide and CFCs. GW not just affecting human life, it is also destroying biodiversity of nature and that would definitely be disastrous for us and our surroundings. As we know adding more carbon dioxide to the atmosphere would intercept infrared radiations which could be lost into space or warming the earth.

1st time in history in 1896 a Swedish scientist Svante Arrehenius understood that human activity like burning fossil fuel could substantially warm the earth by emitting Carbon Dioxide to the atmosphere but at that time it did not ring bell at the peoples ear. In year of 1979 February after 83 years of Svante Arrehenius's findings WMO (World Meteorological Organization) organised World Climate Conference in Geneva (Switzerland). It was one of the first international meetings on climate change and in 2015 December 21st United Nation's Climate Change conference is being held in Paris and 11th after the 1997 Kyoto protocol.

This meeting was attended by many of scientists from different disciplines. This meeting was the milestone of debate on GW and also first step towards the establishment of IPCC.

Objective of Study - We know very well what is global warming and what are the consequences but still mass of people don't know anything about GW. Our objective is to introduce people with GW at very ground level.

What is Global Warming? Our planet earth is only planet in universe which has life. For the life on earth greenhouse gases are responsible. Greenhouse gases are combination of Nitrogen, Carbon Dioxide, Oxygen vapour and 1% of other gases. All of these gases controlled the radiations coming from sun. Most of the amount of sun light and heat absorb by surface and oceans, the part which is left reflect towards the sun, at this point role of greenhouse gases starts these gases maintain the temperature of earth by using the reflected radiations and create a natural blanket effect. Greenhouse gases naturally balance the input and output of radiation to maintain the essential 35p c temperature on earth for life. Here we come at the point that after the industrial revolution percentage of GHG increased rapidly and these gases increased temperature of earth. In past century earth's temperature increased by .5 to 2 degree, this small change in earth's temperature called GW. Because of the GW temperature of land and oceans changed and now we are facing the climatic change and disastrous face of nature every day. Melted glaciers increased the ocean level and disturbed ocean currents which are responsible for heavy rain in entire world and change in these patterns lead many species to be extinct (i.e. since the glaciers start's shrink conditions become very hard for Polar bears. They lost their icy platform of living). In last few years attacks of hurricanes, tornados, typhoons, and cyclones has become more frequent and strong. If the emission of carbon dioxide and other greenhouse gases would not be controlled or reduced, nature will become more destructive and unfortunate for us without any mercy.

Few countries, organizations, agencies and so called smart people still think that GW and climatic change is nothing but just a hokum. We have to open our eyes and see our planet and our changing atmosphere every day.

We can't ignore these climatic changes according to IPCC, 6 reasons why we must adapt the climatic changes.

1. It is impossible to avoid climatic change or GW.
2. Precautionary adaptation is more effective and less costly than last minute forced emergency fixes.
3. Climatic change could be more disastrous and rapid than current estimates.
4. Immediate benefits can be gained from better adaption

*Research Scholar (Sociology) Shree Atal Bihari Vajpayee Govt. Arts & Commerce College, Indore (M.P.) INDIA
**Asst. Professor (Sociology) Shree Atal Bihari Vajpayee Govt. Arts & Commerce College, Indore (M.P.) INDIA

to climatic variability and atmospheric events.

5. Quick benefits can be gained by removing inadequate policies and practices.
6. Climate change brings opportunities as well as threats.

Kyoto Protocol - 1997 Kyoto (Japan) conference is counted as most effective conference in the history of UNFCCC. Kyoto Protocol in an international treaty. The treaty commits state parties (participant countries) to reduce Green House gas emission, based on premise (UNFCCC) that global warming exist and man-made CO2 emission have caused it. Under the Kyoto Protocol countries divided at the bases of carbon dioxide emission and North America, Europe and Asia are mainly responsible for CO2 emission. According to IPCC these areas emit 90% of CO2 of total emission. According to Kyoto Protocol fully industrialised countries like America, Australia and Japan have to decrease CO2 emission 3 to 6% effectively. These countries emit maximum amount of green house gases. Kyoto protocol is not implemented on developing country like China and India. Panel of scientists and Greenpeace workers claim that the Kyoto protocol can't be helpful because if we are trying to control CO2 emission at the level of base year 1990, developed countries have to reduce their CO2 emission up to 60% and practically it is an impossible goal. One another reason why Kyoto protocol failed on ground is the cost. Environmentalists or any media should focus on this issue that if we try to stabilize emission of Carbon Dioxide at the level of 1990, it would cost around 8.6 trillion, almost equal to the world GDP.

Role of Parties - Before a few decades' people thought that major large-scale climatic changes occurred over a time of centuries, but it happened all of sudden in human life. In a life a person can see and feel the major climatic changes. According to Kyoto protocol most sensible step to mitigate the poisonous effect of global warming would be to cut the CO2 emission. Not only developed countries should control and reduce the Carbon Dioxide emission but the developing countries should also cut the CO2 emission effectively. In past 20 years 7 countries over 200+ countries in the world USA, Russia, Japan, Germany, China, South Korea and Canada are responsible for nearly 60% of total emission of green house gases. Rich countries emit more amounts of green house gases and first world countries create more pollution. These countries should pay more attention towards environmental turbulence than developing countries should. Developed countries use more resources as compare to developing nations for the life style and comfort; these few countries have highest numbers of vehicles which produce more gas that depletes the ozone layer. Developed countries also have the capacity and resources to control and reduce climatic damage but most of them are disinclined. According to IPCC we'd have to reduce GHG emission by 50% to 80%. It is only possible when countries applying taxes on Carbon Dioxide emission on individuals and organizations. Industrialisations of developing countries are beginning at the time when global community of science, global governance institution and advocacy groups are telling to reduce carbon dioxide emission. But it is not so easy for both developing and developed countries to reduce GHG emission because developed countries fulfil the demands of their people and in between generating more GHG and developing countries struggling to establish themselves as developed country, only few countries started levying carbon tax on fossil fuel production to help subsidize renewable energy projects under the Kyoto protocol guidelines. Unfortunately this race of countries to become more developed then other nations led us to disastrous future. Now it looks pretty necessary to work on CDM (a carbon offset plan set up under the Kyoto protocol). Only through CDM we become more energy efficient and could be able to develop GHG emission free energy resources.

Alternatives - Use of human labour instead of machineries would be helpful to decrease GHG emission it is also creates balance between production and supply. Deforestation is somewhere directly responsible for GW because trees and plants absorbs CO2 from the atmosphere and then turn it into oxygen, for agriculture, commercial use and mainly to establishment of industries. Each minute equal to three football stadium forests cut down in world, now we can calculate where we are going with these. Green-e-certified energy suppliers produce half of their supply with wind, solar energy and other clean energy resources, these are renewable resources and mainly they don't produce any kind of climate harming by product. People should use fuel efficient vehicles which consume less fuel and emit less amount of GNG. Most of the vehicle manufacturing companies developing smart or hybrid engines, which are able to run with solar energy. If this type of vehicle stepped in main stream, surely emission of GHG would be decreased in upcoming years. Use of energy with proper manner, developing the forest, use of smart vehicle, establishment of renewable energy resources all of these steps only helpful in present time and above all of these awareness towards our planet's future only can save us. Few alternatives which will mitigate the effect of GW -

1. Research and development is required to improve the performance and also we have to improve sustainable development.
2. Use of less energy produces less carbon dioxide. It is quite viable to improve energy efficiency by 60% although this will not be possible without tough policies or introduction of high energy / carbon tax.
3. By use of advanced technology in the field of energy production we save up to 60% of power input.
4. Our planet is full of solar and wind energy, these are alternative energy sources and these sources do not produce any amount of CO2 in the atmosphere. Recently scientists found that biomass is a very promising short term source of energy because biomass gain CO2 from atmosphere to grow and release it as by product when burnt as a fuel, thus there is no net increase in atmospheric CO2. Solar and wind energy sources are excellent and very promising for long term.

5. By growing the forest we cut the atmospheric emission of CO2 and other GHG's.

Iron hypothesis - We have seen, GW is become an international agenda and now cutting of carbon dioxide emission has a huge economic Burdon for all of us. Few of Renault scientists are working on a quick fix or in more appropriate words *techno-fix* of global warming. It is pretty clear that many of oceans are under producing and all oceanic plants need very small amount of iron to grow. Pacific and southern oceanic plants do not get this small quantity of iron dust, it has been suggested if we could fertilize these oceans with iron, this will provoke marine productivity and these marine plants would absorb more surfaced CO2 and turn it in to organic matter, so with the help of this method we could remove or mitigate the CO2 from atmosphere. But few experiments shown the amount required to fertilize the world's ocean would be huge and when we stopped to drop iron into them they release much of stored CO2. Today it looks like far from implementation, may be in upcoming years this will work.

Conclusion - What we have done with our planet is not reversible but if it is not stopped by today, earth will go back to the life less era and it is not just a hypothesis, it would happen very rapidly. Both developed and developing countries should understand their role toward the climatic damage, in the argument of who did what, we are just wasting our precious time.

References:-

1. Maslin. M, Global Warming, a very short introduction. Oxford University press oxford 2004.
2. www.un.org/sustainabledevelpment/climate-chang.
3. Pachouri. R.k; and Reisinger. A; eds. Climate change 2007: synthesis report.
4. https://www.wmo.int>climate>index_en
5. Intergovernmental reports on climatic change (2005 to 2012)

****

घरेलू एवं कामकाजी जनजातीय महिलाओं की सामाजिक - आर्थिक समस्याऐं- एक विश्लेषणात्मक अध्ययन (अलीराजपुर जिले के कट्ठीवाड़ा विकासखण्ड के विशेष संदर्भ में)

आई. एस. सस्त्यां *

शोध सारांश – प्राचीन काल से ही महिलाएँ समाज का एक महत्वपूर्ण घटक रही हैं। महिलाओं के बिना समाज की कल्पना असम्भव है। यदि प्राचीन काल के इतिहास को देखा जाये तो श्रम विभाजन की प्रकृति बहुत सरल थी। पुरूष जहाँ चुनौतीपूर्ण कार्यों का हिस्सा थे, वहीं महिलाएं पारिवारिक कार्यों में सहभागिता कर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करती थी जिसे किसी भी प्रकार कम नहीं आंका जा सकता है। आज सार्वजनिक क्षेत्रों में महिलाओं की सहभागिता तीव्र गति से बढ़ते हुए पुरूष के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर चल रही हैं। सार्वजनिक कार्य अथवा पेशे का शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जहाँ महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज न की हो। पूर्व में जहाँ घर परिवार से बाहर महिलाओं का कार्य करना गलत समझा जाता था और उनका क्षेत्र चार दिवारी तक ही सीमित कर दिया गया था इसे घरेलू महिला की संज्ञा दी जाना उचित होगा। यद्यपि कामकाजी महिलाओं का इतिहास अत्यधिक पुराना नहीं है। कामकाजी महिलाओं से तात्पर्य उन महिलाओं से है जो प्रत्यक्ष रूप से अर्थोपार्जन के लिए घर से बाहर जाकर कार्य कर रही हैं। ठीक इसके विपरीत जनजातीय महिलाएँ परम्परागत रूप से सुदूर एवं दुर्गम क्षेत्रों में निवास करती थी। इन क्षेत्रों में आवागमन के साधन न के बराबर थे, इसीलिए जनजातीय महिलाएँ बाह्य जगत से पूर्णत: कटी हुई थी। उनकी अपनी संस्कृति एवं जीवन-यापन की पद्धति थी। अधिकांशत: वे बाह्य जगत में होने वाले उतार-चढ़ाव से अछूती रहती थी। अध्ययन क्षेत्र में जनजातीय महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय है, जहाँ तक कि उनके लिए शिक्षा, वस्त्र एवं जीने के लिए पर्याप्त संसाधन भी नहीं हैं। इसी को दृष्टिगत रखते हुए शोध अध्ययन में पाया कि कामकाजी महिलाओं की अपेक्षा घरेलू महिलाओं को अधिक मात्रा में आर्थिक स्तर में सुधार की एवं कामकाजी महिलाओं को सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

शब्द कुंजी – घरेलू, कामकाजी महिलाऍं, आर्थोपार्जन, स्वयंसेवी संस्था।

प्रस्तावना – आज भी मध्यप्रदेश में भील जनजातीय बहुल क्षेत्र के रूप में जाना जाने वाला अलीराजपुर जिला एक अविकसित जिले के रूप में ही चर्चित हैं। इस जिले में सबसे पिछड़ा कट्ठीवाड़ा विकासखण्ड आता है। इस क्षेत्र में नदियों के अभाव के कारण ही सुदूर ग्रामीण इलाकों और आदिवासी बहुल वनों में जीवन यापन की संभावनाएं धूमिल हो रही हैं। यहां के आदिवासी भील जनजाति के नाम से जाने जाते हैं। जिनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक नियमों एवं कानूनों में काफी बदलाव भी देखने में आये हैं जो भील जनजाति के लोग शहरी क्षेत्रों में समीपस्थ गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्य में धीरे-धीरे शिक्षित होकर कल-कारखानों में नियोजित होकर वहीं बस रहे हैं और नौकरियों आदि में आने लगे हैं, किन्तु जो लोग आज भी दैनिक जीवन की साधारण से साधारण सुविधाओं तक से वंचित हैं, उनकी वास्तविकता सभ्य समाज को बहुत कुछ सोचने को विवश करती है, जिसे अब और नहीं अनदेखा किया जा सकता है। इस संबंध में इस क्षेत्र में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं में कल्याणी समाज सेवा संस्थान, प्रयास तथा सारा कलिसिया समाज सेवी संस्थान के समाज सेविकाओं द्वारा यथा स्थिति को स्पष्ट करते हुए बताया कि यहां की अधिकांश अशिक्षित युवतियां एवं महिलाएं जहां मजदूरी के लिये गुजरात जाती हैं। वहां संभ्रात परिवार के लोगों द्वारा शारीरिक यौन शोषण भी किया जाता है तथा कुछ महिलाएं जो बाहर नहीं जा पाती हैं वे अपनी पड़ोसी महिलाओं की आधुनिक जीवन शैली के आकर्षण के मोह में फंस कर अपने ही क्षेत्र में यौनाचार जैसे घृणित कार्य में उतर पड़ती हैं।

अवधारणा – अनेक स्तरों पर आदिवासी स्त्रियां शोषित एवं दमित होती हैं किन्तु समाज के नवीकरण और सामाजिक विकास एवं उत्थान के विकसित संसाधनों और सुविधाओं के बढ़ते चरण को देखते हुए यह आशा अवश्य व्यक्त की जा सकती है कि दैहिक शोषण की परंपरा भले ही समाप्त नहीं की जा सके किन्तु इसमें कमी अवश्य लायी जा सकती है।

अध्ययन की आवश्यकता एवं अध्ययन का उद्देश्य – जनजातीय महिलाओं को शासन द्वारा गरीबी और बेरोजगारी निवारण के अब तक जितने उपाय किये गए और योजनाएं शुरू की गई उन सुविधाओं का शत प्रतिशत लाभ आदिवासियों और अति पिछड़े गरीबों को हासिल नहीं हुआ। अत: जनजातीय घरेलू एवं कामकाजी महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाना उचित है।

शोध प्रविधि – अध्ययन के लिए घरेलू एवं कामकाजी (50) महिलाओं का चुनाव किया तथा 1 समाज सेविका स्वंयसेवी संस्था द्वारा ली गई। अध्ययन में पाया गया कि कामकाजी महिलाओं को घरेलू महिलाओं की तुलना में अधिक सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कामकाजी महिलाओं को घरेलू महिलाओं की अपेक्षा अपने जीवन में अधिक कठिनाईयों का सामना करती है क्योंकि उन्हें दो परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। प्रस्तुत अध्ययन घरेलू एवं कामकाजी महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक समायोजन के स्तर ज्ञात करने हेतु किया गया। इस अध्ययन हेतु 25 घरेलू महिलाएं एवं 25 कामकाजी महिलाओं का चुनाव किया। अध्ययन हेतु प्रश्नावली का प्रयोग किया।

विश्लेषण एवं निष्कर्ष – उपरोक्त प्रश्नावली में 10 सामाजिक एवं 10

* सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र) शासकीय महाविद्यालय मनावर, जिला - धार (म.प्र.) भारत

आर्थिक स्तर ज्ञात हेतु कुल 20 प्रश्न थे। सही प्रश्न हेतु एक अंक दिया गया। इस प्रकार प्राप्त अंको के आधार पर सामाजिक–आर्थिक समायोजन का पॉच श्रेणी में निम्न विश्लेषण किया गया।

(अ) सामाजिक स्तर को दर्शाने वाली तालिका (देखे)

(ब) आर्थिक स्तर को दर्शाने वाली तालिका (देखे)

उपर्युक्त दोनों तालिका के अध्ययन में प्राप्त आंकड़ों से ज्ञात होता है कि 40 प्रतिशत घरेलू एवं 30 प्रतिशत कामकाजी महिलाओं में बहुत अच्छे स्तर का सामाजिक स्तर का समायोजन है। जबकि 30 प्रतिशत घरेलू एवं 40 प्रतिशत कामकाजी महिलाओं का आर्थिक स्तर का समायोजन है। 10–10 प्रतिशत घरेलू एवं कामकाजी महिलाओं में औसत सामाजिक स्तर का समायोजन है। जबकि 10–10 प्रतिशत घरेलू एवं कामकाजी महिलाओं का औसत आर्थिक स्तर का समायोजन है। घरेलू महिलाओं की अपेक्षा कामकाजी महिलाओं में 20 प्रतिशत अच्छा आर्थिक स्तर है।

अत: निष्कर्ष निकलता है कि कामकाजी महिलाओं का सामाजिक स्तर निम्न एवं घरेलू महिलाओं का स्तर उच्च है जबकि कामकाजी महिलाओं का आर्थिक स्तर उच्च और घरेलू महिलाओं का निम्न पाया गया इसका कारण कामकाजी महिलाएं शिक्षित होने से एवं बाहरी क्षेत्र में नियोजित होने से उनकी समझ शक्ति एवं समायोजन क्षमता विकसित होना हो सकता है।

सूझाव –

- जनजातीय महिलाओं में सामाजिक एवं आर्थिक स्तर में सकारात्मक वृद्धि हेतु शिक्षित एवं प्रशिक्षित किये जाने की आवश्यकता है।
- पारिवारिक संगठन का महत्व महिलाओं को समझाना आवश्यक है साथ ही पारिवारिक विघटन के भयानक सामाजिक परिणामों से महिलाओं को जागरूक किया जाना आवश्यक है।
- महिलाओं में सामाजिक एवं वैवाहिक समायोजन का संतानों पर पड़ने वाले अच्छे प्रभाव एवं दुष्प्रभावों से अवगत किया जाना आवश्यक है।
- विवाह योग्य युवक एवं युवती हेतु विवाह पूर्व एवं विवाह पश्चात् परामर्श देने हेतु शासकीय एवं अशासकीय परामर्श केन्द्र खोले जाना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. International Journal for Research in Education Vol 2 issue 7 July, 2013
2. प्रसाद ,ज्योति, 'मानवविकास का परिचय' पेज 403
3. शाह के.आर. 'आदिवासी सत्ता' पेज 13,38 (जुलाई,2013)

(अ) सामाजिक स्तर को दर्शाने वाली तालिका

क्रं.	सामाजिक स्तर	अंक	घरेलू महिलाएं	प्रतिशत	कामकाजी महिलाएं	प्रतिशत
1	बहुत अच्छा	8–9	04	40%	03	30%
2	अच्छा	7–6	03	30%	03	30%
3	औसत	5–4	01	10%	01	10%
4	निम्न	3–2	01	10%	01	10%
5	बहुत निम्न	1–0	01	10%	01	10%
	योग		10	100%	10	100%

(ब) आर्थिक स्तर को दर्शाने वाली तालिका

क्रं.	सामाजिक स्तर	अंक	घरेलू महिलाएं	प्रतिशत	कामकाजी महिलाएं	प्रतिशत
1	बहुत अच्छा	8–9	03	30%	04	40%
2	अच्छा	7–6	03	30%	03	30%
3	औसत	5–4	01	10%	01	10%
4	निम्न	3–2	01	10%	02	20%
5	बहुत निम्न	1–0	01	10%	–	0%
	योग		10	100%	10	100%

****

बाल श्रमिकों की समस्या - एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ. कल्पना कोठारी *

प्रस्तावना - 'बाल श्रमिक जब अपनी तूलना दूसरे बच्चों से करता है तो उसे अपनी लघुता का अहसास होता है। यह अहसास ही हीन भावना है हीन भावना से ग्रसित होकर जहां बच्चा अंतर्मुखी होकर अपने आपको धोखा देता है उसमें दायित्वहीनता अपराध बोध जैसे अनेक विकास घर करने लगते हैं और ऐसे बाल श्रमिक पूरा जीवन दु:ख एवं अभावों से जीने को मजबूर हो जाते हैं। 1500 डिग्री के तापमान पर खौल रहे पिघलते कांच को ढोने वाले और खतरनाक रासायनिक घोलो में कोमल नंगे हाथ डूबों कर ताले के लिए धातु के टुकडे तैयार करने वाले बच्चों से लेकर जिस्म बेचने मजबूर बच्चों को आज नई सुबह का इंतजार है। एक प्रसिद्ध गीत की पंक्ति है**-'तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के।'** लेकिन वक्त की सच्चाई यह है कि देश का भविष्य हमारे नैनीहाल बदहाल जिंदगी जी रहे हैं। इसमें से अधिकांश बच्चों ने या तो स्कूल देखा ही नहीं अथवा पढ़ाई बीच में छोड़ दी है। बच्चों के कल्याण को ध्यान में रखकर बहुतेरे नियम-कानून भी बने है, किन्तू वे प्रभावहीन रहे हैं।

बचपन जीवन की एक ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चा अपनी मर्जी से जीना चाहता है यह अवस्था जन्म से लेकर किशोर अवस्था तक पहुंचने की अवस्था होती हैं। इस अवस्था में शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए समुचित अवसर प्राप्त करना हर बच्चे का नैसर्गिक अधिकार है। परिवार समाज एवं राष्ट्र से यह अपेक्षा की जाती हैं कि वे बच्चों को संरक्षण प्रदान कर उन्हें विकास के समुचित अवसर प्रदान करें। संवैधानिक उपबंधों व अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के विधिक प्रावधानों में कदाचित यह कमी दिखाई भी नहीं देती फिर भी मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति, निर्धनता, अशिक्षा, असमानता के कारण समाज में बालश्रम की समस्या विकराल रुप लेती जा रही हैं। बच्चों से उनकी इच्छा व आवश्यकता के विरुद्ध बलात् तरीके से उन्हें जीविकोपार्जन का साधन बनाता बाल-श्रम का वास्तविक उद्देश्य है। बच्चे भविष्य के निर्माता है यदि उन्हें उचित अवसर एवं संरक्षण नहीं मिला तब वे भविष्य का निर्माण कैसे करेंगे? बाल-श्रम भारत की ही नहीं बल्कि वैश्विक समस्या है।

वर्तमान समय में हमारे देश में असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले बच्चों की संख्या सम्मिलित है जो घरों में कार्य करते है। बड़ी संख्या में बच्चे खतरनाक उद्योग जैसे-पटाखा एवं माचिस उद्योग, कालीन बुनाई उद्योग, रत्न कटाई एवं पालिश तथा काँच की वस्तु निर्माण ईकाईयों में काम करते है इन फैक्ट्रियों की कार्य दशाएं अस्वास्थकर एवं खतरनाक है इसमें मालिकों द्वारा सुरक्षा हेतू नियमों का पालन नहीं किया जाता है। कहीं-कहीं नियंत्रक अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है धन की लालच में गैरकानूनी शोषण को आंखे मूंदे देखते है। शिक्षा की कमी उपयुक्त एवं पोष्टिक भोजन का अभाव, स्वास्थ्य के प्रति लापारवाही इत्यादि इन बच्चों की दुर्दशा से जुडे हुए कारक है।

बाल-श्रमिक कौन ? - सामान्य तौर पर किसी उद्योग, कारखाने, खान आदि में श्रम करने वाले 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बाल-श्रमिक कहा जाता है। जेनेवा (स्विजरलैण्ड) स्थित अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई. एल. ओ.) में बाल-श्रम पर अपनी रिपोर्ट में बाल-श्रमिकों को परिभाषित करते हुए लिखा है -

'ये वे किशोर नहीं है जो दिन के कुछ घंटे खेल और पढ़ाई से निकालकर जेब खर्च के लिए काम करते हैं, ये वे बच्चे भी नहीं है जो पारिवारिक भूमि पर कृषि कार्य में सहायता करते है या घरेलू कामों से सहायता करते है बल्कि ये वे मासूम बच्चे है जो 10 से 18 घंटे (लगभग) काम करके कम पैसों पर अधिक श्रम बेचकर बुनियादि शिक्षा और खेल से वंचित रहते हुऐ भी कभी-कभी परिवारों से अलग रहते हुऐ वयस्कों की जिंदगी बिताने को मजबूर है।'

घरो-ढाबो, होटलो, बस अड्डों तथा छोटे बड़े औद्योगिक संस्थानों में ऐसे बच्चों को कार्य करते हुऐ देखा जाता है। जो अपना कार्य तो बड़ी कुशलता से करते है परन्तु शोषण के विरुद्ध संगठित होना या आवाज उठाना इन बेचारों के बस की बात नहीं है। भारत 2000 नामक पुस्तक के आकड़े बताते है कि भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रमिक वर्ग करीब 20 प्रतिशत योगदान देता है। जिसमें से लगभग 7 प्रतिशत योगदान बाल-मजदूरों का होता है।

यह शर्मसार सच्चाई है संसार में सबसे अधिक बाल-श्रमिक हिन्दूस्तान में है। सरकारी आकड़े के मुताबिक लगभग 11 करोड़ 10 लाख से भी ज्यादा बाल-श्रमिक है इसमें खेतीहर मजदूर, कल-कारखाने में, अनेक प्रकार के लघु कुटीर उद्योगों, पत्थर खदानों, होटलो, चाय की दुकानों और दूसरों के घरों पर कार्य कर रहे है। अनेक ऐसे खतरनाक या जोखिम भरे उद्योग/व्यवसाय है जिनमें काफी बड़ी संख्या में बाल-श्रमिक काम कर रहे हैं। जैसे-शिव काशी आतिशबाजी (तमिलनाडु), काँच एवं चूँड़ी उद्योग (फिरोजाबाद, उ. प्र.), रत्न पॉलिश उद्योग (सूरत, गुजरात) पीतल के बर्तन व कलात्मक वस्तु निर्माण (मुरादाबाद), हस्त-निर्मित कालीन उद्योग (अलीगढ़, उ. प्र.) स्लेट उद्योग (मन्दसौर, म. प्र.) आदि सभी जगह शारीरिक एवं मानसिक कोमलता वाले बाल-श्रमिक कार्य करते देखे जाते हैं।

उक्त स्वरुप के अलावा बाल-मजदूरी का एक अन्य पहलू है जो सामान्यत: बाल-मजदूरों के जिक्र से अछूता रह जाता है। वह है बाल मजदूरी बाल तस्करी का। हर वर्ष देश से पचास हजार के लगभग बच्चे लापता हो जाते हैं। ये गुमशुदा बच्चे बाल अनैतिक व्यापार, बंधुआ मजदूरी, जबरन भीख मंगवाना, मानव अंगों की तस्करी के अलावा लाखों बच्चों को बहला फुसलाकर माता-पिता को लालच देकर अथवा बाल-व्यापार के जरिए एक राज्य से दूसरे राज्यों में खरीदा और बेचा जाता है। संवेदनशीलता की कमी और मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण इस तरह के अपराध बढ़ रहे है।

* विभागाध्यक्ष (समाजशास्त्र) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सेंधवा, जिला- बड़वानी (म.प्र.) भारत

बाजारवाद इतना हावी हो गया है कि बच्चे भी वस्तु बन गए है।

भारत में यौन शोषण का कारोबार तथा जबरन श्रम के उद्देश्य बच्चों की तस्करी का कार्य देश में ही नहीं बल्कि देश से बाहर भी होता है। बच्चे की तस्करी, बच्चों की बिक्री, बलात एवं अनिवार्य श्रम, बाल वैश्यावृत्ति, बाल श्रमिकों से अश्लील फिल्मों में काम कराना, नशीली दवाओं की बिक्री आदि कार्यों हेतू बच्चे खरीदे और बेचे जाते हैं।

बाल-श्रम के अनेक कारणों में प्रमुखत: गरीबी, अशिक्षा, अज्ञानता, संयुक्त परिवार, रुढ़वादिता, क्षेत्रीय विविधता, प्रवास (प्रवर्जन), परम्परागत व्यवसाय अनैतिक व्यापार, नशीली दवाओं की बिक्री हेतू खरीदे और बेचे जाते है ऐसे बाल-श्रम के अनेक कारण है।

बाल-श्रम के परिणाम-

1. उद्योग जनित स्वास्थ्य समस्याऐ-

क्र.	व्यवसाय	बीमारी/असमर्थता
1.	माचिस एवं पटाखा उद्योग	श्वास के रोग अंगों का जलवा मांसपेशियों का क्षतिगस्त होना
2.	पत्थर खदानों अथवा स्लेट उद्योग	श्वास लेने हेतू अनुकूल वातावरण न होने से दम घुटने में असमय मृत्यु
3.	कालीन उद्योग	जहरीले कलर, रसायन, फाइवर रेशे, धूल से फेफडे की बीमारी
4.	काँच उद्योग	ज्यादा तापमान से प्रदुषित वातावरण में आयु क्षीण होने की संभावना
5.	बीड़ी उद्योग	सिरदर्द, थकान, आँख, नाक, गले एवं श्वास लेने की समस्या
6.	ताला उद्योग	अस्थमा, सिरदर्द, एसिड से जलना, ट्यूमर,क्षयरोग आदि होना
7.	ढ़ाबों पर काम करना	थकान, अत्यधिक थकान होने के कारण नशीले पदार्थो की ओर अग्रसर होना
8.	बैलून उद्योग	न्यूमोनिया एवं हृदय रोग की संभावना

2. मानसिक व शारीरिक यंत्रणा से बच्चों का विकास अवरुद्ध होना- बाल-श्रमिकों के साथ दुर्व्यवहार के कई रुप सामने आते है। उन्हें डराना, पिटाई करना, गलत कार्यों करने हेतू बाध्य करने जैसे अनेकों कार्य करवाये जाते है जिसमें-बलात्कार, बाल वैश्यावृत्ति एवं गंभीर बीमारी का शिकार साथ ही नशीले पदार्थो की तस्करी में लगाये गये बच्चों में 75 प्रतिशत बच्चे खुद इन नशीले पदार्थों का सेवन करने लगते हैं।

3. देश के विकास में बाधा - किसी भी देश के विकास में मानवीय और प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। मानवीय संसाधन स्वस्थ प्रशिक्षित नहीं होगा तो विकास प्रभावित होगा। ऐसे बाल-श्रमिक जब देश के भाविक नागरीक होगे तब वे स्वयं अपने व अपने परिवार के लिए अर्थपार्जन में असमर्थ होंगे।

4. वयस्क व्यक्तियों के रोजगार की समस्या - बाल-श्रम का एक गंभीर दुष्परिणाम यह है कि नियोक्ता उद्यमिता को बाल-श्रम सस्ते दामों पर उपलब्ध हो जाते हैं। अत: वयस्क श्रमिकों को काम कम मिलता है।

5. श्रम संगठनों की निष्क्रियता - श्रम संगठन श्रमिकों के अधिकार वेतन सुविधाओं आदि के हक के लिए काम करते हैं। लेकिन यह तभी कारगर है जब उद्यम में श्रमिकों का नियोजन द्वारा पंजीकरण हो, वह प्रशिक्षित हो। बाल-श्रमिकों को अवैधानिक तरीके से रखा जाता है इनका पंजीकरण नहीं होता है। ऐसी स्थिति में श्रम संगठन कहीं न कहीं निष्क्रिय हो जाते है।

उक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि बाल-श्रमिक के दुष्परिणाम व्यक्तिगत ही नहीं होते बल्कि राष्ट्र के हित के विरुद्ध भी है। अतएव बाल-श्रम का उन्मूलन आवश्यक है।

संविधान की धारा 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे का कारखाना अथवा ऐसे किसी काम में नहीं लगाया जा सकता जो जोखिम भरा हो। संविधान की धारा 39 में बच्चों के षोषण के विरुद्ध संरक्षण की व्यवस्था की गई हैं।

इसके अतिरिक्त बागान श्रमिक अधिनियम बना जिसके अनुसार चाय-कॉफी और रबर के बागानों में 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम नहीं लिया जा सकता। 1952 में बने खदान अधिनियम के अनुसार 16 वर्ष से कम किशोर से खदानों में काम लेने के लिए डाक्टरी प्रमाण-पत्र आवश्यक हो गया। मोटर परिवहन श्रमिक अधिनियम 1961 में 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी रुप में कार्य करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1966 के बीड़ी और सिगार अधिनियम तथा राज्यों में दुकान तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान अधिनियम पारित किया गया जिसके तहत् बीड़ी उद्योग, कालीन उद्योग, दियासलाई उद्योग, कपड़ा छपाई एवं रंगाई चमड़ा रेगजिन तथा अभ्रक उद्योग में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के काम करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया 1987 में राष्ट्रीय बाल-श्रम नीति बनाई गई जिसके अन्तर्गत बाल-श्रमिकों को शोषण से बचाने, उनकी शिक्षा, स्वास्थ, मनोरंजन तथा सामान्य विकास कार्यक्रमों पर बल की व्यवस्था की गई।

भारत के उच्चत्तम न्यायालय ने रिट याचिका में (सिविल संख्या 465/1986 में) अपने अगस्त 2000 के फैसले में कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए है जैसे-खतरनाक उद्योग धंधों में लगे बच्चों से काम कराने वाले मालिकों पर 20 हजार रुपये तक मुआवजे का भुगतान, बाल-मजदूरी पुनर्वास और कल्याण कोष की स्थापना खतरनाक उद्योग-धंधे से हटाए गए बच्चों के स्थान पर उनके परिवार के एक प्रौढ़ सदस्य को वैकल्पिक रोजगार देना अथवा प्रत्येक बच्चे के लिए 50 हजार रुपये तक की राशि का भुगतान, काम से हटाए गए बच्चों के लिए उपर्युक्त संस्थाओं में शिक्षा की व्यवस्था करना आदि शामिल है। सरकार ने उच्चतम न्यायालय के निर्देशों को प्रभावी बनाने के लिए पहल के रुप में अनेक कदम उठाए।

सरकारी नीतियों के अतिरिक्त विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा भी बाल-श्रम उन्मुलन के प्रयत्न किये जा रहे है। इस तमाम उपायों के बावजूद समस्या यथावत है अक्टुबर 2000 में यूनिसेफ के सम्मेलन में मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और पूर्व मुख्य न्यायाधीश जे. एस. वर्मा ने बड़ी सटीक टिप्पणी की है-'भारत के कानून ने बच्चों के विकास के अच्छे प्रावधान किए है लेकिन राजनैतिक और सामाजिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण इसे लागू करने में परेशानियॉ आती है। तुतलाते बोल, मासूम हँसी, कागज की कश्ती और हरेक को मुग्ध कर देने वाला मासूम बचपन आज उदास आँखें लिए आने वाले कल के प्रति सशंकित है और भूखे पेट ढेरों जानलेवा बिमारियों से जूझ

रहा है। वक्त का तकाजा यह है कि बचपन की नाजुक हथेलियों को थामने का प्रयास ईमानदारी पूर्वक किया जाये, क्योंकि बचपन कभी दोबारा लौटता नहीं।

बाल श्रम संबंधी कानून – बाल–श्रम एक सामाजिक बुराई है। इसे रोकने के लिए बच्चों के लिए उनकी विशेष परिस्थितियों के हिसाब से संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया है।

1. संविधान के अनुच्छेद 23 में किसी भी बच्चे से बलपूर्वक श्रम कराने, बेगारी कराने का मनाही है यह दण्डनीय अपराध है।
2. अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष की आयु से कम के बच्चों को किसी भी कारखाना, खान या अन्य खतरनाक व्यवसाय में लगाने पर प्रतिबंध लगाया है।
3. अनुच्छेद 39 (च) में यह उल्लेख मिलता है कि बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में विकास, स्वास्थ्य विकास के अवसर और सुविधाए दी जाए और बालको तथा अल्प वयस्क परित्याग से रक्षा की जाएगी।
4. संविधान के अनुच्छेद 39 (3) में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि सरकार द्वारा नीति का इस प्रकार संचालन किया जाना सुनिश्चित हो कि बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकताओं से मजबूर होकर ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु व क्षमता के अनुकूल न हो।

बाल–श्रम उन्मूलन के लिए विशेष रुप से खतरनाक उद्योगों में नीतियों और कार्यक्रमों को निर्धारित करने के लिए 1986 में नीतिगत कार्यक्रम योजना तैयार की थी इस नीति के प्रमुख बिंदु इस प्रकार है –

1. वैधानिक कार्य योजना – बाल–श्रम उन्मुलन संबंधी विधेयक अनिवार्य रुप से लागू करना।
2. बाल–श्रमिकों के सर्वांगीण विकास हेतू योजनाऐं लागू करना।
3. परियोजना आधारित कार्य योजना – इस परियोजना के अन्तर्गत बाल–श्रमिकों को औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा का प्रावधान। बाल–श्रमिकों के अभिभावकों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए स्वसहायता समूह का संचालन, बच्चों के लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था, बच्चों के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच। इस तरह इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाल–श्रमिकों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है।
4. 20 नवम्बर 1989 को संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौता पारित हुआ। बाल–श्रम निषेध के संदर्भ में अनुच्छेद 32 में यह स्पष्ट किया गया है कि बच्चों को आर्थिक व लैंगिक शोषण से मुक्त रखा जाए। किसी भी बच्चे को काम करने के लिए बाध्य न करे बच्चों के मुक्त व सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करना सुनिश्चित करें। 1994 में एक उच्च अधिकार प्राप्त निकाय राष्ट्रीय बाल–श्रमिक उन्मूलन प्राधिकरण का गठन किया गया। अत: इनके बगैर बच्चों की प्रतिभा विकसित नहीं हो सकती। 'प्रतिभा के मायने है, बुद्धि में नई–नई कोपले फूटते रहना। नई कल्पना, नया उत्साह, नई खोज, नई स्फूर्ति ये सब प्रतिभा के लक्षण है।'–विनोबा भावे

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. समाज शास्त्रीय निबंध – डॉ. माधवी लता दुबे, म. प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल।
2. भारतीय सामाजिक ढ़ांचा तथा समस्याएं–जितेन्द्र शुक्ला, बेस्ट फ्रेण्ड पब्लिकेशन्स, खजूरी बाजार, इन्दौर।
3. समूहिक परिचर्चा में प्रभावशाली कैसे बने–रजत अरूयर, अरिहंत पब्लिकेशन्स प्रा. लि., मेरठ।
4. मौलिक।

****

जनजातीय महिलाओं की समस्याएं एवं महिला सशक्तिकरण - एक विश्लेषणात्मक अध्ययन (अलीराजपुर जिले के सोण्डवा विकास खण्ड के विशेष संदर्भ में)

दिलीप सिंह चौंगड *

शोध सारांश - किसी समाज की प्रगति का मापदण्ड उस समाज द्वारा स्त्रियों को दी गई पद-मर्यादा है। जिस देश में स्त्रियाँ अधिक पढ़ी-लिखी हैं, जहाँ उन्हें पुरूषों के साथ कन्धा-से-कन्धा मिलाकर चलने का सुअवसर प्राप्त है, जहाँ इस सुअवसर का वे अपनी योग्यता और व्यवहार-कुशलता से लाभ उठाती है और जहाँ स्त्री की स्थिति एक गर्व की वस्तु है वहीं देश और समाज प्रगतिशील समझा जाता है। कहा जाता है कि नारी शक्ति का महान भण्डार है और नारी की वास्तविक महत्व परिवार के संदर्भ में ही समझा जाता है - नारी परिवार की नींव है, परिवार समुदाय की नींव है और समुदाय राष्ट्र की। अत: नारी ही समाज व राष्ट्र की नौका की वास्तविक कर्णधार है। यह आज का नहीं आदिकाल का सत्य है क्योंकि जैसा कि **रायडन** ने कहा 'स्त्रियों ने ही प्रथम सभ्यता की नींव डाली है और उन्होंने ही जंगलों में मारे-मारे भटकते फिरते हुए पुरूषों का हाथ पकड़कर उन्हें स्थिर जीवन या घर में बसाया है। मानव सभ्यता का भविष्य भी उन्हीं की सहयोगिता व सद्प्रयत्नों पर निर्भर है।' इसके विपरीत जनजातीय महिलाएँ परम्परागत रूप से सुदूर एवं दुर्गम क्षेत्रों में निवास करती थी। इन क्षेत्रों में आवागमन के साधन न के बराबर थे, इसीलिए जनजातीय महिलाएँ बाह्य जगत से पूर्णत: कटी हुई थी। उनकी अपनी संस्कृति एवं जीवन-यापन की पद्धति थी। अधिकांशत: वे बाह्य जगत में होने वाले उतार-चढ़ाव से अछूती रहती थीं। अध्ययन क्षेत्र में जनजातीय महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय है, जहाँ तक कि उनके लिए शिक्षा, वस्त्र एवं जीने के लिए पर्याप्त संसाधन भी नहीं है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए शोध अध्ययन में पाया कि जनजातीय महिलाओं की सामाजिक,आर्थिक,शैक्षिक एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान में महिला सशक्तिकरण का क्या योगदान रहा है ? महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य महिलाओं की आध्यात्मिक, राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक शक्ति में वृद्धि करना। इसमें अक्सर सशक्तीकृत महिलाओं द्वारा अपनी क्षमता के दायरे में विश्वास का निर्माण शामिल होता है। महिला सशक्तिकरण से महिलाओं को शक्ति प्राप्त हुई जिससे वे स्वयं समस्याओं को दूर करने में सक्षम हो रही हैं।

शब्द कुंजी - घरेलू, कामकाजी महिलाएँ, आर्थोपार्जन, महिला सशक्तिकरण, सुधार कार्यक्रम।

प्रस्तावना - मध्यप्रदेश में भील जनजातीय बहुल क्षेत्र के रूप में जाना जाने वाला अलीराजपुर जिला एक अविकसित जिले के रूप में ही चर्चित हैं। इस जिले में सबसे पिछड़ा सोण्डवा विकासखण्ड आता है। इस क्षेत्र में नदियों के अभाव के कारण ही सुदूर ग्रामीण इलाकों और आदिवासी बहुल वनों में जीवन यापन की संभावनाएं धूमिल हो रही हैं। यहां के आदिवासी भील जनजाति के नाम से जाने जाते हैं, जिनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक नियमों एवं कानूनों में काफी बदलाव भी देखने में आये हैं जो भील जनजाति के लोग शहरी क्षेत्रों में समीपस्थ गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्य में धीरे-धीरे शिक्षित होकर कल-कारखानों में नियोजित होकर वहीं बस रहे हैं और नौकरियों आदि में आने लगे हैं, किन्तु जो लोग अभी वहीं निवास कर रहे हैं वे आज भी दैनिक जीवन की साधारण से साधारण सुविधाओं तक से वंचित हैं, उनकी वास्तविकता सभ्य समाज को बहुत कुछ सोचने को विवश करती है, जिसे अब और नहीं अनदेखा किया जा सकता है। इस संबंध में इस क्षेत्र में महिलाओं की समस्याओं के निराकरण के लिये शासकीय और अशासकीय संस्थाओं द्वारा अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके बावजूद भी जनजातीय महिलाएं सशक्त होते नजर नही आ रहीं है।

अवधारणा - अनेक स्तरों पर आदिवासी स्त्रियां शोषित एवं दमित होती हैं किन्तु समाज के नवीकरण और सामाजिक विकास एवं उत्थान के विकसित संसाधनों और सुविधाओं के बढ़ते चरण को देखते हुए यह आशा अवश्य व्यक्त की जा सकती है कि जनजातीय महिलाएं समाज और सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरूषों के समान समझी जाती हैं और उन्हें आर्थिक,सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक और सुरक्षात्मक दिशा में आज उन्हें सभी क्षेत्रों में सहभागिता प्राप्त हो रही है।

अध्ययन की आवश्यकता एवं अध्ययन का उद्देश्य -जनजातीय महिलाओं को शासन द्वारा गरीबी और बेरोजगारी निवारण के अब तक जितने उपाय किये गए और योजनाएं शुरू की गई हैं उन सुविधाओं का शत प्रतिशत लाभ आदिवासियों और अति पिछड़े गरीबों को हासिल नहीं हुआ। अत: जनजातीय घरेलू एवं कामकाजी महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का अध्ययन किया जाना उचित है।

शोध प्रविधि - अध्ययन के लिए घरेलु एवं कामकाजी (50) महिलाओं का चुनाव किया तथा 1 समाज सेविका स्वंयसेवी संस्था द्वारा ली गई। अध्ययन में पाया गया कि कामकाजी महिलाओं को घरेलु महिलाओं की तुलना में अधिक सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कामकाजी महिलाओं को घरेलु महिलाओं की अपेक्षा अपने जीवन में अधिक कठिनाईयों का सामना करती है क्योंकि उन्हें दो परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। प्रस्तुत अध्ययन घरेलु एवं कामकाजी महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक समायोजन के स्तर ज्ञात करने हेतु किया गया। इस अध्ययन हेतु 25 घरेलू महिलाएं एवं 25 कामकाजी महिलाओं का चुनाव किया। अध्ययन हेतु प्रश्नावली का प्रयोग किया।

विश्लेषण एवं निष्कर्ष - उपरोक्त प्रश्नावली में 10 सामाजिक एवं 10

* शोधार्थी (समाजशास्त्र) शासकीय महाविद्यालय, अलिराजपुर (म.प्र.) भारत

आर्थिक स्तर ज्ञात हेतु कुल 20 प्रश्न थे। सही प्रश्न हेतु एक अंक दिया गया। इस प्रकार प्राप्त अंको के आधार पर सामाजिक–आर्थिक समायोजन का पॉच श्रेणी में निम्न विश्लेषण किया गया।

(अ) सामाजिक–आर्थिक संबंधी स्तर को दर्शाने वाली तालिका (देखे)

(ब) शैक्षणिक–स्वास्थ्य संबंधी स्तर को दर्शाने वाली तालिका (देखे)

दोनों तालिका के अध्ययन में प्राप्त आंकड़ों से ज्ञात होता है कि 40 प्रतिशत घरेलू एवं 30 प्रतिशत कामकाजी महिलाओं में बहुत अच्छे स्तर का सामाजिक स्तर का समायोजन है। जबकि 30 प्रतिशत घरेलू एवं 40 प्रतिशत कामकाजी महिलाओं का आर्थिक स्तर का समायोजन है। 10–10 प्रतिशत घरेलू एवं कामकाजी महिलाओं में औसत सामाजिक स्तर का समायोजन है। जबकि 10–10 प्रतिशत घरेलू एवं कामकाजी महिलाओं का औसत आर्थिक स्तर का समायोजन है। घरेलू महिलाओं की अपेक्षा कामकाजी महिलाओं में 20 प्रतिशत अच्छा आर्थिक स्तर है।

अत: निष्कर्ष निकलता है कि कामकाजी महिलाओं का सामाजिक स्तर निम्न एवं घरेलू महिलाओं का स्तर उच्च है जबकि कामकाजी महिलाओं का आर्थिक स्तर उच्च और घरेलू महिलाओं का निम्न पाया गया इसका कारण कामकाजी महिलाएं शिक्षित होने से एवं बाहरी क्षेत्र में नियोजित होने से उनकी समझ शक्ति एवं समायोजन क्षमता विकसित होना हो सकता है।

सूझाव –

- जनजातीय महिलाओं में सामाजिक एवं आर्थिक स्तर में सकारात्मक वृद्धि हेतु शिक्षित एवं प्रशिक्षित किये जाने की आवश्यकता है।
- पारिवारिक संगठन का महत्व महिलाओं को समझाना आवश्यक है साथ ही पारिवारिक विघटन के भयानक सामाजिक परिणामों से महिलाओं को जागरूक किया जाना आवष्यक है।
- महिलाओं में सामाजिक एवं वैवाहिक समायोजन का संतानों पर पड़ने वाले अच्छे प्रभाव एवं दुष्प्रभावों से अवगत किया जाना आवश्यक है।
- विवाह योग्य युवक एवं युवती हेतु विवाह पूर्व एवं विवाह पश्चात् परामर्श देने हेतु शासकीय एवं अशासकीय परामर्श केन्द्र खोले जाना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. International Journal for Research in Education Vol 2 issue 7 July, 2013
2. प्रसाद ,ज्योति, 'मानवविकास का परिचय' पेज 403
3. शाह के.आर. 'आदिवासी सत्ता' पेज 13,38 (जुलाई,2013)

(अ) सामाजिक–आर्थिक संबंधी स्तर को दर्शाने वाली तालिका

क्रं.	सामाजिक स्तर	अंक	घरेलू महिलाएं	प्रतिशत	कामकाजी महिलाएं	प्रतिशत
1	बहुत अच्छा	8–9	04	40%	03	30%
2	अच्छा	7–6	03	30%	03	30%
3	औसत	5–4	01	10%	01	10%
4	निम्न	3–2	01	10%	01	10%
5	बहुत निम्न	1–0	01	10%	01	10%
	योग		10	100%	10	100%

(ब) शैक्षणिक–स्वास्थ्य संबंधी स्तर को दर्शाने वाली तालिका

क्रं.	सामाजिक स्तर	अंक	घरेलू महिलाएं	प्रतिशत	कामकाजी महिलाएं	प्रतिशत
1	बहुत अच्छा	8–9	03	30%	04	40%
2	अच्छा	7–6	03	30%	03	30%
3	औसत	5–4	01	10%	01	10%
4	निम्न	3–2	01	10%	02	20%
5	बहुत निम्न	1–0	01	10%	–	0%
	योग		10	100%	10	100%

****

सामाजिक विकास की अवधारणा एवं उसकी मुख्य चुनौतियॉ

प्रो. आई. एस. सस्त्या * डॉ. आर. सी. पान्टेल **

प्रस्तावना – समाजिक विकास– सामाजिक विकास की संकल्पना में आर्थिक विकास के साथ–साथ सामाजिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक विकास भी सम्मिलित होता हैं। सामाजिक विकास सामुहिक प्रकृति वाले होते हैं। सामाजिक विकास के अन्तर्गत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये आवश्यक है कि समृद्धि का लाभ समान रूप से समाज के सभी वर्गो को प्राप्त हो सकें।

सामान्य दृष्टिकोण से सामाजिक विकास का तात्पर्य होता हैं, 'समाज की समग्र उन्नती' सम्पूर्ण जनसंख्या के सभी वर्गो को आर्थिक समृद्धि, सामाजिक समानता एवं न्याय प्रदान करना। स्वतंत्रता समानता तथा बंधुत्व जितने विकसित व्यक्तियों के गुण हैं। उतने ही वे विकसित समाज के गुण हैं क्योकि व्यक्ति का समाज एक दूसरे से अन्त: संबंधित हैं। जो व्यक्ति आत्म निर्भर, उत्पादक तथा सभ्य हैं। उसे ही सामान्यत: विकसित कहा जाता हैं तथा जो समाज अपने सदस्यों को विकल्प तथा कार्य करने की स्वतंत्रता, अवसरों की समानता तथा एक दूसरे के साथ मिलने जुलने का अवसर प्रदान करता हैं। वह सामान्यत: विकसित समाज माना जाता हैं। विकास एक प्रकार से उन्नत दिशा की ओर होने वाला परिर्वतन हैं। सामाजिक विकास, सामाजिक परिर्वतन का एक ऐसा स्वरूप हैं जिसमें उन्नत दिशा की ओर विभेदी करण होता हैं। सामाजिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये आर्थिक लक्ष्य को प्राप्त करना आवश्यक होता हैं। इन लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए एम.एस. गौरे का मत हैं सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा पर्यावरण के विकास से हैं। सामजशास्त्रीयों ने विकास के मुद्दे को अनेक श्रेणियों जैसे पोषण आहार, स्वास्थ्य शिक्षा, अवकाश व मनोरंजन, सुरक्षा और समृद्धि, उत्पादन व आमदनी, उत्पादन की स्थितियॉ, जीवन स्तर, जीवन व कार्य के प्रति दृष्टिकोण, नितियों के अर्न्गत वर्णित किया हैं।

सामाजिक विकास के लक्ष्य – मनुष्य की कोई भी कार्य योजना किसी भी समय किसी भी प्रकार के समाज में बिना लक्ष्य लिये हुए नहीं रहती हैं। प्रत्येक कार्य के पिछे कोई न कोई उद्देश्य अवष्य निर्धारित होता हैं। जिसे प्राप्त करने के लिये मनुष्य साधनों का प्रयोग करते हुए सतत प्रयत्न करता रहा हैं। सामाजिक लक्ष्य निम्नांकित हैं–

1. ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें आम लोगों के लिये जीवन व्यापन की स्थितियॉ बेहतर हो, लोग भुख से पिडित न हो तथा उन्हे जीवन की आधार भुत आवश्यकताओं से वंचित न होना पडे।
2. ऐसे आधारभुत तथ्य तैयार करना जिसमें लोगों की मौलिक आवश्यकताओं के सभी स्तरों की पूर्ति हो सकें। इसमें समाज के गरीब और शौषित वर्ग सम्मिलित हैं।

समाजिक विकास के सूचक – भारत जैसे देश में व्यक्ति के सामाजिकरण में जामातिक विकास की मुख्य भुमिका होती है। सामान्यत: आर्थिक विकास ही उचित माप सामाजिक विकास ही हैं क्योंकि सामाजिक विकास का संबंध किसी एक क्षेत्र में न होकर अनेक क्षेत्रों के होता हैं। जीवन स्तर, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन, सामाजिक समानता, जन स्वास्थ्य, शिक्षा के अवसरों की समानता, सार्वजनिक सुरक्षा एवं कल्याण, संगठनों एवं संस्थाओं की प्रर्याप्त संख्या, स्वतंत्रता आदि सामाजिक विकास के प्रमुख सुचक माने जाते हैं तिनकी पूर्ति के लिये बिना कोई भी राष्ट्र सामाजिक विकास की कल्पना नहीं कर सकता हैं और प्रत्येक राष्ट्र उपरोक्त तथ्यों को बढावा देने की सकारात्मक पहल करता हैं।

समाजिक विकास की रणनितियॉ – समाजिक विकास की रणनितियों को अन्तर्राष्ट्रीय, गैर सरकारी, सामुदायिक संगठनों या अलग अलग राज्यों के द्वारा परिवर्तन के लिये व्यावहारिक मार्ग अपनाने के प्रयत्नों के रूप में परिभाषित किया जा सकता हैं। श्री हट्टन का मत हैं कि सामाजिक विकास निर्णयकर्ताओं की समस्याओं के समाधान हेतु विद्यमान आर्थिक, समाजिक संस्थाओं और परम्पराओं में परिर्वतन का प्रयास हैं। अत: अभिवृद्धि एवं समानता, न्यनतम आवश्यकताएँ तथा जीवन की गुणात्मक प्रमुख रणनीतियॉ होती हैं।

पंचवर्षीय योजनाओं में विकास – आजादी के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने वर्ष 1947 में प0 जवाहर लाल नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक कार्यक्रम समिति का गठन किया। इस समिति ने 25 जनवरी 1948 को अपने प्रस्ताव में सिफारिश की कि देश में एक स्थायी योजना आयोग की स्थापना होनी चाहिए। फलस्वरूप 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया जिसकी अनुषंसा पर प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से लागु की गई। योजना आयोग ने निम्नांकित उद्देश्यों को महत्व प्रदान किया।

1. देश में मौलिक पुॅजीगत, मानवी तकनीकि तथा कर्मचारी वर्ग संबंधी साधनों का अनुमान लगाना तथा जो साधन राष्ट्रीय आवश्यकताओं कह तुलना में कम दिखे उनकी वृद्धि की संभावनाओं के संबंध में अनुसंधान करना।
2. नियोजन में स्वीकृत कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं के बारे में प्राथमिकता निश्चित करना।
3. देश में साधनों के संतुलित उपयोग हेतु योजना बनाना।
4. आर्थिक विकास की गति को रोकने वाले तत्वों को इंगित करना।
5. समय समय पर योजना की प्रगति का मुल्यांकन करना।

प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951–1956 से प्रारम्भ होकर 12 वीं पंचवर्षीय योजना 2012– 2017 वर्तमान में क्रियाशील हैं जिसके मुलभूत उद्देश्य निम्नांकित हैं–

1. सकल घरेलु दर 34.02 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया।
2. कृषि दर वृद्धि का लक्ष्य 4 प्रतिशत रख गया।

* सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र) शासकीय महाविद्यालय, मनावर, जिला धार (म.प्र.) भारत
** सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र) शासकीय महाविद्यालय, मनावर, जिला धार (म.प्र.) भारत

3. शिक्षा के गुणवत्ता विकास पर बल देना।
4. शिक्षा में सामातिक, लैंगिग एवं क्षेत्रिय अन्तरालों को कम करना।
5. योजगार सृजन में तीव्रता लाना।
6. निजी निवेश में उच्च वृद्धि, तीव्र पुनरूत्थान के लिये स्थितियॉ पैदा करना।
7. ऊर्जा और परिवहन के क्षेत्र में विशेषकर कोयला, विद्युत, राष्ट्रीय राजमार्ग, रेल्वे व नगर विमानन में आपूर्ति संबंधी बाधाऍ दूर करना।

प्रथम पंचवर्षीय योजना से लगाकर बाहरवीं पंचवर्षीय योजना के माध्यम से विकास की सच्ची कल्पनाऍ की गई हैं परन्तु कहीं न कहीं सामजिक विकास के अवरोध कारक उत्पन्न हो जाते हैं जिससे निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो सकी हैं।

राजनैजिक संरचना, प्रतिकुल भौगोलिक परिस्थितियॉ, साधनों का अभाव, जनता में व्यापक धार्मिक अविश्वास, जनता में विकास के प्रति उदासीनता, शासक वर्ग की निरंकुशता, सरकारी प्रयासों का अभाव, व्यक्तिव वादीता आदि अवरोधकारकों की उपस्थिति में सामाजिक विकास की कल्पना एक कोरी कल्पना साबित हो रही हैं। विकास की चुनौतियों में सबसे बडी बाधा सामाजिक समस्याऍ हैं क्योंकि सामाजिक समस्याओं से समाज का बडा भाग प्रतिकुल रूप से प्रभावित होता हैं। साामाजिक समस्याओं की उपलब्धता के कारण समाज में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती हैं।

जातिवाद, क्षेत्रवाद, सामप्रदायिकता, भ्रष्ट्राचार, बेराजगारी, निर्धनता, जनसंख्या वद्धि कुछ ऐसी सामाजिक समस्याये हैं जिनकी उपस्थिति में विकास के अथाह प्रयास भी शिथिल हो जाते हैं।

सुझाव–

1. समाजिक विकास को गति तभी प्राप्त हो सकती हैं। जब अधिक से अधिक क्रियान्वित योजनाओं का तीव्रगति से मुल्यांकन किया जाए।
2. भ्रष्ट्राचार को रोकने हेतु शक्त कदम उठाये जाये।
3. समजिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये सामाजिक कार्यकर्ताओं का सहयोग लिया जाये।
4. नौकरशाही तंत्र को ईमानदारी का पाठ पडाया जाये।
5. देश में ऐसे लोगों की सही गणना की जाये जिन्हें विकास की वास्तविक आवश्यकता हैं।
6. जनसंख्या वृद्धि को ठोस कदम उठा कर रोका जाये।
7. देश में अंधविश्वासी लोगों में वर्तमान के प्रति जागरूकता उत्पन्न की जाये।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. अरिहंत पब्लिकेशन (इण्डिया) मेरठ।
2. भारत का आर्थिक विकास।
3. मध्यप्रदेश गजट।
4. युनिफाईड समाजशस्त्र, गुप्ता शर्मा।
5. आर्थिक संरचना एवं प्रणाली, रामरतन शर्मा।

****

नैतिक मूल्यों के गिरावट में परिवार एवं समाज की भूमिका

डॉ. आर.सी. पान्टेल * प्रो. आई.एस. सस्त्या **

शोध सारांश – भारत में शिक्षा एक संस्कार है। संस्कारों से ही सभ्यता व संस्कृति का जन्म होता है, जैसे संस्कार होंगे वैसी ही सभ्यता व संस्कृति होगी। आज के युग में जब शिक्षा जैसे पवित्र संस्कारों में झूठ,फरेब,बेइमानी व लालची प्रवृत्ति की व्यावसायिकता का जाल फैला हो तो हम कल्पना कर सकते हैं, कि आने वाले समय में भारत की सभ्यता व संस्कृति के क्या मायने होंगे जिस पर कभी हमें नाज होता था। नैतिक मूल्यों का दिन प्रतिदिन पतन हो रहा है।

भारतीय संस्कृति का मुख्य प्रतीक कमल है। कमल को सारे प्रतीकों का राजा भी कहा जाता है। भारतीय संस्कृति में कमल की सी सुगन्ध आ रही है।इस संस्कृति में ईश्वर के सारे अंवयवों की तुलना कमल से की गई है। भरतीय संस्कृति में दूसरा महान प्रतीक यज्ञ अथवा हवन है जिसका अर्थ है, त्याग। समाज में हमें एक–दूसरे के लिये कष्ट सहना पडेग़ा, त्याग करना पडेग़ा। कोई भी संस्कार हो, कोई भी समाज सेवा का काम शुरू कीजिये, आपको उसमें हवन करना ही पडेग़ा। यदि आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो अपने सारे सुखों का हवन करना पडेग़ा। विवाह के समय भी हवन होता है। यदि आप दोनों संसार में आनन्द चाहते हैं तो परंपरा के लिये अपनी व्यक्तिगत इच्छा का हवन करना पडेगा तभी आपका गृहस्थाश्रम सुखी बन सकेगा। यदि कोई अपना हठ चलाना चाहे तो फिर सुख कैसे मिल सकेगा। संसार तो मानों सहयोग है, लेन–देन है। आपका गृहस्थाश्रम भी समाज के लिये ही है।

प्रस्तावना – समाज की वर्गीकरण व्यवस्था यूँ तो पुरातन काल से चली आ रही है जो आज भी व्याप्त है और चर–अचर काल तक बनी रहेगी। वर्गीकरण की यह व्यवस्था हर युग की कर्णधार बनी है तथा नए –नए रूपों में आकर मानव जाति में अवसाद उत्पन्न करती रही है। तथा समाज के अस्तित्व पर अपना अतिशेष प्रभाव प्रकट करती रही है। शिक्षा में नैतिक मूल्यों का समावेष होना चाहिए ताकि अपना हित चाहने वालों के द्वारा हमेशा स्मृतिपूर्वक सम्पूर्ण शुभ आचरणों का व्यवहार करना चाहिए। अच्छे आचरण का पालन करने से मानवों को एक साथ दो लाभ होंगे, स्वास्थ्य लाभ और इन्द्रिय विजय। देव, गो,गुरू, वृद्ध,विद्वानों,आचार्यो का आचरण अनुसरण करें। झूठ न बोले,अन्य पर आरोप न करना,शत्रुता में रूचि न रखें, न तो पाप करें, न पाप करने वालों का साथ दें और पापी न पापी बने। स्त्री का अपमान न करें। वर्तमान पीढ़ी के बच्चों को इन नैतिक मूल्यों से कोई लेना–देना नहीं। टी.वी.और मोबाईल ने हमारे सामाजिक जीवन में सर्वाधिक सशक्त माध्यम के रूप में महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। इसके द्वारा जहां सूचनाओं, ज्ञान तथा मनोरंजन में वृद्धि हुई है, वहीं इसके नकारात्मक प्रभावों को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। यही नई पीढ़ी को गलत दिशा देने का कार्य कर रहा है। टी.वी.एवं मोबाईल के द्वारा सेक्स,सामाजिक हिंसा,कुटिलता और सामाजिक अपराधों को बढ़ावा मिल रहा है। नैतिक मूल्यों में गिरावट आ रही है।

समाज में नैतिक मूल्यों का महत्व एवं उपचार – वर्तमान युग को सूचना प्रौद्योगिकी के विस्फोटक युग की संज्ञा दी जाती है। इससे प्रौद्योगिकी के विस्तार के साथ ही जनसंचार के माध्यमों का भी तीव्रतम विकास हुआ है। जनसंचार के क्षेत्र में विज्ञापन का बहुत खास स्थान रहा है। रेडियो,टी.वी., मोबाईल,समाचार–पत्र,पत्रिकाएं,इन्टरनेट आदि। विज्ञापन के इन विकल्पों में टी.वी. और मोबाईल एक सशक्त माध्यम है। मनुष्य की एक स्वाभाविक आदत होती है किवह बुराई को कभी ग्रहण नहीं करना चाहता क्योंकि समाज में उसकी निंदा होती है,अत: व्यक्ति के जीवन में बुराई, अच्छाई का चोला पहनकर प्रवेश करती है, जैसे रावण साधु के वेष में आया और सीता का हरण कर लिया। अगर वह रावण के रूप में आता तो सीता हरण संभव नहीं था। ठीक ऐसे ही दुर्गुण,बुराई व भ्रष्टाचार अच्छाई का चोला पहनकर समाज में शामिल होते हैं, और समाज के नैतिक व सामाजिक मूल्यों पर प्रहार करते हैं। टी.वी. व निजी चैनलों में दिखाये जाने वाले कार्यक्रमों में अष्लीलता, क्रुरता,भड़कीले वस्त्र व मेकअप के द्वारा ग्लैमर दिखाया जा रहा है, मानों न्यूनतम वस्त्रों में पेश करने का बीड़ा उठा रखा है,जो सभ्य समाज के लिये किसी भी प्रकार से स्वीकार्य नहीं है। अर्द्धनग्न व देह व्यापार की जो तस्वीर प्रस्तुत की जाती है,उससे समूचे समाज की ऑखें शर्म से झूक जाती है। भारी ऐतराज की बात तो यह है कि सीरियलों में दिखाये जाने वाले दम्पत्ति महिला,बच्चे या बुजुर्ग एक भी ऐसा नहीं है, जो शुरू से अंत तक अच्छे संस्कार अच्छी सोच और अच्छी भावनाएँ दे सके। जिस तरह बुराई को ग्लैमराइज्ड किया जा रहा है,उसका सर्वाधिक प्रभाव युवावर्ग पर छाया हुआ है। वह आधुनिकता के समुद्र में गोते खा रहा है।

दिशाहीन, उद्देश्यहीन और नैतिक मूल्यों से दूर होकर पारिवारिक तनाव तथा रिश्तों के अमर्यादित आचरण कर 'लिव इन रिलेशनशिप' जैसे संबंधों को बखुबी अपना रहा है, जिससे 'यूज एण्ड थ्रो'जैसे संबंध पनपने लगे हैं जो हमारी विवाह संस्था का मजाक उड़ा रहे हैं। यही नहीं पाश्चात्य संस्कृति मोबाईल, एस.एम.एस.,फेसबुक तथा व्हाटसएप जैसी अनचाही संस्कृति ने युवाओं के भविष्य को असुरक्षित कर दिया है। बढ़ती बेरोजगारी, डिग्रियों की घटती उपयोगिता के चलते युवा वर्ग भ्रमित होकर कई अपराधों को जन्म दे रहे हैं, जो हमारे परिवार तथा राष्ट्र के लिए खतरा है। विज्ञापन भी अनेक विकृतियाँ उत्पन्न कर रहे हैं। दूरदर्शन और निजी चैनलों के एंकर्स,बी.जे.बालाएँ देह प्रदर्शन की प्रतिस्पर्द्धा में हद पार कर चुकी है। यह तो समझ में आता है कि महिलाओं के उपयोग की सामग्री को महिला ही विज्ञापित करें,परन्तु पुरूष उपयोग की सामग्री में महिला की विज्ञापित छवि को क्या कहा जाय पुरूषों द्वारा प्रयुक्त रेजर,शैम्पु,शर्ट्स,जूते,परफयूम,बॉडी स्प्रे,पावडर सेविंग क्रीम

*सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र) शासकीय महाविद्यालय, मनावर, जिला धार (म.प्र.) भारत
**सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र) शासकीय महाविद्यालय, मनावर, जिला धार (म.प्र.) भारत

छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति - एक ऐतिहासिक परम्परा

डॉ. मंजू गायकवाड़ *

प्रस्तावना -लोक कला, लोक गीत, लोग कथा, लोक संगीत एवं लोक साहित्य का समन्वित रूप लोक संस्कृति है जो परम्परागत रूप से जीवित एवं विकसित होती रही है। प्रत्येक पीढ़ी का मनुष्य अपनी ओर से इसके स्वरूप को सजाता एवं संवारता रहा है। लोककला की जडें ग्रामीण परिवेश में गहरी होती है। लोक कलाकार की व्यक्तिगत सृजन प्रतिभा भी होती है। लोक कलाओं का मूल रूप सामाजिक एवं सांस्कृतिक होता है जिसमें प्राचीन परंपराओं का विशेष महत्व होता है। लोक कला में क्षेत्रगत स्थानीयता होती है। किसी क्षेत्र की लोक कला में हमें वहां की विशेषताओं का प्रभाव दिखाई देता है। हमें उस क्षेत्र विशेष में रहने वाले समाज पर लोक कला का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। अत: किसी क्षेत्र विशेष की लोक कला का अध्यन कर हम वहां की समाजिक संस्कृतिक वातावरण की जानकारी प्राप्त कर सकते है। लोक कला परम्पराओं के प्रवाह के साथ विकसित होती है। अत: इनके माध्यम से हमें किसी क्षेत्र में प्रचलित ऐतिहासिक परम्पराओं का ज्ञान होता है।

छत्तीसगढ़ में प्रचलित लोक कलाओं के माध्यम से हम यहां की संस्कृति को जान सकते है। यहां पर परम्पराओं के रूप में प्रचलित आचार-विचार, रहन-सहन को हम लोक कलाओं के दर्पण में झांककर देख सकतें है। छत्तीसगढ़ लोक कलाएं यहा की सांस्कृतिक विरासत की प्रतिबिंब हैं। यहां के समाज कृषि प्रधान एवं ग्रामीण क्षेत्र होते है। जहां रचे-बसे लोक गीतों, लोक नृत्यों, लोक संगीत, लोक वार्ता, लोक चित्र, लोक शिल्प में यहां कि परम्पराओं का इतिहास छुपा है। छत्तीसगढ़ का बहुत बडा हिस्सा जनजातियों का रहा है जहाँ का लोक जीवन परम्परागत जीवन शैली को प्रदर्शित करता है साथ ही नवीन सामाजिक परम्पराओं को अपने भीतर समेट कर स्वंय को समृद्ध करता है। पंथी गीतो के माध्यम से एक नये सामाजिक ढांचे का प्रादुर्भाव देखा जा सकता है। स्वतंत्रता आंदोलन संबंधी गीतों में लोक जीवन में व्याप्त विचारधारा स्पष्ट होती दिखाई देती है। शैल चित्रों के आखेट के दृश्य , पशु-पक्षी ,मानव आकृतियाँ ,युद्ध के दृश्य ,पारिवारिक दृष्य ,नृत्य,वाद्य, आदि दिखाई देते है। चित्रों में पूजा-पाठ एवं धार्मिक क्रियाओं का प्रदर्शन होता है।

छत्तीसगढ़ के लोक जीवन में गोदना की परम्परा है जहां शरीर पर गुदवाया जाता है। जिसके पीछे मान्यता ये होती है। कि बाह्य आभूषण तो मृत्यु के उपरांत निकाल लेते है किन्तु 'गोदना' रूपी आभूषण शरीर के साथ ही जाता है अत: यह चिरसंगिनी आभूषण है साथ ही कम खर्चे में यह गरीबों के सौंदर्यप्रियता व आभूषणों की रूचि को पूर्ण कर देता है। छत्तीसगढ के आदिवासी एवं ग्रामीण अंचल में इसका प्रसार अधिक है। दशहरा -दीपावली के अवसर पर मिट्टी के गणेश -लक्ष्मी ,रावण ,दुर्गा आदि की प्रतिमा बनाते हैं। काष्ठ कला में देवी-देवताओं की मूर्तियां बनाते है जिसमें धार्मिक वातावरण की झांकी प्रस्तुत होती है। धातुशिल्प में हाथी, घोड़े के साथ देवी -देवताओं की कलाकृतियां बनाई जाती है जिनका प्रचलन रायगढ सरगुजा, बस्तर क्षेत्र में अधिक है।

लोक कला के अतिरिक्त लोक साहित्य, लोक गीत, लोक नृत्य एवं लोक कथा के माध्यम से हमें छत्तीसगढ के समाज का इतिहास पता चलता है। यहां के लोगों का जीवन सरल है उसमें कृत्रिमता का अभाव होता है। लोक-गीत बाह्य एवं आंतरिक जीवन के परिचायक है उनमें सूक्ष्मता नहीं स्थूलता और सहजता होती है। ये संक्षिप्त, स्पष्ट, सरल, सहज, सुन्दर व संगीतमय होते हैं। लोक गाथा भी वस्तुत: लोक गीतों का ही आधार होते है। जिनमें प्रेम, जाति, वीरता, शौर्य और युद्ध का विवेचन मिलता है, इसी को लोक गाथा कहते है।

छत्तीसगढ़ राज्य में जो लोक गाथाएं प्रचलित हैं उनमें ढोला-मारू, देवार गीत, लोरिक- चंदा, चन्देनी ,आल्हा पंडवानी आदि प्रसिद्ध हैं,लोक जीवन में लोक कहावतों का भी स्थान है जिसे 'हाना' कहते हैं। लोक गीतो में सोहर गीत ,बरूआ, गीत ,बिदा के गीत संस्कार संबंधी होते हैं। धार्मिक गीतों में देवी सेवा के गीत ,गौरा पूजा, भोजली गीत, उत्सवी गीतों में जन्माष्टमी के आठे कन्हैया, फागुन में फाग के गीत प्रमुख हैं। लोकनृत्य में डंडा नृत्य, पंथी नृत्य, गैंडी नृत्य, करमा नृत्य, सुवा नृत्य, राउत नाचा, बांस गीत व नृत्य, ददरीया, देवार गीत, ढोलान्मारू गीत, आल्हा गीत,पंडवानी गीत, गोपचंद गीत, श्रवण का सरून गीत आदि ये सभी इस अंचल में गाये तथा किये जाने प्रमुख गीत व नृत्य है जो कि लोक संस्कृतिक का महत्वपूर्ण अंग है। करमा नृत्य धार्मिक प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है। पंथी नृत्य छत्तीसगढ के सतनामी समाज का प्रतिनिधित्व करता है। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति यहां का प्राण है और इसे देखकर हम छत्तीसगढ़ी के ग्रामीण समाज का इतिहास जान सकते है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. छत्तीसगढ़ का इतिहास - रमेद्रनाथ मिश्र एवं शांता शुक्ला (1990)
2. छत्तीसगढ़ी लोक गीतों का परिचय - श्यामाचरण दुबे (1939)
3. दण्डकारण्य का सांस्कृतिक इतिहास - हीरालाल शुक्ल (1977)
4. प्राचीन छत्तीसगढ़ - प्यारेलाल गुप्त - (1973)
5. Folk Culture and Peasant Society in India – Indra Dev (1973)
6. Folk Culture and oral tradition – S.L. Shrivastava(1974)

लोकवार्ता संबंधी पारिवारिक शब्दावली

1. Ballad बैलेड (कथा गीत)
2. Epic-Lay इपिक्ले, लोकगाथा (प्रबंध गीत, लोक महाकाव्य)
3. Legends अवदान

* सहायक प्राध्यापक (समाज शास्त्र) शासकीय जे.यो. छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)भारत

4. Fairy Tales (परिकथाएं)
5. Fokl-Tales `m Tale type (कथा रूप)
6. Motifs (कथाभिप्राय)
7. Folk Dramas (लोक नाट्य जैसे महाराष्ट्र का तमाशा, यू.पी.की नौटकी, स्वांग, रासलीला ,एम,पी. की रामलीला छत्तीसगढ में नाचा (राउत) व गम्मत
8. Folk Arts लोककलाएं –जैसे बंगाल की अल्पना, महाराष्ट्र की व गुजरात की रंगोली, उ.प्र. का चौक पुरना, राजस्थान का माडवा और छत्तीसगढ का चौक पुरना
9. Folk Etymology (लोकव्युत्पत्ति) जैसे लायब्रेरी व रायबरेली
10. Folk Heroes लोक नायक

****

आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य की समस्या – एक समाज शास्त्रीय अध्ययन ,छत्तीसगढ़ राज्य के संदर्भ में

डॉ. मंजू गायकवाड़ *

प्रस्तावना – विभिन्नता युक्त भारत एक कृषि एवं ग्राम प्रधान देश है जहाँ विविध प्रकार के आदिवासी अलग–अलग भौगोलिक क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं। सन् 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 1,09,54,52,000 है। जहॉ 8,76,28,160 अर्थात् लगभग 8 प्रतिशत आदिवासी 400 समूहों में रहते हैं। मध्य प्रदेश से अलग होकर बना छत्तीसगढ राज्य 01 नवंबर 2000 को गठित हुआ है। हमारे राज्य छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 2,08,33,803 (सन् 2001 की जनगणना के अनुसार) यहॉ आदिवासियों की संख्या सर्वाधिक 66,16,596 अर्थात 31.76 प्रतिशत है। अत: इसे आदिवासी बाहुल्य राज्य कहा जाता है। जिस राज्य में सर्वाधिक आदिवासियों हो हम उसकी उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। ये आदिवासी न केवल मानव समाज एवं राज्य के अपितु राष्ट्र के महत्वपूर्ण अंग है। इन्हें और इनकी समस्याओं को हम कैसे अनदेखा कर सकते हैं।

मानव अस्तित्व की आवश्यक दशाएँ उसके भौगोलिक, सामाजिक सांस्कृतिक एवं आर्थिक परिवेश पर निर्भर करती है। मनुष्य अपने अस्तित्व की रक्षा हेतु प्राचीन काल से ही विभिन्न समस्याओं से संघर्ष करता रहा है। आदिवासियों के जीवन में कई समस्यायें हैं जैसे निर्धनता, अशिक्षा एवं स्वास्थ्य की समस्या। निर्धनतावश गरीब आदिवासी संतुलित एवं पौष्टिक आहार प्राप्त नहीं कर पातें साथ ही दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में स्वच्छा पेयजल की समस्या है क्योंकि पानी हेतु उन्हें कई किलोमीटर दूर तक पैदल चलना पड़ता है। अत: दूषित जल के प्रयोग से उन्हें विभिन्न प्रकार की बिमारियां हो जाती है जैसे डायरिया,पीलिया, उल्टी, दस्त, हैजा , खाज खुजली ,डिसेन्टी टाईफाईड आदि। मद्यपान इनकी संस्कृति का अंग होने के कारण ये मद्य सेवन करते है अत: धुम्रपान एवं मद्यपान के कारण इन्हें खांसी ,दमा,टी.बी. तथा फेफडे और श्वांस से संबंधित अन्य रोग हो जाते है। इन्हें मलेरिया , डेंगू चेचक, निमोनिया ,कुष्ठ रोग, यौन रोग, त्वचा से संबंधित अन्य रोग भी हो जाते है जिसका मुख्य कारण घर की, स्वंय की एवं वस्त्रों की अस्वच्छता भी है और उसके लिए अशिक्षा ,अज्ञानता एवं निर्धनता प्रमुख उत्तरदायी कारण है।

महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि रूग्ण होने पर आदिवासी चिकित्सालय में जाकर चिकित्सक से अपना उपचार नहीं कराते अपितु जड़ी–बूटी,तंत्र–मंत्र , झाड़–फूंक ,जादू–टोने के द्वारा उपचार कराते हैं। वे परंपरागत चिकित्सक जैसे बैगा ,गुनिया ओझा के पास जाकर ही अपना इलाज करवाते हैं क्योंकि उनका परंपरागत विश्वास उन्हें वहीं ले जाता है। किसी कारण कई बार गंभीर रोग होने व समय पर सही उपचार न हो पाने के कारण इनकी मृत्यु तक हो जाती है। अशिक्षित होने से इन्हें स्वच्छता का महत्व नहीं समझता और निर्धनतावश ये महंगी दवाये प्राप्त नहीं कर सकतें। अतएव आदिवासियों को स्वास्थ्य की समस्या बनी रहती है जो कभी–कभी गंभीर भी हो जाती है।

किसी भी समाज में उसके सदस्यों का स्वास्थ्य एक अहम पक्ष है। क्योंकि 'स्वास्थ्य' एक वैयक्तिक नहीं अपितु सामाजिक विषय है। व्यक्ति के स्वास्थ्य की सुरक्षा मात्र पारिवारिक एवं सामाजिक कर्त्तव्य नहीं है अपितु नागरिकों के स्वास्थ्य एवं कल्याण की जिम्मेदारी राष्ट्र का उत्तरदायित्व है। भारतीय संविधान में इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिये गये है। उत्तम स्वास्थ्य न केवल मानव का अधिकार है बल्कि यह उसका मौलिक अधिकार है। 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते है क्योंकि किसी भी देश की शक्ति उसके स्वस्थ्य नागरिक है जो देश के विकास एवं समाज की प्रगति में अपना योगदान देते है।

भारत एक विकासशील देश है और यह एक प्रतिस्थापित सत्य है कि स्वास्थ्य समाज के और किसी भी देश के समन्वित विकास का एक महत्वपूर्ण प्रकार्य है। यह न केवल वैयक्तिक जीवन अपितु आदिवासियों के पारिवारिक जीवन का भी एक अहम पक्ष है। आदिवासियों के जीवन में स्वास्थ्य की कई समस्यायें हैं जिनके विभिन्न पहलू हैं। जिस समाज में निर्धनता हो, पर्याप्त व संतुलित भोजन की कमी हो, स्वच्छ पेयजल का अभाव हो, आवासों का अभाव हो और जहाँ स्वास्थ्य तथा सामुदायिक सेवाओं की कमी हो वहां निश्चित रूप से हम स्वास्थ्य की वांछित स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार देश के आदिवासी स्वास्थ्य समस्या से ग्रस्त है। छत्तीसगढ़ राज्य के आदिवासी भी इस समस्या से अछूते नहीं हैं। निर्धनता ,अशिक्षा एवं स्वच्छता के प्रति उदासीन होने व जागरूकता के अभाव में आदिवासी कई रोगों से ग्रस्त होते है, फलस्वरूप कई बार गंभीर रोगो से इनकी मृत्यु भी हो जाती है। छत्तीसगढ़ में लगभग 45 प्रकार के आदिवासी हैं जिसमें सर्वाधिक गोंड 55 प्रतिशत है। कुछ जनजातियों की संख्या इतनी कम है कि सरकार ने उन्हें विशेष पिछडी जनजाति घोषित किया है जैसे – बिरहोर ,बैगा , पहाडी कोरवा , अबुझमाडिया, शहरिया, भारिया,कमार ये आदिवासी बहुत पिछडे हुये निर्धन एवं अशिक्षित हैं। जो दरिद्रता की स्थिति में आज भी जीवन यापन कर रहें है। छत्तीसगढ के आदिवासियों में निर्धनता के अलावा अशिक्षा की समस्या व स्वास्थ्य की समस्या प्रमुख है। अपनी स्वास्थ्य समस्याओं अर्थात रोगों के उपचार हेतु आज भी आदिवासियों जड़ी–बूटी, झाड– फूंक ,तंत्र–मंत्र एवं जादू टोने में ही विश्वास करते हैं और उसी में स्वयं को सुरक्षित अनुभव करते हैं। स्वास्थ्य जीवन का एक महत्वपूर्ण पक्ष होने के कारण ही भारत सरकार ने सन् 2012 में स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की बात कही है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची :–

1. Baghel D.S. – the Korwa
2. Bose N.K. – Tribal life In India
3. Chourasiya Vijay – प्रकृति पुत्र बैगा
4. Roy S.C. - The Birhor
5. Choudhary B. – Tribal Health

* सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र) शासकीय जे.यो. छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)भारत

To Study The Effect Of Social Networking Sites On Wellbeing Among Adolescents

Dr. Rashmi Singh * Dr. Shipra Lavania **

Abstract - Technological advancement in modern society have changed people's habits, expectations &lifestyles and made them dependent upon it. Social networking sites are integral parts of modern technology. In our daily lives it is affecting us both positively and negatively. Many popular social networking sites like Facebook twitter etc. are available nowadays. These sites give the opportunity to adolescents to form and maintain relationships. Wellbeing is the state of being comfortable, healthy/happy. Adolescents of today's world are living in a world of competition and there is cut throat competition in every sphere of life. Social networking sites are forum for 'impression management' where comparative status is a matter of competition. Use of these sites triggers evolved mechanism for such social evaluation.Adolescent today are living in an increasingly anxiety ridden atmosphere. These sites have greatly influenced and affected the minds of its active adolescent members. The aim of this study is to investigate the consequences of these sites on wellbeing of adolescents. The sample selected for the present study comprised of 120 adolescent Social networking site members (60 habitual and 60 occasional) selected purposively.Result shows that the frequency with which adolescents used the sites had an effect on their Psychological wellbeing.
Key words - Technology, Social networking sites, wellbeing.

Introduction - Adolescence is the stage Stanley Hall referred to as the period of storm and stress, one of the most difficult problems the adolescent faces in his/her transition from childhood to adulthood is earning to be adult in his/her relationship with other people.It is a period beginning with the onset of puberty and ending when individuals assume adult roles and responsibilities. Friendship is considered as an important factor in social development with own gender and with other genders. Today, as social networks provide the services to be in touch with numerous friends and acquaintances.

A social networking service also known as social networking sites(SNS) is a platform to build social networks or social relations among people who share similar interests, activities, backgrounds or real-life connections. In these webs based services individuals can create a public profile, make friends, and share each and everything with whom they want within the system. Social networking sites are forum for 'impression management' where comparative status is a matter of competition. They also provide mobile connectivity, photo, video sharing and blogging. These sites are mainly Facebook, Google+, twitter etc. which are widely used. From these services adolescents can be updated with the world, can easily connect and interact with one another. But beside all the advantages it is affecting the wellbeing of adolescents. Wellbeing is a general term for the condition of an individual or group, also known as welfare.Ever since Internet use became common as a leisure activity, researchers have been interested in investigating its consequences for well-being.

Review Of Literature - Einarsdottir, Gudrun Alma (2015) studied on a random sample of 2.070 adolescents from a population of 11.116 Icelandic High school students. The majority of participants were from the age 16 to 19 years old. The main results of the study indicated that adolescents who use social network sites more frequently are adversely affected by the usage (both mental and physical well-being as well as having indirect effects on depression through self-esteem.

Schwarts, Sarah (2012) examined how the use of Facebook plays a role in development of self-esteem and well-being in 13, 14, and 15 year old adolescents. Findings shows that respondent groups value their ability to stay socially connected, and associate positive feelings with functions of Facebook such as photo tagging, friend requests, status update and private messages. They also indicated that they associate positive feelings with both their offline friend groups and Facebook friend networks.

Valkenburg, Patti M. et. al. (2006) investigated the consequences of friend social networking sites for adolescent's self-esteem and wellbeing. They conducted a survey among 881 adolescents (10- 19 yrs.) who had an online profile on a Dutch friend networking site. The use of the friend networking site stimulated the number of relationships formed on the site, the frequency with which adolescents received feedback on their profiles, and the tone (i.e. positive vs. negative) of this feedback. Positive feedback on the profiles enhanced adolescents' social self-esteem and wellbeing, whereas negative feedback decreased their

* Counselor, Kendriya Vidalaya, Udaipur (Raj.) INDIA
** Senior Lecturer, Govt. Meera Girls College, Udaipur (Raj.) INDIA

self-esteem and well-being.

Objectives-

1. To study the effect of frequency (habitual/ occasional) of visiting social sites on wellbeing of school students.
2. To study the effect of gender (male/ female) on wellbeing of school students.

Hypothesis-

1. There is no effect of frequency (habitual/ occasional) of visiting social sites on wellbeing of school students.
2. There is no effect of gender (male/ female) on wellbeing of school students.

Variables -

Independent Variable- Gender

a) Male b) female

Frequency of visiting social networking sites

a) Habitual b) occasional

Dependent Variable- Wellbeing

Methodology-

SAMPLE- A total sample of 120 adolescents from class 11th and 12thinclusing 60 boys or 60 girls selected purposively on the basis of use of social networking sites. 60 occasional users and 60 habitual users were selected on the basis of personal interview from schools of Udaipur. The users were characterized as habitual/ occasional on the basis of use of social networking sites per day.

Research Design-

2X2 Factorial Design

FREQUENCY	SEX		
	MALE	FEMALE	TOTAL
OCCASIONALLY	30	30	60
HABITUALLY	30	30	60
TOTAL	60	60	120

Material Used - Florishing Scale by Ed Deiner and Robert Diener, January 2009 is used to measure wellbeing among adolescents. Scale consists of 8 statements with 7 types of responses which measures self-perceived success in areas like relationship, self- esteem, purpose & optimism. It provides single psychological wellbeing score.

Result –

TABLE-1 **(See in the last page)**

It shows that Gender and Frequency independently affect wellbeing whereas when seen as interaction perspective it was found to be non-significant.

TABLE-2 **(See in the last page)**

This shows that gender/sex significantly differ on wellbeing. Female were found to have better wellbeing as compared to males.

TABLE- 3 **(See in the last page)**

It shows that there is significant difference between the two types of users. Frequency of using social networking sites plays a major role in affecting wellbeing. Occasional users were having better wellbeing in comparison to habitual users.

TABLE- 4 **(See in the last page)**

It shows that male occasional were found to have good wellbeing as compared to male habitual.

TABLE- 5 **(See in the last page)**

It shows that Female occasional were also found to have good wellbeing as compared to female habitual.

TABLE- 6 **(See in the last page)**

Table 6 show that there is no significant difference between male occasional and female occasional. In reference to Occasional use of social networking sites no effect of gender is found.

TABLE- 7 **(See in the last page)**

Table 7 show that there is significant difference between male habitual and female habitual .Male habitual were having poor wellbeing in comparison to female habitual.

Discussion - In present study, a comparison between people who use SNS (social networking sites) occasionally or habitually on basis of their wellbeing was sought.

Social networking sites are surely affecting the wellbeing of adolescents. It is creating social isolation in adolescents. They are getting addicted towards social networks. They are spending valuable time on chatting with fake friends which is purely wastage.

In this study we found many boys and girls who sat stuck with their mobile phones from morning to till endless. It is considered today as a primary need like food, water etc.

Frequency of using the social networking sites plays a major role in affecting wellbeing of an individual. Studies shows that habitual users of sites like Facebook, twitter, pin interest etc. are more prone to depression and dissatisfaction regarding their life. When observed and analyzed deeply, it was found that people use occasionally (zero or one times per day) were happier than people who use social networking sites habitually (6 or 7 times a day). The reason behind this result can be foremost habitual users are wasting more of their valuable time on social networking sites than occasional users. They are most likely to use these sites between their study hours, resulting in decrement of concentration and are unable to perform with same efficiency. These factors directly provide a path to depression because of poor performance and dissatisfaction in their school life as well as in their daily lives. This is being the clearest difference between two kinds of users.

Talking about occasional users, the “login” patterns, as at what of the day they’re most likely to use social networking sites, it was found they generally do not prefer using social networking sites when they are at their daily activities. Because of this, their performances were not affected and they were able to work more efficient in comparison to habitual users, about which we’ve already discussed above. Second reason which came into light was the effect of the time spent on these sites. Occasional users, seek these sites as a knowledge pool and to keep themselves upgraded whereas habitual users use social networking sites for being “in touch” with family and friends. These two types of reason behind their usage also have an effect on better wellbeing of occasional users when compared to habitual users. It was seen, habitual users easily fell prey to jealousy because of

comparison with their friend on social networking sites. It Results being dissatisfaction and depression.

Habitual users are more prone to internet addiction, which itself has a bad effect on an individual, showing symptoms like- lack of social quotient, loneliness, depression, to name a few.

Comparison of who has better wellbeing when it comes to both gender, were also studied. Results show that females have better wellbeing than males, in both criteria, being habitual or occasional. It was also observed that only limited number of female users prefer using social networking sites. Reason behind this can be some researchers have found that females are more protective of their personal information and more likely to have private profiles. Other researchers have found that females are less likely to post some types of information. So generally speaking can be said, because of "privacy issues" females do not prefer using social networking sites.

Better wellbeing among female users of social networking sites can be because of the difference in the usage of sites.

References :-

1. Einarsdottir, Gudrun Alma (2015). *Social Network Site Usage among Adolescents: Effects on Mental and Physical 2. Well-being*. BSc Psychology, Reykjavik University.
2. Meena, Parth Singh (2012). Problematic use of social networking sites among urban school going teenagers. *Industrial Psychiatry Journal*, 21 (2), 94-97.
3. Schwartz, Sarah (2012). Does Facebook Influence Well-Being and Self-Esteem Among Early Adolescents? *Master of Social work Clinical Research Papers*.
4. Valkenburg, Patti M. et. al. (2006).Friend Networking Sites and Their Relationship to Adolescents' Well-Being and Social Self- Esteem.*CyberPsychology& Behavior*, 9 (5), 584-590.

TABLE-1

Source	Type III sum of squares	df	Mean Squares	F	Sig.
Sex	567.675	1	567.675	9.760	.002
Frequency	4284.075	1	4284.075	73.656	.000
Sex*frequency using SNS	3.675	1	3.675	0.63	.802
Error	6746.900	116	58.163		
Corrected total	11602.325	119			

TABLE-2

SEX	N	MEAN	STD. DEV.	STD. Error Mean	Mean Diff.	t value	P value
MALE	60	24.75	9.785	1.263	4.350	2.464	0.003
FEMALE	60	29.10	9.554	1.233			

TABLE- 3

Frequency	N	MEAN	STD. DEV.	STD. Error Mean	Mean Diff.	t value	P value
Occasional	60	32.90	8.808	1.137	11.950	8.311	0.000
Habitual	60	20.95	6.816	0.880			

TABLE- 4

	N	MEAN	STD. DEV.	STD. Error Mean	Mean Diff.	t value	P value
Male Occasional	30	30.90	8.976	1.639	12.300	6.240	0.000
Male Habitual	30	18.60	5.998	1.095			

TABLE- 5

	N	MEAN	STD. DEV.	STD. Error Mean	Mean Diff.	t value	P value
Male Occasional	30	34.90	8.306	1.516	11.600	5.897	0.000
Male Habitual	30	23.30	6.864	1.253			

TABLE- 6

	N	MEAN	STD. DEV.	STD. Error Mean	Mean Diff.	t value	P value
Male Occasional	30	30.90	8.976	1.639	4.000	1.791	0.078
Male Habitual	30	34.90	8.306	1.516			

TABLE- 7

	N	MEAN	STD. DEV.	STD. Error Mean	Mean Diff.	t value	P value
Male Occasional	30	18.60	5.998	1.095	4.700	2.824	0.006
Male Habitual	30	23.30	6.864	1.253			

****

Population Density And Its Effect On Human Behaviour

Prof. Smita Jain *

Introduction - The environment that people live in is partially formed by the people living in that environment, by their behaviors, attitudes and even their numbers. The number of people in an environment can greatly change the behavior of the people in that environment. Population density is the term that describes how many people there are in an area. Population density changes the way people behave in relation to the concepts of territory, privacy and personal space. The density of a population also changes the level of noise that a person is exposed to as well as the value that that person gives to the presence of nature.

Privacy - The concept of privacy involves the interaction of individuals with other people and the sharing or limiting of information or physical contact with those people (Privacy, 2004). According to the article Privacy (2004) central to the concept of privacy is the ability of an individual to make "decisions about openness/closedness, as well as abilities to control degrees of openness, vary with time and circumstances". This means that privacy is an issue with two distinct sides. Privacy is not only concerned with the protection of information or physical contact but also with the making these things available to others. Privacy is a flexible concept which varies depending not only on the nature of the situation but also on the individuals involved in that situation (Privacy, 2004).

The Need for Control of Privacy - This flexibility requires that people are able to exert some form of control on the level of privacy that they have (Privacy, 2004). According to the article Privacy (2004) "people develop a desired level of contact with others, compare that desired level with their actually achieved level, and activate privacy regulation mechanisms (if needed and possible) designed to reach their desired levels of contact". These mechanisms are simply strategies which people use to control their privacy through their physical environment such as shutting doors or opening doors (Privacy, 2004). An individual sitting on a crowded bus who wishes to increase his level of privacy may choose the strategy of using a portable music device with headphones in an effort to seclude himself from those around him and prevent people talking to him.

Territoriality - The concept of territory originated with the study of animal behavior (Territoriality, 2004). Territoriality is concerned with the way that both humans and animals use and defend physical space (Territoriality, 2004; Abu-Ghazzeh, 2000). According to Abu-Ghazzeh (2000) "no area can be called a territory unless it is characterized by its owner's personal means of identification and unless it constitutes a component of the social behaviour of its related group". This means that territory is not truly defined geographically but behaviorally. Territories exist because of the marking and defending behaviors of the animals and people that create and regulate their territory.

Marking Territory - People mark two kinds of territories; permanent and temporary (Territoriality, 2004; Abu-Ghazzeh, 2000). Permanent territories are those that people occupy for many years such as a child's room or a person's home (Territoriality, 2004; Abu-Ghazzeh, 2000). Temporary territories can be an area on a beach or a few chairs in a cafeteria (Territoriality, 2004; Abu-Ghazzeh, 2000). A child may child may paint their room or decorate it in order to personalize the room or to make it reflect who they are (Abu-Ghazzeh, 2000). A person might choose to personalize there home by creating a garden or painting a fence a certain color. This personalization can be viewed as a form of marking the individual's territory. To claim a chair in a cafeteria people may use personal items such as a jacket to show that someone is using the chair in case they have to walk away for a moment (Abu-Ghazzeh, 2000). Using personal item to claim space within a public area is a form of marking territory (Abu-Ghazzeh, 2000).

Human Territoriality -Though the concept of territory began with the study of animal behavior there are myriad differences between the way that animals control and use territory and the way that people do (Territoriality, 2004). People use symbolic markers, often use territory in a temporary or transient manner, often live in territory that is owned or defended by other people and may use territory for reasons that are "less rooted in survival needs than in a desire for status, privacy, and solitude".

Edney (1974) asserts that "human territoriality can conveniently be characterized with a catchall description as a set of behaviors that a person (or persons) displays in relation to a physical environment that he terms 'his,' and that he (or he with others) uses more or less exclusively over time". A person's territory is the space that he controls. This may be the place semi-permanent or temporary residence or it may be an area that is only meant to be occupied for a few hours.

Personal Space -The concept of personal space is similar to the concept of territory in that the concept was first described in the context of studying the behavior patterns of animals (Personal Space, 2004). According to the article

* Deptt. of Psychology, Govt. P.G. College, Narsinghpur (M.P.) INDIA

Personal Space (2004) the concept describes "the emotionally tinged zone around the human body that people feel is 'their space'". The area which defines an individual's personal space is relative to familiarity with others, the individual's age and the individual's cultural background (Personal Space, 2004).

In general children do not feel the need for as much personal space as adults do (Personal Space, 2004). Strangers feel the need for a greater amount of personal space than people who are friends or family (Personal Space, 2004). People who are in intimate relationships feel the least need for personal space between each other (Personal Space, 2004). People from different cultures may feel different requirements for personal space (Personal Space, 2004)

Increase of Population Density - Increases in population density lead to increases in the number and intensity of stressors in the daily life of an individual (Urban Environments and Human Behavior, 2004). Many of these stressors involve the concepts of territoriality, privacy and personal space as these concepts become more important as the population density increases (Urban Environments and Human Behavior, 2004).

An Increased Need for Privacy - The article Urban Environments and Human Behavior (2004) states that "Urban behavioral particularities comprise the following: segmented and functional ways of interacting with one another, anonymity and lack of involvement, indifference toward deviant and bizarre behaviors, and restriction and selectivity of responses to other peoples demands". If the concept of privacy is viewed as a gate through which people grant or restrict access to themselves to others then it can be said that this gate is more restrictive in urban environments than it is in rural environments. People in environments with high population density are more likely to restrict their contact with other people (Urban Environments and Human Behavior, 2004). Privacy can be maintained by interacting with fewer people and by establishing rules to guide interactions within existing interpersonal relationships. "In urban settings, interpersonal relationships are governed by rigorous rules, which enable individuals to preserve the minimum privacy needed in order to protect themselves from intrusion by others despite high-density situations".

Increase in Territoriality - An increase in the need for privacy results in an increase in territorial behavior. A greater population density lowers the amount of privacy that people feel which increases their behaviors which insure privacy (Urban Environments and Human Behavior, 2004). A study preformed by Abu-Ghazzeh (2000) shows that "the tendency of residents to delineate territorial boundaries increased in inverse proportion to the sense of privacy provided by the immediate environment". This means that the more people crave privacy the more they are likely to engage in behaviors associated with identifying and defending their territory.

There is a slight paradox here. High density environments increase the value of privacy which decreases the level of interaction between people (Urban Environments and Human Behavior, 2004). At the same time high density environments increase the need for privacy which increases the need people feel to mark their territory and to create more personalized markings (Abu-Ghazzeh, 2000). According to Abu-Ghazzeh (2000) "Personalizing behaviours, such as tending to front yards and gardens, are outdoor activities, and the greater the time spent performing these behaviours, the greater the probability of entering into chance meetings and spontaneous conversations with neighbours and passers-by". This means that some of the behaviors meant to limit social interaction and increase privacy may well serve to increase social interaction among neighbors.

Loss of Personal Space - It almost seems obvious that when the population density rises in a confined area, the amount of space given to each individual would shrink. This holds true in areas that are not completely confined as well. In public areas when the size of a group of people grows the space which they occupy does not grow proportionately but instead the amount of space that each individual holds tends to shrink (Edney, 1974).

Effect of Nature in Urban Environments - Nature has a strong attraction to people living in urban environments. Van den Burg (2007) states that "it appears that people in urbanized societies commonly believe that contact with nature provides them with restoration from stress and fatigue and improves their health and well-being". According to the article Urban Environments and Human Behavior (2004) "urban residents often seek nature and want to visit urban parks, gardens, and recreational areas for leisure". Like an oasis in a desert providing life sustaining water, a public park or garden in an urban environment can provide healthy benefits such as relaxation and freedom from the daily stressors normally found in urban areas (Urban Environments and Human Behavior, 2004).

Community gardens have the benefits of increasing the perception of safety and encouraging social relations between neighbors (Abu-Ghazzeh, 2000). Abu-Ghazzeh (2000) asserts that people "who developed vacant lots into gardens and planted flowers and vegetables on sidewalks often encouraged other people to participate in the environment and care for the rest of the neighbourhood spaces". When the homes within a neighborhood have gardens that are taken care of and maintained regularly it creates a perception that the people within the neighborhood care about their homes and are more likely to protect and defend their homes (Abu-Ghazzeh, 2000). This perception leads to a feeling of increased safety.

Conclusions - An increase in population density changes the way that people behave in relation to the concepts of territory, personal space and privacy. In high population areas people feel greater need for privacy have less personal space and increase the personalization of territorial marking. Population density also determines the amount of noise that a person is exposed to in their daily life. Urban life increases the value that people give to nature and settings such as gardens and public parks. Nature has a restorative effect in people's lives which helps them to relax and decrease their levels of stress. Nature can provide an escape from the crowding in urban life created by population density and the stress created by background noise.

✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻

वन्य जीव संरक्षण एवं प्रबंधन

सुधा शाक्य *

शोध सारांश – आज वन्यजीवों का अस्तित्व खतरे में है, प्रस्तुत आलेख वन्य जीवों का संरक्षण एवं प्रबंधन कैसे किया जाए इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रस्तुत किया गया है। भारत में विभिन्न प्रकार की वनस्पति और जीवों की प्रजातियां पायी जाती हैं, और जैव विविधता के संदर्भ में यह विश्व का सबसे समृद्ध देश है, परंतु कई कारणों से आज वनों, वनस्पतियों एवं वन्य जीवों का खतरा महसूस हो रहा है, तथा कई प्रजातियां संकटग्रस्त, दुर्लभ और विलुप्त होती जा रही हैं। एशियाई चीता, गुलाबी सिरवाली बतख आदि विलुप्त हो चुकी हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा, संवर्धन दिया जा रहा है। परंतु आज हर नागरिक का एक नैतिक दायित्व है कि वह शासन के द्वारा किए जा रहे प्रयासों में सहयोग प्रदान कर सकारात्मक सोच को विकसित करे।

प्रस्तावना – आज धरती पर जीवन पेड़-पौधों एवं वनस्पतियों से ही है, जीवधारियों की उत्पत्ति वनस्पतियों के बिना असंभव थी, इसलिए ही प्रकृति में पहले वनस्पतियां पैदा हुई और उसके पश्चात् जीव-जंतुओं का विकास हुआ। जीव-जंतुओं के भोजन का स्त्रौत पेड़-पौधे ही हैं, और उन्हीं की दी हुई ऑक्सीजन को जीव-जंतु और मनुष्य ग्रहण करते हैं। वन भी परिस्थिति तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वे प्राथमिक उत्पादक हैं जिन पर संपूर्ण जीव निर्भर करते हैं। वन्य जीवन, कृषि फसल उपजातियों में अत्याधिक जैव विविधता पायी जाती है, ये कार्य और प्रकार में वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं, परंतु आंतरिक रुप से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैव विविधता के संदर्भ में भारत विश्व में सबसे समृद्ध देश है। विश्व में पायी जाने वाली समस्त जैव उपजातियों की लगभग 8 प्रतिशत संख्या (लगभग 16 लाख) भारत में पायी जाती है। वनों एवं वन्य जीव संसाधनों का हमारे जीवन में अत्याधिक महत्व है, परंतु पर्यावरण के प्रति व्यक्ति की असंवेदनशीलता से वनस्पति एवं वन्य जीवन पर दबाव बढ़ा है, और इसके परिणामस्वरुप कई वनस्पति मृत प्राय: हो गई हैं, और वन्य जीव-जन्तु विलुल्प होने की कगार पर हैं। वैश्विक तापन का प्रभाव वैश्विक जैव विविधता की बड़े पैमाने पर विलुप्त होने की दशा में खतरा उत्पन्न कर रहा है। आज हमारे देश में लगभग 47 हजार वनस्पति उपजातियों तथा लगभग 81 हजार वन्य जीवन उपजातियां पाई जाती हैं। भारत की जलवायु में भिन्नता होने के कारण जैव विविधता अधिक है। कम से कम आज जो उपजातियां हमारे पास शेष हैं हम उनका संरक्षण कर ही सकते हैं।

वनस्पतियों एवं प्राणियों की जातियों का श्रेणीकरण – अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संघ (आई.यू.सी.एन.) के द्वारा वनस्पतियों एवं प्राणियों की जातियों को कई श्रेणियों में विभक्त किया गया है।

- सामान्य जातियों के अंतर्गत वे जातियां आती हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिये सामान्य मानी जाती है, जैसे पशु, शाल, चीड़, कृन्तक (रोडेंअस) आदि।
- संकटग्रस्त जातियां वे जातियां हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है, और विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है, और यदि वे जारी रहती हैं, तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है। काला हिरन, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गेंडा, संगाई (मणिपुरी हिरण) आदि।
- सुमेध्य जातियां वे जातियां हैं जिनकी संख्या घट रही है, यदि उनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदली जाती और इनकी संख्या घटती रहती है तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जांएगी। नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन आदि।
- दुर्लभ जातियों की संख्या बहुत कम या सुभेध्य है, और यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां नहीं होती तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आज सकती हैं।
- स्थानीय जातियां प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पायी जाने वाली जातियां अण्डमानी चील, निकोबारी कबूतर, अण्डमानी जंगली सुअर और अरुणाचल के मिथुन आदि।
- लुप्त जातियां वे जातियां हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थिति पायी गई हैं ये उपजातियां स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से लुप्त हो गई हैं, ऐसी उपजातियों में एशियाई चीता और गुलाबी सिरवाली बतख शामिल है। IUCN (2006) की रिपोर्ट मे कशेरुकी के 23%, अकशेरु के 5% और पौधों के 70% पौधे जिनका मूल्यांकन किया गया है, उन्हें लुप्त प्राय या संकटग्रस्त के तौर पर नामित किया गया है। मारीशस का डोडो पक्षीयान व शिकार के कारण विलुप्त हो गया है।

संयुक्त राष्ट्र के वन्य जीव प्रवासी प्रजाति संरक्षण मंच ने ध्रुवीय भालू, चिंकारा, व्हेल और शार्क सहित 31 प्रजातियों को संरक्षित वन्य जीव की श्रेणी का दर्जा दिया है। 4 से 9 नवम्बर 2014 तक इक्वाडोर में हुए सम्मेलन में शामिल हुए 120 देशों के 900 से अधिक विशेषज्ञों ने इन प्रजातियों को संरक्षण देने का निर्णय लिया। अब ध्रुवीय भालू चिंकारा, जल जीव में भांटारे, डेविलरे की नौ प्रजातियां, साफिश की पांच, थ्रेशर शार्क की तीन प्रजातियां, हैमर हेड शार्क की दो प्रजातियां और सिल्की शार्क संरक्षित जीवों में शामिल हो गये हैं।

लंदन न्यूज एजेन्सी (नवम्बर 2014) के अनुसार यूरोप में पर्यावरण संरक्षण के तमाम उपायों के बावजूद पिछले 30 वर्षो में पक्षियों की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है। एक अनुमान के मुताबिक पूरे यूरोप में पिछले तीन दशक में लगभग 42 करोड़ 10 लाख पक्षी कम हुए हैं। विज्ञान पत्रिका 'इकॉलाजी लेटर्स' में प्रकाशित अध्ययन रिपोर्ट के मुताबिक पक्षियों की संख्या में यह गिरावट मुख्य रुप से खेती के आधुनिक तरीके और अत्याधुनिक जीवनशैली के कारण पक्षियों के पर्यावरण वास पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव का नतीजा है। 90 प्रतिशत से अधिक गिरावट आम जनजीवन में देखे जाने वाले पक्षियों की संख्या में पाई जाती है। अध्ययन (2014) में पाया गया कि भूरे तीतर, चकवा, गौरैया और मैना की संख्या सबसे अधिक घटी है। गिरावट बहुत चिंताजनक है। कर्नाटक के मैसूर चिड़ियाघर प्रबंधन (दिसम्बर 2014) की जानकारी के अनुसार भूरे भेड़िये, जंगली कुत्ते और शेर जैसी पूंछवाली

* सहायक प्राध्यापक (मनोविज्ञान) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नरसिंहपुर (म.प्र.) भारत

मकाऊ ये सभी जीव विलुप्त प्राय प्रजातियों की सूची में शामिल हैं। शेर जैसी पूंछवाली मकाऊ देश के पश्चिमी भाग, भूरे भेड़िये चित्रदुर्ग बीजापुर और आसपास के इलाकों में तथा जंगलीकृत नागरहोल और बांदीपुर के जंगलों में पाए जाते हैं। गुजरात के कच्छ में पाया जाने वाला विलुप्त होता संरक्षित श्रेणी का पक्षी घोराड़े (इंडियन बस्टर्ड) को संरक्षित एवं संवर्धित किया जा रहा है। जिससे यह प्रजाति बची रह सके।

फिलाडेल्फिया के चिड़ियाघर में रहने वाले ध्रुवीय भालू, ओरांगुटान, स्नोलेपर्ड और गुरिल्ला जानवर पृथ्वी से विलुप्त हो रहे हैं। ध्रुवीय भालू पर जलवायु परिवर्तन के कारण खतरा मंडरा रहा है। वर्ल्ड वाइल्ड फंड फार नेचर (wwf) में इसे कमजोर होती प्रजातियों की श्रेणी में रखा है। ओरांगुटान पाम तेल के पौधे का वृक्षारोपण बढ़ने के कारण ऊष्णकटिबंध वन घट रहे हैं, जिससे ये लुप्तप्राय: प्रजाति में आ गए हैं। मध्य एशिया में पाई जाने वाली स्नो लेपर्ड प्रजाति को wwf ने लुप्तप्राय श्रेणी में रखा है। मध्य अफ्रीका में पश्चिमी लोवलैंड में पाया जाने वाला गुरिल्ला शिकार, जंगलों की कटाई और बीमारी के चलते इस प्रजाति को गंभीर खतरे की श्रेणी दी गई है।

वन्य जीव संरक्षण हेतु राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रयास – वन हमारी एक संपदा है पेड़-पौधे और वनस्पति विभिन्न जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं, साथ ही जलवायु को भी नियंत्रित रखते हैं। मानव ने स्वार्थवश जब से वनों की कटाई प्रारंभ की है जलवायु में भी परिवर्तन आया है, और वन्यजीव का प्राकृतिक आश्रय एवं आवास पर भी संकट आ गया है, इस कारण बहुत सी प्रजातियां संकटग्रस्त, असुरक्षित एवं लुप्त होने की स्थिति में आ गई हैं।

मनुष्यों द्वारा वन्यजीव का अनाधिकार शिकार करना पशुखाल, सीगों चमड़ा, दांत, नाखून पंखों का व्यापार करने से चीता, शेर, हाथी, ब्लेकबक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा हिम तेंदूआ, शुतुरमुर्ग, मोर आदि की संख्या में कमी आई है। वन्यजीवन तथा वनों में तेजी से हो रहे ह्रास के कारण इनका संरक्षण एवं संवर्धन अति आवश्यक हो गया है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रयास किए जा रहे हैं।

- अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र के वन्यजीव प्रवासी प्रजाति संरक्षण मंच का अगला सम्मेलन फिलीपींस में 2017 में होगा।
- मैसूर के चिड़ियाघर प्रबंधन द्वारा विलुप्त प्राय: प्रजातियों में शामिल भूरे भेड़िये, जंगली कुत्ते और मकाउ में संरक्षण के लिए उनका प्रजनन किया जा रहा है, और इन पर शोध किया जाएगा।
- यूरोप में भी पक्षियों के संरक्षण के लिए पर्यावरण संरक्षण के कई उपाय किए जा रहे हैं।
- गुजरात में विलुप्त होते संरक्षित श्रेणी के पक्षी घोराड़ (इंडियल वस्टर्ड) के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए 214 कुत्तों की नसबंदी कराई गई क्योंकि घोराड़ जमीन पर अंडे देता है और सारे अंडे कुत्ते खा जाते हैं। अंडे देने वाले स्थानों पर कुत्ते नहीं रहेंगे जिससे घोराड़े की संख्या में वृद्धि की संभावना की जा सकती है।
- पोलर बियर संस्था शोध अध्ययन तथा कार्यक्रमों के द्वारा कमजोर होती प्रजाति ध्रुवीय भालू के संरक्षण पर विचार कर रहा है।
- स्नोलेपर्ड ट्रस्ट दान के जरिए राशि एकत्र करके भारत, किर्गिस्तान, मंगोलिया और पाकिस्तान में स्नोलेपर्ड लुप्तप्राय श्रेणी की प्रजाति के संरक्षण के लिए काम कर रहा है।
- एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी सी.आई.टी.ई.एस. की स्थापना की गई जिसने पक्षियों और प्राणियों की अनेक जातियों जैसे भालू, डाल्फिन, कैक्टस, प्रवाल, आर्किड और ऐलो की सूची तैयार की और इनके व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया।
- वन्य जीव संरक्षण अधिनियम (1972) देश की परिस्थितिकीय, पर्यावरण सुरक्षा, संरक्षण तथा वन्यजीव पक्षी, जीव-जंतु पादप की सुरक्षा हेतु यह अधिनियम लागू किया गया पृष्ठवंशी तथा पुष्ठवंश रहित जीव आते हैं, जिन्हें फुसलाना, जाल में फंसाना, शिकार करना, पकड़ना, हांकना, चारा देकर ललचाना, शरीर के किसी भाग के क्षतिग्रस्त कर ले जाना, वन्यजीव के अंडो को नुकसान पहुंचाना, घोंसलो को छेड़ना प्रतिबंधित है। 2003 में इस अधिनियम में संशोधन किया और अपनाध करने पर कठोर दंड का प्रावधान है।
- बाघ परियोजना (1973) की शुरुआत हुई। उत्तरांचल में कॉरबेट राष्ट्रीय उद्यान, प.बगाल का सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, म.प्र. का बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, केरल का पेरियार बाघ रिजर्व इस परियोजना में विशिष्ट योगदान दे रहे हैं।
- वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार पर्यावरण तथा वन मंत्रालय द्वारा वर्ष 1995-96 से वन्य जीव संरक्षण और शोध कार्यो के रुप में उल्लेखीनय कार्य करने वाले अधिकारियों एवं क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को सरकार द्वारा राजीव गांधी अवार्ड व सालिम अली फैलोशिप एवं कैलाश सांखला फैलोशिप प्रतिवर्ष प्रदान की जाती है।
- **गिरलॉयन प्रोजेक्ट–** इस प्रोजेक्ट का प्रारंभ गुजरात के पर्वतीय अंचल में हुआ, इसमे बाघों की कई किस्में पनपाई गई हैं, और संरक्षण हेतु प्रयास किए गये। दार्जिलिंग की प्राणी उद्यान इसके लिए प्रसिद्ध है।
- **मगरमच्छ परियोजना–** भारत सरकार द्वारा केरल दक्षिण भारत के समुद्री क्षेत्रों में यह संकर योजना 1947 में प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य मगरमच्छों का संवर्धन संरक्षण एवं विलुप्त होने से बचाना है।
- **गेंडा संरक्षण–** भारत सरकार द्वारा गेंडा परियोजना 1987 से प्रारंभ हुई, इसमे विभिन्न प्रजातियों के गेंडो को विलुप्त होने से बचाया गया।
- भारत सरकार ने भी बाघों के संरक्षण हेतु जागरुकता लाने के उद्देश्य से विभिन्न डाक टिकट जारी किए।
- शासकीय प्रयासों से 2010 में बाघों की संख्या 1706 थी वह आज 2014 में 2226 हो गई है अर्थात 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विभिन्न संस्थाओं द्वारा वन्यजीव संरक्षण आदि पर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी, कार्यशाला, सम्मेलन, निबंध प्रतियोगिता आदि करवाये जा रहे हैं।

निष्कर्ष – वन्य जीवों का जीवन आज बहुत खतरे में है, और यदि व्यक्तियों ने इनके प्रति अपनी सकारात्मक सोच को विकसित नहीं किया तो इनके अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए शासन के द्वारा संरक्षण हेतु किए गए प्रयासों में सहयोग देना एवं उनका संरक्षण करना हमारा नैतिक दायित्व एवं कर्तव्य है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Chalam, K.S. (2012). Environmental Education Professional Compentency in Higher Education, University of Delhi, p 178.
2. पांडे, आर.(2000) मूल्य शिक्षा के परिपेक्ष्य, आर. लाल बुक डिपो मेरठ पृ. 126.
3. शर्मा, एच.एस. एवं सिंह एच.पी. (2010) पर्यावरण शिक्षा शिक्षण, राधा प्रकाशन मंदिर आगरा. पृ. 86
4. श्रीवास्तव, पी.(2014), 'पर्यटन विकास की संभावना' (कोटा जिले के विशेष संदर्भ में) **Naveen Shodh Sansaar, 2,** पृ. **109**
5. तिवारी, ए.(2014) जनसंख्या, वृद्धि एवं पर्यावरण सुरक्षा, कृष्ण कम्प्यूटर्स एवं प्रिंटर्स सागर (म.प्र.) पृ. 73

विद्यार्थियों हेतु नैतिक शिक्षा की उपादेयता

ज्योत्स्ना झारिया *

शोध सारांश – वर्तमान शिक्षा का मूल उद्देश्य है, विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास और सर्वांगीण विकास से तात्पर्य है बालकों का मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, चारित्रिक एवं नैतिक विकास इत्यादि। बालकों के सर्वांगीण विकास में शिक्षा, शिक्षक और शिक्षालय की महत्वपूर्ण भूमिका होती। शारीरिक रूप से स्वास्थ्य एवं मानसिक रूप से समृद्ध होने के बावजूद यदि बालकों में सही चरित्र एवं नैतिकता का विकास नहीं हुआ है, तो उसके शिक्षित होने का कोई महत्व नहीं। विद्यार्थिओं में उत्तम चरित्र एवं नैतिकता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षाविदों ने शिक्षा के उद्देश्य को मात्र ज्ञानवर्धक न मानकर सर्वांगीण विकास माना है।

नैतिक शिक्षा, शिक्षा का आवश्यक अंग है, नैतिक शिक्षा विद्यार्थिओं के उत्तम चरित्र निर्माण में योगदान देती है और इस हेतु शिक्षकों को निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, यथा छात्रों की वैयक्तिक भिन्नता का ज्ञान होना, छात्रों के परिपक्वता के स्तर की जानकारी प्राप्त करते रहना, प्रेम तथा सुरक्षा की भावना, संवेगात्मक वातावरण का निर्माण करना एवं छात्रों को नियंत्रित स्वतंत्रता देना।शिक्षक यदि इन बातों का ध्यान रखे तो निश्चित ही नैतिकता तथा उत्तम चरित्र दोनों का निर्माण कर सकेंगे। विवेक द्वारा निर्देशित होकर स्वेच्छा से व्यवहारों का चयन करके तद्वदुरूप आचरण करना नैतिकता का द्योतक है। नैतिकता को एक आंतरिक वृत्ति माना गया है जो व्यक्ति को उचित अनुचित का बोध कराती है तथा मानवीय मूल्यों को बनाये रखने की प्रेरणा प्रदान करती है। इसे आत्म चेतना की अवस्था माना जा सकता है। जिसमें व्यक्ति भलाई, बुराई, सत्य–असत्य, उचित–अनुचित, न्याय–अन्याय आदि में भेद करना सीखता है। (बद्री नारायण तिवारी 2005)

नैतिक शिक्षा के द्वारा व्यक्ति मानव समाज के साथ अपने संबंधों को समझता है एवं सीखता है। विद्यार्थिओं में नैतिक शिक्षा के कारण समझ में प्रखरता एवं विश्वास में दृढ़ता उत्पन्न होती है। आदर्श के प्रति वे जागरूक हो जाते है एवं आदर्श विरोधी व्यक्तियों एवं वस्तुओं से वे घृणा करने लगते हैं। नैतिक शिक्षा से बालकों की सुरक्षा की भावना में वृद्धि होती है एवं समरूप परिस्थितियों में वे निर्भाकता से निर्णय ले सकते हैं। (बद्री नारायण तिवारी 2005)

प्रस्तावना – शिक्षक को ज्ञान और उसके अवबोध, अभिवृत्ति तथा मूल्य, सामाजिक संबंध, नैतिक शिक्षा, विद्यालय, परिवार तथा समुदाय के संबंधों को नैतिकता तथा चरित्र निर्माण के संदर्भ में विकसित करना चाहिए। बालकों को आवश्यक निर्देश दिये जाने चाहिए तथा आत्म नियंत्रण के अवसर प्रदान किये जाने चाहिए। धर्म तथा नैतिकता चरित्र को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों रूपों से प्रभावित करते हैं।

नैतिक शिक्षा के प्रभावी तत्व –

1. **परिवार –** नैतिक शिक्षा के प्रभावी तत्वों में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका है। माता–पिता एवं परिवार के अन्य सदस्यों के आचरण नैतिक मूल्यों के कितने अनुकूल है उनकी अभिवृत्तियों एवं पूर्वाग्रहों की क्या स्थिति है ? उक्त तथ्य बालक अनुकरण द्वारा सीखता है। माता–पिता एवं अन्य परिजन उसके लिए मॉडल का कार्य करते हैं अत: बालकों के निर्णय, विचार, आदर्श एवं नैतिक मूल्य उसके परिवार के लोगों द्वारा प्रभावित होते हैं।
2. **शिक्षालय–** बालकों के नैतिकता के विकास को शिक्षालय का परिवेश, महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। विद्यालयीन व्यवस्था, अनुशासन, शिक्षक, पाठ्यक्रम, शिक्षार्थिओं की संख्या, शिक्षण शैली इत्यादि ऐसे महत्वपूर्ण तत्व है जो विद्यालयी परिवेश से संबंधित हैं। ये सभी तत्व बालकों में नैतिकता के विकास को प्रभावित करते है।
3. **धर्म–** संसार के सभी धर्मो का एक ही लक्ष्य है कि व्यक्ति को नैतिक बताया जाये। सभी धर्म नैतिकता के विकास के लिए अनेक धर्म ग्रंथों की रचना एवं व्याख्यानों की व्यवस्था करते हैं। इनकी व्यवस्था मंदिरों, मस्जिदों, चर्चो इत्यादि धार्मिक स्थलों से की जाती है। इन संस्थाओं के लोग अपने चरित्र एवं व्यवहार द्वारा लोगों को नैतिकता के वरण हेतु प्रोत्साहित करते हैं।
4. **संगी साथी–** शिक्षालय एवं पड़ोस में बालकों के अनेक संगी साथी बन जाते हैं वह अपन इन साथियों से अनेक प्रकार के नैतिक मूल्यों को सीखते है वे जिस प्रकार के चरित्र वाले साथियों के बीच रहते है उसी प्रकार के नैतिक मूल्य भी वह अनुकरण के द्वारा सीखते है उनके मित्रगण यदि उच्च नैतिक मूल्यों वाले हैं तो वे भी उच्च नैतिक मूल्यों को सीखते है एवं विपरीत नैतिक मूल्य होने पर विपरीत नैतिक मूल्यों को सीखते है।
5. **मनोरंजन।** नैतिक शिक्षा के प्रभावी तत्वों में मनोरंजन का भी महत्वपूर्ण योगदान है। इनके द्वारा नैतिक मूल्य नियंत्रित एवं संचालित होते है। मनोरंजन के साधनों में फिल्में, धारावाहिक, कार्टून फिल्में, साहित्व एवं विभिन्न तरह के इनडोर एवं आउटडोर गेम हो सकते है। सकारात्मक एवं आदर्शपूर्ण स्वस्थ्य मनोरंजन बालकों में नैतिकता के विकास में अपना योगदान देते हैं।
6. **संचार माध्यम।** टी.वी., रेडियो, पत्र–पत्रिकाऐं, अखबार और वर्तमान में इंटरनेट कुछ ऐसे संचार माध्यम हैं जो बालकों में नैतिक मूल्यों के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते है। नैतिक आचरणों को उन्नत करने वाले स्वस्थ्य साहित्य एवं कार्यक्रमों व वेबसाइट का प्रयोग करने हेतु बालकों को प्रेरित करना चाहिए ताकि बालकों में उत्तम चरित्र एवं नैतिकता का विकास हो सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. आलम काजी गौस एवं रामजी श्रीवास्तव एवं अन्य (2002), मोतीलाल बनारसी दास दिल्ली, पृ.क्र. 299–314
2. भटनागर सुरेश (1975), शिक्षा मनोविज्ञान, प्रकाशक–लायल बुक डिपो मेरठ पृ.क्र. 223–223
3. व्यक्तिगत सर्वे एवं शोध।

* सहायक प्राध्यापक (मनोविज्ञान)शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नरसिंहपुर (म.प्र.) भारत

T.S. Eliot's Use of the Upanishad in the Waste Land

Aparna Ray *

Abstract - Inspite of the welter of books dealing with the many-sided achievement of T.S. Eliot, his use of the message of the thunder from the Brhada-ranyka-Upanisad in his The Waste land is not adequately. That the Upanisadic message forms the crux of his poem is unquestionable. The unsympathetic critics of the twenties and thirties considered Eliot's use of the Hindu scripture as an aspect of his "pretentious bungling." Some critics attributed the obscurity of the poem to the four Sanskrit words : datta, dayadhvam, damyata and santih. Even Eliot's champions like Ezra Pound referred to his use of the Sanskrit scripture with a casualness that betrays an inadequate critical attention to it. Rebutting a reviewer's acrimony, Pound said the obscurity of the poem is due to the Sanskrit word, that "one can pass them by…. without losing the general tone of the poem" and that "they are so obviously the words of some ritual or other."[1] The most deceptive of all reasons which account for the insufficient critical thought bestowed on these vital words could be Eliot's own notes on them. They give the necessary translation, enough for any one to proceed with the poem with an illusion of understanding.

Key words -Datta, dayadhvam, damyata,santih, obscurity, Brhada-ranyka-Upanisad.

Introduction - A close study of the original context in which the message is delivered in the Upanisad and its function there, and then an examination Eliot's deft adaptation of it in is poem in a new context for a total different purpose, is amply rewarding. For, besides promoting a deep understanding and hence a future response to the poem, the study reveals a new face in the range of the poet's sensibility and a new aspect of the triumph of his technique and craftsmanship.

In the Brhada-ranyka-Upanisad, the threefold message is symbolic both in its conception and execution. The triple offspring of Prajapati, gods, men and demons (deva, manushya and asura), after the completion of their education under their father, ask him what virtues they have to cultivate to lead a meaningful life.

Then Prajapati utters to each of them in turn the syllable da and asks them what they have understood from it. The gods say that for them it means damyata, "control yourself" ; the men that it means data, "give" ; and to the demons it converys dayadhvam, "be compassionate". What is significant here is that the same syllable da conveys different meanings to different beings of different beings derive different meanings from it: and that the message that each group derives is born out of an instinctive consciousness on its own part of its own main lack. To the gods it says "control yourself," because, endowed as they are with great powers, what they need to acquire is self-control. As men are by nature selfish and greedy it exhorts them to give. To the demons who are strong and cruel be nature it says "be compassionate." Symbolically, it is obvious that to live a peaceful and meaningful life leading to salvation, the gods have to cultivate self-control and overcome their inherent weakness; men have to conquer their selfishness ; and the demons must rid themselves of their inherent cruelty.

The cryptic mode of Prajapati's utterance opened new avenues and possibilities for Eliot. It offered him a new poetic technique to deliver a message of redemption to the inhabitants of the waste land without risking the usual pitfalls of explicit didacticism. The implicit notion which he wanted to convey in his poem is the need for a full consciousness of one's shortcomings. Only this kind of self-realization, proceeding from a full awareness of inherent drawbacks, can liberate the inhabitants of the waste land from their living death and spiritual miasma. From the beginning of the poem through image, metaphor, symbol and myth, The protagonist invites us to see the naked reality which is entirely different from what we think we have experienced and what we hope to find in the future.

….I will show you something different from either
Your shadow at morning standing behind you
Or your shadow at evening dying to meet you;
I will show you fear in a handful of dust.

In the section "A Game of Chess", he depicts the deplorable predicament of humanity devoid of this basic realization. What religion was at one time, sex (particularly sex without children) is to the modern world. When the vital principle of life is reduced to the level of drug addiction, and marriage, the holiest of human institutions, to a kind of licence for this addiction, life on earth is nothing more than a game of chess.

* Asst. Prof. (English) Govt. P.G. College, Neemuch (M.P.) INDIA

For the rich and poor alike, life has lost its value. The life of the rich has become a mechanical foutine,

What shall we ever do ?
The hot water at ten.
And if it rains, a closed car at four.
And we shall play a game of chess,
Pressing lidless eyes and waiting for a
knock upon the door.

To what depths of degradation the domestic life of the poorer classes has fallen is vividly conveyed through the conversation of the cockney women in the pub. The section closes with a challenging question: "What you get married for if you don't want children?"

The section "Fire sermon." a phrase borrowed from the Buddha, symbolically depicts the actual state of the vast panorama of futility and anarchy that is modern life. In his fire sermon the Buddha described all things as burning in the fire of desire. His phrase served Eliot admirably to depict the inhabitants of the waste land as burning in the fire of sterile lust. The root cause of this burning of life in the fire of lust is desire. To be free from the wheel of suffering, according to the Buddha, one must follow the path of asceticism leading to nirvana the "blowing out" of the fire of desire (this is the root meaning of the word). St. Augustine too saw humanity as burning in the unholy fire of lust and he too suggested asceticism as, the cure. As Eliot points out, the collocation of these two representatives of easterm and western asceticism is not an accident. For, both have arrived at the same track independently; and, where truth is concerned, biography and geography do not count.

The death by water in the next section is a metaphorical death into a new life: a baptismal death. It is the quenching of the fire of desire by the waters of knowledge. Syrnbolically it is the emergence of a totally new person through the extinction of the previous gross person. Only by such a thorough transformation a man render himself capable of realizing the true ideal of life, and live by it. This transformation requires an unsparing and disinterested self-scrutiny.

Eliot presents this type of self-exploration in the section, what the Thunder said. The "decay of Europe" and the fall of towers and cities represent the crumbling of false civilization and false ideals, the fall essential for a new building. The two journeys, the journey to Emmaus and the jouruey to Emmaus and the journey to the Chapel Perilous, stand for a spiritual quest. The pain and horror of the quest is wonderfully conveyed in terms of a journey through a dry rocky desert with a landscape of drought:

Amongst the rock one cannot stop or think
Sweat is dry and feet in the sand
If there were only water amongst the rock
Dead mountain mouth of carious teeth that cannot spit
Here one can neither stand nor lie nor sit
There is not even silence in the mountains

At the close of this phantasmagoria of horror and delirium comes the heart-easing "Co co fico co co rico," the call of the bird of dawn, with its spiritual association of nativity, powers to chase away all evil and darkness, heralding new light.

Then, in a short movement of evocative poetry, Eliot creates the appropriate background for the introduction of the Upanisadic messagem He takes us back to the source of the Ganga and the forests of the Himalayas, the home of all vegetation myths and fertility cults according to Miss Weston.

Ganga was sunken, and the limp leaves
Waited for rain, while the black clouds
Gathered far distant, over Himavant.
The jungle crouched, humped in silence.

Ganga, the symbol of continuous life on earth, is sunken. Starved creation is waiting for rain. The clouds beating life-giving waters have gathered over Himavant, the source of the Ganga and the home of all spiritual wisdom from time immemorial, the peak symbolizing spiritual aspiration. The world is yearning for the message. Then speaks the thunder, not Prajapati. Evidently, Eliot is adapting the idea expressed in the Upanisad itself. After the message of Prajapati, the reader's atten tion is directed to the divine voice of thunder: "The very thing the heavenly voice thunder repeats da, da, da, that is control yourself, give, be compassionate."

Eliot rearranged the triad datta, dayadhvam, damyata in a new order of natural sequence The commands are delivered separately and the original cryptic mode of delivery is retained. The different aspects of the message reveal different meanings to different types of people in the waste land, enabling each type to realize ts own major drawback. At the same time, taken together, it serves as a general message to humanity as a whole. The message is announced very aptly by the heavenly voice of thunder. Apart from the upanisadic authenticity, it is quite in harmony with the setting: the cock crowing, a flash of lightning, a damp gust bringing rain, the sunken Ganga, the limp leaves waiting for rain, the black clouds gathered far distant over Himavant and the jungle crouhed and humped in silence. Now it is more appropriate that the cosmic voice of thunder should announce the message rather than Prajapati. An introduction of Prajapati into this picture would be out of place; it would look like an external intervention by a God in the machine, not a natural revelation.

Obviously, Eliot exploited the rich poetic possibilities and the symbolic connotations of the Upanisadic setting and mode of utterance. We must notice that he did not merely repeat it. Such of the connotations as are of value and relevance are fully suggested, so that the reader might not miss the richness and many-sided impact of the message. All the three different responses to the same syllable da, as in the Upainsad, show that the particular section of people have, grasped the highest ideal expressed in each of the three commands, Eliot combined all the three commands into a single message; dropping the details of deva, asura and manushya, he gave it a fully human significance. The, changes he made have a high philosophical basis advocated

by Sankara. Sankara comments on the Upanisadic message;

Other than men, there are neither gods nor demons….. Those who are pre-dominantly selfish are men. In the same way, men who are inclined to cruelty and to inflict pain are demons. The same men, if they acquire self-control and overcome the other two defects, are eligible to be styled as gods…….

Therefore when Eliot telescoped the triad into a single message retaining its triple significance and made it thoroughly human, dropping the detail of deva, rnanushya, asura, he was following a great tradition besides exercising his individual talent.

From what the thunder has said, the protagonist realizes the, true ideal of life and sets about putting his lands in order. Each ideal sets him to an unsparing introspective self-analysis. After datta he questions himself about what he has given. He realizes that he has not given him self up to any high ideal. He has yielded only to sterile lust. not to the demands of love, essential for he preservation of life and race. This is a guilt that cannot be washed away by ordinary penance :

The awful daring of a moment's surrender
Which an age of prudence can never retract?

The command dayadhvam opens his eves to the fact that he has never sympathized with anything outside himself. He has locked himself up in the prison of his own self. Hearing the third command damyata, he becomes aware of the need for self control, for submitting himself to the universal law, that is the need to control individual impulses, to steer the boat of life in accordance with the eternal laws, the tide, current and winds of the sea. In short, to lead a meaningful life, one has to cultivate self-control and live in harmony with the eternal law, "beating obedient to controlling hands," to reach shore safely. This full realization leads to "a peace which passeth understanding." So the poem The waste Land fittingly ends with:

Datta. Day dhvarn. Damyata.
Shantih shantih shantih

Conclusion - What I want to point out is not that Eliot was a Hindu at heart,but that he had a full grasp of the Upanisadic setting, its message and its spirit. He conveyed the need of the message with poetic compulsion and urgency. His aim was not to advocate the need of a particular faith, but to take us to those deeper unnamed feelings and experiences which form the substratum of all faiths. To drive home the necessity of a full awareness of this undefinable ideal through a process of poetic communication, he found the Upanisadic message indispensable. Evidently, he wanted us to understand the four words datta, dayadhvarn, damyata and santih, not merely to mean give, sympathize, control and peace, as is commonly done but by recreating the original context and repeating the actual words, he wanted us to feel them in a particular way, the Upanisadic way.

References :-

1. Hughkenner :The Invisible Poet : : T.S. Eliot, W . H . Allen, London, (1960),p.130
2. S.Radhakrishnan's (Ed.) :The Principal Upanisads, pp. 289-91
3. The Waste Land, II, 27-30
4. Ibid., II. 134-38
5. The Waste Land, II, 164
6. Ibid., See Eliot's note
7. The Waste Land, II, 336-41
8. Ibid., II. 396-400.
9. S.Radhakrishnan's : The Principal Upanishad, p.290
10. S.Radhakrishnan's (Ed.) :The Principal Upanishad, p.290

✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻

गुरूचरण दास के नाटक 'Larins Sahib' में पंजाब का राजनैतिक व सामाजिक परिदृश्य एवं एक अंग्रेज की दुविधा

डॉ. मनीषा जोशी *

प्रस्तावना – कई साहित्यकारों ने इतिहास को अपनी साहित्यिक कृतियों में बड़ी दक्षता से उकेरा है। अन्यथा किसी भी साहित्यिक कृति में समकालिन इतिहास का प्रतिबिम्ब तो अनायास ही रचना में छलक कर आ ही जाता है। भारत का स्वतंत्रता संग्राम वाला काल सर्वाधिक समृद्ध एवं गौरवशाली रहा है। इस काल के अधिकतर भारतीय लेखकों एवं रचनाकारों के लेख राष्ट्रप्रेम की भावनाओं से ओत–प्रोत रहे। भले ही वे हिन्दी साहित्य के रचनाकार हों जैसे – आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, मैथलीशरण गुप्त, दिनकर, सुभद्राकुमारी चौहान आदि या अंग्रेजी लेखन के भारतीय रचनाकार जैसे – अरबिन्दो, रविन्द्रनाथ टेगौर, गांधीजी, जवाहरलाल नेहरू इत्यादि। गुरूचरण दास की 'इंडिया अनबाउन्ड' एक ऐसी कृति है, जो कि 1947 से भारत की आर्थिक यात्रा का ब्यौरा हमें देती है। किन्तु इसके अतिरिक्त इस पुस्तक के द्वारा लेखक भारतीय राजनैतिक एवं सामाजिक सोच पर भी प्रकाश डालते हैं। इसके अलावा उनके अनेको लेख, उपन्यास एवं नाटकों में `The Tragic Dilemma of Larins Sahib' निश्चित ही भारतीय अंग्रेजी लेखन में एक प्रभावशाली ऐतिहासिक नाटक के रूप में स्थापित होता है।

गुरूचरण दास ने अपने 'ब्लाग' में दार्शनिक, सोरेन कैकगार्ड (Soren Kierkegard) के वक्तव्य को उल्लेख किया है– 'Life can only be understood backwards but it must be lived forwards' साहित्य में ऐतिहासिक रचना सदैव ही किसी भी लेखक के लिये किसी चुनौती से कम साबित नहीं हुई । इतिहास के तथ्यों को साहित्य सरस बनाता है, अत: एक सफल साहित्यिक कृति की रचना हेतु सर्वप्रथम रचनाकार का इतिहास का पूर्ण ज्ञान, ऐतिहासिक कल्पनाशीलता एवं इतिहास व साहित्य का समन्वय, उसकी सफलता को पूर्णता प्रदान करता है।

`The Tragic Dilemma of Larins Sahib' की संरचना गुरूचरण दास ने 1846–47 के दौरान पंजाब में हुये ऐतिहासिक घटनाक्रम के मुख्य पात्रों के बीच हुए पत्रों एवं दस्तावेजों के आदान– प्रदान के आधार पर किया है। नाटक पूर्णरूप से भारत के औपनीवेशिक इतिहास के मुख्य घटना के इर्द–गिर्द घूमता है। यह पंजाब के 1840 की दो मुख्य घटनायें– सन् 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु एवं पंजाब में 1845 का प्रथम सिक्ख युद्ध –(अंग्रेज एवं पंजाब के खालसा के बीच), जो कि पंजाब के भविष्य को निर्धारित करता था, पर आधारित है। सन् 1845 के सिक्ख युद्ध में पंजाब पर अंग्रेजों की जीत की सफलता के पश्चात पंजाब का आर्थिक एवं राजनैतिक पतन प्रारंभ हुआ, जिसके फलस्वरूप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी कुटिल योजनाओं के माध्यम से पूरे पंजाब को अपने अधीन कर लिया। वह विदेशी पात्र जिसने इस राजनीतिक उथल–पुथल के दौरान इतिहास के पन्नों पर अपनी छाप छोड़ी वह है– हेनरी लॉरेन्स, जो कि भारत में 'लेरिन्स साहिब' के नाम से आज भी विख्यात है। नाटक का शीर्षक, 'हेनरी लॉरेन्स' का पंजाब में उत्थान, पतन एवं उनकी सफलता व विफलताओं को दर्शाता है। किन्तु यह नाटक केवल ऐतिहासिक घटनाओं का लेखा–जोखा ही नहीं है वरन् इसको रोचक व सार्थक बनाने के लिये, नाटककार ने इन घटनाओं को आधार बनाकर, समकालीन भारतीय समाज के राजनितिक संदर्भ के मूल प्रश्न जो कि भारतीय समाज के उत्थान में सहायक होंगे, को उठाने में सफल रहे हैं। इन प्रश्नों को स्पष्ट रूप से उठाने की जगह, लेखक उन्हे नाटक के मूल विषयों में स्वभाविक रूप से दर्शाते है।

नाटक दो दलों के बीच में द्वन्द को प्रदर्शित करता है– ईस्ट इंडिया कंपनी व उसके अधिकारी जैसे– हार्डिंग, करी एवं इलियट जो ब्रिटिश औपनिवेशवाद का प्रतिनिधित्व करते हैं एवं दूसरी ओर भारतीय राजा दिलीप सिंह, स्व. महाराजा रणजीत सिंह के पुत्र। हेनरी लॉरेन्स की प्रशासनिक श्रेष्ठता की वजह से उन्हें कंपनी पदोन्नत कर सिक्ख राज्य के रेजिमेन्ट के पद पर एवं दिलीप सिंह (स्व. महाराजा रणजीत सिंह के अव्यस्क पुत्र) के संरक्षक के रूप में नियुक्त करती है। हेनरी लॉरेन्स, ब्रिटिश होने के बावजूद भारत की मूल समस्याओं के प्रति सहानुभूति पूर्ण भावना रखने वाला पात्र रचा गया है, जिसकी वजह से वह अपने अधिकारियों के मध्य बहुत कम अंतराल में ही काफी लोकप्रिय भी हो गया। जैसे कि इलियट ने लॉरेन्स के बारे में लॉर्ड हार्डिंग को बताया है कि –

'Henry Lawarence has built up a phenomenal reputation. Just two years on the border as a minor clerk with the Revenue Survey and he`s become a legend. I believe he`s on the first-name terms with most of the nobility of the Punjab. They swear by him, and the peasantries of the Ferozepur district thinks, he`s some kind of a savior'.[1]

किन्तु एक्ट III आते तक यही लॉरेन्स साहिब जो अपने आर्दशों एवं मानवता के लिये प्रख्यात थे, महाराजा रणजीत सिंह के प्रशंसक एवं पंजाब राज्य के लिये निष्ठावान थे, शक्ति के मद में नीचे गिरते चले गये। जैसे कि कहा गया है कि शक्ति व्यक्ति की मति को भ्रष्ट कर देती है, हेनरी लॉरेन्स के अलावा कुछ और पात्र जैसे– लालसिंह, तेजसिंह, हार्डिंग आदि भी शक्ति की चकाचौंध में अपने लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिये छल एवं षडयंत्र को अपना जरिया बनाते है। प्रथम सिक्ख युद्ध में पंजाब सेना का अंग्रेजो के हाथों परास्त होने का यह बहुत बड़ा कारण था।

लेखक ने एक इतिहासकार की भांति संपूर्ण नाटक के विभिन्न आयामों को निष्पक्ष भाव से व्यक्त किया है। पंजाब जैसा सशक्त, समृद्ध एवं वैभवशाली राज्य, अपनी आंतरिक कमजोरियों, परस्पर एकता एवं विश्वास की कमी, मुल्यों का ह्रास , राजनैतिक प्रतिस्पर्धा आपसी वैमन्सय के कारण अंग्रेजों

* प्रध्यापक व विभागाध्यक्ष (अंग्रेजी) शासकीय एम.एल.बी. कन्या पी. जी. महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

के समक्ष कमजोर पड़ता चला गया। इसका प्रभाव राज्य की आर्थिक सुदृढ़ता पर भी पड़ा। लेखक यदि भारतीय धर्म की सहिष्णुता की प्रशंसा करते है, तो धर्म के नाम पर फैलाये अंधविश्वास की आलोचना भी करते है।

प्रारंभ में हेनरी लॉरेन्स की पंजाब के सामंत एवं यहॉ के निवासियों के लिये संवेदनशीलता, अपनत्व सहानुभूति एवं निष्ठा थी, किन्तु समयोपरांत उन्हें ईस्ट इंडिया कम्पनी इस बात का ध्यान करा देती है कि वे पंजाब के मूल निवासी कभी नहीं बन सकते एवं उनकी निष्टा अंतत: कम्पनी के लिये ही होनी चाहिये–

'Inspite of his love for the Punjab, he cannot be a native, but has to be an agent of the company and execute the directions of the Governer-General'[2]

यह सोच लेरिन्स साहिब के बर्ताव में अत्याधिक परिवर्तन लाती है एवं वे लालसिंह और तेजसिंह जैसे गद्यारों से मिल जाते है। रानी, शेरसिंह एवं दिलीप सिंह के प्रति उनके व्यवहार में पूर्णत: परिवर्तन आ जाता है। जिसके परिणाम स्वरूप लेरिन्स शेरसिंह जैसे अच्छे मित्र को खो देता है। सब कुछ का ज्ञान होते हुये भी लेरिन्स ने ताकत के मद में कभी पंजाबियों तो कभी कम्पनी राज की सहानुभूति खो दिया। शेरसिंह जैसे मित्र को खोने के बाद भी उन्हें कहीं पछतावा नहीं था, वो अपने मद के नशे में चूर थे और महाराजा रणजीत सिंह का चोला पहनकर स्वंय को पंजाब का महाराजा ही समझने लगे थे। किन्तु तुरंत ही उन्हें कलकत्ता से गर्वनर जनरल का पत्र प्राप्त होता है, जिसमें उन्हें सूचना दी जाती है कि उनकी पंजाब में सेवायें समाप्त की जाती है और उन्हें कलकत्ता पहुचने का आदेश दिया जाता है। क्षणिक सुख के लिये हेनरी लॉरेन्स को अपनी शक्ति एवं प्रसिद्धि से हमेशा के लिये त्याग करना पडता है।

'Larins Sahib' has a lot of contemporary relevance. It reflects the ugly flight among political leaders. It seems that the political leaders waste their all energy in just maintaining themselves. The playwright seems to say that there is a great deal of investigation into the causes of our past mistakes and failures'

निश्चित ही नाटककार का उद्देश्य पूर्व की गई भूल जो कि पतन का कारण बनी को दर्शाना था जिससे कि आने वाले समय में मनुष्य उनको न दोहराते हुये उक सुदृढ एवं सशक्त देश का निर्माण कर सकें।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. Dr. Manjeet, Gurucharan Das- `Three English plays: A Critical appraisal'(Y King Book, 18 Jain Bhavan, Opp. N.B.C. Shanti Nagar, Jaipur, 2012: ISBN: 978-93-80930-69-5), Pg.18
2. Dr. M.F. Patel ` Recent Explorations in Indian English Writing(Published by, Sunrise Publishers & Distributors, E-566 Vaishali Nagar, Jaipur, 2011, ISBN: 978-81-906067-6-9), Pg.20
3. Dr. Manjeet, Gurucharan Das- `Three English plays: A Critical Appraisal' (Y King Book, 18 Jain Bhavan, Opp. N.B.C. Shanti Nagar, Jaipur : ISBN: 978-93-80930-69-5), Pg.116

****

हिन्दी बाल कविता का विकास

डॉ. वन्दना अग्निहोत्री *

शोध सारांश – हिन्दी में बाल कविता के विकास युग के रूप में 1970 के बाद के समय को लिया जा सकता है। इस समय बालगीत सबसे अधिक लिखें गए।इस दौर में बाल कविता के विविध स्वरूप भी दिखाई दिये। कवियों ने अपनी कविताओं में विचार–तत्व को प्रमुखता प्रदान की बच्चो के मन में भारी बस्ते और पढ़ाई के बोझ को लेकर जो घुटन और उपेक्षा हैं । बड़े लोगों के प्रति उनके मन में जो शिकायते हैं उनके बारे में बड़ी ही सहज और मर्मस्पर्शी बाल कविताएँ लिखीं गई हैं। अमीर और गरीब बच्चों की जीवन–शैली के अन्तर से उत्पन्न दर्द को भी बाल कवियों ने महसूस किया और उनके दर्द को कविताओं के माध्यम से व्यक्त किया ।

प्रस्तावना – बाल कविताओं के रचनाकारों में दिविक रमेश का स्वर अपेक्षाकृत अधिक सशक्त और मौलिक है। उनकी 'घर'कविता में एक बच्चा पापा से सवाल करता है। सवालो पर सवाल के अन्त में कविता गुड्डे की कल्पना से परे, घर को अन्य रूप में खडा कर देती हैं। घर में सुरक्षा है,माँ,बाप का प्यार है, शब्द उन भावनाओं को छू देते हैं

'घूमघाम ले ,खेल–खाल लें,नहीं भूलता लेकिन घर।
नहीं आपको लगता पापा,है माँ की गोदी सा घर।
प्यारी–प्यारी ममता वाला ,सुन्दर–सन्दर न्यारा घर।
थककर जब वापस जाते है, कैसे बिछ–बिछ जाना घर'।।[1]

बच्चा आगे पापा से पूछता है, जिन बच्चों के घर नही हैं वे क्या करते होगें। बेघर बच्चों की पीडा और उनकी समस्याओं को उन्होंने उठाया है।

वे कविता की विचारशक्ति पर ज्यादा भरोसा करते हैं। मुक्त छंद की लय में दिविक का अद्भुत सामर्थ्य दिखाई देता है। सूरज की यह कल्पना भी की वह रोशनी का गट्ठर बॉधकर ला रहा है,जिंदगी की सच्चाई से जुडी हुई है।

'रोज सवेरे, इतना गट्ठर
बॉध रोशनी लाता है'।[2]

इसी तरह की 'बीज और पौधा कविता भी है जो एक नन्हे बीज के एक विषाल दरख्त में बदल जाने की प्रकृति की रहस्यम्यता को खोलती है।'मैंने चिड़ियों को देखा है' एक जीवंत कविता है जिसमें तिनका – तिनका घर बनाती चिडिया के गृहस्थिन रूप को देखा जा सकता है।

हरीश निगम की बाल कविताओं में बहुत सुंदर और ताजे बिंब मिल जाते हैं।एक अनुभूति जो चीजों को नए ढंग से देखकर बहुत हल्के से कह देती है।'यह चुपके से या बारीकी से कह जाने की सफाई हरीश निगम की विशेषता है।उनका कविता लिखने का ढंग नवगीतों के शिल्प से बहुत मेल खाता है। बगैर चाक्षुष बिम्बों के अच्छी कविता नहीं लिखी जा सकती है।[3]'हरीश निगम इस मामले में काफी समृद्ध है।

हरीश निगम ने भी बच्चों पर बढते हुए बोझ को लेकर कविता लिखि है–

'थोडा अपना वजन घटाओ भइया बस्तेजी
हम बच्चों का साथ निभाओं,भइया बस्तेजी।
कमर हमारी टूट रही है,कॉधे दु:खते है।
तुमको लेकर चलते हैं कम/ज्यादा रूकते है'।[4]
परीक्षा का कितना तनाव है बच्चों में यह भी देखिये

'बात परीक्षा की चली ,खेल–कूद है बंद
चिंताये अब तेज हैं,मुस्काने है मंद
सैर सपाटा, ऊधमें ना.टी.वी, ना खेल,
दिवस परीक्षा के हुए अपनी खातिर जेल।।'[5]

'सूर्यकुमार पाण्डेय की बाल कविताओ में बात कहने का एक नया अंदाज है।वे बदलते वक्त के साथ बदलते संस्कारो में बच्चों के बहुत करीब है। 'माँ मैं भी सचिन बनूंगा' क्रिकेट पर लिखी गई एक जीवंत कविता है। जिसमें न सिर्फ क्रिकेट का गतिशील चित्र सामने आता है बल्कि क्रिकेट को लेकर हर बच्चे के सपनें और महत्वाकांक्षा को भी यहॉ अभिव्यक्ति मिली है। जो हर बच्चे के 'हीरो' रूप को दर्शाती है।

उनकी कविताओ में कोई नई बात होती है या वे पुरानी बात को नये रूप में लेकर आत है। जैसे बछडा बोला गाय से। दूध नहीं पीना मुझको। काम चलेगा चाय से। नये नये उपमानो से भरी धूप की कविता जिसमें धूप नन्ही चिडिया और जादू की पुडिया नहीं,सुनहरे बालों वाली बुढ़िया भी बन गई है।

'वह नन्हीं चिडिया सी धूप, जादू की पुडिया सी xxx धूप पके आम से गालों वाली xxx और सुनहरे बालों वाली लगती है बुढिया सी धूप।'[6]

रमेश तेलंग की कविताएँ बच्चो को बहुत आकर्षित करती है।'सुबह का गीत 'में बच्चे के तोतलेपन को नटखट रूप दिया है। कही कही कविताओं में कुछ कथाओं को भी जोडा है। 'सोनमछरिया' ऐसी ही कविता है। जिसमें मछुआरा मछली को छोड़ दे तो खाएगा क्या तब मछली उसे एक मोती लाकर देती है और कविता एक लोककथा के समान सुखकर हो जाती है। यह कविता रोचक कथानक,लयबद्धता और नाटकीयता के कारण याद की जाती है।

'तडप–तडपकर सोनमछरिया/बोली मछुआरे से भैया,
मुझे निकालो,मुझे निकालो/दम घुटता है जाल में।'[7]

हिन्दी बाल कविता के इतिहास में बहुत कुछ नया अपूर्व और मूल्यवान जोड़ने वाली कविता 'निक्का पैसा' है।

'निक्का पैसा कहॉ चला xxx पहले रहा है हँथेली पर ।
यहॉ भला न वहॉ भला xxx निक्का पैसा निकल गया।।[8]

रमेश तेलंग ने किसी विशेष लीक पर न चलते हुए बदलते समय से अपनी कविताओं को नया शिल्प और नया स्वरूप दिया। इसी तरह सुरेश विमल ने बाल कविताओ में मौलिक प्रयोग किये उन्होने ताजे और अनछुए बिंबो को उकेरा है। उन्होंने ग्रामीण जीवन और प्रकृति के चित्रो को कविताओं

* विभागाध्यक्ष (हिन्दी) माता जीजाबाई शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मोती तबेला, इन्दौर (म.प्र.) भारत

में ढाला है।'पतों का गीत में देखिये'।

लगते है केले के पते, हॉथी के से कान।
पीपल के पत्तो की होती, चूहे जैसी पूँछ।।[9]

किसी बात को समझाने के लिए रमेश कौशिक कविता का सहारा लेते दिखाई देते है। ऐसे में कविता का आनंद कम और गद्यात्मकता उभर आती है। उन्होंने 'शून्य' कैमरा' 'ग्रामोफोन, 'रिकार्ड जैसे विषयों पर इतनी अच्छी और दमदार कविताएँ लिखी की वे चकित कर देती है। रमेश कौशिक ने बच्चों के लिए एकदम नये और अछूते विषय 'धरती'और सृष्टि पर भी रोचक कविताएँ लिखी है

'हुआ जन्म तेरा कब ,कैसे। ठीक ठीक कुछ पता नहीं है।
कौन शक्ति से लट्टू जैसी। महाशून्य में घूम रही है।
बीते वर्ष करोडो फिर भी। कभी नहीं थक हारी धरती।'[10]

आसपास के परिवेष और प्रकृति को उन्होने सदायशी द्धष्टि से देखा है।

देवेन्द्रकुमार की बाल कविताओं में शब्दो की मितव्ययता, सम्प्रेषणीयता, और भाषा संगम है।'हवा हुई शैतान' कविता में 'हैरान अम्मा' की उपस्थिति इसे अद्धितीय बना देती है।

'अब ना खाओ में' खाने का आग्रह अम्मा को बुलाकर किया गया 'प्यारी अम्मा। सबने खाया। अब तो खाओ। यह पारिवारिक परिवेश की संतुष्टि यह अंतरंगता विरल है जो बालगीतो में कम दिखाई देती है' हँसने का स्कूल' एक अलग रंग, अलग अंदाज की कविता हैं उन्होनें किस्म किस्म के सार्थक प्रयोग अपनी बाल कविताओं में किये हैं।

अशोकरंजन सक्सेना एवं रत्नप्रकाश शील के बालगीतों में संगीत और लयबद्धता है जो बच्चो के मन को सहज ही मोह लेता है। छम छम करते घुंघरू एवं अक्कड बक्कड। शीलजी ने प्रकृति एवं वैज्ञानिक विषयो पर भी लिखा है। जहीर कुरेशी की बाल कविता में एक चुस्ती एवं सधापन मिलता है। उन्होंने प्रयोगात्मक बालगीत कुछ अलग अंदाज में लिखे है। 'पापा बबलू, बबलू पापा बन जाते है सपने में। इसमें मजेदार स्थितियों का वर्णन हुआ है।' 'पप्पी का शिकायत नामा' बाल मनोविज्ञान से जुडी हुई कविता है।

'तभी आ गई थी रीना की नानी अपने घर
मम्मी एकदम उलझ पडी थी नानी बुढिया सें
अब रीना के घर जायेगी तो तोडेगी टांग
हॉ,पापा यह कहकर मम्मी ने दुत्कारा था।'[11]

बाल साहिल की अनेक विधाओं में राष्ट्रबंधु ने लिखा है। टिली लिली और 'चाँदमाँई खेलो' राष्ट्रबंधु की प्यारी कविताएँ है,जिसमें बच्चे पूर्णत:मगन हो जाते है। भगवतीप्रसाद द्धिवेदी नें कुछ नये प्रयोग किये है।बच्चों को बिस्कुट और आइसक्रीम पसंद है। 'जाता है दिल सबका लुट। ज्यों ही दिख जाते बिस्कुट।'आइसक्रीम को उन्होंने भीम की उपमा दी हैं क्योंकि यह गरमी और लू से लडती है–

'ठंडी ठंडी आइस्क्रीम,आइसक्रीम आइसक्रीम,
खूब तरावट से भरपूर,ठंडापन इसका दस्तूर
इसे देखते ही हो जाता,गरमी का गुस्सा काफूर,
लू से लडती जैसे भीम, आइसक्रीम आइसक्रीम।'[12]

द्धिवेजी ने आज के समय विचार और मुश्किलों से जुडी बाल कविताएँ भी लिखी हैं। प्रदूषण पर उनकी तीखी कविता है जिसमें प्रदुषण के धुएँ के कारण आसपास का संसार 'मौत के कुएँ' जैसा लगता है।इसी तरह बच्चे के भारी बस्ते की मुश्किले और उसके मन की पीडा को भी उन्होने कविता में व्यक्त किया है।

रमेशचंद्रपंत के गीत बच्चो से सीधे–सीधे जुडे है 'नानीजी के गाँव में' चिडिया दादाजी की कुर्सी, अखबार व ऐनक से जुडकर हमारी दुनियॉ में सीधे–सीधे शमिल हो जाती है। रामसेवक शर्मा की कविताओ में प्रकृति के अनेक रंग नजर आते है।राजा चौरसिया ने बच्चो के अन्दर की रचनात्मक ऊर्जा का वर्णन किया है। चित्र बनाकर तृप्ति महसूस करने वाले बच्चे के रचनात्मक क्षण को पकडा है। काम की सफलता बच्चों की खुशी को दोगुना कर देती है।

'कल–कल करती हुई नदी का। मैने चित्र बनाया तो।
हल्के गाढे रंगो से भी मैंनें उसे सजाया तो।।[13]

बच्चो में जन्मदिन मनाने की कैसी चाह होती है,यह राजनारायण चौधरी की 'मने जन्मदिन मेरा' कविता पढकर पता चलता है।उनकी कविताएँ बच्चो की इच्छाओं को नजदीक से देखती और उजागर करती हैं 'नए–नए कपडों में नन्हा, राजकुअँर में लगता। रामानुज त्रिपाठी की बाल कविताओं में बदले समय के चित्र हैं।उन्होंने नये विषयो पर नए ढंग से बात कहने की कोशिश की है। 'छोटे परदे पर' बडी कल्पनाशीलता है। टी.वी. के छोटे पर्दे पर चीजें और दृश्य कैसे बदल जाते हैं।दुनियाँ बच्चों को अलग ही नजर आती है।

'मुँह फैलाये खडा सामने,शेर कभी गुर्राता है,
आगे बढता जब,जब लगता, पास हमारे आता है।'[14]

गोपीचंद्र श्रीनागर की बाल कविताओं में परिवार के साथ उत्सव मनाने की सुन्दर और रंग बिरंगी कल्पनाएँ है।उनकी 'दीदी की शादी' उसी प्रकार की कविता है। आज के बदले हुए समय की चोट और मुश्किलों का चित्रण सुरेन्द्र विक्रम की कविताओ में हुआ हैं। मॅहगाई की मार ने तितली और कोयल के संगीत को सोख लिया है और पूरी दुनियाँ त्रस्त नजर आती हैं।

'रंग लिया उधार तितली से,फिर भी छाई नहीं बहार,
पंचम सुर वाली कोयल के भी अब टूट गए हैं तार,
सरसों के फूलों ने भी इस बार नहीं पहना है हार,
लगता सारे पस्त हुए हैं खाकर मँहगाई की मार।'[15]

बच्चों को सुबह उठना अच्छा नहीं लगता है उसे सूरज से शिकायत है कि वह इतनी जल्दी उठकर क्यों आता है,बिस्तर पर आराम क्यों नहीं करता। इतवार को बाजार बन्द होते है तो सूरज छुट्टी क्यों नहीं मनाता 'कब सोते कब उठ जाते, तैयार कैसे झटपट होते हो। लाते नहीं टिफिन क्या खाना खाकर आते हो। हरिशचंद्र बच्चो के अन्त: संसार से बहुत करीब से जुडे है।उनकी अभिव्यक्ति में एक चुंबकीय आकर्षण है। रमेश राज की बाल कविताओं में बच्चों के मन की परतों को पढा जा सकता है।'

रेखा राजवंशी की कविताओं में कल्पनाशीलता और नाटकीयता दोनों मिलती है। सरोजिनी कुलश्रेष्ठ की भूकंप पर लिखी 'बोलो माँ'कविता बहुत प्रभावशाली है।जिसमें भूकंप में मची अफरा–तफरी, और ध्वंस,विनाश को लेकर बच्चे के मन में उठे सवालों, भय और जिज्ञाताओं की बडी सहज अभिव्यक्ति हुई है।

'तब सह लेती सब शैतानी। कभी न की इतनी मनमानी लोग मर गए इतने सारे। बिछुड गए आफत के सारे। क्यो इतना विष घोल रही है।' भूकंप की विनाश लीला पर लिखी बाल कविता करूणा उत्पन्न करती हैं सरोजिनी अग्रवाल की बाल कविताओ में हास्य की चपलता के साथ भाषा में एक खास तरह की शरारत भी दिखाई देती है। श्यामसिंह शशि की उडा कबूतर गोपी चंदर 'बच्चो के कौतूहल संसार से जुडी कविता है।लगता है जैसे बच्चो के पंख उग आये हो और कवि उन्हे देख रहा हो।आधुनिक बच्चों के नटखटपन और, विज्ञान की दुनिया का मनोरम अंकन मिलता है।'

'मैंने अपना नोट बचाया, नन्हा राकेट एक बनाया,
घर–घर, घर –घर उडा दिया जब, दुश्मन को धरथरा दिया तब'।।[16]

हरिकृष्ण देवसरे की 'पगडी से टोपी' में गॉधीजी और सेठ की मुलाकात का दिलचस्प प्रसंग है। जिसे काव्य रूप दिया है। उनकी हास्य की विलक्षण प्रतिभा उभरकर आई है। सरस्वतीकुमार दीपक बाल मन के चितेरे कवि है। जिनकी कविताओ में बाल संसार की इच्छाओं आकांक्षाओ की रंग बिरंगी नुमाईश सजी हुई है।'गुडियाघर'के गुड्डे–गुडियों की बातों में एक मस्त बस्ती बसा लेते है।

हरिवंशराय बच्चन की बाल कविताओं में भरपूर गेयता के साथ ही कल्पना की सूझ भी दिखाई देती है। गोरा होने के लिये कौआ साबुन की टिकिया उठाकर भाग जाता है।'नीली चिडिया' भी प्रसिध्द है जिसमें बच्चो की जिज्ञासा है कि चिडिया उड उडकर कहॉ कहॉ जाती है भवानीप्रसाद मिश्र ने भी लयात्मक कविताएँ लिखि है जो हर बच्चे को अपनी लगती है।रमेश आजाद बासी तौर तरीके छोडकर कुछ नया करने की धुन के साथ अपनी अलग दुनियॉ रचते है। यश मालवीय और श्याम सुशील की कविताओं में आर्द्र और ममतालु किस्म की पारिवारिकता नजर आती है।'बडे दिनो के बाद याद पापा को उनकी बिट्टी आई'कविता में चिट्ठी पाने का रोमांच आँखो में बस जाता है।

निष्कर्ष – बाल कविता की इस विकास यात्रा में कुछ कवियों का ही अंकन किया है। जिन कवियों की चर्चा की गई है उनसे बाल कविता के मोडो और पडावों की जानकारी हो सकती है। समय के साथ साथ उसका रूप, बच्चो के साथ उनका रिश्ता और आस्वाद कैसे चुपके से बदलता है यह भी। पहले गीत इसलिए लिखे जाते थे कि बच्चे उन्हे याद करें उनसे कोई सीख ले लेकिन अब बाल कविता उनके लिए खिलौनों के समान है।बच्चे उनसे खेले व खेल खेल में याद करें। ऐसी बाल कविताएँ नजर आती हैं जो बाल कविता की विकास यात्रा और समय के साथ उसके रिश्ते को आश्वस्त करती है। आवश्यकता हैं उसे मामूली रचनाओं अलग कर सही मूल्यांकन करने की।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1,2. घर दिविक रमेश 10
4,5. भईया बस्तेजी–हरीश निगम 15
6. धूप सूर्यकुमार पाण्डे 20
7,8. सोनमछरिया निक्का पैसा 26
9. पतों का गीत सुरेश विमल 30
10. धरती रमेश कौशिक 32
11. पप्पी का शिकायतनामा 35
12. आइस्क्रीम भगवतीप्रसाद द्विवेदी 39
13. मँहगाई की मार सुरेन्द्र विक्रम 40
14. छोटे परदे पर रामानुज त्रिपाठी 52
15. राकेश–श्यामसिंह शशि 145 हिन्दी बाल कविता का इतिहास प्रकाश मनु।

****

कबीर का समाज दर्शन

डॉ.अंजली सिंह *

प्रस्तावना – कबीर कई है– 1 जन्म में भी अनेक, जीवन में भी अनेक, मृत्यु में भी अनेक। किंवदंतियों में लिपटे हुए, किंवदंतियाँ को तोड़ते हुए। अपनी जरुरत के अनुसार लोगो को इनमें से कोई एक कबीर अधिक प्रासंगिक लगता है। कबीरों की इस भीड़ में वास्तविक कबीर को बाहर निकालना आसान नहीं है और आज के समय में उनकी सही जगह तय करना भी कठिन हैं ना हिन्दू ना मुसलमान कबीर का अपना पक्ष है । यह लोकमत भी है और साधुमत भी।

आज कल साहित्य में जिस तरह के अस्तित्वाद का फैशन है वह कई प्रश्न उठाते हैं। कोई कहता है कबीर का दु:ख जुलाहे का दु:ख है, उसे तो वही समझ सकता है, जिसे वैसे ही दु:ख की आत्मानुभूति हो। किसी का कहना है कि कबीर दलितों के अपने प्राइवेट धर्मगुरु हैं– उन्हें समझे तो वही समझे जो जल्दी ही स्थापित होने वाले दलित धर्म में दीक्षित होने को तैयार हो। 17 अक्टूबर 99 के जनसत्ता में डॉ. रामस्वरुप चतुर्वेदी ने लिखा है कबीर के इतर पक्षों – संत, भक्त, सूफी, समाज सुधारक– पर बेअनुपात महत्व देने के कारण उनका मूल कवि– व्यक्तित्व आक्रांत हो उठा है।

अधूरेपन के ऐसे साधनों के लिए कबीर सचमुच बहुत बीहड़ हैं। कबीर की कविता वस्तुत: विराट विस्मय से उपजनेवाला उल्लास और उसके साथ अपरिहार्यत: जुड़ा संताप उतना ही प्रामाणिक है जितना कि समाज व्यवस्था मे निहित अन्याय के प्रति रोष आध्यात्मिक और सामाजिक के बीच बैरभाव की कल्पना उनकी मजबूरी है जो कविता की सत्ता संघर्ष का , अस्मिताओं के बीच युद्ध का अस्त्र भर मानते है–। कबीर की कविता बार–बार हमें बताती है कि लौकिक–अलौकिक, भीतर बाहर, सामाजिक आध्यात्मिक जैसे पदों में विरोध का ही नहीं निरंरता का भी संबंध है। निरंरता का यह अहसास कहीं बाहर से नहीं सीखना पड़ता। मनुष्य के चैतन्य का प्रमाण ही है यह अहसास:–

मोको कहाँ ढूँढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में।
ना मैं देवल ना मस्जिद ना काबे कैलास में।।
(शब्दावली भजन 7)

कबीर की खोज ही बाहर–भीतर सबद निरंतर की है। जिज्ञासु कबीर के लिए तो बुनियादी सवाल ही यह है कि प्रेम से यदि परमात्मा मिल सकता है, भक्ति से यदि राम रीझ सकता है, तो मनुष्य और मनुष्य के बीच व्यवहार सें प्रेम, भक्ति और रहनि पर जाति, बरन और कुल क्यों कर भारी पड़ते हैं? उनके जीवन और कवि कर्म में व्याप्त सामाजिक आंलोचना उनकी आध्यात्मिक खोज की ही परिणति है– और यह आध्यात्मिक खोज सामाजिक अनुभव से कतराकर नहीं बल्कि उससे टकराते हुए, उनसे जिरह करते हुए ही संभव होती है।

कबीर की बात शुरु होती है, जाति व्यवस्था में निहित 'अमारण दण्ड' (आ0 हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्द) के प्रति दो टूक विद्रोह से, लेकिन उसकी परिणति दंड देने वाले और पाने वाले सामाजिक समूहों की भूमिका की अदला बदली के प्रस्ताव में नहीं होती। कबीर की संवेदना एक तरह में जातिवाद को दूसरी तरह के जातिवाद से 'रिप्लेस' करने वाली संवेदना नहीं है, बल्कि जाति मात्र कों प्रश्नबिद्ध करने वाली संवेदना है। इस संवेदना में व्यक्ति की पात्रता–अपात्रता, श्रेष्ठता–निकृष्टता का निर्धारण साधना के योग से होता है, प्रत्यक्ष की परख से होता है, जन्म के संयोग से नहीं। इस संवेदना और सहज साधना के ही कारण, अनुभव और अनभय के कारण वह जुलाहा–जिसकी जाति पर सब 'हँसने हार हैं– पूरे विश्वास के साथ कह उठता है, कबीर जुलाहा भया पारख, उतरा अनभौपार'।

आधुनिक अर्थ में कबीर को समाज–सुधारक या समाज द्रष्टा नहीं कह सकते। उनकी चेतना मूलत: आध्यात्मिक थी। वे समाज–रचना के लिए किसी प्रकार के सुधारवादी आंदोलन के पुरस्कर्ता न होकर मानव आत्मा की मुक्ति के लिये आध्यात्मिक संघर्ष करने वाले साधक थे। उनका सारा संघर्ष आसक्ति एवं तृष्णा के विरुद्ध था–

उदै अस्त की बात कहतु हौ सब का किया विवेका हो।
घाटै–बाटै सब जग दुखिया क्या गिरही बैरागी हो।
सुकदेव अचारज दु:ख कै कारनि गरभ सौं माया त्यागी हो।
जोगी दुखिया जंगम दुखिया तपसी कौं दुख दूना हो।
आसा त्रिसनां सबकौ व्यापै कोई महल न सूना हो।
सांच कहौ तौ कोई नमानै झूठ कहा नहिं जाई हो।
ब्रझा बिस्नु महेसुर दुखिया जिनु यहुराह चालई हों।
कहै कबीर सकल जग दुखिया संत सुखी मन जीती हो
कबीर ग्रंथावली संपा. पारसनाथ तिवारी
हिन्दी परिषद, प्रयाग वि.वि. प्रयाग 1961 ई0

कबीर के अनुसार यह सारा व्यक्त जगत एक ही तत्व से उत्पन्न है। इसलिए सभी प्रकार की भेद दृष्टि मिथ्या है मानव–मानव में भेदतो परम अज्ञान का घोतक है। इसी तत्व दृष्टि से प्रेरित कबीर ने जाति–पॉति, छुआछूत, उँच–नीच और ब्राम्हण–शूद्र के भेद का विरोध किया है। इसी आधार पर उन्हें समाज सुधारक समझा जाता है। इसमें संदेह नहीं कि इन भेदों को दूर कर देने पर एक सुंदर समाज की रचना हो सकती है किंतु इस स्तर पर भी कबीर के विरोध का प्रेरणा स्त्रोत आध्यात्मिक सत्य ही है। वे भेदभाव का विरोध इसलिये करते हैं कि तत्वत: ये मिथ्या हैं। वे कहते हैं कि एक ही ज्योति में सब व्याप्त है दूसरा कोई तत्व है ही नहीं–

एकहि जोति सकल घट व्यापक दूजा तत्ता न होई।
कहै कबीर सुनौ रे संतौ भटकि मरै जनि कोई।।
(कबीर ग्रंथावली डॉ0 तिवारी पद 105 पृष्ठ 61)

परमात्मा ने एक ही बूँद से सारी सृष्टि रची है, फिर ब्राम्हणऔर शूद्र का भेद क्यों? यदि हिंदू और तुर्क दो होते तो जन्म से ही इनमें अंतर होता। एक ही नूर से सारा संसार रचा गया है न कोई भला और न कोई मंद। छुआछूत का विरोध

* प्राध्यापक (हिन्दी) शासकीय माधव सदाशिवराव गोलवलकर महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत

भी कबीर ने इसी स्तर पर किया है एक नूर तैं सब जग कीया कौन भले कौन मंदे। वस्तुत: पवित्र और शुद्ध तो वे ही लोग हैं जिन्होने हरि की भक्ति करके अपने मन के विकारो को दूर कर लिया है। कबीर मन की पवित्रता या आंतरिक शुद्धता पर बल देते है जो एक आध्यात्मिक सत्य है।

कबीर ने साधना के सभी क्षेत्रों में बाह्मचार का विरोध किया है। वे सारे औपचारिक कर्म-विधान जिनके मूल में कोई तत्व नहीं है, कबीर के लिये व्यर्थ है। जिन नाथ योगियों से कबीर का सीधा संबंध जोड़ा जाता है उनके बाह्मचार का भी उन्होने विरोध किया है। उन्होंने ऐसे योगियों की निंदा की है जो हाट-बाजार में प्रदर्शन के लिये ध्यान लगाते हैं। प्रदर्शन करने वाले ये योगी कबीर की दृष्टि में कच्चे सिद्ध शरीर का योग साधते हैं, मन का योग बिरला ही साधता है। इसी प्रकार विवेक रहित छापा तिलक लगाने वाले वैष्णवों को भी उन्होंने आडंबरी माना ही माना है

कबीर वैश्नो भया तो का भया बूझया नही बमेक।
छापा तिलक बनाइ करि, दगध्या लोक अनेक।।
कबीर ग्रंथावली (डॉ0 गुप्त) साखी 16 पृष्ठ 78

कबीर मानते है कि जिन साधको के पास लोग मुक्ति की कामना से जाते है वे स्वंय अनेक प्रकार के बंधनों में जकड़े हुए है। योगी के लिये योग सिद्धि का मार्ग है तो लुंचित, मुण्डित, मौनी, जटाधर ये अपनी-अपनी विधियों से सिद्धि प्राप्त करने का दावा करते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि ये सभी बाहयाडम्बर के बंधन मे बँधे हैं। इसी प्रकार कबीर को 'पीर' 'मुरीद', 'काजी', 'मुल्ला', 'दरवेश' आदि सभी भ्रांति में पड़े हुए प्रतीत होते हैं। कबीर पूजा-अर्चा, तीर्थ व्रत तथा रोजा-नमाज को भी ब्राहाचार ही समझते थे। क्योकि उनका मानना है कि यदि दिल साफ नहीं है तो इनका लाभ नहीं है क्योकि अंतत: यह सब मन को परिष्कृत करने के साधन है। उन्होंने सहज सात्विक जीवन पद्धति को महत्व दिया है।

कबीर का ध्यान आर्थिक भेदभाव की ओर भी गया है, उन्होंने लिखा है कि जो निर्धन हैं उनका आदर कोई नहीं करता। वस्तुत: धनी-निर्धन होना प्रभु की मर्जी है।

निर्धन आदर कोई न देई। लाख जनत करै ओहु चित न धरेई।
जौ निरधन सरधन कै जाई। आगे बैठा पीठ फिराई।
जौ सरधन निर्धन कै जाई। दीया आदर लिया बुलाई।
निरधन सरधन दोनों भाई। प्रभु की कला न मेटी जाई।
कहि कबीर निर्धन है सोई। जाके हिरदै नाम न होई।
कबीर ग्रंथावली (नागरीप्रचारिणी सभा) परिशिष्ट-पृष्ठ 302।

उन्हे कर्म का सिद्धांत मान्य था। वे यह तो मानते है कि हिंदु-मुसलमान, ब्राम्हण-शूद्र, ऊँच-नीच, सुजाति-कुजाति, पवित्र-अपवित्र का भेद अज्ञानजनित एवं मिथ्या है किंतु धनी- निर्धन के भेद ने भी मानव-जाति का अपकार किया है इसे वे नहीं मानते थे। वस्तुत: भौतिक वैभव को महत्व ही नहीं देते थे। उनका मानना था कि वैभव के सुख से तो भिक्षा-वृति अच्छी है क्योकि भिक्षा-मॉग कर जीवन यापन करने वाले संतो का समय हरि के सुमिरन में व्यतीत होता है।

कबीर हय गय गैबर सघन धन, छत्र धजा फरराइ।
ता सुख थैं भिष्या भली, हरि सुमिरत दिन जाइ।।
(कबीर ग्रंथावली (डॉ0 गुप्त) सारवी-4, पृष्ठ 89)

मूलत: आध्यात्मिक नैतिक चेतना से प्रेरित होने के कारण ही कबीर के मन में जिस आदर्श मानव की मूर्ति विराजमान थी वह एक सहज, नैतिक, सात्विक ईश्वर भक्त के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। उनकी दृष्टि में आदर्श मानव को ईश्वर भक्त, संसार के आकर्षणों से विरक्त, सत्यनिष्ठ, मन, वाणी कर्म से एक होना चाहिए। मन की विषयोन्मुखता आदर्श मानव के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। इसलिये उसे मन को नियंत्रित रखना चाहिए। कबीर ने वैष्णवों की बार-बार इसीलिए प्रशंसा की है क्योकि वे दयालु, अहिंसक और हरि का सुमिरन करने वाले है। कबीर के लिए सदाचार का सर्वाधिक महत्व है। उन्होने शाक्तों की निंदा उनकी आचारहीनता के कारण ही की है।

वास्तव में कबीर ने भेदभाव की समस्त सीमाओं को तोड़कर भक्त के रुप में जिस आदर्श मानव को सामने रखा है, वह मानव- व्यक्तित्व के विकास की संपूर्ण संभावना अर्थात उसे ईश्वरत्व तक पहुँचाने का है उनके अनुसार नर का नारायाणत्व प्राप्त कर लेना ही सच्चा मानव धर्म है। कबीर का यदि कोई समाज- दर्शन है तो वह मनुष्य के बाह्म जीवन को नैतिक आचरण की मर्यादा में बॉधने वाला, उसके मन का परिष्कार करने वाला और उसकी आत्मा को विश्वात्मा में लय करके उसे सच्चे मानव धर्म की ऊँचाई तक पहुँचाने वाला है। कबीर का लक्ष्य व्यक्ति ही है। उन्होने व्यक्ति को ही आध्यात्मिक चेतना से मंडित करना चाहा है। इसी अर्थ में कबीर को समाज सुधारक कहां जा सकता है। वास्तविकता तो यह है कि उन्होने मनुष्य मात्र में एक ही दिव्य ईश्वरीय ज्योति के दर्शन किये थे और इसी आधार पर मानव मात्र की एकता का प्रतिपादन किया था। वे सच्चे अर्थो में मानवतावादी या मानवधर्मा कहे जा सकते है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. कबीर, डॉ. हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय, बंबई 1664
2. कबीर और कबीर पंथ
3. कबीर, हजारीप्रसाद द्विवेदी, हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय, बम्बई, 1964ई0
4. कबीर के काव्य रुप, नजीर मुहम्मद, 1973 ई0
5. कबीर और पंथ, केदार नाथ द्विवेदी, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, 1965 ई0
6. कबीर ग्रंथावली, संपा0 माता प्रसाद गुप्त, प्रामाणिक प्रकाशन, आगरा, 1969ई0
7. कबीर ग्रथावली, श्यामसुन्दर दास, नागरी प्रचारिणीं सभा, काशी 1038ई0
8. कबीर का रहस्यवाद, रामकुमार वर्मा, 1931ई0
9. कबीर साहित्य की परख, परशुरम चतुर्वेदी, भारती भण्डार, प्रयाग, सं0 2011 वि0
10. हिन्दी साहित्य का इतिहास, रामचन्द्र शुक्ल, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी 2007 ई0

****

आदिवासी संघर्ष और हिन्दी उपन्यास

डॉ. उमा त्रिपाठी *

प्रस्तावना – भारत की जनजातियां आज संक्रमण काल से गुजर रही हैं। अपने ही देश में शोषित, अपमानित, अधिकारों से वंचित आदिवासी सदियों से अभिशप्त जीवन जी रहे हैं। संसाधनों के अभाव, राक्षस और असभ्य जैसी संज्ञाओ से अलंकृत ये जनजातियां अब अपमान की भाषा तोड़ना चाहती हैं। आजादी के मायने समझना चाहती है, अपना इतिहास गढ़ना चाहती हैं। भारत ही नहीं पूरे विश्व में विखरे आदिवासी समुदाय अपने अस्तित्व व अस्मिता के लिये संघर्षरत है। भारत में विकास और लोकतंत्र का लाभ समूचे आदिवासी समाज को सबसे कम प्राप्त हुआ है, गँवाया सबसे ज्यादा है।

पं. जवाहर लाल नेहरू ने 13 दिसम्बर 1946 को संविधान सभा में संकल्प प्रस्ताव रखा था, जिसमें यह घोषणा की गयी थी, 'कि जल्द ही औपनिवेशिक दासता से मुक्त होने वाले इस राष्ट्र का चरित्र स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य का होगा। इसका संविधान अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, अवसरों और दर्जे की समानता तथा कानून के समक्ष व सार्वजनिक नैतिकता और कानून के दायरे में विचार, अभिव्यक्ति, आस्था, विश्वास, उपासना, व्यवसाय, संगठन और कार्यवाई की स्वतंत्रता की गारंटी देगा।' प्रस्ताव में आगे कहा गया कि – 'अल्पसंख्यकों, पिछडों, आदिवासी इलाकों, उत्पीड़ितों और अन्य पिछडे तबकों के लिये पर्याप्त सुरक्षा कवच मुहैया कराया जायेगा..... प्रस्ताव रखते वक्त नेहरू जी ने गाँधी जी की भावना और भारत के महान अतीत के साथ ही फ्रेंच, अमरीकी और रूसी क्रांति जैसी आधुनिक राजनीतिक परिघटनाओं का भी हवाला दिया था। किन्तु इतने दशकों के बाद भी आदिवासी चिन्तन उनके संघर्ष व सपने हमारी सामाजिक संरचना, आर्थिक संरचना के केन्द्र में नहीं आये। शिक्षा और सम्मान से दूर रहने वाला समाज अब अपने संघर्ष, पीड़ा, शोषण हमारे समक्ष रखना चाहता है। आज ये अपनी बात कहना चाहते है। उत्तर आधुनिकता के इस युग में आदिवासी चिन्तन, साहित्य, संस्कृति, चित्रपट और लोक केन्द्र में सुगबुगा रहा है। आज आदिवासी समाज की मुख्यधारा में आना चाहता है। परिवर्तन की प्रक्रिया ने ही आज इन्हें इस मोड़ पर लाकर खड़ा किया है। आवागमन एवं यातायात के साधनों का विकास, जनजातीय क्षेत्रों में जनसंख्या दबाव के कारण अर्थव्यवस्था का पतन, जनजातीय क्षेत्रों में खनिज की अधिकता, शहरी लोगों की जनजातियों के प्रति बढता रूझान एवं सरकारी – गैर सरकारी कल्याणकारी संस्थाओं द्वारा आदिवासी जीवन व क्षेत्रों में सुधार लाने का प्रयास इस सबके लिये जिम्मेदार है।

'भारत में अनुसूचित आदिवासी समूहों की संख्या 700 से अधिक है सन् 1951 की जनगणना के अनुसार आदिवासियों की संख्या 1,91,11,498 थी जो 2001 की जनगणना के अनुसार 8,43,26,240 हो गयी। यह देश की जनसंख्या का 8.2 प्रतिशत है।'[1] भौगोलिक दृष्टि से आदिवासी भारत का विभाजन चार प्रमुख क्षेत्रों में किया जा सकता है– 'उत्तरपूर्वीय क्षेत्र, मध्यक्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत हिमालय अंचल के अतिरिक्त तिस्ता उपत्यका और ब्रम्हपुत्र की यमुना शाखा के पूर्वी भाग का पहाड़ी प्रदेश आता है।' इस भाग के आदिवासी समूहों में गुरूंग लिंबू, लेपचा, आका, डाफला, अबोर, मिरी, मिशमी, सिंगपी, मिकर, राम, कवारी, गोरा, खासी, नाग, कुकी, लुशाई, चकमा आदि है। मध्य क्षेत्र का विस्तार उत्तरप्रदेश के मिर्जापुर जिले के दक्षिणी और राजमहल पर्वतमाला के पश्चिमी भाग से लेकर दक्षिण की गोदावरी नदी तक है। संथाल, मुंडा, उराव, हो, भूमिज, खड़िया, विरहोर, जुआंग, खोड़, सवरा, गोंड़, भील, बैगा, कोरकू, कंमार आदि इस भाग के प्रमुख आदिवासी है।

पश्चिमी क्षेत्र मे भील, ठाकुर, कटकरी आदि आदिवासी निवास करते है। गोदावरी के दक्षिण से कन्याकुमारी तक दक्षिणी क्षेत्र का विस्तार है। चेचू, कोडा, रेड्डी, राजगोड़, कोया, कोलाम, कोदा, कुरूआ, बडागा, टोडा, काडर, मलायन, मुसूवन, उराली आदि आदिवासी उल्लेखनीय है।'[2]

आदिवासी समुदाय की देश की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धरोहर में विशिष्ट भूमिका रही है। स्वतंत्रता के बाद से ही इनके विकास हेतु प्रयास होते रहे है। परन्तु आज भी आदिवासी समुदाय मुख्य धारा मे नहीं आ पाया है। कुछ जनजातियों को छोड़कर अधिकांश जनजातियां विकास के निम्नतम स्तर पर हैं। विकास के नाम पर आदिवासियों के विध्वंस से रची जाती है, विकास गाथा। वीरेन्द्र जैन का उपन्यास 'डूब' ऐसे ही विनाशकारी विकास पर एक प्रश्नचिन्ह है। ' सरकार बेतवा पर बांध बनाना चाहती है, एक गॉव है जो बांध नहीं चाहता। गांव में एक आदमी बांध नहीं चाहता। शुरू से आखिर तक वह अपने सत्य को सत्ता से टकराता चलता है। यह वीरेन्द्र जैन का माते हैं।'[3] माते एक विकास विरोधी चरित्र है। 'डूब' पानी की उपरी सतह की लहरों को नहीं गिनता बल्कि 'डूब' गये यथार्थ को देखता है। 'डूब' हिन्दी की रंगीन आंचलिकता का भी तिरस्कार है। वह एक मौलिक प्रश्न पूंछता है, उस विकास से क्या फायदा जो मनुष्यों को उखाड़ दे, बेघरवार कर दे, उन्हें गलत जगह रोप दे। उनकी सहजात इच्छाओं को रौंद दे।'[4] 'डूब' की खासियत यह है कि वह विकास की अब तक चली आती अवधारणा और उपलब्धियों पर ही प्रश्नचिन्ह लगाता है। माते की घृणा विकास के मानव विरोधी रूप को धिक्कारती है।'[5]

अब लोगों को शिकायत होती है, कि आदिवासी बहुत बोलते हैं। अरूंधती राय आदिवासियों के हक में लिखती है, तो अनुसूचित पिछड़े समुदायों के राजनीतिक लोग उन्हें फतवा दे देते हैं, कि वे तो ब्राम्हण हैं। आदिवासी हक की लड़ाई लड़ रहे हिमांशु कुमार को गॉधीवादी कह दिया जाता है। महाश्वेता देवी के रचनाकर्म को साहित्य ही नहीं मानते हैं। मेघापाटकर बहुत दिनों से नर्मदा बांध के 'डूब' के लिये आदिवासियों की लड़ाई लड़ रही है।

कथाकार संजीव का उपन्यास ' पॉव तले की दूब ' जिसे हम नि:संकोच कुचलते जाते हैं। उपन्यास की कथा का केन्द्र 'सुदीप्त' है। वह झारखण्ड आंदोलन का निष्ठावान कार्यकर्ता है लेकिन आंदोलन की विफलता उसे

* प्राध्यापक (हिन्दी) छत्रसाल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पन्ना (म.प्र.) भारत

अवसादग्रस्त कर देती है। वह अपने कार्यक्षेत्र में वापस लौट जाता है। अन्त में आंदोलन की बेईमानी व असफलता के कारण वह आत्महत्या कर लेता है। सुदीप्त कहता है कि 'झारखण्ड एक शोषित राष्ट्रीयता का सवाल है।'[6] 'पाँव तले की दूब' में यह सवाल हमें इस स्तर पर चुभता है कि क्या हम मुख्यधारा की संस्कृति के दमन में कुछ लोगों को धरती से हमेशा के लिये खतम करने की साजिश को चुपचाप देखते रहेंगे। 'किसी समुदाय की संस्कृति उसके जीवन के पूरे दायरे में अर्जित मूल्य बोध की पूंजी होती है और उसके लिये पहचान के संकट का सवाल तब आता है जब वह देखता है, कि उस पर आक्रमण हो रहे हैं जब उसकी पहचान के विघटित होने का भय उसे आतंकित करता है।'[7] मुख्यधारा की सभ्यता – संस्कृति का लगातार हमला आदिवासियों की संस्कृति को विकृत कर रहा है।

'पाँव तले की दूब' झारखण्ड राज्य बनने के पहले लिखा गया था परंतु झारखण्ड बनने के बाद समस्यायें जस की तस बनी हुई हैं। मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यास 'अल्मा कबूतरी' में कबूतरा जाति के जीवन का संपूर्ण ताना–बाना बडी जीवंतता के साथ प्रस्तुत है। नायिका अल्मा सामाजिक शोषण का शिकार होकर भी हार नही मानती। रूढ़ि को तोड़कर अपने पति को मुखाग्नि देती है। वह पढ़ी लिखी चतुर साहसी नायिका के रूप में संघर्ष कर अपना मुकाम हासिल कर लेती है।पांव तले की दूब के सुदीप्त से वह कहीं बहुत आगे है। बलात्कार के बाद भी वह स्वाभिमान से जीती है। वह एक बोल्ड नारी के रूप में चुनौतियों का सामना करती है।

आदिवासी समाज के संघर्ष और परिवर्तन की बात विश्व भर में फैले आदिवासी समुदाय के संघर्षरत होने की बात है। मुख्यधारा की संस्कृति ने उनके समक्ष दो ही विकल्प छोड़े हैं – या तो आदिवासी अपनी पहचान, अपना इतिहास, अपनी परंपरा को मिटाकर मुख्यधारा की संस्कृति को अपना लें या फिर धरती से अपना अस्तित्व मिट जाने के लिये तैयार रहें। पेरू के माची या झारखण्ड के विरहोर, शबर, कोरबा, असुर राजस्थान के सहारिया जनजातियों की तरह क्रमश: मिटते चले जाये। हद तो यहां तक है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जारवा, आंजे समुदाय को चिडियाघर में बंद वन्य जीवों की तरह पर्यटन की वस्तु बना दिया है। 'विकास और बाजार का समन्वय' राष्ट्रीयताओं को समाप्त कर रहा है।

आज जब भारत में हाशिए के लोगों का विमर्श आरम्भ है, तब आदिवासी भी अपने अधिकारों के लिये जागरूक हो रहे हैं,उनके सपने भी विस्तार पा रहे हैं और मुख्यधारा में आने की छटपटाहट भी उनमें दिखाई देने लगी है। जनजातियों के इस संक्रमणकाल ने अनेक नेतृत्व विज्ञानवेत्ताओं का ध्यान आकर्षित किया है। आधुनिक सभ्यता से सम्पर्क के कारण आदिवासियों की सांस्कृतिक अस्मिता खोने लगी है, वहीं उनका शैक्षणिक और आर्थिक विकास भी हुआ है।

डॉ. धुरिए के अनुसार – 'जनजातियों को आधुनिक सभ्यता के सम्पर्क में लाने की आवश्यकता है। इससे उन्हें अपनी निम्न स्थिति एवं दयनीय दशा का ज्ञान होगा और उसे सुधारने की प्रेरणा मिलेगी।' [8]

बैरियर एल्विन – आदिवासियों को जहॉ तक संभव हो, बाहरी जगत के साथ सम्पर्क से वंचित रखना चाहते थे।

नवेन्दुदत्त मजूमदार का मत है कि 'भारत के राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक ढाँचे में जनजातीय समूहों का एकीकरण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि उन्हें उनकी परम्परागत सांस्कृति से एकदम ही विलग न कर दिया जाये जिससे उन्हें अपूर्व और भौतिक मनोवैज्ञानिक क्षति पहुँचे।'[9] आदिवासियों के बाह्य जगत के साथ संपर्क के प्रति मजूमदार कोई निश्चित मत व्यक्त नहीं कर पाते। अपने एक लेख में वे लिखते हैं कि हैजोंग लोगों में हिन्दू जाति के दो महत्वपूर्ण तत्वों खान–पान एवं विवाह–प्रणाली के कठोर नियमों को अपनाया है।'[10]

'आन्द्रेविताई ने अपने एक शोध लेख में राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में पीपलखुन्त के मीणाओं के लिए लिखा है कि वो लोग अपनी आदिवासी परम्पराओं का खण्डन करने के लिए राजपूतों के नामों का अनुकरण करने लग गये हैं, जिसके परिणामस्वरूप उनकी वेषभूषा, पूजा करने की विधि, विवाह के नियम आदि में परिवर्तन आ गया है।'[11]

विरहोर, थारू, मुण्डा आदि सभी जनजातियाँ परिवर्तन को अपना रही हैं। परिवर्तन प्रारम्भ है। वर्तमान समय में परिवर्तन का प्रवाह सम्पूर्ण समाज को स्पष्ट रूप से एक सामान्य मार्ग की ओर ले जा रहा है। हमारा प्रयत्न इतना होना चाहिए कि जनजातियों को इस योग्य बनाया जाय कि वे वृहत्तर समाज में भाग लें और– यथोचित भूमिका निभायें। शिक्षा और आर्थिक सुधार ही इन्हें मुख्य भूमिका में ला सकते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. इंटरनेट से प्राप्त जानकारी। www.debateonline.in
2. इंटरनेट से प्राप्त। www.debateonline.in
3. सुधीश पचौरी, उत्तर–आधुनकि साहित्यिक विमर्श, डूब: विकास पर सवाल पृष्ठ–149
4. सुधीश पचौरी, उत्तर–आधुनकि साहित्यिक विमर्श, डूब: विकास पर सवाल पृष्ठ–151
5. सुधीश पचौरी, उत्तर–आधुनकि साहित्यिक विमर्श, डूब: विकास पर सवाल पृष्ठ–155
6. पांव तले की दूब, संजीव, वाग्देवी, पाकेट बुक्स, संस्करण 2005, पृष्ठ 88
7. डॉ. रामदयाल मुण्डा, आदिवासी अस्तित्व और झारखण्डी अस्मिता के सवाल, 2002 पृष्ठ–29
8. साह डी.सी. एवं सिसोदिया यतीन्द्र सिंह, घुरिये (2004) ट्राईबल इश्यूजन इण्डिया, रावत पब्लिकेशन जयपुर।
9. नवेन्दुदत्त मजूमदार (1953) दि ट्राईबल प्राब्लम दि– आदिवासीज पृष्ठ–30
10. मजूमदार, रेसेस एण्ड कल्चर्स ऑफ इण्डिया (1958) एशिया पब्लिशिंग हाउस, बम्बई पृष्ठ– 388
11. आन्द्रेविताई (1967) 'दि फ्यूचर ऑफ दी बैकवर्ड क्लासेस' फिलिप मैंसन (सम्पादक) यूनिटी एण्ड डाईवर्सिटी, इण्डिया एण्ड सीलोन, आक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस।

****

नाटक – आदमी की तकलीफ देह यात्रा है

डॉ. रत्नेश विष्वक्सेन *

प्रस्तावना – क्रीड़नीयक इच्छामो दृश्यं श्रव्यं च यद् भवेत की पंचमवेदी प्रार्थना के रूप में, सर्ववार्णिकता की मनुष्य समर्थित सद्भावना के तौर पर यह विधा जीवन और जगत में आकार लेती है। सामूहिकता, सामाजिकता और सहृदयता नाट्य चेतना एवं रंग परिकल्पना का आधारभूत स्थापत्य है। इसलिए यह जीवन की शक्ल के रूप मे अपनी मुकम्मल पहचान बनाती है। यह हमारे सामने घटित होती है और यह प्रक्रिया उसी तरह यातनादायी या फिर आनंदधर्मी होती है या हो सकती है जिस तरह एक जिंदगी का चेहरा स्याह या फिर प्रफुल्लित अपने पराजय या जय पर होता है, या हो सकता है। दुनिया एक रंगमंच है और हम इसके पात्र यह दर्शन नहीं है या फिर ऐसा दर्शन है जो इतना सच पर सीधा है कि मात्र दर्शन कह कर हम बरी नहीं हो सकते।

'नाटक का अपने आप में जीवंत माध्यम होना ही वह निर्णायक तत्त्व है जो उसे सारी विधाओं से एकदम अलग कर देता है। ..... नाटक की कल्पना आदमी के बिना नहीं की जा सकती। नाटक का कथानक चाहे जीव–जंतुओं से जुड़ा हो, वस्तुओं से जुड़ा हो अथवा अमूर्त विचारों पर भी आधारित हो, उसे घटित अन्ततः मनुष्यों के माध्यम से ही होना है। नाटक में मनुष्य की उपस्थिति अनिवार्य है।'[1]

संवाद और संवेदना को मनुष्य से जोड़े और फिर उसे नाटक से तो आसानी से उसकी अनिवार्य उपस्थिति का रहस्य समझ में आ जाएगा। हम जिस तरह रोजमर्रा के जीवन में अनेक रूपों को जीते हैं यथा पुत्र, भाई, शत्रु, मित्र तो अवश्य ही हम नाटकोचित प्रतिज्ञा से रू–ब–रू होते हैं, या उसके विपरीत नाटक में मंचित हो रही घटनाओं और पात्रों के बीच से जीवन का प्रवाह स्पंदित होता दिखाई पड़ता है। इनको देखें तो मेरे कहने का आशय स्पष्ट होगा कि जीवन में जितना नाटक रोज मंचित हो रहा है, उतना नाटक में जीवन घटित हो रहा है, नाटक और जीवन पारस्परिकता में इस तरह अनुस्युत है कि वह हमारी दैहिक चेष्टाओं से आत्मा के संवाद तक अनवरत गतिमान है। भरतमुनि ने जब कहा कि –

'त तज्ज्ञानं न तच्छिल्पं न सा विद्या न सा कला,
नासौ योगो न तत्कर्म नाट्येऽस्मिन यन्न दृश्यते।।

अर्थात् ऐसा न कोई ज्ञान है, न शिल्प है, न कला है, न विद्या है, न योग है, न कर्म है, जो इस नाट्य में न देखा जाता हो, तो इसी जीवनधर्मी संपूर्णता की बात वो कर रहे थें।

नाट्यशास्त्र में काव्यशास्त्र, छंदशास्त्र, संगीतशास्त्र, अभिनय आदि आ जाते हैं इसलिए नाट्य लोकानुरंजन करने वाला है – तब निश्चित तौर पर संपूर्ण नाट्य की कल्पना एक पूर्ण इकाई के रूप में दिखाई देती है। ब्रह्माण्ड की संपूर्णता और अखंडता को विविधता में देखना–समझना हो तो यह 'पंचमवेद' सबसे विश्वसनीय और जीवनानुरोधी है।

'कटलुं जोडतां जोडतां, जोने अजोड अे रूप जडियुं
अखिल ब्रह्माण्डनी सामग्रीथी केवुं नमणुं ने विशेष धडियुं

– देखिए न, कितना कुछ जोड़ते–जोड़ते जोड़ा तब जाकर कहीं वह अतुलनीय रूप मिला, जो अखिल ब्रह्माण्ड की सकल सामग्री से कैसा सुंदर और निःशेष गढ़ा गया।'[2]

यह गुजराती कविता नाट्य संचेतन–संवेदन की संपूर्णता और उसके लोकानुरंजक सौंदर्यशास्त्र की सटीक व्याख्या करती है। यह रंगस्थ खेल के नाम से जाना जाता है। 'खेल' या अंग्रेजी में प्ले बड़ा आकर्षक लगता है। खेल की सबसे बड़ी शक्ति या फिर अनिवार्यता ही सामूहिकता में हैं। या यो कहें कि यह सामाजिकता, समुदाय–भाव इस खेल की पूंजी है। सहयोग, विश्वास, सौहार्द्र–भाव इस खेल की पूंजी है इनका अनूठा समन्वय इसकी प्रक्रिया को निरंतर माँजता रहता है। सच तो यह है कि रंगस्थ खेल या क्रीड़नीयक या काव्येषु रम्यं वाली यह विधा अंततः जीवन की ओर ले जाने वाली मानुष भाव के प्रति ईमानदार और दायित्बोध की प्रेरणा भरनेवाली विधा क्योंकर है, इसे समझना कठिन नहीं है। संस्कृत नाटक और रंगमंच से लेकर नुक्कड़–नाटक की इस यात्रा में कई परिवर्त्तन शिल्प वस्तु और प्रस्तुतियों के स्तर पर आया है, लेकिन संवाद, सहृदयता और उपस्थित मनुष्य की अनिवार्यता आज भी चूकी नहीं है, कई मायनों में वह एकदम प्रतिमान सा सिद्ध हुई है। नाटक मानवीय सरोकारों को स्वयं में समाहित करता है। इस तरह से वह अपने समय और समाज के महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रति सहृदयता से मिलता–जुलता है। यह मात्रा जितनी ज्यादा होगी रचनात्मकता का कद उतना ही ऊँचा होगा। लोकधर्मिता वह प्राण है जिससे किसी भी रचनात्मक विधा को शक्ति मिलती है। इसके विपरीत लोक से जितनी दूरी होगी वह प्रभावहीनता का उतना ही शिकार होता चला जाएगा। हमारे यह लोक शास्त्र से और शास्त्र लोक से संपुष्ट व प्रमाणित होता है।

'लोक को मनुष्य–समुदाय मात्र तक सीमित करना भी लोक की व्यापकता को सीमित करना है। लोक की व्यापकता में विन्यस्त है हमारा समग्र जीवन। जीवन जो संचरणशील है, ... जीवन जो स्थावर है वानस्पतिक, नदी, पहाड़, चल–अचल, चेतन–अचेतन सब कुछ। लोक व्यतीत नहीं है। लोक हर क्षण उपस्थित है। वर्त्तमान है। लोक सजीव है, निर्जीव नहीं। लोक हमारे बीच प्रमाण के रूप में स्वीकृत होता है।'[3]

इस तरह नाटक और रंगमंच की यह लोकोन्मुखता ही उसमें जीवन भरती है। संस्कृत नाटक और रंगमंच स्वयं में अनुष्ठान है, चाक्षुष यज्ञ है। एक विशिष्ट और विस्तृत व्यवस्था के तहत गढ़े गये सौंदर्यशास्त्र है। कई बार उसमें विशिष्ट वर्ग, अभिजात्य सौंदर्य एवं नियमित प्रेक्षागृह का आग्रह बार–बार दिखता है। ठीक यहीं पर हिन्दी में विशेषकर आम आदमी के समसामयिक नाटक की माँग भी उठती है जो जनचेतना को उभारने के साथ–

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) राँची कॉलेज, मोहराबादी, राँची (झारखण्ड) भारत

साथ लोकभाषा और लोकनाट्य वाले मुक्त सौंदर्य को घटित होते देखना चाहती है। हिंदी रंगमंच की प्रकृति को प्रस्तुत करने की चाह और अपनी माटी और उसके निवासियों से जुड़ने की व्याकुलता ने अनिवार्यत: लोक-नाट्य-शैली के प्रयोग पर बल दिया। 1976-77 का वह समय जो राजनीतिक हलचल और जनांदोलन का समय भी था, तथा जिसने निश्चित तौर पर उन परिस्थितियों का निर्माण किया कि रंगमंच और नाट्य लेखन को लोक-नाट्य शैली की तरफ आना पड़ा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की बकरी जिसपर नौटंकी का प्रभाव है एवं मणि मधुकर के रस गंधर्व व दुलारी बाई जिसपर राजस्थानी ख्याल का प्रभाव-प्रयोग है इस रास्ते पर पहला कदम है। लोक में मौजूद अनंत भाव, उनके उमंग-इच्छाएँ, स्वतंत्रता स्वाभाविकता तथा उन्मुक्त चेतना की बरबसता नाट्य के लिए बड़ी प्रेरणा बनती है। डॉ0 लक्ष्मीनारायण लाल के शब्दों में - 'शास्त्रगत सीमाओं को तोड़कर अभिनय और अनुष्ठान के क्षेत्र को सहज कर उसे जीवन की भाँति असीम कर लेना लोकनाटक की सबसे बड़ी देन है।'

इस वक्तव्य में लोक की सबसे बड़ी शक्ति उसकी सहजता में है तो नाटक की स्वयं को जीवन की भाँति असीम करने में। यों लोकनाटक सहजता से स्वयं को जीवन की प्रस्तावना बनाकर प्रस्तुत करता है। उन्मुक्तता, सहजता और सामूहिकता के कोलाज से यह निर्मित होता दिखाई पड़ता है।

'लोकमंच जनजीवन के बीच खुला क्षेत्र है जो अपने आप रच उठता है - कभी गली गलियारे में, कभी आँगन, चौपाल, मंदिर में कभी नदी-नाले, वन पर्वत, द्वार-उपवन, न दृश्य-परिवर्त्तन। एक खुला मंच ही विभिन्न स्थल बन जाता है सूचना मात्र से अभिनय से। चारो ओर बैठा दर्शक सक्रिय भागीदार, टिप्पणीकार भी होता है।'[4]

इतनी सारी विशेषताएँ के साथ पूरे भारत में अनेक नाट्यशैलियाँ लोक की यथा - नौटंकी, रासलीला, रामलीला, भगत, स्वांग, नकल, ख्याल, यात्रा, माच, भवई, यक्षगान, अंकिया, नाच, भांड, बिदेसिया, तमाशा, करियाला मौजूद है। इन सभी की स्थानीय विशेषताएँ है जो क्षेत्र की मान्यता विश्वास, जीवन पद्धति और जीवन-अभ्यास से रगड़ खाकर विकसित हुई है। लोकनाट्य की सहजता और जीवंतता से हिन्दी या भारतीय नाटक व रंगमंच खुद को जनता की अनिवार्यता के रूप में सिद्ध कर सकता है, करना चाहिए। राष्ट्रीय फलक पर हबीब तनवीर अपने मूल लोक कलाकारों द्वारा छत्तीसगढ़ी लोकनाट्य-रूपों का सर्जनात्मक उपयोग 'चरनदास चोर' में कर कितनी संभावनाएँ सामने रख दी यह बताने की आवश्यकता नहीं है। इसी परिवर्त्तन या हिन्दी रंगमंच में विकास और प्रयोग की दृष्टि से नुक्कड़ मंच सामने आया। 'आम जनता तक और अधिक व्यापक जनसमूह तक पहुँचने की कोशिश, एक आम भाषा की तलाश और नाट्यान्दोलन के रूप में।'[5] इस तरह हमारे सामने नुक्कड़ नाटक की तात्कालिकता और सामयिकता के विषय-वस्तु की प्रस्तुति आती है। इसमें भारतीय लोकमंच की सादगी, उन्मुक्तता, लचीलेपन, संगीतात्मकता, सामूहिकता से उसका संबंध था तो दूसरी ओर वामपंथी विचारधारा की प्रतिबद्धता और जनपक्षधरता थी जिससे नुक्कड़ मंच और नाटक का स्वरूप विकसित हुआ।

वर्त्तमान दौर में फिल्में, धारावाहिक व्यावसायिक तौर पर सफल दिखाई पड़ती है। कलाकार को थियेटर अर्थ का कितना संतोष दे पाता है यह एक मुश्किल और महत्वपूर्ण सवाल है। बाजार के समस्त पहलुओं और उत्पाद बन जाने की पीड़ा या फिर उत्पादों के विज्ञापन के लिए स्वयं को उन शर्तों पर उतारना जो खुराफाती हैं, कलाकार कितने समझौते के लिए तैयार है आदि। पर नाटक केवल इतना और इस तरह से नहीं समझा जा सकता है। एक अभिनेता रंगमंच पर जितनी मौलिकता से स्वयं के रचाव को प्रदर्शित करता है, जितनी स्वतंत्रता उसे मयस्सर होती है, वह फिल्मों में संभव नहीं है।

बहरहाल नाटक, रंगमंच, निर्देशक अभिनेता और दर्शक इन सबको परस्पर गूंथते है तो जाकर कहीं साधारणीकरण की स्थिति आती है। सहृदयता की कसौटी मुकम्मल होती है, आर्थिक चरित्रहीनता के दौर में जब उपभोक्ता और मतदाता के अलावा हमारी पहचान कहीं नहीं बची है, हम नाटक में मनुष्य के रूप में बचे हुए है। साबूत आदमी के रूप में संवेदना व आत्मीयता के तार एक-दूसरे को जोड़ते हैं, संवादहीन समय संवेदनशून्य समाज मुनाफाखोर सोंच, कृत्रिम रिश्ते, लाभांश खोजते मूल्यों के बीच जाकर क्या हम वास्तव में समूहहीनता के त्रास से नहीं झुलस रहे हैं।

नाटक प्रकारांतर से संवाद, संवेदना, मूल्यवत्ता और सामूहिकता का विस्तार है। मम से ममेतर तक भाव प्रवाह है, मानव से मानवेतर तक रस प्रसार है। इस तरह वास्तव में आदमी होने की तकलीफदेह पर ईमानदार अनुभूति व अभिव्यक्ति का माध्यम है। हम जब संदेहग्रस्त होंगे, अंधेरे में भटकाव महसूस करेंगे तब हम इस विधा के माध्यम से अपनी वापसी की उम्मीद जगा सकते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. दर्शन-प्रदर्शन-देवन्द्रराज अंकुर-पृ0सं0-13, राजपाल, 2002.
2. नटरंग-जुलाई-दिसम्बर, पृ0सं0-166, अशोक वाजपेयी।
3. परिकथा - युवा रंगकर्म, अंक-पृ0सं0-33, मई-जून, 2012, शंकर।
4. हिन्दी नाटक और रंगमंच नयी दिशायें, नये प्रश्न-गिरीश रस्तोगी, पृ0सं0-107, अभिव्यक्ति-1999.
5. वही पृ0सं0-135.

****

DSS Divya Shodh Samiksha (An International Refereed Research Journal) Oct. to December 2015
ISSN 2394-3807, E-ISSN 2394-3513, Imapct Factor - 0.745 (2014)

ऐतिहासिक उपन्यासों की परम्परा और प्रासांगिकता लोक चेतना के विशेष संदर्भ में

डॉ. अमित शुक्ल*

शोध सारांश – हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यास साहित्य मे लोकचेतना का उदय प्रेमचंद के उपन्यासों से माना जाता है हिंदी उपन्यास साहित्य को मनोरंजन के स्तर से उठाकर लोक जीवन के साथ सार्थक रूप मे जोड़ने का काम उन्होने ही किया चारो ओर फैले हुए जीवन ओर अनेक सामायिक समस्याओ जमीदारों, पूँजीपतियों और सरकारी कर्मचारियो द्धारा किसानों का शोषण निर्धनता, अशिक्षा अन्धविश्वास, दहेज की कुप्रथा घर और समाज में नारी की स्थिति साम्प्रदायिक वैमनस्य लोक जीवन में व्याप्त विषयो और प्रसंगों को उपन्यासों का विषय बनाया। लोक चेतना का संबंध देश के स्थल सुख दुख और आक्रोश के चित्रण से ही नहीं होता है। बल्कि राष्ट्र की आत्मा या चेतना की पहचान से होता है। उससे भी कुछ अधिक होता है। जिसमें देश या समाज की संस्कृति की आत्मा या चेतना स्पंदित होती है। सन् 1940 से लेकर सन् 1980 तक के 43 वर्षो की कालावधि में हिन्दी उपन्यास साहित्य में लोक चेतना के अनेक रूपो और आयामों का चित्रण हुआ है, उसमें सबसे पृथक पहचान प्रेमचंद परपंरा के उपन्यासों की लोक चेतना का है।
शब्द कुंजी– उपन्यास, लोकचेतना, मनोवैज्ञानिक, सौंदर्यबोध, प्रकृति, प्रगतिवाद, एकात्मकता ।

प्रस्तावना – प्रेमचंद ने अपने उपन्यास साहित्य में उत्तरोत्तर आदर्श भावना से मुक्त होकर जीवनधारा ताजगी तथा यर्थातता को महत्त्व देते गये। सामान्य जिन्दगी को उसकी संपूर्ण मार्मिकता के साथ लोक जीवन की गहराई में डूब कर उपन्यास साहित्य में तीव्र संवेदना के साथ व्यक्त करके प्रेमचंद ने आगे आने वाले रचनाकारों का मागदर्शन किया। प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासकारो मे जैनेन्द्र ने सामाजिक मनोवैज्ञानिक चेतना पुरस्कर्त्ता के रूप में प्रतिष्ठित हुए। लोक चेतना की मनोवैज्ञानिक संवेदना को उपन्यास का विषय बनाकर जैनेन्द्र उसे विशेष व्यक्तित्व प्रदान किया।लोक चेतना का संबंध देश के स्थल सुख दुख और आक्रोश के चित्रण से ही नहीं होता है। बल्कि राष्ट्र की आत्मा या चेतना की पहचान से होता है। उससे भी कुछ अधिक होता है। जिसमें देश या समाज की संस्कृति की आत्मा या चेतना स्पंदित होती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लिखे गये उपन्यासों में लोक संम्पृक्ति या लोक चेतना का भाव सन्नहित है। जिसमें सहज लोक जीवन के करीब पहुँचने का प्रयत्न परिलक्षित होता है। लोक जीवन तथा लोक चेतना के प्रति उन्मुखता में प्रगतिवाद का प्रभाव कहा जा सकता है। इस कालखण्ड के उपन्यास साहित्य में लोक जीवन की अनुभूति, सौंदर्यबोध, प्रकृति और उसके प्रश्नों को मिट्टी की गंध से सिंचित कर उसे अभिव्यत्ति देने का प्रयास किया गया है। [1]

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के उपन्यासकारों में यद्यपि जैनेंद्र, अज्ञेय, अमृतलाल नागर, इलाचंद जोशी ने भी अपनी विशिष्ट शैली और विचारधारा के कारण सामान्य व्यक्ति की जिन्दगी से अपने उपन्यास लेखन को जोड़ा लोक चेतना का वह स्वरूप उनमें नही दिखलाई पड़ता जिसे प्रेमचंद्र ने गहराई के साथ लिया था ओर सेवा सदन तथा गोदान मे अभिव्यक्ति किया था स्वातंत्रोत्तर उपन्यासकारों मे लोक चेतना की दृष्टि से यशपाल का अपनी विशिष्ट विचारधारा और सर्जनात्मक शक्ति के कारण स्वतंत्र व्यक्तित्व है, यद्यपि मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित होने के कारण इनके प्रारंभिक उपन्यासों मे समाजवादी यथार्थ की प्रतिबद्ध लोकचेतना अधिक है किन्तु 1858.60 के बीच लिखे गए झूठा सच उपन्यास मे भारतीय जीवन की लोकचेतना का संवेदनात्मक तथा यथार्थ चित्रण मार्मिकता के साथ चित्रित है। झूठा सच यशपाल ने जीवन के विभिन्न रूपों, आयामो, समस्याओं, जटिलताओं और लोकचेतना को अपने ढंग से प्रभावशाली रूप में चित्रित किया। वतन और देश तथा देश का भविष्य में इस उपन्यास में देश विभाजन की पृष्टभूमि पर व्यापक परिकल्पना साामयिक, सामाजिक, राजनैतिक वातावरण को यथार्थ के संदर्भ में व्यक्त करना यशपाल की लोक जीवन के प्रति प्रगाढ़ उन्मुखता का प्रमाण है। [2] यशपाल का 'तेरी मेरी उसकी बात' उपन्यास भी संलिष्ट है। आधुनिकतावादी उपकरणों के साहित्य में गाँव का वातावरण बदलने लगता है। इस बदलाव में अवसरवादी राजनेताओं के नकाब उतारकर युवापीढ़ी के संघर्षो का जिस ढंग से चित्रण किया है, वह देश की ऐतिहासिक लोक चेतना की पहचान का सूचक है। आंचलिक चेतना को आधार बनाकर राही मासूम रजा शिवप्रसाद सिंह, रामदरस मिश्र, हिमांशु श्रीवास्तव आदि ने भी उपन्यास लिखे है। राही का 'आधागाँव' शिया मुस्लमानों की जिन्दगी पर लिखा गया है। ऐसा उपन्यास है जिसमें भारत विभाजन के पहले और बाद की जिन्दगी का राष्ट्रीय आकांक्षाओं और जन चेतना के संदर्भ में तीखे दर्द के साथ उभारा गया है। शिवप्रसाद सिंह उपन्यास 'अलग अलग वैतरणी' में आधुनिकता बोध और लोकचेतना को सन्निविष्ट करने की कोशिश की है। इसके परिवेश में नए पुराने मूल्यों, नयी पुरानी पीढ़ी, भिन्न भिन्न वर्गो और जातियों की टकराहट में सारे मूल्य गड्ड–मड्ड हो जाते है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी गाँव के लोग अपनी वैतरणी पार न कर सकें। सो नरक हो गये जहाँ अलगाव और टूटन है। वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक तथा समूचे गाँव के देश के सामाजिक राजनीतिक लोक जीवन का यथार्थवाद चित्रण है यशपाल की औपन्यासिक लोकचेतना की धार को पैना बनाने मे सबसे बाधक रही है उनकी मार्क्सवादी केन्द्रीय चेतना इसका फल यह हुआ है कि लोक जीवन के सत्यचित्रण में संलग्न होकर किसी जटिल मार्ग से गुजरने की उन्हे जरूरत नही हुई है इसलिये उनके उपन्यास झूठा सच, तेरी मरी, उसकी बात वह अपेक्षित रचनात्मक ऊँचाई नही पा सके। स्ववंत्रता प्राप्ति के समय देश विभाजन के कारण जन जीवन में नई समस्याएं उत्पन्न

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत

हुई। उन्हें भी औपन्यासिक रूप दिया गया। यशपाल के 'झूठा सच' मेरी तेरी उसकी बात उपेन्द्र अश्क की 'गिरती दीवारें', गर्मराख, भगवती चरण वर्मा के टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले विसरे चित्र, राही मासूम रजा का, आधा गाँव आदि उपन्यासों में व्यक्ति समाज और देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय की अनेक समस्याओं को उठाया गया है। टूटी हुई आस्थाओं और विश्वास के माहौल में भी जूझते हुए व्यक्तियो और समाज के मध्य उभरती हुई लोकचेतना को सन् 1850 के बाद के उपन्यासों में देखा जा सकता है।[3] निश्चय ही ये आस्थाएं स्वतंत्र देश के उल्लास मनोबल और धरती से जुड़ी हुइ जनचेतना से अनुप्रेरित है। इसके अतिरिक्त ग्रामांचल पर लिखे गये फणीश्वरनाथ रेणु, नागार्जुन, उदय शंकर भट्ट, राही मासूम रजा, शिवप्रसाद सिंह, रामदरस मिश्र, हिमांशु श्रीवास्तव आदि के उपन्यासो में भी इसी आस्था और लोकचेतना को हम देखते है। इनमें रेणु के उपन्यासों में लोकचेतना के विशद और जीवंत चित्र देखने को मिलते है। 'मैला आंचल और परती परिकथा' उपन्यासों में ग्रामांचल की छोटी छोटी घटनाओं, कथाओं, आचार विचार, रीति नीति, राजनीतिक, नैतिक अवधारणाओं, पारिवारिक संबंधो के संलिष्ट चित्र मिलते हैं, जो पूरे अंचल की लोक चेतना के संदर्भ में गत्यात्मक स्तर पर रामदास मिश्र का 'जल टूटता हुआ' तथा 'सूखता हुआ तालाब', हिमांशू श्रीवास्तव का 'रथ के पहिए', अब्दुल बिस्मिल्ला का झीनी झीनी बीनी चदरिया, गॉव के दमघोटू वातावरण, समस्याओं, विसगंतियों, आभावों और आंतरिक संदर्भो की लोकचेतना को तीव्रता से अभिव्यक्त करते है। आधुनिकीकरण, बाहरी सभ्यता और लोक जीवन के संक्रमण के बीच निरंतर बदल रहे गॉव और नगर के विभिन्न आयामों को इन उपन्यासों में उद्घटित किया गया है। सामाजिक पृष्ठभूमि पर लिखे गये लोकचेतना के उपन्यासकारों में मन्मथनाथ गुप्त, भैरव प्रसाद, अमृत राय, राजेन्द्र यादव, नरेश मेहता, भीष्म साहनी, कृष्ण बलदेव वेद, गिरिराज किशोर, रमेश वसी, मधुकर गंगाधर, उदयराज आदि के नाम उल्लेखनीय है। इनमें से कुछ उपन्यासकार मार्क्सवादी दृष्टिकोण से प्रतिबद्ध होने के कारण वर्ग संघर्ष की प्रगतिवादी चेतना से आच्छंन्न है। उनमें लोकचेतना का यथार्थवादी रूप नहीं मिलता मन्मथनाथ बहता पानी, भैरव प्रसाद के मशाल और गंगा मैम तथा अमृतराय के बीज, नागफनी व देश और हाथी दाँत ऐसे ही उपन्यास है। राजेन्द्र यादव मन्नु मंदारी ने भारतीय समाज की चेतना को उखड़े हुए लोग उपन्यास में अधिक गहराई के साथ पकड़ने की कोशिश की है। आज की आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था व्यक्ति को कैसे समझौतावादी बनने के लिए बाध्य करती है ।[4] यह इस उपन्यास के कथा प्रसंग से स्पष्ट होता है।समय के साथ चेतना प्रवाह इतना विश्रखंल हो गया है, कि जिन्दगी पूरे तौर पर विश्लेषित न होकर कालखंड में बिखर बिखर कर रह गई है। गॉवों और देशे की चेतना इसी बिखरेपन को झेलती किसी तरह आगे बढ़ रही है इसीलिए छोटे फलक पर विस्तृत जीवनानुभूतियों के अनेक चित्र, शिवप्रसाद, गिरधर गोपाल, सर्वेश्वर दयाल के उपन्यासों में मिलते है। रूद्र की बहती गंगा गिरधर गोपाल का 'चॉदनी रात के खण्डहर' सर्वेश्वर दयाल का 'सोया हुआ जल' ऐसे ही उपन्यास है। इनमे परिस्थतियों, घटनाओं, मनोदशाओं और मध्यवर्गीय परिवार की खोखली आर्थिक स्थिति के खण्ड-खण्ड चित्र है। कहीं-कहीं अंतश्चेतना की भूख, व्याकुलता और अतृप्ति के चित्र है जो देश में व्याप्त बृहत्तर लोक चेतना के प्रतिबिम्ब है गुमशुदा आस्था की तलाश अनेक अभिशप्त पात्रो और चरित्रो की सृष्टि गंगा प्रसाद विमल की विशेषता है। बदलते हुए रिश्तो को लेकर अपनी मिट्टी की पहचान खोदने वाले पात्रों को लेकर ज्ञान रंजन और उदय प्रकाश ने उपन्यास लिखे है। गिरजा किशोर के उपन्यास में आज की परिस्थितियों में निर्णय न ले सकने वाले व्यक्तियों के कथा चित्र है जिसमें वर्तमान समाज की विसंगतीयों के चित्र है। नरेन्द्र कोहली अतीत के कथा प्रसंग को वर्तमान से जोड़कर लिखते है। 5 उनमे देश की लोकचेतना को झकझोरने की शक्ति है। महिला उपन्यासकारों में ममता कालिया, निरूपमा सारवती, कृष्णा सोवती, मालती जोशी, कृष्णा अग्निहोत्री, दीप्ति खंडेलवाल ने समाज में व्याप्त अस्वीकार, ऊब, भीड़ में अकेलेपन, तथा राजनीति की उठापटक के सृजन की आंतरिक विवशता मान कर कथात्मक रूप प्रदान किया है। मन्नू भंडारी, शिवानी, कृष्णा सोबती ने अपने सृजन में आधुनिक नारी की मन स्थिति पारिवारिक जीवन के रिश्ते तथा उनके सीमित दायरे को अधिक समझा है।

निष्कर्ष - यह है कि स्वतंत्रता के बाद सन् 1940 से लेकर सन् 1980 तक के 43 वर्षो की कालावधि में हिन्दी उपन्यास साहित्य में लोक चेतना के अनेक रूपो और आयामों का चित्रण हुआ है, उसमें सबसे पृथक पहचान प्रेमचंद परपंरा के उपन्यासों की लोक चेतना का है, दूसरी उस सामाजिक लोक चेतना का जो प्रगतिवाद से प्रभावित है। मनोवैज्ञानिक चेतना को उभारने वाले उपन्यास भी लिखे गये है वास्तव में भारत जैसे विभिन्न संस्कृतियों, धर्मो, भाषाओं तथा प्रदेशो में बटे हुए देश की लोकचेतना की एकात्मकता को उभारने के लिए हिन्दी साहित्य में संश्लिष्ट रूप से उपन्यासों में जो प्रयास किये गये है, उन्हीं को स्थायित्व मिला है।[6]

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. शुक्रवार कालका जी नई दिल्ली अक्टूबर 2007 पृष्ठ 20
2. वीणा पत्रिका रवीन्द्र नाथ टैगोर मार्ग इन्दौर अगस्त 2008, पृष्ठ 10
3. दैनिक जागरण समाचार पत्र भोपाल नवम्बर 2008, पृष्ठ 6
4. आउटलुक, पाठक साहित्य सर्वे मासिक पत्रिका जनवरी 2011 सफदरजंग नई दिल्ली पृष्ठ 36, 49
5. दि संडे राष्ट्रीय साप्ताहिक समाचार पत्र दिल्ली, नोएडा, देहरादून से प्रकाशित उत्तराखण्ड संस्करण, 20-02-2011 लेख-सृजन संसार के अंतर्गत डॉ अमित शुक्ल, रीवा पृष्ठ - 20
6. स्वंय का सर्वेक्षण एवं निष्कर्ष।

****

भूमण्डलीकरण के दौर में हिन्दी साहित्य पर संचार क्रांति का प्रभाव

प्रीति कुमारी *

शोध सारांश – 'भूमण्डलीकरण वैश्विक स्तर पर घटित एक ऐसी घटना है जिसने समग्र विश्व को अपनी चपेट में ले लिया है। इस दौर में जो पीछे रह गया, भूमण्डलीकरण उसे हाशिए पर छोड़ता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है। भूमण्डलीकरण की इस परिघटना को आकार देने में संचार क्रांति ने अहम भूमिका निभाई है। तकनीकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से आज हिन्दी साहित्य 'ग्लोबल विलेज' में प्रवेश कर चुका है व वैश्विक पटल पर अपनी पहचान कायम कर रहा है।

प्रस्तावना –'अंग्रेजी के 'ग्लोबलाइजेशन' (Globalization) शब्द के लिए हिन्दी में 'भूमण्डलीकरण' शब्द प्रचलित है। इसके लिए 'वैश्वीकरण' शब्द भी प्रयुक्त होता है। यह शब्द बीसवीं सदी के अंतिम दशक में व्यापक रूप में प्रयोग में आया।[1] भूमण्डलीकरण की यह परिघटना अपने व्यापक रूप में 1991 में घटी, सोवियत संघ के विघटन के बाद जब दुनिया एक ध्रुवीय हो गयी और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने अमेरिका के नेतृत्व में तीसरी दुनिया के बाजार पर कब्जा करना शुरू किया। भारत ने भी इसमें अपनी भागीदारी घोषणापूर्वक 1991 में ही दर्ज की, जब विदेशी मुद्रा के संकट के कारण 24 जुलाई को नयी उद्योग नीति की घोषणा की गई।

'भूमण्डलीकरण' शब्द से 'वसुधैव कुटुम्बकम' व 'सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय' की भावना का भ्रम पैदा होता है मानो यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें लोग अपने छोटे स्वार्थों से ऊपर उठकर, विश्व के मंगल के लिए एकजुट हो जायेंगे किन्तु यह व्यवस्था पूँजीवादी प्रतिष्ठानों व बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हितों की रक्षा का माध्यम बनी हुई है। 'हालांकि, इससे यह भ्रम पैदा होता है कि संसार के लोग जुड़ रहे हैं और संसार एक 'वैश्विक गांव' (Global Village) बन गया है, परन्तु वास्तव में इससे सिर्फ संसार का एक सम्पन्न वर्ग ही अपने व्यापारिक या व्यावसायिक हितों के लिए एक दूसरे से जुड़ता है। प्रत्येक क्षेत्र और देश में नये संचार माध्यमों से संसार से जुड़े समूह अपने ही आस-पास के बहुसंख्यक वंचित समूहों से पूरी तरह कट जाते हैं। संसार का एक नया विभाजन सूचना समृद्ध और सूचना से वंचितों के बीच होता है।'[2]

दुनियाभर के जो लोग इसके इतिहास से परिचित नहीं है उन्हें लगता है कि यह समस्या अचानक न जाने कहाँ से आ टपकी, किन्तु इसके लिए धीरे-धीरे वर्षों से राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक जमीन तैयार हो रही थी। 'हमारे मिथकों में अगर भूमण्डलीकरण से प्रभावित आज के हालात की कोई मिसाल मिल सकती है तो वह सिर्फ समुद्रमंथन की पुराणगाथा ही है, जिसमें सभी पक्ष जुटे हुए थे और किसी को ठीक-ठीक नहीं पता था कि सुमेरू पर्वत से बनी उस विराट मथानी से क्या-क्या निकलेगा। लेकिन मंथन में शामिल होने के कारण वे सभी उन परिणामों का फल भोगने के लिए अभिशप्त थे।'[3] इसी तरह आज भी सभी राष्ट्र बिना परिणाम जाने इस प्रक्रिया में सम्मिलित होना चाहते हैं जो राज्य, क्षेत्र व लोग इसके दायरे में नहीं आना चाहते भूमण्डलीकरण ने उन्हें हाशिये पर डाल दिया है। 'भूमण्डलीकरण और हाशियाकरण एक ही परिघटना की प्रतिछवियाँ हैं।'[4] भूमण्डलीकरण आज खुद को मुख्यधारा की संस्कृति के रूप में स्थापित कर चुका है। 'यही कारण है कि आज बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के सिद्धांतकार और विचारक हमें समझा रहे हैं कि राष्ट्रवाद या राष्ट्रीयता पुरानी चीज हो गयी है। क्षेत्रीय स्वायत्तता और भाषा के आधार पर संस्कृति की पहचान करना पिछड़ापन है। अपनी राष्ट्रीयता, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति के बारे में सोचना विकास की सहज गति को अवरूद्ध करना है।'[5]

भूमण्डलीकरण के इस दौर में आगे बढ़ने की धुन इस तरह सवार है किइस प्रक्रिया में जो हाशिये पर रह जायेगा भूमण्डलीकरण उसे धकेलते हुए आगे बढ़ जायेगा। 'वैश्वीकरण आज थोड़े लोगों के हाथों में केन्द्रित एक ऐसी संस्कृति का निर्माण कर करा रहा है जिसमें हाशिये के लोगों को उससे भी बाहर धकेलने की पूरी तैयारी कर ली गई है।'[6] भूमण्डलीकरण राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं सांस्कृतिक सीमाओं के ऊपर सदैव हावी रहा, इसने सरहदों को कभी सीमा नहीं बनने दिया। 'सवा सौ साल से ज्यादा लम्बे इस सफर में आधुनिकता ने इस मंजिल को कभी आँखों से ओझल नहीं होने दिया। वह लगातार कोशिश करती रही कि सत्ता की 'ग्लोबल' संरचनाएं अन्य सरहदों की नियामक बनें न कि उन्हें सरहदों की जरूरतों के मुताबिक काम करने पर मजबूर होना पड़े।'[7] इसका सम्बन्ध व्यापार, वित्तीय पूँजी, तकनीक, ज्ञान, संस्कृति और लोगों के आने-जाने के मामलों में राष्ट्रों की दीवारें टूटने से है।

अगर भूमण्डलीकरण को आधुनिकता की आर्थिक अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाय तो अपने आरम्भिक पैंतालीस वर्षों में (1870 से 1914) के बीच यह तेज रफ्तार से दौड़ता नज़र आता है किन्तु प्रथम विश्व युद्ध ने इस क्रम को धीमा किया। इसके बाद पूरी दुनिया में जहाँ राष्ट्रों की सरहदें पूँजी और श्रम की नियामक हो गयीं वहीं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया दो हिस्सों में बंट गयी। और दोनों ही हिस्से एक दूसरे से प्रतियोगिता करते नजर आये 'इस प्रतियोगिता को हम वामपंथी बनाम दक्षिणपंथी या समाजवाद बनाम पूँजीवाद की प्रचलित श्रेणियों के नाम से जानते हैं।'[8] बीसवीं सदी के अंतिम दशक में जो भूमण्डलीकरण अपनी पूरी शक्ति के साथ हमें बढ़ता दिखाई देता है, जमीन सत्तर के दशक में बनने लगी थी। 'उसे बनाने में न केवल पूँजीवाद के समर्थक जुटे हुए थे, बल्कि इसकी प्रतिक्रिया में कार्यरत पूँजीवाद के घोषित विरोधी भी जाने अनजाने हालात को उसी तरफ ले जा रहे थे। हथियारों की होड़ और अन्य बहुतेरे कारणों से जैसे ही

* शोधार्थी (हिन्दी) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ (म.प्र.) भारत

तत्कालीन समाजवादी राज्य का ढाँचा संकटग्रस्त हुआ और दुनिया एक ध्रुवीय होने की तरफ बढ़ी, वैसे ही भूमण्डलीकरण का रास्ता साफ होने लगा।'[8] विविधता व बहुसांस्कृतिकता को सुरक्षित करने के संदर्भ में भूमण्डलीकरण का आग्रह था कि समस्त राष्ट्र व संस्कृतियों कुछ समान मूल्यों को अपनायें साथ ही उसने यह धमकी भी दी कि अगर ऐसा नहीं किया जायेगा तो उससे ताकत के दम पर निबटा जायेगा। भूमण्डलीकरण के तीन आयाम हैं – आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सांस्कृतिक जिनमें आर्थिक सर्वप्रमुख है।

भारत ने 24 जुलाई 1991 को पेश किये गये बजट व नयी उद्योग नीति के साथ भूमंडलीकरण के इस दौर में प्रवेश की घोषणा की।तात्कालिक रूप में यह नीति विदेशी मुद्रा संकट के कारण कांग्रेस की नरसिंह राव सरकार के अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लिये गये कर्ज का परिणाम थी। किन्तु इसकी अघोषित भूमिका सत्तर व अस्सी के दशक से ही बनने लगी थी। सांस्कृतिक स्तर पर भारतीय अभिजनों ने भूमण्डलीकरण को आधुनिकता की अभिव्यक्ति के रूप में आसानी से स्वीकार कर लिया किन्तु इसका लाभ केवल अमीरों व साधन सम्पन्न लोगों को ही मिला।

भूमण्डलीकरण की इस परिघटना को आकार देने में संचार क्रांति की अहम भूमिका है। पिछले पच्चीस वर्षों से नेटवर्क सोसाइटी की रचना के माध्यम से एक ऐसी आभासी दुनिया का अविष्कार किया जा रहा है, जिसमें सबकुछ है मगर किसी भी चीज की दैहिक उपस्थिति नहीं। 'इण्टरनेट के संक्षिप्त इतिहास में ब्रूस स्टार्लिंग ने नेट की तुलना अंग्रेजी भाषा से की है, जो इस अर्थ में बिल्कुल सटीक है कि जैसे अंग्रेजी का कोई मालिक, पहरेदार या ठेकेदार नहीं है, उसी तरह नेट भी बहते नीर की तरह है– स्वतंत्र और अबाध।'[10] अभी नेट का अधिकतर कार्य अंग्रेजी में ही होता है, दुनिया में इतनी बड़ी संख्या में बोली जाने वाली भाषाओं के लिए यह एक तरह से भूमण्डलीकरण के लिए चुनौती भी है। 'यह विचार कि एक दुनिया के सभी लोग अंग्रेजी भाषी हो जाएँगे, एक ख्याली पुलाव सा लगता है।'[11] धीरे–धीरे लोगों ने कम्प्यूटर की भाषा को स्थानीयकृत करना शुरू किया और आज वर्ल्ड वाइड वेब, विभिन्न भाषाओं में उपस्थित है। साहित्य के भूमण्डलीकरण को लेकर सीमा भाषाओं की भिन्नता की है। 'उन्नीसवीं सदी की क्लासिक कृतियों का भूमण्डलीकरण उस तरह कभी भी नहीं हो पाया जैसे संगीत और अन्य चाक्षुस कलाओं का। इटली के बाहर ऐसे लोग बहुत कम होंगे जो दांते की काव्य प्रतिभा से परिचित हों और उसका महत्व समझते हों क्योंकि दांते को उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। केवल रूसी लोग और रूसी भाषा से परिचित लोग ही पुश्किन को रूस का सार्वकालिक महानतम कवि मानते हैं।'[12]

जहाँ तक हिन्दी बोलने वालों की संख्या का प्रश्न है, हिन्दी भाषा विश्व में तीसरे नम्बर पर है। विश्व में सबसे अधिक बोलने वालों की संख्या चीनी की है, दूसरे नम्बर पर अंग्रेजी और तीसरे पर हिन्दी। तकनीकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से आज हिन्दी 'ग्लोबल विलेज' में प्रवेश कर चुकी है। इण्टरनेट पर सैकड़ों हजारों वेबसाइटस पर हिन्दी साहित्य की सामग्री बिखरी पड़ी है किन्तु अधिकांश सामग्री रोमन लिपि में होने व यूनिकोडित नहीं होने से हिन्दी साहित्य को इंटरनेट पर ढूँढ़ना और पढ़ना मुश्किल काम था। ललित कुमार ने 5 जुलाई 2006 को इण्टरनेट पर कविता कोश नामक परियोजना (www.kavitakosh.org) की शुरूआत की। आज यह कोश 55000 से भी अधिक रचनाओं का संकलन बन चुका है जिसमें दो हजार से अधिक रचनाकार संकलित हैं। ललित कुमार ने ही 2008 में गद्य कोश नामक नई परियोजना (www.gadyakosh.org)की शुरूआत की। जिस तरह कविता कोश हर काव्य विधा को अपने में समाहित करता है उसी तरह गद्य कोश की परिकल्पना भी एक ऐसे विश्व कोश के रूप में की गई जिसमें सभी गद्यात्मक विधाएँ संकलित हो सकें।

विश्व में इण्टरनेट के प्रयोग और हिन्दी में इसके आरम्भ में तीन दशकों का अंतर रहा है। यह अंतर इण्टरनेट पर उपलब्ध साहित्य में भी देखा जा सकता है। वर्तमान समय में विकीपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया सन्दर्भ का अद्यतन स्त्रोत हैं। हर भाषा के अपने–अपने पोर्टल्स हैं। विश्व भाषाओं में अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेन, डच, जर्मन जैसी भाषाओं के साहित्य की वेबसाइटें अधिक हैं। अंग्रेजी भाषा के जानकार दुनिया भर में हैं अंग्रेजी भाषा की वेबसाइटें दुनिया भर से चलाई जाती है और सारी दुनिया के लोग उन्हें लिखते पढ़ते भी है अत: अंग्रेजी साहित्य का स्तर हिन्दी की तुलना में उच्च होना स्वाभाविक हैं।

निष्कर्ष–हिन्दी में भी नियमित रूप से ऑनलाइन लेखन करने वाले हिन्दी प्रेमी व सैकड़ो वेबसाइटें है– किन्तु उनके अद्यतन न होने व विभिन्न विश्वविद्यालय व विभागों की उपस्थिति इण्टरनेट पर नियमित न होने से अभी हिन्दी साहित्य की विश्व में भागीदारी की संभावनाओं पर प्रश्न चिन्ह लगना स्वाभाविक ही है। हिन्दी साहित्य ने इण्टरनेट के माध्यम से ग्लोबल विलेज में अपनी उपस्थिति तो दर्ज करा दी है किन्तु वैश्विक पटल पर अपना स्तर बनाने व सर्वोच्च स्थिति में पहुँचने में अभी समय लगेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. डॉ0 अमरनाथ, हिन्दी आलोचना की पारिभाषिक शब्दावली, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, दूसरे संशोधित संस्करण की पहली आवृत्ति 2013, पृ0 258.
2. वही, पृ0 259.
3. सम्पा0 –अभय कुमार दुबे, भारत का भूमण्डलीकरण, श्रृंखला सम्पादक विजय बहादुर सिंह, योगेन्द्र यादव, वाणी प्रकाशन, दरियागंज, नयी दिल्ली, संस्करण 2008, पृ0 27.
4. वही, पृ0 91.
5. डॉ0 अमरनाथ, हिन्दी आलोचना की पारिभाषिक शब्दावली, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, दूसरे संशोधित संस्करण की पहली आवृत्ति 2013,पृ0 259.
6. मिथिलेश, वैश्वीकरण का त्रासद आख्यान : ग्लोबल गांव के देववा; सम्पा0 अरूण कमल पत्रिका आलोचना (त्रैमासिक), सहस्त्राब्दी अंक उनचास, अप्रैल–जून 2013, पृ0 100.
7. सम्पा0 – अभय कुमार दुबे, भारत का भूमण्डलीकरण, श्रृंखला सम्पादक विजय बहादुर सिंह, योगेन्द्र यादव, वाणी प्रकाशन, दरियागंज, नयी दिल्ली, संस्करण 2008, पृ0 28.
8. वही, पृ0 29.
9. वही, पृ0 32.
10. लेखक, रविकांत, लेख, भविष्य का इतिहास, सम्पादक अभय कुमार दुबे, भारत का भूमण्डलीकरण, पृ0 290.
11. लेखक (इरिक हॉब्सबॉम और एन्तोनियोपोलितो की बातचीत से) इरिक हॉब्सबॉम का कथन, लेख भूमण्डलीकरण : अर्थव्यवस्था, राजनीति और संस्कृति, सम्पादक अरूण कमल, पलिका–आलोचना (त्रैमासिक) सहस्त्राब्दी अंक सैतालीस (अक्टूबर–दिसम्बर 2012) पृ0 66.
12. वही, पृ0 64.

स्वातंत्रयोत्तर हिन्दी पत्रकारिता के विविध आयाम

डॉ. गुरविन्दर सिंह गिल *

प्रस्तावना – स्वतंत्रता के पश्चात् हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं का बहुआयामी विकास हुआ है।[1] स्वातंत्रयोत्तर भारत में हिन्दी पत्रकारिता ने साहित्यिक विधाओं को पर्याप्त महत्व दिया। इन विधाओं में निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण, रिपोतार्ज, फीचर, यात्रावृत्त, आत्मकथा, डायरी लेखन आदि प्रमुख हैं। विविध पत्र-पत्रिकाओं ने साहित्य की भी वृद्धि की है। इनमें दैनिक पत्रों, साप्ताहिक पत्रों, मासिक व त्रैमासिक पत्रों का विशेष योगदान रहा है।

साहित्यिक अभिरुचि का विकास– मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास उसके सामाजिक जीवन से ही संभव हुआ है।[2] साहित्य अभिरुचि तभी विकसित होती, है, जबकि लेखक सरल शब्दों में अपने मानस की अनुभूतियों को सरल व सुस्पष्ट भाषा में कहे, इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि पाठक की सवेदना में लेखक द्वारा कहा गया सब कुछ समा जाए। तात्पर्य यह है कि लेखक और पाठक दोनों के बीच सम्बन्ध बना रहे। यह तभी सम्भव हो सकता है, जब लेखक के पास प्रेषणीय क्षमता हो और पाठक के पास ग्राह्यिका शक्ति। प्रसिद्ध अंग्रेजी समीक्षक रिचर्ड्स ने श्रेष्ठ और सफल लेखक की चर्चा करते हुए लिखा है कि 'प्रेषणीयता का गुण प्रत्येक लेखन की सफलता की पहचान है।'

स्वातंत्रयोत्तर पत्र-पत्रिकाओं में से अधिकांश का उद्देश्य भले ही व्यावसायिक रहा हो, किन्तु उससे साहित्य का विकास अवश्य हुआ है। पारिवारिक परिशिष्ट पत्रिका में कहानी, कविता, सत्यकथा, प्रेरक लघु कथाएँ आदि को स्थान दिया जाता है जो कि मनुष्य की साहित्यिक अभिरुचि को जागृत करती है। आप कोई भी दैनिक पत्र देख लीजिए सभी में साहित्य से सम्बन्धित सामग्री निहित रहती है। इस तरह इन पत्रिकाओं में साहित्य की नवीनतम सूचनाएँ होती है।[3]

साप्ताहिक हिन्दुस्तान, धर्मयुग जैसे पत्रों में नियमित रूप से कविता, कहानी, संस्मरण, धारावाहिक, उपन्यास, रेखाचित्र आदि प्रकाशित होते रहते हैं। ऐसे प्रमुख साप्ताहिकों की संख्या भी कम नहीं है। प्राय: देखने में आता है कि जो व्यक्ति साहित्य से सम्बन्धित नहीं है वे भी प्रमुख साप्ताहिकों को इसलिए पढ़ते हैं कि उनमें उन्हें कोई सुन्दर कहानी, कोई मन को बाँधने वाली कविता और कोई अच्छा धारावाहिक उपन्यास पढ़ने को मिल जाता है। आज कितने ही ऐसे लेखक है जो पत्र-पत्रिकाओं में छपते-छपते अपना एक प्रतिष्ठित स्थान बना चुके हैं। आधुनिक हिन्दी साहित्य के अधिकांश प्रतिष्ठित लेखक, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में पत्रकार भी रहे हैं। पत्रकारिता- इतिहास और प्रश्न के लेखक कृष्णबिहारी मिश्र का यह कथन महत्वपूर्ण है-'स्वातंत्रयोत्तर काल में नई पीढ़ी के कुछ कृति साहित्यकारों के व्यक्तिगत प्रयत्नों से साहित्यिक पत्रकारिता के क्षेत्र में स्तरीय कार्य हुआ है।[4]

सांस्कृतिक अभिरुचि का विकास–स्वातंत्रयोत्तर काल में हिन्दी पत्र-पत्रिकाएँ जीवन का एक अंग बन गयी है। वे अनेक साहित्यिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की प्रसारक व विश्लेषिका है। स्वातंत्रयोत्तर वर्षो में अनेक ऐसी पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाश में आई हैं जिन्होंने जन-जीवन में सांस्कृतिक छवि को विकसित किया है।

पत्र-पत्रिकाओं ने हमारी सांस्कृतिक अभिरुचियों को बढ़ाया है। सांस्कृतिक अभिरुचि में धर्म, नीति, दर्शन समाज-साहित्य और खेलकूद अथवा मनोरंजन के साधन आते हैं। इस दिशा में प्रमुखत: कादम्बिनी, दिनमान, पुरोधा, श्रीकृष्ण संदेश, कल्याण, सरिता, मुक्ता, धर्मयुग, नवनीत, भारती, ज्ञानोदय आदि का प्रमुख योगदान है। ये वे पत्र-पत्रिकाएँ हैं जिनका योगदान विशेष रूप से सांस्कृतिक है। भारती, नवनीत आदि पत्रिकाओं में कहानियाँ, कविताएँ, लेख और परिसंवाद प्रकाशित होते हैं, ये लेख सांस्कृतिक मूल्यों को विकसित करने में सहायक होते हैं, ये पत्रिकाएँ हमारे आत्मिक परिष्कार के लिए उपयोगी है।

नैतिक और धार्मिक मूल्यों की प्रतिष्ठा के लिए कुछ पत्र-पत्रिकाएँ सामने आई है। ऐसी पत्र-पत्रिकाओं में कल्याण, अखण्ड-ज्योति आदि प्रमुख हैं। ये वे पत्र-पत्रिकाएँ हैं जिनमें धर्म, ईश्वर तथा आध्यात्मवाद की चर्चा होती है कि किस तरह श्रद्धा, भक्ति, प्रजा और आराधना जीवन की बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकताएँ हैं। अखण्ड ज्योति में मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा के लिए अनेक उपयोग एवं मूल्यवान लेख रहते हैं।

बाल पत्रिकाएँ– उपर्युक्त पत्र-पत्रिकाओं के अतिरिक्त बाल पत्रिकाएँ जैसे बालसखा, नन्दन, चम्पक, पराग, चन्दामामा, बालक, वैज्ञानिक बालक, बाल भारती, गुड़िया आदि प्रकाशित होते हैं वह बच्चों की सांस्कृतिक अभिरुचियों को विकसित करने में सहायक हैं, ऐसे कुछ लेख भी होते हैं, जो नैतिक आदर्शों के प्रति निष्ठा जगाते हैं। कुछ ऐसे हैं, जो क्रियाशीलता का पाठ पढ़ाते हैं जो लोभ, स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष अन्य प्रवंचकारी मनोवेगों से मुक्ति दिलाते हैं। अनेक लघु कथाएँ भी ऐसी प्रकाशित होती है, जो आत्मिक विकास के लिए तथा नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा के लिए मार्गदर्शन करती है। यही स्थिति पराग व चन्दामामा की है। बच्चों की पाठ्य सामग्री बच्चों की ही भाषा में 'पराग' की विशेषता है।[5]

भाषा शिल्प का विकास– स्वातंत्रयोत्तर पत्र-पत्रिका ने जहाँ सांस्कृतिक अभिरुचि को प्रोत्साहित किया, नवचेतना का विकास किया और सामाजिक जीवन को सुधार परिष्कार और जागृति की राह दिखाई है वहीं, शैल्पिक क्षेत्र में भी उल्लेखनीय योगदान दिया है। पत्रकारिता का अन्तस कलात्मक है और उसका शरीर अपनी सज्जा के लिए कभी-कभी विज्ञान व मुखापेक्षी रहता है। सर्वप्रथम तो समाचार-पत्रों ने बोलचाल व सामान्यजन की भाषा को परिष्कृत जनभाषा का शिल्पायन करने का सफल प्रयत्न किया। आज जिसे अखबारी भाषा कहा जाता है वह इसी की देन है। भाव व्यक्त करने में जनजीवन की भाषा ही उनके लिए सर्वाधिक उपयोगी हो सकती है। बोलचाल के शब्दों का प्रयोग, नित नवीन शब्दों का निर्माण और दिन-प्रतिदिन घटित होने वाली विविध प्रकार की घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में निर्मित नयी शब्दावली का प्रयोग पत्रकारिता के अन्तर्गत प्रयुक्त होने वाली भाषा की अन्यतम विशेषताएँ हैं। भाषा की सरलता को अधिकाधिक प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दीर्घ वाक्यावली के स्थान पर छोटे-छोटे किन्तु आकर्षक वाक्यों का प्रयोग करके

* सहायक प्राध्यापक (वरिष्ठ) एवं विभागाध्यक्ष (भाषा विभाग) एम.बी. खालसा महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

पत्रकारिता ने जिस शैल्पिक क्षमता का विकास कर हिन्दी को सँवारा है उससे भाषा व्यक्ति से और व्यक्ति भाषा से जुड़ गया है अर्थात् स्वातंत्रयोत्तर हिन्दी पत्रकारिता का भाषिक स्वरूप सरल, बोधगम्य और सम्प्रेषण की क्षमता से युक्त है।

वैचारिक क्रांति– स्वतंत्रता के पश्चात् पत्र–पत्रिकाएँ एक आवेग के साथ सामने आने लगी और उनमें छपे हुए समाचार जीवन को एक दूसरी दिशा की ओर ले जाने में सक्षम हुए। स्वातंत्रयोत्तर पत्रकारिता ने एक ओर जहाँ सुप्त मानव चैतन्य को आगे बढ़ाया है वहीं दूसरी ओर अन्धविश्वास कम हुए हैं। नित्य प्रति समाचार–पत्रों में छपने वाली खबरें सड़ी–गली मान्यताओं के प्रति अविश्वास पैदा करती है अपितु विद्रोह की आग भी भड़कती है। स्वातंत्रयोत्तर पत्रकारिता की यात्रा एक क्रान्ति की यात्रा की तरह है जिसमें समाज को न केवल बाहर से बदला गया है अपितु भीतर से भी बदलने का क्रम जारी है। पिछले वर्षों में भारतीय जनमानस नवोन्मेष, नवजागृति और नवचेतना से भर उठा है। इस तरह पत्रकारिता ने सामाजिक मनुष्य को संमार्ग दिखाया है।[6] स्वातंत्रयोत्तर पत्रकारिता ने प्रत्येक मनुष्य के मन में स्वाभिमान, आत्मरक्षा का भाव, अस्तित्व के प्रति चिन्ता और बौद्धिक–क्षमता जैसी भावनाओं को विकसित किया है। पत्रकारिता ने यह काम सीधी और सरल भाषा में कर दिखाया। एक बार के लिए कुछ पुराने और प्रज्ञाशील व्यक्ति भले ही पत्रकारिता की भाषा को अखबारी भाषा कहकर टाल देते हैं, किन्तु यह बात भी भुलाई नहीं जा सकती है कि भारत का आम आदमी यदि कोई भाषा समझ सकता है तो वह समाचार–पत्रों की भाषा ही हो सकती है।

जनजागरण – स्वातंत्रयोत्तर पत्रकारिता ने जहाँ जनजागरण का संदेश दिया है वहीं सुधार और परिष्कार का काम भी किया है। समानता, भातृत्व, स्वतंत्रता और उन्मुक्तता की नींव पर निर्मित मानवता समाज का ढाँचा खड़ा करने और उसे मजबूत बनाने में स्वातंत्रयोत्तर पत्रकारिता ने विशेष योगदान दिया है। ऐसी शायद ही कोई पत्रिका हो जिसमें मानवता, स्वतंत्रता और मानवीय सम्बन्धों को सुदृढ़ और यथार्थ स्थिति किसी न किसी रूप में विश्लेषित न किया जाता हो। विभिन्न विचारों के प्रगतिशील पत्र आज भी मानव जीवन को नई धारा की ओर उन्मुख करने में लगे हुए हैं। वस्तुत: पत्रकारिता ने आज समाज में फैली हुई अनेक बुराइयों के विरुद्ध अपना सशक्त अभियान चलाया है। शिशु हत्या, बाल विवाह, वैधव्य का दुख, दहेज प्रथा, वेश्यावृत्ति और छुआछूत जैसी कुप्रथाओं को दूर करने में हिन्दी पत्रकारिता ने उल्लेखनीय योगदान दिया है।

प्रखर विचारों की पोषक पत्रकारिता ने एक दिव्य चेतना एवं लोकमत के निर्माण में महती भूमिका निभाई है।[7] सभी कुप्रथाओं के कुपरिणामों और त्रासद परिणामों का विवेचन बड़े–छोटे सभी पत्र–पत्रिकाओं ने खूब लिखा है। दैनिक–पत्रों में रविवारीय परिशिष्टों में तो आए दिन दहेज प्रथा, विधवा विवाह आदि कुप्रथाओं पर लेख छपते ही रहते हैं। बड़ी पत्रिकाएँ ही नहीं वरन् बच्चों की पत्रिकाएँ भी कहानी व लेख माध्यम से नवजागृति के संदेश देकर उसे अन्धविश्वासों से छुटकारा दिलाते है। इस तरह स्वातंत्रयोत्तर पत्रकारिता युगीन चेतना की अभिव्यक्ति है, उसमें लोक मानस प्रतिरूपित हुआ है और यही युगधारा स्वातंत्रयोत्तर पत्रिकाओं की प्राणधारा बन गई है।

स्वस्थ मनोरंजन– त्रासद परिवेश और व्यस्त जीवन की प्रश्नाकुल स्थितियों से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य मनोरंजन का सहारा लेता है। सिनेमा, खेलकूद, पारस्परिक गपशप, हल्के मनोरंजन के साधन है, जबकि स्वस्थ मनोरंजन अथवा मनोविनोद का सशक्त माध्यम हास्य–व्यंग्य पत्रकारिता है। स्वातंत्रयोत्तर वर्षों में जिस तेजी से पत्रकारिता का विकास हुआ है उसमें शुद्ध और स्वास्थ मनोरंजन वाली हिन्दी पत्रकारिता की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। विनोद जीवन की आवश्यकता है और हास्य उस आवश्यकता की पूर्ति का एक साधन है। आज जितनी भी पत्रिकाएँ निकलती है, उनमें से अधिकांश ऐसी है जो पूरी तरह भले ही हास्य–व्यंग्य को महत्व न देती हों, किन्तु उनमें ऐसे स्तम्भ अवश्य होते हैं। यह स्तम्भ हास–परिहास, व्यंग्य–विनोद, प्रश्नोत्तर, फुलझड़ी, चुटकूले, कहकहे आदि के रूप देखे जा सकते हैं। धर्मयुग, साप्ताहिक हिन्दुस्तान, कादम्बिनी, इतवारी पत्रिका, मायापुरी, लोटपोट, दीवाना आदि कितनी ही पत्र–पत्रिकाएँ इसका उदाहरण हैं।

अलग–अलग पत्र–पत्रिकाओं में व्यंग्य–विनोद अलग–अलग शीर्षक लिए होते हैं। जैसे–कादम्बिनी में चुटकियाँ, किस्से खोजा फकीर के, नन्दन में चटपट, तेनालीराम, चीटू–मीटू आदि। नवनीत में दो क्षण तो हँस ले, मुक्ता में शाबास, दास्तानें, दफ्तर में लड़कियाँ, ये शिक्षक, जाह्नवी में अब थोड़ा हँस लें, चम्पक में देखों हँस न देना, सारिका में कबिरा खड़ा बाजार में, साप्ताहिक हिन्दुस्तान में ताल–बेताल, धर्मयुग में बैठे–ठाले आदि हास्य–व्यंगय के प्रमुख स्तम्भ है। इसके साथ ही यह भी स्मरणीय रखना चाहिए कि कुछ पत्रिकाएँ तो पूरी तरह हास्य–व्यंग्य विनोद से भरी होती हैं। जैसे–लोटपोट, दीवाना, मधु–मुस्कान आदि।

वैज्ञानिक क्षेत्र– विज्ञान की प्रगति, उद्योग–धंधों की बाढ़ तथा बदलते जीवन मूल्यों ने मनुष्य पर गहरा प्रभाव डाला है।[8] यह एक सामान्य सत्य है कि प्रत्येक व्यक्ति वैज्ञानिक नहीं हो सकता किन्तु वह विज्ञान द्वारा प्रदत्त सुविधाओं द्वारा लाभ उठा सकता है, जो वैज्ञानिक तथ्य आम आदमी के काम आते हैं वे हमें पत्र–पत्रिकाओं में ही मिलेंगे।

हिन्दी समाचार–पत्रों में ज्यादातर रविवारीय संस्करण या मासिक पत्रों में ऐसी वैज्ञानिक सामग्री होती है जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में प्रस्तुत किया है ताकि साधारण मनुष्य की समझ में भी वैज्ञानिकता से भरे जटिल प्रश्नों का समाधान किया जा सके। परन्तु दैनिक पत्रिकाएँ भी इसका अपवाद नहीं है। सर्वप्रथम नवभारत टाइम्स में नियमित वैज्ञानिक स्तम्भ विज्ञान और जीवन शुरू किया और यह स्तम्भ पाठकों को नई–नई जानकारी देता आ रहा है। प्रथम स्पुतनिक जब छोड़ा गया तो सभी समाचार–पत्रों ने इसे प्रमुखता देकर स्थान दिया था, नवभारत टाइम्स ने इससे समबन्धित एक चित्र देकर विज्ञान के प्रति लोगों को जागरुकता पैदा की और उसे समझने में जनसाधारण को कठिनाई भी नहीं हुई। ऐसे स्तम्भ में सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि वैज्ञानिक गोष्ठियाँ, सम्मेलन, विज्ञान विषयक जानकारी हिन्दी में पाठकों को मिलती रही। इसी प्रकार बच्चों की बाल पत्रिकाओं–पराग, नन्दन चम्पक आदि में भी वैज्ञानिक लेख प्रकाशित किये जाते हैं।

अन्त में कहा जा सकता है कि स्वातंत्रयोत्तर पत्रकारिता आज हर क्षेत्र में अपना पदार्पण कर चुकी है चाहे वह क्षेत्र साहित्यिक हो, सांस्कृतिक हो, भाषा शिल्प हो, या विज्ञान हो सभी क्षेत्र में इसका योगदान अभूत है। आज हर देश पत्र–पत्रिकाओं के योगदान के कारण ही जनजागृति के द्वार खोलकर उन्नति की ओर अग्रसर हो रहा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. डॉ. विनोद गोदरे, हिन्दी पत्रकारिता–स्वरूप एवं संदर्भ, पृष्ठ 59
2. डॉ. रामविलास शर्मा, स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य, पृष्ठ 33
3. डॉ. विनोद गोदरे, हिन्दी पत्रकारिता–स्वरूप एवं संदर्भ, पृष्ठ 63
4. कृष्णबिहारी मिश्र, पत्रकारिता–इतिहास और प्रश्न, पृष्ठ 151
5. डॉ. विनोद गोदरे, हिन्दी पत्रकारिता–स्वरूप एवं संदर्भ, पृष्ठ 69
6. डॉ. टी.डी.एस. आलोक, सांस्कृतिक पत्रकारिता, पृष्ठ 1
7. डॉ. टी.डी.एस. आलोक, सांस्कृतिक पत्रकारिता, पृष्ठ 1
8. डॉ. विनोद गोदरे, हिन्दी पत्रकारिता–स्वरूप एवं संदर्भ, पृष्ठ 71

लोक संस्कृति एक चिंतन

डॉ. प्रेमलता तिवारी *

प्रस्तावना – ब्रम्ह की भाँति अवर्णनिय है संस्कृत जिसके साथ जुड़ी है लोक याने अनेक तत्वो का बोध करना वाली अन्तमुखी प्रवृतियाँ जो ग्रामीण जन मानस मे रच बस गयी है । लोक यह एक सामुहिक पहचान है, दीन हीन शोषित दलित, जंगली, जातियां जैसे कोल, संथाल, भील, नाग, आदि की मिली जुली संस्कृति मे यह आज भी पूर्ण रूप से विद्यमान है । वेशभूषा खानदान, पहरावा, ओढ़वा, चाल–व्यवहार नृत्य, गीत, कला, भाषा के विभिन्न स्वरूपो को एक माला मे जोड़ पहचान दिलाने वाली संस्कृति ही लोक संस्कृति है जो कभी भी सभ्य समाज की मोहताज नही रही है । किसी क्षेत्र विशेष मे निवास करने वाले लोगो के पारस्परिक धर्म, त्यौहार, रीति , रिवाज, पर्व आदि को लोक संस्कृति का नाम दिया जाता है । प्रो. रेडफिल्ड ने सर्वप्रथम लोक संस्कृति को नगरीय जीवन से प्रतिकल विशिष्ट संस्कृति के रूप मे उल्लेखित किया था । लोक मानस की मांगलिक भावनाओ को जीवन्त रखती है यहा संस्कृति तभी तो हम दुकान बन्द करन नही कहकर दुकान मंगल करना कहते है दीपक बुझाना कभी नही कहा जाता क्योकि यह संस्कृति सत्य विश्वास अनुभव और अनुभूतियों के घुमावो से गुजरती हुई पर्दो के माध्यम से आनन्द के द्वार खोलती है जिसमे बिछुड़ने का कोई दर्द नही है , वह जिसमे जीवन की तलाष पूरी होती है यह संम्पूर्ण मानवीय असिमता का प्रतिक है जो ज्ञान प्रज्ञा , सत्य , विश्वास और आस्था को समेट सदेव निरंतर आगे बढ़ने मे विश्वास रखती है –

विकिपिडिया – भारतीय लोक – संस्कृति की आत्मा भारतीय साधारण जनता है जो नगरो से दुर गांव, वनपर्वतो मे निवास करती है ।

श्रद्धा भक्ति से जुड़ी है यह संस्कृति जहाँ भय, तर्क, और अविश्वास के लिये कोई जगह नही है । समाज की आकांक्षाओ इसी की गोद मे पलती है सर्वे भवन्तु सुखिन को साकार करती है लोक संस्कृति जो ईश्वर अंश जीव अविनाशी को मानकर कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करि तो तस फल चाखा को जीवन्त रखती है । इसमे लोक की आत्मा का निवाद है गीत, नृत्य, संगीत, चित्र के माध्यम से हजारो हजारो वर्षो से इतिहास को जीवन्त रखने वाली संस्कृति जनमान्य का मर्म है ।

एतिहासिक परंपरा से चली आ रही यह संस्कृति शनै: शनै: होने वाले परिवर्तन को स्वीकार करती है क्योकि अतिरिक्त पारिवारिक परिवर्तन के दौर मे जनमानस के जीवन यापन के तरिको को प्रभावित किया है यह बदलाव लोक संस्कृति को जीवन्त रखने के लिए आगे बड़ने का कारण बन सकता है गहराई से चितंन करे तो समाज के लिये इसकी उपयोगिता अवर्णनीय है क्योकि लोक संस्कृति क विभिन्न आयाम जैसे जैसे गतिशील होगें समाज भी उतना ही गतिशील होकर संगठित होगा । लोक संस्कृति हम की भावना को पुष्ट करती है , आधुनिक विघटित होते समाज को एकता का पाठ पढ़ाती है –

'राम रह रहीम रह
जूण न सुधार जो।
राम खुदा एक है ।
किण न ई पुकार जो ।
हिन्दु मुसलमान सिख ।
दश मिल संवारजो ।'
कणाणाच नाम कण काट जो बंधारजो

लोक संस्कृति के विभिन्न आयाम जैसे साहित्य, संगीत, भाषा , चित्रकला, धर्म और कला हर मनुष्य के जीवन से कही न कही जुड़े है जो सामाजिक विरासत के रूप मे हस्तांतरित होकर संस्कृति को उर्जावान बनाते हे जीवन मुल्यो के निरंतर होते छल मे लोक संस्कृति ही वह माध्यम है जो समाज के नैतिक मुल्यो के पतन को रोक पायेगा । भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रो मे रहने वाले जनमानस मे आज भी यह संस्कृति सम्पन्न एवं परिपूर्ण रूप से रची बसी है ।

बदलती वैश्विक परिस्थितियों ने इसे अपने प्रभाव से समेटना शुरू कर दिया है । लोक गीत, लोक कथा, आज धीरे धीरे लुप्त होने की कगार पर है भारतीय जनमानस पुरातन सांस्कृतिक मुल्यो के साथ जीने का आदि है पर सांस्कृति टकराव और सांस्कृतिक विघटन जनमानस की एकता को खंडित कर रही है । पाश्चात्य संस्कृतिके बढ़ते प्रभाव ने आधुनिकता के नाम पर लोक संस्कृति को परे कर दिया है । एतिहासिक विशेषताओं को सहेज कर पारंपरिक एवं सुगठित संस्कृति व पर्यटन को उत्कर्ष प्रदान करने वाली लोक संस्कृति आधुनिक भौतिकता के प्रभाव के कारण परिवर्तन के दौर से गुजर रही है सांस्कृतिक मुल्य और आधुनिक मुल्यो के बिच युवा भटक सा रहा है । कुकुरमुत्ता की भाँति आये टी.वी, चैनलो मे लोक संस्कृति के लिये कही जगह नही है । बाजारवाद के दौर मे अखबार भी लोक संस्कृति को भूल से गये है । विज्ञापन बाजी की बढ़ती प्रतियोगिता मे लोक संस्कृति खड़ी नही होगी क्योकि लोक संस्कृति न तो खरीदी जा सकती है और न ही बेची जा सकती है । जीवन शैली और संस्कारो की शीत– युद्ध मे सामुहिकता और सहयोग कुचले जा रहे हे । भावो की सहज अभिव्यक्ति के रूप मे पहचान बनाने वाले भगोरिया नृत्य, संझा, राई , दिवाली , पोला, दिलवारिया जैसे पर्व अपनी पहचान खो रहे है । दिखावे से दूर श्रम साध्य वाली प्रकृति की निकटता को महसुस कराने मे सक्षम यह संस्कृति उपक्षित हो रही है । मुल्य पर भावनाओ की अभिव्यक्ति का आधार बन जीवन को संवारने वाली संस्कृति की मौलिकता आज की अवश्यक्ता है –

'करनी की गती और है , कथनी की और ।
बिन करनी कर्थे बकबादी बौरे ।।
करनी बिन कथनी इसी , ज्यो संखि बिन रजनी।
बिन अस्तर ज्यो सुरमा, भुषन बिन सजनी ।।'

जनमानस को आज के परिर्वतनशील दौर मे उर्जा ताजगी माधुर्य और पवित्रता की आवश्यक्ता है तो लोक संस्कृतिमे प्राण फूंके होगें । भौतिक

*प्राध्यापक,(हिन्दी) शासकीय महाविद्यालय, बड़वाह (म.प्र.) भारत

वादी संस्कृति के विनाशक परिणाम को जानकर लोक संस्कृति से जुड़ना होगा क्योकि बौद्धिक ज्ञान और जन–ज्ञान के बीच चौड़ी होती खाई मानवता के लिये भविष्य में धातक सिद्ध होगी। भारत के अंचल अंचल में लोक संस्कृति लोकनृत्य, लोकगीत और लोक साहित्य बिखरा हुआ पड़ा है। चार कोस में बदले पानी और आठ कोस में बदले वाणी सांस्कृतिक विविधता की ज्ञान परंपरा लोक संस्कृति के इतिहास के पन्नों में छुपी हुई है लेकिन विलुप्त होती सांस्कृतिक चेतना नई पीढ़ी के भावनातमक विकास कि लिये घातक है , सांस्कृतिक संरक्षण का जारी मुखौटा भावना ज्ञान और अध्यात्म का शोषण करने में सफल हुआ है बिखरी – बिखरी समृध्द लोक संस्कृति और सुधा से पीड़ित लोक कलाकार का वास्तव में त्रास दायी है क्योकि भारतीय संसकृति के इतिहास कों पर्व, चित्र, कला, गीत, संगीत, नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत कर जिवंत रखने वाले से कलाकार ही तो हे जिन्हें फिल्मी कलाकारों ने उपेक्षित कर दिया है। धार्मिक और राष्ट्रीय आदर्श के प्रतिक के रूप में पहचान बनाने वाली यह संस्कृति भूमंडलीय आर्थिकवाद का शिकार बन गयी है । यह संस्कृति भूमण्डलीय आर्थिवाद का शिकार बन गयी है।

संवेदनाशून्य होती जनता की जटिलता का दुर करने मे सक्षम यह संस्कृति पुन: स्थापित होगी तो समकालीन सामाजिक परिक्षेत्र मे हजारी युवा पीढ़ी अवश्य प्रभावित होगी उसकी अपरिमय संवेदनशीलता और कल्पना शक्ति को नई सोच मिलेगी अनुभवो की अुल्य धरोहर उसके सर्वागिण विकास मे सहयक होगी इसलिये राज्य और केन्द्र सरकार को समाजिक संस्थाओ और जनमानस के माध्यम से प्रोत्साहित कर युवा पीढ़ी को मुल स्वरूपमे हस्तांतरित करने के सफल प्रयास किये जाने चाहिये। लोक जीवन शिवाय स्वरूप ही भौतिकता स्वार्थ, आतंक, हिंसा, सांप्रदायिक्ता को खत्म कर सकेगा अशर्ते लोक संस्कृति को पूर्ण सुरक्षित कर विकसित दौर के परिर्वतन को स्वीकार कर उसके विकास से सर्वागिण प्रयास किये जये।

अपसंस्कृति न हमारी अनुभूतियों को ग्रास लिया है पर हमे यह नही भूलना चाहिये कि सिर उंचा कर आकाश को छूना श्रेष्ठतर है पर पैर तो पृथ्वी पर ही जमे होना चाहिए। क्योकि पृथ्वी की पहचान ही लोक संस्कृति से है। मनुष्य की वैयक्तिकता को सामाजिकता में बदलने वाली यह संस्कृति अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है लेकिन हम अपसंस्कृति के वारिस बन गये है। स्वार्थी अहंकारी और शोदक बन हम मानवीय चेतना से परिपूर्ण संस्कृति का तिरस्कार कर रहे है , सच है कि हम स्वयं विध्वंस के जिम्मेदार है यदि नहीं तो अगली पीढ़ी के सर्वागीण विकास के लिये दर्द और संघर्ष में संबल देने वाली लोक संस्कृति को पुष्ट करना ही होगा कुछ इन पंक्तियों के साथ –

Though the crushed jewels drop and gade
The artists labour wil not cease
And of the rains shall be made
Some get more lovely masterpiece
हालाकि कुचले गए रत्न गिरकर मलिन हुए
पर कलाकार का श्रम नहीं रूकेगा
भग्न अवशेसों से ही गढ़ ली जायेगी
कोई नायाब कृति फिर भी.....

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. लोक संस्कृति wiki pidia.com
2. पाखी अक्टूंबर 2015
3. राजधानी लोकगीत.com
4. अहा ! जिंदगी दिसंबर।

****

प्रसाद और उनकी बिम्ब योजना

डॉ. शबनम खान *

प्रस्तावना – काव्य अमूर्त और अव्यक्त अनुभूतियों को मूर्त रुप देकर संप्रेषित करने का प्रयास करता है। अत: 'काव्य में अर्थग्रहण मात्र से काम नहीं चल सकता, बिम्बग्रहण अपेक्षित होता है।'[1] प्रत्येक कवि का व्यक्तित्व उसके कृतित्व में प्रतिफलित होता है और काव्य बिम्बों में अभिव्यक्ति पाता है। कवि के बिम्बों में ही उसका स्वभाव, उसकी रुचि, जीवन के आरंभ से उसके मन पर पड़े हुए संस्कार ज्ञात और अज्ञात रुप में अभिव्यक्ति का मार्ग खोजते है। प्रसाद के काव्य–बिम्बों में भी उनके व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति हुई है।

प्रसाद की जिन पारिवारिक परिस्थितियों एवं घटनाओं ने उनके बिम्बों को प्रभावित किया, उनमें से उनका वैभवपूर्ण पारिवारिक वातावरण, वंशानुगत शैवसंस्कार, अल्पायु में ही क्रमश: पिता, माता और भाई की मृत्यु, पुन: एक–एक कर दो पत्नियों का निधन, ग्यारह वर्ष की अवस्था में अपनी माता के साथ धाराक्षेत्र, ओंकारेश्वर, पुष्कर और उज्जैन आदि विभिन्न स्थानों की यात्रा तथा सुगंध व सूँघनी का पैतृक व्यवसाय आदि प्रमुख है। परिस्थितियों एवं घटनाओं ने प्रसाद के व्यक्तित्व का निर्माण किया और वह व्यक्तित्व उनके बिम्बों में प्रतिबिम्बित हुआ। वैभवपूर्ण पारिवारिक वातावरण के प्रभाव से प्रसाद के व्यक्तित्व में एक आभिजात्य–पूर्ण गरिमा आ गई थी। उनका यह अभिजात्य उनके बिम्बों में भी प्रतिफलित हुआ, जो उन बिम्बों को अन्य कवियों के बिम्बों से कुछ अलग कर देता है।

शोध पत्र – प्रसाद ने अपने जीवन में एक ओर तो अनेक आघात सहे थे जिनके कारण उनको दु:ख की व्यापकता को स्वीकार करना पड़ा और दूसरी ओर उनको वंशानुक्रम से आनंदवादी शैव दर्शन के संस्कार मिले थे, जिसके कारण वे आनंद को नित्य मानते थे। उनके ये दोनों ही विश्वास उनके बिम्बों में व्यक्त हुए हैं। 'आँसू' में प्रसाद जी लिखते हैं –

वेदना विकल फिर आई, मेरी चौदहों भुवन में,
सुख कहीं न दिया दिखाई, विश्राम कहाँ जीवन में।[2]

इसमें ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रसाद जी वेदना को ही शाशवत मान रहे हो, किन्तु वे निराश नहीं हैं –

हैं पड़ी हुई मुँह ढ़क कर, मन की जितनी पीड़ाएँ,
वे हँसने लगे, सुमन–सी, करती कोमल क्रीड़ाएँ।[3]

'प्रसादजी आदिम आर्यों की तरह सौन्दर्य पूजक हैं और उससे शक्ति, आनंद व उल्लास ग्रहण करते हैं।'[4] कामायनी के 'लज्जा सर्ग' में प्रसाद जी ने नारी के सहज सौन्दर्य के स्वरुप को कुछ बिम्बों की सहायता से अंकित किया है, जिनमें उसका शक्तिदायी और आनंददायी रुप प्रकट हुआ है –

नयनों की नीलम की घाटी, जिस रसघन से छा जाती हो,
वह कौंध कि जिससे अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो।[5]

नीलम की घाटी में रसघन की इस शीतलदायी कौंध के बिम्ब में सौन्दर्य का आनंदमय रुप प्रस्फुटित हुआ है। एक अन्य बिम्ब में उसका शक्तिदायी रुप भी है–

अम्बर–चुम्बी हिम श्रृंगों से कलरव कोलाहल साथ लिये,
विद्युत की प्राणमयी धारा बहती जिसमें उन्मदा लिये।[6]

किन्तु प्रसाद जी बाह्य सौन्दर्य की अपेक्षा आंतरिक सौन्दर्य को अधिक महत्व देते थे। अनिन्द्य सुन्दरी कमला के बाह्य सौन्दर्य की कारुणिक परिणिति से यह बात भलीभांति सिद्ध हो जाती है। इसी को प्रसाद जी के बिम्बों से भी समझा जा सकता है –

ढुलक रही है हिम–बिन्दु–सी,
सत्ता सौन्दर्य के चपल आवरण की,
हँसती है वासना की छलना पिशाची–सी,
छिपकर चारों ओर व्रीड़ा की उँगलियाँ
करती संकेत है व्यंग्य उपहास में।[7]

शास्त्रीय संगीत में प्रसाद जी की विशेष रुचि रही है। वे षिवरात्रि आदि उत्सवों पर शास्त्रीय संगीत का आयोजन किया करते थे। उनकी इस रुचि का ज्ञान उनके बिम्बों से हो जाता है। उन्होंने भारतीय संगीत की विभिन्न राग–रागिनियों तथा अन्य पारिभाषिक शब्दों के भी सुन्दर बिम्ब अंकित किये है। 'तू भी अब तक सोई है आली आँखों में भरे विहाग री।'[8] 'मुखरित था कलरव, गीतों में स्वर लय का होता अभिसार'[9] में क्रमश: विहाग और स्वर–लय का विम्बांकन हुआ है। उन्होंने वीणा, मृदंग, नुपूर, दुंदुभि, तूर्य, वंशी आदि भारतीय वाद्यों की सहायता से भी बिम्बों की सृष्टि की है जो उनके संगीत–प्रेम का बोध कराते है। चित्र कला में भी प्रसाद जी की रुचि थी, यह बात उनके बिम्बों से प्रमाणित होती है। उनके समय में चित्रकला के (पुनर्जागरण काल) के वाश पद्धति के चित्रों का अधिक प्रचलन था, जिनमें छायावादी कविताओं के समान वातावरण की सृष्टि प्राय: की जाती थी।

'नारी जीवन का चित्र यही, क्या विकल रंग भर देती हो,
अस्फुट रेखा की सीमा में आकार कला को देती हो।'[10]

इसमें चित्रण की पद्धति का ज्ञान भी प्रकट होता है। प्रसाद जी ने चाहे स्वयं चित्रकारी न की हो परन्तु उनको चित्रकारी के संबंध में जानकारी थी और रुचि भी। उनके समय में रंगों को पीस कर कपड़े में छानकर तैयार किया जाता था, उन्होंने इस क्रिया का बिम्बांकन प्रकृति के माध्यम से किया है –

'इस अवकाश पटी पर कितने चित्र बिगड़ते बनते है,
उनमें कितने रंग भरे जो सुरधनु–पट से छनते है।'[11]

प्रसाद जी की गन्ध–चेतना अत्यंत सूक्ष्म थी। उनके गंध–बिम्बों से उनकी इस विशेषता का समर्थन हो जाता है। उन्होंने गन्ध के एक–एक परमाणु के समन्वय में अपनी इस सूक्ष्म चेतना का परिचय दिया है –

कुसुम कानन अंचल में मन्द पवन प्रेरित सौरभ साकार,
रचित परमाणु पराग शरीर खड़ा हो ले मधु का आधार।'[12]

प्रसाद जी के पुत्र रत्नशंकर जी ने 'प्रसाद जी की दिनचर्या' नामक लेख में इस बात का उल्लेख किया है कि वे गन्ध सम्मिश्रण के कार्य में कितने पटु थे और

* प्राध्यापक (हिन्दी) माता जीजाबाई शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मोती तबेला, इन्दौर (म.प्र.) भारत

बहुमूल्य यन्त्रों की 'लेबोरेटरी' का काम गन्ध तन्मात्राओं से निकाल लेते थे।'[13] प्रसाद जी ने जहाँ गन्ध-बिम्बों का चित्रण किया है वहाँ गन्ध की मात्रा का भी ध्यान रखा है। कमला के शरीर की भीनी गन्ध का यह बिम्ब देखिए -

'शतशत दलों की,
मुद्रित मधुर गन्ध भीनी-भीगी रोम में
बहाती लावण्य धारा।'[14]

प्रसादजी के वर्ण-बिम्बों में नीले, सुनहरी और पिंग वर्णों की प्रधानता है। प्रसाद जी ने जहाँ भी वस्त्रों की कल्पना की है, वहाँ उनको प्राय: नीले रंग में देखा है। स्वर्णिम और पिंग वर्ण उन्होंने प्राय: प्रकृति में देखे है। नीला रंग शान्त और अन्तर्मुखी स्वभाव का प्रतीक होता है और स्वर्णिम रंग वैभव-विलास-प्रियता का। प्रसाद जी के व्यक्तित्व में इन दोनों का अद्‌भुत समन्वय था, यह बात उनके बिम्बों से प्रकट होती है। एक ओर तो उनका जन्म वैभव सम्पन्न परिवार में हुआ तो दूसरी ओर जीवन को विषम परिस्थितियों और आघातों ने उन्हें अन्तर्मुखी बना दिया। इस प्रकार का विरोध प्रसाद जी के संपूर्ण जीवन में व्याप्त था। एक ओर काव्य रचना तथा दूसरी ओर व्यवसाय-प्रसाद जी ने दोनों दायित्वों का निर्वाह समान रुप से किया। रायकृष्णदास जी के शब्दों में 'उन्होंने दोनों ही रकाबों पर बड़े ठाट और दृढ़ता से पांव जमाये।'[15]

प्रसाद जी के मन में राष्ट्रीयता की प्रबल भावना थी, जिसको उनके काव्य बिम्बों में अभिव्यक्ति मिली। इस संबंध में डॉ. ओमप्रकाश का मत है कि किसी भी कवि का राष्ट्रप्रेम इस बात से जाना जा सकता है कि उसकी 'विचारधारा राष्ट्र की शाश्वत विचारधारा का कितना उद्धाटन करती है और राष्ट्र के गौरव चिन्ह-देश की प्राकृतिक स्थिति, नदी और पर्वत, ऋतु और जलवायु-राष्ट्र के उत्सव और त्यौहार व्यवस्था तथा प्रथाएँ कवि के हृदय को प्रभावित कर पाई है या नहीं, उसने राष्ट्र के इतिहास तथा दर्शन, साहित्य एवं जीवन के प्रति श्रद्धा दिखाई है या नहीं।'[16] प्रसाद जी के बिम्बों में राष्ट्रीय विचारधारा का उद्धाटन हुआ है। भारत के नदी-पर्वत, ऋतु-जलवायु आदि को उनके काव्य में विषद अभिव्यक्ति मिली है -

'हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयंप्रभा समुज्जवला स्वतंत्रता पुकारती,

अमर्त्य वीरपुत्र हो, दृढ़प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पन्थ है, बढ़े चलो, बढ़े चलो।'[17]

भारत के स्वर्णिम अतीत के प्रति प्रसाद जी के मन में अत्यधिक रागात्मक आकर्षण था। प्रसाद जी ने इतिहास के अनेक पृष्ठों को अपनी कविताओं के रुप में बिम्बांकित किया है।

निष्कर्ष - यद्यपि किसी भी कवि का समग्र और सही विश्लेषण अत्यंत कठिन है और वह भी बिम्बों के माध्यम से फिर भी हम यह पाते है कि प्रसाद के काव्य बिम्बों में उनके व्यक्तित्व के अनेक पक्षों की अभिव्यक्ति हुई है। जीवन के विविध दायित्वों का एक साथ निर्वाह, सौन्दर्य और प्रणय के प्रति आकर्षण, उत्सवप्रियता, शास्त्रीय संगीत और चित्रकला में रुचि, गंधवर्ण आदि की सूक्ष्म चेतना, राष्ट्रप्रेम और स्वर्णिम अतीत के प्रति आकर्षण आदि उनके व्यक्तित्व की अनेक विशेषताओं का बोध उनके काव्य बिम्बों से हो जाता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. रामचंद्र शुक्ल-'चिंतामणि' भाग-1, पृष्ठ 145
2. 'आँसू'-पृ. 53
3. 'आँसू'-पृ. 73
4. डॉ. रामेश्वरलाल खंडेलवाल-जयशंकर प्रसाद वस्तु और कला', पृ. 286
5. कामायनी (लज्जा सर्ग)-पृष्ठ 82
6. कामायनी (लज्जा सर्ग)-पृष्ठ 81
7. लहर (प्रलय की छाया)-पृष्ठ 80
8. लहर-पृष्ठ 19
9. कामायनी (चिन्ता सर्ग)-पृष्ठ 16
10. कामायनी (लज्जा सर्ग)-पृष्ठ 86
11. कामायनी (स्वप्न)-पृष्ठ 145
12. कामायनी (श्रद्धा सर्ग)-पृष्ठ 44
13. निर्मल तलवार-प्रसाद पृष्ठ 4
14. लहर-पृष्ठ 62
15. रामकृष्णदास-'प्रसाद का जीवन-दर्शन कला और कृतित्व'-पृष्ठ 12
16. डॉ. ओमप्रकाश-'आलोचना की ओर'-पृष्ठ 110
17. चन्द्रगुप्त-अंक 4, पृष्ठ 177

****

निराला - एक प्रगतिशील कवि

सुमन मरावी *

प्रस्तावना - 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्ष में ऐसे महामानव का जन्म हुआ, जिसने समाज को नई दिशा, नया मार्ग और नई सोच दी। उस व्यक्ति की सोच ने पूरे राष्ट्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन ला दिया, वह महापुरूष कोई और नहीं बल्कि निराला थे। इनका सम्पूर्ण जीवन दु:ख और संघर्ष में बीता बाल्यकाल से लेकर जीवन के अंतिम क्षणों तक वे सतत् संघर्ष करते रहे, उस सामाजिक व्यवस्था से जिसने उन्हें संघर्ष करने के लिए विवश किया। साथ ही समाज में फैली उन रूढ़ियों का जो पुरातनकाल से चली आ रही थी, उनका घोर विरोध किया तथा समाज को उजाले की ओर ले जाने का सफलतम प्रयास किया।

निराला जी का साहित्य में प्रवेश ऐसे समय में हुआ, जब हिन्दी कविता खुद को स्थापित करने के लिए मजबूत कंधों का सहारा ढूँढ़ रही थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनके कुछ सहयोगी हिन्दी की अलख जगाने का प्रयास कर रहे थे। इसके पूर्व का साहित्य ब्रज की रास में ऐसा लीन था कि कविगण उस भाषा का त्याग कर हिन्दी को अपनाने में डर रहे थे, लेकिन द्विवेदी जी के अथक प्रयासों से श्रृंगारिकता का स्थान राष्ट्रीयता और ब्रज का स्थान हिन्दी लेने लगी। ऐसे ही समय में हिन्दी कविता का राजकुमार निराला 'जूही की कली' के साथ साहित्य में प्रवेश करता है और हिन्दी कविता के व्योम में अविराम चार दशक तक छाया रहता है। इनका साहित्य जड़ की जगह चेतन और रूढ़ि की जगह प्रगति का प्रचारक बना।

वैसे तो निराला जी का सम्पूर्ण साहित्य पुरातन से नवीन में प्रवेश की सूचना देता है, लेकिन कुछ कविताएँ ऐसी हैं जिनमें कवि की प्रगतिशील चेतना उन्मुख हुई है। उन्होंने आदिकाल से चले आ रहे वर्ण्य-विषय को नया दृष्टिकोण तथा नवीन विषयों को अपनाकर प्रगतिशील सोच का परिचय दिया। निराला के पूर्ववर्ती एवं समकालीन कवि जहाँ भारत का गान, राजप्रासाद का वैभव और स्त्रियों के नख-शिख सौन्दर्य तक सीमित थे, वहीं इन्होंने यथार्थ के धरातल में प्रवेश करके आम मानव की दु:ख गाथा, सामाजिक रूढ़ि, अत्याचार, आतंक और भ्रष्टाचार जैसे अनेक विषयों को अपनाया एवं नये कवियों के लिए लेखन की नई पृष्ठभूमि तैयार की। निराला द्वारा तैयार नींव में केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, मुक्तिबोध, धूमिल आदि कवियों ने प्रगतिशील कविता की इमारत खड़ी की।

निराला का साहित्य में प्रवेश क्रान्तिकारी के रूप में हुआ उनके आगमन से हिन्दी कविता में एक नये युग का सूत्रपात हुआ। सन् 1916 में प्रकाशित प्रथम कविता 'जूही की कली' ने आदिकाल से चली आ रही तुकांत कविता की परिपाटी को तोड़कर मुक्त छंद का आगाज किया -

'विजन वन वल्लरी पर
सोती थी सुहाग भरी
स्नेह स्वप्न मग्न
अमल कोमल तनु तरुणी
जूही की कली'

कवि का आशय है कि व्यक्ति के अन्तर्मन में उठने वाले उद्‌गारों को व्यक्त करने के लिए तुक की नहीं बल्कि भाव की आवश्यकता होती है। इस कविता के प्रकाशन ने जहाँ हिन्दी कविता में भूचाल ला दिया, वही दूसरी तरफ लय और ताल में जकड़ी कविता को मुक्त कर निराला अपने नाम के अनुसार हिन्दी आभा मंडल पर सूर्य की भाँति दीप्त हुये। साथ ही उनकी ये पंक्तियाँ 'कुछ मुझे तोड़ते गत विचार/पर पूर्ण रूप प्राचीर भार/ढोते मैं हूँ अक्षम' ने यह पूर्णत: सिद्ध कर दिया कि वो पुरानी और जड़ परम्पराओं के साथ समझौता नहीं कर सकते चाहे इसके लिए उन्हें कितना ही विरोध क्यों न झेलना पड़े। निराला यही नहीं रूके, अनवरत रूप से आगे बढ़ते रहे और उन सभी बंधनों को तोड़ दिया, जिसमें वे जकड़न महसूस करते थे। नायिका भेद, राज प्रशंसा को छोड़ विधवा, भिखारी, मजदूर जो आम व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें काव्य में स्थान दिया और उनके जीवन संघर्ष को मुखरित किया-

'वह आता
दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता,
पेट-पीठ दोनों मिलकर है एक,
चल रहा लकुटिया टेक।'

यह कविता एक भिखारी मात्र को केन्द्रित कर के नहीं लिखी गई, बल्कि उन सभी असहाय, गरीब, किसान, मजदूर वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, जो इस प्रकार का जीवन जीने के लिए मजबूर है। इस कविता के माध्यम से कवि हमारे समक्ष एक प्रश्न छोड़ जाते हैं कि आखिर क्यों मेहनतकश दो रोटी के लिए दूसरों का मोहताज है? सर्वहारा वर्ग का पक्ष लेते हुए 'कुकुरमुत्ता' काव्य संग्रह के माध्यम से निराला पूँजीपतियों और शोषकों को भी फटकार लगाते हुए कहते हैं -

'अबे, सुन बे गुलाब,
भूल मत जो पाई खुश्बू रंगो आब
खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट
डाल पर इतराता है कैपीटलिस्ट'

यहाँ मिलमालिकों और अमीरों पर व्यंग्यात्मक प्रहार किया है कि आज इनके पास जो शान-शौकत, रूपया-पैसा, ख्याति है, वह मजदूर वर्ग के पसीने की कमाई है। इसके बदले में उन्हें मिला भी तो क्या, सिर्फ शोषण और अत्याचार। निराला जी ने सर्वहारा वर्ग को मुकम्मल स्थान दिलाने हेतु उनका पक्ष लिया और उनके हक के लिये आवाज उठाई।

निराला ने नारी जाति के प्रति आदिकाल से चली आ रही कंचन-कामिनी छवि को तोड़कर उसके मजबूत पक्ष को प्रस्तुत किया। रीतिकालीन कवि में जहाँ नारी के सौन्दर्य और नख-शिख वर्णन से आगे नहीं बढ़ पाए तथा भोग-विलास की वस्तु बनाकर सीमित कर दिया था। वहीं आधुनिक काल आते-आते नारी के प्रति दृष्टिकोण बदला, लेकिन उसे अभी भी दीन-हीन ही समझा जाता था। तभी तो राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त जैसे सशक्त

* शोधार्थी, अवधेश प्रतापसिंह विश्वविद्यालय, रीवा, (म.प्र.) भारत

कवि ने 'अबला-जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आँचल में है दूध और आँखों में पानी' के रूप में स्त्री जाति को देखा। छायावाद के आधार स्तंभ कहे जाने वाले कवि प्रसाद जी नारी के प्रति श्रद्धा और सहानुभूति मात्र ही प्रदर्शित कर सके और 'नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग-पग-तल में' ही कह सके। वहीं निराला ने अपने पूर्ववर्ती कवियों की मान्यताओं और धारणाओं का खण्ड़न करते हुए नारी के उदात्त एवं यथार्थ रूप को प्रस्तुत किया। 'वह तोड़ती पत्थर' जैसी कविताओं में नारी की कंचन-कामिनी छवि का मर्दन करते हुए उसके संघर्षशील एवं यथार्थ स्वरूप को प्रस्तुत किया। यह उन लोगों के लिए करारा जवाब था जो नारी को भोग-विलास और आनंद की वस्तु मानते थे। नारी के सर्वश्रेष्ठ रूप के दर्शन कवि द्वारा 100 बंध के खण्ड़काव्य 'तुलसीदास' में दिखाई देते हैं। इस रचना के नायक भले ही भारतीय दर्शन के पुरोधा, विश्वकवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, लेकिन निराला के अनुसार उन्हें विश्वकवि के स्थान तक पहुँचाने का श्रेय उनकी पत्नी रत्नावली को ही है। तुलसीदास जी जब पत्नी के प्रेम में आसक्त होकर उनके नैहर पहुँचते हैं, तो रत्नावली उन्हें लक्ष्य करती हुई कहती हैं -

'धिक्! आये तुम यो अनाहूत
धो दिया श्रेष्ठ कुल-धर्म धूत
राम के नहीं काम के सुत कहलाए!
हो बिके जहाँ तुम बिना दाम,
वह नहीं और कुछ हाड़-चाम'

निराला ने स्त्री के त्याग और बलिदान को तो दिखलाया साथ ही भारतीय ललना किस प्रकार अपने सुख का त्याग कर राष्ट्रहित के लिए पति को कर्म मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, यह बतलाकर उसे मार्गदर्शिका और पथप्रदर्शिका के श्रेष्ठ स्थान में प्रतिष्ठित किया हैं। निराला नारी को मनभावन, दीन-हीन और आनंद प्रदायक नहीं बल्कि उसे शक्ति का रूप मानते हैं। तभी तो चतुर्दिक विजेता श्रीराम जब हताश होते हैं तो इसी शक्तिरूपा नारी का आह्वान कर विजयश्री का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।

निराला के अन्दर क्रान्ति की ज्वाला और परिवर्तन की एक सी लहर विद्यमान थी कि वे सम्पूर्ण समाज में फैली पुरातन परम्पराओं, रूढ़ियों को इस मशाल द्वारा जला देना चाहते थे। उन्होंने शिल्पगत और नारी के प्रति संकुचित सोच को ही नहीं, वरन् मिथकों का प्रयोग भी नवीन ढंग से कर प्रगतिशील होने के संकेत दिये। 'राम की शक्तिपूजा' में राम पौराणिक पात्र के रूप में शक्ति सम्पन्न नहीं बल्कि जीवन से संघर्ष करता हुआ, असत्य से लड़ता हुआ एक सामान्य मानव हैं। राम जब लड़ते-लड़ते इस समाज में फैले रावण रूपी आतंक और अत्याचार से खुद को हारता हुआ महसूस करते हैं, तो उनका हृदय चित्कार करते हुए कह उठता है -

'धिक् जीवन जो पाता ही आया है विरोध,
धिक् साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध।।'

निराला ने राम के साथ-साथ अपने जीवन-संघर्ष को इन पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त किया है। इनके जीवन में संघर्ष बाल्यावस्था से ही प्रारम्भ हो गया था। अल्पायु में माता की मृत्यु, उसके बाद पत्नी का भी छोड़कर चले जाना तथा क्रमश: पिता जी एवं चाचा जी का भी स्वर्गवास। इक्कीस वर्ष की आयु में चार बच्चों का बोझ, जीवन-यापन के लिये काम की तलाश में इधर-उधर भटकना किसी भी व्यक्ति में आक्रोश भर सकता है। कवि का यही आक्रोश उनकी कविताओं, कहानियों और उपन्यासों में दिखाई देता है।

निराला में परिवर्तन की चाह इतनी ज्यादा थी कि जिस विषय को काव्य में स्थान प्रदान किया, उसे नये नजरिये से देखा। समाज में भयंकर बीमारी की तरह फैली रूढ़ परम्परायें, जो राष्ट्र और समाज के उन्नति का मार्ग अवरूद्ध कर रही थी, उन्हें जड़ से मिटाना चाहते थे। इसके लिये उन्होंने प्रकृति का भी सहारा लिया। 'बादल-राग' जैसी प्रकृति-परक कविताओं के माध्यम से कवि ने क्रान्ति लाने का प्रयास किया। यह कविता प्रकृति मूलक जरूर है, लेकिन किसान की दुरावस्था का वर्णन और उस अवस्था से मुक्ति सिर्फ 'विप्लव के वीर' ही ला सकते हैं, ऐसा कवि का मानना है। फिर भी यह कहना असंगत न होगा कि प्राकृतिक उपादानों का जिस प्रकार प्रयोग निराला ने किया है वैसा प्रयोग तत्कालीन कवियों ने नहीं किया। यह निराला की प्रगतिशील विचारधारा का परिणाम है।

समकालीन रचनाधर्मिता को निराला जी ने जो संवेदना, संघर्ष और क्रान्तिकारी स्वरूप प्रदान किया वह तत्कालीन राष्ट्रीय आवश्यकता थी। इसके अलावा राष्ट्रीय-सांस्कृतिक विचारधारा, प्रेम की अभिव्यक्ति, प्रकृति का सौन्दर्यतम रूप भी इनके साहित्य में मिलता है। समीक्षक भले ही इनको छायावादी कवि घोषित करते हुए इनकी सीमा का निर्धारण करते हैं, परन्तु निराला का सम्पूर्ण साहित्य इसको खारिज करता है। निराला किसी वाद-विशेष के कवि नहीं बल्कि एक विचारक थे, जिनका एकमात्र लक्ष्य राजनैतिक और सामाजिक विसंगतियों को दूर कर उन्नत राष्ट्र का निर्माण था। अत: यह कहना कि निराला प्रगतिशील कवि थे, बिल्कुल न्याय संगत होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सं. नन्दकिशोर नवल-निराला रचनावली भाग 1, 2-राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली।
2. राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी-निराला और अपरा, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा।
3. डॉ. रामविलास शर्मा-निराला की साहित्यिक-साधना भाग 1, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली।
4. डॉ. अजय तिवारी-प्रगतिशील कविता के सौन्दर्य मूल्य-परिमल प्रकाशन, इलाहाबाद।
5. डॉ. रणजीत-हिन्दी के प्रगतिशील कवि-पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
6. डॉ. कृष्ण भावुक-निराला और दिनकर के काव्य में भारतीय संस्कृति-प्रेम प्रकाशन, नई दिल्ली।

****

पं0 कामताप्रसाद 'गुरू'- एक विलक्षण व्यक्तित्व

डॉ. अर्चना देवी अहलावत *

प्रस्तावना – राष्ट्रभाषा हिन्दी का परिष्कार करने वाले यशस्वी भाषाशास्त्रियों में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी एवं यश: काय आचार्य पं0 किशोरीदास वाजपेयी के साथ ही 'हिन्दी व्याकरण' के रूप में प्रथम बार वैज्ञानिक पद्धति पर 'हिन्दी का व्याकरण' लिखने वाले पं0 कामताप्रसाद 'गुरू' का नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित है।

24 दिसम्बर सन् 1875 की मध्य रात्रि के पश्चात मध्य प्रदेश के सागर शहर के 'परकोटा वार्ड' में चतुर्भुज घाट के किनारे पैतृक मकान में जन्म लेने वाला बालक कामता प्रसाद' ही हिन्दी का परिष्कारक बना। उनके नाम के साथ गुरू लगने की कथा कम लोग ही जानते हैं, हुआ यूँ कि पं0 कामता प्रसाद 'गुरू' के पूर्वज दो शताब्दी पूर्व उत्तर प्रदेश से जाकर मध्य प्रदेश के 'सागर' शहर में बस गये थे। उन्ही पूर्वजों में एक पं0 देवताराम पाण्डेय संस्कृत एवं ज्योतिषशास्त्र के प्रकाण्ड ज्ञाता थे, अत: सागर के दांगी राजघराने की रानियों को उनसे शिक्षा-दीक्षा दिलाई गयी और पाण्डेय के स्थान पर गुरू कहा जाने लगा। हिन्दी व्याकरण के पं0 कामता प्रसाद इसी वंश की पॉचवी पीढ़ी में हुए और उनके समय तक यह 'राज-दीक्षा' की परम्परा चलती रही।

भाषा शास्त्री एवं व्याकरण वेत्ता के रूप में पं0 कामता प्रसाद 'गुरू' की ख्याति राष्ट्रीय सीमाओं को लांघकर विदेशों तक भी पहुॅची, जिसका प्रमाण इटली के विख्यात भाषाविद् ऐजतुर बिरयानी द्वारा 26 जुलाई 1967 को लिखे पत्र की इन पंक्तियों में मिला जाता है-'मेरे यहॉ कैलाग तथा कामता प्रसाद 'गुरू' कृत दो हिन्दी व्याकरण हैं। कामता प्रसाद 'गुरू' का व्याकरण श्री जवाहरलाल नेहरू ने पिछले वर्ष भेज दिया और वह हिन्दी भाषा के अध्ययन के लिये अत्यन्त उपयोगी है। मेरा विचार यह है कि यह हिन्दी का श्रेष्ठ व्याकरण है।' वस्तु: सुदूर राष्ट्र इटली के विद्वान का यह कथन विशेष महत्व का हो जाता है, चूॅकि इसमें प्रधानमंत्री पं0 जवाहरलाल नेहरू द्वारा उन्हें पं0 कामता प्रसाद 'गुरू' का हिन्दी व्याकरण भेजने का उल्लेख है, जिससे उनके व्याकरण ग्रन्थ की लोकप्रियता सिद्ध होती है।

'हिन्दी के पाणिनी' की संज्ञा से विभूषित आचार्य पं0 किशोरी दास वाजपेयी ने अपने ग्रन्थ 'हिन्दी शब्दानुशासन' का समर्पण 'गुरू' जी को ही किया है। उन्होने लिखा है-'मैने अपने हिन्दी शब्दानुशासन का समर्पण 'गुरू' जी को ही किया है। जिस महान पंचायत को वह समर्पण है, उसमें 'गुरू' जी भी हैं।' आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने तो स्पष्टत: यहॉ तक लिखा है- 'प्रेरककर्ता द्विवेदी जी, राहुल जी और डा0 अमरनाथ झा'। चिन्तन के बीच- पं0 अम्बिका प्रसाद वाजपेयी और पं0 कामता प्रसाद 'गुरू' जिनके व्याकरणों में विमति (मौलिक मतभेद) ही 'हिन्दी शब्दानुशासन' का कारण है। आचार्य वाजपेयी के ये ह्रदय से निकले शब्द भाषाशास्त्री के रूप में पं0 कामता प्रसाद 'गुरू' के अक्षय महत्व की स्वीकृति ही हैं।

नि:सन्देह आचार्य पं0 महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से काशी नागिरी प्रचारणी सभा, वाराणसी द्वारा 1920 में प्रकाशित पं0 कामता प्रसाद 'गुरू' द्वारा वर्षो की साधना से लिखा गया 'हिन्दी व्याकरण' एक ऐसी अमर कृति है, जिस पर हम गर्व कर सकते हैं और जो युगों तक उनकी कीर्ति को अक्षुण्ण रखेगी। बहुत कम लोग आज ऐसे है जो यह जानते हैं कि व्याकरण और भाषा परिष्कार के महत्वपूर्ण कार्य में वे जीवन पर्यन्त जुटे रहे और सन् 1947 से जब वे काल कवलित हुए, तब भी हिन्दी व्याकरण के संशोधन में ही लगे हुए थे।

बहुआयामी रचनाकार – भाषाशास्त्री एवं व्याकरणवेत्ता पं0 कामताप्रसाद 'गुरू' मूलत: कवि, निबन्धकार, समीक्षक, नीतिशास्त्री, कथाकार एवं नाटककार रहे हैं, लेकिन 'हिन्दी व्याकरण' के कारण उन्हे जो ख्याति मिली, उसकी चकाचौंध में उनकी रचनाएॅ बहुत कम प्रकाश में आ सकीं। 'गुरू' जी की रचनाओं पर एक दृष्टि डालते ही उनके बहुआयामी रचनाकार के व्यक्तित्व का परिचय हमें मिल जाता है-

1. भौमासुर वध (ब्रजभाषा काव्य) 2. विनय पचासा (ब्रजभाषा काव्य) 3. पद्य पुष्पावली 4. बाल पद्यावली (दोनों खड़ी बोली में बाल उपयोगी काव्य संग्रह) 5. हिन्दुस्तानी शिष्टाचार (नीति विषयक कृति) 6. देशोद्धार (विद्यार्थियों के लिये नीतिपरक निबंधों का संग्रह) 7. सत्य प्रेम, पार्वती, यशोदा (उपन्यास) 8. सुदर्शन (लोकप्रिय पौराणिक नाटक)

इसके साथ ही तत्कालीन सरस्वती , 'श्री शारदा', 'सुधा', एवं प्रसिद्ध 'माधुरी' जैसी पत्रिकाओं में प्रकाशित कविताएॅ बहुत लोकप्रिय हुईं। एक विशेष उल्लेखनीय तथ्य है कि विद्यालयों के लिये सबसे पहले कविता संग्रह में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने नाथूराम यशंकर' यमैथिलीशरण गुप्त' एवं कामता प्रसाद 'गुरू' की कविताएॅ संकलित की थीं और इस संकलन का नाम था-'कविता कलापय।

पं0 कामता प्रसाद 'गुरू' जी हिन्दी के साथ-साथ उर्दू, अंग्रेजी तथा उड़िया के भी अच्छे ज्ञाता थे और लेखक थे। जब वे व्याकरण लिख रहे थे, तब तुलनात्मक अध्ययन के लिए मराठी, बंगला तथा गुजराती भाषा उन्होनें विशेष रूप से सीखी थी। तत्कालीन अंग्रेजी पत्रिकाओं 'इण्डियन एजूकेशन' तथा जबलपुर टाइम्स' में कामता प्रसाद यगुरू के अंग्रेजी में लिखे आलोचनात्मक निबंध छपा करते थे। हिन्दी में जहॉ कविवर बिहारी लाल एवं पद्माकर की रचनाएॅ उन्हे कण्ठस्थ थीं, वहीं उर्दु में गालिब और अकबर 'इलाहाबादी' तथा अंग्रेजी में टैनीसन और ग्रे की रचनाएॅ भी उन्हे कण्ठस्थ थीं।

विलक्षण कवि-हिन्दी के 'द्विवेदी युग' में जिन कवियों को प्रसिद्धि और यश मिला उनमें पं0 कामता प्रसाद 'गुरू' भी हैं। राष्ट्रप्रेम , जन-जागरण एवं नारी मुक्ति से संबंधित उनकी कविताओं को सुनकर आज भी रसानूभूति

* प्रवक्ता (हिन्दी) (स्ववित्तपोषित योजना में नियुक्त) दयानंद आर्य कन्या पी0जी0 कॉलेज, मुरादाबाद (उ.प्र.) भारत

सहज रूप में होती है। बाबू श्यामसुन्दर दास द्वारा संपादित 'हिन्दी प्रवेशिका' (सन् 1926-27 में 'गुरू' जी की एक कविता छपी थी-'जन्मभूमि जो प्रेरणा का अजस्र-स्रोत सिद्ध हुई थी। इसी कविता के दो छन्द प्रस्तुत हैं।

'जिसे जन्म की भूमि भाती नही है/ जिसे देश की याद आती नही है/ कृतघ्नी महा कौन ऐसा मिलेगा?/ उसे देख जी कया किसी का खिलेगा? जिसे जन्म की भूमि का मान होगा/ उसके भाइयों का सदा ध्यान होगा/दशा भाइयों की है जिसने न जानी/ कहेगा उसे कौन देशाभिमानी?

कवि के रूप में 'गुरू' जी ने जो सरस काव्य-रचनाएँ हिन्दी को दी, उनमें हास्य व्यंग्य की चटक देखकर सहसा विश्वास नहीं होता कि गंभीर प्रकृति के व्याकरणवेत्ता ऐसी सरस कविताएँ लिख सका होगा। एक कविता है 'नेकटाई' जिसका हास्य व्यंग्य तो देखते ही बनता है-

'काल-चाल से हैं, खुले, तेरे भाग्य विचित्र।
भारत में तू तो गई, कण्ठी-तुल्य पवित्र।।'

द्विवेदी-युगीन राष्ट्रीयता तो उनकी रचनाओं में प्रमुख स्वर बनकर मुखरित हुई है। उनकी रचना-'राम', 'शिवाजी', 'परशुराम', द्वदुर्गावती' एवं चाँदबीबी में राष्ट्रीय चेतना विलक्षण ही है। भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन से वे पूरी तरह जुड़े हुए थे और युगानुकूल कविता का लक्ष्य उनकी दृष्टि में था यवीर पूजा'-

'उचित यही है करें वीर-पूजा मिल हम सब।
यही धर्म है, सत्य यही है, सच्चा करतब।।'

पं0 कामताप्रसाद 'गुरू' ने कविता को नीतिशास्त्र से जोड़कर उसकी उपयोगिता प्रमाणित की है। उनकी सर्वथा विशिष्ट ढंग की कृति है- 'हिन्दुस्तानी शिष्टाचार' जो उनके जीवनादर्शों का निर्मल दर्पण ही है। अपनी इस कृति के माध्यम से उन्होंने अनेक ऐसी उक्तियाँ सहज, सरल ढंग से कह दीं, जिनको स्पष्ट करने के लिए लम्बे भाषण दिये जा सकते हैं। इसमें गहरी चोट है, जो व्यंजना के नुकीले तीर पर बैठकर सीधे मर्म को बेध जाती है। 'नीति पद्यमाला' से कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं-

'एक चाक से ज्यों नही, होती रथ की चाल।
त्यों ही पौरूष के बिना निष्फल भाल।।'

ऐसा ही एक और उदाहरण है जिसमें अलंकार का समुचित प्रयोग कथ्य को गरिमा प्रदान करता है। वक्रोक्ति को रूपायित करता उदाहरण-

'कष्ट प्राप्त है सगुण को, निर्गुण को सुख-भोग।
शुक्र को बंधन, काग को है स्वतन्त्रता योग।।'

ये उक्तियाँ ही उनकी विलक्षण कवि प्रतिभा का प्रमाण है। निबंधकार, उपन्यासकार तथा नाटककार के रूप में भी उन्हें लोकप्रियता मिली। उनके तीनों उपन्यासों 'सत्यप्रेम' 'पार्वती एवं यशोदा के साथ ही पौराणिक नाटक 'सुदर्शन' में तत्कालीन सामाजिक एवं सांस्कृतिक चेतना का सफल चित्रांकन हुआ और ये साहित्य की अमूल्य निधि बन चुके हैं।

पं0 कामता प्रसाद 'गुरू' के बहुमुखी साहित्यिक जीवन का एक अजाना-अछूता पक्ष है, जिस पर बहुत कम प्रकाश पड़ा है। वे एक सफल अनुवादक भी थे और सम्पादन कार्य से भी जुड़े रहे। उड़िया के प्रसिद्ध उपन्यासों 'पार्वती' और 'यशोदा' का उन्होने अनुवाद किया था और जस्टिस शारदा चरण मित्र की यदेवनागरी' पत्रिका में उड़िया के कुछ निबन्ध एवं अनुवाद उनके छपे थे। अध्यापन कार्य से अवकाश लेकर नागपुर गये थे 'हिन्दी ग्रंथ माला' का कार्य करने और परोक्ष रूप से वहाँ के 'हिन्दी केसरी' के सम्पादन से जुड़ गये। प्रयाग की यात्रा उन्होने यसरस्वती' तथा यबालसखा' का सम्पादन करने के लिये ही की थी।

पं0 कामता प्रसाद 'गुरू' बहुआयामी रचनाकार रहे हैं, जिनके एक आयाम 'व्याकरण' को इतना गौरव मिला कि उसके तले कविता, निबंध, उपन्यास, नाटक आदि की रचना करने वाले विलक्षण रचनाकार और नीतिशास्त्री 'गुरू' को भुला सा दिया गया। प्रख्यात समालोचक श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी के शब्द इस महान रचनाकार के विषय में कहा है-'पं0 कामता प्रसाद 'गुरू' हिन्दी के उन निर्माताओं में से थे, जिनके कारण आज हिन्दी साहित्य उन्नति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। वे हिन्दी साहित्य ही नहीं, हिन्दी भाषा के भी निर्माता कहे जा सकते हैं। हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में गुरू जी सचमुच 'गुरू' जी ही थे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. उत्तर प्रदेश अंक दिसम्बर 1985, सम्पादक - कौशल कुमार राय

****

जीवन मूल्य और साहित्य एक संदर्भ

डॉ. एस. एस. राठौर *

प्रस्तावना – जीवन मूल्य बीसवी शतब्दी का सर्वाधिक चर्चित शब्द है। सामान्य अर्थो में जीवन मूल्य शब्द से ध्वनित होने वाला अर्थ वस्तु के दाम या कीमत की तरह ही है। साहित्य में जिस मूल्य की चर्चा को रही है उस की व्युत्पत्ति संस्कृत की मूल धातु में यत् प्रत्यय के संयोग से हुई है जिसका अर्थ है कीमत।1 मूलेन आनाम्यते मूलने समंगा इति मूल 2 अर्थात मूल्य किसी वस्तु के बदले में मिलने वाली कीमत का नाम है।

अंग्रेजी में बैलू शब्द का साहित्य में युक्त होने वाला मूल शब्द समानार्थी है। बेल्यू शब्द लेटिन भाषा के Valera से बना है। जिसका अर्थ है अच्छा। सुन्दर मूल्य शब्द में शिवं एवं सुन्दरं की भावना सन्निहित है। 'जो कुछ भी इच्छित वांछित है वही मूल्य है।' मानव जीवन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जीवन के कुछ मापदण्ड निर्धारित किये गये है , वास्तव में उन्हीं मानदण्डों के आधार पर मूल्य की अवधारणा की गई है। मूल्य का अर्थ मानव जीवन से संबंधित है। अवंन ने लिखा है – 'किसी भी इच्दा या आवश्यकता के पूरक ही मूल्य है।'वही वस्तु अन्तिम रूप से मूल्यवान है जो कि व्यक्तियों को आत्मानुभूति की ओर ले जाती है। 'मूल्य न तो किसी मशीन द्वारा उत्पादित वस्तु है और न ही ये किसी सरकार द्वारा निर्मित कानून है। मूल्य तो जीवन के प्रति एक गुण है, एक अन्तर्दृष्टि है , एक अवधारणा है एक दृष्टिकोण है' जगत को मिथ्या, क्षणभंगुर तथा त्याज्य समझने वाली धारणा तथा जगत को ही एकमात्र सत्य और योग्य मानने वाली विचारधारा इन दोनों के बीच समान्वय स्थापित करते हुए भारतीय दर्शन जगत को ब्रम्ह की ही अभिव्यक्ति स्वीकार करता है । इसलिये सांसरिक भोग से सम्बधित भौतिकवादी तथा ब्रम्ह को काम्य मानकर आध्यामिकतावादी दृष्टि दोनों को ही समान्वित रूप में स्वीकृति देता है। चिन्तनकी इसी समन्यवादिता पर पुरूषार्थ की धारणा अवलम्बित है।

भारतीय दर्शन के अन्तर्गत पुरूषार्थ को ही जीवन मूल्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। पुरूषार्थ का मूल्य उन प्रयत्नों से है, जिन्हे जीवन की उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है। हिन्दू जीवन दर्शन में पुरूषार्थ का रूढ़ अर्थ मानव जीवन के उद्देश्यों से है। भारतीय दार्शनिकों ने मानव जीवन के चार मूल्य स्वीकार किये है।

1. धर्म
2. अर्थ
3. काम
4. मोक्ष

मोक्ष को जीवन का साध्यात्मक मूल्य तथा धर्म अर्थ और काम को साधनात्मक मूल्य के रूप में मान्यता दी है। भारतीय संस्कृति के महाकाब्यों का उद्देश्य भी इन्हीं शाश्वत् जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा करना है। देवी प्रसाद गुप्त ने लिखा है 'हमारे महाकाब्यों का उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की फल प्राप्ति माना गया है। इसमें प्रतिपादित शाश्वत् जीवन मूल्य भोग योग और कर्म है। मन, बुद्धि, शरीर और आत्मा इन चार तत्वों का मिलन ही मनुष्य है । शरीरिक विकास हेतु अर्थ, मानसिक विकास के लिए काम, बौद्धिक विकास के लिये धर्म तथा आध्यात्मिक विकास के लिये मोक्ष को पुरूषार्थ तथा लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया है । भारतीय साहित्य के लिये प्राचीनतम् मूल्य है। भारतीय साहित्य में प्राचीन काल से ही जीवन मूल्यों पर विचार किया जाता रहा है। सुखदुख राग द्वेष जगत आदि सभी से मक्ति डॉ. राधाकृष्णन पुरूषार्थ को जीवन के मूल्य स्वीकार करते हुए लिखते है – अपना अस्तित्व बनाये रखना, आत्मा की निर्मलता को बनाये रखना ही जीव का लक्ष्य है। मानव केवल भौतिक सम्पत्ति और ज्ञानार्जन से ही संतुष्ट नहीं रह सकता उसका ध्येय है आत्म–सक्षात्कार करना।

जीवन मूल्यों के संदर्भ में भारतीय चिंतन ने सर्वागीण मानव जीवन की व्यवस्था को लक्ष्य मानकर जिन चार पुरूषार्थ अथवा मूल्यों की प्रतिष्ठा की है उनसे अनतर्वती तथा बाह्रय साध्यात्मक और साधनात्मक शाश्वत और सामयिक वैयक्तिक एवं सामाजिक सभी तरह के मूल्य समाविष्ट है। आज की वैज्ञानिक और अन्तर्राष्ट्रीय आधुनिका के संदर्भ में थोडे बहुत स्वरूप भेद के साथ समस्त नवीन जीवन मूल्यों को इन्हीं के अन्तर्गत देखा जा सकता है। युगानुकूल संदर्भ बदलते रहते है पर लक्ष्य वही रहता है। मानव जीवन का विकास सतत रूप से इन्हीं मूल्यों के आधार पर गतिमान है।

पाश्चात्य विचारकों के अनुसार जीवन मूल्य के रूप मे धर्म, व्यवहारिकता सुखवादिता, फलवादिता, वैज्ञानिकता तथा प्रकृतवादिता के रूप में स्वीकार किया गया है। धीरे–धीरे भारतीय जीवन मूल्यों के संदर्भ में पश्चिमी विचारक भी चिन्तन करने लगे है । आधुनिक जीवन की अन्तर्राष्ट्रीय जीवन व्यवस्था से चिन्तन में बदलाव आना स्वाभाविक है। इसीलिए भारतीय दर्शन में की गई पुरूषार्थ की अवाधरणा को पाश्चात्य जगत में भी विश्लेषित किया जाने लगा है।

भारतीय संस्कृति का चरम लक्ष सत्यम शिवम सुन्दरम युक्त मानवीय विचारणा या चिन्तन का निचोड़ या परिणाम है । जीवन मूल्य के सरूप निर्धारण में दो तत्वों का महत्वपूर्ण योग है।

1. व्यक्ति चिन्तन की प्रधानता।
2. समाज सुख एवं कल्याण की भावना।

मनुष्य स्वभावत: अपने चेतना के विकास और जीवन के सुखद व सुन्दर भविष्य के प्रति, आशावादी कल्पनाशीलता से आदर्श चयन का प्रयत्न करता है। मनुष्य का चरम लक्ष्य अपनी चेतना को विकसित करने में ही रहा है। इसी आधार पर भारतीय मूल्य धारणा का जन्म भी मानवीय सुख की भावना को लेकर हुआ है। इसीलिए मानवीय चेतना के विकास और समाज हित की भावना के कारण लक्ष्य की दृष्टि से जहां हमने भारतीय चिन्तन को जीवन मूल्य का स्वरूपाधार माना है वहां की व्यवावहारिकता की वैज्ञानिक संयोजना का निष्कर्ष रूप पश्चात्य सिद्धांत को अपनाया है। इसी समन्वित

* प्राध्यापक (हिन्दी) छत्रसाल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पन्ना (म.प्र.) भारत

मार्ग से हमने सुन्दरम् और शिवम् का तत्व भारतीय दर्शन से तथा तथ्य चिन्तना का मनो वैज्ञानिक आधार पाश्चात्य विचारधारा से प्राप्त किया है।

जीवन मूल्य और साहित्य दोनों की अन्त: निर्भरता – जीवन को सुन्दर और श्रेष्ठतर रूप में देखने की चाह से प्रेरित होकर ही मनुष्य साहित्य तथा अन्य कलाओं का सृजन करता है। वे बौद्धिक कल्पना के माध्यम से कलाकार कुछ इस प्रकार के कल्याणमय चिन्तन को जन्म देता है जो कि जीवन का मार्ग दर्शन कर सके और भावनात्मक कल्पना के सहारे वह अभिव्यक्ति में ऐसी रमणीयता का सृजन करता है। जो जीवन में सौष्ठय उत्पन्न करके उसे आनन्दित कर सके। साहित्य तथा कलाओं में जीवन मूल्यों का यथार्थ अंकन होता है साहित्यकार अपने वर्तमान जीवन के अभावों अपूर्णताओं आदि की सीमाओं से व्याकुल होकर साहित्य तथा कला के बहाने एक कल्पनात्मक जीवन को ही अपना आर्दश रूप मान लेता है और उसी के अनुसार आचरण करने लगता है।

भर्तृहरि ने लिखा है 'साहित्य संगीत कला विहीन: साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन:' मनुष्य के जीवन में संगीत और साहित्य दोनों का अपना अलग महत्व है। साहित्य मानव सृजित होने के कारण मानव जीवन का चित्रण करना साहित्य का परम लक्ष्य होता है। इसीलिए साहित्य का मानव जीवन से घनिष्ठ संबंध है। साहित्य मानव जीवन की विविध स्थितियों घटनाओं एवं भावनाओं आदि का रूपान्तरण है। साहित्य में जीवन मूल्य उपर से अरोपित नहीं होते बल्कि वह साहित्यकार के अनुभूत सत्य होते है। जो उनकी आत्योपलब्धि की प्रक्रिया में रूपायित होकर अपनी सुन्दरता उदान्तता और महत्ता के कारण समाज द्वारा जीवन मूल्यों के रूप में स्वीकार किये जाते है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. हिन्दी विश्वकोश – श्री नगेन्द्रनाथ वसु।
2. संस्कृत हिन्दी कोश – वामन शिवराम आप्टे।
3. पूर्व–पश्चिम भारतीय दर्शन – डॉ. राधाकृष्णन।
4. आधुनिक काब्य में नवीन जीवन मूल्य – डॉ. हुकुम चन्द्र राजपाल।
5. हिन्दी उपन्यास और जीवन मूल्य – डॉ. मोहनी शर्मा।
6. मानव मूल्य और साहित्य – डॉ. धर्मवीर भारती।

****

जनजातियों में पति पत्नी गीत (निमाड़ के संदर्भ में)

डॉ. गुलाब सोलंकी *

पश्चिम निमाड़ की जनजातियो में सामाजिक गीतो में आपसी रिश्तों की पहचान मिलती है।

साथ ही सामाजिक सभ्यता,संस्कृति और वैचारिकता भी दृष्टिगोचर होता है। सभी रिश्ते प्रेम और स्नेह पर आधारित होते है। सामाजिक लोकगीतो में पति-पत्नी के मध्य प्रेम की नोक-झोक है वही भाभी-ननद में आपसी टकराव ,वर-वधु के प्रति व्यंग्य भाव भी है। जेठ-जेठानी,जेठानी-देवरानी,भाभी-देवर के आपसी संबंधो में एक मनोवैज्ञानिक आन्तरिक एहसास भी है।

जनजातियो में नारी गीतो के साथ पुरूष गीत भी है। पुरूष अपनी मस्ती भरा जीवन जीने का अभ्यस्त है।

उनके गीतो में जहां दारू की मादकता है, वही दूसरी और नारी सौन्दर्य के प्रति मोहिनी रूझान भी।

पति-पत्नी लोकगीत- पति-पत्नी संबंध मनमोहक और आनंददायक होता है। इसकी जानकारी इनके गीतो में देखी जा सकती है।

आसो आव मन म, निकल जाय वन म।
सावल बना सी परणावी ।
आसो आव.....
माय आरू बाप माया केरा लोभी
सांवला बना सी परणावी
काका-काकी माया केरा लोभी
सांवला बना सी परणावी
आसो आव मन म.....

भावार्थ- नवविवाहिता की मनोवेदना है। नवविवाहिता कहती है, कि मेरे मन मे ऐसी इच्छा होती है,कि मै जंगल मे कही चली जाऊं मेरे माता-पिता,काका-काकी ने धन को लोभ (कन्या मूल्य) में मुझे सांवले,काले दूल्हे से ब्याह दिया है।

नवयौवना अपने पति को कहती है, कि मुझे घर में बहुत काम करना पड़ता है, जिससे मेरे हाथो में तकलीफ होती है।

'म्हारी गोरी हतेली मे छाला पड़ी गया मारू जी
चारू नही काटू रे मना बन्द-छन्द मे'

भावार्थ- मेरी हतेली में छाले पड़ गए है, मैं घास काटने नही जाऊंगी।

नवयौवना कहती है-

'छोड़ी मति जाय मने, मैली मति जाय
परदेश टाण्डा रा नाथ एकली,
बेन्या झुर थारी बार-तिबार रे
टाण्डा नाथ एकली.....
छोड़ी मति जाय.....
परदेश टाण्डा.....
माता झूर थारी जनम जोगणी
पिता झुर भरी हथाय।
छोड़ी मति जाय मने, मैली मति जाय।
इणी गिणी दोनो झोपड़ा रे
डुलता नी लागी तुक बार रे
छोड़ी गयो मक एकली।'

हे स्वामी मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम अपनी कमजोर बहन,माता-पिता को दुखी कर जा रहे हो।

एक युवती अपने पति से कहती है-

चलो चलो म्हारा भोलो बालमे
दिल्ली घणी दूर छे.....
दिल्ली घणी दूर छे, जाणो भी घणी दूर छे।
मत पीजो म्हारा भोलो बालम दारू बुरी चीज है
देखो-देखो म्हारा भोला बालम लोग नशा म चूर छे
मत- खेलो, मत खेलो म्हारा भोला बालम
सट्टा को बजार छे, खेलण बालो हजार छे
श्वेत,खलो मकान बेचो, पयसा सी उधार छे
मत देखो म्हारा भोलो बालम राण्ड बड़ी कमजात छे।
वका पर मक बड़ी झाल छे
रूको-रूको म्हारा भोलो बालम, सत संगत की रात छे
देखो सुनो म्हारा भोलो बालम राम भगत की बात छे।

भावार्थ- पत्नी-पति से दारू, सट्टा के दुष्परिणामो का बखान कर रही है।

भेजी द मके पीयर, कब सी गई नहीं
राखी बीती, नवदुर्गा भी रीति
दिवालई भी निकलई गयी।
भेजी द मके पीयर, कब सी गई नहीं
तुमन कयो थो , राखी पर जाजे
रयजे दो मईना, दिवालई पर आवजे
मूंग की दाइकी पर मक भेजी, जुवाई मकई काटण गयी
सेगंलई की दाइकी निकलई।
माय रस्तो देखे , बाप संदेशो भेजे
भाय की गाड़ी गडडा म पड़ी
भेजी द मके पीयर
तीज त्यौहार पर नई तुमने भेजी
लई चलो जातरा खरगुण की
उपर नीचे जाणया झूला पर झूलो
पिपल्या,राजपुर की जातरा भी निकलई

भावार्थ- युवती अपने पति से मायके जाने के लिए कहती है। पति उसे हर बार कोई न कोई बहाना बना कर रोक देता है। पत्नी परेशान होकर कहती है राखी, दिवाली,नवदुर्गा सभी त्यौहार निकल गए।

मूंग,मक्का,ज्वार कटने लग गयी फिर भी पीयर नहीं भेजा पिताजी का संदेश आया अब मेरा मन नहीं लगता है। अब मुझे खरगोन का मेला जिसमे बड़े-बड़े झुले आए है झुलाने ले चलो,बच्चो राजपुर,पिपल्या का मेला तो निकल चुका है। पत्नी-पति की नोक-झोक गीत में झलकती है।

नसो चयड़ी गयो, दारू की थूङ्ग में
नसो चयड़ी गयो, दारू की थूङ्ग में
मने कयो थो, दारू मति पीजो

* प्राध्यापक (हिन्दी) शासकीय महाविद्यालय, धामनोद, जिला - धार (म.प्र.) भारत

मने कयो थो, दारू.....
मने कयो थो स्वामी सला करजो
कल्ला पेरी आया दारू की धुन में
नसो चयड़ी.....
मने कयो थो साकलई लावाजो
बाकलई खायी आया, दारू की धुन्न में
मने कयो थो झुमको लावजो,
ठुमको दई रया दारू की धुन्ने में
मने कयो थों, लुगड़ो लावजो,
कुकड़ो लयी आया, दारू की धुन में,
नसो चयड़ी गयो दारू की धुन्न में।

भावार्थ- पति नशे की हालत में है,पत्नी व्यंग्य गीत के माध्यम से कहती है कि जो चीजे मंगायी थी,वे नहीं लाए और दूसरी चीजे लेकर आ गए। पति-पत्नी के मध्य हास-परिहास है, तो परिवार जनो के प्रति आत्मीय संबंधो की गहराई भी-

'बाजरा की रोटी, मसूर की दाले
पिया जिमाडू सखी री पाल।
सासू के कई दीजो ससरा क
कई दीजो, म्हारा माय-बाप
को नाव मत लीजो।
बाजरा की रोटी, मसूर की दाले।'

(मायके की बुराई नारी कभी सहन नहीं करती है। मायके की निन्दा के प्रसंग पर नायिका कहती है- बाजरा की रोटी,मसूर की दाल का स्वाद मजेदार होता है। हे सखी पिया को पाल(बांध) पर बैठाकर भोजन खिला रही हुँ। भोजन कराते वक्त पति को कह दिया है कि आपके परिवार जन को कह देना की मेरे माता-पिता अर्थात मेरे परिवार के सदस्यो पर किसी भी प्रकार का व्यंग्य नही करे। पत्नी अपने रूठे हुए पति को मनाने का प्रयास कर रही है। आपकी पसंद का क्या-क्या बनाया है।)

'मने झटका सी रांधी सांग,
साहेब म्हारो जीमणे ख आया
दाल भी रांध्या, मने भात भी रांध्या
मने कढ़ी बघारी अभी हाल।
सीरो भी सेक्यो, मने खीर भी ओटाड़ी
तेमे पूरणपोली को घणो स्वाद।
दही बडा बणाया मने भजा भी बणाया,
पूरी उतारी झटपट, साहेब म्हारो जीमणे ख आया।'

भावार्थ- हे प्रियतम मैने अच्छी सब्जी बनायी है, भोजन कर लो, साथ ही दाल- चावल,खीर,हलवा,सब बनाऐ है।

पति- अपनी रूठी हुई पत्नी को मनाने का प्रयास करते हुए कहता है-

तू कण्डा की थाप ,थारा गोबर वाल हाथ
तू केतरी सुन्दर छे, तू केतरी सुन्दर छे
दिन रात गोबर पाणी,तुक कुण
कए राणी.....
तू कण्डा की थाप-थारा गोबर वाल हाथ
तू केतरी सुन्दर छे।

पति- पत्नी के मायके जाने से दुखी है, और कहता है-

थारा बिन सुणो लागे वो गोरी आंगणु
कसो मने क समझावणु
पियर तू गयी वो गोरी
थारा भाई का साथ मे
घुंघरा बाजे कान में
थारा बिना सुणो लागे वो
गोरी आंगणु

भावार्थ - हे प्रिय तुम्हारे जाने से आंगन सुना लगता है। तुम्हारे घुंधरू(पायल) की आवाज मेरे कानो को झंकृत कर रही है।

नायिका अपने पति से आभूषण के लिए जिद कर रही है। सभी महिलाओ के पास गहने है, उसके पास नहीं है। इसलिए कहती है-

स्वामी मक लाई देवो, करण फूल झूमको
स्वामी.....
झूकमो पेरी न हाऊ पाणी गयी थी,
ससूजी क लगी गयों चणकों
स्वामी मक लायी देवो करणफूल झूमको।

पत्नी अपने पति से शहर छोड़ गांव में चलने के लिए कहती है-

हॉ रे सायबा शयर छोड़ी न चलो गांव मा
हाऊ तो नी रहेण की यहां कोई भाव मा
मिनत की खावांग, रूखी-सुखी रोटी
वहां नी रवांगा हम कोई का दबाव म
चलो गांव मा.....
हा रे सायबा शहर छोड़ी न चलो गांव मा।

नायिका कुँऐ से पानी लाने में कहती है-

कुवां पाणी कसी जाऊं सा
नजरे लगी जाय, हवा लगी जाय
म्हारा साहेब जी का घणा बाग
फुलड़ा तोइन कसी जाऊ सा
नजर लगी जाय।

पत्नी अपने पति से खेत में काम करने के संबंध में कहती है-

'निंदणा मे मक आव पसीनू
बलम थारी दाइकी म खोयो नगीनु
म्हारा माय-बाप की हऊ त लाइकी
पियर म हऊ कदी गई न दाइकी
सासरा म हऊ त झुरून, बलम थारी दाइकी
म खोयो नगीनु।
थकई-मुकई ने मक भेजी सासरे
जेठ-जेठानी मक घणा आखरे
निदणा म त मक आव पसीनू
बलम थारी दाइकी मे खोयो नगीनु
आसा सासु-ससरा न के जिन्दा गाड़ा
चार चवकी जुवार रोजे दलाड़े
चार चवकी का रोटा कसा करणु
बलम थारी दाइकी म खोयो नगीनु
रोटी नी खाय देवर नखरा करे
ऊपर सी देराणी चत्तरई करे
बलम थारी दाइकी मे खोयो नगीनू'

भावार्थ- महिला खेत में काम करने के लिए जाती है, उनकी अंगुठी का नग गिर जाता है। अपने ससुराल वालो के प्रति और उसकी भावना व्यक्त होती है और कहती है कि काम करने के बहाने उनका नगीना गुम हो गया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. जी. सोलंकी शोध प्रबंध।
2. रामनारायण उपाध्याय निमाड़ी साहित्य।
3. डॉ कृष्णदेव उपाध्याय लोक संस्कृति की रूपरेखा।

Music Piracy And Copyright Protection

Poorva Jadhav *

Introduction - The basis of copyright law, despite the evils enumerated by **Lord Macaulay**, is a monopoly. The core emphasis of copyright law is the protection of creators of literary and artistic works so that people do not use their work for unauthorized distribution, alteration, reproduction, etc. While Lord Macaulay's famous speech was in the backdrop of a debate on extending the period of copyright protection for a literary work beyond the life of the author, today the reaches of the said law and nature of the areas meriting its protection have indeed come a long way. Technological advancements such as digitization of literary and artistic works thereby rendering them vulnerable to infringement have been the subject matter of many debates in recent years with the entertainment industry being one of the highest stakeholders of this debate. New trends in the music industry such as version recordings fall in the grey area in which there is absence of legal clarity.

Copyright Provlems in India - India's first copyright law, the Copyright Act of 1914 (1914 Act), substantially resembled Britain's copyright law of 1911 because of British rule in India during that time.[1] The legislation changed, however, once India gained its independence and began to evolve into a sovereign nation.[2] Following India's independence, it adopted the Copyright Act of 1957, which retained some 1914 Act provisions, yet introduced several modifications and additions. The next amendment to the Copyright Act of 1957 occurred on August 9, 1984 with the adoption of The Copyright (Amendment) Act of 1983.[3] The Indian Parliament introduced numerous revisions for the new amendments to conform to the Berne Convention and Universal Copyright Convention, two conventions to which India is a party.India adhered to certain general terms of the conventions; however, the international community raised serious criticisms against the Copyright Act of 1983.[4] These criticisms stemmed from India's increasing piracy problem. In response, the Indian Parliament in 1984 enacted another amendment to India's copyright law.[5] The Copyright Act of 1984 introduced provisions discouraging and preventing widespread piracy of film and records.

India's Copyright Laws and Enforcement System: Present Condition -

Overview of Improvements Made to Indian Copyright Act and Problems Facing Copyright Enforcement - With the adoption of the Copyright Act of 1994 amendment, India modernized and strengthened its copyright protection laws, thereby bringing the country in harmony with international practice and affording artists around the world better copyright protection.[6] In addition to updating the copyright laws, the Indian Government established the Copyright Enforcement Advisory Council to advise the government on measures to improve copyright enforcement.[7] Police personnel received training through seminars and videos to better understand the importance of copyright law protection. The government passed legislation critical to the regulation of video shops and cable operators who were constantly faced with piracy issues. The Indian Government also encouraged state governments to establish special cells to deal directly with copyright and other intellectual property rights (IPR) violations.

Despite these efforts, the country's film industry continues to face serious cable and video piracy problems because the Indian Government and courts have failed to properly execute and enforce newly adopted laws. A prominent personality in the Indian film industry noted, for example, that a number of theaters recently ceased operations because Indian audiences, who can watch the latest movies on cable television, stopped patronizing the cinema halls. In 1998, only three years after the passage of the amended 1994 Copyright Act, piracy reached an alarming high with new movies shown on cable television either before the movie's release in theaters or only days after it played in the cinema halls. Pirated videos and video CDs are not only available in all major cities, but cable industry sources also estimate that between 40,000 to 70,000 cable operators around the country screen unauthorized films, costing the film industry millions of dollars in lost revenues.

Problems with Indian Criminal and Civil Court Systems- The Indian court system presents a challenge to copyright enforcement.[8] The Indian High Courts address copyright infringement only after cases meet exhaustive administrative requirements. The most difficult problem, however, lies at the lower criminal judiciary level where copyright cases remain the lowest priority. India's criminal system is extremely slow and cumbersome, which delays the litigation process and becomes an expensive endeavor for producers, directors, and actors who seek immediate enforcement against copyright violators. Trial delays also increase because investigators are frequently transferred to remote locations

*Student, Batch11, Hidayatullah National Law University, Raipur (C.G.) INDIA

for other projects, and once they are relocated, securing their presence for a given case is difficult. Due to these delays, the investigators' evidence for the case is often misplaced or unusable; this helps the defendant obtain a motion to postpone the hearing or trial and further delays the litigation process.

The slow, burdensome criminal court system has been detrimental not only to the enforcement of copyright laws on the national front, but also internationally, by failing to conform to international standards set forth in the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement).[9] The current condition of the Indian court system violates Articles 41(2), 42, and 61 of the TRIPS Agreement, provisions that are specifically concerned with fair and equitable treatment towards litigants. If India does not immediately reform its criminal court system, the international community will be reluctant to invest in India's entertainment industry.

Conclusion - India's copyright laws have evolved significantly since the implementation of its first copyright act in 1957. Due to both national and international pressure, India has become a leading nation in copyright laws as a result of the stringent copyright provisions enacted most recently in the Copyright Act of 1994. Although India took great measures to modernize its copyright laws to be more compatible with the entertainment industries of developed nations, such as the United States, it still does not satisfy the TRIPS Agreement requirements. For India to become a TRIPS-compatible nation, to prevent U.S. scrutiny, and to lift the current U.S. trade sanctions, India must strengthen its copyright enforcement tactics. Without immediate measures, the world's largest film industry faces a serious threat to its existence.

Creativity has become a magic word, but it is not easy to ascertain its meaning, and the law also faces certain difficulties in incorporating creativity in its system. This is particularly true of creativity in music because music is a form of art with certain unique features. It has been shown that copyright is not primarily directed at the protection of creativity, although the wide scope of copyright protection also covers creative works. The entertainment industry is dependent on the production of creative works, but it is not the appropriate vehicle to promote creativity. The business structures and business strategies of media companies rely to a large extent on established works, thus on products of past creativity, otherwise their profits could be jeopardized. The creation of new artistic works (i.e. present creativity) is not of crucial importance to them, because works/artists that are not yet recognized or do not follow established patterns of artistic expression cannot promise safe future returns.

References :-

1. See Aseem Chhabra, "Bollywood Confidential: Bollywood Films Sing and Dance Their Way to Center Stage", Boston Globe, Mar. 10, 2002
2. See P. Narayanan, "Copyright and Industrial Designs" 5 (Eastern Law Private Ltd 1995) (1986) (discussing Indian copyright law history)
3. Ibid, at 9-10 (summarizing amendments made to 1957 copyright law in 1983).
4. See Kala Thairani, "How Copyright Works in Practice 14" (Popular Prakashan PVT. Limited 1996)
5. Ibid at 58
6. See Intellectual Property Rights in India, Embassy of India, Washington, D.C. Policy Statements [hereinafter IPR-Embassy India] (discussing India's improvements in intellectual property rights protection), at http:// www.indianembassy.org/policy/ipr/ipr_2000.htm
7. N.K. Nair,"Study on Copyright Piracy in India, Sponsored by Ministry of Human Resources Development Government of India" (observing India's force in copyright field),at http:// www.education.nic.in/htmlweb/cr_piracy.study/cpr8.htm
8. See Chander M. Lall, "The Indian Film Industry and Copyright Laws, Counsel for Motion Picture Association-International" (discussing threat to today's Indian film industry), at http://www.filmpiracy.com/artc.html
9. See International Intellectual Property Alliance, 2000 Special Report India [hereinafter India 2000 Report] (discussing problems with court system incompatible with international agreements), at http:// www.iipa.com/rbc/2000/INDIA_2000.pdf.

****

Role Of Government In Protection And Preservation Of The Environment

Dr. Anand Sharma * Dr. R. Sudhir **

Introduction - India is one of the very few countries in the world which has provided for constitutional safeguards for the protection and preservation of the environment. Directive Principles of State Policy, according to Dr. B.R. Ambdekar, are "the instruments of instruction given by the ultimate sovereign, namely the people to their rules or their representatives."

Articles 48A provides - "Protection and improvement of environment and safeguarding of forests and wild life. The State shall endeavour to protect and improve the environment and to safeguard the forests and wild life of the ountry."

Article 51-A in Part IV-A of the Indian constitution states. 'It shall be the duty of every citizen of India to protect and improve the natural environment, including forests, lakes and wildlife and have compassion for living creatures'. It is thus a constitutional obligation of the State and of every citizen of India to preserve and protect the natural environment. The government has launched several programmes to fulfill this fundamental duty. There are laws for control of air and water pollution and for conservation of forests. A substantial portion of the land mass has been put under protected national parks and wildlife sanctuaries. Planning documents and most party mainfestos are careful to mention the importance of environments. There is no denying the fact that the Government of India has become increasingly conscious the environmental crisis engulfing the country.

The Department of Environment was established in India in 1980 to ensure a healthy environment for the country. This later become the Ministry of Environment and Forest in 1985.

The constitutional provisions are backed by a number of laws - acts, rules, and notifications. The EPA (Environment Protection Act), 1986 came into force soon after the Bhopal Gas Tragedy and is considered an umbrella legislation as it fills many gaps in the existing laws. Thereafter a large number of laws came into existence as the problems began arising, for example, Handling and Management of Hazardous Waste Rules in 1989.

Following is a list of the environment legislations that have come into effect -

- **General**
- **Forests and wildlife**
- **Water**
- **Air**

General -

1986 - The Environment (Protection) Act authorizes the central government to protect and improve environmental quality, control and reduce pollution from all sources, and prohibit or restrict the setting and / or operation of any industrial facility on environmental grounds.

1986 - The Environment (Protection) Rules lay down procedures for setting standards of emission or discharge of environmental pollutants.

1989 - The objective of Hazardous Waste (Management and Handling) Rules is to control the generation, collection, treatment, import, storage and handling of hazardous waste.

1989 - The Manufacture, Storage, and Import of Hazardous Rules define the terms used in this context, and sets up an authority to inspect, once a year, the industrial activity connected with hazardous chemicals and isolated storage facilities.

1**989 - The Manufacture, Use, Import and Export, and Storage of hazardous Micro-organisms/Genetically Engineered Organisms or Cells Rules** were introduced with a view to protect the environment, nature, and health, in connection with the application of gene technology and microorganisms.

1991 - The Public Liability Insurance Act and Rules and Amendment, 1992 was drawn up to provide for public liability insurance for the purpose of providing immediate relief to the persons affected by accident while handling any hazardous substance.

1995 - The National Environmental Tribunal Act has been created to award compensation for damages to persons, property, and the environment arising from any activity involving hazardous substances.

1997 - The National Environment Appellate Authority Act has been created to hear appeals with respect to restrictions of areas in which classes of industries etc. are carried out or prescribed subject to creation safeguards under the EPA.

1998 - The Biomedical waste (Managment and Handling) Rules is a legal binding on the health care institutions to streamline the process of proper handling of hospital waste such as segregation, disposal, collection and treatment.

1999 - The Environment (Siting for Industrial Projects) Rules, 1999 lay down detailed provisions relating to areas

***Prof., Govt. M.V.M., Bhopal (M.P.) INDIA**
****Asst. Prof., Govt. S.N.G. College, Bhopal (M.P.) INDIA**

to be avoided for siting of industries, precautionary measures to be taken for site selecting as also the aspects of environmental protection which should have been incorporated during the implementation of the industrial development projects.

2000 - The Municipal Solid Wastes (Managament and Handling) Rules, 2000 apply to every municipal authority responsible for the collection, segregation, storage, transportation, processing and disposal of municipal solid wastes.

2000 - The Ozone Depleting Substances (Regulation and Control) Rules have been laid down for the regulation of production and consumption of ozone depleting substances.

2001 - The Batteries (Management and Handling) Rules, 2001 rules shall apply to every manufacturer, importer, re-conditioner, assembler, dealer, auctioneer, consumer and bulk consumer involved in the manufacture, processing, sale, purchase and use of batteries or components so as to regulate and ensure the environmentally safe disposal of uses batteries.

2**002 - The Noise Pollution (Regulation and Control) (Amendment)** Rules lay down such terms and conditions as are necessary to reduce noise pollution, permit use of loud speaker or public address systems during night hours (between 10:00 p.m. to 12:00 midnight) on or during and cultural or religious festive occasion.

2002 The Biological Diversity Act is an act to provide for the conservation of biological diversity, sustainable use of its components, and fair and equitable sharing of the benefits arising out of the use of biological resources and acknowledge associated with it.

Forest and wildlife -

1927 - The Indian Forest Act and Amendment, 1984, is one of the many surviving colonial statues. It was enacted to consolidate the law related to forest, the transit of forest produce and the duty leviable on timber and other forest produce.

1972 - The Wildlife Protection ct, 1973 and Amendment 1991 provides for the protection of birds and animals and for all matters that are connected to it whether it be their hebitate or the waterhole or the forests that sustain them.

1980 - The Forest (Conservation) Act and Rules, 1981, provides for the protection of and the conservation of the forests.

Water -

1882 - The Easement Act allows private rights to use a resource that is, groundwater, by viewing it as an attachment to the land. It also states that all surface water belongs to the state and is a state property.

1897 - The Indian FIsheries Act establishes two sets of penal offences whereby the government can sue any person who uses dynamite or other explosive substance in any way (whether coastal or inland) with intent to catch or destroy any fish or poisonous fish in order to kill.

1956 - The River Boards Act enables the states to enroll the central government in setting up an Advisory River Board to resolve issues in inter-state cooperation.

1970 - The Merchant Shipping Act aims to deal with waste arising from ships along the costal areas within a specified radious.

1974 - The Water (Prevention and Control of Pollution) Act establishes an institutional structures for preventing and abating water pollution. It establishes standards for water quality and effluent. Polluting industries must seek permission to discharge waste into effluent bodies. The CPCB (Central Pollution Control Board) was constituted under this act.

1977 - The Water (Prevention and Control of Pollution) Cess Act provides for the levy and collection of cess or fees on water consuming industries and local authorities.

1978 - The Water (Prevention and Control of Pollution) Cess Rules contains the standard definitions and indicate the kind of and location of meters that every consumer of water is required to affix.

1991 - The Coastal Regulation Zone Notification puts regulations on various activities, including construction, are regulated. It gives some protection to the backwaters and estuaries.

Air

1948 - The Factories Act and Amendment in 1987 was the first to express concern for the working environment of the workers. The amendment of 1987 has sharpened its environmental focus and expanded its application to hazardous processes.

1981 - The Air (Prevention and Control of Pollution) Act provides for the control and abatement of air pollution. It entrusts the power of enforcing this act to the CPCB.

1982 - The Air (Prevention and Control of Pollution) Rules defines the procedures of the meetings of the Boards and the powers entrusted to them.

1982 - The Atomic Energy Act deals with the radioactive waste.

1987 - The Air (Prevention and Control of Pollution) Amendment Act empowers the central and state pollution control boards to meet with trave emergencies of air pollution.

1988 - The Motor Vehicles Act states that all hazardous waste is to be properly packaged, labelled and transported.

References :-

1. Agarwal, A., Copora, R. and Sharma, K. (1996), 'The State of India's Environment : A Citizen's Report, Centre for Science and Environment, New Delhi, p. 175-183.
2. Agarwal, A. (1985), 'Human-Nature Interactions in a Third World Country' (The Fifth World Conservation Lecture), Centre for Science and Environment, New Delhi, p- 1-19.
3. Menon, M.G.K. (1991), Coping with global environmental change : The role of science and democracy Education, 8(2), 4-8.
4. Salter, J.R. (1997). Environmental legislation and regulation. Asia Pacific Tech Monitor, 14(2), 37-41.
5. Environmental policy-making in India - The process and its pressure, TERI report.
6. Indian Environmental Legislations, list from the MOEF web site.
7. Strengthening Environmental Legislations in India, document by Centre for Environmental Law, WWF.

****

National Commission For Scheduled Caste - An Overview

Poorva Jadhav *

Introduction - The framers of the Constitution took note of the fact that certain castes, races or tribes in the country, who occupy the lowest rank in the ritual hierarchy of Indian society, were suffering from extreme social, educational and economic backwardness arising out of age-old practice of untouchability, lack of infrastructure facilities and geographical isolation, and who need special consideration for safeguarding their interests and for their accelerated socio-economic development. These communities were notified as Scheduled Castes as per provisions contained in Clause 1 of Articles 341 and 342 of the Constitution and have been defined under clause 24 of Article 366 of the Constitution of India. Since Independence, several strategies for sustainable development have been evolved and during last ten Five Years Plan several programmes and schemes have been implemented with a view to bring the Scheduled Castes in the mainstream of the Indian Society. For effective implementation of various safeguards provided in the Constitution for the SCs and various other protective legislations, the Constitution provided for appointment of a Special Officer under Article 338 of the Constitution. The Special Officer who was called as Commissioner for SCs & STs was assigned the duty to monitor and investigate all matters relating to the safeguards for SCs and STs in various statutes and to report to the President upon the working of these safeguards. The First National Commission for Scheduled Castes was constituted with Shri Suraj Bhan, Chairperson Fakirbhai Vaghela, Vice-Chairperson Phool Chand Verma, Member V. Devendra, Member and Smt. Surekha Lambture as Members.

Origin of National Commission for Scheduled Castes - Special provisions have been made in the Constitution with a view to providing safeguards against the exploitation of Scheduled Castes and to promote and protect their social, educational, economic and cultural interests. For effective implementation of various safeguards provided in the Constitution for the Scheduled Castes and various other protective legislations, the Constitution had provided for appointment of a Special Officer under Article 338 of the Constitution. The Special Officer appointed on 18th November, 1950 and designated as Commissioner for Scheduled Castes was assigned the duty to investigate all matters relating to the safeguards for Scheduled Castes in various statutes and to report to the President upon the working of these safeguards. On persistent demand of the Members of Parliament that the Office of the Commissioner for Scheduled Castes alone was not enough to monitor the implementation of Constitutional safeguards, a proposal was moved for amendment of Article 338 of the Constitution (46th Amendment) for replacing the arrangement of one Member system with a Multi-Member system. While the amendment to Article 338 was still under consideration, the Government decided to set up a Multi-Member Commission through an administrative decision vide Ministry of Home Affairs' Resolution. The first Commission for Scheduled Castes was, therefore, set up in August, 1978. The functions of the Commission for Scheduled Castes broadly corresponded with those of the Commissioner for Scheduled Castes.

Nature and effect of NCSC - The Committee note that the National Commission for Scheduled Castes has been vested with the duty to inter alia investigate all matters relating to the safeguards provided to SCs and to enquire into specific complaints with respect to the deprivation of rights and safeguards of the SCs. The Committee further note that while investigating such matters, or making inquiry in specific complaints, powers of a civil court, trying a suit, have been given to NCSC under clause (8) of the Article 338 of the Constitution. The Committee, however, note that the role of NCSC as a civil court is limited to that of summoning and enforcing attendance of any person, call for production of any document and examine evidence on affidavits but has no judicial power as other civil courts have. The Committee also note that the recommendations made by the Commission are referred to the concerned Central Ministries/ Departments/State Governments for taking appropriate action on the recommendations but these are not binding upon them to implement those recommendations. The role of Commission as an advisory body has been stressed by the Secretary of the Ministry and admitted by the Secretary, NCSC. The verdict delivered by the Supreme Court in case of All India Indian Overseas Bank Scheduled Castes and Scheduled Tribes Employees Welfare Association and others Vs. Union of India and others had justified the view of the Delhi High Court that the Commission lacks the power to issue interim order. In such a situation, the Committee are of the view that the Commission has been placed in a peculiar position as on the one hand the Commission has

*Student, Batch11, Hidayatullah National Law University, Raipur (C.G.) INDIA

been given powers to investigate matters as a civil court but on the other hand its recommendations are treated as only advisory in nature. The Committee feel that NCSC has not been treated as a separate constitutional entity capable of functioning effectively for the betterment of the SCs. It is also interesting to note that the verdict of Supreme Court had come in 1996 and it was against the erstwhile NCSCST when it was not bifurcated. The Committee would like to know whether this aspect was examined when Article 338 was being amended to have separate Commissions for SCs and STs, and if so, necessary amendments should have been suitably incorporated in the Constitution (Eighty Ninth Amendment) Act, 2003 when it was being brought. The Committee note that the Commission has been taking up the matter from time to time for giving more effective powers to it. The Committee strongly recommend that if necessary, the Constitution should be amended to provide greater powers to the Commission so as to enable it to act as an effective and independent organisation.

Publicity about the work of National Commission of Scheduled Caste - The Committee note that NCSC has published some leaflets for handling atrocities cases. They have also brought out monthly magazine namely "Anusuchit Jati Vani" and published a booklet on RTI and Yellow Hand Book giving the information/data. They have also launched their web-site more than one year ago and established a Toll Free Telephone number. The Committee further note that the information is available in Hindi and English and wherever possible the State Offices of the Commission translate the same in the regional language. The Committee strongly recommend that the material should be made available at all times in regional laungages for wider dissemination. The Committee note that information about the Commission reaches the Scheduled Castes population through press conferences with print and electronic media which is not enough. Many Scheduled Caste people are still living in remote areas where the media cannot reach; they cannot read or write and are still in dark about their rights and the safeguards available to them. The Committee would, therefore, recommend that NCSC should send teams to remote areas not only to monitor and evaluate the working of safeguard physically but also to create an increased level of awareness among SCs.

Conclusion - The Committee under Article 338 of the Constitution, a Special Officer who was designated as Commissioner for SCs and STs was assigned the duty to investigate all matters relating to the safeguards for SCs and STs in various statutes. The Office of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes alone was not enough to monitor the implementation of constitutional safeguards, a proposal was moved for amendment of Article 338 under the Constitution (46th Amendment) for replacing the arrangement of one member system with a multi-member system. The first Commission for SCs and STs was set up in August, 1978 through an administrative decision vide Ministry of Home Affairs Resolution. The functions of this multi-member Commission were modified in 1987 and the Commission for SCs and STs was renamed as the National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The Committee, however, note that the first statutory National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes under the Constitution (Sixty-fifth Amendment) Act was constituted only on 12.03.1992, replacing the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Article 338 was amended to create National Commission for Scheduled Castes and Article 338A was inserted to create National Commission for Scheduled Tribes. Thus the erstwhile National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes was bifurcated into two different Commissions.

References :-

1. www.ncsc.nic.in.,Annual report of NCSC 2004 - 05. Ch-4, Educational Development of Schedule Castes.
2. http://www.jstor.org/stable/3520173, Pandey, Balaji. Development among Scheduled Castes. Vol. 14, No. 2/3 (Feb.- Mar.,1986), pp.59 - 68.
3. http://www.jstor.org ., Jenkins, Robert. Cheif Planning Section and Eimar Barrr, Deupty Director, Programmes UNICEF India.73 Lodhi Estate New Delhi, India- 100013. Social Exclusion of Scheduled Caste in India, Draft Oct. 5, 2006.

****

Relationship Between Teachers' Trust In Principal And Teacher Burnout

Luxmi Nagar *

Abstract - Progress and advancement of a nation depends upon the quality of education. The role of the principal and teachers is the pivot role in the system of education and the success of the school depends entirely on them. The purpose was to relationship between teachers' trust in principal and teacher burnout by taking 100 teachers from 10 public schools of Faridabad and used by Omnibus T- scale by Hog and Tschanne- Moran(2000) for measuring teachers' trust and Maslach Burnout inventory by Maslach and Jackson(1981) . The study revealed that there is a significant relationship between teachers' trust in principal and teacher burnout.

Key Words - Teachers' Trust, Principal, Teacher Burnout and public schools.

Introduction - Since time immemorial teaching is acknowledged as a prosperous and respectable profession. Teacher is the foundation stone in any system of education. S/he is the spiritual and intellectual father who leads the students from darkness of ignorance to the light of knowledge, understanding and helps to keep the lamp of civilization burning. In this connection Crow and Crow rightly said, "A good teacher and qualities of his teaching have always been of paramount to a free man and the society."

Teachers' burnout refer, as burnout in other profession, to a decline in well being i.e. cause by chronic stress in the work situation and is generally considered as multi-dimensional syndrome. Several work and organizational characteristics – workoad, time pressure, role conflict and role ambiguity have shown positive association with burnout whereas participation in decision making autonomy and social support from supervisors negatively related with burnout. Apart from these factors, role of the head or principal of the institute cannot be ignored. Principals played a significant role in teachers' burnout. Principal found everywhere – behind the desk, at Parent- teacher Association meetings in halls, stair ways, in and out of the class, school board question them, supervisor watch them, teacher plaque them, students respect and scared of them. Sabo and Hoy contend that the effective school principals are actively engaged in the organizational life of the school and support the faculty. They argued that in schools with supportive environment teachers developed harmonious, open professional relations with their colleagues come to trust the principal and finally each other. It is an atmoshphere of openness that leads to trust and cooperation among colleagues and the principal, which ultimately promotes effective schools.

Justification Of The Study - Developing trusting relationship and reducing teacher burnout are two pressing issues that principals and superintendents confront on a daily basis in public schools. Although much has been written about school reforms in the past decade, but insufficient attention has been given to the important relationships among the adults within the school which may prove helpful in reducing burnout of teachers. Evidences in teachers' burnout in relation to their trust specifically in principal are scanty in nature. After reviewing the literature a need to study the relationship between teachers' trust and teacher burnout arises. Although some studies have conducted abroad in this field, but evidences in Indian context are very few.

With the increasing demand of state mandate testing no child left behind and improving standard for all students, principals and superintendent need to understand the relationship between the factors that influence student performance and positive learning environment.

Objectives -

1. To study the male and female teachers burn out in relation to their trust in principal.
2. To study the different age group teachers trust in principal in relation to their burnout.
3. To study the relationship between different teaching experience group teachers burnout in relation to their trust in principal.
4. To study the relationship between teachers' trust in principal and teachers burnout.

Hypotheses -

1. There exists no significant relationship between male and female teachers burnout in relation to their trust in principal.
2. There exists no significant relationship among different age group teachers' trust in principal in relation to their burnout.
3. There exists no significant relationship among different teaching experience group teachers' burnout in relation

* **Assistant Professor, Dehat Vikas Institute of Education and Technology, Tigaon, Faridabad (Haryana) INDIA**

to their trust in principal.

4. There exists no significant relationship between teachers' trust in principal and teachers' burnout.

Methodology - The descriptive survey method was employed.

Sample - A purposive sampling technique was applied to select the schools whereas subjects were selected by the technique of random sampling. Teachers of public schools constitute the population of the study. A sample of 100 teachers was drawn from 10 public schools of Faridabad district.

Tools Used -

1. Omnibus T – Scale by Hog and Moran (2002) for measuring teachers' trust.
2. Maslach Burnout Inventory (MBI) by Maslach and Jackson (1981).

Statistical Technique Used

Pearson's Product Moment correlation was used for analysis of data .

Table 1

Correlation between Teachers' Trust in Principal scores (A) and Teacher Burnout scores (B) of Male and Female Teachers

Teacher Gender

Female(N=50)			Male(50)	
Group	A	B	A	B
A	1	-0.4**	1	-0.56**
B	-0.4**	1	-0.56**	1

** Significant at .01 level

It can be observed from the table 1 that the calculated r value of female and male teachers' trust in principal in relation to their burnout are -0.4 and -0.56 respectively. These values are significant at 0.01 level of significance. Therefore, the hypotheses that there is no significant relationship between male and female teachers burnout in relation to their trust in principal is rejected. Although both the group displayed significant correlation but male group appeared to have a slightly higher correlation than their female counterpart.

Table 2 (See in the last page)

It is evident from the table 2, the Pearson Product Moment correlation is -0.5 for teachers less than 30 years of age and -0.57 for teachers 30-40 years of age. These are significant at 0.01 levels. For the teacher, 41 years and above the age, correlation is -0.59 which is significant at 0.05 level (due to small sample size). Therefore, the hypotheses that there is no significant relationship among different age group teachers' trust in principal in relation to their burnout is rejected. It implies that the age of the teacher does not appear to affect the teacher trust – burnout relationship much at all if any.

Table 3 (See in the last page)

This table highlights correlation between teachers' trust in principal and teacher burnout differs by teacher's experience. The correlation among trust and burnout by teaching experience is -0.36 for teachers with 1to years 10 years experience and is -0.59 for the teachers with 11 or more experience. The correlations are significant at the 0.01 level of significance for both the group of teachers. Therefore, the hypotheses that there is no significant relationship among different teaching experience group teachers' burnout in relation to their trust in principal is rejected.

In this study teaching experience moderately affects the teacher trust – burnout relationship. In addition, this effect appears to slightly stronger with increase in teacher's experience.

Table 4

Correlation between Teachers' Trust in Principal scores (A) and Teacher Burnout scores (B)

N	Groups	A	B	Level of significance
100	A	1.00	-0.94	Significant at
100	B	-0.94	1.00	0.01 level

It can be observed from the table 4 that the calculated 'r' value is -0.94 which is significant at 0.01 level of significance. Therefore the hypothesis that there is no significant relationship between teachers' trust in principal and teachers' burnout is rejected. Negative correlation indicates that when there is high trust in principal there exist cordial relationship between teacher and principal.

The result of present study is supported by the findings of the studies conducted earlier by the researchers Tarter, Bliss and Hoy (1989) and Ceyanes (2004). Al these studies inferred that principal's support lessen the teacher burnout. The reason behind this may be good understanding between teachers and principal, openness, support to solve the educational problems, participation in decision making, emotional support, greater predictability, improved communications, dependability, confidence and willingness to listen.

Educational Implications - The findings of the present study have important implications for the teachers, principals and superintendents or supervisors in the educational system. These are as follows -

1. Principals must be willing to create and maintain positive working relationships with their teachers. Principals must be open, honest, benevolent, truthful, use power wisely, make sensible decisions, promote curriculum and professional growth, be confident, empowering teachers and encourage them to trust their principal. In order to create positive learning environment for all constituents, principal must always remember that trust is the foundation for any relationship and without trust; the relationship will struggle, if not fail. If principal do not actively develop trusting relationship with their teachers they will be at risk for creating working environment where teachers are burned out and less productive.
2. The study has the implications for the teachers also. Teachers build trust with their principals when they demonstrate commitment to their students and students learning needs. So teachers need to demonstrate sincerity and honesty towards students. Teachers must be loyal, supportive and rationale, be friendly and

cheerful. Then they will be able to influence students in a positive way that encourages them to grow and learn as independent thinkers.

3. This study has some practical and theoretical implications. Its results are significant for educational institutions. Education moulds the character of the society. In order to have proper growth and development of schools which are miniature of society, superintendents have an obligation to insist that their principals spend time on developing trusting relationship with their teachers. Superintendents should require yearly professional development activities that promote "team building" and foster "relationship building". Superintendents must continually remind the principals that relationships with teachers can be building blocks for a successful school system.
4. Universities and colleges of educations must integrate the importance of developing relationships in school into the curriculum for their students, teachers and aspiring principals. With the basic element of successful relationship being trust, teacher and administration certification program should include this topic in curriculum and classroom activities.

References:-

1. **Cayanes W.J. (2004).** An analysis between teacher trust in principal and teacher burnout as identified by teachers in selected Texas public schools. Ph.D thesis, Texas: A & M University.
2. **Bryk, A.S. & Schneider, B. (2003).** Trust in schools: A core resource for school reform. Educational Leadership, 40-44.
3. **Cherniss and Ccary (1998).** Observed supervisory behaviour and teacher burnout in special education. Exceptional Childern, Vol. 54, PP.449-454.
4. **Tschannen-Moran, M & Hoy, W. K. (2000).** A multidisciplinary analysis of the nature, meaning, and measurement of trust. Review of Educational Research, 70(4), 547-593.
5. **Dash N. (1999).** A study of organizational climate of the school in relation to teachers' attitude towards instructional management behaviour of principals. M. Phil Dissertation, Kurukshetra University, Kurukshetra
6. **Walker, J.C (1997).** The relationship between social support and professional burnout among public secondary school teachers in North – East Tennessee. Dissertation Abstract International, section A: Humanities and social sciences
7. **Tarter, C.J., Bliss, J., & Hoy, W.K. (1989).** School characteristics and faculty trust in secondary schools. Educational Administration Quarterly, 25, 294-308.
8. **Shapiro, B.L (1987).** The relationship of teacher burnout to individual and environmental variables. Dissertation Abstracts International, Vol. 48(5), pp. 1157 A

Table 2

Correlation between Teachers' Trust in Principal scores (A) and Teacher Burnout scores (B) among different Age group Teachers.

Variables	Less than 30 yrs (N=39)		30-40yrs (N=41)		40 yrs and above (N=15)	
	A	B	A	B	A	B
A	1	-0.5**	1	-0.57**	1	-0.59*
B	-0.5**	1	-0.57**	1	-0.59*	1

*Significant at .05 level** Significant at .01 level

Table 3

Significance of relationship among different Teaching Experience Group Teachers Burnout (B) in relation to their Trust in Principals (A)

Variable	1 to10 yrs (N=68)		11 yrs and above (N=32)	
	A	B	A	B
A	1	-0.36**	1	-0.59**
B	-0.36**	1	-0.59**	1

** Significant at .01 level

****

Study Habits Of XI Standard Of Arts, Commerce And Science Students

Suman * Dr. Satish Gill **

Abstract - The objectives of the present investigation is the compare between the study habits of Government Senior Secondary students belonging to Art, Commerce and science streams. Samplings were selected through random sampling techniques. Data was collected with the help of Study Habit Inventory constructed and developed by Pasane and Sharma's from 100 senior secondary school students from in and around Faridabad division of Haryana State. By the application of mean, standard deviation, and t-test indicated is no significant difference no significant difference in Study Habits of Government Senior secondary students belonging to Arts, Commerce and Science streams.
Key Words - Study Habits, Arts, Commerce and Science streams ,and Government Senior Secondary students.

Introduction - One individual may differ from another in term of knowledge due to environmental and genetic factors. Study habit is the study of attitude of students to study in systematic or disorganized way. Study habit of students may differ from sex to sex, region to region and person to person. Actually good habits occupy a central role in acquisition of facts, figure , concepts, knowledge, skills attitude, creativity etc .Learning is not contented with sheer creation of habits but rather than forming better habits for better growth and development of students own inner power of knowledge , understanding, analysis, synthesis and evaluation of happenings. In order to study efficiently, students should not mere be interested in the study but must have knowledge of modern and efficient method of study. Study habits are voluntary activity also depends upon attitude, temperament and cooperation of parents, attitude of teachers, attitude of students, educational culture as well as availability of learning material. Since study habit is a voluntary activity, therefore, it can be improved by providing better educational environment to the students.

Objective -

- To compare between the study habits of Government Senior Secondary students belonging to Art, Commerce and science streams.

Hypotheses -

- There is no significant difference in Study Habits of Government Senior secondary students belonging to Arts, Commerce and Science streams.

Sample - A random sampling technique was used to collect data from urban and countryside students of male and female sex. Target students were 50 girls and 50 boys (total 100) students of 11 class of Senior Secondary School students of Fridabad city.

Tool Used - Study Habit Inventory constructed and developed by Pasane and Sharma (2012) was used to collect data and scoring.

Statistical Techniques - Mean, Standard Deviation and t-ratio technique were used to analyze the data.

Table - 1 (See in the next page)

Table 1 shows the t-value 0.067, 0.652 and 0.600 which significant levels at 0.01 and 0.05 are not significance .So, the hypotheses is accepted. It indicates that senior secondary level of male and female students of Art stream differ significantly in their total study habits since the mean scores of male students was higher than that of the female students of art stream. It may be said that overall study habits of male students were better than that of female students of Arts streams Whereas the senior secondary level of male and female students of commerce stream differ significantly in their total study habits since the mean scores of female students was higher than that of the male students of commerce stream. It may be said that overall study habits of female students were better than that of male students of commerce stream. Which the senior secondary level of male and female students of Science stream differ significantly in their total study habits since the mean scores of female students was higher than that of the male students of Science stream. It may be said that overall study habits of female students were better than that of male students of science streams.

Table: 2 (See in the next page)

Male - Table 2 shows the t-value 0.1610, 0.344, and 0.630 which significant levels at 0.01 and 0.05 are not significance .So, the hypotheses is accepted.. It indicates that senior secondary school male students of Arts and Commerce streams do not differ significantly in their total study habits since the mean scores of male arts student was higher than that of Commerce students. It may be said that overall study habits of arts student were better than that of male students of commerce streams. Whereas the senior secondary level male students of arts and science streams do not do not differ significantly in their total study habits

*ResearchScholar, Shiv College of Education Tigaon, Faridabad (Haryana) INDIA
**Associate Professor, Shiv College of Education Tigaon, Faridabad (Haryana) INDIA

since the mean scores of male arts students was higher than that of Science students. It may be said that overall study habits of arts students were better than that of male students of Science streams. Which the senior secondary school male students of Commerce and Science streams do not differ significantly in their total study habits since the mean scores of male Science students was higher than that of commerce students. It may be said that overall study habits of Science students were better than that of male students of Commerce streams.

Female - Table 2 shows the t-value 0.402, 0.756, and 0.626 which significant levels at 0.01 and 0.05 are not significance .So, the hypotheses is accepted.. It indicates that senior secondary school female students of Arts and Commerce streams do not do not differ significantly in their total study habits since the mean scores of female Commerce students was higher than that of Arts students. It may be said that overall study habits of commerce students were better than that of female students of Art streams. Whereas the senior secondary school's female students of Arts and Science streams do not differ significantly in their total study habits since the mean scores of female Science students was higher than that of art students. It may be said that overall study habits of Science students were better than that of female students of arts stream. Which the senior secondary school female students of commerce and science stream do not differ significantly in their total study habits since the mean scores of female Science students was higher than that of commerce students. It may be said that overall study habits of science students were better than that of female students of commerce stream.

References :-

1. Pasane and Sharma (2012) : Manual of study Habit Inventory, National Psychological Corporation, Agra.
2. Best J.W. & Kahn, J.V (2005): "Research in Education", Prentice Hall of India, New Delhi
3. Kale, Vanita (2011): "Study habits of the Secondary and Higher Secondary School students ", Edutracks, vol. 10 – No.p 10.
4. Shital S. Salve(2014): "Study Habits of XI standard Arts, Science and Commerce Student", Edutracks ,Vol. 14 – No. 2 , pp 37 - 40
5. Promila (2014)" Study habits of Senior Secondary School Students in relation to Gender and academic stream" Edutrack,Vol.8,No.1.
6. Jaban,Q.,(1985): "Study Habits of students of Science, Arts and Commerce at the Higher Secondary Level of education in relation to their Academic Achievement" Indian Educational. Rev.,23, pp89-93
7. Khan ,Saifullah (2014): A Study of Differences in Study Habits of Students in Relation to Area and Sex International Journal of Combined Research & Development (IJCRD) ,Vol.: 2; Issue, 5.pp 59-64.
8. E – Sources -
   (a) www.educationcorner.com
   (b) www.termpaperwarehouse.co

Table - 1

Significance of difference between Mean scores of total study habits in respect of Senior Secondary school students of male and female Arts, Commerce and Science streams.

Sr. No.	Category	Respondents	No.	Mean	S.D.	SED	't'Value
1.	Art	Male	15	49.33	7.28	7.535	0.067
		Female	15	45.13	6.50		
2.	Commerce	Male	15	46.13	7.19	7.224	0.652
		Female	15	47.40	8.01		
3.	Science	Male	15	47.4	7.13	14.632	0.600
		Female	15	48.6	5.88		

Table - 2

Significance of difference between Mean scores of total study habits in respect of senior secondary school students of male students of Arts, Commerce, and Science streams

Sr. No.	Respondents	Category	No.	Mean	S.D.	SED	't'Value
1.	Male	Art	15	49.33	7.28	6.90	0.161
		Commerce	15	46.13	7.19		
		Art	15	49.33	7.28	7.55	0.344
		Science	15	47.40	7.13		
		Commerce	15	46.13	7.19	7.430	0.630
		Science	15	47.4	7.13		
2.	Female	Art	15	45.13	6.50	6.330	0.402
		Commerce	15	47.4	8.01		
		Art	15	45.13	6.50	6.715	0.756
		Science	15	48.6	5.88		
		Commerce	15	15	47.4	6.108	0.626
		Science	15	48.6	5.88		

DSS Divya Shodh Samiksha (An International Refereed Research Journal) Oct. to December 2015
ISSN 2394-3807, E-ISSN 2394-3513, Imapct Factor - 0.745 (2014)

Ancient, Medieval and Modern Education : A Comparison

Sangeeta Vashisth *

Abstract - There is a wide gap between Ancient, Medieval Indian Education and Modern Education. Still there are several elements of ancient education which can find room in modern education both in theory and practice. But the medieval or Islamic education was based on the principles and teachings in Holy Quran. Akbar lifted up those reforms to the maximum points. He opened admissions to Hindu students and founded a new religion called Din-Ilahi, fusing the fine principles and teachings of the Islam and Hinduism.

Introduction - In Vedic age students used to lead a simple and sober life. Nowadays the life style of young general ions has altogether changed. They like to lead luxurious and majestic life, full of fashion and show. They have give up the principle of 'simple living and High Thinking' and adopted its reverse principle i.e. High Living and Simple Thinking**.** In present time the balance of the life is disturbed. They must realize the importance of ancient life style to make their life healthy and smooth.

The medieval or Islamic education was based on the principles and teachings in Holy Quran. Akbar lifted up those reforms to the maximum points. He opened admissions to Hindu students and founded a new religion called Din-Ilahi, fusing the fine principles and teachings of the Islam and Hinduism.

We are living in modern age but we feel proud of civilization and cultural heritage of our ancestors. Spiritualism, character, and philosophy are more important to us in comparison to wealth, materialism and science. We still believe in idealism and wish to lead and ideal life. The ancient schools followed the principle of education for self sufficiency. The school of that time was like integrated community which was self sufficient in every way. Education was free and universal. The fee was to be paid, after attaining, education from the earning of the young man who got education in the form of **'**Guru Dakshina'**.** The students did not pay for their residence. After independence, according to our constitution it is the duty of the government to provide free education to every child of 0-14 yrs age group. Many programs were started but still desired objective has not been achieved. Therefore Vedic education has its great significance in Modern age.

(1) Education of Vedic Period - The study of Vedas aimed at the all-round development of the potentialities of the individual. The Vedic system of education aimed at leading the individual from the darkness of ignorance to the light of knowledge. Spiritual, physical, moral and character development was also considered. The students could develop not only their spiritual qualities but also their vocational proficiency. For attaining salvation, the importance was laid on attention, concentration and yoga. The aims of Vedic education can be Self realization- all-round development of personality, formation of character, vocational development, infusion of a spirit of piety and religiousness, inculcation of civic and social sense and promotion of social efficiency, and preservation and transmission of national culture

Curriculum - The beginning of education was marked by the 'Upanayana' a ceremony which was generally performed at a prescribed age level. The education of that system was not only theoretical but related to the realities of life. The curriculum was bagged with various branches of learning. Mainly Philosophy, Grammar, Astrology and Logic were taught. In the teaching of languages, proper pronunciation and grammar were given due importance. Along with theory, practical aspects of education were mainly focused.

The pupils' residence in teachers' house helped them to develop social contacts. The student's life was considered as the laboratory for the educational experimentation. For the social development, the pupils, residing in the house of the Gurus, begging alms for their own subsistence and also for the preceptor. Noble sentiments of humanitarian virtues were developed in the pupils by the practice of begging alms. The main aim behind this system was to sublimate the unruly passions and ego in the pupils, which enabled them to face the realities of life and helped in social integration.

This practice was considered a concrete lesson in the development of virtue of self-help and the sense of gratitude and duty towards the society. Religious instruction was given much importance in the curriculum. Even Though the curriculum in vogue was essentially spiritual and religious in character, yet the material aspect was not ignored.

The content of education - The content of education in ancient Indian system of education was the four Vedas. The

* **Assistant Professor, Shiv College of Education, Tigaon, Faridabad (Haryana) INDIA**

Vedas and Vedangas (Shiksha, Chhandas, Vyakarna,Nirukta, Kalpa and Jyotisha) constituted the core curriculum of the Brahmin class. Archery, Horsemanship, Chariot race, swort fight and other arts of warfare were the special subjects of the Kshatriyas. Agriculture and trade were the main subjects of the Vysyas. Crafts Ayurveda, Bhutavidya etc. were also taught. Shudras were denied any kind of formal education. Their main work was to serve the upper class through menial work.

Method of Teaching - Sanskrit was the medium of instruction. The method of teaching Vedas was oral. The shishya listened to the recitation of Vedas by his Guru and repeated after him. The shishya learned this by imitation and repetition. Then they were helped to understand the meaning of what they have learnt through meditation. The teacher recited Vedic hymns, and the pupils listened and repeated. This was generally followed by discussion and contemplation. The classical methods of study consists of - Sravana (listening),Manana(reflection on their meaning), and Nidhidhyasana(constant meditation, realization and experience).

Teacher-Pupil Relationship - In this period, the child becomes a member of Guru's family in every respect. Guru becomes his spiritual father, and is held responsible for any drawback in his shishya. He used to advise them what to do, what to avoid, what to eat, when to sleep and so on. The guru was a model for him. The character of shishya is formed on this model. The guru did not accept fees or any rewards from his students. He used to nurse them when they felt sick. The shishyas used to contact his guru after leaving the gurukul and refresh their knowledge of the Vedas. Their relationship was life-long

(2) Education of Medieval Period - The important aim of education during Islamic period was spiritual. The study of Holy Quran was given top priority for Muslims. It was the aim of the life of Muslims "to spread the message of Holy Quran". It also aimed at the development of the moral life and character of individuals. Muslim rulers who ruled over India wanted to spread Islam and for this, education was used as a powerful instrument. They considered it as their religious duty. There is only one God that is Allah. The Muslims believed that Idol worship is a sin and Jehad against it is the sacred duty of every genuine Muslim. Muslim rulers made use of their educational policy to get the support of the people for a stable government. Propagation of Islam, the teachings and principles of Holy Quran, to spread the belief in only one God were the main aims of Islamic education.

Curriculum - The students in Medieval period are encouraged to seek both a broad historical and cultural knowledge as a whole and knowledge in depth of some important segments of it by taking appropriate courses and tutorials. To ensure breadth, students must take at least one Medieval/Renaissance class from the areas of Art, History/Music, Literature, and Philosophy/Religion. At least three classes or tutorials should be in one of these four areas in order to provide the student with a disciplinary "base." Students should also take at least two courses in related fields such as classical antiquity, early Judaism and Christianity, Byzantium, classical Islam or the 17th century, as well as at least three semesters of a foreign language. Normally, this will be Latin, but for some programs, at the sponsor's discretion, another language might be substituted.

The content of education - The content of primary education consisted of learning of 3R's, the last 13 chapters of Holy Quran, Persian, grammar etc. Higher education lasted for 10 to 12 years. Islamic education was mainly spiritual but secular subjects were also given important place in the curriculum. The content of religious education consisted of Holy Quran, interpretation of the Holy Quran, Muslim rules, theology etc. The content of secular education consisted of logic, Arabic, grammar, philosophy, law, astrology, arithmetic, history, geography, medicine (yunani) Persian etc.

The medium of instruction was Arabic and Persian. During the days of Aurangzeb, Urdu was the medium of instruction.

The method of teaching - The method of teaching was mainly oral. During the days of Akbar, writing was given great importance. Lecture method was followed in Madrassahs. Debates and discussions were conducted under the guidance of experts. Individual method or self study was also used. Sometimes, students were asked to learn certain portions of the text by themselves in solitude. Rote learning was always encouraged.

Women's education was not encouraged, especially the women of lower and middle strata of the society. But the princess and the girls of aristocratic families received education at home.

Nur Jahan and Mumtaz Mahal were scholars in Persian and Arabic languages. Purda system was also existed.

Teacher-Pupil Relationship - The teacher was known an Ustad, Sheik, Imam or Maulavi. The teacher was always held in high esteem in the society. They did not live together like the guru and shishya of the Vedic period. Strict discipline was enforced. Corporal punishment was common. In some Madrassahs, there were hostels and so the teacher and the taught lived under the same roof. Teacher-pupil relationship was not as good that in the former periods.

(3) Education of Modern Period - This period have various aims such as Knowledge (Knowledge explosion, knowledge can be a means to an end and not an end in itself), Character (Courage, strength, virtue, the ability to forget etc. good acts and habits are the basis of good character and therefore character formation is a continuous process from birth to death), Harmonious Development (Complete development of the personality), Vocational (Bread and Butter aim of education. Education prepares a child for a profession and enables him to earn his livelihood), Complete Living (Ways and means of leading a successful life), Religious And Spiritual (religious tolerance, communal harmony, ahimsa and peaceful co-existence in spiritual matters)., Moral (Cultivate socially desirable values courage - honesty and

patriotism in pupils for creating a morally soundman in children), Development of Culture(Communicated from one generation to another),Leisure (The advancement in science, technology and means of transport and communication has reduced time and space resulting in the increase of leisure hours), and Individual and Social(Develop the individuals according to their interests and capacities. It means the free growth of individuality, and education for social service and education for citizenship).

Curriculum - Principal of Utility, Principle of Interest, Practical of Experience and Principle of Integration are some of the modern principles of modern curriculum. So, in modern context, the curriculum should be flexible, dynamic and integrated which aids the developing child.

Content of education - In the modern period, content is divided into two stages-

1. At lower secondary stage -

A. For non-Hindi speaking areas, the study of three languages - The mother tongue or the regional language, Hindi at a higher or lower level, and English at a higher or lower level should be included.

B. For Hindi-speaking areas, the study of three languages -A modern Indian Language other than Hindi, Mathematics, Science History, Geography and Civics, Art, Work-experience and Social Service, Physical Education, and Education in Moral and Spiritual Values should be included.

2. At Higher Secondary Stage

A. Any two languages, including any modern Indian Languages, or modern foreign and classical language

B. Any two subjects from the following-An additional language, History, Geography, Economics, Logic,Psychology,Sociology,Art,Physics,Chemistry, Mathematics, Biology,Geology, and Home Science

C. Work experience and Social Service

D. Physical Education

E. Art and Craft

F. Education in moral and Spiritual Values.

Teaching Method - In the modern period, principles for teaching methods like Principle of Purposive Process of Learning, Principle of Learning by Doing and Principle of Integration are to be followed. This is because knowledge is one whole and this principle seeks to maintain unity in diversity. Thus, the method is most effective which brings about and employs this correlation and integration of all subjects, activities and experience.

Teacher-Pupil Relationship - In the modern times, the teacher is neither superfluous nor the supporting authority; he is friend, guide and counselor of the child. It is who educates the child in self-discipline and active participation.

References :-

1. Walia J.S., “Philosophical and Sociological Bases of Education”.
2. Sachdeva M.S., Hooda S.K. and Nivedita, “ Secondary Education & School Management”.
3. Thankachan T.C., “Philosophical and Sociological Bases of Education”.
4. Mishra Manju, “Education in Emerging Indian Society”.
5. Saxena Swaroop,” Philosophical and Sociological Foundations of Education”.
6. Education in the Vedic age, vnbhat.mht
7. Essay on Vedic Education Knowledge
8. Education in the Middle Ages, Middle Ages.mht

****

Continuous And Comprehensive Evaluation (CCE)

Bimlesh Yadav *

Abstract - Continuous and Comprehensive Evaluation is a key educational reform in assessment proposed by the Central Board of Secondary Education for primary and upper classes in CBSC affiliated schools. This article makes an attempt to analyze working and effectiveness of CCE and its impact on our education system .Continuous and comprehensive evaluation is about understanding the ways in which children learn, reflecting on the teaching- learning processes employed in schools and empowering both students and teachers in processes related to schooling.
Key words: Examination system, Continuous and comprehensive Evaluation, Formative and Summative assessment, National policy on Education, Teacher manual.

Introduction - Indian education system experiences a number of innovations before and after independence. Our educational system has improved from time to time according to social need and requirements and become one major manpower exporting country of the world. Our Government has attempted to evaluate the standard of Education so that it will be helpful in fulfilling the national objectives. National policy on Education (1986) pointed towards, this for the first time and recommended the implementation of Continuous and comprehensive evaluation in place of present examination system.

The concept of continuous and comprehensive evaluation: The concept of CCE had been embraced by Mr Kapil Sibal (former HRD minister) to decrease the accumulated stress of board exams on the students and to introduce a more uniform and comprehensive pattern in education for the children all over the nation from 2009 onwards. The process of education with CCE become interactive, communicative and collaborative and efforts that are required to meet the challenges of learning develop wonderfully with everlasting relationships in very short time.

Table1: The CCE Matrix

Subjects	**Overall Grades(FA and SA)**		
Part1:Academics perf -ormance: scholastic Areas Language1			
Language2			
Language 3			
Mathematics			
Science			
Social Science			
Additional Subject	Descriptive Descriptive Indicators		
Part 2: Co-scholastic Areas			
Life skills (10)			
Work education			
Visual and performing arts			
Attitudes(3) and values(10)			

Part 3:Co-Curricular Activities (any two)

Literary and creative skills/scientific skills ,information and communication technology/ organizational and leadership skills

Health and physical education			
Work education			
Visual and performing arts			

The scholastic domains are to be assessed on a five point scale, grades for which vary from A (4.1-5.0) to E (0-1.0). Formative assessments (FA) and Summative assessment(SA) are to be used for assessing the scholastic components. Under the scheme, formative assessment refers to using techniques like assignments, quizzes, projects, debates, elocution.Group discussion, etc., and summative assessment, refer to written, end of term exam, including both objective and short and long answer types.

A co-scholastic domains are to be assessed on a nine point scale, grades for which vary from A1-(91-100) through E2 (0-20).Each student has to be graded on each of the life skills, work education, visual and performing arts, three attitudes,10 values,2 Co curricular activities and any two health and physical education related activities.Each of these domains has descriptive indicators against which the students are to be continuously observed and allotted marks. An average then needs to be calculated by dividing the total score obtained by a student by the number of items in that

* **Assistant Professor, Shiv College of Education, Tigaon, Faridabad (Haryana) INDIA**

component. Finally, the average score in each domain is to be converted into its corresponding grade.

The CCE has been found to have a significant effect on both the scholastic areas, namely mathematics, Language and Environmental science, co-scholastic areas, namely, regularity, punctuality, discipline, cleanliness and co-curricular activities, presented in a tabular format.. Continuous and comprehensive evaluation is the most effective,most advanced and most used evaluation. As the name indicates it is an evaluation programme which is continuous as well as comprehensive i.e, it is carried throughout the academic sessions and it includes all the aspects of the teaching - learning process.

CCE does not label Children- CBSE manual cautions the teachers against labeling students as bright or dull. Schools shall diagnose learning difficulties through formative tests right from the beginning of the academic year and bring it to the notice of parents at appropriate intervals of time….Similarly, especially gifted children should be provided with further reinforcements by giving them additional assignments, enrichment material and mentoring.

Merits of Continuous And Comprehensive Evaluation

Reducing stress on students - Reduction of stress on students is also linked to the fact that under the RTE, no student can be detained till class viii. CCE reduces the pressure of memorizing textbooks for one big exam, it may encourage students to develop all aspects of their personality especially in the context of co-curricular areas,all spaces will now become public spaces and anytime may be a good time to observe and record student behavior.

Grades are Non-oppressive –Grades are attached to them in terms of marks and that is common knowledge to students as well.

Realistic Picture of Teaching-Learning-Process – Through CCE, a realistic picture of teaching learning process is drawn.The teachers, the students and the school management come to know the ground realities of the educational program.

Development of confidence among students –In CCE students are regularly evaluated , examined and tested. Due to this, they do not feel any fear or anxiety prior to test. This results in the development of confidence among students.

Reduction of work load on students – In CCE students progress is evaluated every weekend or every month. Thus ,their work load is reduced, they do not have to remember all the lessons again and again.

Interaction between students and Teachers – CCE provides lots of opportunities and chances for interaction between the students and Teachers. The teacher has to observe the students very closely if he wants to evaluate the student comprehensively.

Knowledge about the strengths and weakness of students – When they know his strength and weakness, he can work-hard to improve upon his weakness and further strengthen his strength.

Helpful in selecting Teaching Methods and Strategies: CCE is helpful for teachers also. They come to know about the effectiveness Thus,it helps the teachers in selecting the appropriate and effective teaching methods and strategies.

Helpful in Motivation: This approach,is also helpful in providing the students continous and effective motivaton. Whenever student show favourable results and behavior, they are motivated.

Promotion of real learning: CCE ,assess the modification of behavior of the student of each step. Thus ,it promotes the real learning.

Helpful in realizing aims and Objectives of Education: CCE programme provides a realistic picture of current situation of educational programme. The difficulties of the students are identified and remedial measures are suggested .Thus it help in realizing the aims and objectives of Education.

Demerits of Continuous and Comprehensive Evaluation:

Biasness on Part of Teacher: Sometimes the teachers gives more marks to their favourite students even if they don,t perform well and some good students get lower grades only because they have no cordial relations with teachers.

Subjective approach: The ideas, thoughts, philosophy and prejudices of the teacher have a direct influence on the outcome of this evaluation approach.

Time consuming: CCE goes on throughout academic sessions,this approach requires one complete year for evaluation of one complete year.

Not appropriate for crowded class: This approach is quite impractical when it is applied to crowded classes.In such classes,the teacher does not have enough time and opportunities to get in touch with all the students and evaluate them.

Needs Congenial Environment: CCE cannot be carried out in adverse Environment. For this type of evaluation ,congenial and conductive environment is needed.

Needs more Energy and Effort: CCE needs much more energy and efforts than the traditional examination approach.The teacher has to evaluate all the aspects,both scholastic and non-scholastic,of the students.

Needs Training for Proper Implementation: CCE can be done by properly trained Personnels. They are required to undergo a training programme before utilizing this evalution approach.

Reference :-

1. Personal survey.

✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻

विद्यार्थियों की उपलब्धि अभिप्रेरणा एवं अधिगम पर नवाचार उपागमों का प्रभाव

डॉ. सुगन शर्मा * इति व्यास **

शोध सारांश – शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष शिक्षण अभ्यास कार्यक्रम है, ऐसे में नवाचार मुक्त विधियों, प्रविधियों में नयी तकनीकी का प्रयोग जो संप्रेषण को गतिमान एवं अधिक ग्राह्य व रोचक बना सके ऐसी तकनीकी को प्रोत्साहित किया जाना आज की अहम आवश्यकता है। नवाचारों के माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया, विधियों एवं तकनीक में वांछित परिवर्तन लाये जा सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि एक ओर शिक्षण प्रक्रिया को सरल, सुगम और रूचिकर बनाया जा सकता है। वहीं दूसरी और शिक्षा के साथ तारतम्य रख शिक्षण को आनन्ददायी और सुग्राही बनाया जा सकता है।

प्रस्तावना – वैज्ञानिक एवं प्रतिस्पर्द्धा के युग में जीवन के प्रत्येक पक्ष में परिवर्तन की प्रक्रिया एक विश्वव्यापी आवश्यकता बन गई है। इस आवश्यकता ने मानव जीवन के सभी पक्षों को पर्याप्त सीमा तक प्रभावित करने के साथ, सर्वाधिक रूप में शिक्षा और शैक्षिक प्रक्रिया को प्रभावित किया है जो वर्तमान एवं भविष्य के मानव–जीवन और उसके उत्थान–विकास का महत्वपूर्ण पक्ष है।

आज तकनीकी युग है और कोई भी क्षेत्र इससे अछूता नहीं रह सकता। शिक्षा की गुणवत्ता तथा उसका राष्ट्र के विकास में योगदान प्रत्यक्ष शिक्षक से जुड़ा है। शिक्षक की गुणवत्ता शिक्षा पर निर्भर करती है।

शिक्षक शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष शिक्षण अभ्यास कार्यक्रम है, न पाठ–योजनाएं सही ढंग से संशोधित की जाती है न ही पर्यवेक्षण सही हो पाता है, यहां तक कि पाठ का प्रदर्शन भी मॉडल स्वरूप नहीं हो पाता, शिक्षण कार्य एक उबाउ प्रक्रिया बन कर रही गमी, ऐसे में नवाचार युक्त विधियों, प्रविधियों में नयी तकनीकी का प्रयोग जो संप्रेषण को, गतिमान एवं अधिक ग्राह्य व रोचक बना सके ऐसी तकनीकों को प्रोत्साहित किया जाना आज की अहम् आवश्यकता है।

शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक द्वारा किये गये नवीन प्रयास ही नवाचार की श्रेणी के आते हैं। इसके अन्तर्गत शिक्षण में सुधार शैक्षिक उन्नयन हेतु नवीन प्रयोग या कार्य पद्धति आदि सम्मिलित है। इन्हें खोजकर नियोजित तरीके से प्रयोग में लाने होते हैं। नवाचारों के माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया, विधियों एवं तकनीक में वांछित परिवर्तन लाये जा सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि एक ओर शिक्षण प्रक्रिया को सरल, सुगम और रूचिकर बनाया जा सकता है, वही दूसरी और शिक्षा के साथ तारतम्य रख शिक्षण को आनन्दायी और सुग्राही बनाया जा सकता है।

अध्यापक सीखने–सीखाने को नवीनतम विधियों की खोज करता है और अपने नवीन प्रयोगों एवं अनुभवों का उपयोग भिन्न–भिन्न युक्तियों के माध्यम से करता है, जो शिक्षक के अपनी रूचि, क्षमता व्यवहार एवं व्यक्तित्व पर आधारित होते है।

संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि नवाचार शिक्षण, शिक्षक के स्वयं के विचारों में अपना प्रयोग है, जिसमें वह अपने नवीन अनुभवों का प्रदर्शन करता है। वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये नवाचार उपागमों का प्रयोग कर शिक्षण को रूचिकर प्रभावी सुग्राह्य एवं स्थायी बनाता है।

समस्या का चयन – शोधार्थी द्वारा चयनित समस्या कथन इस प्रकार से है–

'विद्यार्थियों की उपलब्धि अभिप्रेरणा एवं अधिगम पर नवाचार उपागमों का प्रभाव'

पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या –

नवाचार – नवाचार शिक्षक के स्वयं के विचारों में अपना प्रयोग है, जिसमें वह अपने नवीन अनुभवों का प्रदर्शन करता है, वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये आवश्यक संसाधन जुटाते हुए शिक्षण को रूचिकर प्रभावी सुग्राह्यि एवं स्थायी बनाता है।

ई.एम. रोजर्स – 'नवाचार एक ऐसा विचार है, जिससे व्यक्ति को नवीनता की अनुभूति होती हैं।'

उपलब्धि अभिप्रेरणा – उपलब्धि अभिप्रेरणा से अर्थ एक ऐसी इच्छा शक्ति या प्रेरक से है, जो व्यक्ति को अधिक उच्च लक्ष्य प्राप्ति तथा दूसरों से अधिक उच्च लक्ष्य प्राप्ति तथा दूसरों से अधिक अच्छा कार्य करने की प्रेरणा देता है।

अधिगम – सामान्यत: अधिगम का अर्थ तथ्यों, जानकारी सूचनाओं की सम्प्राप्ति से लगाया जाता है। आजकल अधिगम को व्यवहार में परिवर्तन या व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना जाता है।

परिसीमन –

1. प्रस्तुत शोध कार्य उदयपुर (राज.) तक सीमित है।
2. प्रस्तुत शोध कार्य दो चर (उपलब्धि अभिप्रेरणा व अधिगम) लिये गये है।
3. इस शोध कार्य को माध्यमिक विद्यालय के कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों तक सीमित रखा गया है।

प्रस्तुत शोध में चयनित विद्यालयों में से न्यादर्श स्वरूप 60 विद्यार्थियों का चयन किया गया है।

उद्देश्य –

1. नवाचार उपागमों का प्रयोग करने से पूर्व विद्यार्थियों के उपलब्धि अभिप्रेरणा का पता लगाना।
2. नवाचार उपागमों का प्रयोग करने से पूर्व विद्यार्थियों के अधिगम का पता लगाना।

* प्राचार्या, विद्याभवन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, उदयपुर (राज.) भारत
** शोधार्थी, पेसिफिक विश्वविद्यालय, पहेर, उदयपुर (राज.) भारत

उप उद्देश्य –

1. नवाचार उपागमों के प्रभाव का अध्ययन करना।
2. नवाचार उपागमों का प्रयोग करने से पूर्व नियंत्रित एवं प्रायोगिक समूह की उपलब्धि अभिप्रेरणा का पता लगाना।
3. नवाचार उपागमों का प्रयोग करने से पूर्व नियंत्रित एवं प्रायोगिक समूह की अधिगम का पता लगाना।
4. नवाचार उपागमों का प्रयोग करने से पश्चात् नियंत्रित एवं प्रायोगिक समूह की उपलब्धि अभिप्रेरणा का पता लगाना।
5. नवाचार उपागमों का प्रयोग करने से पश्चात् नियंत्रित एवं प्रायोगिक समूह की अधिगम का पता लगाना।

परिकल्पनाएँ –

1. नवाचार उपागमों का प्रयोग करने से पूर्व नियंत्रित एवं प्रायोगिक समूह की उपलब्धि अभिप्रेरणा में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
2. नवाचार उपागमों का प्रयोग करने से पूर्व नियंत्रित एवं प्रायोगिक समूह की अधिगम में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
3. नवाचार उपागमों का प्रयोग करने के पश्चात् नियंत्रित एवं प्रायोगिक समूह की उपलब्धि अभिप्रेरणा में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
4. नवाचार उपागमों का प्रयोग करने के पश्चात् नियंत्रित एवं प्रायोगिक समूह की अधिगम में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

अध्ययन विधि – शोध कार्य में प्रयोगात्मक विधि का चुनाव किया गया है। अनुसंधित्सु द्वारा अपने शोध कार्य में निम्न विधियाँ काम में लेंगी – Tutorial Method, Peergroup Learning, Inquiry Based.

1. उदयपुर शहर के राजस्थान माध्यमिक विद्यालय का चयन किया गया।
2. इस विधि के अन्तर्गत चयनित विद्यालय से कक्षा 7 के विज्ञान विषय के 30–30 विद्यार्थियों के दो समूह बनाये गये।
3. प्रथम समूह पर परम्परागत शिक्षण विधि तथा द्वितीय समूह पर नवाचार उपागमों द्वारा शिक्षण कार्य करवाया गया।
4. दोनों समूहों में पूर्व परीक्षा तथा पश्च परीक्षा द्वारा परीक्षण कराकर उनकी तुलना की गई।

न्यादर्श का चयन –

1. इस अध्ययन में सोद्देश्य न्यादर्श का चयन किया गया है।
2. प्रस्तुत शोध में राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले के माध्यमिक विद्यालय का चयन किया गया।
3. चयनित विद्यालय में 30–30 विद्यार्थियों का चयन किया गया।

शोध उपकरण –

1. अधिगम के मापन हेतु स्वनिर्मित उपकरण।
2. उपलब्धि अभिप्रेरणा के मापन हेतु डॉ. वी.पी भार्गव द्वारा निर्मित मानकीकृत उपकरण।

अध्ययन में प्रयुक्त सांख्यिकी तकनीकी –

1. मध्यमान
2. मानक विचलन
3. टी–मान
4. सह–सम्बन्ध

परिणाम –

परिकल्पना – नियंत्रित समूह के पूर्व एवं पश्च उपलब्धि अभिप्रेरणा में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

Table1 - Control Group

Test	N	Mean	SD	t	Result
Pre	30	21.10	2.796	-0.954	NS
Post	30	21.77	2.738		

अत: प्रथम परिकल्पना स्वीकार की जाती है। अर्थात् नियन्त्रित समूह के पूर्व एवं पश्च उपलब्धि अभिप्रेरणा परीक्षण में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

परिकल्पना :– प्रायोगिक समूह के पूर्व एवं पश्च उपलब्धि अभिप्रेरणा में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

Table 2 - Experimental Group

Test	N	Mean	SD	t	Result
Pre	30	21.83	2.718	-2.468	*
Post	30	22.97	3.285		

अत: परिकल्पना प्रायोगिक समूह के पूर्व एवं पश्च उपलब्धि अभिप्रेरणा परीक्षण में कोई सार्थक अन्तर नहीं है को स्वीकार नहीं करती है। अर्थात् प्रायोगिक समूह के पूर्व एवं पश्च उपलब्धि अभिप्रेरणा में सार्थक अन्तर है।

परिकल्पना – नियन्त्रित समूह के पूर्व एवं पश्च अधिगम में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

Table 3 - Control Group

Test	N	Mean	SD	t	Result
Pre	30	21.30	2.562	-1.167	NS
Post	30	22.10	3.122		

नियन्त्रित समूह के पूर्व एवं पश्च अधिगम परीक्षण में सार्थक अन्तर नहीं है।

परिकल्पना – प्रायोगिक समूह के पूर्व एवं पश्च अधिगम में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

Table 4 - Experimental Group

Test	N	Mean	SD	t	Result
Pre	30	22.77	2.359	-2.576	*
Post	30	24.57	3.559		

प्रायोगिक समूह के पूर्व एवं पश्च अधिगम परीक्षण में सार्थक अन्तर है।

परिकल्पना :– नियन्त्रित व प्रायोगिक समूह के पूर्व उपलब्धि अभिप्रेरणा परीक्षण के तुलनात्मक अध्ययन में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

Table 5 - Pre Test

Test	N	Mean	SD	t	Result
Control	30	21.10	2.80	-1.030	NS
Experimental	30	21.83	2.72		

नियन्त्रित समूह व प्रायोगिक समूह के पूर्व उपलब्धि अभिप्रेरणा परीक्षण के तुलनात्मक अध्ययन में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

परिकल्पना – नियन्त्रित व प्रायोगिक समूह के पश्च उपलब्धि अभिप्रेरणा परीक्षण के तुलनात्मक अध्ययन में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

Table 6 - Post Test

Test	N	Mean	SD	t	Result
Control	30	21.77	2.74	-1.537	NS
Experimental	30	22.97	3.29		

नियन्त्रित समूह व प्रायोगिक समूह के पश्च उपलब्धि अभिप्रेरणा परीक्षण के तुलनात्मक अध्ययन में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

परिकल्पना – नियन्त्रित व प्रायोगिक समूह के पश्च अधिगम परीक्षण के तुलनात्मक अध्ययन में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

Table 7 - Post Test

Test	N	Mean	SD	t	Result
Control	30	22.10	3.12	-2.854	**
Experimental	30	24.57	3.56		

नियन्त्रित समूह व प्रायोगिक समूह के पश्च अधिगम परीक्षण में सार्थक अन्तर है।

निष्कर्ष – प्रस्तुत शोध कार्य की विवेचना से स्पष्ट है नवाचार उपागमों का विद्यालय शिक्षण में प्रयोग विद्यार्थियों पर स्पष्ट रूप से पड़ता है। तथा इनके प्रयोग से विद्यार्थियों की उपलब्धि अभिप्रेरणा एवं अधिगम स्तर को उच्च स्तर तक ले जाता है। तथा उनके अध्ययन में एक सुधार दिखाई देता है। विद्यार्थी स्वतन्त्र रूप से खोज करना सीखते हैं। स्वअधिगम की भावना का विकास होता है तथा विद्यार्थियों के सम्बन्धों में विकास होता है।

सुझाव –

1. विद्यार्थियों में अधिगम किस प्रकार अधिकतम हो इसके लिये नवीन शिक्षण विधियों से शिक्षण करवाना चाहिये।
2. विद्यार्थियों में अधिगम एवं अभिप्रेरणा विकसित करने के लिये विषय से सम्बन्धित अधिक से अधिक जानकारी हासिल करने के लिये प्रेरित करना चाहिए।
3. विद्यालय को समय के अनुसार नवीन शिक्षण विधियों का प्रयोग करने के लिये अध्ययन व छात्रों को प्रोत्साहित करना चाहिये।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :–

1. Adedeji Tella (2007) “The Impact of Motivation on Student’s Academic Achievement and Learning Outcomes in Mathematics Among Secondary School Students in Nigeria"
2. Dr. Darnadharan (2010) “Innovative Method of Teaching."
3. Jyoti Bhall (2011) “A Study of Factor Affecting the use Computer by the School Teacher in Teaching – Learning Process."
4. Annika Stelber (2012) “Organizational Innovations : A Conceptualization as how they are Created, Diffused and Sustained."
5. www.psychologia.org
6. www.lib.umd.edu.
7. www.dissertation.com

****

माध्यमिक स्तर के विकलांग बालक व बालिकाओं की शिक्षा के लिए किए गए शासकीय प्रयासों का मूल्यांकन (बुरहानपुर जिले के संदर्भ में)

राजेश कुमार मौर्य *

प्रस्तावना – अमेरिकन षिक्षा अध्ययन राष्ट्रीय परिषद ने असाधारण बालको को इस प्रकार परिभाषित किया है। 'असाधारण बालक वे है जो कि सामान्य बच्चो से शारीरिक, मानसिक संवेगात्मक या सामाजिक विशेषताओं में इतना अधिक अलग होते है कि अपनी उच्चतम योग्यता तक विकसित होने के लिये उन्हे विशेष शैक्षिक सेवाओं की आवष्यकता पडती है।'

क्रो एवं क्रो :– का कथन है कि अनोखा या असाधारण शद्ध ऐसे व्यक्ति (विशिष्ट बालक) के लिए प्रयोग किया जाता है।

विकलांग बालकों के प्रकार :–

सामान्य बालक			
मानसिक रूप से विचलित	सामाजिक रूप से विचलित	शैक्षिक रूप से भिन्न	शारीरिक रूप से भिन्न
प्रतिभाशाली बालक	सांवेगिक रूप से परेशान बालक	शैक्षिक रूप से समृद्ध	सांवेदिक रूप से विकलांग
सृजनात्मक बालक	असमायोजित बालक	शैक्षिक रूप से पिछड़ा	गतीय रूप से विकलांग
मन्द बुद्धि बालक	वंचित बालक	किसी अमुख विषय को सीखने में निर्योग्य	बहुल विकलांग
	समस्यात्मक बालक	सम्प्रेषण वाधित	
	बाल अपराधी		
	माता–पिता द्वारा तिरस्कृत बालक		

श्रवण विकलांग का अर्थ – कानों के द्वारा सुनने में बाधा से उत्पन्न अयोग्यता व्यक्ति विशेष को श्रवण विकलांग बनाती है। शैक्षिक दृष्टि से श्रवण विकलांग ऐसी शारीरिक निर्योग्यता है जो बालक को मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा षिक्षा ग्रहण करने में बाधा उत्पन्न करती है।

चक्षु विकलंगता का अर्थ – चक्षु विकलांग बालक से तात्पर्य है चक्षुओं से कुछ भी न देख पाना अर्थात पूर्णता दृष्टिहीनता शैक्षिक दृष्टि से चक्षुहीनता से अभिप्राय है ऐसा दृष्टि विकार जिसके परिणाम स्वरूप षिक्षण अंष रूप से भी संभव न हो सकें, चक्षु हीनता के रूप में आंका जायेगा

विकलांग बच्चो हेतु योजनाएँ – नि:शक्त व्यक्ति (समान सुविधाएं,अधिकार संरक्षण एवं भागीदारी अधिनियम 1995) (विधि न्याय एवं कंपनी मामलो मे मंत्रालय विधान या कानून संबंधी असाधारण गजट)

उक्त अधिनियम ने जनवरी 1996 को राष्ट्रपति स्वीकृति प्राप्त की एवं सर्व की सूचनार्थ प्रकाशी अपंग व्यक्तियों के लिए (समान सुविधाएं, अधिकार सुरक्षा एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 संसद के दोनों सदनो द्वारा लोक सभा मे 22 दिसंबर 1955 मे और राज्य सभा मे 22 दिसंबर 1995 को पारित किया गया।

इस अधिनियम का जो की 1995 मे कानून बना दिया गया (1996 के राजपत्र की संख्या– एक) केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी तय करना किया वे उस हद तक जिस हद तक उनके संसाधन उन्हें अनुमति देते है, विकलांग बालको को सेवाएँ उपलब्ध कराएं, उनके लिए सुविधाओं का सृजन करें और उन्हे मदद दें, ताकि वे अपनी क्षमताओ की अधिकतम सीमा तक देश के उत्पादक एवं सहयोगी नागरिक के रूप मे भागीदारी निभाने मे समान अवसर हासिल करने के लायक बन सके। यह सरकारें (केंद्र एवं राज्य) सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी डालती है कि विकलांगता देश के किसी भी नागरिक को सम्पूर्ण जीवन जीने की ओर अपनी क्षमता के अनुसार सम्पूर्ण योगदान देने से रोकती नहीं है।

इसी क्रम मे राष्ट्रीय न्याया अधिनियम 1999, समेकित शिक्षा योजना–1992, दीनदयाल समर्थ योजना–2004 एवं उत्थान अभियान–2006, योजनाएँ विकलांगता के संबंध मे क्रियान्वित की गई जिनका उद्देश्य शैक्षणिक सुविधाएं, चिकित्सा सुविधाएं, रोजगार एवं सामाजिक पुनर्वास की सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

मूल्यांकन की आवश्यकता – विकलांग बालको की पहली आवश्यकता यह होती है कि उन्हें उनके विशिष्ठ गुणों, क्षमताओं एवं कमियों के आधार पर उनके अनुकूल शिक्षा व प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए ताकि वे समाज मे अपने आप को समायोजित कर सके और समाज उनसे लाभान्वित हो सके सामान्य बालक से संबन्धित अनेक शोध कार्य हुए परंतु विशिष्ट बालको की शिक्षा व्यवस्था से संबन्धित बहुत अल्प शोध हुए हैं। बाला (1985) ने सामान्य तथा शारीरिक विकलांग विद्यार्थियों के मानसिक संकल्प एवं शैक्षिक सुविधाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया।

उद्देश्य – सामान्य तथा शारीरिक विकलांग बालको के व्यक्तित्व लक्षण मुख्य आत्म संकल्पना मानसिक संकल्प तथा समायोजन का अध्ययन करना।

निष्कर्ष – सामान्य विद्यार्थियो की तुलना मे शारीरिक विकलांग विद्यार्थियो मे व्यक्तित्व लक्षण, मुख्य आत्म संकलन मानसिक संकल्प तथा समायोजन

* शोधार्थी, सेंट पॉल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, भंडारिया रोड़, खंडवा (म.प्र.) भारत

क्षमता का स्तर सार्थक रूप से कमजोर पाया गया।

तिवारी (1983) इंदौर शहर के कुछ मूकबधिर एवं अंध विद्यालयों मे अध्ययनरत विद्यार्थियों की समस्याओं का तुलनात्मक अध्ययन किया।

निष्कर्ष –

1. सम्पूर्ण मूकबधिर व अंधे छात्र व छात्राओं की शैक्षिक सामाजिक अध्ययन प्रशासन व व्यक्तिगत संबन्धित समस्याओं के योग मे कोई अंतर नहीं था।
2. मूकबधिर व अंधे छात्राओं की व्यक्तिगत समस्याएँ जैसे विद्यालयो मे पढ़ते पढ़ते थक जाना, मन अवस्थिर रहना परेशानी का अनुभव करना आगे पढ़ाई चालू रखना कठिन लगना, चिंतित होना भाग्य को अच्छा ना समझना आदि समस्याओं मे अंतर नहीं पाया गया।

उद्देश्य – विकलांग बालको के लिए किए गए शासकीय प्रयासों का एक मुक बधिर अंध विद्यालय मे अध्ययनरत विद्यार्थीयों की प्रतिक्रिया के आधार पर मूल्यांकन करना।

सीमांकन –

1. प्रस्तुत अध्ययन मे न्यादर्श हेतु बुरहानपुर जिले मे स्थित मूक बधिर अंध विद्यालय मे अध्ययनरत 50 विद्यार्थियों का चयन किया गया।
2. विद्यार्थियो के लिए प्रतिक्रिया मांपनी का प्रयोग किया गया ।
3. उद्देश्यों से संबन्धित प्रदत्यों का विश्लेषण प्रतिशत मान द्वारा किया गया।

न्यादर्श – प्रस्तुत अध्ययन मे बुरहानपुर शहर के अशासकीय मुक बधिर अंध विद्यालय मे अध्ययन 50 विद्यार्थियो को न्यादर्श के रूप मे चयन किया गया है।

उपकरण – प्रस्तुत शोध मे विकलांग बालको के लिए किए गए शासकीय प्रयासो के प्रति विद्यार्थियो की प्रतिक्रिया से संबन्धित जानकारी के लिए प्रतिक्रिया मापनी मे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रकार के कथनो को सम्मिलित किया गया है। नियमित प्रतिक्रिया मापनी मे तीन बिन्दुओं वाली मापनी सहमत, असहमत एवं अनिश्चित के आधार पर प्रतिक्रिया ली गई है। प्रतिक्रिया मापनी मे सोलह सकारात्मक कथन रखे गए है।

प्रविधि – शोधकर्ता द्वारा सर्वेक्षण विधि प्रयुक्त की गई है।

प्रदत्ता संकलन प्रतिक्रिया – शोधकार्य के लिए शोधकर्ता द्वारा मूक बधिर अंध विद्यालय बुरहानपुर का चयन किया गया। इसके पश्चात विद्यालय के प्राचार्य को अपने शोध के उद्देश्यों से अवगत कराया गया तथा अध्ययन के लिए अनुमति प्राप्त की गई। इसके पश्चात अध्यापकों को विश्वास मे लेकर शोधकार्य के लिए समय निश्चित किया गया तथा विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया मापनी अध्यापकों के मार्गदर्शन से भरवाई गई।

प्रदत्तों का विश्लेषण – प्रस्तुत अध्ययन मे विद्यार्थियो से भरवाई गई प्रतिक्रीया मापनी से प्राप्त प्रदत्तों का विश्लेषण प्रतिशत मान विश्लेषण द्वारा किया गया।

परिणाम एवं विश्लेषण – प्रस्तुत शोध का उद्देश्य विकलांग बालको के लिए किए गए शासकीय प्रयासो का विद्यार्थियो की प्रतिक्रिया के आधार पर मूल्यांकन करना था इस उद्देश्य से संबन्धित प्रदत्तों का विश्लेषण प्रगतिमान द्वारा किया गया जिसमें प्रदत्तों का परिणाम तालिका द्वारा प्रदर्शित किया गया है। विकलांग विद्यार्थियों की षिक्षा के लिये शासकीय प्रयासों हेतु विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया प्रतिषत को कथन वार दर्षाती तालिका –

कथन	सहमत	असहमत	अनिष्चित
1	100%	–	–
2	–10%	90%	10%
3	60%	36%	14%
4	04%	96%	–
5	30%	70%	–
6	40%	30%	30%
7	80%	20%	–
8	10%	80%	10%
9	30%	60%	10%
10	90%	10%	–
11	10%	80%	10%
12	60%	30%	10%
13	24%	64%	12%
14	10%	76%	14%
15	56%	28%	16%
16	48%	36%	16%

व्याख्या – सारणी से स्पष्ट है कि विकलांग बालको हेतु निर्मित प्रतिक्रिया मापनी सरकार द्वारा विकलांग बालकों को निशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की जाती है के लिए प्रतिक्रिया में 100 प्रतिशत सहमत प्रतिक्रिया दी गई सरकार द्वारा विशिष्ट विद्यालयों में निशुल्क भोजन व्यवस्था नहीं है के लिए 10 प्रतिशत सहमत 80 प्रतिशत असहमत तथा 10 प्रतिशत अनिश्चित मिली सरकार द्वारा विशिष्ट विद्यालयो मे खेलकुद गतिविधि कराई जाती है मे 60 प्रतिशत सहमत 36 प्रतिशत असहमत तथा 14 प्रतिशत अनिश्चित प्रतिक्रिया मिली सरकार द्वारा विकलांगता हेतु छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की जाती है के लिए 4 प्रतिशत सहमत 96 प्रतिशत असहमत प्रतिक्रिया प्रदान की विकलांग बालको के लिए विकलांग प्रमाण पत्र निशुल्क बनाए जाते है के लिए 30 प्रतिशत सहमत 70 प्रतिशत असहमत प्रतिक्रिया मिली सरकार द्वारा विकलांग बालको हेतु उचित चिकित्सा परीक्षण नहीं कराये जाते है के लिए 30 प्रतिशत सहमत 40 प्रतिशत असहमत तथा 30 प्रतिशत अनिश्चित प्रतिक्रिया प्रदान की विकलांग बालको को यात्रा किराया मे रियायत दी जाती है के लिए 80 प्रतिशत सहमत तथा 20 प्रतिशत असहमत प्रतिक्रिया मिली विकलांग बालको को शिक्षा के लिए समान अवसर प्रदान नहीं किए जाते है के लिये 10 प्रतिशत सहमत 80 प्रतिशत असहमत तथा 10 प्रतिशत अनिश्चित प्रतिक्रिया मिली विकलांगो को उनकी विकलांगता के अनुरूप विद्यालय मे बैठक व्यवस्था होती है के लिए 30 प्रतिशत सहमत 60 प्रतिशत असहमत तथा 10 प्रतिशत अनिश्चित प्रतिक्रिया मिली विकलांग बालको के पालको के लिए भी सरकार द्वारा विकलांगता से संबन्धित प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया जाता जिसमे 90 प्रतिशत सहमत तथा 10 प्रतिशत असहमत प्रतिक्रिया मिली विकलांग बालको को शासकीय सेवाओ मे आरक्षण प्राप्त नहीं होता है के लिए 10 प्रतिशत सहमत 80 प्रतिशत असहमत तथा 10 प्रतिशत अनिश्चित प्रतिक्रिया मिली विकलांग बालको को पाठ्य सामाग्री क्रियाएँ करवाते समय उनकी विकलांगता का विशेष ध्यान रखा जाता है के लिए 60 प्रतिशत सहमत 30 प्रतिशत असहमत तथा 10 प्रतिशत अनिश्चित प्रतिक्रिया मिली विकलांग बालको की शिक्षा के लिए समाजसेवी व

स्वयंसेवी संस्थाएं आर्थिक सहायता प्रदान नहीं करती के लिए 24 प्रतिशत सहमत 64 प्रतिशत असहमत तथा 12 प्रतिशत अनिश्चित प्रतिक्रिया प्रदान की सरकार द्वारा विकलांग बालको को निशुल्क कृत्रिम अंग सहायक उपकरण प्रदान किए जाते है के लिए 10 प्रतिशत सहमत 76 प्रतिशत असहमत तथा 14 प्रतिशत अनिश्चित प्रतिक्रिया मिली विकलांग बालको को सरकार द्वारा रोजगार हेतु प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया जाता के लिए 56 प्रतिशत सहमत 28 प्रतिशत असहमत तथा 16 प्रतिशत अनिश्चित प्रतिक्रिया मिली सरकार द्वारा उन विकलांग बालको की समस्या का समाधान किया जाता है जिन्हें परिवार का सहारा है के लिए 48 प्रतिशत सहमत 36 प्रतिशत असहमत तथा 16 प्रतिशत अनिश्चित प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है।

सारांश – विकलांग बालको के लिए किए गए शासकीय प्रयासो का मूक बधीर अंध विद्यालयो मे अध्ययनरत विद्यार्थियो की प्रतिक्रिया के आधार पर मूल्यांकन करना था जिसमें प्रतिक्रिया के आधार पर मूल्यांकन करने पर पाया गया कि वर्तमान समय मे विकलांग बालको को शिक्षित करने हेतु सरकार कई तरह की योजनाएं चलाकर उन्हे लाभान्वित करने का प्रयास कर रही है। बालक इन योजनाओ के माध्यम से अपना जीवनयापन कर अपना सर्वागीण विकास कर सकते हैं। अत: निष्कर्ष के रूप मे यह कहा जा सकता है कि विकलांग बालकों के लिए किए गए शासकीय प्रयासो हेतु विकलांग बालको की समेकित प्रतिक्रिया सकारात्मक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अग्रवाल जी (1981) विकलांगता समस्या और समाधान दिल्ली निधि प्रकाशन।
2. आहूजा एस. (1994) दृष्टिहीनो का संरक्षण पुनर्वसन मुंबई एन ए बी।
3. भालेराओ यु. (1985) मध्यप्रदेश के शिक्षित दृष्टिहीनों के सामाजिक अध्ययन दिल्ली गौरव पब्लिशन हाऊस।
4. बिष्ट आभारानी (1990) विशिष्ट बालक, आगरा, विनोद पुस्तक मंदिर।
5. भार्गव महेश (2003) विशिष्ट बालक, आगरा, एच पी भार्गव बूक हाऊस।
6. शुक्ला नीरजा (1997) श्रवण विकारयुक्त बच्चो का भाषा विकास राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद।
7. पाल, हंसराज (2006) प्रगत शिक्षा मनोविज्ञान दिल्ली हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निर्देशालय दिल्ली विश्वविद्यालय।
8. शर्मा आर.ए.(2003) शिक्षा अनुसंधान मेरठ आर. लाल बूक डिपो ।

****

ग्रामीण एवं शहरी बालक एवं बालिकाओं के शैक्षिक मूल्यों का तुलनात्मक अध्ययन

जूली शुक्ला * डॉ. सुधा रिछारिया **

शोध सारांश – प्रस्तुत शोध कर्ा उत्तर प्रदेश उन्नाव जिले के तीन विद्यालयों में किया गया है। इसमें 100 बालक एवं 100 बालिकाओं को न्यादर्श के रूप में लिया गया। यह शोध पत्र बढ़त हुऐ आधुनिकीकरण के कारण बालक एवं बालिकाओं के शैक्षिक मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों को दर्शाता है। प्रस्तुत शोध में जी.पी. शैरी व आर.पी. वर्मा द्वारा निर्मित प्रश्नावली का उपयोग आंकडों का संग्रह करने हेतु किया गया। इस शोध द्वारा प्राप्त परिणाम दशति हैं कि सौन्दर्यात्मक, आर्थिक व ज्ञानात्मक मूल्य बालक व बालिकाओं में समान रूप से विद्यमान है।

प्रस्तावना – शिक्षा एक ऐसा प्रकाश है जिसकी रौशनी में हम खुली सास ले सकते हैं। शिक्षा ही मानव के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं सामाजिक विकास को दिशा प्रदान करती है। समय–समय पर शिक्षा से विभिन्न प्रकार की अपेक्षाएँ की जाती रही हैं। प्रारंभ में इससे संरक्षण, संवर्धन व हस्तांतरण की अपेक्षाएँ की जाती थी। परन्तु वर्तमान में इससे मूल्यों का संवर्धन, परिमार्जन, परिवर्धन, अस्तित्व का निर्माण व वर्तमान समाज के स्वरूप को हिंसात्मक रवैयों से निकाल कर मानव जीवन के अनुकूल बनाने व मूल्यों में सकारात्मक परिवर्तन करने का माध्यम समझा जाता है। विभिन्न विचारकों ने शिक्षा की आवश्यकता को स्वीकार है और माना है कि शिक्षा के बिना मानव विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। वेदों में भी कहा गया है कि शिक्षा ही सारे प्रकाश का स्त्रोत है और उचित शिक्षा से ही समाज सशक्त बन सकता है। वस्तुत: प्रीचन समय में शिक्षा को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक साधन के रूप में लिया जाता था जिसका मुख्य कार्य मोक्ष प्रदान करना था। इसके कुछ समय बाद इसको, 'आंतरिक शक्तियों को प्रकाश में लाने वाला साधन माना गया तथा समझा गया कि यह सम्पूर्ण में पूर्णता लाने वाली शक्ति है। शिक्षा को बालक के शरीर, मस्तिष्क व आत्मा का विकास करने वाली शक्ति भी कहा गया है। वर्तमान में भी इसको कभी व्यावसायिकता से, कभी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति से, कभी विज्ञान एवं तकनीकी के प्रयोग व नई–नई खोजों से जोड़ा गया। आज स्कूली शिक्षा को ही पूर्ण शिक्षा समय लिया जाता है। परन्तु शिक्षा तभी पूर्ण हो सकती है जब शिक्षा के महत्व को जन जागरण से जोडा जाए व से प्राप्त करने के बाद उसका उपयोग दैनिक जीवन में किया जाए तभी समाज के मूल्यों को परिवर्धित व परिष्कृत किया जा सकेगा।

विकास की इस दौड़ में आज समाज व देश में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। इसके साथ–साथ शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति का समावेश भी हो रहा है जिससे लोगों के जीवन स्तर में बहुआयामी परिवर्तन आया है। वही दूसरी ओर हमारे आदर्शो व मूल्यों में कमी होती जा रही है। आज समाज में धार्मिक कुट्रता, भाग्यवाद, अंधविश्वास, आंतकवाद, दुराचार, उत्पीड़न एवं अत्याचार हो रहे हैं, मान स्नेह सात्वीकरण, भाईचारे की भावनाओ की उपेक्षा की जा रही है। ऐसी परिस्थिति में आवश्यक है कि हमारे विद्यार्थियों में उदारता के मूल्य विकसित कर सम्पूर्ण मानव समाज को लाभांवित किया जा सके।

मानव जीवन के कुछ अनुभव व सिद्धांत होते हैं जो मानव व्यवहार को दिशा प्रदान करते है इन्हीं सामान्य सिद्धांतो को मूल्य कहा जाता है। अनुभव के साथ इन मूल्यों में परिपक्वता आती है, जो व्यक्ति और समाज को जीवतंता प्रदान करती है। मनुष्य के व्यवहार को मनोवृत्तियाँ प्रकाशित करती है और ये मनोवृत्तियाँ मूल्यों द्वारा ही निर्मित होती। मानव आचरण तथा व्यवहारों को जीवन मूल्यों द्वारा ही मापा जाता है। वस्तुत: ये मूल्य एक ऐसे आचरण तथा गुणों का समूह है जिसके द्वारा मानव अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। इस प्रक्रिया में मनुष्य की मनोवृत्तियाँ विचार आस्थायें तथा धारणायें समाहित होती हैं।

उद्देश्य – प्रस्तुत शोध का उद्देश्य ग्रामीण एवं शहरी उच्च माध्यमिक स्तर पर बालक एवं बालिकाओं के सौन्दर्यात्मक, आर्थिक व ज्ञानात्मक मूल्यों का तुलनात्मक अध्ययन करता है।

परिकल्पना –ग्रामीण एवं शहरी बालक एवं बालिकाओं के मूल्य (सौन्दर्यात्मक, आर्थिक व ज्ञानात्मक) प्राप्तांकों के मध्य सार्थक अंतर नहीं है।

शोध विधि –

न्यादर्श– प्रस्तुत 200 छात्र छात्राओ का न्यादर्श उन्नाव जिले के वेयर गॉव के उच्च माध्यमिक स्तर के तीन विद्यालयों से लिया गया है। जिसमें सुविधानुसार राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अचगंज से 75 बालिकाये एस.ए.बी. इंटर कॉलेज अचलगंज से 75 बालक राजकीय इंटर कॉलेज उन्नाव से 25 बालक, सरस्वती विद्या मंदिर अचलगंज से 25 बालिकाओ का चयन यादृच्छिक न्यादर्श द्वारा किया गया है। इस शोध में विश्वसनीय व बैध परिणाम प्राप्त करने के लिये जे.पी.शैरी व आर.पी.वर्मा द्वारा निर्मित व्यक्तिगत मूल्य प्रश्नावली उपकरण का चयन किया गया है। अव्यवस्थित आंकडो को सुबोध एवं ग्राह्य बनाने के लिये प्रयुक्त अध्ययन में मध्यमाना, प्रमाणिक विचलन, मध्यमानो के अंतर की सार्थकता (टी.मूल्य) अथवा क्रांतिक अनुपात का प्रयोग किया गया है।

* शोधार्थी, जे.जे.टी. यूनिवर्सिटी, झुनझूनू (राज.) भारत
** प्राचार्या, श्रीमती विद्यावती कॉलेज ऑफ ऐजुकेशन, झांसी (उ.प्र.) भारत

सारणी–1 (देखे)

सारणी एक पर दृष्टिपात करने पर विदित होता है कि बालक एवं बालिकाओं के सौन्दर्यात्मक मूल्य प्राप्तांक क्रमानुसार 13.38 तथा 12.54 है व क्रांतिक अनुपात 0.209 है। इसी प्रकार आर्थिक मूल्य प्राप्तांक 8.92 व 9.26 तथा क्रांतिक अनुपात 1.399 है व ज्ञानात्मक मूल्य प्राप्तांक क्रमश: 15.57 व 15.74 तथा क्रांतिक अनुपात 0.419 है। इन तीनों मूल्यों के प्राप्तांक विश्वास के किसी भी स्तर पर सार्थक नहीं हैं। अत: शोध कार्य की परिकल्पना बालक एवं बालिकाओं के सौन्दर्यात्मक आर्थिक व ज्ञानात्मक मूल्य प्राप्तांको के मध्य सार्थक अंतर नहीं है की पुष्टि होती है। इसलिये यह कहा जा सकता है कि दोनों समूहों के विद्यार्थियों में सौन्दर्य की भावना सजना–संवरना, सौन्दर्य की प्रशांसा करना व सुंदर वस्तुओ के प्रति आकर्षित होना तथा भौतिक धन सम्पदा को महत्व देने के साथ–साथ तथ्यों को समझने तथा सत्य प्राप्ति के प्रति अनुराग व जिज्ञासा का भाव समान रूप से निहित है।

अत: कहा जा सकता है ग्रामीण एवं शहरी बालक एवं बालिकाओं के सौन्दर्यात्मक, आर्थिक व ज्ञानात्मक मूल्यों के मध्य सार्थक अंतर नहीं है क्योंकि आज समाज के प्रत्येक वर्ग में परिवर्तन आया है चाहे वह किसी के क्षेत्र में हो, जिसके कारण अधिकांश अभिभावक अपने बच्चों को समान शिक्षा देने का प्रयत्न करते हैं और उनके पालन–पोषण में कोई कमी न करने के साथ उनमें कोई भेदभाव नहीं करते हैं और दोनों के ही समान अधिकार प्रदान किये गए है। जिसके परिणामस्वरूप बालक एवं बालिकाओं दोनों में ही मूल्य के प्रति आशक्ति का भाव समान रूप से निहित है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

सारणी–1

क्र.सं.	मूल्य	समूह	संख्या	मध्यमान	मानवक विचलन	क्रांतिक अनुपात	सार्थकता
1.	सौन्दर्यात्मक	बालक–बालिकाएँ	100 100	11.38 12.54	3.104 3.644	0.209	सार्थक नहीं है
2.	आर्थिक	बालक–बालिकाएँ	100 100	8.92 9.26	3.033 2.988	1.399	सार्थक नहीं है
3.	ज्ञानात्मक	बालक–बालिकाएँ	100 100	15.57 15.74	2.937 2.798	0.419	सार्थक नहीं हैं

****

डॉ. जाकिर हुसैन का शिक्षा दर्शन तथा उसका वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर प्रभाव

डॉ. पंकज पारीक * पुष्पा ढ़ोल्या **

प्रस्तावना – समय समय पर शिक्षा मानव को समाजोपयोगी नागरिक निर्मित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करती है। शैक्षिक विचारों एवं उनके प्रयोगो को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए देश के कविपय भागों में विभिन्न प्रकार की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जाती रही है। स्वतन्त्रता आन्दोलन के समय कई भारतीय शैक्षिक चिन्तकों ने अपने शिक्षा सम्बन्धी विचारों को प्रस्तुत किया, जिनमें डॉ. जाकिर हुसैन भी एक है, साथ ही शिक्षा को यह स्वरूप प्रदान करने में महात्मा गांधी, गुरूदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, महर्षि अरविन्द, डॉ. सम्पूर्णानन्द, डॉ. राधा कृष्णन एवं डॉ. जाकिर हुसैन की भूमिका श्लाघनीय एवं अनुकरणिय रही है। अत: यह सापेक्ष होगा की उपरोक्त शिक्षा विदों के शिक्षा दर्शन एवं भारतीय शिक्षा के विकास में इनके योगदान की समीक्षा की जाय।

भारतीय शिक्षा के स्वरूप में समय – समय पर काफी परिवर्तन आए परन्तु शिक्षा मूल में विदेशी आवरण से मुक्त नहीं हो पायी तथा संभवत: यही मूल कारण रहा है कि हम बहुत प्रयत्न करने के बावजूद भी शिक्षा को भारतीय स्वरूप प्रदान नहीं कर पाये। इसका एक मुख्य कारण निश्चित रूप से यह रहा है कि हमने हमारे पूर्वज शिक्षा विद्दों द्वारा समय समय पर शिक्षा की अवधारणा एवं उनके विचारों को कभी गहराई से नहीं लिया और न नहीं इस बात के प्रयास किये कि उन विचारों को वर्तमान शैक्षिक परिपेक्ष में समाविष्ट किया जाय, अर्थात यहां यह कहना न्यायोचिन होगा कि हमने शिक्षा के इतिहास में हमारे भरतीय शिक्षा विदों के बहुमूल्य विचारों एवं व्यवहारों के चिन्तन को अब तक उपेक्षित रखा है। प्रस्तुत शोध कार्य में इसी उपेक्षित दायरे को मूर्त रूप देने का एक विनम्र प्रयास किया गया है शिक्षा का जा वर्तमान स्परूप हमारे सामने है वह बालक को न तो जीवन के लिए तैयार करता है और नहीं बालक के सर्वांगीण विकास की अवधारणा को महत्व प्रदान करता है। सम्भवतया यही कारण है कि समाज में शिक्षा के वर्तमान स्वरूप के प्रति एक नफरत का आलम है बार – बार किये गये प्रयत्नों के बावजूद भी नतो सरकार और न ही समाज इस वर्तमान शिक्षा प्रणाली को आत्मसात कर पाई है।

डॉ. जाकिर हुसैन एक ऐसे शिक्षाविद है जिन्होंने शिक्षा के विभिन्न पक्षों पर चिन्तन कर अपने विचार दिए है तथा डॉ. हुसैन ने जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थान की नींव डालने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। डॉ. हुसैन ने अंग्रेजी प्रणाली की शिक्षा प्राणत की थी। ये इसके गुण दोषों से परिचित थे। गांधी जी द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय शिक्षा की पाठ्य चर्या को अन्तिम रूप देने का कार्य डॉ. हुसैन की अध्यक्षता में बनी समिति को सौपां गया था डॉ. हुसैन ने जामिया मिलिया और बेसिक शिक्षा की पाठ्य चर्या में मूर्तरूप प्रदान किया।

डॉ. जाकिर हुसैन तथा उनके शैक्षिक योगदान पर शोध कार्य की आवश्यकता अनुभव कर अनुसन्धात्री द्वारा निम्न शीर्षक आधारित कार्य किया।

समस्या कथन – शोध समस्या का शीर्षक है – डॉ. जाकिर हुसैन का शिक्षा दर्शन तथा उसका वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर प्रभाव।

EDUCATIONAL PHILOSOPHY OF Dr. Jakir Hussain and its impact on present education system

शोध अध्ययन के उद्देश्य – प्रस्तुत शोध कार्य के निम्नांकित उद्देश्य

1. डॉ. जाकिर हुसैन के शिक्षा दर्शन का वर्तमान भारतीय शिक्षा प्रणाली पर पड़े प्रभाव का अध्ययन करना।
2. डॉ. जाकिर हुसैन के शैक्षिक दर्शन का अध्ययन करना तथा उनके शैक्षिक दर्शन के व्यावहारिक स्वरूप का पता लगाना।
3. डॉ. जाकिर हुसैन की बेसिक शिक्षा के विविध पहलुओं पर प्रस्तुत विचारों का अध्ययन करना।
4. डॉ. जाकिर हुसैन के शिक्ष दर्शन की वर्तमान परिवेश में सार्थकता की खोज करना।

शोध परिकल्पना – ऐतिहासिक अनुसंधान में परिकल्पनाओं का निर्माण प्राय: नहीं किया।

शोध परिकल्पना – ऐतिहासिक अनुसंधान में परिकल्पनाओं का निर्माण प्राय: नहीं किया जाता है ऐसे अनुसधानों में जिनका उद्देश्य केवल तथा संग्रह ही हो, परिकल्पना का होना आवश्यक नहीं है।

वर्तमान शोध अध्ययन का औचित्य – वर्तमान शोध अध्ययन इस आशा के साथ किया गया है कि यह निम्नाकित रूपों में उपयोगी सिद्ध होगा।

1. **अनुसंधान की दृष्टि से** – सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन से ज्ञात हुआ कि शिक्षा सकांय के अन्तर्गत अब तक डॉ. राधाकृष्णा, विनोबा भावे, अरविन्द, विवेकानन्द, महात्मा गांधी, डॉ. सम्पूर्णानन्द के शैक्षिक योगदान पर कार्य किया गया है, किन्तु डॉ. जाकिर हुसैन जिन्होंने राष्ट्रीय शिक्षण एवं बेसिक शिक्षा पर पर्याप्त चिन्तन किया उन पर कोई सापेक्ष शोध कार्य नहीं हुआ अत: इस आशा से यह शोध कार्य किया, गया कि इसके परिणाम आधुनिक भारतीय शिक्षा में पुनर्निर्धारण एवं पुनर्गठन की दृष्टि से लाभकारी सिद्ध होगें।

2. **शैक्षिक समाज की दृष्टि से** –स्वतन्त्र भारत के शैक्षिक समाज के लिए यह आवश्यक है किवे अपने देश के शिक्षा चिन्तकों के शिक्षा दर्शन, शैक्षिक विचारों से परिचित हो तथा अपने अध्यापन में इन शैक्षिक चिन्तकों के शिक्षा दर्शन का उपयोग करें तथा उसे अधिक सार्थक प्रभावी एवं राष्ट्रोपयोगी बना सकें। अत: यह आशा की जाती है कि इस दृष्टि से प्रस्तुत शोध के परिणाम उनके लिए लाभकारी सिद्ध होगें।

* प्राचार्य, मंत्रम शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत
** शोधार्थी, पेसिफ़िक विश्वविद्यालय, पहेर,उदयपुर (राज.) भारत

3. **शिक्षा संकाय की दृष्टि से** – इस शोध कार्य का प्रयोजन डॉ. हुसैन का आधुनिक भारतीय शैक्षिक चिन्तकों के मध्य स्थान निर्धारित करना है, यह आशा की जाती है की यदि यह सिद्ध हो जाता है कि डॉ. जाकिर हुसैन एक आधुनिक भारतीय शैक्षिक चिन्तक थे तो शिक्षा संकायों को यह लाभ होगा कि डॉ. हुसैन के शैक्षिक योगदान को शिक्षा संकायों के पाठ्यक्रमों में शामिल किया जा सकेगा तथा उनके शैक्षिक निहितार्थ का लाभ भागी अध्यापक पीढ़ी उठा सकेगी।

शोध अध्ययन की सीमाएं – प्रस्तुत शोध समस्या का शीर्ष है –

'डॉ.जाकिर हुसैन का शिक्षा दर्शन तथा उसका वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर प्रभाव'

'Educational Philosophy of Dr. Jakir Hussain and its impact on present education system.'

इस दृष्टि से इस अनुसन्धान कार्य में निम्नांकित क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है।

1. डॉ. जाकिर हुसैन द्वारा प्रस्तुत विचारों में से शैक्षिक विचारों को ही सम्मिलित किया गया जिनकी अभिव्यक्ति डॉ. जाकिर हुसैन ने अपने व्याख्यानों निबन्धों, दस्तावेजों, पत्रों डायरी में की है। इसके अलावा महान शिक्षा मनिषियों द्वारा डॉ. जाकिर हुसैन के शैक्षिक विचारों से सम्बन्धित अन्य समकालिन शिक्षा चिन्तकों एवं आधुनिक लेखकों के विचारों को सम्मिलित किया गया।
2. साथ ही डॉ. जाकिर हुसैन के शैक्षिक विचारों (दर्शन) का वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर पड़े प्रभाव को भी अध्ययन में सम्मिलित किया गया।
3. डॉ. जाकिर हुसैन के शिक्षा दर्शन में उनके शैक्षिक व्यवहार को भी सम्मिलित किया गया, जिसके अन्तर्गत डॉ. जाकिर हुसैन द्वारा किये गये अध्ययन कार्य एवं उनके द्वारा स्थापित निम्नांकित संस्थानों की कार्यप्रणाली का अध्ययन भी शामिल है।

(अ) जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली।
(ब) जामिया मिलिया (शिक्षा संकाय) नई दिल्ली।
(स) डॉ. जाकिर हुसैन महाविद्यालय नई दिल्ली।

न्याय दर्श (Sample) - प्रस्तुत शोध कार्य में न्यादर्श के अन्तर्गत सम्पूर्ण जनसंख्या को शामिल किया गया है। डॉ. हुसैन के समस्त शैक्षिक विचारों का जो उपलब्धता, अनुसंधात्री ने संकलित किया है। इन्हे सम्पूर्ण रूप से प्राथमिक स्त्रोत्रों –

1. डायरी
2. पत्र
3. दस्तावेज
4. व्याख्यान
5. लेख
6. जीवनी

आदि को सहायक स्त्रोतों के रूप में संकलित किया गया। समस्त सम्बन्धित स्थलों से जहां भी उनके विचार संग्रहित है प्रदतों के संकलन का कार्य किया गया। शैक्षिक व्यवहार एवं दर्शन के अन्तर्गत उन समस्त शैक्षिक संस्थाओं का अध्ययन एवं मूल्यांकन कार्य किया गया। जिनकी स्थापना में डॉ. जाकिर हुसैन का मुख्य हाथ था।

1.शोध विधि उपकरण एवं प्रविधि –

1. प्रस्तुत शोध समस्या की क्रियान्वति। ऐतिहासिक विधि द्वारा की गई ऐतिहासिक प्रक्रिया द्वारा सम्बन्धित प्रदतों को निम्न स्त्रोत्रों के रूप में संकलित किया गया।

- प्राथमिकता स्त्रोत – सप्रयोजन प्रदान
- सहायक सत्रोत – अनचाहे प्रदत

2. **साक्षात्कार प्रक्रिया** द्वारा प्रदत संग्रह किये गये एवं इस कार्य हेतू अनुसधारकणी द्वारा साक्षात्कार प्रश्नावली निर्मित की गई।
3. **अवलोकन** डॉ. जाकिर हुसैन द्वारा स्थापित एवं वर्तमान कार्यरत संस्थाओं का अवलोकन किया गया एवं उनमें उपलब्ध अभिलेखों का अध्ययन कर प्रदत संकलित किये गये।

शोध निष्कर्ष –

1. डॉ. जाकिर हुसैन के अनुसार मानव मस्तिष्क के पूर्ण पोषा का नाम शिक्षा है। मस्तिष्क के पोषण से डॉ. जाकिर हुसैन का तात्पर्य मनुष्य की बुद्धि और विवेक के विकास से था। ऐसे विकास से कि मनुष्य उचित अनुचित में भेद कर सके और उचित का चयन करे।
2. मनुष्य जब उचित का चयन करेगा तो उसका बहुमुखी विकास होगा अर्थात मनुष्य शारिरिक, सामाजिक, मानसिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, चरित्र का एवं राष्ट्रीय भावना का विकास उचित चयन पर ही तो निर्भर है।
3. सामान्य दृष्टि से देखने पर ऐसा लगता है कि डॉ. जाकिर हुसैन ने न तो शिक्षा के स्वरूप को स्पष्ट किया है और न उसके कार्यों को परन्तु शिक्षा दर्शन का गहराई से अध्ययन करने पर यह निचोड़ निकलता है कि डॉ. जाकिर हुसैन ने जड़ को पकड़ा है यदि जड़ मजबूत होगी तो तना डालियों और पते तो स्वयं मजबूत हो जायेगें।
4. डॉ. जाकिर हुसैन ने अपने भिन्न – भिन्न भाषणों एवं लेखो में शिक्षा के समस्त सार्वभौमिक एवं सार्वकालिक उद्देश्यों पर जोर तो दिया है परन्तु सर्वाधिक बल मानसिक विकास बुद्धि एवं विवेक शक्ति के विकास पर दिया है।
5. डॉ. हुसैन गांधीजी के शैक्षिक विचारों से सहमत थे साथ ही इनके अपने मौलिक विचार भी थे।

भावी अध्ययन हेतू सुझाव –

1. डॉ. जाकिर हुसैन के शैक्षिक चिन्तन के संदर्भ में उनके द्वारा स्थापित संस्थाओं का अध्ययन शिक्षा के क्षेत्र में उनके शैक्षिक योगदान का पता लगाने हेतु किया जा सकता है।
2. डॉ. जाकिर हुसैन के समकालिन शिक्षाविदों के शैक्षिक चितंन का तुलनात्मक अध्ययन भी किया जाना चाहिए।
3. डॉ. हुसैन एवं गांधी दोनों ने ही शिक्षा के विविध पक्षों पर शैक्षिक चितंन किया है अत: इनके शैक्षिक विचार और व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन भी किया जाना प्रांसगिक होगा।
4. डॉ. जाकिर हुसैन के अध्यक्षता में बनी समिति द्वारा बुनियादी शिक्षा की वर्तमान में उपादेयता पर भी अध्ययन किया जाना प्रांसगिक होगा।

उपसंहार – कुल मिलाकर डॉ. जाकिर हुसैन दार्शनिक दृष्टि से मानवतावादी धार्मिक दृष्टि से धर्म निरपेक्षतावादी, सामाजिक दृष्टि से कर्मवादी, और राजनैतिक दृष्टि से राष्ट्रवादी व्यक्ति के साथ ही एक समर्पित शिक्षक थे। डॉ. हुसैन गांधी जी की क्राफ्ट शिक्षा को केवल कार्य के प्रतिप्रेम और शरीर श्रम के प्रति आस्था उत्पन्न करने का साधन मानते थे। डॉ. हुसैन ने संस्कृति धर्म और राष्ट्रीयता के विषय में जो विचार व्यक्त किए है वे एक दम बिना किसी लाग – लपेट के किए है काश आज के शिक्षा विद् उनके इन बिना लाग – लपेट के विचारों का स्वीकार करे तो कोई अतिशयोत्ति नहीं कि शिक्षा जगत की ही नहीं वरन् पूरे राष्ट्र की समस्याओं का निराकरण हो जाए। डॉ. हुसैन के

विचारों एवं कार्यों के लिय यह देश हुसैन का चिरऋणी रहेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. Ahluwalia B.K. Zakir Hussain a study Introduction by V.V. Giri Sterling Publishing House, Jullunder -3
2. Buch M.B. A survey of research in Education (Five volumes)
3. Dutta, The Philosophy of Mahatama Gandhi (Canada University of windoten Press, 1953)
4. Gandhi Indira, Dr. Zakir Hussain as I saw him. Indian Publications 14/52 W.E.A. carolbagh, Rajhans Road, New Delhi.
5. Good Carter V. Dictionary of Ed. New york, Mecgrw Hill, 1973.
6. Kabir Humayan. Indian Philosophy and Education, Asia Pub. House, Bombay 1961.
7. Munjeeb M. Dr. Zakir Hussain – A Biography National Book Truest India, New Delhi March 1972.
8. Mathur V.S. Zakir Hussain, Educationist and Teacher Arya Book Depot, New Delhi.
9. EducationalReconstruction in Indian by Dr. Zakir Hussain Broadcast over all indian Radio, Dec. 1958
10. Sayeed khursheed Alam-Zakhir Sahib ki khani (Urdu) New Delhi National Book Trust 1957.
11. B.H. Zaidi- Dr.. Zakhir Hussain as I saw him, (New Delhi, India Pun. 1974).
12. Anees Chisti – President Zakir Hussain a study (Rachana Prqkashan 1967), New Delhi.
13. A,G, Noorani – A quest for Excellence (Dr. Zakir Hussain) populr Orakashan, Bombay 1967.
14. Indira Gandhi “His life want an Education" Radhey Mohan.

- **REPORTS -**

1. The Challenges of Education, New Delhi, govt. of India.
2. (A) Report of Un. Edu. Com. 1948-49.
   (B) Report on Sec. Edu. Commision 1952-53.
   (C)Report of ed. commission(1964-66).

- National Policy on Education 1968.
- Ministry of Ed. Govt. Of India.
- National Policy on Ed. 1986 Ministry of human resources, Govt. Od India 1986.

(F) Survey :-Sixth survey of education research 1993-2000 Vol. I, NCERT.

****

The Effect Of Training On Ability To Play Square Cut & Pull Shot

Dr. Gajender Singh Saroha * **Vineet Masih** **

Abstract -A research work was conducted on district level cricket players of Kota & Bundi. It was ascertained whether training can improve the ability of players to play square cut and pull shot. It is generally believed that it is innate, intrinsic and natural skill of player that determines whether player can perfectly & effectively execute square cut as well as pull shot. Is it the physic of a batsman that is most important or the training can play a vital role; to determine this fact' research work was taken into hands. Performance of batsmen prior to training and after training was measured & compared. **Key Words -** square cut, pull shot, training.

Introduction - Whenever players come to the crease they hope they will play a good inning and will score well. Every batsman put his effort to score as many runs as possible. Today the pressure is always there on batsman not to waste balls and score runs quickly. In this regard paler has to be perfect to play any type of delivery. Fast ballers frequently ball short balls; batsmen can score good runs with square cut and pull shots on theses short pitch balls. But for this special training is essential else player may get bowled out dragging the ball to the stumps or may be caught in the 30 yard circle/ in deep/ ball may shoot up & caught by fielder.

Objectives :

1. To find whether training can improve ability of batsmen to play square cut.
2. To find whether training can improve ability of batsmen to play pull shot.

Sample :

District	Number of cricket players
Kota	25
Bundi	25
Total	50

Research Tool - Selected district level cricket players of Kota & Bundi were trained to play square cut and pull shot on short pith balls. Training was given to play fast as well as spin bowling. Pre & post training strokes played by all these selected players were recorded. Shots were judged by cricket experts and then one month training was given to them. Cricketers ability to play square cut and pull shots were judged again by cricket experts after one month training. How well batsman middle & stroke the ball was the criteria of judgment.

Data Analysis Tool - Percentage, correlation and paired T-test were used to analyse the data recorded by the experts prior to training and after training.

Hypothesis - Following two hypotheses were framed:

H1. There is no significant effect of training on ability to play square cut.

H2. There is no significant effect of training on ability to play pull shot.

Testing of Hypothesis :

1. Prior to training the ability of selected 50 players to play square cut was 28.16% and after training it reached to 38.68%. It was really a good improvement which is also visible from the chart 1. It shows that every player's ability to play square cut has increased.

Chart 1 - Effect of training on ability to play Square Cut

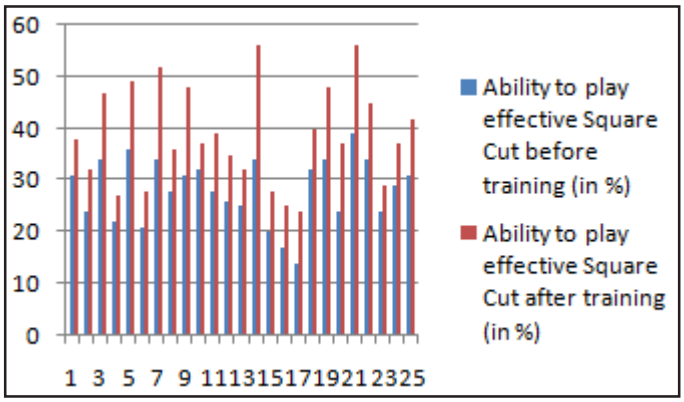

There is a very positive correlation (0.92) between training and players ability to play square cut.

The P value for paired T- test was found 7.99E-12 which is less than the level of significance .05 so we reject null hypothesis H1, proving that there is highly significant increase in ability to play square cut after training among batsmen.

2. Prior to training the ability of selected 50 players to play pull shot was 38.88% and after training it reached to 47.44%. It was really a good improvement which is also

* Asst. Prof. (Physical Education) Pacific University (Raj.) INDIA
** Research Scholar, Pacific University (Raj.) INDIA

visible from the chart 2. It shows that every player's ability to play pull shot has increased.

Chart 2 - Effect of training on ability to play Pull Shot

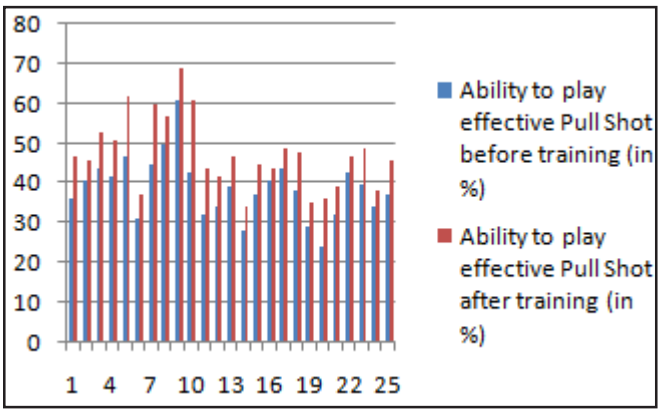

There is a very positive correlation (0.91) between training and players ability to play pull shot.

The P value for paired T- test was found 131E-11 which is less than the level of significance .05 so we reject null hypothesis H2, proving that there is highly significant increase in ability to play pull shot after training among batsmen.

Conclusion - Training programme has significantly improved the district level players' ability to play square cut and pull shot on short pitch ball. Training has benefited all in playing short pitch ball.

1. Ability to play square cut increased 37.35% due to training.
2. Ability to pull shot cut increased 22.02% due to training.

Training is very fruitful for the district level batsmen to improve their stroke play. It should be given frequently.

Suggestion - Training of playing square cut and pull shot improve the stroke playing ability of batsmen so frequent training camps should be organized by different district cricket associations so that good stroke playing batsmen can be produced raising the level of game.

References :-

1. Beashel, P. and Taylor, J. (1998). The World of Sport Examined, Walton-on-Thames, Thomas Nelson and Sons Ltd.
2. Clarke SR. Dynamic programming in one-day cricket—optimal scoring rates. Journal of the Operational Research Society 1988;39(4):331–7.
3. Gilbert, W, Cote, J. & Mallet, C. (2006). " Development Paths and Activities of Successful Sports Coaches", International Journal of Sports Science and Coaching, 1 (1): 69-76.
4. Kimber AC, Hansford AR. A statistical analysis of batting in cricket. Journal of the Royal Statistical Society, Series A 1993;156:443–55.

****

Indian Tourism And Hospitality Sector - Potential, Challenges & Government Initiatives

Munish Ahlawat *

Introduction - The Indian tourism and hospitality industry has emerged as one of the key drivers of growth among the services sector in India. The third-largest sub-segment of the services sector comprising trade, repair services, hotels and restaurants contributed nearly US$ 187.9 billion or 12.5 per cent to the Gross Domestic Product (GDP) in 2014-15, while growing the fastest at 11.7 per cent Compound Annual Growth Rate (CAGR) over the period 2011-12 to 2014-15. Tourism in India has significant potential considering the rich cultural and historical heritage, variety in ecology, terrains and places of natural beauty spread across the country. Tourism is also a potentially large employment generator besides being a significant source of foreign exchange for the country.

Market Size -

1. The number of Foreign Tourist Arrivals (FTAs) has grown steadily in the last three years reaching around 4.48 million during January–July 2015. Foreign exchange earnings (FEEs) from tourism in terms of US dollar grew by 3.2 per cent during January-July 2015 as compared to 1.9 per cent over the corresponding period of 2013. FEEs during the month of July 2015 were Rs 11,452 crore (US$ 1.74 billion) as compared to FEEs of Rs 10,336 crore (US$ 1.57 billion) in July last year.
2. Foreign Exchange Earnings (FEEs) between January-July 2015 were US$ 11.41 billion compared to US$ 11.06 billion in the same period last year. The growth rate in FEEs in rupee terms in January-July 2015 was 6.9 per cent.

Investments -The tourism and hospitality sector is among the top 15 sectors in India to attract the highest foreign direct investment (FDI). During the period April 2000-May 2015, this sector attracted around US$ 8.1 billion of FDI, according to the data released by Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP).

With the rise in the number of global tourists and realising India's potential, many companies have invested in the tourism and hospitality sector. Some of the recent investments in this sector are as follows:

1. Fairfax-owned Thomas Cook has acquired Swiss tour operator Kuoni Group's business in India and Hong Kong for about Rs 535 crore (US$ 85.6 million) in order to scale up inbound tour business.
2. US-based Vantage Hospitality Group has signed a franchise agreement with India-based Miraya Hotel Management to establish its mid-market brands in the country.
3. Thai firm Onyx Hospitality and Kingsbridge India hotel asset management firm have set up a joint venture (JV) to open seven hotels in the country by 2018 for which the JV will raise US$ 100 million.
4. ITC is planning to invest about Rs 9,000 crore (US$ 1.42 billion) in the next three to four years to expand its hotel portfolio to 150 hotels. ITC will launch five other hotels - in Mahabalipuram, Kolkata, Ahmedabad, Hyderabad and Colombo - by 2018.
5. Goldman Sachs, New-York based multinational investment banking fund, has invested Rs 255 crore (US$ 40.37 million) in Vatika Hotels.
6. Japanese conglomerate SoftBank will lead the Rs 630 crore (US$ 95.6 million) funding round in Gurgaon based OYO Rooms.
7. MakeMyTrip will acquire the travel planning website Mygola and its assets for an undisclosed sum, and will together look to focus on innovating the online travel segment.

Growth of Tourism and Hospitality in India -

1. Tourism in India accounts for 6.8 per cent of the GDP and is the third largest foreign exchange earner for the country
2. The tourism and hospitality sector's direct contribution to GDP totalled US$ 44.2 billion in 2015
3. Over 2006–15, direct contribution is expected to register a CAGR of 10.5 per cent
4. The direct contribution of travel and tourism to GDP is expected to grow 7.2 per cent per annum to US$ 88.6 billion (2.5 per cent of GDP) by 2025 **(See in the last page)**

Increase in foreign arrivals -

1. Over 7.757 million foreign tourist arrivals were reported in 2015
2. Foreign tourist arrivals increased at a CAGR of 7.1 per cent during 2005-15
3. By 2025, foreign tourist arrivals are expected to increase to 15.3 million, according to the World Tourism Organisation. **(See in the last page)**

Road Ahead (Potential) - India's travel and tourism industry has huge growth potential. The medical tourism market in India is projected to reach US$ 3.9 in size this year having grown at a CAGR of 27 per cent over the last three years,

* **Asst. Lecturer, Institute of Hotel Management, Dehradun (Uttarakhand) INDIA**

according to a joint report by FICCI and KPMG. Also, inflow of medical tourists is expected to cross 320 million by 2015 compared with 85 million in 2012. The tourism industry is also looking forward to the expansion of E-visa scheme which is expected to double the tourist inflow to India. Rating agency ICRA ltd estimates the revenue growth of Indian hotel industry strengthening to 9-11 per cent in 2015-16. India is projected to be the fastest growing nation in the wellness tourism sector in the next five years, clocking over 20 per cent gains annually through 2017, according to a study conducted by SRI International.

Exchange Rate Used: INR 1 = US$ 0.0152 as on September 18, 2015

Challenges - Potential for the travel and tourism industry in India is enormous. However, at the same time, the industry faces numerous challenges, of which the most critical is lack of proper infrastructure.

Various challenges/issues faced by the domestic travel and tourism industry in India:

1. Lack of proper infrastructure
2. Human resources
3. Service levels
4. Lack of adequate marketing and promotion
5. Taxation
6. Security
7. Regulatory issues

Government Initiatives - The Indian government has realised the country's potential in the tourism industry and has taken several steps to make India a global tourism hub. Some of the major initiatives taken by the Government of India to give a boost to the tourism and hospitality sector of India are as follows - **(See in the last page)**

1. Government of India plans to cover 150 countries under e-visa scheme by the end of the year besides opening an airport in the NCR region in order to ease the pressure on Delhi airport.
2. The Tourist Visa on Arrival (TVoA) scheme enabled by Electronic Travel Authorisation (ETA), launched by the Government of India on November 27, 2014 for 43 countries has led to sharp growth in usage of the facility. During the month of July, 2015 a total of 21,476 tourist arrived on e-Tourist Visa as compared to 2,462 during the month of July, 2014 registering a growth of 772.3 per cent. During January-July, 2015 a total of 1,47,690 tourist arrived on e-Tourist Visa as compared to 14,415 during January-July, 2014 registering a growth of 924.6 per cent.
3. The Government of India has set aside Rs 500 crore (US$ 79.17 million) for the first phase of the National Heritage City Development and Augmentation Yojana (HRIDAY). The 12 cities in the first phase are Varanasi, Amritsar, Ajmer, Mathura, Gaya, Kanchipuram, Vellankani, Badami, Amaravati, Warangal, Puri and Dwarka.
4. Under 'Project Mausam' the Government of India has proposed to establish cross cultural linkages and to revive historic maritime cultural and economic ties with 39 Indian Ocean countries.

Government Other Initiatives - The Ministry of Tourism undertakes various initiatives to promote tourism in the country. These include -

Infrastructure development - Adequate infrastructure facilities are vital for the tourism industry. Thus, the Ministry of Tourism has been making efforts to develop quality tourism infrastructure at tourist destinations and circuits. The Ministry has launched a scheme for development of nationally and internationally important destinations and circuits through Mega Projects. It is also taking initiatives with other Central Govt. Ministries — Railways, Civil Aviation, Road Transport & Highways, and Food Processing and Urban Development and the concerned state governments — to achieve convergence and synergy with their programmes, to maximise the impact of investments. The various schemes offered are as follows:

Marketing and promotion initiatives -

Incredible India Campaign - To promote India as an ultimate tourist destination on the global tourism map, in 2002, GoI promoted the "Incredible India" campaign in the overseas markets. The campaign was an integrated marketing communication effort to attract tourists to the country. It projected India as an attractive tourist destination by showcasing different aspects of Indian culture, history, spirituality, and yoga. This campaign included visible branding in the outdoor media such as advertising at airports, on trams, taxis and buses and through the print, online and electronic media as well as via participation in travel marts and road shows. The campaign was conducted globally and received appreciation from industry persons and travelers.

Atithi Devo Bhavah - This is another initiative of the Ministry of Tourism to harness the potential of the tourism industry in India. It aims to create awareness about the effects of tourism and sensitise people about our country's rich heritage and culture, cleanliness and warm hospitality. It intends to instill a sense of responsibility towards tourists among the stakeholders of the tourism industry. The main components of the campaign are training and orientation of taxi drivers, guides, immigration officers, tourist police and other personnel directly interacting with the tourists, while simultaneously creating brand equity for the trained persons. This concept was designed to complement the "Incredible India" campaign.

The Atithi Devo Bhavah is a seven point programme of hospitality and training. The components are captured in the table below.

Visit India 2009 - In an attempt to boost the inflow of visitors and tourists after the terror attacks in Mumbai in 2008 and to weather the impact of the global economic slowdown, the Ministry of Tourism and the World Travel & Tourism Council jointly announced the "Visit India 2009" scheme. The scheme which was valid from April to December 2009 and had the support of the hospitality sector, tour operators, travel and airline companies, who offered various incentives and valueadded services during this period. The incentives included one complimentary air passage for a travelling companion, one night complimentary stay in a hotel and complimentary sightseeing tour in a city. Rural eco-packages and wellness packages were also offered to overseas tourists. Road shows were organised in important tourist markets overseas with participation of different segments of the travel industry.

Other promotional initiatives - In addition to the aforementioned marketing and promotional activities, the Ministry of Tourism also organises road shows in important tourist markets overseas; arranges overseas marketing meets; undertakes familiarisation tours under the hospitality programme; and participates in major international travel fairs and exhibitions. It also undertakes online promotional activities on Websites in the US, UK, Germany, Italy, France, Japan, and China as well as on search portals (Yahoo! and Google). The Ministry of Tourism has 14 offices overseas, through which it undertakes these activities. It also generates tourist publications in different foreign languages to promote India as a tourist destination in other countries.

Initiatives undertaken to promote different tourism products - Several other initiatives undertaken to promote different tourism products include the following:

Rural tourism - Rural tourism showcases rural life, art, culture and heritage at rural locations and interactions with the tourists benefit the local community economically and socially. The existing scheme for destination development supports the development of infrastructure in rural areas. Under this scheme, the thrust is on promotion of village tourism as a primary product to spread tourism and its socio-economic benefits to rural and new geographic regions. The Ministry of Tourism has joined hands with the United Nations Development Programme (UNDP) for capacity building. Around 153 rural tourism projects have been sanctioned in 28 states/union territories including 36 rural sites where UNDP offers support in capacity building. During the "Visit India 2009" scheme, around 15 rural tourism sites were selected as rural eco-holiday sites.

Cruise tourism - To facilitate growth in the cruise tourism sector, GoI approved the cruise tourism policy in June 2008. The objective of the policy is to a make India an attractive cruise tourism destination. With state-of-the-art infrastructure and cruise facilities across various parts of the country, the aim is to attract foreign tourists to cruise shipping in India and popularise the concept of cruise shipping with Indian tourists. The Ministry of Tourism provides Central Financial Assistance to state governments/union territories for development of tourist infrastructure and promotion of tourism including river cruises.

Adventure tourism - GoI is taking several measures in this regard. These include financial assistance to the state governments/union territory administrations for development of adventure tourism destinations and granting of exemption from customs duty on inflatable rafts, snow-skis sail boards and other water sports equipment. In July 2009, the Ministry of Defence gave permission for opening of 104 additional peaks in Leh area of Jammu & Kashmir for adventure tourism.

Medical tourism - Medical tourism has emerged as one of the important segments of the tourism industry; initiatives taken for promoting this include financial assistance to service providers under the Market Development Assistance Scheme and issuance of Medical visas for patients and their attendants coming to India for medical treatment. In addition, GoI has also requested the state governments to promote medical tourism by offering suitable packages of identified hospitals and price banding for specific treatments.

Open Sky Policy - GoI's Open Sky policy, which gives permission to domestic airlines to commence international flights, start-up of various low-cost carriers, and fleet expansion by domestic players have created immense incentives for domestic travelers to explore far-off destinations within and outside India. The booming aviation business is bringing an ever-increasing number of passengers to India and pulling Indians out of their homes.

Foreign Direct Investment - In the hotel and tourism industry, 100% FDI is permissible through the automatic route. Here, the term 'hotel' refers to restaurants, beach resorts, and other tourist complexes providing accommodation and/or catering and food facilities to tourists. The tourism industry includes travel agencies; tour operating agencies; tourist transport operating agencies; and units providing facilities for cultural, adventure and wild life experience and surface, air and water transport facilities; and leisure, entertainment, amusement, sports, health and convention/seminar units.

Recommendations - Key Recommendations for boosting tourism sector in India have been summarized below:

1. Projection of India's image as a safe and secure tourist destination
2. Attract private investment
3. Infrastructural development
4. Development of tourism destinations
5. Development of tourist circuits across states
6. Seamless travel within circuits
7. Joint marketing programs
8. Partnership oriented marketing

References :-

1. Tourism Operations and Management (English) 01 Edition by VANDANA JOSHI , ARCHANA BIWAL SUNETRA RODAY , publisher : Oxford University Press.
2. Hospitality Marketing (English) 2 Revised Edition by Bowie Buttle, publisher : Taylor & Francis India Pvt Ltd - New Delhi.
3. Hotel Management: Food and Food Services by R. P. Saxena, **Publisher:** Anmol Publications Pvt.Ltd.
4. Development Of Indian Tourism Industry by Achintya Mahapatra, **Publisher:** Abhijeet Publication.
5. Tourism Concepts,Issues And Challenges by S. P. Bansal Sandeep Kulshreshtha Prashant Gautam, **Publisher -** Neha Publishers & Distributors.
6. http://www.ibef.org/industry/tourism-hospitality-india.aspx
7. http://www.investindia.gov.in/tourism-and-hospitality-sector/
8. http://www.yourarticlelibrary.com/tourism/the-tourism-hospitality-industry-in-india-2346-words/7568/
9. *www.dinodiacapital.com/.../Indian-Tourism-Hospitality-Industry-Rising*
10. http://www.hospitalityindia.com/hospitality-industry-in-india.htm
11. KPMG-CII-Travel-Tourism-sector-Report, December 2013.

Direct contribution of tourism and hospitality to GDP (US$ billion)
100
80
60
40
20
0
CAGR : 8.7%
18
25
24
26
31
31
36
40.1
41.1
44.2
88.6
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2025E
Source: World Travel & Tourism Council's Economic Impact 2015, TechSci Research

Foreign tourists arriving in India (million)
18
15
12
9
6
3
0
CAGR : 7.1%
3.9
4.4
5.1
5.3
5.2
5.8
6.3
6.6
7
7.4
7.8
15.3
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2025E
Source: World Travel & Tourism Council's Economic Impact 2015,Ministry of Tourism, TechSci Research

Exhibit 4.1: Key areas of the Tourism Policy 2002
Swagat (Welcome)
Soochana (information)
Suvidha (facilitation)
Suraksha (security)
Sahyog (cooperation)
Samrachana (infrastructure)
Safai (cleanliness)
Tourism policy
Source: Ministry of Tourism, D&B Research

****

Public Building Drainage System- An Architectural View

Prof. S. A. Deshpande * Prof. Kiran P. Shinde **

Introduction - According to World Health Organization (WHO) sanitation if defined as: "*Sanitation generally refers to the provision of facilities and services for the safe disposal of human urine and waste".* Inadequate sanitation is a major cause of disease world-wide and improving sanitation is known to have a significant beneficial impact on health both in households and across communities. The word 'sanitation' also refers to the maintenance of hygienic conditions, through services such as garbage collection and wastewater disposal. Building services, energy and environmental engineering is an independent, extremely varied field which opens up interesting and technically demanding tasks for engineers. The poor drainage system becomes a real challenge for front-line technicians who are responsible for drain cleaning and maintenance.

Fig. 1 Diagram of Building Drainage System **(See in the last page)**

The above diagram reflects all possible connectivity among all chambers, lines and drainage discharge points. It can clearly be seen that the pathways available to air are in any direction. Infectious agents in the air carried by droplet nuclei, skin flakes and fine particles, move sufficiently slowly relative to the air that they are essentially carried by the airflow (Tang et al, 2011). It is therefore imperative to understand airflows, both in the drainage system and in rooms in order track transmission routes. As the prime objective of any drainage system is collection network of solid and liquid waste such as faucal solids, urine, toilet paper and vomit, means it is potentially a rich reservoir of pathogenic microorganisms. Scientifically designed drainage system not only solves the problem of waste water flow and storage but also keep control over potential transmission of pathogen that is released directly into the drainage system (Gormley al., 2011).

Public buildings viz. Health Care Centres and Hospitals always present complex set of hurdles to architect and front line workmen to design surface & underground drainage system that can keep drains and pipes flowing. Architecturally designed and tested drainage mechanism manages solid waste into under drain pipes and reservoir while locking seepage and false smell. For a subsequent public building drainage system Architects follow synergetic approach which includes -

Fig. 2 **(See in the last page)**

Drain location - underground drain location must be within the pavement area of the premises while considering the height & slopes of grassed batters, location on inlets and roads, access of trucks in required etc.

Surface Obstruction - such as electricity supplier poles, roads, buildings, native vegetation or large trees etc. may affect the proposed alignment of the drain.

Underground Obstruction - includes cables, sewer line, electricity cables, gas lines, water line etc.

Ground Condition - discuss about topography and ground configuration which affect directly to the drainage design, configuration and its technical aspects.

Design Depth - various factors that affects drain depth includes ground condition, hydraulic consideration, and provision of space above a drain for other services etc.

In a research on aseptic suction drainage to prevent infection from wound discharge a simplified unique discharge technique has been introduced in which a drainage receiver for receiving drainage from the body of a patient after wounding will collect into a receiver and after filling to a desired extent, It would be sealed so that the receiver along with its drainage contents is disposable as a unit. Then, a vacuum system using valve discharge waste material moved outside the hospitals and protect it from all possible contamination Pannier K, Reynolds G, Sorenson J (1973). Further add-on to the related topic wound drainage system proposed a method and apparatus for withdrawing fluid from a wound comprising providing a passage between the wound and a collection container with a valve there between to control flow of fluid from the passage to the container. The study introduced advanced technique of managing and discharging wound fluid using vacuum (sub-atmospheric) pressure to assist hospital drainage. The function of wound drainage is to promote rapid and efficient healing of post-operative wounds Michael Dixon, Raymond Lawrence Stubber (1999).

Fig. 3 **(See in the last page)**

[* File contains invalid data | In-line.JPG *]Hospitals are the major source of solid, semi-liquid & liquid waste

***Approved Guide, RTM Nagpur University (Maharashtra) INDIA**
**** Principal, School of Architecture, IPS Academy, Indore (M.P.) INDIA**

material. The biggest challenge before an Architect is to manage it efficiently. Fig 3 figure out the pictorial form of architecturally suggested and designed drainage system. It works upon all critical points such as discharge flow angle, vent point, configuration of collection chamber, discharge valves. Vent system is an important aspect of discussed drainage mechanism and its efficiency completely depend upon admission of air with desired force to supply the air to fill the vacuum caused by water flowing through some portion of the pipe beyond the trap. J. Pickering (A Boston Architect) 1911, in his book argued upon vent system in building drainage system and suggested the concept of mechanical air vent point into water traps to avoid siphon age problem. Adding to this argument, Puntam (1911) tested and suggested a single pipe system for multi-story building which further supported by various authors as safe & economical option and that if properly designed, building drainage system do not require every trap to be vented (Dr. Michael Gormley, 2007).

Apart from internal drainage system architect also work upon ground water drainage management around public buildings. Land drainage and management is done through open channels, surface ditches, tile drains etc. Architects used various scientific methods for drain control including 'Channels & Sub-surface Drainage'.

Channels - channels are the best way of managing surface drain but its technical specification should match the land configuration. The channels should be 1"1.5 m deep. Their trapezoid cross-section should have the bottom width of 0.5 m and 1:1 side slope ratio. The length of collectors depends on the size of plots with similar gradients; it is generally no more than 1"1.2 km. The least underwater gradient is 0.0005. The distance between collectors on clays and loams depend on the surface gradients and climatic conditions; they are generally no more than 60"120 m apart. Open collectors are not used for the drainage of plow land; the short channel spacing (50"100 m) interfere with machinery (by eolss.net).

Sub-surface Drainage - In sub-surface drainage method groundwater is collected and discharged into the conductive system through openings of a specified slope made in the subsoil layer. The opening walls and cavities can be paved or free. Therefore, drains are classified into the following groups: drains with paved walls and a free cavity (tile, plastic, wooden, etc.), drains with loose walls and a free cavity (mole and crevice), and drains with loose walls and a filled cavity (fascine, bat, and stone). Drains with paved walls or cavities (material drainage) are more stable and therefore preferable (by eolss.net).

These techniques ensure public buildings to be more competitive in organizing and managing internal as well as external drain.

References :-

1. Dixon, M., Stubber, R.L., (1999). Wound Drainage System,https://www.google.com/patents/US5944703#forward-citations, 28/11/15
2. Gormley, M., Swaffield, J.A., Sleigh, P.A. and Noakes, C.J. 2011. An assessment of, and response to, potential cross-contamination routes to defective appliance water trap seals in building drainage systems. Building Services Engineering Research and Technology, 1(1), 1- 15.
3. Gormley, M. (2007). Building Drainage Waste and Vent System, *Heriot Watt University* https://www.ecobuilding.org/code-innovations/case-studies/Heriot_ Watt_ University_reportJan2007fromStudorwebsite.pdf
4. Pannier K, Reynolds G, Sorenson J (1973). Aseptic suction drainage system and valve therefor, https://www.google.com/patents/US3719197, 27/11/15
5. Putnam, J. P. (1911) 'Plumbing and household sanitation' Doubleday, Page & Co, Garden City, New York
6. Tang. J.W., Noakes, C.J., Nielson, P.V., Eames, I., Nicolle, A. Li. & Settles, G.S. (2011) 'Observing and quantifying airflows in the infection control of aerosol- and airborne transmitted diseases: an overview of approaches' Journal of Hospital Infections 77:2011 213 - 222
7. WHO (World Health Organization). 2003. Final Report: Amoy Gardens. WHO Environmental Investigation.
8. http://www.who.int/topics/sanitation/en/, 23/11/15
9. http://www.facilitiesnet.com/plumbingrestrooms/article/Drain-Cleaning-Hospitals-Present-Difficult-Challenges-Facility-Management-Plumbing-Restrooms-Feature—12275, 24/11/15
10. http://www.irbnet.de/daten/iconda/CIB_DC27049.pdf, 24/11/15
11. http://www.melbournewater.com.au/planning-and-building/standards-and-specifications/design-general/pages/general-approach-to-drainage-systems.aspx, 27/11/15
12. http://www.eolss.net/sample-chapters/c10/e5-09-03-01.pdf, 30/11/15

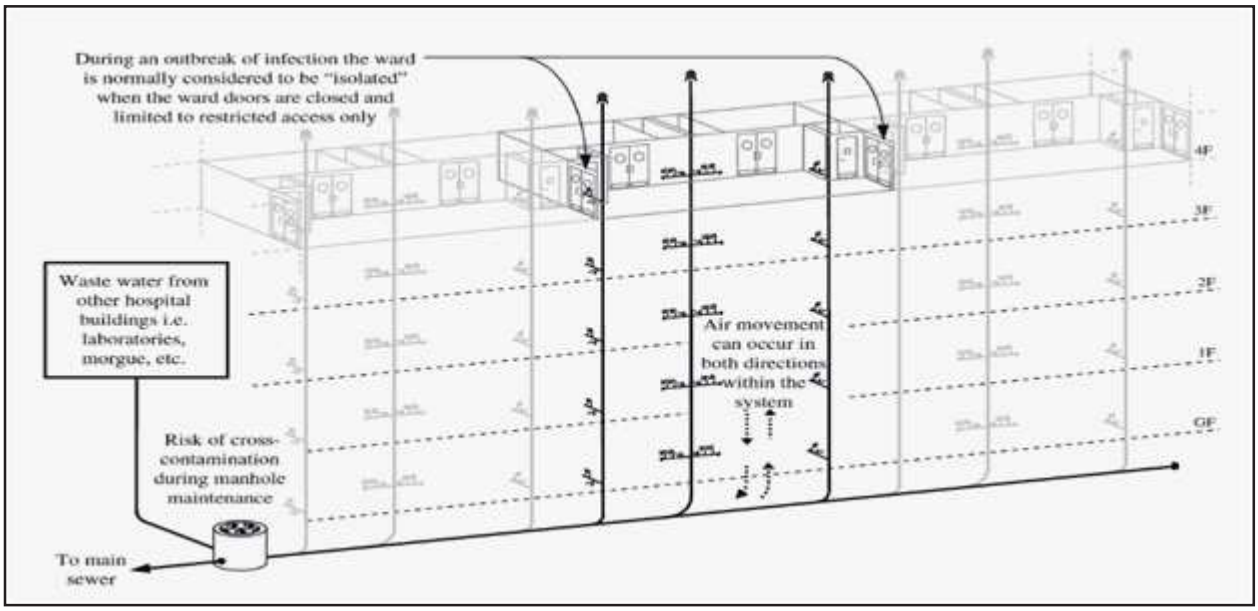

Fig. 1 Diagram of Building Drainage System

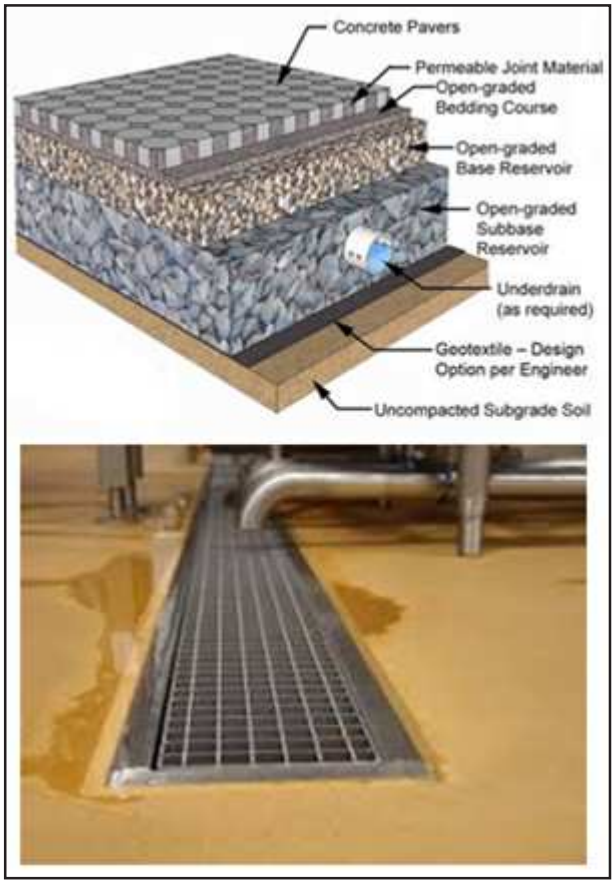

Fig. 2

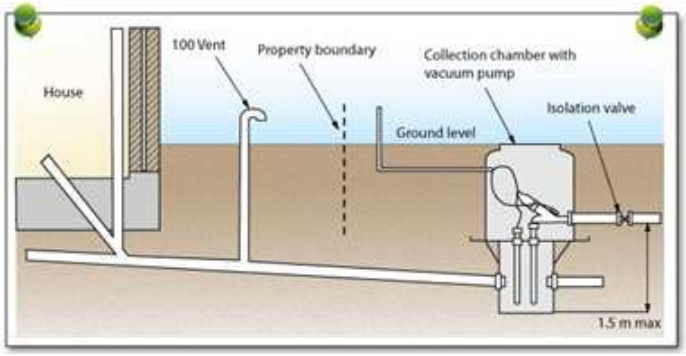

Fig. 3

****

माखनलाल चतुर्वेदी एक पुण्य स्मरण

प्रो. सीमा कदम *

प्रस्तावना – खण्डवा देश के मानचित्र में जिस वजह से पहचाना जाता है उनमें एक बड़ी वजह यह है कि पद्मभूषण, स्वतंत्रता सेनानी, प्रखर पत्रकार, लेकर कवि माखनलाल चतुर्वेदी की कर्मभूमि रहा है। यही से उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी की कर्मभूमि रहा है। यही से उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम का अलख जगाया। 30 जनवरी माखनलालजी की पुण्य तिथि है। कोई भी तिथि, तारीख, महज तारीख या तिथि नहीं होती बल्कि अपने आप में इतिहास समेटे होती है उसके मार्फत हम उन क्षणों को जीते है जो हमारी प्रेरणा है।

माखनलालजी भव्य व्यक्तित्व के धनी तो थे ही उनका कृतित्व भी बहुआयामी था मध्यप्रदेश की माटी ने पं. माखनलाल चतुर्वेदी के रूप में ऐसे ही कालजयी महामानव को जन्म दिया। जिनका व्यक्तित्व जितना विराट था कृतित्व भी उतना ही यशस्वी रहा। 4 अप्रैल 1889 को बाबई, जिला होशंगाबाद में जन्मे माखनलालजी राष्ट्रीय मुख्य धारा के अग्रणी साहित्यकार थे। उन्होंने साहित्य को आजादी की लड़ाई से जोड़ने का पहले पहल आव्हान किया था। वक्तृत्व कला के ऐसे धनी कि श्रोता न केवल मंत्र मुग्ध होकर सुने बल्कि भाषण के प्रवाह में बह जाये, महात्मा गांधी के शब्दों में 'हम सब बात करते है बोलना तो माखनलालजी जानते है' और यह संस्कार उन्हें बाल्यकाल में उनकी मॉ ने दिये, मॉ के बारे में कवि लिखते है कि 'मेरे जीवन की कोमलतर घडियों का आधार मेरी मॉ है, मेरे छोटे से ऊॅचे उठने में भी फूला न समाने वाला तथा मेरी वेदना में व्याकुल हो उठने वाला उस जैसा कोई नहीं'। बचपन में आल्हा उदल के छन्दो में हरदोल का चरित्र बड़े चाव से सुनते थे। पंचतंत्र की कहानियों ने कवि को सुधारवादी और प्रगतिवादी बनने की प्रेरणा दी। उन्हें हरवाहों और चरवाहों के गीत बहुत प्यारे लगते थे।

छात्र जीवन में ही माखनलाल चतुर्वेदी के संवदेनशील मन पर अपने आसपास के परिवेश का गहरा असर होने लगा। उन्होंने गॉव की गरीबी देखी ही नहीं भोगी भी। गॉव की बंजर पड़ी जमीन और जमीदारों द्वारा लुटती फसले देखी, कर्ज से दबे किसानों और भूख से तड़कते मजदूरों को करीब से देखा, परिणाम स्वरूप उनके भीतर एक अदम्य विद्रोह की भावना जन्म लेने लगी इसी भावना के तहत वे युवकों को ललकारते हुये कहते हैं।

द्धार बलि का खोल चल भूडोल कर दे/ एक हिमगिरि एक सिर का मोल कर दे मसल कर अपने इरादो सी उठा कर / दो हथेली है, कि पृथ्वी गोल कर दे स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के कारण कई बार उनको जेल हुई लेकिन वे बाहर आते ही अपने लेखों और भाषणों से जनता में जोश भर देते। प्रसिद्ध उर्दू साहित्याकार रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी कहते है कि जब देश गुलाम था तो कर्मवीर में पं माखनलाललली के लेख मेरे और मेरे जैसे लाखो देशवासियों के दिलों में गुलामी के खिलाफ ऐसा जोश भर देते थे जिसे भुलाया नहीं जा सकता। जब देश गुलाम था तब अंग्रेजी भाषा में और भारतीय भाषाओं में देशभक्ति के समर्थन और गुलामी के विरोध में कई करोड़ शब्द बोले गये और लिखे गये और आज किसी के दिल या कानो में गुॅज नहीं रहे हैं पर माखनलालजी के लेख श्रेणी अब तक कानों और दिलों में गूॅज रही है उनके लेख पढ़ते समय ऐसा लगता था कि आदि शक्ति शब्दों के रूप अवतरित हो रही है या गंगा स्वर्ग से उतर रही है।

माखनलालजी मूल रूप से ओज और विद्रोही के कवि थे। उनके काव्य में ओज और विद्रोह का यह स्वर उनके जीवन संघर्ष से आया था। वे आंरभ से ही बड़े निर्भीक थे तथा स्वतंत्रता संघर्ष में सक्रीय भाग लेते थे। क्रांतिकारियों के साथ सीधा संवाद था। जीवन के इन्ही संघर्षो ने उनकी अनुभूतियों को उद्दाम जीजिविशा से भर दिया तथा उन्हें पौरूष का कवि बना दिया। चतुर्वेदी की अनेक कविताओं में हमें उनके जीवन दर्शन की झलक मिलती है अपने संघर्षरत जीवन के संबंध में वे कहते हैं–

सूली का पथ ही सीखा हूॅ सुविधा सदा बचाता आया/मैं बलिपथ का अंगारा हूॅ जीवन ज्वाला जलाता आया

उस समय स्वतंत्रता सेनानियों में त्याग की भावना अत्यंत उत्कट थी। सभी में राष्ट्र के प्रति समर्पित हो जाने की चाह थी और वे अपने बलिदान द्धारा स्वतंत्रता के मंदिर की स्थापना करना चाहते थे। मंदिर में कंगूरा बनने की बजाय वे नींव का पत्थर बनाना अधिक पसंद करते थे चतुर्वेदी जी इस राष्ट्र मंदिर की नींव का पहला पत्थर बनने की इच्छा रखते थे यह उनकी सदाश्यता और विनम्रता समर्पण की पराकाष्ठा है।

माखनलाल जी उनकी साहित्य साधना के लिये अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया वे बड़ी विन्रमता से कहते है 'बड़ों से में आर्शीवाद चाहता हूॅ और छोटो को मैं आर्शीवाद देना चाहता हूॅ। समाज और स्नेहियों के ये पुष्प मुझ पर नहीं मेरे द्धारा साहित्य पर और गुरूजनों पर चढ़ रहे है ये पुष्प उन तरूणों पर चढ़ रहे है जिनकी उमंगों की दुनियॉ हरी है जो मस्तक का पानी लेखनी पर उतारते है राष्ट्र और मानवता के संकेतों पर मस्तक उतार कर रख देने वालों की दुनिया बनाते आये है।'

30 नवम्बर 1959 को सागर विश्वविद्यालय द्धारा इस साहित्य साधक को डी. लिट की उपाधि प्रदान की गई। यह उपाधि उन्हें तत्कालीन उपकुलपति डॉ. द्धारका प्रसाद मिश्र द्धारा खण्डवा में भव्य दीक्षान्त समारोह में प्रदान की गई। लखनऊ विश्वविद्यालय ने भी कवि को डी. लिट की सम्मानित उपाधि से विभूषित करना चाहा, परन्तु कवि ने लखनऊ जाकर दीक्षान्त समारोह में उपाधि लेना स्वीकार नहीं किया ।

कवि स्पष्टवादी व निर्भीक थे। वे कर्मवीर के माध्यम से सामान्तवादियों के भ्रष्टाचार का भण्डाफोड कर रहे थे तब नरसिंहपुराधिपति ने उन्नीस हजार रिश्वत देकर उनका मुॅह बंद करना चाहा परन्तु उन्होंने स्पष्ट कर दिया ऐसा नहीं हो सकता। मैं पत्रकार हूॅ और पत्रकार का कार्य तथ्य को जनता के सामने लाना होता है अपने दायित्व से मुख मोड़ना मेरे लिये असमम्भव है। माखनलाल जी जीवनभर कर्मरत रहे कर्म को प्रतिष्ठा देते हुये उन्होंने लिखा है–

कर्म है अपना जीवनण प्राण/कर्म में बसते है भगवान

* सहायक प्राध्यापक (गृह विज्ञान) मा. च. शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खंडवा (म.प्र.) भारत

कर्म है मातृभूमि का मान/कर्म पर आये हो बलिदान

सन्, 1922 में लिखी कविता पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी के नाम का पर्याय बन गई। इसमें कोई दो मत नहीं कि इस कविता में कवि की त्याग उत्सर्ग और राष्ट्र प्रेम की भावनाएं पूरी सशक्तता के साथ व्यक्त हुई। वे काव्य लिखते थे और काव्य बोलते भी थे। कवि ने पुष्प के माध्यम अपने जीवन की अभिलाषा तो व्यक्त की ही है, इसके साथ ही कवि के रूप में भी उन्होंने कविता धर्म स्पष्ट किया है। इस कविता में कवि के जीवन की एकमात्र अभिलाषा अपने राष्ट्र के लिए स्वयं को बलिदान करने की है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उनकी कविता अत्यंत लोकप्रिय रही है तथा अनेक युवाओं के कण्ठो में इसमे सम्मानित स्थान प्राप्त किया।

चाह नही सुरबाला के गहनों में गुँथा जॉऊ/ चाह नहीं प्रेमीमाला में
बिंध प्यारी को ललचाऊ
मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना तुम फेंक/मातृभूमि को शीष
चढ़ाने जिस पथ जावें वीर अनेक

इस कविता में कार्य अपना जीवन श्रृंगार के सुख और ऐश्वर्य में डुबाना नहीं चाहता।, कवि सत्तासुख नहीं चाहता मोक्ष की एवं भोग की कामना भी नहीं है,। नहीं अपने आपको विशिष्ट समझने का भाव वह तो नितान्त सहज व सामान्य बना रहना चाहता है। वह तो उस पथ पर बिछ जाना चाहता है जिस रास्ते से होकर बलिदानी गुजरते है। यह अमर गीत 18 फरवरी 1922 को बिलासपुर जेल में उन्होंने लिखा चतुर्वेदी जी के पूर्व बलिदान की इस भावना को और उसकी महत्ता को अन्य साहित्यकार ने इतने सबल रूप में प्रस्तुत नहीं किया।

काव्य की ओजस्वी वाणी से जहॉ चतुर्वेदीजी ने काव्य द्वारा राष्ट्रीय भावना को जागृत किया है वही जीवन को हर पहलू को हर दृष्टिकोण से देखकर विभिन्न विधाओं द्वारा प्रस्तुत किया उन्होंने नाटक, कहानी, आलोचना आदि से भी हिंदी साहित्य को समृद्ध किया।कृष्णार्जुन युद्ध, नाट्यकृति, ऐतिहासिक महत्व के साथ ही साहित्य काव्य तथा रंगमचीयता के गुणों से भरपूर है।

कला के अनुवाद कहानी संग्रह की कहानियों का जन्म, जीवन के घात-प्रतिघात से हुआ है यह उनके जीवन कई पहलुओं को प्रकाशित करती है साहित्य देवता में साहित्य और जीवन के विविधरूपों की हृदय स्पर्शी आलोचना है वही 'चिन्तक की लाचारी' में चतुर्वेदी जी के विचार और चिन्तन की सुस्पष्ट अभिव्यक्ति हुई इन भाषणों में भाषा, साहित्य, और कला चिन्तक प्रचारक के गुण उत्तरदायित्व, साहित्य में मौलिकता, साहित्य सजृन जैसे विषयों पर विचार व्यक्त किये है। भाषा पर ऐसा अधिकार था कि उनके बारे में डॉ. सच्चिदानंद ने पटना में कहा था 'माखनलाल जी बोलते है यदि वही हिन्दी है तो में हिन्दी का प्रबल समर्थक हूँ।'माखनलाल व्यक्तित्व एक ऐसा प्रकाशस्तम्भ है जो साहित्यकारों, पत्रकारों आलोचकों तथा वक्ताओं सभी के लिये प्रेरणा का स्त्रोत और अनुकरणीय है।

हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर ने उनके व्यक्तिव के बारे मे लिखा है 'पं. माखनलाल चतुर्वेदी शरीर से योद्धा, हृदय से प्रेमी, आत्मा से विह्व भक्त, और विचारो से क्रांतिकारी है।'

30 जनवरी 1968 शाम साढे पॉच उन्होंने यह नश्वर देह त्याग दी। यह कैसा संयोग था कि माखनलाल चतुर्वेदी, महात्मा गांधी के निर्वाण दिवस पर ठीक उसी समय विदा हुए जबकि गांधीजी हुये थे। 31 जनवरी को प्रात: 9 बजे।

सारा खण्डवा नगर शोक संतप्त हो उनकी अंतिम विदा में शामिल हुआ ऐस शलाका पुरूष को शत-शत प्रमाण।

शिर हो चिन्तन का सामगान
डर हो बलिदानों का प्रमाण
उठ कोटि, कोटि के महाप्राण।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

****

स्त्री शिक्षा कल आज और कल

डॉ. आशा शुक्ला *

प्रस्तावना – शिक्षा मानव विकास का केन्द्र है, उसी से ही मानव का पूर्ण विकास संभव है। और फिर स्त्री शिक्षा इसका तो महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है क्योंकि स्त्री दोनो कुल का विकास करती है। यदि वह पढ़ी लिखी व समझदार है तो वह दोनो ही परिवार व आस पड़ोस का माहौल भी बदल देती है। शिक्षा और विकास एक ही सिक्के के दो पहलू है। वर्तमान समय में स्त्री व पुरूष दोनो का शिक्षित होना समाज व राष्ट्र के हित में है। एक राष्ट्र के रूप में हमारी पूरी क्षमता का उपयोग तभी हो पाता है, जब महिला में पर्याप्त रूप से षिक्षित हो, क्योंकि बच्चों का भविष्य निर्माण में व उनके सर्वागीण विकास के लिए स्त्री शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है।

भारत में स्त्री शिक्षा को कालक्रम के अनुसार युगों में खण्डित किया गया है। वैदिक युग में स्त्री शिक्षा अपने उत्कर्ष पर था। स्त्रियॉ पुरूषों के समान बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्राप्त करती थी। दर्शन व दर्शन शास्त्र में स्त्रियां बहुत निपुण थी उन्हें यक्ष संवाद विद्या अध्ययन करने का पूर्ण अधिकार था तथा स्त्री व पुरूष पुत्र एवं पुत्रियों दोनो को समान अध्ययन करने के साथ-साथ उपनयन संस्कार सम्पन्न कराने का पूर्ण अधिकार था। ऋगवेद में अनेक ऋचाओं में महिलाओं ने योगदान दिया। अपाला, रोयशा, उर्वशी, विश्ववारा, सिकता, निवावटरी, घोषा, लोपामुहा आदि पंडित स्त्रियां इनमें अधिक प्रसिद्ध थी। पति के साथ समान रूप से यज्ञ में सहयोग करती थी, यज्ञ सम्पादित करती थी। श्रीराम के युवराज पद पर अभिषेक के समय तक कौशल्या ने यज्ञ किया था।

वैदिककाल में छात्राओं के दो वर्ग थे, एक सद्योवधु तथा दूसरा ब्रम्हवादिनी, सद्योवधु वे छात्रायें थे जो विवाह के पूर्व तक कुछ वेद-मंत्रों और याक्षिक प्रार्थना का ज्ञान प्राप्त कर लेती थी। इन छात्राओं को नौ वर्ष तक वेद व्याकरण, संगीत, ज्योतिष छंद आदि की शिक्षा दी जाती थी। ब्रम्हवादिनी वे छात्रायें थी जो अपनी शिक्षा पूर्ण करने में अपना जीवन लगा देती थी तथा कुछ स्त्रियां पूरा जीवन अध्ययन में लीन रहती थी और तो कुछ विवाह भी नहीं करती थी व कुछ अपने ही समान गुण धर्म मार्गी युक्त ऋषियों को पति के रूप में स्वीकार करती थी। ऐसी स्त्रियां बहुमुखी प्रतिभा की धनी होती थी।

पूर्व वैदिक युग भांति उत्तर वैदिक युग में भी स्त्रियां ब्रम्हचार्य में रह कर शिक्षा ग्रहण करती थी। उनका उपनयन संस्कार भी होता था। अर्थवेद में कहा गया है कि ब्रम्हचर्य द्वारा ही कन्या योग्य पति को प्राप्त करने में सफल हो सकती थी। अत: कन्या लड़कों के समान ब्रम्हचर्य को धारण करके शिक्षा ग्रहण करें। विवाहित स्त्रियों को हम यज्ञों में मात्र लेते हुए पति है। कुछ स्त्रियों ने धर्म एवं दर्शन के क्षेत्र में निपुणता तथा विद्वता प्राप्त कर लिया था। वैदिक गान के अतिरिक्त वह ललित कलाओं में भी पारंगत होती थी किन्तु समय के साथ-साथ हम स्त्री शिक्षा में गिरावट आ गई। कन्याओं को गुरूकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजने की प्रथा समाप्त हो गई तथा घर पर ही शिक्षा देने का समर्थन किया गया। अब वे केवल अपने ही पिता, माई तथा चाचा आदि से ही शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। ऐसी स्थिति में केवल कुलीन परिवार की कन्यायें ही शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। परिणाम स्वरूप उनके धार्मिक अधिकार कम हो गये।

सूत्रकाल में स्त्रियों का उपनयन संस्कार बंद हो गया तथा विवाह के अतिरिक्त व उनसे संबंधित अन्य संस्कारों में वैदिक मंत्र का उच्चारण नहीं होता था। कन्याओं के विवाह की आयु भी घटा दी गई जिससे उसका प्रभाव उनकी शिक्षा पर पड़ा। इसके पश्चात शिक्षा केवल सम्पन्न एवं कुलीन परिवारों में लड़कियों को शिक्षा का अवसर प्राप्त था। राज परिवार की महिलाओं को ही शिक्षा मिल पाती थी उन्हें ललित कलाओं, संगीत, नृत्य, चित्रकारी, मालाकारी आदि की कलाओं का विधिवत अध्ययन दिया जाता था।

महाकाव्य काल में भी स्त्री शिक्षा में गिरावट आयी। सम्पन्न महिलाओं को शिक्षा के अवसर सीमित थे। केवल उच्च वर्ग की महिलायें ही पर्याप्त षिक्षित होती थी। रामायण में कौषिल्या तथा तारा को 'मंत्रविद' कहा गया है, सीता नित्य संध्या करती हुई तथा क्षेत्रीय वेदांत का अध्ययन करती हुई दिखाई गई थी। कैकेई अस्त्र, शस्त्र की शिक्षा में निपुण थी। महाभारत में सुलमा, द्रोपदी तो पंडित थी ही। उत्तरा में अर्जुन से संगीत तथा नृत्य इस तरह महिलाओं लौकिक के साथ-साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी ग्रहण करती थी।

महाकाव्य काल में वैदिक युग की भांति सह शिक्षा प्रचलित थी। पार्वती काल में नारी शिक्षा पर प्रतिबंध लगने लगा था। यद्यपि बौद्ध परम्पराओं से ज्ञात होता है कि स्त्रियां शिक्षित व विद्वान हुआ करती थी, विद्या, धर्म दर्षन के प्रति उनकी बहुत ज्यादा रूचि थी। मेरी गाथा के कवयित्रियों में 32 आजीवन ब्रम्हचारिणी और 18 विवाहित मिक्षुकिया था। उनमें सुमेधा शुभा और अनोप या उच्च शिक्ष वंश की कन्यायें थी। जिनसे विवाह करने के लिये राजकुमार और सम्पत्तिशाली सेठों के पुत्र उत्सुक थे। मिक्षुकी सेना उस युग की उच्च शिक्षा प्राप्त स्त्री थी जिसकी विद्वता की ख्याति दूर-दूर तक फैली थी। इस युग की साधारण स्त्रियां ज्ञान बिपासु थी। ब्रम्हचर्य का जीवन यापन करके वे अत्यंत मनोनिर्देश पूर्वक ज्ञान अर्जित करती थी। जैन महिला से भी विदुशी स्त्रियों के बहुत से उदाहरण प्राप्त होते है। इस युग में अनेक महिलायें शिक्षिका बनकर आध्यात्मिक का जीवन व्यतीत करती थी। जो अपना शिक्षण कार्य उत्साह और लगन के साथ सम्पन्न करती थी ऐसी स्त्रियों उपाध्याय कही जाती थी। ये उपाध्याय छात्राओं को पढ़ाया करती थी तथा उन्हें अन्य विषयों का भी ज्ञान प्राप्त करती थी इनकी अलग अपनी शिक्षण शालाएँ हुआ करती थी। जहां महिलायें जाकर शिक्षा ग्रहण करती थी।

पुराणों से यह ज्ञात होता है कि नारी शिक्षा के दो रूप है। एक आध्यात्मिक तथा दूसरा व्यवहारिक, आध्यात्मिक ज्ञान की अभिव्यक्ति योग और तप पर निर्भर करती थी, जिससे स्त्री का ब्रम्हचर्य, सदाचरण शीलता, सच्चरित्र, सदव्यवहार शामिल था।

पूर्व मध्यकाल की भांति मध्यकाल में भी स्त्रियों का शैक्षणिक अवनति

* सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) इंदिरा गाँधी गृहविज्ञान कन्या महाविद्यालय, शहडोल (म.प्र.) भारत

जारी रही साधारणतया स्त्रियों को न तो शिक्षा दी जाती थी न समाज में सम्मान, सन 1902 से 1922 के कालखण्ड में शिक्षा के सभी चरणों में महिला शिक्षा का उत्तरोत्तर विकास हुआ। सन 1921-22 ई0 में प्राथमिक कक्षाओं में छात्राओं का नामांकन बढ़कर बारह लाख के करीब पहुंच गया एवं माध्यमिक कक्षाओं में इसकी छ: गुना संख्या बढ़ गई। मेडिकल, तकनीकी, व्यवसायिक इसके अलावा हर श्रेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। 1922 से 1947 के समय में समाज सुधार एवं गांधी नेहरू जी द्वारा संचालित आंदोलनों, लड़कियों के विवाह की उम्र बढ़ने इसके साथ सन् 1926 में सम्पन्न 'अखिल भारतीय महिला सम्मेलन' हर्टोग समिति के सिफारिशों के फलस्वरूप प्राथमिक शिक्षा में नामांकन की संख्या 12 लाख से बढ़कर 35 लाख तक पहुंच गई। इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा में प्रवेश की संख्या 37000 से बढ़कर 2 लाख 81 हजार हो गई। इस काल में उच्च शिक्षा में प्रवेश की गति काफी तेजी से बढ़ रही है। 1921-22 में यह संख्या 1/529 थी जो 1946-47 में बढ़कर 23028 हो गई आंकड़ों से स्वतंत्रता पूर्व की महिला शिक्षा का विकास का प्रमाण अवश्य मिलता है। पर कुल मिलाकर देखे तो लड़कियों का नामांकन उनकी संख्या मात्र 60 प्रतिशत ही है।

ब्रिटिश काल से ही स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी प्रयास शुरू हो चुका था एवं बहुत से सामाजिक आंदोलन हुए यद्यपि स्वतंत्रता के समय तक स्त्री शिक्षा को अपेक्षित मुकाम हासिल नहीं हो सका। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् सरकार ने लगभग सभी पंचवर्षीय योजनाओं, शैक्षणिक आयोग एवं समितियों संवैधानिक उपबंधों के द्वारा स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया।

सन 1950-51 में प्राथमिक शिक्षा व उन कक्षाओं में 54 लाख बालिकायें नामांकित थी वहीं 1995-96 में इनकी संख्या बढ़कर लगभग 5 करोड़ हो गई। 1950-51 उच्च शिक्षा में 6 लाख बालिकायें नामांकित थी जबकि 1995-96 में इसकी संख्या बढ़कर लगभग 01 करोड़ 80 लाख हो गई। इसी प्रकार हायर सेकेण्ड्री में 1950-51 में 2 लाख से बढ़कर 1995-96 में 88 लाख बालिकायें हो गई। 1996-97 में उच्च शिक्षा में शिक्षा 21 लाख 92 हजार बालिकायें नामांकित थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आंकड़ों के अनुसार जहां 2000-01 में टेक्नोलॉजी कोर्स में दाखिला लेने वाली लड़कियों की संख्या लगभग 25000 थी वहीं 2009-10 में इसकी संख्या बढ़कर 280000 हो गई। इसके पश्चात 2012-13 में 3 लाख 50 हजार हो गई। वर्तमान समय में लगभग 80 लाख लड़कियॉ उच्च शिक्षा हासिल कर रही है। 2020 तक लगभग 01 करोड़ 25लाख होने की उम्मीद है। 2020 तक कुल जनसंख्या में आधी महिलायें होने ही संभावना है।

शिक्षा के ऐतिहासिक स्थिति देखने से ऐसा स्पष्ट होता है कि स्त्री शिक्षा ने ऐतिहासिक कालखण्ड में अनेक अनवति एवं उन्नतियां हुई है। ब्रिटिश शासनकाल में स्त्री शिक्षा की स्थिति एवं स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् शिक्षा के क्षेत्र में काफी सुधार आया है। वर्तमान समय में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा इतनी योजनाये शिक्षा में प्राथमिकता दी गई है। जिसमें लगभग गांव एवं शहरों की सभी बालिकायें महिलाओं को प्राथमिक एवं मिडिल शिक्षा दी जा रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना, विपत्तिगस्त महिला, बालिकाओं को समाज की मुख्यधारा से जोड़कर पुन: स्थापित किये जाने के लिए महिला बाल विकास विभाग मध्यप्रदेश शासन की अभिनव योजना भी प्रांरभ की गई है जिससे ग्रामीण एवं मध्य व शहरी क्षेत्रों की बालिकाओं महिलाओं को सुविधा मिल रही है व उनका लाभ उठाकर आगे बढ़ रही है। इसके साथ महिलाओं को अधिकार के साथ पूरी आजादी भी मिलें क्योंकि आज आवश्यकता है कि देश समाज व पूरे विश्व में महिलायें देश के विकास में भागीदारी निभाती हो इसलिए इनकी पूरी सुरक्षा, सहयोग प्राप्त हो ताकि बेखाब होकर अपने पथपर आगे होती रहें, अपने पूरे आत्मविश्वास व सम्मान के साथ यही मात्र भूमि के साथ मातृशक्ति का भी सच्ची आजादी होगी। महिलाओं के विकास में पूरा बल मिलेगा क्योंकि कहा भी तो जाता है कि यदि 'पुरूष साक्षर होता है तो एक व्यक्ति साक्षर होता है। जबकि यदि महिला साक्षर होती है तो एक नहीं दो परिवार भी साक्षर हो जाते है।'

यदि महिला शिक्षा को हम हर समय व युग में प्राथमिकता दें तो महिलाओ का पूर्ण विकास हो सकेगा क्योंकि बीच-बीच में कोई युग में प्राथमिकता दी जाती है। एवं कभी नहीं दी जाती इससे उनको ज्यादा ध्यान न देने के कारण पिछड़ जाती है। ग्रामीण एवं पिछड़े राज्यों में दंगो में भी महिलाओं की शिक्षा में प्राथमिकता दी जा रही है। यदि देश राष्ट्र विश्व का विकास करना है तो महिला शिक्षा का आगे भी प्राथमिकता देनी होगी तभी सम्पूर्ण विकास हो सकेगा जिससे कल आज और कल संवर सकेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. रामायण।
2. ऋगवेद।
3. वैदिक साहित्य एवं संस्कृति।
4. महाभारत 4:10:
5. अर्थवेद।
6. पतांजलि।
7. दैनिक भास्कर 2015
8. हिन्दुस्तान मार्च 2013
9. आज की प्रतियोगी(हिन्दी पत्रिका 2013)
10. मध्यकालीन भारत (भाग 2)
11. नेट।

****

श्रृद्धा की साधना से रामायण के रचयिता तक

प्रो. जी.एस. वास्कले *

प्रस्तावना – सनातन धर्म के प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि श्रृद्धा व भक्ति से चमत्कारिक कार्यों को करके ऐसी प्रेरणात्मक स्थितियों, कहानियों, गाथाओं व ग्रंथों की रचना हुई है जिनके अध्ययन चिंतन–मनन से जीवन में प्रेरणा का रक्त संचारित कर एक से एक यथार्थ व चमत्कारिक जीवन की रचना हुई है। कहा भी जाता है कि श्रृद्धा से पहाड़ों को भी हिलाया जा सकता है, एक मनुष्य के जीवन में कब श्रृद्धा का संचार हो सकता है कहा नहीं जा सकता लेकिन जब भी मनुष्य के जीवन में श्रृद्धा व भक्ति का संचार हुआ है मनुष्य ने निश्चित ही पूरी तरह समर्पित होकर अपने जीवन को श्रृद्धा और भक्ति के लिए समर्पित कर दिखाया है।

प्राचीन समय के ऐसे ही कुछ उदाहरणों से अनुसूचित जनजाति विशेष के मनुष्यों ने श्रृद्धा व भक्ति पूर्ण जीवन व्यतीत कर प्राचीन ग्रंथों, वेदों, रामायण, महाभारत व प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्वर्ग में अपना नाम प्रतिस्थापित किया है। जिन्हें यह देश कभी भूला नहीं सकता, परन्तु वर्तमान समय वैज्ञानिक व कम्प्यूटरीकृत नेट इंटरनेट व मोबाईल तकनीक जमाने का समय है। जिसमें इनके कार्यों को प्रतिस्थापित कर प्रेरणात्मक व आदर्श जीवन व्यतीत किया जा सकता है। ऐसे ही एक व्यक्तित्व व कृतित्व पर आधारित चिंतन की लाईन वाल्या भील से रामायण के रचयिता वाल्मिकी तक एक प्रेरणात्मक वाक्या के संबंध में कहा जा सकता है कि–

भारत में वाल्मिकी रामायण का नाम बड़े आदर्श से लिया जाता है। यह किसी पंडित, पुरोहित, ज्ञानवान, विद्धान लेखक की कृति नहीं है। पढ़ने–सुनने में आता है कि प्राचीन समय में एक वाल्या भील अपना दीनहीन जीवन व्यतीत करता था, जीवन जीने के लिए यह पापी पेट क्या–क्या करवाता है, पेट भरने के लिये मनुष्य को कुछ न कुछ तो करना ही पड़ता है। इसी फिराक व नासमझी में वह रास्ते के राहगीरों को लूटकर अपना जीवन व्यतीत करता था। इसलिए अनुसूचित जनजातियों की ऐतिहासिक कहानियों में वालिया भील लूटेरा या वालिया भील डाकू कहलाता था। रास्ते के राहगीरों को पता होने पर उस रास्ते पर निकलना राहगीरों ने बंद कर दिया जिस रास्ते पर वाल्या भील लूटेरा लूट को अंजाम देता था। परन्तु एक दिन ऐसा आया जिस दिन उसके पापी पेट को भरने के लिए उसे कुछ भी मिलना मुश्किल हो गया। वह कहने लगा मरा–मरा, कहते–कहते राम–राम कहने लगा और उसके जीवन में श्रृद्धा साधना व भक्ति का संचरण हुआ और श्रृद्धा व भक्ति के संचरण से उसने एक बड़ा ग्रंथ जिसे रामायण कहा जाता है कि रचना कर डाली। जिसे यह भारत वर्ष वाल्मिकी रामायण के नाम से जानता व पूंजता है। इस ग्रंथ को इस युग व युगों–युगों तक अध्ययन कर आदर्श जीवन बनाकर मनुष्य जीवन व्यतीत कर सकता है। अत: यह चिंतनीय है कि कब मनुष्य के जीवन में शब्दों व वाक्यों के हेर–फेर से श्रृद्धा व भक्ति का संचरण हो जाय और मनुष्य के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन हो जाय निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता है। देखिये और सुनिये कैसे वाल्या लूटेरा से रामायण का रचयिता हो गया। उनके श्रृद्धा व भक्ति से ओत–प्रोत चमत्कारिक जीवन को विस्मृत नहीं किया जा सकता और मनुष्य चाहे तो इसके प्रेरणात्मक अध्ययन से अपने जीवन में यथार्थ व चमत्कारिक जीवन बनाकर जीवन व्यतीत कर सकता है।

वाल्मिकी रामायण में अनेक आदर्श पात्रों का रोचक वर्णन दिया गया है और इस ग्रंथ में वर्णित पात्रों के अध्ययन तथा मनन से एक आदर्श इंसानियत पर आधारित जीवन मनुष्य बना सकता है। मानव जीवन ही आदर्शों, सद्गुणों आदि अच्छे गुणों पर आधारित होना चाहिए जिसे अच्छी तरह से वाल्मिकी रामायण में रचित किया गया है। मर्यादा पुरुषोत्ताम श्रीराम के जीवन का सम्पूर्ण वर्णन बाल्यकाल से लेकर उनके अयोध्या के राजा बनने तथा राम–रावण युद्ध में कैसे असत्य पर सत्य की विजय को दर्शाया गया है जिसे यह संसार युगों–युगों तक नहीं भूला सकता है। ऐसे ही विभिन्न पात्रों में जानकी माता सीता का भी आदर्श नारी के रुप में चरित्र–चित्रण किया गया है जिसे भारतीय नारी वर्तमान समय में भी पूजती है और उन्हें भूला नही सकती। ऐसे कई पात्रों में भाई, मित्र, माता–पिता, पत्नि सभी पारिवारिक संबंधों पर आधारित आदर्शात्मक चरित्र–चित्रण वाल्मिकी रामायण में पढ़ने को मिलता है। जिसे आत्मसात कर इस युग के मनुष्य भी अपने जीवन को अच्छा आदर्शात्मक अध्यात्मिक इंसानियत मानवता पर आधारित बना सकते हैं। संबंधों पर आधारित जीवन मनुष्यों में मर्यादा, अनुशासन, सत्य, ईमानदारी जैसे बहुमूल्य सामाजिक, राजनीतिक मूल्यों को आत्मसात करके सृजनात्मक एवं आदर्शात्मक जीवन व्यतीत कर सकते है। संपूर्ण दृष्टि से वाल्मिकीजी का ग्रंथ सम्पूर्ण मानव जीवन की संरचना पर आधारित है और यह भारत भूमि का अत्यधिक पूजनीय ग्रंथ बना है।

वाल्या भील की कहानी पर आधारित लेखक के यह अपने प्रेरणात्मक विचार हैं। जय हिन्द!

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. वाल्मिकी रामायण
2. रामचरितमानस, टीकाकार : हनुमान प्रसाद पोद्दार, गीता प्रेस गोरखपुर
3. रामायण : विकिपीडिया
4. मौलिक

* प्राध्यापक, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सेंधवा, जिला – बड़वानी (म.प्र.) भारत

Coalition Government in India

D.C. Chauhan*

Abstract: The practice of coalition government has been successfully established in the Indian Political system. The coalition government provided the opportunity to regional parties to participation in the Union cabinet, it checked the misuse of power by the Union government and it promoted the co-operative federalism in the country, but it created political in-stability, confrontation, in-cordination and difficulties in strong decision making. Hence, the collective responsibility, commitment, a code of conduct and democratic conventions should be developed for the smooth functioning of coalition government in the country.
Keywords: Coalition partners, Political interests, Common Minimum Program, Political in-stability, Collective responsibility.

Introduction - India has a democratic political system, which intermediated by multi-party system. The practice of coalition government has started in 1989 and now it has been established at the Centre and in several states. Usually the coalition government has successfully worked in the country. But, in some of the cases, coalition government had failed owing to vested interests of its coalition partners. It has negative consequences on the Indian political system. This scenario provides the relevance of this research paper. This paper critically analyses the periods of various coalition governments, the positive and the negative consequences of coalition governments and it suggests remedial measures for smooth working of coalition government.

The word 'coalition' means 'to go' or to grew together. Coalition means uniting into the alliance. In the Political Science the term coalition is used for an alliance between various political groups for the exercise or control of political power. Thus, the coalition partners are expected to compromise, accommodate and adjust him in the coalition government. They don't lose their identity and they agree to a common agenda of governance. Although, the basic principles of coalition partners collide against each other and they can withdraw from the coalition government when they find it difficult. We can critically analyse the periods of various coalition governments under the following heads:

1. Janata Party Government (1977-1979) : In January (1977), Janata Morcha, Bharatiya Jan Sangh, Bharatiya Lok Dal, Socialist Party and Congress for Democracy decided to merge themselves and they formed the Janata Party. The Janata Party won 295 highest seats and its allies won 303 seats in the Lok Sabha election, 1977. The Janata party parliamentary party leader, Morarji Desai, took oath as the first non – Congress Prime Minister on 24 March,1977[1]. In fact, it was not a coalition government, because its four partners had agreed to merge and fought the election on single manifesto and on a shared symbol. The Janata party government favored the non-alignment policy, improvement relations with South Asian countries, USA, Britain, France, USSR, decentralisation, rural development and labour intensive industry. It enacted the 44th Constitutional Amendment Act,1978. But, these policies could not succeed. The mutual differences between the various political groups created tussle and the followers of Charan Singh left the Janata party and they formed the new party,i.e.,Janata party (s).Consequently, a no-confidence motion was moved in the Lok Sabha by the Leader of Opposition against the Janata Party Government headed by Morarji Desai. The Janata Party Government lost his majority in the House owing to defection in the party. Hence, the Prime Minister, Morarji Desai, submitted his resignation in July, 1979. Madhu Dandvate observed,"... temperamental incompatibility of some leaders and fierce inner controversy over the dual loyalty of the Jan Sangh activists to the Janata Party as well as the RSS, wrecked the Janata Party and its government, which in reality was a coalition government."[2]

On the other hand, the Congress (I) party supported to Charan Singh to form the government. Hence, the Janata Party(s)leader Charan Singh formed the government and he took oath as the Prime Minister on July 28, 1979 with the outside support of the Congress (I)[3]. The Janata Party(s)-led three party coalition had 182 seats : 92 seats of Janata party (S), 75 seats of Congress (O),15 seats of Socialist party and outside support 7 members of CPI and 73 members of the Congress (I)in the Lok Sabha. In fact, the Janata Party (S) was a party of defectors and it was

*Associate Professor (PoliticalScience) Govt. College, Bawal, Rewari (Haryana) INDIA

not recognised as a party in the Lok Sabha . The Congress (I) demanded that the Special Courts to prosecute the emergency cases be scrapped. Charan Singh led government was unable to accede this demand. In view of defeat on a vote of confidence in the Lok Sabha Charan Singh resigned after 24 days in office. The Charan Singh government remain in power for just about four months. It became Charan Singh the first Prime Minister who never face the House, which was inconsistent with the parliamentary democracy in the country. Moreover, Prime Minister, Charan Singh, advised the President to dissolve the Lok Sabha and order a mid-term poll. Thus, the Lok Sabha election was held in January, 1980, the Congress(I) again came to power.

2. National Front Government (1989-1990): The 9th Lok Sabha election was held in November, 1989, the non-Congress groups- rightists and leftists have joined hands to back the National Front led by V.P. Singh. The Congress (I) won highest 197 seats in the House, but his leader Rajiv Gandhi refused to form the government. The Janata Dal emerged as second largest party with 143 seats in the Lok Sabha. Hence, The Janata Dal – led National Front (NF) parliamentary party leader V.P. Singh took oath as Prime Minister on December 2,1989[4]. The National Front consisted Janata Dal ,Telugu Desam Party (TDP), Asom Gana Parshid (AGP),Dravida Munnetra Kazhagam (DMK), Jharkhand Mukti Morcha (JMM) etc. It was the first minority-cum-coalition government with outside support of BJP and Left parties like Communist Party of India (CPI), Communist Party of India – Marxist (CPI-M), Indian Forward Bloc (IFB), Revolutionary Socialist Party (RSP). The National Front (NF) Government started the implementation of its election manifesto and Agenda for Governance to fulfill its objective of social justice. It focused on Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Minorities, Labour Classes, Farmers and so on. It enacted the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocites) Act,1989. On the other hand, the dissatisfied Chandra Shekhar go hand with Deputy Prime Minister, Devi Lal, and they created the problems in the working of coalition government. Consequently, Prime Minister, V. P. Singh, announced the implementation of Mandal Commission Report on August 7,1990, which provides 27% reservation to the Other Backward Classes (OBCs) in government jobs and educational institutions. It led the widespread strikes, sabotage, violence and self immolation by students in the country. It weakened the V. P. Singh Government. In counter-attack of Mandalism, the BJP has began his Ayodhya campaign. In 1990, the BJP and the Vishwa Hindu Parishad (VHP) announced their decision to go ahead with the construction of the Ram Temple in Ayodhya (U.P.). Thus, the BJP leader, L.K. Advani, started a Rath Yatra from Somnath (Gujarat) to Ayodhya (U.P.). It created a communal tension in the country. Hence, V.P. Singh Government took a decisive action against this matter and L.K. Advani was arrested by the state government of Bihar under the National Security Act on October 23, 1990[5].Consequently, the BJP withdrew its support from the NF Government and the Government lost his majority in the Lok Sabha. The NF Government defeated by 142/346 votes on the confidence motion in the Lok Sabha on November 7,1990[6].On the other hand, Chandra Shekhar and Devi Lal had engineered a split in the Janata Dal and they formed the new party, the Janata Dal (Socialist). Thus, the NF coalition government remained in power for eleven months only. The first major effort to build an alternative to the Congress (I) had ended in failure. The then President, R. Venkataraman, observed, it is my impression that if V. P. Singh had headed a government with a clear majority instead of dependent on a conglomeration parties mutually destructive to each other, he would have given a good administration to the country. Being dependent on parties with different objectives and ideologies, he could not withstand pressures from discordant group[7].

The Congress (I) supported to Chandra Shekhar to form the government. He was already waiting to fulfill his cherish of become the Prime Minister. Hence, the Janata Dal (Socialist) headed by Chandra Shekhar formed a minority-cum-coalition government with the outside support of Congress(I), AIADMK, Bahujan Samaj Party (BSP), Muslim League, J&K National Conference, Kerala Congress (M), Shiromani Akali Dal (Panthic) and a few independent members. Chandra Shekhar took oath as the Prime Minister on November 10, 1990[8]. The Prime Minister, Chandra Shekhar, tried to solve the terrorism in Punjab, Jammu & Kashmir and North-East. The government took efforts for welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes and Minorities. But, the JD(S) government did not provide good governance and it failed the solution of economic crisis of the country. Moreover, it mortgage the gold of the country to the World Bank for money. The Congress (I) withdrew its support from the JD(S) government in view of his political interests. Consequently, the Prime Minister, Chandra Shekhar, was forced to resign in March, 1991, but he advised President to mid-term poll to the Lok Sabha. Thus, Chandra Shekhar government survived only four months. Obviously, the major effort to provide an alternative government to the Congress (I) was again failed. As Robert L. Hardgrave and Stanley A.Kochanek observed," India's second major effort to build a centrist alternative to the Congress (I) Party had ended in failure."[9]

3. United Front Government (1996-1998): A hung parliament has emerged after the 11th election to the Lok Sabha in May, 1996. The BJP emerged as a single largest party with 163 seats in the House. As established democratic convention the President, Shankar Dayal Sharma, invited the BJP parliamentary party leader, Atal Bihari Vajpayee, to form the government. Atal Bihari Vajpayee took oath as the Prime Minister on May 16, 1996[10]. However, the Vajpayee government was enabled to obtain the support from any other parties in the Lok Sabha as they decided

not to support the BJP government of his so-called communal face. Hence, the Vajpayee government was forced to resign after 13 days, which is the shortest term government in Indian parliamentary history.

The leaders of National Front, Left Front and some regional parties were formed the United Front (UF) after the Lok Sabha election. It was a alliance of 14 political parties led by Janata Dal including Samajwadi Party, CPI-M, CPI, RSP, IFB, Tamil Manila Congress, DMK, TDP, AGP, All-India Indira Congress (Tiwari), Karnataka Congress Party and Madhya Pradesh Vikas Congress. Thus, the UF become the third front at national level politics. The Congress(I) supported the UF government from the outside. H.D. Deve Gowda (Janata Dal) unanimously elected the leader of UF parliamentary party leader and he took oath as the Prime Minister on June 1,1996[11]. The coalition government was formed a Common Minimum Program(CMP), which included the preservation of national unity, social and economic equality, friendly relations to other countries, and a commitment to secularism and federalism. But, owing to lack of national stature and experience of Prime Minister, H.D. Deve Gowda, and personalities clashes among the UF leaders, the UF Government did not take any major policy decisions. Ajay Mehra observed, the Deve Gowda had Government had developed a CMP, which was based not only on the members of the coalition partners, but also incorporated the political agenda of those parties, which had not participated in the government[12].

In fact, the UF Steering Committee had became a super-cabinet and the CPI-M General Secretary, Hari Kishan Singh Surjeet, became the Super Prime Minister. All above, Prime Minister, H. D. Deve Gowda, used the Central Bureau Investigation (CBI) as an instrument to fulfill his political interests against Congress (I) leaders. Consequently, the Congress (I) president, Sita Ram Kesari, decided to withdrew support to the UF government. The first UF government survived only ten months. It created political instability in the country. The leaders of the UF tried for consensus candidate for the post of Prime Minister. The name of Bihar Chief Minister, Laloo Prasad, Samajwadi Party leader, Mulayam Singh, TMC leader, G.K. Moopnar and Janata Dal leader, Ram Vilas Paswan, were discussed. The TDP leader and Chief Minister of Andhra Pradesh, N. Chandrababu Naidu, played the role of king maker in the selection of the name of Prime Minister candidate. Lastly, the UF Steering Committee has decided the name of External Affairs Minister, Inder Kumar Gujral, for the Prime Minister and the second UF coalition-cum-minority government formed and Inder Kumar Gujral took oath as the Prime Minister on April 21,1997[13].

The UF coalition government tried to implementation of its Common Minimum Program (CMP). It continued welfare of Scheduled Casts, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, minorities, labour class and womens, enforcement of Gujral doctrine for friendly relations to neighboring countries, economic liberalisation and co-operative federalism. However, the UF coalition government could not take any major decision due to weak personality of Prime Minister, I. K. Gujral, and internal resistance of its coalition partners. Moreover, the Jain Commission Report, 1991, created tussle between UF government and Congress (I) party. The Commission indicated the nexus between DMK and LTTE and the involvement of DMK in assassination of Congress (I) leader Rajiv Gandhi. The Congress(I) party demanded the explusion of DMK ministers from the Cabinet, but prime minister I.K.Gujral could not fulfill this demand. Hence, the Congress(I) party withdrew its support to the UF government and it forced to resign of the government.

4. BJP-led Coalition Government (1998) : A hung parliament has emerged after 12th Lok Sabha election in March, 1998. The BJP won 179 seats and it emerged as the single largest party in the Lok Sabha. Hence, the President has invited to the BJP parliamentary party leader, Atal Bihari Vajpayee, to form the government according to the established democratic convention. A B Vajpayee took oath as the Prime Minister on March 19, 1998[14]. The BJP-led minority coalition government consisted 13 pre-election and 9 post-election allies and outside support by TDP and National Conference. The BJP allies were Shiv Sena, Samata Party, Shiromani Akali Dal (SAD), Lok Jan Shakti Party (LJSP), Biju Janata Dal (BJD), All India Anna Dravida Munnetra Munnetra Kazhagam (AIADMK), Pattali Makkal Katchi(PMK), Marumalarchi Dravida Munnetra Kazhagam (MDMK), Trinamool Congress (TMC), Telangana Rashtra Samithi (TRS), Arakshan Virodhi Party (AVP) etc. The BJP developed a consensus with its coalition partners for smooth functioning of the coalition government. The coalition partners formed the National Agenda for Governance. The BJP avoided the controversial issues like deletion of Article 370, construction of Ram temple at Ayodhya and introduction of Uniform Civil Code and so on. The coalition government faced the challenges from its coalition partners like Shiv Sena of Maharashtra, Samata Party of Bihar and AIADMK of Tamil Nadu. On March, the coalition government faced the economic problems like large fiscal deficits, inadequate infrastructure, slow economic growth, high un-employment and a stalled process of economic reforms. Moreover, it conducted nuclear tests at Pokhran in May, 1998 that led the imposition of economic sanctions on country by the USA and the Western Europe. The government tried to tackled the situation. It opened the Insurance sector for FDI, passed the investment friendly budget, passed a revised Patent Bill (1999), and a bill to create 3 new States named Uttrakhand, Jharkhand and Chhattisgarh and so on. However, the coalition government could not take any major policy decision owing to internal resistance of its coalition partners, lack of experience and lack of relevant economic policy.

All above, a no-confidence motion was passed against Vajpayee Government in the Lok Sabha on April 17, 1999 by one vote and the government was forced to resign[15]. It

pave the way for mid-term election to the Lok Sabha again for the third time in the three years.

5. NDA Government (1999-2004): The 13th Lok Sabha election was held in October, 1999. The BJP formed the National Democratic Alliance (NDA), which consisted 24 political parties named BJP, Shiv Sena, Shiromani Akali Dal, Samata Party, LJP, TDP, JD (Sharad Yadav group), DMK, MDMK, PMK, TRS, MGR-Kazhagam, BJD, TMC, MGR-ADMK, Sikkim Democratic Front etc. It was based on Common Minimum Program(CMP). The BJP highlighted the foreign origin issue of Congress (I) president, Sonia Gandhi, and the India's success in Kargil war (May-July,1999). It influenced the voters. The BJP won 182 seats and it emerged as the single largest party in the Lok Sabha. The NDA got stunning majority with 300 seats in the House. Thus, the NDA parliamentary party leader, Atal Bihari Vajpayee, again took oath as the Prime Minister on October 13,1999[16].

The BJP-led coalition government faced several challenges like the Kargil war crisis(1999), a earthquake in Gujarat (2000), a serve drought, a series of corruption scandals and the Godhra carnage in February, 2002. On the other hand, the Vajpayee government started the second wave of economic reforms like FDI in insurance sector, Foreign Exchange Regulation Act, new regulatory authorities for Securities and telecommunication industries, creating new industries for disinvestment and telecommunication, privatisation of Indian Oil and so on. Hence, the economic growth rate grew at 8.5% and the BJP won the several key state assembly elections in December, 2003.

In spite of pressure from Rashtriya Savyam Sevak Sangh (RSS), contradiction in BJP organization and internal resistance of coalition partners, the Prime Minister, Atal Bihari Vajpayee, has successfully tackled the situation, he protected the national security and he provide the stable government, good governance, cooperative federalism and8.5% economic growth on the basis of his national stature ,ability and experience. The BJP-led NDA government became the first non-Congress government to survive a full term of five year term in office. The BJP proclaimed a new era of 'India Shining' and they overestimated its performance. Hence, the BJP decided to hold an early election to the Lok Sabha to renew its mandate. But, the NDA got stunning defeat in the Lok Sabha election and the Congress (I) - led Opposition parties got a clear mandate unexpectedly in the election.

6. UPA Government (2004-2009) : The 14th Lok Sabha election was held in May, 2004. The Congress (I) party won 145 seats in the Lok- Sabha and its allies won 77 seats. Thus, the Congress (I) alliance won 222 seats, it was just short of a majority in the House. The Left parties supported the coalition government from outside based on a Common Minimum Program (CMP). They formed the Congress(I)-led United Progressive Alliance (UPA), which consisted 14 political parties including two national parties and twelve regional parties. On the other hand, the BJP, the RSS and the fundamentalists criticised the Congress (I) president, Sonia Gandhi, on her foreign origins and demanded that a foreign-born Sonia Gandhi cannot be accept as Prime Minister of India. Hence, Sonia Gandhi stepping aside and she nominated Manmohan Singh as Prime Minister of the country. Manmohan Singh took oath as the Prime Minister on May 22, 2004[17]. The NCP, RJD, JMM, DMK, PMK, MDMK, TRS, LJP, RPI, National Conference, Muslim League, Kerala Congress, Rajiv Congress and All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeem were participated in the Congress (I)- led UPA government (2004-2009). The CPI, CPI-M, RSP, IFB, Bahujan Samaj Party (BSP) and Samajwadi Party were supported from outside to the UPA government. As a power-sharing arrangement, the Congress (I) president, Sonia Gandhi, became the Chairperson of the National Advisory Council (NAC), a coalition coordinating body designed to ensure the smooth functioning of the alliance. The UPA government tried to implementation of its CMP. It improved the economic growth,it stressed on sustainable development, it introduced the Right to Information Act,2005, the National Rural Employment Guarantee Act, 2005,it improved the image of country on the international platforms and it signed the agreement with Russia, USA, France, Britain, Germany and Japan. It preferenced the trade agreement with European Union, G-8, G-20, BRICS, ASEAN, SAARC and IORA. The coalition partners shared the power with Congress (I) in the coalition government. However, the coalition government faced many challenges like the intervention of UPA chairperson, Sonia Gandhi and Congress (I) leader Rahul Gandhi, Naxalite challenges to internal security, internal resistance of coalition partners specially TRS, DMK and National Conference and so on. Moreover, CPI, CPI-M, RSP, IFB and BSP were opposed the 123 US-Indo Nuclear Agreement and they withdrew their support after three years from the UPA government. The Left parties has moved a no-confidence motion in the Lok Sabha against the UPA government. However, the motion could not pass in the House by the support of its coalition partners like Samajwadi Party, RJD, DMK, PMK and National Conference etc. In spite of all problems the Congress (I)-led UPA government completed his full term of five years in office. The improvement in economic growth of the country, introduction of RTI Act, 2005 and NREGA,2005 were the major contribution of Congress (I)-led UPA government headed by Manmohan Singh to the country.

7. UPA Government (2009-2014): The 15th Lok Sabha election was held in May, 2009, again Congress (I) emerged as the single largest party with 206 seats and its allies won62 seats in the Lok Sabha. Thus, the Congress (I)-led UPA got a clear majority with 268 seats in the House. The UPA consisted eleven political parties including two national Parties and nine regional parties. The Congress-led UPA included the Congress (I), Nationalist Congress Party (NCP), Trinamool Congress(TMC), National Conference (NC), Rashtriya Janata Dal (RTD), Jharkhand Mukti Morcha

(JMM), Muslim League (Kerala), Viduthalai Chruthaigai Katchi (VCK) Kerala Congress (Mani Group), Republican Party of India (RPI), and BDF. The NDA consisted Bharatiya Janata Party (BJP), Shiv Sena (SS), Shiromani Akali Dal (SAD), Janata Dal-United (JD-U), Telugu Desam Party (TDP), Telangana Rashtra Samithi (TRS), Lok Jan Shakti Party (LJSP), Biju Janata Dal (BJD), All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (AIADMK), Desiya Murpakku Dravida Kazhagam (DMDK), National Conference (NC), People's Democratic Party (PDP). Hence, the UPA parliamentary party leader, Manmohan Singh, took oath as the Prime Minister on May 22, 2009[18]. The NCP, DMK,RJD, JMM, National Conference and All India Masjis-e-Ittehad-Muslimeem were participated in the Congress (I)-led UPA government (2009-2014). The UPA government has smoothly worked. It maintained the economic growth of the country, it saved the country from the worldwide economic Recession(2008), it continued the sustainable development, it strengthened the friendly relations with Russia, USA, France, Japan, Germany, Britain, ASEAN and South-Asian Countries. It continued trade agreement with European Union, G-8, G-20,IORA, BRICS, ASEAN and SAARC. On the other hand, the UPA government faced many challenges like internal resistance of coalition partners, price rising of essential commodities, Black money, Naxalite challenge to internal security, insurgency in Jammu & Kashmir and North-East and so on. It has negative consequences on the working of UPA government. The intervention of UPA Chairperson Sonia Gandhi and Congress (I) leader Rahul Gandhi in the decision making of the UPA government make the three power centre like Prime Minister Manmohan Singh, UPA Chairperson Sonia Gandhi and Congress (I) leader Rahul Gandhi. It weakened the UPA government. All above, 2G Spectrum scandal, Coal Bloc scandal and corruption charges on UPA leaders defamed the UPA government. On the other hand, the BJP- led Opposition parties strongly criticised the personality cult and dynasty factor of Nehru-Gandhi family in the Congress (I) party, Nationalism, Hindutava agenda, Black money, price rising and corruption charges on the UPA leaders. It downgraded the image and mass support of the UPA government. Consequently, the Congress (I) -led UPA defeated in the Lok Sabha election in 2014.

8. NDA Government (2014 to onwards): The 16th general election to the Lok Sabha was held in May, 2014. The BJP won the 282 seats with 31 percent votes and it emerged as the single largest party in the Lok Sabha unexpectedly. it was surplus majority of BJP. Hence, the BJP – led National Democratic Alliance (NDA) formed the government. it was one-party ,i.e., BJP dominated coalition government. The BJP-led NDA parliamentary party leader, Narendra Modi, took oath as the Prime Minister on May 26, 2014[19].The NDA consisted 28 rightist and centrist parties like BJP, Shiv Sena, Shiromani Akali Dal, JD-U, LJSP, TDP, TRS, Desiya Murpakku Dravida Kazhagam (DMDK),BJD, AIADMK,PDP, National Conference and so on. The Congress (I) party won 44 seats only, which was less 1/10 seats in the House. Hence, the Congress (I) parliamentary party leader, Mallikarjun Kharge, could not be recognised the Leader of Opposition in the House by the Speaker. He was recognized as a Leader of Largest Party in House. It weakened the Opposition parties in the House. The NDA coalition partners formed a Common Minimum Program (CMP). The BJP-led NDA coalition government focused on its CMP. It stressed on national security, construction of infrastructure, administrative efficiency, digitalisation of economy, friendly relations with USA, France, Canada, China, Germany, Russia, European Union, ASEAN and SAARC, BRICS, IORA. Prime Minister, Narendra Modi, centralised the power in the Prime Minister Office (PMO), he controlled on the ministers and he adopted the authoritative working style. The NDA government de-established the Opposition parties ruled state governments in Karnataka, Uttrakhand, Assam and Goa by the use of Article 356 of the Constitution to fulfill its political interests, which was against the federal democracy in the country. Moreover, the NDA government was alleged for interfere in the working of institutions like Election Commission of India (ECI), Enforcement Directorate (ED) and Central Bureau of Investigation (CBI) to fulfill its political interests. It undermines the democratic governance in the country.

Besides these challenges the NDA government headed by Narendra Modi successfully tackled the terrorism in Jammu&Kashmir, insurgency in North-East, naxalite challenge to internal security, illegal migration in West Bengal and Assam, introduction of Swachh Bharat Mission on October 2, 2014, Made in India on September 25, 2014 so on. It strengthened the friendly relations with USA, France, Japan, Britain, China, Russia, European Union, G-7, BRICS, IORA, ASEAN and SAARC. It provided the political stability, efficient administration and it improved the image of the country on the international platforms. It made Narendra Modi as strong and popular Prime Minister of the country.

Consequences of Coalition Government: The development of coalition government in India has the following positive consequences:

1. The coalition government promoted the co-operative federalism in the country.
2. It provided the opportunity to regional political parties to participate in the Union cabinet.
3. It promoted the responsibility in regional parties regarding national interest rather than regional interests.
4. It fulfilled the regional aspirations in the Union Government.
5. It checked the misuse of Article 356 owing to internal resistance of coalition partners.
6. It promoted unity in -diversity in plural and multi-cultural society of the country.

The coalition government has the following negative consequences:

1. The development of coalition government created political instability, horse trading, defection and

corruption.
2. The coalition government became regional parties more strong.
3. It created confrontation in Union cabinet, because coalition partners gives preferences on their regional interests on national interest.
4. It created the problem of coordination among coalition partners.
5. It became weakened the Union Government.
6. It became the weak position of the Prime Minister.
7. It created difficulty in the strong decision-making for the solution of major problems.
8. It would be negative consequences on the sovereignty, unity and integrity of the country.

Remedial Measures: The following remedial measures may be used for the proper functioning of coalition government in the country.

1. The collective responsibility should be developed among the parties of a coalition government.
2. A code of conduct should be introduced for the political parties regarding sovereignty, unity and integrity of country.
3. The coalition government should honestly implement the Common Minimum Program.
4. A democratic convention should be developed for the political parties regarding commitment to national interest rather than regional interest.
5. The people should neglect those political parties who participated in a coalition government to fulfill their vested interests like power or money rather than national interest.

Conclusion: India has a plural and multi-cultural society. It led the multi party system which promoted the coalition government in the country. The practice of coalition government has been successfully established in the Indian political system. From 1989 to 2019 the twelve coalition government formed in the country. Even five coalition governments have been successfully completed their tenure and they provided the stable government to the country. The coalition government provided the opportunity to regional parties to participation in the Union cabinet, it checked the misuse of power by Union government and it promoted the Co-operative federalism in the country, but it created political in stability, confrontation, in-coordination and difficulties in the strong decision making. The coalition government became a real fact in the country. Hence, the collective responsibility, commitment, a code of conduct and democratic conventions should be developed for the political parties for smooth functioning of coalition government in the country.

References:-

1. Indian Express, New Delhi, March 25, 1977.
2. Dandvate, Madhu, “Coalition Politics in India” in Politics in India, 1977, p.2.
3. Times of India, New Delhi, July 29, 1979.
4. The Hindu, Madras, December 3, 1989.
5. Hindustan Times, New Delhi, October 24, 1990.
6. Indian Express, New Delhi, November 8, 1990.
7. Venkataraman, R., My Presidential years, 1994, p.437.
8. Times of India, New Delhi, November 11, 1990.
9. Hardgrave, Robert L. and Kochanek, Stanley A., India: Government and Politics in a Developing Nation, Seventh edition, Thomson, Boston,2008, p.327.
10. Indian Express, New Delhi, May 17, 1996.
11. Times of India, New Delhi, June 2, 1996.
12. Mehra, Ajay K., “The cabinet system in a coalition situation” in Kashyap, Subhash C. (ed.), Coalition Government and Politics in India, New Delhi, 1997, p. 98.
13. Hindustan Times, New Delhi, April 22, 1997.
14. Times of India, New Delhi, March 20, 1998.
15. Indian Express, New Delhi, April 18, 1999.
16. Times of India, New Delhi, October 14, 1999.
17. Hindustan Times, New Delhi, May 23, 2004.
18. Tribune, New Delhi, May 23, 2009.
19. Indian Express, New Delhi, May 27, 2014.

✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻